राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक: 2 **सोलहवीं विधान सभा के दूसरे सत्र का इकतीसवां दिवस** संख्या:20

शुक्रवार,

02 अगस्त 2024

(राजस्थान विधान सभा की बैठक 11.00 बजे
राजस्थान विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।)

(श्री वासुदेव देवनानी, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

श्री अध्यक्षः प्रश्न काल। कुमारी रीटा चौधरी।

हेतमसर के राजकीय कन्या महाविद्यालय का क्रमोन्नयन

354. कुमारी रीटा चौधरी (मंडावा): क्या उच्च शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

क्या सरकार विधान सभा क्षेत्र मण्डावा के राजकीय कन्या महाविद्यालय, हेतमसर को स्नातकोत्तर में क्रमोन्नत करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उच्च शिक्षा मंत्री (डॉ. प्रेम चन्द बैरवा): माननीय अध्यक्ष महोदय, विधान सभा क्षेत्र मण्डावा स्थित राजकीय कन्या महाविद्यालय, हेतमसर को स्नातकोत्तर में क्रमोन्नत करने का कोई प्रस्ताव वर्तमान में विचाराधीन नहीं है।

कुमारी रीटा चौधरी (मंडावा): माननीय अध्यक्ष महोदय, राजकीय कन्या महाविद्यालय, हेतमसर के अन्दर लगभग सात सौ लड़कियां हैं और चार सौ ने ज्योग्राफी सब्जेक्ट ले रखा है। मैं सी.एम. साहब से भी मिली, मैंने आपको भी भिजवाया है कागज तो आप यह तो बतायें कि विचाराधीन क्यों नहीं है?

डॉ. प्रेम चन्द बैरवा (उप मुख्य मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, राजकीय कन्या महाविद्यालय, हेतमसर, झुंझुनू की स्थापना 2019 में हुई थी। राजकीय कन्या महाविद्यालय, हेतमसर कला संकाय एवं विज्ञान संकाय राजसेस से संचालित है। कला संकाय के अन्तर्गत हिन्दी साहित्य, अंग्रेजी साहित्य, इतिहास, अर्थशास्त्र, गृह विज्ञान, राजनीति विज्ञान, भूगोल, उर्दू एवं विज्ञान संकाय में वनस्पति शास्त्र, रसायन शास्त्र, भौतिक शास्त्र, गणित एवं प्राणि

कार्यवाही वृत्तान्त में प्रयुक्त संकेताक्षर

+++: शब्द/अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

000: अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

शास्त्र विषय स्वीकृत है। राजकीय कन्या महाविद्यालय, हेतमसर में कला संकाय एवं विज्ञान संकाय प्रथम वर्ष में 2-2 कुल चार वर्ग स्वीकृत हैं। राजकीय कन्या महाविद्यालय, हेतमसर में 2023-24 में कुल 555 छात्राएं अध्ययनरत हैं।

कुमारी रीटा चौधरी (मंडावा): मंत्री महोदय,...

श्री अध्यक्षः सुनिये, उत्तर तो सुनना पड़ेगा। उत्तर के बाद आपको कोई पूरक पूछना है तो पूरक पूछिये।

डॉ. प्रेम चन्द बैरवा (उप मुख्य मंत्री): राजकीय कन्या महाविद्यालय, हेतमसर में सन् 2024-25 में कला संकाय में 200 सीटों के विरुद्ध 245 आवेदन आये हैं एवं विज्ञान संकाय में बॉयो ग्रुप के 88 सीटों के विरुद्ध 50 तथा मैथ्य ग्रुप में स्वीकृत 88 सीटों के विरुद्ध 18 आवेदन प्राप्त हुए हैं। राजकीय कन्या महाविद्यालय, हेतमसर में वर्तमान में स्वयं के नवीन भवन में चल रहा है।

कुमारी रीटा चौधरी (मंडावा): मैंने तो यह पूछा है मंत्री महोदय, विचाराधीन क्यों नहीं है? हम लोग एक तरफ बोलते हैं बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ। ग्रामीण क्षेत्र में विधान सभा क्षेत्र मण्डावा में एक भी राजकीय कॉलेज नहीं है जो पी.जी. हो।

डॉ. प्रेम चन्द बैरवा (उप मुख्य मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्या ने कहा है, एक तो इनकी ग्राम पंचायत में ही है महाविद्यालय लेकिन स्नातकोत्तर में क्रमोन्नत करने के लिए छात्राओं की पर्याप्त संख्या एवं संसाधनों की उपलब्धता के अनुसार विचार किया जाता है। हेतमसर में 15 किलोमीटर की दूरी पर राजकीय कन्या महाविद्यालय, झुंझुनू में स्नातकोत्तर हेतु पर्याप्त सुविधाएं उपलब्ध हैं।

श्री अध्यक्षः अगला प्रश्न। श्री देवेन्द्र जोशी।

उम्मेद सागर बांध के जलग्रहण क्षेत्र में अतिक्रमण पर कार्यवाही

355. श्री देवेन्द्र जोशी (सूरसागर): क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विधान सभा क्षेत्र सूरसागर में उम्मेद सागर एवं उसके जलग्रहण क्षेत्र की कुल कितनी भूमि विभाग के नाम दर्ज है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि उक्त समस्त भूमि पर अतिक्रमण है? यदि हां, तो सरकार द्वारा उक्त अतिक्रमण हटाने के संबंध में अब तक क्या-क्या कार्यवाही की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार उक्त अतिक्रमण की जांच हेतु विशेष जांच दल गठित करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री (श्री कन्हैयालाल): (1) जिला कलेक्टर, जोधपुर के पत्र दिनांक 07.06.2022 के क्रम में विधान सभा क्षेत्र सूरसागर में उम्मेदसागर एवं उसके भराव क्षेत्र की कुल 740.15 बीघा भूमि राजस्व विभाग द्वारा दिनांक 08.06.2022 को कृषि विभाग

से जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के नाम नामान्तरण की गई है। भूमि नामान्तरण की जमाबंदी की प्रति परिशिष्ट-अ पर संलग्न हैं।

(2) बांध के भराव क्षेत्र में अतिक्रमण के दृष्टिगत जिला कलेक्टर जोधपुर के आदेश दिनांक 07.04.2022 द्वारा गठित कमेटी द्वारा उम्मेद सागर एवं उसके भराव क्षेत्र में सर्वे उपरांत कुल 281 अतिक्रमण चिह्नित किये गये थे। विवरण परिशिष्ट-ब पर संलग्न है।

जिला कलेक्टर के पत्र दिनांक 12.06.2024 के क्रम में गठित कमेटी द्वारा जून, 2024 में पुनः सर्वे कर कुल 313 अतिक्रमण चिह्नित किये गये हैं। विवरण परिशिष्ट-स पर संलग्न है।

विभाग द्वारा सर्वे किये गये अतिक्रमणों को हटाने हेतु 235 नामजद अतिक्रमणियों को माह जुलाई, 2024 में नोटिस तामील/चस्पा कर अतिक्रमण हटाने हेतु पाबन्द किया गया है तथा 78 अज्ञात अतिक्रमणियों के निर्माणों पर नोटिस चस्पा किये गये हैं। बांध भराव क्षेत्र के अतिक्रमणियों के विरुद्ध जिला प्रशासन के सहयोग से विधि सम्मत कार्यवाही करते हुए अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही की जायेगी।

(3) बांध क्षेत्र में अतिक्रमणों को हटाने की प्रभावी कार्यवाही की जा रही है।

श्री देवेन्द्र जोशी (सूरसागर): माननीय अध्यक्ष महोदय, उत्तर मुझे मिल गया है।

श्री अध्यक्ष: पूरक प्रश्न पूछिये। ये कह रहे हैं कि उत्तर मिल गया तो पूरक प्रश्न।

श्री देवेन्द्र जोशी (सूरसागर): माननीय अध्यक्ष महोदय, उम्मेद सागर रियासत काल से कायलाना एवं तख्त सागर के ओवरफ्लो और भैरवा नहर से लेकर चौपासनी चोखा तक की समस्त पहाड़ियों के वर्षा जल संरक्षण का बहुत बड़ा केन्द्र है। दूसरा यह सुन्दर बालाजी पहाड़ी जो कि जोधपुर का सबसे आकर्षक सनसेट पाइंट है, की तलहटी में बना हुआ है इस कारण उम्मेद सागर, कायलाना, तख्त सागर का वैकल्पिक वाटर रिजर्व बनने की समस्त पात्रता रखता है। नया कुछ नहीं करना है रियासतकाल में ही वर्षा जल को कायलाना तख्त सागर के...।

श्री अध्यक्ष: प्रश्न पूछो, माननीय सदस्य।

श्री देवेन्द्र जोशी (सूरसागर): मैं पृष्ठभूमि के बिना तो...।

श्री अध्यक्ष: नहीं, भूमिका नहीं, प्रश्न सीधा पूछो।

श्री देवेन्द्र जोशी (सूरसागर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न है कि सरकार ने स्वीकार किया है कि वर्ष 2022 में कुल 281 अतिक्रमण थे वो 2024 में बढ़ कर 313 हो गये। मेरा माननीय मंत्री महोदय से पूरक प्रश्न यह है कि 2022 में तो कांग्रेस की सरकार थी जिसकी नियति ही अतिक्रमियों और भ्रष्टाचारियों को बढ़ावा देने की रही है। मेरा प्रश्न यह है कि जब इन अतिक्रमियों को नोटिस दिये जा चुके हैं तो सरकार उन अतिक्रमणों को कब तक पूर्णतः हटा देगी? समयबद्ध आश्वासन सदन को प्रदान करें।

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी।

श्री कन्हैयालाल (जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो उम्मेद सागर की बात बताई है उम्मेद सागर बांध, चौपासीन जागीर ग्राम में

स्थित है। भू अभिलेख कार्यालय के अनुसार उम्मेद सागर बांध का भराव क्षेत्र खसरा नम्बर 5 किस्म गैर मुमकिन बांध रकबा 742 बीघा कृषि विभाग के नाम दर्ज था। आयुक्त, कृषि आयुक्तालय, जयपुर, राजस्थान के कार्यालय आदेश 2726 दिनांक 5.7.2017 द्वारा जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, जोधपुर को स्थानांतरित करने की स्वीकृति प्रदान की गई। कार्यालय जिला कलेक्टर, जोधपुर क्रमांक राजस्व 2022, 5241 दिनांक 7.6.2022 को कार्यालय तहसीलदार, जोधपुर क्रमांक राजस्व 22, 598 दिनांक 7.6.2022 की पालना में 740.15 बीघा गैर मुमकिन बंधा कृषि विभाग से जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, जोधपुर को दिनांक 8.6.2022 को पटवार मण्डल, चौखा तहसील जोधपुर द्वारा नामान्तरण किया गया। उक्त खसरे की शेष जमीन गैर मुमकिन सड़क जो सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के नाम दर्ज की गई। बांध के नीचे का खसरा नम्बर 7 रकबा 542 बीघा किस्म गैर मुमकिन बांध कृषि विभाग के नाम से दर्ज है।

श्री अध्यक्ष: इन्होंने अतिक्रमण का पूछा है वह कब तक हटायेंगे? यह बता दो।

श्री कन्हैयालाल (जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री): मैं अतिक्रमण का बताना चाहता हूं कि हमारे पास 2022 में आया। हमने इनके जितने भी अतिक्रमी हैं 2022 तक जिस तरह से माननीय सदस्य ने बताया कि लगभग 281 अतिक्रमण थे, बाद में 313 हो गये। इनके नोटिस भी दे दिये सारी चीज हो गई है। मैं तो माननीय सदस्य को कहना चाहता हूं कि हमारे विभाग ने जो इनको नोटिस दिये हैं इनका जवाब भी ले रहे हैं इसके साथ-साथ नगर निगम द्वितीय दक्षिण में जो है उसके साथ में और कलेक्टर के साथ में मिल कर और प्रशासन से मिल कर आने वाले दो महीने में हम इनको चिह्नित करके इनका अतिक्रमण हटायेंगे।

श्री अध्यक्ष: अगला पूरक प्रश्न।

श्री देवेन्द्र जोशी (सूरसागर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा दूसरा प्रश्न है कि जो कैचमेंट एरिया डिसाइडेड है उसमें भी अतिक्रमण हो तो नोटिस देने की किस नियम के तहत आवश्यकता है?

दूसरा, यह सरकार ने, दूसरी मेरी मांग है कि 2022 से 2024 के बीच जो अतिक्रमण भारी संख्या में बढ़ गये हैं उसके लिए कौन अधिकारी और कार्मिक दोषी है, सरकार उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही, कब तक कर देगी? समयबद्ध आश्वासन सदन को बतायें।

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी।

श्री कन्हैयालाल (जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, जब से यह चीज हमारे विभाग के संज्ञान में आयी है तब से हम चिह्नित करके इनको नोटिस भी दे रहे हैं, कार्यवाही भी कर रहे हैं और मैं तो इतना ही कहना चाहता हूं इनको कि आने वाले क्योंकि नोटिस पी.एच.ई.डी. विभाग ने ही दिया है बाकी कानूनन नोटिस 91 का तहसीदार के द्वारा दिया जाता है, प्रशासन के द्वारा भी देंगे। नगर निगम के क्षेत्र में पेराफेरी एरिया में है जबकि वह पी.एच.ई.डी. के नाम है उनको भी साथ में लेते हुए इसका अतिक्रमण आने वाले

दो महीने में हटा देंगे।

श्री अध्यक्षः अगला प्रश्न। श्री ललित मीना।

हथियादह सिंचाई परियोजना के डूब क्षेत्र में राजकीय भूमि पर बने मकानों का मुआवजा

356. श्री ललित मीना (किशनगंज): क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या सरकार विधान सभा क्षेत्र किशनगंज की हथियादह मध्यम सिंचाई परियोजना के डूब क्षेत्र में आये गाँवों में राजकीय भूमि (चरागाह, सिवायचक, वनभूमि) में बने हुए मकानों का मुआवजा नहीं दिया गया है? यदि हां, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार उक्त को विशेष अनुदान स्वीकृत करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

जल संसाधन मंत्री (श्री सुरेश सिंह रावत): (1) जी हां, विधान सभा क्षेत्र किशनगंज तहसील की हथियादह मध्यम सिंचाई परियोजना के बांध निर्माण में आये डूब क्षेत्र के गाँवों में राजकीय भूमि, चरागाह एंव वन भूमि पर स्थित परिसम्पत्तियों/मकानों को भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकार और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 के अनुसार मुआवजा भुगतान का प्रावधान नहीं होने से मुआवजा भुगतान नहीं किया गया है।

(2) भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकार और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 अनुसार विधान सभा क्षेत्र के उक्त बांध निर्माण के डूब क्षेत्र में आये ग्रामों की राजकीय भूमि (चरागाह, सिवायचक, वन भूमि) पर स्थित परिसम्पत्तियों/मकानों के मुआवजा भुगतान का प्रावधान नहीं होने के कारण विशेष अनुदान (EX-GRATIA) के प्रस्ताव स्वीकृति हेतु प्रक्रियाधीन है, स्वीकृति उपरान्त संसाधन उपलब्धतानुसार अग्रिम आवश्यक कार्यवाही की जा सकेगी ।

श्री अध्यक्षः माननीय सदस्य।

श्री ललित मीना (किशनगंज): माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मंत्री जी से पूछना चाहूंगा कि 2013 के नियम के अनुसार आपने चरागाह, सिवायचक में इनको मुआवजा देने के लिए मना कर दिया, परन्तु लगभग 970 परिवार वहां पर पुनर्स्थापित होकर पुनर्वास उनका होना है। आज दिन तक उनको 6 साल हो गये, उनको एक को भी वहां पर विस्थापित करके उनको बसाया नहीं गया है और आपके द्वारा यहां पर लगभग 223 हमारे ऐसे परिवार हैं जो हमारे चरागाह, सिवायचक और वन भूमि में बसे हुए हैं।

Kas/rtm/02.08.2024/11.10/1b

उनका 6.79 करोड़ का प्रस्ताव बनाकर दिया हुआ है, उनको भी इसमें कम से कम शामिल करें। चूंकि वह आपके 2013 के नियम में नहीं आ रहे हैं, पर मेरा आपके माध्यम से निवेदन है कि इनको सरकार सहानुभूति पूर्वक विचार करके कर देगी क्या? वहां पर जनजाति

क्षेत्र है और 2005 के नियम के अनुसार हमारे जो जनजाति के भाई हैं, उनको लैंड फोर लैंड देने का भी प्रावधान है। मेरा मंत्री महोदय से निवेदन है कि यह राशि स्वीकृत कर इनको वहां पर पुनर्वास कराने का विचार रखते हैं क्या?

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी।

श्री सुरेश सिंह रावत (जल संसाधन मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं हमारे युवा माननीय सदस्य को आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि हाथीदेई बांध की डूब क्षेत्र की सरकारी भूमि चरागाह वन भूमि पर निवास कर रहे 223 कृषकों को, जिसमें करवडीकलां, करवडीखुर्द एवं मजरा के पुनर्वास हेतु भू-खण्ड व विशेष अनुग्रह राशि 6 करोड़ 79 लाख रुपये के प्रस्ताव जल संसाधन संभाग कोटा के स्तर पर परीक्षणाधीन है। शीघ्र ही प्रस्ताव मंगवा कर मंत्रिमंडलीय स्वीकृति उपरांत भुगतान किया जाना प्रस्तावित है।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य।

श्री ललित मीना (किशनगंज): अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि प्रस्तावित तो है, लेकिन क्या आप स्वीकृत कर देंगे? क्योंकि आपने जवाब में कहा है कि 2013 के नियमानुसार इसमें नहीं आते। आप कर देंगे तब तो आपको बहुत-बहुत आभार। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: अभी प्रस्तावित है।

श्री ललित मीना (किशनगंज): वह वहां धरने पर भी बैठते हैं। वे हमारी पूर्व सरकार के पास भी गये, लेकिन उनका कोई उचित समाधान नहीं हुआ। वर्तमान में हमारी सरकार है, तो मैं मंत्री महोदय से निवेदन करुंगा कि आप सदन के माध्यम से आश्वासन दें कि जो एक्सग्रेसिया वाले 200 परिवार बच रहे हैं, उनको हम सैंक्शन कर देंगे ।

श्री सुरेश सिंह रावत (जल संसाधन मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, यह जिस विशेष अनुग्रह राशि की बात कर रहे हैं वह मंत्रिमंडल से स्वीकृति के उपरांत ही संभव है। मैं भी मेरी तरफ से यह प्रयास करुंगा कि जल्दी ही यह राशि मिले।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न। श्री कालूराम।

झालावाड़ में स्कूटी योजना में लाभान्वित विशेष योग्यजन

357. श्री कालूराम (डग): क्या सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) जिला झालावाड़ में विशेष योग्यजनों (दिव्यांग) की संख्या कितनी है? उक्त में से कितनों को पेंशन स्वीकृत की जा चुकी है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) सरकार द्वारा उक्त को क्या-क्या सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं?

(3) जिला झालावाड़ के कितने विशेष योग्यजनों (दिव्यांगजनों) को स्कूटी से लाभान्वित किया जा चुका है? संख्यात्मक विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या सरकार विशेष योग्यजनों (दिव्यांगजनों) की मासिक पेंशन में वृद्धि करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री (श्री अविनाश गहलोत): (1) विशेष योग्यजनों द्वारा Specialy Abled Person (SAP) पोर्टल पर दिव्यांगता प्रमाण-पत्र हेतु आवेदन किया है उनमे से पात्र विशेष योग्यजनों को दिव्यांगता प्रमाण-पत्र जारी किये है, इस अनुसार झालावाड जिले में जारी दिव्यांगता प्रमाण-पत्र की कुल संख्या 25,981 है। विशेष योग्यजनो को नियमानुसार एवं पात्रतानुसार पेंशन का लाभ मिल रहा है। राजएसएसपी पोर्टल पर दिनांक 30.07.2024 के अनुसार झालावाड जिले मे विशेष योग्यजन पेंशनर्स की कुल संख्या 25,946 है।

(2) विशेष योग्यजनों को निम्नानुसार पात्रता के आधार पर गत वर्ष में निम्न सुविधाओं से लाभान्वित किया जा रहा हैः-

1. विशेष योग्यजन सम्मान पेंशन योजना- लाभान्वितों की संख्या- 25946
2. मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन स्वरोजगार योजना- लाभान्वितों की संख्या- 05
3. सुखद दाम्पत्य जीवन योजना- लाभान्वितों की संख्या- 04
4. संयुक्त सहायता योजना - लाभान्वितों की संख्या- 171
5. विशेष योग्यजन स्कूटी योजना -लाभान्वितों की संख्या- 172

(3) जिला झालावाड मे विशेष योग्यजनो (दिव्यांगजनो) को 261 स्कूटी वितरित कर लाभान्वित किया गया है।

(4) जी हां। 01 अप्रैल 2024 से सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनान्तर्गत दिव्यांगजन सम्मान पेंशन योजना की आधार दर में 15 प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि कर अभिवृद्धि पेंशन राशि वर्तमान में रुपये 1150/-प्रतिमाह एवं 75 वर्ष व अधिक आयु वर्ग के दिव्यांगजनों को रुपये 1250/- प्रतिमाह पेंशन का भुगतान किया जा रहा है।

श्री कालूराम (डग): माननीय अध्यक्ष महोदय, नंबर एक मैं पूछना चाहता हूं कि आपने इसमें संख्या दी है 25981 और इसमें से 25946 को पेंशन दे रहे हैं। काफी दिव्यांग लोग ऐसे हैं, जिनको अभी तक पेंशन नहीं मिल रही है। मंत्री महोदय, मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि बाकी वंचित लोगों को पोर्टल खोल कर आप पेंशन देने का विचार रखते हैं? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी।

श्री अविनाश गहलोत (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे पोर्टल पर विभाग के पास जो भी इन दिव्यांगों की पेंशन के लिये एप्लीकेशंस आती हैं, उनका एक कमेटी के माध्यम से वेरिफिकेशन होता है। वेरिफिकेशन के बाद विभाग के पास आता है और उसके तुरंत बाद ही हम लोग दिव्यांगों की पेंशन का भुगतान कर देते हैं और जो शेष लंबित हैं, उनकी जांच चल रही है, जांच के बाद रेगुलर प्रोसेस है, उसके बाद शेष का भी भुगतान हो जायेगा।

श्री कालूराम (डग): माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा दूसरा प्रश्न है, आपने मुख्यमंत्री योग्यजन स्वरोजगार योजना में लाभान्वितों की संख्या मात्र 5 बताई है। सुखद दाम्पत्य

जीवन योजना में संख्या मात्र 4 दी है। संयुक्त सहायता योजना में 171 दी है और विशेष योग्यजन स्कूटी में 172 दी है। इसमें क्या आप स्कूटी की संख्या बढ़ाना चाहते हैं? क्या सुखद दाम्पत्य जीवन योजना में भी केन्द्र सरकार या राज्य सरकार बढ़ाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं तो क्यों?

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी।

श्री अविनाश गहलोत (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य कालूराम जी मेरे अजीज मित्र हैं। आपकी जानकारी के लिये निवेदन करता हूं कि अभी 10 जुलाई, 2024 को हमारे हाल ही के बजट में हमारी वित्त मंत्री जी ने युवा दिव्यांगों को संबल प्रदान करने के लिये 2000 दिव्यांगजनों को स्कूटी प्रदान करने की घोषणा की है। मैं माननीय सदस्य को आश्वस्त करना चाहता हूं कि पिछली सरकार के समय 2019-20 में किसी स्कूटी का वितरण नहीं हुआ। 2020-21 में किसी स्कूटी का वितरण नहीं हुआ। उसके बाद के तीन सालों में पहले साल में 1985 आवंटित हुईं, उसके बाद कुछ हुईं। अभी हमारा पहला साल है, हमने पहले बजट में 2000 स्कूटी का वितरण करने का निर्णय लिया है। आपके डग विधान सभा क्षेत्र में भी 261 स्कूटी का वितरण हमने कर दिया है। जैसे ही हमारे पास आपकी सूची आयेगी, नियमानुसार कार्यवाही करके आपके वहां जितने भी स्कूटी के आवेदन आयेंगे, उन सबको वितरण कर दिया जायेगा।

श्री कालूराम (डग): माननीय मंत्री महोदय, मुझे यह सूची उपलब्ध कराएं।

श्री अविनाश गहलोत (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री): कौनसी सूची?

श्री कालूराम (डग): नाम आये हैं, मुझे सूची उपलब्ध कराएं।

श्री अविनाश गहलोत (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री): आप जो जानकारी मांगेंगे, मैं आपके घर आकर वह जानकारी उपलब्ध कराऊंगा।

श्री अध्यक्ष: विराजिए। विधायक और मंत्री जी के बीच में इतना प्रेम सम्बन्ध हो रहा है, और क्या चाहिये?

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदय ने खंड 2 में बताया है कि विशेष योग्यजन स्कूटी योजना में लाभान्वितों की संख्या है 172 और खंड 3 में आपने बताया है कि 261 स्कूटी वितरण की है, इन दोनों में अंतर क्या है? यह बताएं। खंड 4 में आपने कहा है कि दिव्यांगजनों को हम 1150 और 1250 रुपये पेंशन दे रहे हैं, लेकिन सरकार जो विशेष असहाय दिव्यांगजनों को 1000 रुपये अलग से भी देती है, उसका कहीं जिक्र नहीं है।

श्री अविनाश गहलोत (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, जो 100 परसेंट डिसेबल पर्सन होते हैं, उनको 1000 रुपये की पेंशन अलग से मिलती है। नेता प्रतिपक्ष महोदय, आप तो इस विभाग के मंत्री रहे हैं, आपके पास सारी जानकारी है। इसमें राज्य सरकार और केन्द्र सरकार की कैटेगरी बनी हुई है, जिसमें 40 परसेंट से ऊपर अगर डिसेबल होता है, उसको राज्य सरकार की तरफ से और 80 परसेंट से ऊपर होता है,

उसको सुविधाएं अलग-अलग कैटेगरी में मिलती हैं। जो 100 परसेंट डिसेबल पर्सन होते हैं, उनको 1000 रुपये अलग से सहायता दी जाती है। जैसे 1250+1000=2250 रुपये की पेंशन राशि प्रतिमाह सरकार की तरफ से मिलती है।

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): इसमें लिखा नहीं आपने।

श्री अविनाश गहलोत (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री): वह मैंने हाउस को बता दी। मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने वह सवाल पूछा, जिससे हमारा पूरा सदन अवगत हो जाये कि 2250 रुपये प्रतिमाह उनको मिलता है।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न। श्री गोपाल शर्मा।

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): खंड 2 और 3 में जो स्कूटी में अंतर है, वह नहीं बताया।

श्री अविनाश गहलोत (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री): नेता प्रतिपक्ष को मैं आश्वस्त करता हूं कि मैं आपके घर आकर इसकी जानकारी दे दूंगा।

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): मैं तो खुद ही पता कर लूंगा।

श्री अध्यक्ष: सबके नहीं जाना है, विशेष लोगों के ही जाना है।

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): घर तो मैं ही आ जाऊंगा, लेकिन सब लोग घर नहीं जा पायेंगे।

श्री अविनाश गहलोत (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री): सरकार बड़े लोगों के साथ में गरीबों के द्वार भी जाती है, आप तो इतने बड़े केबिनेट मंत्री के बराबर हैं, मैं सरकार की तरफ से आश्वस्त करता हूं कि आप जो-जो जानकारी चाहेंगे, हम घर आकर आपको उपलब्ध करा देंगे।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न। श्री गोपाल शर्मा।

जयपुर में उपभोक्ताओं हेतु सुविधा एवं मध्यस्थता केन्द्र की स्थापना

358. श्री गोपाल शर्मा (सिविल लाईन्स): क्या खाद्य एवं नागरिकता आपूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि प्रदेश की सभी राशन की दुकानों पर digital weigh bridges उपलब्ध करवाकर पॉईंट ऑफ सेल (POS) से जोड़ा जा चुका है? यदि नहीं, तो कौन-कौन से जिले की कितनी-कितनी राशन की दुकानें इस सुविधा से वंचित हैं? उक्त वंचित दुकानों को कब तक जोड़ा जाना प्रस्तावित है? संख्यात्मक विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा हेतु जयपुर में राज्य स्तरीय सुविधा एवं मध्यस्थता केन्द्र स्थापित किया जाना था? यदि हां, तो उक्त केन्द्र किस स्थान पर और कितनी लागत से निर्मित किया गया तथा वित्तीय वर्ष 2023-2024 में उक्त पर कितनी राशि व्यय की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या उक्त केन्द्र कार्यशील है? यदि हां, तो उक्त से कितने व्यक्ति लाभान्वित हुए हैं? संख्यात्मक विवरण सदन की मेज पर रखें।

खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री (श्री सुमित गोदारा): (1) वर्तमान में प्रदेश की 25,500 सक्रिय राशन की दुकानों पर digital weigh bridges उपलब्ध करवाकर नवीन 4जी पाइंट ऑफ सेल (pos) से जोड़ा जा चुका हैं, विवरण परिशिष्ट-1 पर संलग्न है तथा शेष उचित मूल्य दुकानों का जिलेवार विवरण परिशिष्ट-2 पर संलग्न है। उक्त शेष दुकानों के सक्रिय होने पर आवश्यकतानुसार digital weigh bridges नवीन 4जी पाइंट ऑफ सेल (pos) से जोडे जाने हेतु समस्त जिला रसद अधिकारियों कोनिर्देशित किया जा चुका है।

(2) जी,हाँ। उक्त सेन्टर हसनपुरा जयपुर में आवंटित भूमि पर निर्मित किया जाना है,जिसका निर्माण कार्य प्रारम्भ नहीं हुआ ।

वित्तीय वर्ष 2023-2024 में इस पर कोई राशि व्यय नहीं की गई।

(3) जी,नहीं।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य।

श्री गोपाल शर्मा (सिविल लाईन्स): पूरक प्रश्न संख्या एक, उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा के लिये जो सुविधा व मध्यस्थता केन्द्र बनाया जाने वाला था, उस दिशा में आज तक कोई कार्यवाही नहीं हुई। क्या इसके लिये निर्वाचित मंत्रीगण ही जिम्मेदार रहेंगे या अफसरों के खिलाफ कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी?

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी।

Msk/rtm/02.08.24/1120/ 1c

श्री सुमित गोदारा (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं सिविल लाइन्स से आने वाले माननीय सदस्य को बताना चाहूंगा कि उपभोक्ता विषय गतिविधियों के संचालन एवं उपभोक्ताओं को न्याय प्रदान करने हेतु फैसिलिटेशन एवं मेडिएशन सेन्टर मध्यस्थता केन्द्र, जयपुर में दिनांक 19.10.2015 को उपभोक्ता भवन के निर्माण हेतु बंगला नंबर 1-बी, हसनपुरा, जयपुर की सम्पूर्ण भूमि एवं बंगला नंबर 1 के पीछे खाली जमीन लगभग 600 वर्गगज भूमि आवंटित की गयी। उक्त आवंटित भूमि पर बजट घोषणा 2023-24 की अनुपालना में राज्य स्तरीय फैसिलिटेशन एवं मेडिएशन सेंटर स्थापित किये जाने का निर्णय लिया गया था, पर बजट के अभाव में 2023-24 में इसका कार्य नहीं हो पाया था।

श्री गोपाल शर्मा (सिविल लाईन्स): 4 करोड़ 36 लाख उपभोक्ताओं से जुड़ी राशन की दुकानें क्या इस समय बन्द हैं और जनता राशन से मरहूम है और उन्होंने अपनी मांगों को लेकर POS मशीनें ज्यादातर जिलों में लौटा दी है।

श्री रफीक खान (आदर्श नगर): मरहूम का मतलब मरा हुआ होता है।

श्री अध्यक्ष: कृपया बीच में नहीं, आप जयपुर-जयपुर की राजनीति मत करो।

श्री गोपाल शर्मा (सिविल लाईन्स): कृपया बीच में मत बोलिये। जो मैं बोलता हूं, सोच समझ कर बोलता हूं, मेरे को आपसे पूछने की जरूरत है क्या? महरूम है।

श्री अध्यक्षः मंत्री जी की बात सुनें।

श्री सुमित गोदारा (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं सिविल लाईन्स से आने वाले माननीय सदस्य ने जो बात कही है। 01 तारीख से राशन डीलर अपनी कुछ मांग रख रहे हैं, हम उनसे चर्चा कर रहे हैं, हम उनका जल्दी ही उनका समाधान कराकर उचित मूल्य की दुकान से गरीब निर्धन लोग हैं, उनको राशन उपलब्ध कराया जायेगा।

श्री अध्यक्षः अगला प्रश्न। श्री अरूण चौधरी।

लूणी नदी को पुनर्जीवित करने हेतु योजना

359. श्री अरूण चौधरी (पचपदरा): क्या वन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि शुष्क वन अनुसंधान संस्थान, जोधपुर द्वारा लूणी नदी को पुनर्जीवित करने हेतु कोई योजना बनाई गई है? यदि हां, तो विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) सरकार द्वारा उक्त की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) या योजना पर कितनी राशि व्यय की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) सरकार द्वारा विगत पांच वर्षों में लूणी नदी क्षेत्र में कितने पेड़-पौधे लगाये गये? संख्यात्मक विवरण सदन की मेज पर रखें।

राज्य मंत्री, वन (श्री संजय शर्मा): (1) जी हां। शुष्क वन अनुसंधान संस्थान (आफरी), जोधपुर द्वारा लूणी नदी को पुनर्जीवित करने हेतु बनायी गयी योजना का विवरण परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(2) उक्त डी.पी.आर, शुष्क वन अनुसंधान संस्थान (आफरी), जोधपुर द्वारा बनाई गई है। इस हेतु राशि रुपये 51 लाख का वहन भारत सरकार द्वारा किया गया है।

(3) विगत 5 वर्षों में लूणी नदी के आस-पास के क्षेत्र में कैम्पा, नाबार्ड, राज्य निधि एवं सी. एस. आर. योजना में लगाये गये पौधों का विवरण परिशिष्ट-2 पर संलग्न हैं।

श्री अध्यक्षः माननीय सदस्य।

श्री अरूण चौधरी (पचपदरा): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदय को पूछना चाहता हूं कि इस योजना में आपने डीपीआर में 53 लाख रुपये खर्च किये। मैं चाहता हूं कि इस पर कुल लागत जो 534 करोड़ है, उसमें से अगर पूरी योजना को लागू करें तो बहुत अच्छी बात है। नहीं तो मेरे बाड़मेर के अन्दर जो भी है, उसको आप लागू करने की घोषणा करेंगे तो अति मेहरबानी होगी।

श्री संजय शर्मा (राज्य मंत्री, वन): माननीय अध्यक्ष महोदय, डीपीआर 51 लाख रुपये की बनायी गयी है, जिसका खर्चा भारत सरकार द्वारा वहन किया गया था। माननीय सदस्य ने बाड़मेर जिले और स्वयं के विधान सभा क्षेत्र के बारे में जो चर्चा की है, उसके बारे में आपके माध्यम से माननीय सदस्य से आग्रह करुंगा कि वे जो-जो प्रस्ताव देंगे, उन प्रस्तावों को प्राथमिकता से वन विभाग लागू करेगा। चाहे कैम्पा स्टेट प्लान के अधीन हो, हम उन कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर करेंगे।

श्री अरूण चौधरी (पचपदरा): मेरा माननीय मंत्री महोदय से प्रश्न है कि इसमें अभी राजस्थान के अन्दर कितने प्रोजेक्ट ऐसे हैं, जो विदेशी योजना के अन्तर्गत इस वन विभाग के तहत मंजूर हैं तो उसकी कॉपी की प्रति मेरे को उपलब्ध करवा दी जाये।

श्री संजय शर्मा (राज्य मंत्री, वन): माननीय सदस्य को निश्चित रूप से कॉपी उपलब्ध करा दी जायेगी।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न। श्री हरीश चौधरी

प्रश्न संख्या 360

(अनुपस्थित। कृपया आगे देखें।)

अगला प्रश्न। श्रीमती गीता बरवड़।

भोपालगढ़ नगरपालिका द्वारा करवाये गये कार्य

361. श्रीमती गीता बरवड़ (भोपालगढ़): क्या स्वायत्त शासन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) नगर पालिका भोपालगढ़ द्वारा माह जून, 2021 से मई, 2024 तक कितनी-कितनी राशि के कौन-कौनसे कार्य कहां-कहां पर करवाए गये? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि उक्त नगरपालिका द्वारा करवाए गए उक्त कार्यों में से कई कार्य अपूर्ण हैं? यदि हां, तो कौन-कौनसे? अपूर्ण कार्यो को कब तक पूर्ण करवा दिया जायेगा? विवरण सदन की मेज पर रखें।

राज्य मंत्री, स्वायत्त शासन (श्री झाबर सिंह खर्रा): (1) नगर पालिका भोपालगढ़ द्वारा जून, 2021 से मई, 2024 तक की अवधि में करवाये गये कार्यों का सम्पूर्ण विवरण परिशिष्ट 'अ' पर संलग्न है।

(2) जी हां। अपूर्ण रहे कार्यों की सूची परिशिष्ट 'ब' पर संलग्न है।

अपूर्ण रहे कार्यों को पूर्ण करवाये जाने की अवधि का विवरण परिशिष्ट 'ब' की सूची में अंकित है।

श्रीमती गीता बरवड़ (भोपालगढ़): एक पूरक क्वेश्चन है। भोपालगढ़ में सिद्धेश्वर तालाब है, उसमें 49 लाख रुपये का आदेश हुआ। इसमें 50 परसेंट काम 12.01.2022 तक हो गया और 50 परसेंट काम अभी बाकी है और अब 2024 चल रहा है। दो-तीन साल हो चुके हैं, लेकिन अभी तक यह काम पूरा नहीं हुआ है। जो जिम्मेदार अधिकारी हैं, ठेकेदार हैं, क्या आप इनके खिलाफ कोई कार्यवाही करवाना चाहते हैं और यह काम कब तक पूरा हो जायेगा?

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी। माननीय सदस्य, विराजें, आपने पूछ लिया, फिर दुबारा पूछ लेना, खड़े मत रहो। माननीय सदस्य, प्रश्न काल में अपनी सीट नहीं छोड़ें।

श्री झाबर सिंह खर्रा (राज्य मंत्री, नगरीय विकास): माननीय विधायक महोदया ने जो प्रश्न पूछा है। जो कार्य अपूर्ण हैं, उनके कार्यादेश के अनुसार कार्य की समाप्ति दिनांक एवं नगरपालिका द्वारा कार्य निर्धारित अवधि में पूर्ण नहीं किये जाने पर दिये गये नोटिस का

ब्यौरा भी आपके जवाब में शामिल है।

श्रीमती गीता बरवड़ (भोपालगढ़): नोटिस 2022 में दिया गया था। उसके बावजूद भी अभी 2024 चल रहा है।

श्री अध्यक्ष: पहले पूरा जवाब सुन लीजिये, उसके बाद दूसरा प्रश्न पूछना।

श्री झाबर सिंह खर्रा (राज्य मंत्री, नगरीय विकास): मैं विधायक महोदया को और सदन को आश्वस्त करना चाहूंगा कि जिस भी संवेदक ने कार्यादेश प्राप्ति के बाद निर्धारित अवधि में कार्य पूर्ण नहीं किया, उसके खिलाफ नियमों के अनुसार दण्डात्मक कार्यवाही करके जो भी पैनल्टी लगायी जायेगी, वह लगायेंगे।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न। श्री भागचन्द टांकड़ा।

बांदीकुई में परिवहन कार्यालय की स्थापना

362. श्री भागचन्द टांकड़ा (बांदीकुई): क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या सरकार द्वारा उप परिवहन कार्यालय खोलने के प्रावधान/मापदण्ड/दिशा-निर्देश निर्धारित किए गए हैं? यदि हां, तो विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार विधान सभा क्षेत्र बांदीकुई में उप परिवहन कार्यालय खोलने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

परिवहन मंत्री (डॉ. प्रेम चन्द बैरवा): (1) जी हां। उप परिवहन कार्यालय खोलने हेतु परिवहन एवं सड़क सुरक्षा विभाग द्वारा मापदण्ड निर्धारित हैं, जिसकी प्रति परिशिष्ट-1 पर संलग्न हैं।

(2) उप परिवहन कार्यालय खोलने हेतु विभागीय मापदण्डों के आलोक में परीक्षण करवाकर आमजन की आवश्यकता अनुसार बांदीकुई में उप परिवहन कार्यालय खोले जाने के संबंध में जनहित में निर्णय लिया जाएगा।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य।

श्री भागचन्द टांकड़ा (बांदीकुई): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय उप मुख्य मंत्री महोदय को अवगत कराना चाहूंगा कि बांदीकुई उपखण्ड मुख्यालय पर आपके द्वारा दिये गये जवाब में परिशिष्ट संख्या 1 के बिन्दु संख्या 2 को पूर्ण करता है। ऐसी स्थिति में सरकार बांदीकुई में उप परिवहन कार्यालय खोलने पर विचार रखती है। यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

डॉ. प्रेम चन्द बैरवा (उप मुख्य मंत्री): अगर मापदण्ड पूरे रखते हैं तो निश्चित रूप से आपके इस कार्यालय पर विचार किया जायेगा।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न, श्री यूनुस खान।

डीडवाना में संचालित आर.ओ. प्लांट

363. श्री यूनुस खान (डीडवाना): क्या जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र डीडवाना में आर.ओ. प्लांट संचालित हैं? यदि

हां, तो कहां-कहां एवं कब से स्थापित हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त आर.ओ. प्लांट में से कितने चालू व कितने बन्द हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त आर.ओ. प्लांट किन-किन संवेदकों को किन नियमों से कितने समय के लिए दिए गए हैं? फर्म के नाम एवं किये गये भुगतान सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या सरकार उक्त आर.ओ. प्लांट के सुचारु संचालन के लिए कोई योजना बनाने का विचार रखती है? यदि हां, तो क्या व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री (श्री कन्हैयालाल): (1) जी हां, विधान सभा क्षेत्र डीडवाना में भू-जल में गुणवत्ता से प्रभावित ग्रामों में अल्पकालीन समाधान के लिये 4 चरणों में कुल 94 आर.ओ. संयंत्र स्थापित कर संचालित किए गए हैं। आर.ओ. संयंत्र का विवरण परिशिष्ट अ पर संलग्न है।

(2) विधान सभा क्षेत्र डीडवाना में 68 आर.ओ. संयंत्रों की संचालन एवं संधारण अवधि समाप्त होने एवं इन ग्रामों को इंदिरा गांधी नहर आधारित वृहद् पेयजल परियोजना से लाभान्वित होने के कारण इनकी आवश्यकता नहीं होने के मद्देनजर वर्तमान में बंद हैं। शेष 26 आर.ओ. संयंत्र स्थापित करने वाली फर्म द्वारा नियमित रूप से उनका संचालन एवं संधारण किया जा रहा है। उक्त संधारण के अंतर्गत समस्त प्रकार की मरम्मत भी सम्मिलित है। स्थानवार आर.ओ. संयत्र का विवरण परिशिष्ट ब में निहित है।

(3) विधान सभा क्षेत्र डीडवाना के भू-जल की गुणवत्ता प्रभावित ग्रामों में 4 संवेदकों के माध्यम से 94 आर.ओ. संयंत्र स्थापित किये गये हैं, अनुबंध अनुसार संयंत्र स्थापित करने के पश्चात 7 साल का संचालन एवं संधारण भी सम्मिलित है। विवरण परिशिष्ट ब पर संलग्न है।

(4) आर.ओ. संयंत्र स्थापित समस्त ग्राम इंदिरा गांधी नहर आधारित वृहद् पेयजल परियोजना से लाभान्वित हो जाने एवं उक्त आर.ओ. संयंत्रों का 7 वर्षीय अनुबंध अवधि समाप्त होने के उपरांत इन्हें निरंतर संचालित रखने का कोई औचित्य नहीं होने के कारण कोई योजना विचाराधीन नहीं है।

श्री यूनुस खान (डीडवाना): उत्तर आ गया है, मैं पूरक पूछ लेता हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, उत्तर आया है उसके लिए तो धन्यवाद। माननीय अध्यक्ष जी, मेरा आपसे आग्रह रहेगा कि सवाल के उत्तर हमें सुबह मिलते हैं। जब घर से निकलते हैं, तब मिलते हैं, तो पढ़ने का समय नहीं होता है। मैंने यहां पढ़ा है। फिर भी आपके माध्यम से यह कहना चाहूंगा कि थोड़ा-सा जल्दी मिल जायेगा तो ठीक रहेगा।

मैंने अभी पढ़ा है तो इसमें इन्होंने कहा है कि अनुबंध की अवधि सात वर्ष है और जो एनेक्सर लगाया है, उसमें आठ वर्ष लिखा हुआ है। एक तो यह है। दूसरा, इन्होंने लिखा है कि आर.ओ. प्लांट का संचालन है, उसमें 'संचालन' की जगह 'पूर्ण' लिख दिया है। दो ऐसे हैं। कार्यादेश हो गये 12.02.2017 में और कार्य चालू उसके एक साल बाद हुआ है। कार्यादेश बाद में हुआ है और कार्य चालू एक साल पहले हो गया। यह जवाब में आया है। इसलिए मेरा

निवेदन है कि ये दो-तीन चीजें मैंने अभी यहां आकर पढ़ी हैं। मैं जब रास्ते में आ रहा था तो स्टाफ ने कहा कि सुबह..।

श्री अध्यक्ष: मैं एक जानकारी दे दूं। वैसे प्रश्न का उत्तर रात्रि तक पहुंचाने की व्यवस्था कर रखी है। कल पूरे जयपुर में तेज बरसात तेज थी, इस कारण से हो सकता है कि आपको लेट मिला हो।

श्री यूनुस खान (डीडवाना): अध्यक्ष महोदय, हमारा निवेदन है कि सिर्फ दो दिन पहले मिल जाये तो हम पढ़ लें। आपके नोटिस में थोड़ा-सा यह डालना था।

इसमें एक तो यह है कि आठ वर्ष है और आपने सात वर्ष लिखा है। अवधि आठ वर्ष की है।

श्री अध्यक्ष: पहले नहीं आता था, अब शुरू किया है।

श्री यूनुस खान (डीडवाना): मेरा आपसे निवेदन यह है कि क्या बन्द पड़े आर.ओ. संयंत्र को सरकार चालू करने का विचार रखती है? क्योंकि आपने बताया है कि लगभग 68 आर.ओ. ऐसे हैं, जो बन्द हो गये और 26 आर.ओ. ऐसे हैं, जो कि अभी चालू हैं। गवर्नमेंट का बहुत बड़ा पैसा लग गया। 12 करोड़ 25 लाख रुपये लगे हुए हैं। अभी वे अच्छी स्थिति में हैं। इसलिए क्या सरकार इसको चालू करने का इरादा रखती है और जो बन्द हो गये, उनका ऑपरेशन करेगी या वे वहीं पड़े रहेंगे? यह मेरा आपसे निवेदन है।

mdp/rtm/02.08.2024/11:30/1d

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी।

श्री कन्हैयालाल (जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो प्रश्न में 7 वर्ष, 8 वर्ष जो बोला है, मैं बैठकर चैक कर लूंगा, अगर उनमें एक वर्ष बाकी होगा तो उनको रेगुलर हम चालू करेंगे। दूसरी चीज, जो लगभग 94 आर ओ थे, इनमें से वर्तमान में 68 आर ओ संयंत्र बंद हैं। आर ओ संयंत्र स्थापित, समस्त इंदिरा गांधी नहर आधारित वृहत पेयजल परियोजना से लाभान्वित हो जाने एवं उक्त आर ओ संयंत्रों की सात वर्षीय अनुबंध अवधि समाप्त हो जाने के कारण बंद है।

जी हां। अनुबंध संयंत्र स्थापित करने के पश्चात सात साल का संचालन एवं संधारण अवधि समाप्त होने के पश्चात इनकी आवश्यकता नहीं होने के कारण बंद किया जाना प्रस्तावित है। प्रथम, द्वितीय और चतुर्थ चरण के अंतर्गत स्थापित 92 आर ओ संयंत्रों को विभागीय नियमानुसार अनुपयोगी घोषित कर निर्धारित प्रक्रिया द्वारा नीलामी द्वारा निस्तारित किया जाना प्रस्तावित है। तृतीय चरण के दो आर ओ संयंत्रों को अनुबंध की शर्तों के अनुसार कार्यकारी फर्म को सुपुर्द किया जाना प्रस्तावित है।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य।

श्री यूनुस खान (डीडवाना): माननीय अध्यक्ष जी, मेरा दूसर सप्लीमेंट्री यह है कि अभी तो प्रस्तावित है। मेरा निवेदन है कि बहुत बड़ी प्रोपर्टी है। मंत्री महोदय, अगर मीटिंग बुलाएंगे

तो मैं भी आ जाऊंगा। मेरा दूसरा यह है कि इस जवाब में इन्होंने यह कहा है कि इंदिरा गांधी नहर का पानी आ गया। मेरा आपके माध्यम से आग्रह है कि पानी तो आ गया, ये बात सही है और सरकार कोशिश भी कर रही है, लेकिन हमको 40 एमएलडी पानी अलॉट है, उसमें से 28 एमएलडी पानी हमको मिल रहा है। ग्रामीण क्षेत्र का 32 है, उसमें ग्रामीण क्षेत्र का कम है, लगभग 22 एमएलडी के करीब पानी मिल रहा है। पानी भी नहीं आ रहा है, आरओ भी बंद हो गये। मेरा आग्रह है कि वह जो हमारा बाकी 12 एमएलडी पानी है, उसके लिए सरकार क्या व्यवस्था करेगी? क्योंकि इस जवाब में आया है तो मेरा माननीय मंत्री जी से आपके माध्यम से निवेदन है कि थोड़ा-सा इसको आप, क्योंकि हमारे प्रभारी मंत्री भी हैं, अच्छे इंसान है, मुझे उम्मीद है कि जो हमारा 12 एमएलडी पानी है, उसको ये पूरा करेंगे।

श्री अध्यक्ष: ये अच्छे हैं, आप भी अच्छे हैं। अगला प्रश्न। आप बताएंगे।

श्री कन्हैयालाल (जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री): अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य का सही कहना है कि अभी हमें जितना पानी मिलना चाहिए था, उतना पानी वहां से हम राजस्थान केनाल से ले नहीं पा रहे हैं, उसके लिए हमने टेंडर्स लगाएं हैं। कोई सिस्टम में मोटर लगाना या पम्प हाउस बनाना या उनके लिए हम टेंडर लगाते हैं, वह पूरा पानी नागौर और डीडवाना के सभी विधान सभाओं में हम आने वाले 6 महीने के अन्दर उसकी व्यवस्था करके देंगे।

दूसरी चीज, आप ये कह रहे हैं कि ये सही स्थिति में है तो आपसे निवेदन है कि आप बैठकर अगर कोई ग्राम पंचायत इनको लेना चाहती हो, उनको हम हैंडओवर कर सकते हैं, या विभाग इस पर विचार कर रहा है कि इसका किस तरह से दोबारा ओएंडएम हम किसी कंपनी को देते हुए दोबारा जहां आप बताएंगे, जिन गांवों के अन्दर, जहां आवश्यकता है, क्योंकि ये आरओ लगभग पर-ऑवर 20 लीटर 10 पैसे या 20 पैसे, इसमें दरें अलग-अलग निश्चित कर रखी थी तो कई जगह पर, कई गांव वाले, वह जो कार्ड लगाना, वह नहीं था, हम डायरेक्ट भी दे सकते हैं। गांव वाले चाहे तो उसको फ्री में भी चला सकते हैं। उसके संधारण के लिए लगभग 94 हैं, हमने इनका मोटा-मोटा निकाला है, ओएंडएम का 52 हजार रुपये पर-इयर एक का खर्चा आता है। विभाग उसको वहन करने के लिए तैयार है। उसको चलाने के लिए कोई व्यवस्था हो आप हमें बता देना, बिलकुल सौ प्रतिशत जनता के हित में करेंगे।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न। श्री शत्रुघन गौतम।

विभाग को आवंटित बजट से अतिरिक्त जारी निविदाएं

364. श्री शत्रुघन गौतम (केकड़ी): क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) प्रदेश में जल संसाधन विभाग का वर्ष 2023-2024 में कितना बजट आवंटित किया गया था? क्या आवंटित बजट के अतिरिक्त निविदा जारी की गई है? यदि हां, तो किस नियम के तहत एवं किस फर्म को निविदा जारी की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि विभाग द्वारा बजट से अधिक नियम विरुद्ध स्वीकृति जारी की

है? यदि हां, तो सरकार संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

(3) धौलपुर में जी.वी.पी.आर. को कौनसा कार्य किस दर पर दिया गया? विवरण सदन की मेज पर रखें।

जल संसाधन मंत्री (श्री सुरेश सिंह रावत): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से केकड़ी से आने वाले माननीय सदस्य को बताना चाहूंगा कि (1) प्रदेश में जल संसाधन विभाग को योजनाओं हेतु वर्ष 2023-24 के लिए संशोधित अनुमान के अनुसार राशि रुपये 4854.36 करोड बजट आंवटित किया गया था। विभाग द्वारा परियोजनाओं की डी.पी.आर. तैयार कर प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति जारी की जाती है। इन परियोजनाओं को पूर्ण करने की अवधि सामान्यत: एक वर्ष से अधिक होती है, जिससे बजट की मांग वर्षवार, अनुमानित की जाती है तथा परियोजना पर कार्य करवाये जाने हेतु निविदा/निविदाएं आंमत्रित की जाती हैं। आमंत्रित निविदाओं की कुल राशि उस कार्य हेतु स्वीकृत प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति की सीमा तक होती है, परन्तु आंमत्रित की गई निविदा/निविदाओं की कुल राशि उस वर्ष हेतु आंवटित बजट से अधिक होना स्वभाविक है। वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान स्वीकृत संशोधित बजट अनुमान के अनुसार राशि रुपये 4854.36 करोड के विरूद्ध राशि रुपये 3726.79 करोड व्यय किये गये।

(2) जल संसाधन विभाग द्वारा परियोजनाओं/कार्यो की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति उपरांत निविदा आंमत्रित कर सक्षम स्तर से स्वीकृति उपरांत कार्यादेश जारी किया जाता है। परियोजनाओं/कार्यो को पूर्ण करने की अवधि सामान्यत: एक वर्ष से अधिक होती है, जिस हेतु वर्षवार बजट की मांग अनुमानित की जाती है। वित्तीय वर्ष 2023-24 में विभाग के अन्तर्गत स्वीकृत सभी परियोजनाओं की कुल लागत उस वर्ष के दौरान इन परियोजनाओं हेतु आंवटित बजट से अधिक होना स्वाभाविक है। अत: स्वीकृतियाँ नियमानुसार जारी किये जाने से किसी अधिकारी के विरुद्ध कोई कार्रवाई प्रस्तावित नहीं है।

(3) धौलपुर जिले में जल संसाधन विभाग द्वारा संवेदक जीवीपीआर को कालीतीर लिफ्ट सिंचाई परियोजना का कार्यादेश ईपीसी आधार पर अनुमानित राशि से 8.92% Below पर वर्ष 2023-24 के दौरान दिया गया।

धौलपुर लिफ्ट सिंचाई परियोजना का कार्यादेश ईपीसी आधार पर मैसर्स जीवीपीआरईएल-कृष्णा कारपोरेशन (Joint Venture) हैदराबाद को अनुमानित राशि से 0.19% Below पर वर्ष 2017-18 के दौरान दिया गया।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य।

श्री शत्रुघन गौतम (केकड़ी): माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि धौलपुर में कालीतीर लिफ्ट परियोजना जो 650 करोड़ रुपये के कार्यादेश थे। इसमें अधिकतम पाइप का काम है और जो पाइप एस्टीमेट के तकमीने में लिये गये हैं, क्या वे ही पाइप काम में लिये या पाइप की डिजाइन चेंज कर दी गयी? यदि पाइप की

डिजाइन चेंज की गयी तो किस आदेश से की गयी, क्यों की गयी? जरा सदन को बताएं।

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी।

श्री सुरेश सिंह रावत (जल संसाधन मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से केकड़ी से आने वाले माननीय सदस्य को बताना चाहता हूंकि जल संसाधन विभाग द्वारा धौलपुर लिफ्ट सिंचाई एवं पेयजल परियोजना हेतु इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, बैंगलोर द्वारा तकनीकी अध्ययन के आधार पर ही पाइप की थिकनेस नियत की गयी थी। परंतु माननीय सदस्य ने जो विषय उठाया है, मैं उसकी जांच हेतु एक कमेटी गठित करके, जांच करके अगर कोई दोषी होगा तो उसके खिलाफ कार्यवाही करेंगे और फर्म के खिलाफ भी कार्यवाही करेंगे।

श्री शत्रुघन गौतम (केकड़ी): माननीय अध्यक्ष महोदय, क्या यह सही है कि पूर्ववर्ती सरकार ने 650 करोड़ का जीवीपीआर कंपनी को यह काम दिया। इसमें केवल दो कांट्रेक्टर आए और जो एक कांट्रेक्टर जीवीपीआर है, वह मध्य प्रदेश व अन्य राज्यों में ब्लेक लिस्टेड है। सरकार की ऐसी क्या मजबूरी थी कि जीवीपीआर को काम देना पडा। क्या इसकी जांच करवाकर कुछ कार्यवाही करने की सरकार इच्छा रखती है? यदि हां, तो कब तक, नहीं तो क्यों?

श्री सुरेश सिंह रावत (जल संसाधन मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से केकड़ी से आने वाले माननीय सदस्य को बताना चाहता हूं कि जो विषय आपके द्वारा संज्ञान में लाया गया है, जब निविदाएं आमंत्रित की जाती है तो कांट्रेक्टर से एक शपथ पत्र लिया जाता है। उस शपथ पत्र के अन्दर ये सारी बातें लिखी होती हैं। अगर उसने शपथ पत्र में गलत लिखा है तो हम इसकी जांच करवा कर कार्यवाही करेंगे।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न। श्री गोरधन।

अनुसूचित जाति व जनजाति छात्रों को छात्रवृत्ति

365. श्री गोरधन (धोद): क्या सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) सरकार द्वारा अनुसूचित जाति व जनजाति श्रेणी के छात्रों को कौन-कौनसी छात्रवृत्तियां किस-किस योग्यता के आधार पर कितनी कितनी दी जाती है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) सरकार द्वारा जनवरी 2019 से दिसम्बर 2023 तक कितने छात्रों को किन-किन श्रेणी में छात्रवृत्ति प्रदान की गई? वर्तमान में वंचित छात्रों को कब तक छात्रवृत्ति प्रदान कर दी जायेगी? संख्यात्मक विवरण सदन की मेज पर रखें।

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री (श्री अविनाश गहलोत): (1) सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों को देय उत्तर मैट्रिक छात्रवृति योजनाओं की योग्यता/पात्रता एवं वार्षिक आय सीमा का योजनावार विवरण परिशिष्ट 'अ' पर संलग्न है एवं योजनवार देय राशि का विवरण परिशिष्ट 'ब' पर संलग्न है।

(2) विभाग द्वारा संचालित अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति उत्तर मैट्रिक छात्रवृति योजनाओं के अन्तर्गत जनवरी, 2019 से दिसम्बर, 2023 तक के छात्रवृति वितरित विद्यार्थियों की संख्या एवं लम्बित आवेदन पत्रों का वर्षवार विवरण परिशिष्ट 'स' पर संलग्न है।

लम्बित छात्रवृति आवेदनों को भुगतान पात्रता एवं बजट उपलब्धता के आधार पर किया जाता है। तदनुसार सभी लम्बित आवेदनों का निस्तारण किया जावेगा।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य।

श्री गोरधन (धोद): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि जो केन्द्र सरकार और राज्य सरकार के द्वारा 60:40 के रेशियो में जो छात्रवृत्ति दी जाती है, क्या उन छात्रवृत्तियों को आप एक साथ करके छात्रवृत्ति देने का श्रम कर सकते हैं? दूसरा मेरा इसी में एक क्वेश्चन है कि हमारे जो सीकर जिले में ओबीसी का एक छात्रावास बना हुआ है, अन्य पिछड़ा वर्ग का, जिसमें संभागीय आयुक्त का कार्यालय चल रहा है, मेरा निवेदन यह है कि उस छात्रावास को कब तक चालू करेंगे?

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी।

श्री अविनाश गहलोत (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, धोद से आने वाले माननीय सदस्य ने दो सवाल लगाए हैं। पहला, जो रेशियो है केन्द्र का, राज्य सरकार का, यह पहले से तय आ रहा है। आप कहेंगे तो मैं उसकी डिटेल जानकारी दे दूं। दूसरा, जो आपने पूछा सीकर मुख्यालय पर, माननीय अध्यक्ष महोदय, अक्सर ऐसा होता है, पिछली गवर्नमेंट के समय कि जब सरकारें चलती हैं सचिवालय से और मुख्य मंत्री कार्यालय से, लेकिन जिसका उद्देश्य होता है, उस उद्देश्य के विपरीत आपने पिछले बजट में घोषणा की थी सीकर संभाग की, हमारे छात्रों के लिए ओबीसी का जो एक हॉस्टल बना हुआ है, उसमें छात्र नहीं रह रहे हैं, लेकिन वहां सीकर संभाग मुख्यालय आपने खोल दिया है। निश्चित ही माननीय सदस्य की जो भावना है, उसके अनुसार आगे आने वाले समय में हम बैठकर इस सम्बन्ध में बातचीत करेंगे। ये जो हॉस्टल जिस उद्देश्य से बना है 2021-22 में, उसको जैसे ही हमारे संभाग मुख्यालय की बिल्डिंग बन जाएगी, उसके बाद में छात्रावास में उसका परिवर्तन कर दिया जाएगा।

श्री अध्यक्ष: आपका हो गया।

Ans/rtm 11.40 1e 02.08.2024

श्री गोरधन (धोद): माननीय अध्यक्ष महोदय, सीएम उच्च शिक्षा छात्रवृति योजना में जो स्वीकृत बजट है, उसमें 2020-21 से लेकर 2024 तक राशि का आवंटन तो ज्यादा है, लेकिन खर्च क्यों नहीं हुआ, माननीय मंत्री महोदय, इसका भी बताए।

श्री अविनाश गहलोत (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य को आश्वस्त करना चाहता हूं कि चूंकि यह उच्च शिक्षा विभाग से जुड़ा हुआ

प्रश्न है। मैं हमारे डिप्टी सीएम साहब और आपके बीच मध्यस्थता कराकर जो भी उचित फैसला होगा वह करवा देंगे। यह सही है कि पिछली सरकार में उच्च शिक्षा में जितना मूल बजट था, वह पूरा खर्च नहीं हो पाया। हम चाहते हैं कि सरकार जितना बजट आवंटित करे उसका पूरा पैसा लाभार्थियों के खाते में जाए और हमारे छात्रवृति वाले बच्चे हैं उनको उसका लाभ मिले।

श्री अध्यक्षः अगला प्रश्न। श्रीमती दीप्ति किरण माहेश्वरी

राजसमन्द में खाद्य सुरक्षा योजना के प्राप्त आवेदन

366.श्रीमती दीप्ति किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): क्या खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विधान सभा क्षेत्र राजसमन्द में विगत तीन वर्षों में खाद्य सुरक्षा व प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना में कितने व्यक्तियों ने आवेदन किया? उक्त में से कितने आवेदन स्वीकृत किए गए तथा कितने निरस्त किए गए? वर्षवार संख्यात्मक विवरण सदन की मेज़ पर रखें।

(2) क्या सरकार वंचित पात्र परिवारों को उक्त योजना से लाभान्वित करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक? विवरण सदन की मेज़ पर रखें।

खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री (श्री सुमित गोदारा): (1) विगत तीन वर्षों में माह जनवरी 2022 से आज दिनांक तक विधान सभा क्षेत्र राजसमन्द में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजनान्तर्गत नाम जुडवाने हेतु 6175 व्यक्तियों ने आवेदन किया। उक्त में से 2277 स्वीकृत एवं 703 आवेदन निरस्त किये गये है।

(2) भारत सरकार द्वारा राज्य हेतु निर्धारित सीलिंग 4.46 करोड़ के विरुद्ध शेष रहे स्थान हेतु राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना में लाभार्थियों को सम्मिलित किये जाने हेतु नवीन आवेदन प्राप्त नहीं करके, पूर्व में प्राप्त कुल 19.58 लाख आवेदनों में से लम्बित आवेदन लगभग 13.9 लाख में से परीक्षण पश्चात नाम जोडने की कार्यवाही विभागीय स्तर पर प्रक्रियाधीन है

श्री अध्यक्षः माननीय सदस्य।

श्रीमती दीप्ति किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से जाना चाहूंगी कि राजसमन्द में शेष 3 हजार 195 आवेदन अभी तक लम्बित हैं, उनका क्या कारण हैं? इन शेष आवेदकों के नाम कब तक जोड़े जाएंगे?

श्री अध्यक्षः माननीय मंत्री जी।

श्री सुमित गोदारा (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): माननीय अध्यक्ष जी, मैं राजसमन्द से आने वाली माननीय सदस्या को बताना चाहूंगा कि हमने 13 लाख 90 हजार बाकी हैं उनको जोड़ने की प्रक्रिया शुरू की है। साथ ही मैं सभी माननीय सदस्यों को बताना चाहूंगा कि विशेष योग्यजन, हमने 1 लाख 66 इस पोर्टल में जोड़े। अभी भी लगभग 44 हजार 374 यूनिट, यानी डेढ़ लाख विशेष योग्यजन जो भी आपके क्षेत्र में हैं, जिनका इस खाद्य सुरक्षा में नाम नहीं जुड़ा, वह जाकर पोर्टल पर जुडवाए, उनका नाम स्वत: ही इस योजना में जोड़ दिया जाएगा। बाकी 8 लाख रिक्त स्थान है, उस पर जोड़ना प्रक्रियाधीन है। 13 लाख 90

हजार में से आवेदन लम्बित है, अगर उसमें आपके आवेदन लम्बित है तो 8 लाख लोगों को जोड़ दिया जाएगा, प्राथमिकता से हैं, जो पहले आए हैं उनको।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य।

श्रीमती दीप्ति किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय को धन्यवाद देना चाहूंगी और मैं आपसे यही निवेदन करूंगी कि 13.9 लाख आवेदन अभी तक लम्बित है, इनकी भी जल्दी से जल्दी जोड़ने की कार्यवाही की जाए। यह एक खाद्य सुरक्षा का मैटर है।

श्री अध्यक्ष: प्रश्न।

श्रीमती दीप्ति किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): इसमें आप जल्द से जल्द कार्यवाही करे।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न। श्री उदयलाल।

माण्डल स्थित कपड़ा उद्योगों द्वारा दूषित पानी छोड़ने पर कार्यवाही

367. श्री उदयलाल भडाणा (माण्डल): क्या पर्यावरण राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र माण्डल में कपड़ा उद्योग व प्रोसेस हाउस से केमिकल युक्त काले पानी को नदी व नालों में छोड़ने से किसानों की उपजाऊ भूमि बंजर होती जा रही है? यदि हां, तो इसकी रोकथाम हेतु सरकार की क्या कार्य योजना है? विवरण सदन की मेज़ पर रखें।

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी।

राज्य मंत्री, वन (श्री संजय शर्मा): विधान सभा क्षेत्र माण्डल में कपड़ा उद्योग व प्रोसेस हाउस से केमिकल युक्त काले पानी को नदी व नालों में छोड़ने से किसानों की उपजाऊ भूमि बंजर होने के संबंध में कृषकों/कृषक संगठनों द्वारा कोई शिकायत राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल एवं कृषि विभाग को प्राप्त नहीं हुई है।

यह उल्लेखनीय है कि राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल द्वारा सभी कपडा उद्योगों को शून्य जल निस्त्राव की शर्त पर ही सम्मति दी गयी है।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य।

श्री उदयलाल भडाणा (माण्डल): अध्यक्ष महोदय, बड़े-बड़े अखबारों में, टीवी पर, सब कुछ हो रहा है। मैंने मंत्री महोदय को मोबाइल पर कल वाट्सऐप भी कर दिया।

श्री अध्यक्ष: प्रश्न पूछो। जो आपको पूछना है, प्रश्न पूछो।

श्री उदयलाल भडाणा (माण्डल): मैं यह कहना चाहता हूं कि प्रोसेस हाउस का, बड़ी-बड़ी फैक्ट्रियों का काला पानी छूट रहा है, तो इसको बंद करने के लिए सरकार तत्पर है क्या? कंचन प्रोसेस वाले हैं उन्होंने अपनी फैक्ट्री के अन्दर बोरिंग करवा रखा है और काला पानी उसी में छोड़ रहे हैं। नीचे का भू-स्तर खराब हो रहा है। आस-पास के गांव के लोग हैं...

श्री अध्यक्ष: मैं कह रहा हूं प्रश्न पूछो। यह भाषण का नहीं है। प्रश्न काल और चर्चा में

अंतर है।

श्री उदयलाल भडाणा (माण्डल): या तो आज के बाद प्रश्न ही नहीं पूछेंगे। कोई बात नहीं, आपको जैसा लगता है कर दो, कोई बात नहीं। ठीक है, जैसा आपको लगे। यह कोई बात हुई क्या?

श्री संजय शर्मा (राज्य मंत्री, वन): अध्यक्ष महोदय, माण्डल से आने वाले माननीय सदस्य ने विशेष रूप से उद्योग के नाम की चर्चा की है। उसको लेकर नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी। साथ ही साथ आपने काले पानी की समस्या के बारे में सदन को अवगत कराया, यह ठीक है कि राजस्थान में इस व्यवसाय से जुड़े हुए उद्योग हैं, वह बरसात की आड़ में पहले से ही पानी छोड़ देते हैं, चाहे वह भिवाड़ी की समस्या हो, चाहे पाली से आने वाले माननीय सदस्य हो, चाहे राजसमन्द के सदस्य हो, चाहे लूणी नदी का मामला हो।

माननीय सदस्य ने माण्डल को प्रश्न किया है। मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को यह बताना चाहूंगा, मैं आज इस सदन में घोषणा भी करता हूं कि भीलवाड़ा, पूरे ज़िले की औद्योगिक इकाइयों के लिए जो प्रदूषण की समस्या है, विशेष रूप से कपड़ा प्रोसेसिंग यूनिट है जो पानी छोड़ते हैं, उसको लेकर जिला कलक्टर भीलवाड़ा की अध्यक्षता में चार सदस्यों की समिति का गठन करने की मैं घोषणा करता हूं, जिसमें भीलवाड़ा के प्रदूषण नियंत्रण मण्डल के क्षेत्रीय अधिकारी, जिला उद्योग केन्द्र के अधिकारी एवं कृषि विभाग के जिला अधिकारी को सम्मिलित किया जाएगा। यह समिति सभी माननीय जन प्रतिनिधियों से बात भी करेगी, उनके सुझाव भी लेगी और सारगर्भित सुझाव लेकर, किस प्रकार से प्रदूषण रुके उसकी चिंता करेगी। उसके बावजूद भी उद्योग में प्रदूषण की समस्या को लेकर दोषी पाया गया तो उस उद्योग के खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही भी करेगी।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न। श्री हरलाल सहारण।

श्री उदयलाल भडाणा (माण्डल): अध्यक्ष महोदय, एक..

श्री अध्यक्ष: हो गया। जांच कमेटी हो गई और क्या चाहिए। ...(व्यवधान)...

श्री उदयलाल भडाणा (माण्डल): प्रोसेस हाउस का मैं आपको नाम बता दूंगा, उसके अन्दर बोरिंग करके वह काला पानी उसमें छोड़ रह हैं। जमीन का भू- स्तर खराब हो रहा है।

श्री अध्यक्ष: उसमें जांच कमेटी हो गई ना।

श्री उदयलाल भडाणा (माण्डल): भौतिक सत्यापन कर, मौके पर जाकर बंद कराएंगे क्या? यह कहना चाह रहा हूं।

श्री अध्यक्ष: बताएंगे?

श्री संजय शर्मा (राज्य मंत्री, वन): माननीय सदस्य ने उस उद्योग का नाम भी सदन के अन्दर उल्लेख किया है। मैंने पहले भी कहा कि वह समिति सभी जन प्रतिनिधियों से बात करेगी।

श्री अध्यक्ष: श्री हरलाल सहारण।

प्रश्न संख्या 368

(अनुपस्थित। कृपया आगे देखें।)

अगला प्रश्न। श्री कैलाश चन्द्र वर्मा।

नवीन कॉलोनियों में मूलभूत सुविधाएं

369. श्री कैलाश चन्द वर्मा (बगरू): क्या नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) प्रदेश में नवीन कॉलोनियां विकसित करने संबंधी क्या नियम निर्धारित किए गए हैं? विवरण सदन की मेज़ पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि कॉलोनाईजर्स द्वारा बिना मूलभूत सुविधाओं के ही कॉलोनियां काटी जा रही हैं? यदि हां, तो उक्त कॉलोनियों में आमजन को मूलभूत सुविधायें उपलब्ध करवाने हेतु सरकार की क्या कार्य योजना है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

राज्य मंत्री, नगरीय विकास एवं आवासन (श्री झाबर सिंह खर्रा): (1) नवीन कालोनियां विकसित करने हेतु तकनीकी प्रावधान "राजस्थान टाउनशिप पालिसी-2010" के द्वारा निर्धारित है।

(2) जी नही।

टाउनशिप पॉलिसी-2010 के प्रावधानों के अनुरूप मूलभूत सुविधा की सुनिश्चितता उपरान्त ही नगरीय निकाय में प्राप्त होने वाली योजनाओं को अनुमोदित किया जाता है।

वर्तमान टाउनशिप पॉलिसी-2010 के अनुसार योजना में आन्तरिक विकास कार्यो यथा सड़क, सीवरेज एवं पानी आदि की सुनिश्चितता हेतु पॉलिसी में 12.5 प्रतिशत भूखण्ड रहन रखे जाने का प्रावधान है। आन्तरिक विकास कार्यों की सुनिश्चितता उपरान्त ही इन भूखण्डों को रहन मुक्त किया जाता है, जिसकी प्रति परिशिष्ट 'अ' पर संलग्न है।

राज्य के नगरीय क्षेत्रों में कॉलोनाइजर द्वारा बिना मूलभूत सुविधाओं के काटी जा रही अवैध कॉलोनियों के संबंध में नगरीय निकाय में शिकायत प्राप्त होने पर उचित कार्यवाही की जाती है।

टाउनशिप पॉलिसी-2010 में संशोधन हेतु सुझाव आमंत्रित किये गये है। प्रारूप पॉलिसी वर्तमान में पब्लिक डोमेन में उपलब्ध है। समस्त सुझावों पर विचार कर नई संशोधित पॉलिसी जारी की जावेगी।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य।

श्री कैलाश चन्द वर्मा (बगरू): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहूंगा, क्या यह सही है जेडीए जोन-10 स्थित खो-नागोरियान में स्थित खसरा नम्बर 1954 से 1958 जो सरकारी पॉल व तालाब पेटा भूमि पर आवासीय भूमि काटी जा रही है, इस पर कार्यवाही की सरकार की क्या मंशा है? अगर है तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी।

श्री झाबर सिंह खर्रा (राज्य मंत्री, नगरीय विकास): अध्यक्ष महोदय, मैं आपके मार्फत

माननीय विधायक जी को और सदन को आश्वस्त करना चाहूंगा कि इन्होंने जिस सरकारी भूमि पर कॉलोनी काटे जाने के बारे में सदन के सामने अवगत करवाया है, उसकी जानकारी करवाकर, अगर वास्तव में सरकारी भूमि पर किसी के द्वारा कॉलोनी काटी गई है, तो उस कॉलोनी को ध्वस्त करने के साथ-साथ, जिसके द्वारा कॉलोनी काटी गई है, उसके खिलाफ विधि के अनुसार निश्चित रूप से कार्यवाही भी की जाएगी।

श्री अध्यक्ष: और पूछना है? बाकी रह गया?

श्री कैलाश चन्द वर्मा (बगरू): माननीय अध्यक्ष जी, मेरा दूसरा पूरक क्वेश्चन है। क्या यह सही है कि जेडीए द्वारा कॉलोनियों को अनुमोदित करने के दौरान सड़क, सीवरेज सहित विभिन्न सुविधाओं के लिए राशि जमा की जाती है, यदि हां तो कितनी अवधि में, उक्त सुविधाएं उपलब्ध कराये जाने का प्रावधान है? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी।

VPS-RTM-02.08.202-11.50-1f

श्री झाबर सिंह खर्रा (राज्य मंत्री, नगरीय विकास): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके मार्फत माननीय विधायक और माननीय सदन को यह बताना चाहूंगा कि पिछले समय में जितनी कॉलोनियां विकसित हुईं और उनमें जितना विकास शुल्क जमा हुआ उसमें बहुत सी जगह वास्तव में विकास नहीं हो पाया। उसका कारण यह था कि जो सड़कें बननी थीं, जो सेक्टर रोड्स बननी थीं, उनका मार्ग निर्धारण सही तरीके से नहीं हो पाया और उसके कारण हमारी बहुत सी सड़कें और सेक्टर रोड्स मार्ग निर्धारण नहीं होने की वजह से निर्मित नहीं हो पाये। इसी के लिए हम टाउनशिप पॉलिसी 2010 में जो परिवर्तन करने जो रहे हैं और उसमें मैंने मेरे विभाग की अनुदान मांगों के जवाब में भी सभी माननीय सदस्यों से यह निवेदन किया था कि आप अपने-अपने सुझाव दें और हम जो तीन पॉलिसीज में परिवर्तन करने का प्रयास कर रहे हैं, उसमें सुझाव देने की अंतिम तिथि 20 अगस्त, 2024 निर्धारित कर दी है। सारे के सारे यू.डी.एच. विभाग की जो वेबसाइट है, https://udh.rajasthan.gov.in, उस पर यह उपलब्ध है और साथ ही मैं सदन को यह भी आश्वस्त करना चाह रहा हूं कि हमने इन सारी समस्याओं के समाधान के लिए यह संशोधन करने के साथ-साथ राज्य स्तर पर एक वेब-पोर्टल बनाया जाना भी प्रस्तावित है जिस पर स्थानीय निकाय द्वारा स्वीकृत सभी योजनाओं का पूरा विवरण दर्ज करने का विचार है तथा विकासकर्ता द्वारा इस पोर्टल पर योजना में किये जा रहे विकास कार्यों व अन्य विवरण को नियमित रूप से पोर्टल पर अपडेट करना होगा जिससे किसी भी समय आमजन व राज्य सरकार को योजनाओं की वास्तविक स्थिति की जानकारी हो सकेगी, हम यह भी प्रयास करेंगे।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न। श्री धर्मपाल।

श्री जीवाराम चौधरी (सांचोर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा एक सुझाव है।

श्री अध्यक्षः नो। अगला प्रश्न, श्री धर्मपाल। आपका प्रश्न नहीं है। श्री धर्मपाल।

श्री जीवाराम चौधरी (सांचोर): ये सुझाव मांग रहे हैं।

श्री अध्यक्षः अभी सुझाव आपसे नहीं मांगा है। आपसे नहीं मांगा है, आप विराजिये।

श्री झाबर सिंह खर्रा (राज्य मंत्री, नगरीय विकास): आप सुझाव लिखित में भिजवा दीजिए।

श्री अध्यक्षः माननीय मंत्रीजी। माननीय मंत्रीजी, कोई बीच में बोले तो उत्तर नहीं देना है।

खेतड़ी में पॉलिटेक्निक कॉलेज की स्थापना

370. श्री धर्मपाल (खेतड़ी): क्या तकनीकी शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र खेतड़ी के उप खण्ड मुख्यालय पर पॉलिटेक्निक कॉलेज नहीं है? यदि हां, तो क्या सरकार उप खण्ड मुख्यालय खेतड़ी में महिला पॉलिटेक्निक कॉलेज खोलने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

तकनीकी शिक्षा मंत्री (डॉ. प्रेम चन्द बैरवा): जी नहीं। वर्तमान में खेतड़ी उप खण्ड मुख्यालय पर 01 निजी पॉलिटेक्निक, विवेकानन्द पॉलिटेक्निक कॉलेज संचालित है जो विद्यार्थियों के प्रवेश की न्यून स्थिति के कारण बंद होने की कगार पर है।

खेतड़ी के उपखण्ड मुख्यालय पर महिला पॉलिटेक्निक कॉलेज संचालित नहीं है। राज्य में राजकीय महिला पॉलिटेक्निक कॉलेज अभी तक केवल पुराने संभाग मुख्यालयों पर ही संचालित है जिनमें भी गत तीन वर्षों में औसतन 51 प्रतिशत प्रवेश ही हुए है।

वर्तमान में विधान सभा क्षेत्र खेतड़ी के उपखंड मुख्यालय पर राजकीय महिला पॉलिटेक्निक महाविद्यालय खोलने का कोई प्रस्ताव विभाग में विचाराधीन नहीं है ।

भविष्य में संभाग मुख्यालयों के अतिरिक्त जिला एवं उपखंड मुख्यालयों पर महिला पॉलिटेक्निक खोले जाने का निर्णय क्षेत्र की मांग, वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता एवं गुणावगुणों के आधार पर किया जा सकेगा।

श्री धर्मपाल (खेतड़ी): माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे पास उत्तर आ गया है मंत्री महोदय का, मेरे सीधे-सीधे दो सवाल हैं।

श्री अध्यक्षः हां, आप पूरक प्रश्न पूछें। यह अच्छा है, आप सीधे ही पूछें।

श्री धर्मपाल (खेतड़ी): खेतड़ी में एशिया का सबसे बड़ा तांबा संयंत्र है इस लिहाज से वहां पर तकनीकी शिक्षा की बहुत ज्यादा जरूरत है। मैं सीधा पूरक प्रश्न नम्बर एक यह पूछना चाहता हूं कि क्या वहां पर तकनीकी शिक्षा उपलब्ध करवाने के लिए मंत्री महोदय, इंजीनियरिंग कॉलेज या पॉलिटेक्निक कॉलेज खोलने का विचार रखते हैं? सहानुभूतिपूर्वक यदि खोलने का विचार रखते हैं तो आप निश्चित रूप से बतायें।

डॉ. प्रेम चन्द बैरवा (उप मुख्य मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी वहां पर कोई विचार नहीं है क्योंकि वहां पर एक प्राइवेट पॉलिटेक्निक कॉलेज खुली हुई है और वह भी बंद की कगार पर है। निश्चित रूप से अगर वहां पर फिजिबिलिटी उपलब्ध होगी तो विचार करेंगे।

मैं आपको यह भी बता दूं कि खेतड़ी उपखंड कार्यालय में महिला पॉलिटेक्निक कॉलेज खोलने का भी कोई प्रस्ताव इसलिए नहीं है क्योंकि सम्भाग मुख्यालय पर ही अभी कन्या पॉलिटेक्निक महाविद्यालय खोले जा रहे हैं अगर उपखंड पर या जिला स्तर पर खोले जाएंगे तब इस पर विचार कर लिया जायेगा।

श्री धर्मपाल (खेतड़ी): पूरक प्रश्न नम्बर दो, मेरे खेतड़ी विधान सभा क्षेत्र में एक राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्र चलता है, उसमें दो-तीन ट्रेड बढ़ाने का विचार रखते हैं?

श्री अध्यक्ष: विराजिये। वे उत्तर देंगे पर आप बैठोगे तो उत्तर देंगे।

डॉ. प्रेम चन्द बैरवा (उप मुख्य मंत्री): आपके वहां पर ऐसा कोई आप मुझे बता दें अगर फिजिबिलिटी होगी तो निश्चित रूप से खोलने का विचार होगा।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न। श्री विद्याधर सिंह।

श्री विद्याधर सिंह (फुलेरा): माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा उत्तर आ गया है।

श्री अध्यक्ष: पहले आप प्रश्न संख्या बोलें।

फुलेरा में पेयजल आपूर्ति

371. श्री विद्याधर सिंह (फुलेरा): क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र फुलेरा में वर्तमान में पेयजल की आपूर्ति कम मात्रा में एवं अधिक अन्तराल में की जा रही है? यदि हां, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) सरकार द्वारा उक्त विधान सभा क्षेत्र में स्वीकृत पेयजल की आपूर्ति के लिए क्या कार्ययोजना प्रस्तावित है एवं कब तक नियमित रूप से स्वीकृत पानी उपलब्ध करा दिया जायेगा? विवरण सदन की मेज पर रखें।

जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री (श्री कन्हैयालाल): (1) विधान सभा क्षेत्र फुलेरा में कुल 163 गांव एवं 3 कस्बे सांभरलेक, फुलेरा एवं किशनगढ-रेनवाल है। विधानसभा क्षेत्र फुलेरा के 163 गांवों में वर्तमान में प्रतिदिन 72.8 लाख लीटर एवं कस्बों में क्रमशः 16.00, 17.50 और 14.00 लाख लीटर पेयजल वितरण किया जा रहा है। विवरण परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

दूदू बीसलपुर परियोजना की ट्रांसमिशन पाइप लाइन-1 की परिकल्प अवधि समाप्त हो जाने के कारण वर्तमान में मांग के अनुरूप पेयजल उपलब्ध करवाया जाना संभव नहीं हो पा रहा है।

(2) विधान सभा क्षेत्र फुलेरा की वर्ष 2054 की मांग हेतु ट्रांसमिशन पाइप लाइन-1 के संवर्धन कार्य राज्य स्तरीय योजना स्वीकृति समिति द्वारा 25वीं बैठक दिनांक 02.07.2021 द्वारा राशि रुपये 265.96 करोड़ की जारी की गई है। योजना का कार्यादेश दिनांक 06.10.2023 को राशि रुपये 310.41 करोड़ का जारी किया गया है। योजना का कार्य वर्तमान में प्रगति पर है एवं योजना पूर्ण करने की निर्धारित दिनांक 15.06.2025 है।

श्री अध्यक्ष: उत्तर आ गया है? पूरक प्रश्न पूछिये।

श्री विद्याधर सिंह (फुलेरा): हां, उत्तर आ गया है लेकिन उत्तर बड़ा घूमा फिराकर दिया गया है मंत्रीजी द्वारा। ...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्ष: आप तो प्रश्न पूछें।

श्री विद्याधर सिंह (फुलेरा): मैं यह प्रश्न पूछ रहा हूं कि इन्होंने यह माना है कि आपके यहां पर 50 परसेंट पानी ही आपको दिया गया है फुलेरा क्षेत्र के लिए और उन्होंने यह कारण भी दिया है कि पुरानी पाइप लाइन की अवधि खतम हो गयी थी, उस अवधि को हम आगे बढ़ाने के लिए, 2025 तक का वह समय है तो क्या 2025-26 तक फुलेरा बिना पानी के ही रहेगा? यह मंत्री महोदय बताने की कृपा करें कि फुलेरा में वैकल्पिक व्यवस्था क्या करेंगे?

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्रीजी।

श्री कन्हैयालाल (जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य के विधान सभा क्षेत्र फुलेरा के अन्दर 163 गांव तीन शहर क्रमश: सांभरलेक, फुलेरा एवं किशनगढ-रेनवाल है। वर्तमान में विधान सभा क्षेत्र फुलेरा के 163 गांवों की जल मांग 12.41 एम.एल.डी. है तथा शहरी क्षेत्रों की जल मांग मात्र क्रमश: 1.89, 2.21 और 2.48 एम.एल.डी. है, इस प्रकार कुल मांग 18.99 एम.एल.डी. है। ग्रामीण क्षेत्रों में बीसलपुर परियोजना तथा स्थानीय जल स्रोतों से मिलाकर 7.2 एम.एल.डी. तथा शहरी क्षेत्रों में क्रमश: 1.6 एम.एल.डी., 1.75 एम.एल.डी. एवं 1.4 एम.एल.डी. पेयजल वितरण किया जा रहा है, इस प्रकार औसतन 12.3 एम.एल.डी. पेयजल वितरण प्रतिदिन किया जा रहा है और लगभग 6 एम.एल.डी. इनको पानी कम मिल रहा है।

मैं माननीय सदस्य को यह कहना चाहता हूं कि पिछले ...(व्यवधान)...

श्री विद्याधर सिंह (फुलेरा): माननीय अध्यक्ष महोदय, 12 एम.एल.डी. में से 6 एम.एल.डी. ही मिल रहा है। ...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्ष: आप प्रश्न पूछे न।

श्री कन्हैयालाल (जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री): मैं सबका जवाब दूंगा आपको। विद्याधरजी, आप जवाब सुनो।

श्री अध्यक्ष: आपको मौका देंगे।

श्री कन्हैयालाल (जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री): देश के यशस्वी प्रधान मंत्री मोदीजी ने 2019 में 15 अगस्त को हर घर में 55 लीटर पानी देने की योजना प्रस्तावित की थी।

श्री अध्यक्ष: आप फुलेरा का बाताओ।

श्री कन्हैयालाल (जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री): उसके तहत फुलेरा विधान सभा क्षेत्र के ग्रामीण इलाके में भी सबको जो पहले बीसलपुर में 2021 तक की योजना बनी थी, जो भी पाइप लाइन 2021 तक हुए, एक तरह से उनकी उम्र या एज खतम हो चुकी थी। वहां पर केवल 35 लीटर पानी मिल रहा था और 35 लीटर में भी कहीं पर लीकेज था, कहीं पर सीपेज था तो इस कारण से लगभग 15 से 20 लीटर पानी ही उनको मिल रहा था। जब यह योजना चालू हुई तो किसी ने भी यह नहीं देखा कि सबसे पहले पानी जिस जगह से लेंगे,

वहां पर पानी है या नहीं। क्योंकि इन्होंने ई.आर.सी.पी. पर कोई काम नहीं किया। ई.आर.सी.पी. चाहे पांच साल बाद में आती लेकिन उसको आरक्षित कर देते तो हम वहां पर जो पानी बचा हुआ होता तो उसको हम इस योजना में प्रस्तावित कर सकते थे। यह योजना में प्रस्तावित ही नहीं था इस वजह से पहले तो इन्होंने योजना ही नहीं बनाई और जब योजना बनाई तो यह योजना तो बना दी कि घर-घर लाइनें डालने की बाकी जो मेन पम्प हाउस कैसे बनेगा, इन्टेक पम्प हाउस, उसका फिल्टर प्लांट कैसे बनेगा, उस सिस्टम के लिए इन्होंने कोई काम नहीं किया। इसके बाद में लास्ट में जब घर-घर, उस उपभोक्ता को ...(व्यवधान)...

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): ये तो पहली बार विधायक बने हैं। आप फुलेरा का बताओ न। ...(व्यवधान)...

श्री कन्हैयालाल (जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री): पहले पूरी बात सुनें। मैं उसका जवाब दूंगा पर आपको पूरा सुनना पड़ेगा। आप सुनिये। क्यों नहीं आ रहा है, उसका भी जवाब दूंगा।

श्री अध्यक्ष: आप क्यों खड़े हो? आपके मंत्री खड़े हुए हैं।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): इसमें इनका क्या दोष है?

श्री कन्हैयालाल (जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री): जवाब आप सुनिये। दोष इनको नहीं है, दोष पिछली सरकार का है। सबसे पहले इन्टेक हाउस बनाना चाहिए था, फिल्टर प्लांट बनाना चाहिए था और वह लाइन आती। जब उपभोक्ता के घर पर नल लग गया तो उसमें पानी ...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्ष: आप उत्तर तो सुनिये।

श्री कन्हैयालाल (जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री): जब नई बड़ी लाइन है, हमने उसके टेंडर कर दिये, उसका वर्क आर्डर दे दिया। बड़ी लाइन डल रही है, फिल्टर प्लांट के लिए, माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपके अजमेर की वजह से उसके इन्टेक पम्प हाउस के पैसे 265 करोड़ रुपये हमें दिलायें, उसका फिल्टर प्लांट भी बना रहे हैं, इन्टेक पम्प हाउस भी हम बना रहे हैं और आने वाले 2025 तक हर उपभोक्ता को 55 लीटर पीने का पानी मिलेगा। ...(व्यवधान)...

श्री विद्याधर सिंह (फुलेरा): मंत्रीजी, मेरा सीधा सा सवाल है, उसका आप जवाब दीजिए। फलेरा के लिए पानी की व्यवस्था क्या करेंगे? ...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य।

श्री कन्हैयालाल (जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री): यह आपको पिछली सरकार के समय में काम करना चाहिए था जो आप लोगों ने काम नहीं किया, यह कमी आपकी है। ...(व्यवधान)...

श्री विद्याधर सिंह (फुलेरा): आप वैकल्पिक व्यवस्था क्या करेंगे?

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न। श्री सुरेश गुर्जर। यह हो गया। आप क्यों खड़े हो?

...(व्यवधान)...

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): माननीय अध्यक्ष महोदय, पॉलिटिकल जवाब देने से काम नहीं चलेगा। कोई वैकल्पिक व्यवस्था हो तो मंत्रीजी बतायें और यह जिस जे.जे.एम. पर बात कर रहे हैं न ...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्ष: आज पानी पर चर्चा भी है। माननीय सदस्य, आप उस पर बोल लेना। ...(व्यवधान)...

झालावाड़ में प्रस्तावित सिंचाई परियोजना

372. श्री सुरेश गुर्जर (खानपुर): क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या झालावाड जिले के बकानी क्षेत्र में वर्तमान में कोई सिंचाई परियोजना संचालित है? यदि हां, तो विगत तीन वर्षों में सिंचाई सुविधाओं के विकास हेतु कितनी राशि आवंटित की गई व कितनी राशि व्यय की गई है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या उक्त क्षेत्र में कोई नवीन सिंचाई परियोजना प्रस्तावित है? यदि हां, तो प्रस्तावित नवीन सिंचाई योजनाएं और उनके क्रियान्वयन की समय सीमा क्या है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

जल संसाधन मंत्री (श्री सुरेश सिंह रावत): (1) झालावाड़ जिले के बकानी क्षेत्र में राजपुरा लघु सिंचाई परियोजना संचालित है, जिसके द्वारा 310 हैक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई सुविधा प्रदान की जा रही है।

राजपुरा लघु सिंचाई परियोजना के विकास के लिये विगत 3 वर्षो में मनरेगा के अन्तर्गत दो कार्य करवाये गये, विवरण परिशिष्ट-'अ' पर संलग्न है।

(2) बजट घोषणा वर्ष 2024-25 के अन्तर्गत 100 एनीकटों के निर्माण/मरम्मत एवं जीर्णोद्धार के तहत नानोर-झालावाड में सौर आधारित फव्वारा सिंचाई प्रणाली की घोषणा की गई है। प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति पश्चात निविदा आमंत्रित कर कार्य करवाया जाना प्रस्तावित है।

श्री अध्यक्ष: पूरक प्रश्न।

श्री सुरेश गुर्जर (खानपुर): माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्रीजी से यह मेरा पूरक प्रश्न है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र के आगरिया, ...(व्यवधान)...

SSY/RTM/02.08.2024/12:00/1g

श्री अध्यक्ष: प्रश्नकाल समाप्त। प्रश्नकाल समाप्त। माननीय सदस्य, आसन पांवों पर, प्रश्नकाल समाप्त, प्रश्नकाल समाप्त। बैठिये। प्रश्नकाल समाप्त हो गया।

स्थगन प्रस्तावों पर अध्यक्षीय व्यवस्था

मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि निम्नांकित स्थगन प्रस्तावों की सूचना प्राप्त हुई है :-

(1) श्री पितराम सिंह काला, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र पिलानी के मंड्रेला क्षेत्र

के बजावा गांव में घर पर सो रहे रिटायर्ड सूबेदार, उनकी पत्नी एवं लाखू गांव निवासी चन्द्रपाल यादव की निर्मम हत्या किये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

(2) श्री चन्द्रभान सिंह चौहान, सदस्य की ओर से प्रदेश के निजी विद्यालयों में अध्ययन करने वाले छोटे बच्चों के बैग का वज़न अत्यधिक होने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

(3) श्री ललित यादव, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र मुण्डावर के बेहरोज गांव की भूमि को वन विभाग में दर्शाये जाने से ग्रामवासियों को हो रही परेशानी से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

(4) श्रीमती अनिता जाटव, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र हिण्डौन के ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल की समस्या से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

(5) श्री जयकृष्ण पटेल, सदस्य की ओर से प्रदेश में संविदा कार्मिकों की सेवाएं समाप्त किये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

(6) श्री थावर चन्द, सदस्य की ओर से डूंगरपुर जिले में थाना पारसोला के मूंगाणा कस्बे में हुए तिहरे हत्याकाण्ड में पुलिस द्वारा किये गये सराहनीय कार्य के लिए पुलिस जवानों को गैलेन्ट्री प्रमोशन दिये जाने के संबंध में।

(7) श्री रविन्द्र सिंह भाटी, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र शिव में लम्बित कृषि एवं घरेलू विद्युत कनेक्शनों को शीघ्र जारी किये जाने के संबंध में।

उपरोक्त प्रस्ताव ऐसे नहीं हैं कि सदन की पूर्व निर्धारित कार्यवाही को रोककर इन पर विचार किया जाये, अतः इन पर अनुमति देने में असमर्थ हूँ।

(8) श्री रफीक खान, सदस्य की ओर से प्रदेश के विभिन्न जिलों में लम्बे समय से चल रही सफाई कर्मचारियों की हड़ताल से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(9) श्रीमती गीता बरवड़, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र भोपालगढ़ के ग्राम मेलाना हनुमान सागर, तहसील बावड़ी में अनुसूचित जाति के काश्तकार परिवार पर हुए हमले से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(10) श्री पूसाराम गोदारा, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र रतनगढ़ के शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में बारिश के पानी का निकास नहीं होने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

(11) श्री सुरेश गुर्जर, सदस्य की ओर से झालावाड़ जिले के मंडावर थाना क्षेत्र में कालीसिंध नदी की रपट से बहे तीन लोगों की अभी तक तलाश नहीं होने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

उपरोक्त प्रस्ताव भी ऐसे नहीं है कि सदन की पूर्व निर्धारित कार्यवाही को रोककर इन पर विचार किया जाये। अतः अनुमति देने में असमर्थ हूं। फिर भी माननीय सदस्य श्री रफीक खान, श्रीमती गीता बरवड़, श्री पूसाराम गोदारा एवं श्री सुरेश गुर्जर को उनके प्रस्ताव की विषय वस्तु पर दो- दो मिनिट बोलने की अनुमति होगी।

नियम 295 के अन्तर्गत प्राप्त विशेष उल्लेख की सूचनाएं

(1) श्री हरिमोहन शर्मा, सदस्य की ओर से बूंदी विकास प्राधिकरण का गठन किये जाने

के संबंध में।

(2) श्री भीम राज भाटी, सदस्य की ओर से पाली जिले में बागडिया सामूहिक कृषि सहकारी समिति लिमिटेड के लिए आबंटित भूमि के संबंध में।

(3) श्री राम सहाय वर्मा (रेगर), सदस्य की ओर से निवाई शहर में सीवरेज के निर्माण की स्वीकृति जारी किये जाने के संबंध में।

(4) सुश्री नौक्षम, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र कामां के ग्राम नीमला में वैवाहिक धोखाधड़ी करने वाले गिरोह पर कार्यवाही किये जाने के संबंध में।

(5) श्री गोपीचन्द मीणा, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र जहाजपुर की तहसील कोटडी तथा जहाजपुर में लम्बित राजस्व प्रकरणों का त्वरित निस्तारण किये जाने के संबंध में।

(6) श्री जब्बर सिंह सांखला, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र आसीन्द के उपखण्ड बदनोर स्थित बैराठ माताजी मन्दिर की सड़क का डामरीकरण करवाये जाने के संबंध में।

(7) श्री लक्ष्मण राम, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र मेड़ता में संचालित सीमेन्ट फैक्ट्रियों तथा चाईना क्ले के भट्टे से उत्पन्न होने वाले प्रदूषण के संबंध में।

(8) श्री कान्ति प्रसाद, सदस्य की ओर से प्रदेश में खेतों से गुजरने वाली विद्युत लाइनों का संबंधित काश्तकार को मुआवजा दिये जाने का प्रावधान करने के संबंध में।

(9) श्री गणेशराज बंसल, सदस्य की ओर से प्रदेश में कृषि भूमि पर स्वीकृत आवासीय योजनाओं में पेयजल आपूर्ति हेतु नियमों में शिथिलता प्रदान किये जाने के संबंध में।

(10) श्री जाकिर हुसैन गैसावत, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र मकराना के कालवा से मीठडीया तक एम.डी.आर. को तकनीकी मापदण्डानुसार सुगम एवं सुरक्षित बनाये जाने के संबंध में।

(11) श्री विश्वराज सिंह मेवाड़, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र नाथद्वारा में धर्म के व्यवसायीकरण पर प्रतिबंध लगाये जाने के सम्बन्ध में।

(12) श्री गोरधन, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र धोद के ग्रामीण क्षेत्रों से निकलने वाली हाईटेंशन लाइनों के लिए काश्तकारों को दी जाने वाली मुआवजा राशि में बढ़ोतरी किये जाने के सम्बन्ध में।

(13) श्री विनोद कुमार, सदस्य की ओर से पीलीबंगा जिला हनुमानगढ में अपर जिला न्यायालय खोले जाने के सम्बन्ध में।

(14) श्री जितेन्द्र कुमार गोठवाल, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र खण्डार के बोथल रोड पर छाण तथा जेतपुर में बेशकीमती जमीन से अतिक्रमण हटाये जाने के संबंध में।

(15) डॉ. ऋतु बनावत, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र बयाना मुख्यालय पर संचालित ए.डी.जे. नंबर 02 कोर्ट को उपखण्ड मुख्यालय रूपवास पर स्थानान्तरित किये जाने के संबंध में।

माननीय सदस्यों को उनके द्वारा दी गयी सूचना को पढ़ने की अनुमति होगी।

पर्ची

आज दिनांक 02 अगस्त, 2024 को शून्यकाल में बोलने हेतु 45 पर्चियां प्राप्त हुई. जिनमें से शलाका द्वारा 04 पर्ची निकाली गई।

श्री शंकर सिंह रावत, माननीय सदस्य द्वारा दी गई पर्ची, इसी विषय पर दिनांक 23 जुलाई, 2024 को ध्यानाकर्षण के माध्यम से सदन में चर्चा हो जाने से पुनरावृत्ति के कारण निरस्त की गई।

क्रम संख्या	पर्ची संख्या	माननीय सदस्य का नाम	विषय
1.	45	श्री विरेन्द्र सिंह (मसूदा)	संस्कृत महाविद्यालय पर चर्चा।
2.	26	श्री भागचन्द टांकड़ा	मेरे विधान सभा क्षेत्र में विभिन्न महाविद्यालयों के नाम परिवर्तन के सम्बन्ध में चर्चा।
3.	31	श्री रामस्वरूप लाम्बा	विधान सभा क्षेत्र के नसीराबाद शहर में अवैध रूप से संचालित बूचड़खानों को बन्द करवाने के सम्बन्ध में।

श्री रफीक खान।

स्थगन प्रस्ताव आदि पर चर्चा

राज्य में जारी सफाई कर्मचारियों की हड़ताल

श्री रफीक खान (आदर्श नगर): माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे स्थगन प्रस्ताव पर बोलने का मौका दिया, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं।

अध्यक्ष महोदय, एक मसला है सफाई कर्मचारियों का, और सफाई कर्मचारियों का मसला बहुत सारे दिनों से वह लोग स्ट्राइक पर हैं। पूरे शहर के अन्दर गंदगी, कचरे के ढेर लगे हुए हैं। हालत यह है कि पूरा शहर सड़ रहा है। यह कमोबेश जयपुर में ही नहीं, पूरे राजस्थान में यही हालत है।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य।

श्री रफीक खान (आदर्श नगर): सफाई कर्मचारियों पर हम कोई संज्ञान नहीं ले रहे हैं।

श्री अध्यक्ष: खड़े नहीं रहें। अरुण जी, अरुण चौधरी।

श्री रफीक खान (आदर्श नगर): उसके ऊपर से बारिश का प्रकोप, खड्डे, कीचड़, मेरी सदन से गुजारिश है कि मंत्री जी की तरफ से कोई प्रतिनिधि मंडल जाये।

श्री अध्यक्ष: आप खड़े क्यों हो दोनों। माननीय, मैंने कहा कि खड़े होकर बात नहीं करनी है। दस बार कहा।

श्री रफीक खान (आदर्श नगर): सफाई कर्मचारियों से बात करे। ऐसे समय में जब बारिश का प्रकोप चारों तरफ है तो मैं यह चाहता हूं कि मंत्रिमंडल की तरफ से कोई भी

सरकार का नुमाइंदा जाये, सफाई कर्मचारियों से बात करे। ऐसी हालत में भी वह धरने पर बैठे हैं। पिछले 2 दिन से लगातार 24 घंटों से ज्यादा बारिश हुई है। ना स्ट्राइक करने वालों को बैठने की जगह है, साफ-सफाई के मामले में पूरा शहर सड़ रहा है।

मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि अभी तक सफाई कर्मचारियों से कोई प्रतिनिधि मंडल बात नहीं कर रहा है। हम सबको मिलकर के इन सफाई कर्मचारियों की बात सुननी चाहिए। इसका समाधान जल्दी से जल्दी करें।

इस तरह का माहौल है कि जयपुर के अन्दर अतिवृष्टि होने से गंदगी चारों तरफ है। कचरे के ढेर लगे हुए हैं। चारों तरफ कीचड़ फैल गया है। एक तरफ जहां वे बैठे हैं, वहां वह अमानवीय स्थिति में बैठे हैं। उनसे बात करें और उनको बोलें कि आपकी समस्याओं का समाधान करेंगे। उनको वापस इस बात के लिए एश्योर करें कि एक बार वह मानवीय स्थितियों को देखते हुए काम पर लौटें। मैं यही गुजारिश करना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष: श्रीमती गीता बरवड़।

मेलाना हनुमान सागर ग्राम (भोपालगढ़) में अनुसूचित जाति के परिवार पर हमला

श्रीमती गीता बरवड़ (भोपालगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे स्थगन प्रस्ताव पर बोलने का मौका दिया, इसके लिए आपका बहुत-बहुत आभार।

मेरी विधान सभा भोपालगढ़ के मेलाना हनुमान सागर, तहसील बावड़ी, जिला जोधपुर के एक अनुसूचित जाति के काश्तकार भभूतराम वगैरह दिनांक 19/07 को उनकी खातेदारी खेत में बुआई करने हेतु जाते समय ताराराम, जैताराम, नैनाराम, बाबूलाल, मोहन, गंगाराम, कपिल मेघवाल, तीन बेटियां सुखी, पानी और जमना, तब उस समय जबरन बलपूर्वक कब्जा करने की नीयत से इन काश्तकारों को जान से मारने की नीयत से एकराय होकर इनके खेत में हत्यारों से लैस 2 कैम्पर गाड़ी, 3-4 ट्रेक्टरों पर सवार होकर आते हैं और इन गरीब तबके के लोगों पर कातिलाना हमला किया जाता है। जिसकी वीडियो भी वायरल हो रही है। धमकी देने वाले आरोपियों को तत्काल गिरफ्तार करवाकर सख्त कार्यवाही करायें। इस परिवार को सुरक्षा करवाने की मैं आपसे मांग करती हूं।

अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए आपका बहुत-बहुत आभार। धन्यवाद। जय भीम।

Spp/Rtm/02.08.2024/12.10/1h

श्री अध्यक्ष: मैं माननीय सदस्यों को एक जानकारी दे रहा हूं जब प्रश्न लगायें और पूरक प्रश्न पूछें तो तैयारी के साथ आयें। इसके साथ ही किसी माननीय सदस्य की जब पर्ची लगती है या स्थगन आता है, उसको 295 नहीं बनायें। केवल 295 में ही देखकर बोला जाता है। जब आपने कोई स्थगन लगाया तो उस विषय वस्तु पर दो मिनट बिना देखे हम अपनी बात रखें। उसको यदि पढ़ेंगे तो फिर स्थगन बन्द करना पड़ेगा। स्थगन प्रस्ताव और पर्ची का एक अलग विषय है एक्स-टेम्पोर उस पर बोलिये। दो मिनट तो अपन बोल ही सकते हैं।

अगला स्थगन, श्री पूसाराम।

रतनगढ़ के शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में वर्षा जल के निकास का अभाव

श्री पूसाराम गोदारा (रतनगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे आपने विधान सभा प्रक्रिया नियम 50 के अन्तर्गत रेन फॉल पर बोलने का मौका दिया। मेरे विधान सभा क्षेत्र रतनगढ़ और चूरू जिला मुख्यालय पर 110 से लेकर 135 एम एम बारिश हुई। इसके कारण बहुत जबरदस्त हालात खराब हो गये। रतनगढ़ कस्बा पूरी तरह से मार्केट और हॉस्पिटल एरिया और फरमाना ताल पूरी तरह से भर गया। सुबह 4 बजे से लेकर 7 बजे तक बरसात हुई। अभी तक संसाधन सीमित हैं। नगरपालिका में नहीं के बराबर संसाधन होने के कारण दो-चार पम्पों से पानी नहीं निकल पाया और इसके अलावा नगरपालिका राजलदेसर में भी मार्केट और बस्तियां पानी से भर गयी। वहां मात्र दो पम्प होने के कारण से वहां पर पानी की अभी तक निकासी नहीं हुई। पांच-पांच फीट पानी चढ़ा। व्यापारियों का माल खराब हो गया। लाखों रुपये का नुकसान हो गया। गरीबों के मकान गिर गये और इसके अलावा ग्रामीण क्षेत्र में पंचायत समिति और पंचायतें हाथ पर हाथ रखे बैठी हैं। उनके पास न तो पम्प सैट हैं, न उनके पास जनरेटर हैं। गांव तालाब बने हुए हैं और हालात बहुत खराब हो रहे हैं। हालांकि बहुत अच्छी बात है कि प्रदेश में शानदार मानसून चल रहा है। किसानों के लिये, आप और हम सबके लिये खुशहाली है। लेकिन इतनी बड़ी आपदा जहां 110 से 135 एम एम बारिश हुई। हमारे साथी विधायक मुख्यालय चूरू के भी हरलाल जी सामने बैठे हैं, उनको भी मालूम है 135 एम.एम. बारिश हुई है, आज अख़बार में भी छपा है। बहुत बड़ी आपदा है। अभी भी वहां पर दो-दो फीट पानी हॉस्पिटल और मार्केट में भरा हुआ पडा है। व्यापारी परेशान हैं। आमजन और ग्रामीण लोग परेशान हैं। इसलिये तत्काल ही पानी की निकासी के लिये नगरपालिका, पी एच ई डी मंत्रीजी से और इसके अलावा मैं माननीय आपदा राहत मंत्रीजी से भी निवेदन करना चाहूंगा कि जिला कलेक्टर को निर्देश दें और अतिरिक्त संसाधन उपलब्ध करायें और इसके लिये अतिरिक्त बजट दिया जाये। सारी सड़कें टूट गयीं, सारे गांवों के रास्ते अवरूद्ध हो गये। इसलिये कृपया इसके लिये गंभीरता से सरकार इसको लेवे। मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिये आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिन्द।

श्री अध्यक्ष: धन्यवाद। श्री सुरेश गुर्जर।

मंडावर थाना क्षेत्र (झालावाड़) में कालीसिंध नदी की रपट से बहे लोगों की तलाशी

श्री सुरेश गुर्जर (खानपुर): माननीय अध्यक्ष महोदय, नियम 50 के अन्तर्गत आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिये बहुत-बहुत धन्यवाद। माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र के गागरोन के निकट आहू और काली सिंध नदी के संगम पर जो रपट बनी हुई है, उस रपट पर दो युवक और एक युवती नदी पार करते समय पैर फिसलने से बह गये हैं। कल से ही पुलिस और एस डी आर एफ की टीमें तलाश कर रही हैं, पर उनको सफलता नहीं मिली है। मेरी आपसे मांग है, सरकार से मेरी मांग है कि आप कोटा से या अन्य जगहों से गोताखोरों को भेजकर उनका तलाशी अभियान तेज किया जाये। इसके साथ

ही, मेरी मांग है कि बरसात के समय रपटों पर, पुलियाओं पर पुलिस की व्यवस्था की जाये, ताकि कोई भी व्यक्ति नदी पर पानी होने पर या पुलियाओं पर पानी होने पर निकले तो पुलिस उनको रोके। धन्यवाद।

श्री अध्यक्षः श्री हरिमोहन शर्मा, 295 पढ़ें।

नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख

बूंदी विकास प्राधिकरण का गठन

श्री हरिमोहन शर्मा (बून्दी): माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन के नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख प्रस्ताव प्रस्तुत कर निवेदन है कि कोटा विकास प्राधिकरण अधिनियम जब से पास किया गया है, तब से ही तथा पूर्व में नगर विकास न्यास कोटा में हमारे बूंदी जिले के 64 गांव एवं नगर पालिका क्षेत्र केशोरायपाटन को शामिल किया गया, तब से ही हमारा विकास अवरुद्ध हो गया। कोटा ग्रीन एयरपोर्ट के लिए बूंदी जिले की 3,000 बीघा जमीन दी गई। यह जमीन ग्राम-तुलसी, कैथूदा, बालापुरा और देवरिया की है। केशोरायपाटन एवं तालेड़ा क्षेत्र के लाखों बीघा आबादी, चरागाह, सिवाय चक भूमि कोटा विकास प्राधिकरण के खाते दर्ज कर दी गई। ग्रीन एयरफील्ड एयरपोर्ट एम ओ यू में बूंदी का नाम अंकित तक नहीं किया गया, जबकि एयरपोर्ट बूंदी जिले में बन रहा है। इसके एवज में जो भूमि कोटा एयरपोर्ट ऑथोरिटी की है, उससे प्राप्त आय को भी बूंदी के विकास में खर्च नहीं किया जा रहा है। संविधान संशोधन कर जो अधिकार ग्राम पंचायतों को और नगरपालिकाओं को दिये थे, उनका हनन हो रहा है। ये संस्थाएं अपने क्षेत्र में किसी भी प्रकार के विकास कार्य नहीं करवा पा रही हैं, आम आदमी परेशान हैं और दोहरा प्रशासन हो रहा है।

अतः बूंदी के नागरिक एवं समस्त जन-प्रतिनिधि एक राय से मांग करते हैं कि या तो कोटा विकास प्राधिकरण अधिनियम का निरसन किया जाये अथवा बूंदी जिले के शहरी और ग्रामीण क्षेत्र के सभी गांवों को इस प्राधिकारण से निकाल कर वापस पूर्व की भांति रखा जावे। साथ ही बूंदी विकास प्राधिकरण की स्थापना की जावे।

(समय बजे)

(श्री संदीप शर्मा, सभापति, पदासीन)

श्री सभापतिः श्री भीमराज भाटी। श्री रामसहाय वर्मा।

श्री भीम राज भाटी (पाली): माननीय सभापति महोदय, मैं माफी चाहता हूं।

श्री सभापतिः माननीय सदस्य, कहां घूमते रहते हैं?

श्री भीम राज भाटी (पाली): माफी चाहता हूं सर।

श्री सभापतिः बोलिये।

पाली में बागडिया सामूहिक कृषि सहकारी समिति लिमिटेड के लिए आवंटित भूमि

श्री भीम राज भाटी (पाली): माननीय सभापति महोदय, राजस्थान विधान सभा के

प्रक्रिया तथा कार्य संचालन के नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख प्रस्ताव के अन्तर्गत मैं सदन के माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहूंगा कि बागडिया सामूहिक कृषि सहकारी समिति लिमिटेड बागडिया के नाम से राजस्थान सरकार कार्यालय जिला कलेक्टर पाली द्वारा वर्ष 1959 में ग्राम बागडिया रोड स्थित खसरा नम्बर 288 रकबा 452 बीघा 18 बिस्वा भूमि आवंटित की गई थी। उक्त आवंटन की दिनांक से, संस्थान की दिनांक से सस्थान के सदस्यों द्वारा अपने-अपने हिस्से की 15 बीघा 02 बिस्वा भूमि पर कृषि कार्य किया जाता रहा है। उक्त कृषि भूमि पर आज दिनांक तक संस्थान के सदस्यों का कब्जा काश्त निरंतर चला आ रहा है तथा वर्तमान में भी उक्त कृषि भूमि संस्थान के सदस्यों का ही कब्जा काश्त है तथा जिला कलेक्टर पाली के आदेश दिनांक 16.08.2021 को नगर सुधार न्यास, पाली को उक्त भूमि हस्तान्तरण कर दी गई।

उल्लेखनीय यह है कि इनके द्वारा उक्त कृषि भूमि को अपनी गाढ़ी खून-पसीने की कमाई से विकसित किया तथा कृषि योग्य बनाया एवं अपने अपने हिस्सों पर लगातार काश्त कर रहे हैं।

मेरा इस सदन के माध्यम से सरकार से निवेदन है कि उक्त कृषि भूमि को इनके पक्ष में नियमन करने का आदेश फरमावें या डी.एल.सी. रेट के अनुसार उक्त को मुआवजा दिलवाने की कृपा करें।

श्री सभापतिः श्री राम सहाय वर्मा।

निवाई शहर में सीवरेज के निर्माण की स्वीकृति

श्री राम सहाय वर्मा (रेगर) (निवाई): माननीय सभापति महोदय, निवाई में सीवरेज की स्वीकृति के संबंध में प्रक्रिया के नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख प्रस्ताव के माध्यम से निवेदन है कि मेरा विधान सभा क्षेत्र निवाई प्रदेश में अपनी अलग पहचान रखता है।

श्री सभापतिः माननीय सदस्य, जो आपने लिखकर दिया है, वही पढ़ें। माननीय रामसहाय जी।

श्री राम सहाय वर्मा (रेगर) (निवाई): वही पढ़ रहा हूं।

श्री सभापतिः नहीं, यह नहीं पढ़ रहे हैं आप। निवाई में सीवरेज की स्वीकृति के सम्बन्ध में आपने 295 लगाया है। आप मन से बोल रहे हैं।

श्री राम सहाय वर्मा (रेगर) (निवाई): यहां पर स्थित वनस्थली विद्यापीठ में दूर-दूर से छात्राएं अध्ययन करने के लिए आती है। बड़ी संख्या में बाहर से आने वाली छात्राएं कमरा लेकर निवाई में ही रहती है। निवाई की जनसंख्या 50 हजार से ज्यादा है तथा यहां सैकड़ों कॉलोनियां हैं। लेकिन सीवरेज लाइन न होने के कारण सड़कों पर घरों से निकलने वाला पानी बहता रहता है। पहले भी कई बार जन प्रतिनिधियों ने निवाई में सीवरेज डालने हेतु आवाज उठाई थी किन्तु पूर्ववर्ती सरकार द्वारा इस संबंध में कोई कार्य नहीं किया गया है।

अतः माननीय सभापति महोदय, मेरा आपके माध्यम से माननीय नगरीय विकास मंत्री महोदय से निवेदन है कि इसी बजट सत्र में निवाई में सीवरेज की स्वीकृति जारी करवाने की

कृपा करें।

श्री सभापतिः सुश्री नौक्षम चौधरी।

नीमला ग्राम (कामां) में वैवाहिक धोखाधड़ी करने वाले गिरोह पर कार्यवाही

सुश्री नौक्षम (कामां): शुक्रिया माननीय सभापति महोदय। विधान सभा कार्य व संचालन संबंधी नियम 295 के अन्तर्गत विशेष उल्लेख के तहत विधान सभा क्षेत्र कामां के ग्राम नीमला में हुए मैरिज फ्रॉड के संबंध में निवेदन है। माननीय सभापति महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र कामां के ग्राम नीमला में बहुत बड़ा मैरिज फ्रॉड हुआ है। उक्त प्रकरण संख्या 0029 दिनांक 07.02.2024 पुलिस थाना कैथवाड़ा में दर्ज है। शादी करवाने के नाम पर लोगों को फुसलाकर पैसे लेने और इससे दोगुनी कीमत का सामान दिलाने का झांसा देकर गिरोह द्वारा ठगी की जा रही है। उक्त प्रकरण में जिन लोगों के साथ मैरिज फ्रॉड हुआ है उनके पैसों की वसूली करने की कार्रवाई पुलिस प्रशासन द्वारा की गई है या नहीं और मैरिज फ्रॉड करने वाले गिरोह के कितने लोगों की गिरफ्तारियां हुई हैं?

(समय बजे)

(श्री वासुदेव देवनानी, अध्यक्ष, पदासीन)

Jyg/rtm/020824/12.20/1j

श्री अध्यक्ष: श्री गोपीचन्द मीणा।

जहाजपुर व कोटड़ी तहसीलों के प्रकरणों का त्वरित निस्तारण

श्री गोपीचन्द मीणा (जहाजपुर): माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया एवं कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख प्रस्ताव के माध्यम से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि विगत कांग्रेस कार्यकाल में मेरी ओर से निरन्तर मांग के बावजूद विधान सभा क्षेत्र जहाजपुर की तहसील जहाजपुर व तहसील कोटड़ी क्षेत्र का सेटलमेंट नहीं किया गया, जबकि भीलवाड़ा की अन्य सभी तहसीलों में सेटलमेंट की कार्यवाही पूर्ण कर दी गई। सेटलमेंट के अभाव में आज मेरे विधान सभा क्षेत्र की दोनों ही तहसीलों के हजारों किसान बन्धु रेवेन्यू रेकॉर्ड में खातेदारों की आपसी हिस्सेदारी अशुद्धियों, तरमीम अशुद्धियों, बैंक रहन अशुद्धियों, खातेदारों के नाम, जाति, पते की अशुद्धियों से बुरी तरह से परेशान होकर पटवारियों, तहसील कार्यालय, एसडीओ कार्यालय में चक्कर काट रहे हैं, विधान सभा क्षेत्र जहाजपुर के एसडीओ कार्यालय जहाजपुर व एसडीओ कार्यालय कोटड़ी में राजस्व वादों का अम्बार लगा हुआ है। लम्बित राजस्व प्रकरणों के निस्तारण नहीं होने से किसान परिवादी वर्ग अपनी खेती-कमाई छोडकर राजस्व न्यायालय एवं राजस्व वकीलों के यहां हाजरी देकर समय और धन बर्बाद करने को बाध्य हो रहे हैं।

अतः सरकार से मेरा विशेष आग्रह है कि उक्त दोनों ही तहसीलों में कृषक खातेदारों के रेवेन्यू रेकार्ड में दर्ज अशुद्धियों को कैम्प लगवाकर निस्तारण किया जावे। प्राथमिकता के आधार पर तहसील जहाजपुर व तहसील कोटड़ी का भू-प्रबन्ध (सेटलमेंट) के सरकारी आदेश

जारी किये जावे तथा उप खण्ड जहाजपुर व उप खण्ड कोटड़ी के राजस्व न्यायालयों में लम्बित राजस्व वादों का निस्तारण करवाकर राहत दी जावे।

श्री अध्यक्षः श्री जब्बर सिंह सांखला।

बदनोर उप खण्ड स्थित बैराठ माताजी मन्दिर के रास्ते का डामरीकरण

श्री जब्बर सिंह सांखला (आसीन्द): माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया एवं कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख प्रस्ताव के माध्यम से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि मेरे विधान सभा क्षेत्र आसीन्द-हूरडा के बदनोर उप खण्ड में बैराठ माताजी का भव्य मंदिर है जो अरावली की पहाडी पर है, उस मंदिर में वर्ष भर आसपास के गांवों के लाखों श्रद्धालु दर्शन के लिए जाते हैं। उस मंदिर तक जाने के लिए लगभग 2 से 3 किलोमीटर की चढाई को पैदल चढकर जाना पडता है। वहां जो अरावली की पहाडी है वह फोरेस्ट की जगह है। मेरा निवेदन है कि फोरेस्ट की वजह से वहां सड़क नहीं बनी हुई है। वन एवं पर्यावरण मंत्री महोदय जी से निवेदन है कि लाखों श्रद्धालुओं की भावना तथा क्षेत्रवासियों की भावना को समझते हुए वहां डामर की सड़क का निर्माण कराए जाने की आवश्यकता है क्योंकि आधे रास्ते पर कच्ची सड़क है तथा आधे रास्ते पर पगडण्डी बनी हुई है। वहां बहुत ही दुर्गम तथा पथरीला रास्ता है और वहां आये दिन कई तरह की घटनाएं-दुर्घटनाएं होती रहती हैं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा आग्रह है कि अगर वन विभाग स्वीकृति दे दे तो इस रास्ते को भामाशाहों द्वारा डामरीकरण होने की भी पूरी सम्भावना है। मैं मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि बेराठ माताजी का यह बहुत ही भव्य तथा प्राचीन मंदिर है मगर दुर्गम पहाड़ों पर होने व रास्ता सही नहीं होने से सभी को परेशानी होती है। जनता की इस उचित मांग को मानते हुए इस रास्ते के डामरीकरण की स्वीकृति होती है तो आपकी अति कृपा होगी। इससे पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा तथा सनातन धर्म प्रेमियों का भी उत्साहवर्धन होगा।

श्री अध्यक्षः श्री लक्ष्मण राम।

मेड़ता में सीमेंट फैक्ट्रियों व चाइना क्ले के भट्टों द्वारा कारित प्रदूषण

श्री लक्ष्मण राम (मेड़ता): माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया एवं कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख प्रस्ताव के माध्यम से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि मेरे विधान सभा क्षेत्र मेडता में संचालित जे.के. सीमेन्ट फैक्ट्री, गोटन एवं भोपालगढ़ विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत अल्ट्राटेक सीमेन्ट (बिरला व्हाइट सीमेन्ट) फैक्ट्री. खारिया द्वारा लम्बे समय से क्षेत्र में गोचर भूमि पर अवैधानिक खनन कार्य किया जा रहा है, जिससे दोनो ही विधान सभा क्षेत्रों में असीमित पर्यावरण प्रदूषण हो रहा है। उक्त क्षेत्र में अंधाधुंध वृक्षों की कटाई भी की जा रही है. जिससे पिछले चार वर्षों से बारिश का ग्राफ गिरता जा रहा है। अपर्याप्त वर्षा के कारण क्षेत्र में अकाल की स्थिति लगातार बनी हुई है। प्रदूषण की मात्रा ज्यादा होने एवं प्रदूषण पर किसी प्रकार का

नियंत्रण नहीं होने के कारण क्षेत्र में कई बीमारियों ने डेरा डाल दिया है। क्षेत्र में सिलीकोसिस, अस्थमा, चर्मरोग, टीबी इत्यादि गंभीर बीमारियों से आम जन ग्रसित होकर अकाल मृत्यु को प्राप्त हो रहा है।

गोटन रेलवे स्टेशन के ठीक सामने चाइना क्ले के भट्टे संचालित है, जिनसे भी क्षेत्र में गंभीर रूप से पर्यावरण प्रदूषण जनित गभीर बीमारियां फैल रही हैं। साथ ही रेलवे स्टेशन पर आने वाले राहगीरों व यात्रियों को भी काफी समस्याओं का सामना करना पड रहा है। उक्त भट्टों के संचालन से रेलवे स्टेशन का सौन्दर्य पूरी तरह से धूमिल होकर स्टेशन का मूर्त रूप खत्म हो चुका है।

अतः मेरा आपसे निवेदन है कि मेडता विधान सभा क्षेत्र में संचालित विभिन्न सीमेन्ट फैक्ट्रियों एवं चाइना क्ले के भट्टों द्वारा फैलाये जा रहे असीमित पर्यावरण प्रदूषण पर नियंत्रण कर आम जन को राहत प्रदान करने का श्रम करें।

श्री अध्यक्षः श्री कान्ति प्रसाद।

किसानों को खेतों से गुजरने वाली विद्युत लाइनों का मुआवजा

श्री कान्ति प्रसाद (थानागाजी): माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया एवं कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख प्रस्ताव के माध्यम से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि राज्य सरकार ने इस बजट में ऊर्जा के क्षेत्र में विकसित राजस्थान 2047 के सपने को साकार करने के लिए और हर घर हर खेत बिजली निर्बाध रूप से उपलब्ध कराने के लिए बड़ी-बड़ी योजनाओं की घोषणा की है, लेकिन इस देश के रीढ़ की हड्डी कहे जाने वाले किसान की ओर बहुत कम ध्यान दिया गया है। आज हम देख रहे हैं की गांवों में किसानों के खेतों में बड़ी-बड़ी 11 हजार केवी, 33 हजार केवी, 132 केवी की लाइनें खींच दी जाती है जिसकी वजह से उस किसान के पास कृषि योग्य भूमि बहुत कम रह जाती हैं। किसान के खेत में बड़ी बड़ी लाइनों का जाल सा फैल जाता हैं और खेतों में आये दिन तार टूटते रहते हैं जिसकी वजह से अनेकों बार दुर्घटनाए भी होती रहती हैं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, इसलिए राज्य सरकार से किसान को उसके खेत में से इन बड़ी-बड़ी लाइनों को लेकर जाने का मुआवजा दिलाया जाए। जिस प्रकार सरकार के सड़कों के अनेक बड़े प्रोजेक्ट में भूमि अधिग्रहण करते समय किसान को उसकी भूमि अवाप्त करने का मुआवजा दिया जाता हैं, ठीक उसी प्रकार से किसान के खेत से गुजरने वाली बड़ी बड़ी 11 हजार केवी, 33 हजार केवी, 132 केवी की लाइनों का मुआवजा बिजली कम्पनियों द्वारा दिया जाना चाहिए ताकि किसान को होने वाले नुकसान की भरपाई हो सके । राज्य सरकार को किसान को उसके खेत में से गुजरने वाली बड़ी-बड़ी लाइनों का मुआवजा दिए जाने का प्रावधान करना चाहिए।

श्री अध्यक्षः श्री गणेशराज बंसल।

कृषि भूमि पर स्वीकृत आवासीय योजनाओं में

पेयजल आपूर्ति हेतु नियमों में शिथिलता

श्री गणेशराज बंसल (हनुमानगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया एवं कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख प्रस्ताव के माध्यम से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90-क के अंर्तगत कृषि भूमि पर स्वीकृत आवासीय योजनाओं में पेयजल आपूर्ति हेतु जन स्वास्थ्य एवं अभियान्त्रिकी विभाग की नीति बहुत ही जटिल और महंगी है, जिससे निजी कॉलोनियों में निवास कर रही राज्य की बहुत बड़ी आबादी स्वच्छ पेयजल से वंचित है और भूमिगत जल का दोहन कर फ्लोराइडयुक्त जल पीने के लिए मजबूर है।

केन्द्र सरकार हर घर नल से जल पहुंचाने की मंशा रखती है और जल जीवन मिशन के तहत ग्रामीण क्षेत्र की ढाणी-ढाणी पेयजल पाइप लाइन पहुंचाई जा रही है, किन्तु शहरी क्षेत्र में स्वीकृत निजी आवासीय योजनाओं में निवास कर रही राज्य की बहुत बड़ी आबादी स्वच्छ पेयजल से वंचित है।

जिस प्रकार विधुत विभाग द्वारा कॉलोनियों में विद्युतीकरण की कुल लागत को प्रति व्यक्ति के हिसाब से उपभोक्ता से वसूल किया जाता है, उसी प्रकार जन स्वास्थ्य एवं अभियान्त्रिकी विभाग द्वारा भी कुल लागत को प्रति व्यक्ति के हिसाब से उपभोक्ता से वसूल कर आमजन को लाभान्वित किया जा सकता है।

अतः माननीय सभापति महोदय के माध्यम से मंत्री महोदय से निवेदन है कि कृषि भूमि पर स्वीकृत आवासीय योजनाओं में पेयजल आपूर्ति हेतु जनस्वास्थ्य एवं अभियान्त्रिकी विभाग की नीति का सरलीकरण आमजन को राहत प्रदान करे।

श्री अध्यक्ष: श्री जाकिर हुसैन गैसावत।

मकराना की कालवा-मीठड़ीया एमडीआर का मापदण्डानुसार सुदृढ़ीकरण

श्री जाकिर हुसैन गैसावत (मकराना): माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया एवं कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख प्रस्ताव के माध्यम से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि मेरे विधान सभा क्षेत्र मकराना के कालवा से मीठड़ीया तक CRF के तहत State MDR सडक का निर्माण घटिया सामग्री के साथ दोषपूर्ण तकनीकी, घुमाव, मोड़, उबड़-खाबड़ सडक का निर्माण करना, निर्धारित मापदण्डो का कतई ध्यान नही दिया जाकर सम्बन्धित फर्म, कम्पनी और अभियन्ताओं ने मात्र अपने स्वयं के हितलाभ को देखते हुए मेरे विधान सभा क्षेत्र मकराना को असंख्य दुर्घटनाओं से परिपूर्ण सड़क (32 कि.मी.) बना दी गयी है। सरकार से मेरा विशेष आग्रह है कि विशेष उल्लेख प्रस्ताव की भावना एवं तथ्यों को देखते हुए उक्त दोषपूर्ण सड़क को तकनीकी मापदण्डानुसार सुगम, सुरक्षित बनवाया जाए ताकि आये दिन हो रही जनहानि एवं दुर्घटनाओं पर ब्रेक लग सके।

MLS/RTM/02.08.2024/12:30/1k

श्री अध्यक्षः श्री विश्वराज सिंह मेवाड़।

नाथद्वारा में धर्म के व्यवसायीकरण पर प्रतिबंध

श्री विश्वराज सिंह मेवाड़ (नाथद्वारा): माननीय अध्यक्ष, आपने मुझे सदन में नियम 295 के तहत एक विशेष उल्लेख रखने की अनुमति दी, उसके लिए आपका धन्यवाद। विषयः पर्यटन की दृष्टि से कुछ सालों से धार्मिक शहरों और स्थानों को अनुचित तरीके से बढ़ावा देकर धर्म को कहीं मनोरंजन और व्यवसाय के स्थल पर उतारा जाना, इससे लोगों में रोष और आलोचना। भारत में किसी भी धर्म की बात करें, ज्यादातर लोगों में आस्था है। सदियों से लोग अपने धर्म अनुसार तीर्थ यात्रा करते आ रहें है, उन्हें लुभाने की आवश्यकता नहीं है। यात्रियों के लिए या स्थलों की सुविधाएं, इन पर ध्यान देना आवश्यक है।

धर्म स्थलों की पहचान और रख-रखाव से परे पर्यटन के नाम से मनोरंजन और सम्बन्धित व्यवसाय तेजी से अपनाये जा रहे हैं। इससे न तो धर्म स्थल का रखाव होता है, मनोरंजन भी अधूरा रह जाता है और आस्था फीकी पड़ जाती है। नाथद्वारा एक मन्दिर, मूर्ति के लिए प्रसिद्ध है, जिस मूर्ति से हमें धर्म, इतिहास और संस्कृति की शिक्षा मिलती है, मगर नाथद्वारा में ही मनोरंजन और मन्दिर के एक भद्दे मिलाप का उदाहरण एक अन्य मूर्ति से है, जो इतनी विशाल है कि आप उसके अन्दर जा सकते हैं और अन्दर जाकर उसके कन्धों तक चढ़ सकते हैं। मूर्ति का ऐसा उपयोग न तो धार्मिक, न ही नास्तिक, बल्कि अधर्म का प्रतीक ही कहा जा सकता है। मूर्ति परिसर में मनोरंजन भी उपलब्ध है। सम्भव है कि एक विशाल हनुमान जी की मूर्ति भी बनेगी।

इसके अलावा प्रसिद्ध स्थल की नकल में, उन्हीं के नाम से मीलों दूर धर्म स्थल उभर रहे हैं। सरकार से आग्रह और प्रश्न है, क्या धर्म के नाम से ऐसी गतिविधियों को रोका जायेगा, क्या स्थानीय लोगों की भावना और धार्मिक क्रिया को ध्यान में रखते हुए ही प्रस्तावित कार्य की अनुमति दी जायेगी? आखिरकार धर्म की रक्षा आस्था से की जाती है, दिखावे से नहीं। धन्यवाद।

श्री अध्यक्षः श्री गोरधन।

धोद में काश्तकारों को हाईटेंशन लाइन की एवज में मुआवजा राशि में वृद्धि

श्री गोरधन (धोद): माननीय अध्यक्ष महोदय, धन्यवाद। राजस्थान विधान सभा के नियम 295 के अन्तर्गत विशेष उल्लेख प्रस्ताव के अंतर्गत निवेदन है कि धोद विधान सभा क्षेत्र के सिंगरावट, लोसल, हरिपुरा, सांगलिया, भगतपुरा, कर्णपुरा, खूड़, इनके अलावा दूसरी लाइन में कासली दूजोद व विधान सभा के कई गांव शामिल हैं, जिन किसानों के खेतों से होते हुए विद्युत प्रसारण निगम की हाई टैंशन लाइन निकल रही है। उसमें केन्द्र सरकार के निर्देशानुसार विद्युत प्रसारण निगम द्वारा जहां पोल लगेगा, उसके चारों ओर एक मीटर तक डीएलसी का दुगना व जहां से लाइन निकल रही है, उस क्षेत्र का डीएलसी का 30 परसेंट मुआवाज़ा देने का प्रावधान किया है, जिसको राजस्थान सरकार ने सहमति दी है।

इसमें मेरा निवेदन है कि इस राशि को राजस्थान सरकार अपने विवेक से बढ़ाने पर

विचार कर सकती है। इसमें निवेदन है कि सरकार उक्त मुआवाज़े को डीएलसी रेट का तीन गुना व लाइन के नीचे के क्षेत्रफल का 50 परसेंट मुआवजा देने का विचार किया जाये व साथ ही अभी जिन किसानों के खेतों में उक्त लाइन का कार्य चल रहा है, उनको भी इस मुआवज़ा राशि में शामिल किया जाये। साथ ही, भारत सरकार के उपक्रम पावर ग्रिड के द्वारा 765 केवी हाई टैंशन लाइन, जो भड़ला, गुजरात से बीकानेर होते हुए पलसाना 765 केवी जीएसएस में आ रही है जो कि धोद विधान सभा क्षेत्र के गांवों की घनी आबादी से गुजर रही है। इससे जान-माल को अत्यधिक नुकसान होने की सम्भावना है। अतः महोदय से निवेदन है कि इसके स्थान परिवर्तन के बारे में विचार किया जाये। धन्यवाद।

श्री अध्यक्षः श्री विनोद कुमार।

पीलीबंगा में अपर जिला न्यायालय की स्थापना

श्री विनोद कुमार (पीलीबंगा): माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन के नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख प्रस्ताव पर बोलने का मौका दिया, उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। महोदय, प्रक्रिया के नियमों के नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख प्रस्ताव प्रस्तुत कर निवेदन है कि पीलीबंगा मण्डी जिला हनुमानगढ़ की प्रमुख मण्डी है। पीलीबंगा में अपील अधिकारी राजस्व न्यायालय का कैम्प कोर्ट है व यहां सन् 1992 से सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट का न्यायालय है तथा यहां वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अति. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट का न्यायालय है।

पीलीबंगा में 35 वर्षो से तहसील व उप-खण्ड कार्यालय है। मण्डी पीलीबंगा का यह क्षेत्र विकासशील क्षेत्र है। अतः अध्यक्ष महोदय, माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर द्वारा पूर्व में अपर न्यायालय स्वीकृत कर वितीय स्वीकृति हेतु राजस्थान सरकार को लिखा गया था, लेकिन किसी कारण वितीय स्वीकृति के अभाव में पीलीबंगा में अपर जिला न्यायालय स्वीकार नहीं हुआ था। आपके माध्यम से राज्य सरकार से आग्रह करूंगा कि पीलीबंगा में अपर जिला न्यायाधीश न्यायालय खोला जाये। धन्यवाद।

श्री अध्यक्षः श्री जितेन्द्र कुमार गोठवाल।

खण्डार में छाण व जेतपुर में जमीनों पर अतिक्रमण

श्री जितेन्द्र कुमार गोठवाल (खण्डार): 000

श्री अध्यक्षः माननीय सदस्य, जो दिया है, वही बोलना है।

श्री जितेन्द्र कुमार गोठवाल (खण्डार): वही बोल रहा हूं, भाई साहब।

श्री अध्यक्षः नहीं, उसमें अन्तर है।

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): भाई साहब नहीं है, अध्यक्ष महोदय हैं।

श्री जितेन्द्र कुमार गोठवाल (खण्डार): 000

श्री अध्यक्षः यह कहां हैं? यह नहीं है कहीं भी। माननीय सदस्य, यह कहीं नहीं है आपका।

श्री जितेन्द्र कुमार गोठवाल (खण्डार): भाई साहब, मैं सैकण्ड पैराग्राफ पढ़ रहा हूं।

श्री अध्यक्षः जो आपने यहां दिया है, उसकी कॉपी पढ़िये।

श्री जितेन्द्र कुमार गोठवाल (खण्डार): बिलकुल वही पढ़ रहा हूं भाई साहब।

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): भाई साहब, भाई साहब, क्या लगा रखा है यह?

श्री जितेन्द्र कुमार गोठवाल (खण्डार): अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे राजस्थान विधान सभा के नियम 295 के अन्तर्गत बोलने का अवसर दिया, उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

महोदय, उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र खण्डार में छाण तथा जेतपुर में कई वर्षों से अतिक्रमियों ने अवैध अतिक्रमण कर रखा है, जिन्हें पिछली सरकार में राह मिला हुआ था तथा कई नेताओं का उनको संरक्षण मिलता था। इस वजह से कई लोगों ने वहां की बेशकीमती जमीनों पर अवैध कब्जा कर लिया है, जिसमें अधिकतर मुसलिम समाज के लोग हैं। उन्होंने इतना बेखौफ होकर अवैध कब्जा कर रखा है कि छोटा-मोटा अधिकारी अगर वहां जाकर कहता है या कब्जा हटाने की कार्यवाही करता है तो वे झगड़ा करने पर उतारू हो जाते हैं। इससे लगता है कि इनको कुछ नेताओं का संरक्षण मिला हुआ है। मुझे तो लगता है कि अगर सही अधिकारियों की एक उच्च स्तरीय कमेटी का गठन करके इसकी सही जांच करायी जाती है तो इसमें कई नेताओं के नाम सम्मिलित होने जैसे मामले उजागर हो सकते हैं।

अतः मेरा सरकार से आग्रह है कि खण्डार में बोथल रोड पर छाण तथा जेतपुर में बेशकीमती जमीनों पर मुसलमान जाति के कुछ लोगों द्वारा किया हुआ अवैध अतिक्रमण हटाकर सरकार करोड़ों की जमीन अवैध अतिक्रमियों से मुक्त कराकर जनता को राहत दें व उन अवैध अतिक्रमियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही कर दण्डित करे तथा जिन अधिकारियों की मिलीभगत से यह अतिक्रमण हुआ, उन अधिकारियों को दण्डित करने की कृपा करे।

श्री अध्यक्षः डा. ऋतु बनावत।

बयाना मुख्यालय में एडीजे कोर्ट नं. 2 का
उप-खण्ड मुख्यालय रूपवास पर स्थानान्तरण

डा. ऋतु बनावत (बयाना): माननीय अध्यक्ष महोदय, धन्यवाद, आपने मुझे विधान सभा के प्रक्रिया एवं कार्य संचालन के नियम 295 के अन्तर्गत बोलने का अवसर प्रदान किया। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगी, मेरे विधान सभा क्षेत्र बयाना रूपवास के रूपवास उप-खण्ड मुख्यालय पर लोगों के लिए सस्ता और सुलभ न्याय उपलब्ध कराने के लिए अभिभाषक संघ की ओर से गत दो दशक से कई मांगें की जा रही हैं, लेकिन आज दिन तक इस दिशा में कोई सार्थक कदम नहीं उठाए गये हैं। इस सम्बन्ध में मैं प्रस्ताव प्रस्तुत कर रही हूं।

अभिभाषक संघ की ओर से उप-खण्ड मुख्यालय पर एडीजे स्थायी कोर्ट स्थापित करने के लिए बयाना मुख्यालय पर संचालित एडीजे नम्बर 2 कोर्ट को रूपवास मुख्यालय पर स्थानान्तरित किया जाये। रूपवास मुख्यालय पर स्थित अतिरिक्त सिविल कोर्ट को अपग्रेड

करके एसीजेएम कोर्ट स्थापित की जाये। रूपवास उप-खण्ड मुख्यालय पर न्यायालय के लिए भवन निर्माण हेतु आराजी खसरा नम्बर 1035 रकबा चार बीघा आठ बिस्वा भूमि की किस्म परिवर्तित करवाते हुए आवण्टन कराया जाये। परिवादियों को राज्य सरकार की मंशा अनुसार सस्ता और सुलभ न्याय उपलब्ध कराने हेतु ये सभी कदम उठाये जाने जरूरी हैं। राज्य सरकार गम्भीरतापूर्वक विचार करके शीघ्र इस दिशा में कार्यवाही करेगी, ऐसा विश्वास है। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: आज अपने यहां राज्यपाल दीर्घा में उत्तर प्रदेश के श्रम रोजगार मंत्री श्री रघुराज जी व इनके साथ जो राज्यपाल दीर्घा में विराजे हैं, मैं सदन की ओर से उनका स्वागत करता हूं।

पर्ची। श्री विरेन्द्र सिंह।

पर्ची के माध्यम से उठाये गये मुद्दे

राजकीय शास्त्री संस्कृत महाविद्यालय, जालिया-2

को राजकीय वित्त पोषित में परिवर्तन

श्री विरेन्द्र सिंह (मसूदा): माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे पर्ची के माध्यम से बोलने का अवसर दिया, उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। मेरे विधान सभा क्षेत्र मसूदा में जालिया सैकंड में राजकीय शास्त्री संस्कृत महाविद्यालय 2003 में स्ववित्त पोषित के नाम से चालू किया गया। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से आग्रह करना चाहूंगा कि उस महाविद्यालय में 20 वर्षों तक आचार्य, सह आचार्य और कर्मचारियों के वेतन का सारा भुगतान गांव के लोगों द्वारा किया जा रहा है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से आग्रह करना चाहूंगा कि अब उस स्ववित्त पोषित महाविद्यालय को राजकीय वित्त पोषित कराकर गांव वालों को सहयोग प्रदान करें।

अब गांव वालों का धैर्य जवाब दे गया है। वेतन दिलाना बड़ा मुश्किल हो रहा है। अतः अध्यक्ष महोदय, मैं पुनः आपके माध्यम से निवेदन करता हूं कि उसे राजकीय वित्त पोषित महाविद्यालय में परिवर्तित करने की घोषणा की जाये। दूसरा, अपने भिनाय में राजकीय महाविद्यालय जो महात्मा गांधी राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में संचालित हो रहा है, उसके भवन की अतिशीघ्र सैंक्शन जारी करवाकर महाविद्यालय का भवन बनवाया जाये। बहुत-बहुत धन्यवाद।

mkd/rtm/02.08.2024/12.40/2l

श्री अध्यक्ष: श्री भागचन्द टांकड़ा।

बांदीकुई के महाविद्यालयों का नाम परिवर्तन

श्री भागचन्द टांकड़ा (बांदीकुई): अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे पर्ची के माध्यम से बोलने का अवसर दिया, उसके लिए धन्यवाद।

मैं माननीय महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि बसवा में स्थित राजकीय

महाविद्यालय का नाम राणा सांगा के नाम से किया जाये। राणा सांगा राजकीय महाविद्यालय, बसवा करने की कृपा करें।

राजकीय कन्या महाविद्यालय, बांदीकुई का नामकरण सावित्री बाई फूले के नाम करें। राजकीय महाविद्यालय, आभानेरी का नाम कर्नल किरोड़ी बैंसला के नाम नामकरण करने के सम्बन्ध में मंत्री जी से निवेदन करूंगा। इनके तीनों महाविद्यालयों के नामकरण किये जाएं।

श्री अध्यक्षः श्री रामस्वरूप लाम्बा।

नसीराबाद में संचालित अवैध बूचड़खानों पर कार्यवाही

श्री रामस्वरूप लाम्बा (नसीराबाद): माननीय अध्यक्ष महोदय, धन्यवाद। मैं आपके माध्यम से मेरे विधान सभा क्षेत्र नसीराबाद के नसीराबाद शहर में पुलिस व प्रशासन की मिलीभगत से हो रहे अवैध बूचड़खाने के संचालन का मामला रखना चाहूंगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, नसीराबाद क्षेत्र में अनेक अवैध बूचड़खानों का संचालन स्थानीय पुलिस व प्रशासन की मिलीभगत से हो रहा है। जिससे बरसात के मौसम में भारी दुर्गन्ध आने व बीमारी फैलने का डर बना रहता है।

पूर्व में भी नसीराबाद की जनता और आमजन के द्वारा एक बड़ा आंदोलन किया गया। स्थानीय व्यापारियों ने भी पूरे बाजार को बन्द रखा और करीबन डेढ़, दो महीने बन्द रहने के पश्चात जिला प्रशासन से इसमें समझौता हुआ और उसके बाद ये अवैध बूचड़खाने बन्द हुए।

ये पुलिस और प्रशासन की मिलीभगत से आजकल वापस चालू हो रहे हैं। इनको पुलिस का पूरा सहयोग मिल रहा है। उस समय समझौते में तत्कालीन कलेक्टर आरूषि मलिक जी ने शहर में स्लॉटर हाउस और अवैध बूचड़खानों को बन्द करने निर्देश दिये और इन्हें शहर से दूर ले जाकर जमीन अलॉट की गई, परन्तु वर्तमान में पुनः इन बूचड़खानों को संचालन किया जा रहा है। कई संगठनों द्वारा समय-समय पर पुलिस को ज्ञापन भी दिये जा चुके हैं और पुलिस के समक्ष यह बात भी रखी जा चुकी है, पर प्रशासन का कोई सहयोग नहीं मिल रहा है।

मैं आपके माध्यम से निवेदन करता हूं कि इन बूचड़खनों को बन्द किया जावे और पुलिस का पूरा सहयोग मिले। जो दोषी हैं, उन पर कार्यवाही हो, बहुत-बहुत धन्यवाद।

व्यवस्था

ध्यानाकर्षण प्रस्तावों व अन्य सूचीबद्ध प्रस्तावों के उत्तरों की तय समय में उपलब्धता

श्री अध्यक्षः ध्यानाकर्षण प्रस्ताव। उसके पहले सारे माननीय मंत्रियों और बाकी सभी विभागों को कहना चाह रहा हूं कि माननीय सदस्यों के द्वारा ध्यानाकर्षण प्रस्ताव प्राप्त होते हैं, उसके जवाब नियमानुसार तीन दिवस की अवधि में प्रस्तुत किये जाने होते हैं, लेकिन इस सचिवालय को लम्बी अवधि व्यतीत होने के उपरान्त भी उत्तर प्राप्त नहीं हो रहे हैं। यहां तक कि, पहले भी नहीं होते थे। वही कह रहा हूं, यहां भी नहीं होते थे।

यहां तक कि सूचीबद्ध प्रस्तावों के जवाब भी सदन की कार्यवाही शुरू होने से पूर्व तक भी

प्राप्त नहीं हो रहे हैं। इसलिए, यह सदन अपेक्षा करता है कि विभाग ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के जवाब नियम, समय, अवधि तक सदन के उपयोग के लिए प्रस्तुत करें।

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय कार्य मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, आपकी व्यवस्था शिरोधार्य है। हमने पूरा प्रयास किया है, चाहे प्रश्न हों, ध्यानाकर्षण हों या स्थगन हों, जैसी व्यवस्था होगी, उसका हम पूरी पालना करते हैं। आज आपने और निर्देश दिया है, इसकी सख्ती से पालना की जायेगी।

श्री अध्यक्ष: तीन दिन में।

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय कार्य मंत्री): नियमानुसार समय पर आयेगा। पहले से ही सरकार तो सावधान थी, सावधान है, सावधान रहेगी और समय पर जवाब देती आई है, फिर भी आपका आदेश है तो इसकी पालना होगी।

एक मिनट जूली साहब। अब आपके आदेश की अवहेलना कौन कर सकता है? हम तो हमेशा आपके आदेश की पूरी पालना करते हैं, शत-प्रतिशत करते हैं। रात को नींद में भी आ जाता है कि स्पीकर साहब का कोई आदेश नहीं हो जावे। ...(व्यवधान).. जजमान, हम तो पूरी पालना करते हैं, कोई कमी नहीं आयेगी।

श्री अध्यक्ष: राठौड़ साहब की ट्रेनिंग हो गई।

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): अध्यक्ष जी, ये पालना करते तो आपको कहना नहीं पड़ता। प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं है। संसदीय कार्य मंत्री, आप गम्भीर होइये। आप गम्भीर रहिये।

श्री अध्यक्ष: मैं इसका उत्तर दे रहा हूं। मैंने पिछले समय के पांच सालों के भी निकाले, तब भी नहीं आ रहे थे और आज भी नहीं आ रहे हैं। इसलिए, वे भी आयें। आप व्यवस्था करें।

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय कार्य मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, एक व्यवस्था की बात है। आप एक धन्यवाद तो सरकार को दें कि इस सत्र में जितने भी प्रश्न लगे, शायद 95 परसेंट तक के उत्तर मिल गये हैं। हम भी एमएलए रह चुके हैं। तीन-तीन, चार-चार विधानसभाओं, 15वीं, 13वीं के जवाब अब आ रहे हैं तो इसलिए इतना धन्यवाद तो सरकार को अवश्य दें।

श्री अध्यक्ष: सरकार को भी है। चलिये, अब हो गया। आपके नेता खड़े हैं। आपके नेता बोल चुके हैं। अब ये बोल रहे हैं।

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): अध्यक्ष जी, यह भी पहली बार हुआ है कि इतने क्वेश्चनों के गलत आंसर सरकार की तरफ से आये हैं। इनको आपने भी डायरेक्शन दिये हैं। सदस्य भी उसको संज्ञान में लाये हैं।

श्री अध्यक्ष: यह केवल एक जानकारी के लिए है। यह वाद-विवाद का समय नहीं है। समय हो रहा है। आप बैठिये, हो गया। भाई, ध्यानाकर्षण के लिए कह दिया है। श्री ताराचन्द जी।

ध्यानाकर्षण प्रस्ताव

नगर निगम, उदयपुर को हस्तांतरित योजनाओं में अनियमितताओं की जांच

श्री ताराचन्द जैन (उदयपुर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे नियम-131 के तहत सदन में ध्यान आकर्षित करने का जो अवसर प्रदान कर रहे हैं, उसके लिए मैं बहुत-बहुत आभार प्रकट करता हूं। उदयपुर शहर के अन्दर..।

श्री अध्यक्ष: आपको तो केवल मुद्दे पर ध्यान आकर्षित करना है, दो वाक्य बोलने हैं। बाद में मंत्री जी जवाब देंगे, फिर आप बोलना । माननीय मंत्री जी।

श्री झाबर सिंह खर्रा (राज्य मंत्री, नगरीय विकास): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके मार्फत उदयपुर से आने वाले माननीय विधायक के ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के सम्बन्ध में विधायक महोदय को, आपको और सदन को अवगत कराना चाहूंगा कि वर्ष 2004 में नगर विकास प्रन्यास, उदयपुर द्वारा नगर निगम को 30 योजनाएं एवं 16 कच्ची बस्तियां हस्तान्तरित की गईं। उक्त 30 योजनाओं में कुल 6046 भूखण्डों की पत्रावलियां एवं 16 कच्ची बस्तियों में कुल 4363 भूखण्ड/सर्वेधारियों की पत्रावलियां प्राप्त हुई हैं।

नगर निगम, उदयपुर द्वारा उक्त योजनाओं के भूखण्डों में कुल 2501 नामान्तरण एवं पट्टे जारी किये गये तथा कच्ची बस्ती में कुल 7 नामान्तरण एवं 935 पट्टे जारी किये गये।

नगर निगम द्वारा उक्त भूखण्डों में कुल 34 भूखण्डों की नीलामी की गई, जिससे राशि रुपये 11,19,27,812/-(ग्यारह करोड़ उन्नीस लाख सत्ताईस हजार आठ सौ बारह) की आय हुई।

कुछ प्लॉट्स का नगर विकास न्यास द्वारा आवंटन किया गया, लेकिन आवंटी द्वारा राशि जमा नहीं कराने पर उक्त प्लॉट्स का आवंटन स्वतः ही निरस्त हो गया पर इन प्लॉट्स की पत्रावलियां निगम को हस्तान्तरित नहीं की गई थीं। तथा उक्त योजनाओं में खाली प्लॉट्स कार्नर प्लाट व यूआईटी द्वारा निरस्त किये गये आवंटन से संबंधित पत्रावलियों के बारे में नगर निगम, उदयपुर को किसी भी प्रकार की जानकारी नहीं थी।

उक्त भूखण्डों के सम्बन्ध में नगर निगम द्वारा विभागीय जांच हेतु महापौर, नगर निगम, उदयपुर के निर्देशानुसार दिनांक 28.12.2021 को जांच समिति गठित की गई। जिसमें तीन अधिकारी एवं तीन जनप्रतिनिधियों को सम्मिलित किया गया एवं जांच कमेटी द्वारा दिनांक 14.03.2022 को नगर निगम, उदयपुर को नगर विकास प्रन्यास द्वारा हस्तान्तरित योजनाओं के सम्बन्ध में जांच प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया। जिसमें तीन अधिकारियों के हस्ताक्षर किये गये, परन्तु जनप्रतिनिधियों ने हस्ताक्षर करने से मना कर दिया। जांच प्रतिवेदन में 316 पत्रावलियों के सम्बन्ध में कोई उल्लेख नहीं था। नगर निगम द्वारा संदिग्ध 40 खाली भूखण्डों का जांच कमेटी में कोई उल्लेख नहीं है। जांच में 04 कार्मिकों, 01 सहायक प्रशासनिक अधिकारी एवं 03 वरिष्ठ सहायक को दोषी पाया जाने पर उनके विरूद्ध सीसीए नियमों के नियम 16 के तहत आरोप पत्र जारी किये गये है।

नगर विकास प्रन्यास, उदयपुर से नगर निगम, उदयपुर को हस्तान्तरित योजनाओं में हुए घोटाले के सम्बन्ध में पुलिस थाना, सूरजपोल, उदयपुर एवं पुलिस थाना, हिरण मगरी उदयपुर में प्रकरण दर्ज हुए, जिन्हें दिनांक 25.5.2022 को एस.ओ.जी. यूनिट जोधपुर के जिम्मे किया गया। जहां से अनुसंधान पश्चात् दिनांक 9.5.2023 को एस.ओ.जी यूनिट उदयपुर के जिम्मे हुआ एवं इसके पश्चात् दिनांक 23.4.2024 को अग्रिम अनुसंधान हेतु एस.ओ.जी यूनिट अजमेर को सुपुर्द किए गये।

वर्तमान में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक एस.ओ.जी यूनिट अजमेर द्वारा अनुसंधान किया जा रहा है। अनुसंधान पूर्ण होने पर नगर निगम के तात्कालिक आयुक्त एवं अन्य दोषी कार्मिकों/अधिकारियों/लोक सेवकों के विरूद्ध विधि अनुसार सक्षम न्यायालय में कार्यवाही की जायेगी तथा संदिग्ध भूखण्डों को वापस सरकार के कब्जे में लेने की कार्यवाही की जावेगी।

Bhs/Rtm/02.08.24/12.50/1m

इसके साथ ही मैं निवेदन करना चाहूंगा आपको और सदन को और माननीय विधायक को बताना चाहूंगा कि इस प्रकरण में 15वीं विधान सभा में प्रश्न लग चुके हैं, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव लग चुके हैं, 16वीं विधान सभा में भी इसका प्रश्न लग चुका है और अब ध्यानाकर्षण के माध्यम से यह प्रकरण फिर मेरे सामने आया है। मैंने इसी सत्र में जब यह प्रश्न का जवाब अधिकारी मेरे पास लेकर आये तो मुझे यह महसूस हुआ कि इस प्रकरण में बहुत गम्भीर अनियमितताएं हुई हैं और जो वास्तविक आरोपी है उसके खिलाफ अब तक किसी प्रकार की कोई अनुशासनात्मक कार्यवाही नहीं की गई है। छोटे कर्मचारियों के खिलाफ निश्चित रूप से कार्यवाही की गई है। कुल मिला कर मोटा-मोटी रूप में देखा जाये तो यह लगभग-लगभग सौ करोड़ रुपये के आस-पास का गड़बड़ घोटाला है जिसमें जिन पत्रावलियों में पट्टे जारी किये गये वो सारे कूट रचित थे। न्यास में या प्राधिकरण में जो राशि जमा होनी थी उसकी फर्जी रसीदें पत्रावली में लगी हुई थी और इस प्रकार यह एक बहुत गम्भीर प्रकरण है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय विधायक फिर कोई पूरक प्रश्न करें उससे पहले मैं विधायक महोदय और सदन को आश्वस्त करना चाहता हूं कि इस प्रकरण में जिन भूखंडों पर शायद 5-7 भूखंडों पर, न्यायालय में वाद चल कर स्थगन आ गया उनको छोड़ कर बाकी जितने भी खाली भूखंड हैं या तो प्राधिकरण ने कब्जे में ले लिये और नहीं लिये तो आने वाले समय में हम उनको प्राधिकरण के कब्जे में लेकर नीलामी के मार्फत उनका निस्तारण करेंगे ताकि वास्तविक रूप से कितनी राशि का गड़बड़-घोटाला हुआ उसकी सही-सही जानकारी प्राप्त हो सके।

दूसरा मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि इसमें मूल रूप से राजस्थान प्रशासनिक सेवा का अधिकारी, जो उस समय आयुक्त था जिसके द्वारा यह सारी गड़बड़ की गई, मैं सदन को आश्वस्त करना चाहूंगा कि नगरीय विकास विभाग द्वारा अगले दस कार्य दिवसों में राजस्थान

सिविल सर्विसेज क्लासिफिकेशन कंट्रोल एंड अपील रूल्स, 1958 के नियम 16 के तहत आरोप पत्र तैयार कर कार्मिक विभाग को भेजा जायेगा और कार्मिक विभाग उस आरोप पत्र का परीक्षण कर अगले पन्द्रह कार्य दिवस में सम्बन्धित अधिकारी को आरोप पत्र जारी कर स्पष्टीकरण प्राप्त करेगा और स्पष्टीकरण प्राप्त होने के बाद उस अधिकारी के खिलाफ आगे जो कार्यवाही की जानी है, उसके लिए कार्मिक विभाग मुख्य सचिव को प्रस्ताव प्रेषित करेगा और मुख्य सचिव माननीय मुख्य मंत्री जी के संज्ञान में लाकर उस पर यथोचित निर्णय करवायेंगे।

श्री अध्यक्ष्: माननीय सदस्य।

श्री ताराचन्द जैन (उदयपुर): माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदय के जवाब से मैं संतुष्ट हूं लेकिन कुछ बातें आपके ध्यान में लाना आवश्यक समझता हूं। पहली बात तो यह आपने सौ करोड़ का घोटाला माना है लेकिन मैं आपको यह बिलकुल विश्वासपूर्वक कह सकता हूं कि तीन सौ-चार सौ करोड़ का घोटाला है, जो विभाग ने मुझे जवाब दिया है उन्होंने यह लिखा है कि तीन सौ का कहीं उल्लेख नहीं है। मैं आपको इस जांच रिपोर्ट की प्रति दूंगा जिसमें 12,115 प्लॉट जो यू.आई.टी. ने नगर निगम को, जो रिकार्ड में थे, 6046 पट्‌टों की पत्रावली नगर निगम को ट्रांसफर की। 5733 की पत्रावली दी नहीं। इन दोनों का अन्तर 316 होता है जो दोनों में हैं ही नहीं, न तो इधर हैं न उधर हैं जो पत्रावलियां नहीं दीं वो भी घोटाले में हैं लेकिन 316 का इसमें जोड़ में फर्क है इन दोनों में तो 316, मैं इस जांच की रिपोर्ट आपको दूंगा।

दूसरी बात, चार सौ संदिग्ध का कहीं उल्लेख नहीं है मैं उस जांच रिपोर्ट की कॉपी अधिकारियों की आपको दूंगा और चालीस भूखंड संदिग्ध माने हैं और उन्होंने लिखा है यू.आई.टी. को जांच के लिए देंगे और यू.आई.टी. को आज तक कोई कागज नहीं दिया है। 16सी.सी. नोटिस का यह सारा प्रकरण पिछले पांच साल में कांग्रेस राज से चालू हुआ है। प्रतिपक्ष के नेता उस समय के माननीय गुलाब चंद जी कटारिया ने जो सदन के पटल पर मैं यह पत्र पढ़ कर आपको सुनाता हूं।

श्री अध्यक्ष: सुनाना नहीं है पत्र भेंट कर देना। यहां सुनाना नहीं है। सुनाना नहीं आप तो पत्र इनको दे देना। सुनाना नहीं है। पत्र कोई सुनाया नहीं जाता, उल्लेख किया जाता है।

श्री ताराचन्द जैन (उदयपुर): उन्होंने यह पत्र, ये प्रतिपक्ष के नेता रोज उठ कर खड़े हो जाते हैं लेकिन सदन के पास माननीय प्रतिपक्ष के नेता का जवाब...।

श्री अध्यक्ष: आप उल्लेख कर दो न इनको क्यों सम्बोधित कर रहे हो। आप तो उल्लेख करो।

श्री ताराचन्द जैन (उदयपुर): दूसरी बात, एक घोटाला इससे भी बड़ा हुआ है। रेलवे पटरी के पास 12 हजार फीट की जमीन चालीस रुपये फीट में दे दी है। उदयपुर के अन्दर जहां सभी पत्रों में लिखा हुआ है कि 1853 रुपये जिसकी डी.एल.सी. रेट है, रेलवे ने ...(व्यवधान)... एक मिनट आप सुन तो लो। सुनिये आप। आपके कारनामे सुनो आप।

1,36,000 रुपये में... ...(व्यवधान)... आप सुनो तो सही।

श्री अध्यक्षः आप उनसे बात क्यों कर रहे हो, उनसे बात नहीं करनी है। आप पहली बार आये हैं। आपको अध्यक्ष को सम्बोधित करके बोलना है उधर नहीं।

श्री ताराचन्द जैन (उदयपुर): 1,36,000 रुपये में सारी जमीन दे दी है। दूसरा, ...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्षः माननीय सदस्य। आपस में नहीं।

श्री ताराचन्द जैन (उदयपुर): दूसरा, रेलवे ने डबल लाइन की स्वीकृति जारी की है उसी रोड पर सुप्रीम कोर्ट ने जिसको अतिक्रमी माना है। 12 साल से यू.आई.टी. ने उसके ऊपर वाद दायर करके अतिक्रमी साबित किया और उसके बाद हिम्मत सिंह बारहठ ने उसी प्लॉट को केवल 1 लाख 36 हजार में दे दिया। यह इतना गम्भीर मसला है।

श्री अध्यक्षः अगला ध्यानाकर्षण। आप कुछ कहना चाहेंगे? हां, मंत्री जी कुछ कहेंगे।

श्री झाबर सिंह खर्रा (राज्य मंत्री, नगरीय विकास): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय विधायक महोदय को और सदन को अवगत कराना चाहूंगा कि मैंने सौ करोड़ का अनुमान कुछ दूसरे आधार पर लगाया है और उसके साथ मैंने यह भी सदन से निवेदन किया है जो भूखंड प्राधिकरण के कब्जे में आयेंगे हम उनकी नीलामी करेंगे और नीलामी करने के बाद कुल क्षेत्रफल से उसका गुना करने के बाद पता चलेगा कि यह कुल मिला कर कितने सौ करोड़ रुपये का घोटाला हुआ है।

दूसरा, मैं माननीय विधायक महोदय को यह भी आश्वस्त करना चाहूंगा कि मैं अतिरिक्त महानिदेशक, पुलिस, एस.ओ.जी. से यह अपेक्षा करूंगा कि वर्ष 2024 में इसका निष्पक्ष अनुसंधान करके जो भी दोषी हैं उनके खिलाफ न्यायालय में चालान प्रस्तुत कर दें।

श्री अध्यक्षः आज काम ज्यादा है इसलिये आज भोजनावकाश नहीं होगा।

अगला ध्यानाकर्षण। श्री फूल सिंह मीणा।

जावर (उदयपुर ग्रामीण) के खनन प्रभावित क्षेत्र के युवाओं को प्रशिक्षण देकर रोजगार प्रदायगी

श्री फूल सिंह मीणा (उदयपुर ग्रामीण): माननीय अध्यक्ष महोदय, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद कि महत्वपूर्ण मसले पर आपने मुझे ध्यानाकर्षण प्रस्ताव की अनुमति दी। विधान सभा क्षेत्र उदयपुर ग्रामीण की ग्राम पंचायत जावर के खनन प्रभावित क्षेत्र के युवाओं को प्रशिक्षण देकर रोजगार प्रदान करने के सम्बन्ध में मैं मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

श्री अध्यक्षः माननीय मंत्री जी।

श्री गजेन्द्र सिंह (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, हिन्दुस्तान जिंक की जो माइनिंग लीज है वह 2030 तक जायज है और माननीय सदस्य की तीन ग्राम पंचायतें उस माइन्स के एरिया में आती हैं जावर, टीडी और चणवदा। वहां पर जो टोटल जमीन 3,620 हैक्टेयर अलॉट की गई जिसमें से 1538 हैक्टेयर फॉरेस्ट की जमीन थी और

गांव वालों की सहमति एग्रीमेंट से सब करके यह डाइवर्जन करके यह जमीन भी इनको इनके माइन्स के लिए दी गई। इसमें आम सहमति बनी थी कि तीनों जो गांव, एक्चुअली वहां पर दस ग्राम पंचायतें हैं जिनमें से तीन माननीय सदस्य की हैं। यह एक एग्रीमेंट हुआ था उन गांव वालों से कि हम सहमति दे रहे हैं फॉरेस्ट लैंड के लिए, हमारे को एम्प्लोयमेंट चाहिये। वहां पर हिन्दुस्तान जिंक ने एक वोकेश्नल ट्रेनिंग सेन्टर डवलप किया और 2014 के अन्दर 240 लोगों को ट्रेनिंग देकर वहीं पर एम्प्लोयमेंट दिया गया।

Kas/rtm/02.08.2024/13.00/1n

जब 2020 में कोविड आया, उस समय 2500 लोग वहां पर काम कर रहे थे। कोविड के बाद 2-3 साल थोड़ी प्रोब्लम आई और आज वहां पर उस क्षेत्र के 2700 लोगों को वहां रोजगार मिल रहा है। अभी एक हफ्ते पहले गांव वालों ने माइनिंग की एक्टिविटीज को रोका और कहा कि हमें और रोजगार चाहिये। कोविड के बाद में 200 लोगों का ही इसमें इजाफा हुआ है। उन्होंने मांग की कि हमारे लोगों को रोजगार दिया जाये। एक हफ्ते धरना चला। सीएसआर फंड के 31 करोड़ रुपये कंपनी गांवों के डवलपमेंट के लिये खर्च कर चुकी है। हिन्दुस्तान जिंक हाई कोर्ट में गया। हाई कोर्ट ने कलेक्टर को निर्देश दिये कि धरने को हटा दिया जाये। अध्यक्ष महोदय, इसमें मेन इश्यू यह है कि हिन्दुस्तान जिंक को जिस समय एनओसी मिली थी और इनकी आपस में सहमति बनी थी, उसमें यह एश्योरेंस नहीं दिया गया था कि कितना रोजगार दिया जायेगा, कोई फिगर तय नहीं हुआ था। यह जरूर है कि कोविड के बाद खाली 200 लोग बढ़े हैं। हाई कोर्ट के ऑर्डर से धरने को हटा दिया गया है। डिपार्टमेंट यह जरूर प्रयास करेगा कि हिन्दुस्तान जिंक से सहमति बनाकर इनके वोकेशनल सेंटरों में और ट्रेनिंग दिलाकर इनके और लोगों को वहां पर एम्प्लायमेंट की अपोर्चुनिटी मिले।

श्री फूल सिंह मीणा (उदयपुर ग्रामीण): अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय ने बताया कि 2030 तक इनको लाइसेंस मिला हुआ है। अध्यक्ष महोदय, 1950 में इनको खनन करने की परमिशन मिली थी। 2014 को इनका पहले का एग्रीमेंट समाप्त हो गया था। 2014 में इनको और आगे बढ़ाने के लिये 2030 तक इसका क्राइटेरिया रखा, जिसमें सभी पंचायतों के सरपंच को बुलाकर इन्होंने एग्रीमेंट किया। उस एग्रीमेंट में इन्होंने सारी बात लिखित में दी और उसमें कंपनी के अधिकारियों के साइन भी हैं। इसमें लिखा था कि कंपनी अगर ब्लास्टिंग करती है और उसकी वजह से गांवों में कहीं दरारें पडेंगी, तो उसकी एक कमेटी बनाकर प्रभावित व्यक्ति को मुआवजा देंगे। मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से यह जानकारी चाहूंगा कि आज तक कितने लोगों के ऐसे केस आये और किन-किन को मुआवजा दिया गया?

दूसरा, यह एग्रीमेंट किया गया था कि प्रबंधन द्वारा बेरोजगारों को तकनीकी एवं व्यावसायिक प्रशिक्षण देकर प्राइवेट पार्टनर पेटेंट पर हम आईटीआई लगाने हेतु प्रतिबद्ध है

और इस दिशा में कार्य किया जा रहा है तथा प्रशिक्षण पश्चात वरीयता अनुसार रोजगार दिया जायेगा। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से यह पूछना चाहता हूं कि उन्होंने यह एग्रीमेंट किया था कि हमारे स्थानीय बेरोजगार लोगों के लिये ट्रेनिंग स्कूल खोलकर प्रशिक्षण देकर उनको रोजगार देंगे, आज तक उन्होंने एकप्रशिक्षण केन्द्र नहीं खोला और एक भी स्थानीय व्यक्ति को प्रशिक्षण नहीं दिया गया।

श्री अध्यक्षः विराजिए।

श्री फूल सिंह मीणा (उदयपुर ग्रामीण): अध्यक्ष महोदय, प्लीज, हमारे ट्राइबल ऐरिया के बेरोजगारों का मामला है। मंत्री महोदय, वह अभी भी धरने पर बैठे हैं, उनका धरना अभी समाप्त नहीं हुआ है।

श्री गजेन्द्र सिंह (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): अध्यक्ष महोदय, ऐसे जो भी प्रकरण होते हैं, उसमें कोई भी काम होता है वह या तो गुडविल से होता है या फिर लीगल डाक्यूमेंट से कोर्ट कचहरी में होता है। माननीय सदस्य ने फरमाया कि उस समय हमारा एग्रीमेंट हुआ था। अगर उस एग्रीमेंट की लीगल सैंक्टिटी है, तो आप उसकी कॉपी पेश करेंगे तो डिपार्टमेंट उसको कोर्ट में भेजकर कार्यवाही करेगा।

श्री अध्यक्षः आप टेबल कर देना।

श्री गजेन्द्र सिंह (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): अध्यक्ष महोदय, डिपार्टमेंट यह भी ट्राइ करेगा कि मिडिल मैन का रोल करके भाईचारे से कंपनी से बात करके समझाइश करेगा। इतने साल तक आपकी सहमति रही और आपके वहां के 2700 लोगों को वहां रोजगार मिला है। आपका मेन इश्यू यह है कि कोविड के बाद में खाली 200 लोग बढ़े हैं। अपन बैठ कर इनको समझायेंगे। जैसा मैंने बोला कि या तो म्यूचुअल कंसेंट्स से कोई काम होता है या फिर कोर्ट कचहरी में होता है। हाई कोर्ट ने कलेक्टर को कहकर धरना हटा दिया। दुबारा अगर यह कानून हाथ में लेते हैं तो फिर कानून का तो अपना ही रास्ता है। डिपार्टमेंट आपको आश्वासन देता है कि इसमें मध्यस्थता करके हम इसको सॉर्टआउट करने की पूरी कोशिश करेंगे।

श्री अध्यक्षः अगला। श्री रतन देवासी।

श्री फूल सिंह मीणा (उदयपुर ग्रामीण): अध्यक्ष महोदय, वहां पर लोग बिना पानी के मर रहे हैं। चुनाव का बहिष्कार किया था। वहां पर प्रदूषित पानी से लोग और पशु मर रहे थे। वहां पर टेलिंग डैम से लोगों में बीमारियां बढ़ रही हैं, चर्म रोग हो गया था।

श्री अध्यक्षः कार्यवाही का आश्वासन दिया है।

श्री फूल सिंह मीणा (उदयपुर ग्रामीण): अध्यक्ष महोदय, उन्होंने टेलिंग डैम को बड़ा करके मेरी ही नहीं सलूम्बर विधान सभा क्षेत्र की भी पंचायतें प्रभावित हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से वहां का संरक्षण चाहूंगा, वहां के लोगों को रोजगार नहीं दे रहे हैं।

श्री अध्यक्षः विराजिए, आपका विषय आ गया।

जोधपुर स्थित राईका बाग़ रेलवे स्टेशन का राम त्रुटिवश राई का बाग़ अंकन

श्री रतन देवासी (रानीवाड़ा): अध्यक्ष महोदय, मैं सबसे पहले आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मामले की गंभीरता को समझते हुए इसे प्राथमिकता दी ताकि एक बहुत बड़ा समाज जो लाखों की आबादी में रहता है, उसका आंदोलन समाप्त हो सके।

अध्यक्ष महोदय, जोधपुर स्थित रेलवे स्टेशन के नाम में त्रुटिवश राई और का अलग-अलक हो गया, जिसको लेकर पूरा समाज आंदोलित था। मैं नियम 131 के तहत माननीय मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष: मंत्री जी।

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय कार्य मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने एक विषय रखा है, जोधपुर के पास एक स्टेशन है राइ का बाग़। इसकी वस्तु स्थिति मैं आपके सामने रखूं फिर माननीय सदस्य की जो भी शंका का भी समाधान करेंगे।

महोदय, उपरोक्त विषयान्तर्गत सादर निवेदन है कि उपखण्ड अधिकारी, जोधपुर-उत्तर से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार ग्राम जोधपुर (दक्षिण) के खाता संख्या 949 खसरा नम्बर 332 रकबा 1.10 बीघा किस्म रेलवे स्टेशन रेलवे विभाग के नाम वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है। खसरा गिरदावरी ग्राम जोधपुर संवत् 2020 से 2021 में खसरा संख्या 332 में स्टेशन राईका बाग लिखा हुआ है। राईका एक साथ है। खसरा गिरदावरी संवत् 2004 से 2007 में खसरा नम्बर 332 रकबा 1.10 बीघा में खालसा स्टेशन, राईका बाग दर्ज है, उसमें भी राईका एक ही शब्द है। खसरा गिरदावरी संवत् 2010 से 2013 में खसरा संख्या 332 रकबा 1.10 बीघा खालसा, स्टेशन राईका बाग दर्ज है, इसमें भी राईका ही है।

उक्त प्रकरण में श्री वीर हड़मल जी राईका इतिहास एवं संस्कृति संरक्षण संस्थान, जोधपुर द्वारा राईका बाग रेलवे स्टेशन के नाग में शुद्धिकरण हेतु निवेदन किया गया था। इस संबंध में इस कार्यालय के पत्र दिनांक 01.07.2024 के द्वारा वरिष्ठ मण्डल वाणिज्य प्रबंधक, उत्तर पश्चिम रेलवे, जोधपुर को राजस्व रिकार्ड अनुसार राईका बाग स्टेशन की भूमि के संबंध में तथ्यात्मक रिपोर्ट प्रेषित की गई थी, साथ ही संघर्ष समिति द्वारा उपलब्ध कराये गये दस्तावेजी साक्ष्यों के आधार पर राईका बाग रेलवे स्टेशन का अंकन करते हुए लिपिकीय त्रुटि सुधार हेतु लिखा गया था तथा वरिष्ठ मण्डल वाणिज्य प्रबंधक, उत्तर पश्चिम रेलवे, जोधपुर के पत्र दिनांक 01.07.2024 के द्वारा रिकार्ड की जांच कर 15 दिवस के भीतर रिपोर्ट प्रस्तुत करने बाबत लिखित आश्वासन दिया गया था।

Msk/rtm/02.08.24/1310/ 1o

तत्पश्चात इस क्रम में स्मरण पत्र दिनांक 13.07.2024 एवं 20.07.2024 द्वारा भी पुनः निवेदन किया गया।

समिति के प्रतिनिधि मण्डल से दिनांक 25.07.2024 को उक्त विषय पर वार्ता की गयी। जिसमें अवगत कराया गया कि रेलवे द्वारा उक्त पत्र के संदर्भ में कोई सूचना समिति को नहीं दी गयी है और ना ही कार्यालय हाजा को अवगत कराया गया है।

श्री वीर हड़मल जी राईका इतिहास एवं संस्कृति संरक्षण संस्थान, जोधपुर ने प्रकरण का समाधान ना होने पर दिनांक 04.08.2024 को महा पंचायत आयोजित करने बाबत अवगत कराया है। जिससे कानून व्यवस्था की स्थिति बिगड़ने की संभावना है। इस बाबत पुलिस उपायुक्त, जोधपुर (पूर्व) के द्वारा भी पत्र दिनांक 19.07.2024 महानिदेशक पुलिस को लिखा गया है।

उक्त वस्तुस्थिति रिपोर्ट इस कार्यालय के पत्र क्रमांक राजस्य/विविध/2024/2007 दिनांक 26.07.2024 द्वारा श्रीमान संयुक्त शासन सचिव, राजस्व (ग्रुप-1) विभाग, राजस्थान, जयपुर को अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की गई, जिसमें विशिष्ट शासन सचिव, राजस्व (ग्रुप-1) विभाग जयपुर से प्राप्त रिपोर्ट क्रमांक फलां-फलां दिनांक 30.07.2024 द्वारा श्रीमान संयुक्त शासन सचिव, सामान्य प्रशासन (ग्रुप-3) विभाग को रेलवे स्टेशन के नाम परिवर्तन के संबंध में आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रकरण प्रेषित किया गया है।

प्रकरण में रेलवे विभाग से प्राप्त पत्र क्रमांक फलां-फलां दिनांक 31.07.2024 के अनुसार सर्वे ऑफ इंडिया के प्रथम प्रकाशन, 1964, ओएसएम प्रकाशन, 2011 एवं रेलवे का मानचित्र, 2022 में 'राई का बाग़' लिखा होना अवगत कराया है एवं उन्होंने बताया कि हाल समय में यह लिपिकीय त्रुटि नहीं है। लिपिकीय त्रुटि तो हुई है, पर हाल ही में नहीं हुई है, पुरानी है। मामले की गंभीरता को देखते हुए रेलवे विभाग द्वारा अंतरिम रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है। इसके अलावा भी रिकॉर्ड की खोज एवं सत्यापन कार्य रेलवे विभाग द्वारा किये जाने के प्रयास किये जा रहे है। रेलवे विभाग से प्राप्त रिपोर्ट संलग्न प्रेषित है।

मैं माननीय सदस्य को आपके मार्फत विश्वास दिलाता हूं कि यह लिपिकीय त्रुटि है। राजस्थान सरकार ने रेलवे को लिखा है कि इस लिपिकीय त्रुटि को ठीक किया जाये। 'राई-(डेस) न होकर राईका, एक ही शब्द लिखा जावे। हमें विश्वास है कि शीघ्र ही इसका समाधान हो जायेगा।

श्री अध्यक्षः माननीय सदस्य।

श्री रतन देवासी (रानीवाड़ा): माननीय अध्यक्ष महोदय, लगभग सारी बातें आ गयी हैं। माननीय मंत्री जी ने जो कहा है, रिकॉर्ड पर वही है और प्रक्रिया भी, जिन-जिन दिनांक का इन्होंने बताया है, वह दिनांक से जिला प्रशासन जोधपुर और रेलवे के जो सीनियर कमर्शियल मैनेजर हैं, उन लोगों के बीच में वही पत्राचार हुआ है।

इस सम्बन्ध में मेरे दो ही निवेदन हैं, बाकी लगभग सारी बातें आ गयी हैं। प्रथम तो भारत सरकार को आपने लिखा है। चूंकि आप संसदीय कार्य मंत्री भी हैं, आपने इस सम्बन्ध में सभी विभागों से राजस्थान में बात करते हुए इस मामले को आप यहां तक लाये हैं। दूसरा इस सम्बन्ध में मैं रेल मंत्री जी के कार्यालय में मिला और जो स्थानीय सांसद हैं, जो केन्द्रीय मंत्री हैं, उन्होंने भी मेरे सामने वहां बात की थी। उनको मैंने ज्ञापन दिया था। उनका भी धन्यवाद, आप लोगों का भी। इस मसले कि ताकि आन्दोलन नहीं हो, यह ठीक-ठाक हो जाये, उसके लिए आप सबने प्रयास किया।

बस एक ही निवेदन है। चूंकि भारत सरकार का रेलवे विभाग यही कह रहा है कि रेवेन्यू रिकॉर्ड देख लो। रेवेन्यू रिकॉर्ड देख लिया, जिला प्रशासन जोधपुर ने उसको बता दिया कि यह रहा है और इसको एक शब्द होना चाहिए। रेलवे के कमर्शियल मैनेजर ने भी जून-जुलाई की चिट्ठियों में यही मांगा था, वह भी उन्होंने उनको दे दिया है। भारत सरकार के जो वरिष्ठ अधिकारी, जिनको मैं रेल मंत्री के हवाले से मिला था, उन्होंने यह कहा है कि हमको जैसे ही राजस्थान सरकार प्रस्ताव भेजेगी, हम यहां से उस प्रस्ताव को वापस लौटा देंगे, क्योंकि नाम का शुद्धिकरण हो, त्रुटि हो, उसको ठीक करना है या नाम चेंज करना है, उसका राज्य सरकार प्रस्ताव भेजेगी, तब भी हम उसको करेंगे। चूंकि यह इतिहास से जुड़ी हुई बात है, इतिहास से जुड़ी थी। जैसे कि कई समाजों की भावनाओं के अनुरूप होता है, ऐसा एक इतिहास उसका वहां रहा है और इतिहास के पीछे इस नाम को दिया गया था।

मैं एक ही निवेदन करता हूं कि आप स्पेशल आफिसर ओ.आई. बनाकर उनको इस संवाद के लिए कि पत्र भारत सरकार के रेलवे विभाग को चला जाये और वहां से जल्दी आ जाये, बस आप इतनी घोषणा कर देंगे तो मैं समझता हूं कि ये सारी बातें ठीक हो जाएंगी। आपका आभार, धन्यवाद।

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय कार्य मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, रानीवाड़ा से आने वाले माननीय सदस्य की भावना सही है और कथन भी सही है। एक समाज के नाम से जुड़ा हुआ विषय भी है। भावनात्मक विषय भी है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि राजस्थान सरकार इस सम्बन्ध में इस लिपिकीय त्रुटि को ठीक करने के लिए भारत सरकार से सम्पर्क कर, रेलवे विभाग से सम्पर्क कर यथाशीघ्र इसका समाधान करायेगी और समाज से मेरी अपेक्षा है कि यह लिपिकीय त्रुटि है, इसमें आन्दोलन की आवश्यकता नहीं। राजस्थान सरकार पूरी व्यवस्था करेगी और समाज की भावना के साथ है।

श्री अध्यक्ष: सदन की मेज पर रखे जाने वाले पत्रादि, वार्षिक प्रतिवेदन। श्री सुरेश सिंह रावत।

सदन की मेज पर रखे गये पत्र

प्रतिवेदन एवं लेखे

राज्य बांध सुरक्षा संगठन का द्वितीय वार्षिक प्रतिवेदन (वर्ष 2023-24)

श्री सुरेश सिंह रावत (जल संसाधन मंत्री): अध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति से बांध सुरक्षा अधिनियम, 2021 की धारा-45 (1) के अन्तर्गत राज्य बांध सुरक्षा संगठन का द्वितीय वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2023-24, सदन की मेज पर रखता हूं।

श्री अध्यक्ष: समिति के प्रतिवेदनों का उपस्थापन, श्री हमीर सिंह भायल।

समिति प्रतिवेदन

याचिका समिति के प्रतिवेदन (क्रम संख्या 1 से 8)

श्री हमीर सिंह भायल (सिवाना): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से कार्य सूची में किये गये उल्लेख के अनुसार याचिका समिति, 2024-25 के निम्न प्रतिवेदनों का

उपस्थापन करता हूं:-

(1) जल संसाधन विभाग से संबंधित समिति को प्राप्त याचिकाओं के संबंध में प्रथम प्रतिवेदन;

(2) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग से संबंधित समिति को प्राप्त याचिकाओं के संबंध में द्वितीय प्रतिवेदन;

(3) उच्च शिक्षा विभाग से संबंधित समिति को प्राप्त याचिकाओं के संबंध में तृतीय प्रतिवेदन;

(4) परिवहन विभाग से संबंधित समिति को प्राप्त याचिकाओं के संबंध में चतुर्थ प्रतिवेदन;

(5) सार्वजनिक निर्माण विभाग से संबंधित समिति को प्राप्त याचिकाओं के संबंध में पंचम प्रतिवेदन;

(6) नगरीय विकास विभाग से संबंधित समिति को प्राप्त याचिकाओं के संबंध में षष्ठम प्रतिवेदन;

(7) सिंचाई विभाग से संबंधित समिति को प्राप्त याचिकाओं के संबंध में सप्तम प्रतिवेदन; एवं

(8) चिकित्सा शिक्षा विभाग से संबंधित समिति को प्राप्त याचिकाओं के संबंध में अष्ठम प्रतिवेदन;

श्री अध्यक्ष: याचिकाओं का उपस्थापन। श्री रविन्द्र सिंह भाटी।

याचिका

राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, लाबराऊ, उपखण्ड रामसर में शिक्षकों की नियुक्ति

श्री रविन्द्र सिंह भाटी (शिव): अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से कार्य सूची में किये उल्लेख के अनुसार राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय लाबराऊ उपखण्ड रामसर में शिक्षकों की नियुक्ति के संबंध में एक याचिका का उपस्थापन करता हूं।

श्री अध्यक्ष: श्री रुपिन्द्र सिंह कुन्नर।

सतीरामपुर ग्राम पंचायत (डूंगरपुर) के कतिपय क्षेत्रों में नवीन डामर सड़क का निर्माण

श्री रुपिन्द्र सिंह कुन्नर (करणपुर): अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से कार्य सूची में किये गये उल्लेख के अनुसार ग्राम पंचायत सतीरामपुर पंचायत समिति डूंगरपुर में पावर हाउस से जाहेला फला मरता/बदा के घर के पीछे गुमानपुरा मेन रोड़ तक नवीन डामर सड़क निर्माण की स्वीकृति के संबंध में एक याचिका का उपस्थापन उपस्थान करता हूं।

श्री अध्यक्ष: श्री कैलाश चन्द वर्मा।

बगरू में नन्दपुरी चौराहे से जगतपुरा तक योजनानुसार सेक्टर रोड का निर्माण

श्री कैलाश चन्द वर्मा (बगरू): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से कार्य

सूची में किये गये उल्लेख के अनुसार बगरू विधान सभा क्षेत्र स्थित नन्दपुरी चौराहे से जगतपुरा तक सेक्टर रोड को अनुमोदित योजनानुसार 80 फीट किये जाने के संबंध में एक याचिका का उपस्थापन करता हूं।

श्री अध्यक्ष: श्री भगवान राम सैनी।

उदयपुरवाटी के गुढा गौड़जी में उपखण्ड कार्यालय की स्थापना

श्री भगवाना राम सैनी (उदयपुरवाटी): अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से कार्य सूची में किये गये उल्लेख के अनुसार उदयपुरवाटी के गुढा गौड़जी में उपखण्ड कार्यालय खोलने के संबंध में एक याचिका का उपस्थापन करता हूं।

श्री अध्यक्ष: सुश्री नौक्षम।

कामां में अवैध खनन पर अंकुश

सुश्री नौक्षम (कामां): अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से कार्य सूची में किये गये उल्लेख के अनुसार कामां में अवैध खनन पर अंकुश लगाये जाने के संबंध में एक याचिका का उपस्थापन करती हूं।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्यगण, आज दो महत्वपूर्ण विषय हैं। पेयजल पर कल भी चर्चा हुई है, लेकिन उसमें जो रह गया था, ऐसा तय हुआ था, उसकी चर्चा अपन अभी करेंगे। उसके बाद हमारे पी.एच.ई.डी. मंत्री उसका उत्तर देंगे। उसके बाद बिजली पर चर्चा होगी, फिर बिजली के मंत्री। दोनों दलों की ओर से सूची आ गयी है। सूची में जो समय इनके सचेतकों ने दिया, उसका हम अक्षरतः पालन करें। अपने को 9 बजे तक सदन, आज शुक्रवार भी है, 9 बजे तक आज सदन चलेगा, उसके पहले-पहले सब लोग बोल भी लें और मंत्रियों के उत्तर भी आ जायें, इसलिए हम सब लोग समय का पालन करेंगे।

श्री संदीप शर्मा।

राज्य में पेयजल की स्थिति पर विचार

श्री संदीप शर्मा (कोटा दक्षिण): माननीय अध्यक्ष जी, आपका आभार, आपने मुझे जल जैसे गंभीर विषय पर बोलने की अनुमति प्रदान की है। माननीय अध्यक्ष जी, कल भी जल पर चर्चा थी। जैसे प्रतिपक्ष के साथी, जो हमारी आठ महीने की सरकार है, उस पर आरोप-प्रत्यारोप लगा रहे थे। उन्होंने पांच साल सरकार में रहकर काम किया। आवश्यकता थी कि उनकी जो कमियां- खामियां थीं, कुछ सुझाव जल जैसे गंभीर विषय पर वे देते तो निश्चित रूप से राजस्थान प्रदेशवासियों का भला होता। परन्तु आपने जिस तरीके का, कल-कल मैं देख रहा था कि 15-15 मिनट आरोप-प्रत्यारोप के अलावा आप कुछ नहीं बोले। जनता बड़ी अपेक्षा भरी निगाहों से हमारी और देखती है। वह चाहती है कि कुछ न कुछ अच्छा हम इस सदन से करके जायें, जिससे कामों की अच्छी क्रियान्विति हो सके।

आज राजस्थान में देखें तो बहुत बड़ा भू-भाग, जो पूरे देश का सबसे बड़ा भू-भाग राजस्थान है, लगभग 110 देशों के क्षेत्रफल से भी अधिक हमारे राजस्थान का हमारा भू-भाग पानी की कमी से जूझ रहा है। माननीय अध्यक्ष महोदय, यही कारण है कि हमारे मारवाड़

और शेखावाटी के लोग पलायन करके अन्य प्रदेशों में जाकर अपना जीवनयापन कर रहे हैं। परन्तु हम जल की कमी से आज भी नहीं उबर पा रहे हैं।

कल भू-जल संरक्षण पर विधेयक था। बहुत इम्पोर्टेंट विषय था, क्योंकि जिस तरीके से भू-जल का लगातार दोहन हो रहा है और साथ ही साथ भू-जल के संरक्षण के लिए हम लोग कोई प्रयास नहीं कर पा रहे हैं। हमने जो हार्वेस्टिंग सिस्टम लागू किये थे, वे पूरी तरह से फेल हो गये, नगर निकाय भी उसमें सक्षम नहीं हो पाये कि जो जल बरसात का आता है, उसको पुनः कैसे भू-गर्भ में भेजा जाये। क्योंकि यह भी बहुत आवश्यक विषय है कि जो अभियान हैं, योजनाएं हैं, उसके साथ-साथ हमारे राजस्थान के भू-जल की स्थिति है, हमारे जो ब्लॉक्स हैं, वे लगातार डार्क जोन बनते जा रहे हैं।

mdp/rtm/02.08.2024/13:20/1p

आज हमें आवश्यकता है, क्योंकि राजस्थान हमारा, जहां उत्तर पश्चिम राजस्थान में मरू प्रदेश जिसे हम थार का रेगिस्तान कहते हैं, पूर्व में हम देखें तो हाड़ौती एकमात्र ऐसी जगह है, जहां पानी की थोड़ी उपलब्धता है। परंतु जयपुर, अजमेर, जोधपुर और जैसलमेर में तो यह स्थिति है कि भू-जल वैज्ञानिकों के अनुसार 2025 तक जो स्थिति केपटाउन और बैंगलोर की हुई है, जहां भू-जल स्तर खतम हो गया और पेयजल के लिए हम या तो भू-जल पर या बांधों का जल या नदी का पानी या बरसात के जल को फिल्टर करके प्राप्त कर सकते हैं। पानी की कमी से हम जूझ रहे हैं। हमारे माननीय प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी जी ने इन कमियों को देखते हुए ऐसे जो भौगोलिक प्रदेश हैं, उनमें जल जीवन मिशन की योजना वह लेकर आए। हमारे राजस्थान में भी पिछले 2018 से 2023 तक ये योजना चली। लेकिन अफसोस कि जो काम हमें घर-घर पेयजल पहुंचाने के लिए जल जीवन मिशन योजना में करना चाहिए था, ये जो इतिहास लिखने वाली एक योजना थी, इसको आपने धूल में मिला दिया।

अध्यक्ष महोदय, देश में 14 हजार 133 आवासीय क्षेत्रों में फ्लोराइड युक्त भू-जल की अधिकता है। इनमें से आधे से भी अधिक 7670 आवासीय क्षेत्र ऐसे हैं जो राजस्थान के अन्दर हैं। इसमें 40 लाख से भी अधिक लोग फ्लोराइड युक्त पानी पीने के लिए मजबूर है। फ्लोराइड किस तरह से हमारी हड्डियों को गला रहा है, हमारे जोड़ों को खराब कर रहा है, फिर भी हम गंभीर नहीं। राजस्थान की इस कमी को देखते हुए भी आपका दिल नहीं पसीजा और जल जीवन मिशन में, हालांकि मैं, लेकिन ये वास्तविकता है कि किस तरीके का भ्रष्टाचार उस जल जीवन मिशन में हुआ। एक तरफ तो आपके नेता जी वहां मुहब्बत की दुकान चलाते रहे, दूसरी तरफ यहां भ्रष्टाचार की दुकान खोल ली। ...(व्यवधान)... ऐसी भ्रष्टाचार की दुकान आप सुन नहीं पाएंगे, माननीय सदस्य, क्योंकि इतने टेंडर हुए, सब फर्जी टेंडर, दस्तावेजों के आधार पर मिले।

श्री अध्यक्षः आप बोलिए। आपका भी नंबर आएगा, आप तब बोलना।

श्री संदीप शर्मा (कोटा दक्षिण): माननीय अध्यक्ष महोदय, जलदाय विभाग के मुख्य

अभियंता के यहां फर्जी अनुभव प्रमाण पत्र बनाकर दो फर्मों को 900 करोड़ का ठेका दे दिया। मंत्री के करीबी +++ जो जेजेएम के ठेकेदार हैं, 5 करोड़ की रिश्वत लेते हुए पकड़ा। 5 करोड़ की रिश्वत ठेकेदार ने किसके लिए दी, यह तो भगवान जाने। आपने छिपाने की कोशिश की, लेकिन ईडी ने आकर आपके सारे काले कारनामों को खोल दिया। प्रशासनिक अधिकारियों के घर पैसे मिल रहे हैं। सोने की ईटें मिल रही हैं। अफसरों, दलालों के घर पैसे मिल रहे हैं, मंत्री जी के घर पैसे मिल रहे हैं। सरकारी दफ्तर में कैश और सोना मिल रहा है। सरकारी फाइल ठेकेदार के यहां मिल रही हैं। कबाड़ से पाइप लाइन लाकर जेजेएम की योजना में बिछा दिया। वह भी कोई बात नहीं, उसमें भी तसल्ली कर लें, परंतु वहां से चोरी करके, माननीय अध्यक्ष महोदय, चोरी करके ले आए और जाकर यहां पर जेजेएम के मिशन में बिछा दी। ...(व्यवधान)... इतना भयंकर भ्रष्टाचार।

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): अध्यक्ष जी, मैंने कल भी एक बात कही थी। बिजली, पानी पर गंभीर विषय है। आज भी मात्र दो ही मंत्री हैं। आपका पूरा कोरम अभाव में अभी दो ही मिनट में हो जाएगा। आप थोड़ा इस चीज को, आप, संसदीय मंत्री महोदय, मेरी बात को गंभीरता से लें। आप नाराज मत होइए। अध्यक्ष जी, आप खुद देख लीजिए आठ-दस लोग सत्ता पक्ष के हैं। सत्ता पक्ष क्या चाहता है? मंत्री हैं नहीं, सचेतक हैं नहीं?

श्री अध्यक्ष: मंत्री बैठे हैं। पेयजल मंत्री बैठे हैं।

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): पेयजल के ही है बस।

श्री अध्यक्ष: विषय पेयजल का है।

श्री संदीप शर्मा (कोटा दक्षिण): मेरा समय मत काटिए, माननीय नेता प्रतिपक्ष।

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय कार्य मंत्री): मंत्री बैठे हैं। पेयजल का और सरकार का प्रतिनिधि बैठा है, फिर क्या चाहिए आपको।

श्री अध्यक्ष: चलिए, आज समय कम है। ...(व्यवधान)... आपको क्या हो गया? विराजिए।

श्री विद्याधर सिंह (फुलेरा): आप वही बैठ जाइए।

श्री अध्यक्ष: आप बैठ जाइए। विराजिए।

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय कार्य मंत्री): आप बैठिए। हमेशा अनर्गल बातें करते हैं। ...(व्यवधान)... आपको, माननीय सदस्य, न तो कुछ पता है और यहां बैठ जाइए, वहां बैठ जाइए, समय आने पर वहां भी बैठ जाएंगे, आपको पूछ कर नहीं बैठेंगे। आपको बोलने का अधिकार नहीं है। ...(व्यवधान)... बोलना सीख लीजिए पहले।

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी।

श्री संदीप शर्मा (कोटा दक्षिण): अध्यक्ष महोदय, इस बार भ्रष्टाचार की ऐसी पराकाष्ठा कि इन्होंने भ्रष्टाचार में अपने सारे पुराने रिकॉर्ड तोड़कर इन पांच सालों में नये कीर्तिमान स्थापित किए। मैं बताना चाहूंगा कि प्रदेश में 1 करोड़ 6 लाख 99 हजार 741 घर, जल जीवन मिशन में आपको 92 लाख 11 हजार घरों तक पानी पहुंचाना था, परंतु आपके कुप्रबंधन, लापरवाही

और भ्रष्टाचार में कितने लगे? चार साल में मात्र 52 लाख 8 हजार 511 घरों तक आप नल पहुंचा पाए, लेकिन उनमें पानी नहीं पहुंचा पाए, क्योंकि स्रोत आपने नहीं ढूंढे। इसलिए सिर्फ आप नल लगाकर रह गये।

मैं कोटा संभाग की बात करूं तो कोटा में तीन साल में आपका लक्ष्य 8 हजार 503 करोड़ का बजट आपने स्वीकृत किया, 8 लाख 21 हजार 589 कनेक्शन देने का लक्ष्य आपको निर्धारित किया। इसमें से लगा कितने पाए, 3 लाख 50 हजार 80 कनेक्शन आप जारी कर पाए। इस योजना में 34 राज्य चिह्नित किये गये। इनमें केन्द्र शासित प्रदेश भी थे। आपका कौनसा नंबर रहा जल जीवन मिशन में? आपका 33वां नंबर था, आखिरी पायदान से 33वें नंबर पर राजस्थान को आप लेकर आए और आप कहते हैं हमने क्या किया? अफसोस की बात। राजस्थान में तो हमें बहुत आवश्यकता थी जल की, इतनी भारी कमी है। भू-जल स्तर गिरता जा रहा है। लगातार डार्कजोन में हमारे ब्लॉक आते जा रहे हैं, फिर भी कोई असर नहीं, कोई संवेदनशीलता नहीं। महिलाएं 5-5 किलोमीटर से पानी सिर पर उठाकर मटके भर-भर कर ला रही हैं। फिर भी कोई संवेदनशीलता नहीं।

अध्यक्ष जी, पहला बजट पास हुआ है। आगे आने वाले समय में देख लेना एक साल के अन्दर लक्ष्य की पूर्ति कैसे करेंगे। माननीय मुख्य मंत्री जी ने 15 हजार करोड़ की लागत से 5 लाख ग्रामीण परिवार, शहरी परियोजनाओं में 1784 करोड़, ग्रामीण पेयजल परियोजनाओं में 2400 करोड़, 20 हजार करोड़ में 6 बड़ी परियोजनाएं, प्रदेश में 5840 गांवों में पेयजल उपलब्ध कराने का यह सिर्फ अभियान नहीं, संकल्प पत्र के साथ काम करने वाला विजन, यह आप देखना कि किस तरीक से, शहरी क्षेत्रों में भी 5180 करोड़ से पेयजल के कार्य कराएं जाएंगे, उपलब्धता करायी जाएगी।

अध्यक्ष जी, कोटा शहर की बात करना चाहत हूं। (समय समाप्ति सूचक घंटी) कोटा यूं तो सदा नीरा चम्बल नदी के किनारे बसा हुआ है। परंतु 510 एमएलडी।

श्री अध्यक्षः वाइंड अप कीजिए।

श्री संदीप शर्मा (कोटा दक्षिण): मेरे दो मिनट तो ये खा गये साहब।

श्री अध्यक्षः दो मिनट में वाइंड अप कीजिए। जो समय है, उसमें कीजिए।

श्री संदीप शर्मा (कोटा दक्षिण): कोटा में 510 एमएलडी, मंत्री महोदय, आप बैठे हुए हैं, 510 एमएलडी पानी उत्पादित होता है इनटेक वेल से। परंतु फिर भी चम्बल नदी के किनारे हाहाकार है। अधिकांश कॉलोनियों में हम चम्बल का पानी नहीं दे पा रहे। मल्टी स्टोरी में पानी नहीं दे पा रहे। वहां फ्लोराइड युक्त पानी पी रहे हैं। हालात ये हैं कि ले देकर जब भी देखते हैं, पिछले साल भी जितना काम हुआ, वह पुनः जितनी भी डीपीआर अमृत योजना की बनी, उसमें ले देकर फिर वही इनटेक वेल, जबकि आवश्यकता थी कि हम डिस्ट्रीब्यूटरी पर भी काम करते।

मैंने कई बार इस विधान सभा में प्रश्न लगाया और बार-बार आपके विभाग ने ये उत्तर दिया है कि 40 से 50 प्रतिशत पानी छीजत में बह जाता है। उस छीजत वाले पानी को क्यों

नहीं रोका जाता? यह आवश्यकता है कि वह छीजत का पानी, हो सकता है कि बड़े इनटेक वेल बनाने में ठेकेदारों को फायदा हो, परंतु ये सरकार उस फायदे को देख सकती है। आज हमको इस बात को देखना है कि हमारी डीपीआर में लोगों को हम कितना अधिक से अधिक पानी पहुंचा सके।

चम्बल के किनारे ये स्थिति है कि जो मेरी विधान सभा के क्षेत्र हैं, वहां पर महावीर नगर, तलवंडी, दादाबाड़ी, विज्ञान नगर, शिवपुरा ऐसे सारे क्षेत्र जिनमें पानी की लगातार कमी बनी हुई है। वहां पर देखने की आवश्यकता है कि किस तरीके से हम उन पाइप लाइनों को ठीक कराएं। (समय समाप्ति सूचक घंटी) माननीय अध्यक्ष महोदय, बस एक मिनट में अपनी बात समाप्त कर रहा हूं।

श्री अध्यक्ष: तीस सेकण्ड में।

श्री संदीप शर्मा (कोटा दक्षिण): जिस तरीके से कुछ उच्च जलाशय बनाने की आवश्यकता थी।

श्री अशोक (हिण्डोली): हमें भी तीन मिनट मिलेंगे।

श्री अध्यक्ष: जो समय दिया है, उससे एक मिनट भी ज्यादा नहीं दूंगा। जितना समय आपकी पार्टी ने दिया है, उतना ही दूंगा।

श्री संदीप शर्मा (कोटा दक्षिण): कुछ स्थानों पर सुभाष नगर, दीनदयाल नगर, बालाकुड और महावीर नगर, नई डीपीआर वहां बने और नई डीपीआर में इन सारी चीजों को देखते हुए पानी की उपलब्धता को सुनिश्चित किया जाए, जिससे कोटा जैसी जगह वहां पर लोग फ्लोराइड पानी नहीं पीएं। सदा नीरा चम्बल नदी है, जो एक-तिहाई राजस्थान को पानी पिला सकती है।

Ans/rtm 13.30 1q 02.08.2024

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, हो गया।

श्री संदीप शर्मा (कोटा दक्षिण): उस चम्बल नदी के किनारे प्यासे नहीं रहे। माननीय अध्यक्ष जी, बहुत-बहुत आभार। बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: श्री टीकाराम जूली।

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): माननीय अध्यक्ष महोदय, बिजली और पानी दोनों ही बहुत गंभीर विषय थे, जिनको आपने सदन में चर्चा के लिए रखा, उसके लिए आपका आभार।

ऑस्ट्रेलिया के मशहूर क्रिकेटर हुए थे स्पिनर शेन वार्न। जब एक बार पूछा गया कि सचिन तेंदुलकर के बारे में आप क्या सोचते हैं, तो कहा कि सचिन तेंदुलकर मेरे सपने में आता है। आज स्थिति ऐसी हो रही है कि आपके जितने भी सदस्य हैं, उनके सपने में टीकाराम जूली आता है। हर चीज में नेता प्रतिपक्ष को जोड़ते हैं।

(समयः बजे)

(श्री अर्जुन लाल जीनगर, सभापति, पदासीन)

श्री जोगेश्वर गर्ग (सरकारी मुख्य सचेतक): आपको बहुत ग़लतफ़हमी है। आपको निपटाने के लिए आपके लोग ही बहुत हैं, हमारी जरूरत ही नहीं है।

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): पानी का बहुत गम्भीर विषय है।

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय कार्य मंत्री): माननीय प्रतिपक्ष के नेता, हमको सपने में किसी रूप में आते हैं, यह आपको ध्यान है। ...(व्यवधान)...

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): कोई बात नहीं, आना चाहिए।

श्री श्रीचन्द कृपलानी (निम्बाहेड़ा): हमारे सपने में डोटासरा जी आते हैं कि कहीं कब्जा नहीं कर ले।

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): सभापति जी, यह मेरा टाइम ले रहे हैं।

श्री सभापतिः आप कंटीन्यू करें।

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): सबसे पहले तो यह कहना चाहूंगा कि आप जे.जे.एम. की बात कर रहे हो कि हमारे प्रधानमंत्री जी की घोषणा है और वह पैसे दे रहे हैं। एक चीज स्पष्ट करना चाहूंगा। मैं यह दावे के साथ कह रहा हूं, दिल्ली के अन्दर जब मनमोहन जी की सरकार थी, हमारी सरकार थी, उस समय पानी का जो पैसा दिल्ली से आता था वह 90 परसेंट पैसा भारत सरकार देती थी और 10 परसेंट पैसा राजस्थान सरकार देती थी। घर-घर नल पहुचाऊंगा का दावा करने वाले प्रधानमंत्री जी और 25 के 25 राजस्थान के सांसद होने के बावजूद, राजस्थान के जल शक्ति मंत्री होने के बावजूद, जो पैसा पहले 90 परसेंट मिलता था, वह पैसा आज 45 परसेंट कर दिया है, इस बात में गलती हो तो मंत्री जी आप बता देना। यह तो आपका घर-घर नल का मिशन है, उसकी सच्चाई है।

दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा कि आप पानी के बड़े-बड़े दावे कर रहे हैं। माननीय स्पीकर साहब चले गए, खुद अध्यक्ष जी ने कहा कि अजमेर के अन्दर 4-4 दिन में पानी आ रहा है, यह आपके दावे की पोल खुल रही है। मैं बात करना चाहूंगा, प्रदेश के अंदर पहली बार ऐसा हुआ है, अलवर के अन्दर, किसी बुजुर्ग एडवोकेट ने पानी नहीं मिलने की वजह से सुसाइड कर लिया, यह हमारे लिए शर्म की बात है।

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय कार्य मंत्री): आपके टाइम हुआ है। हमारे टाइम कोई नहीं करेगा।

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): आपके टाइम का है। यह ऐसे अंगुली घुमाने से पता नहीं चलेगा। जो सच्चाई है वह समझनी पड़ेगी। आपके जवाब में बता देना। यह भी बता देना कि अलवर में गंदा पानी आने की वजह से पीलिया फैल गया। एक व्यक्ति की मौत हो गई और काफी लोग हॉस्पिटल में एडमिट रहे। यह सिर्फ एक अलवर की बात नहीं है, पूरे प्रदेश का यही हाल है।

मैं अगर अलवर की बात करूं। कोई ऐसा दिन नहीं जाता होगा, जहां पानी के लिए

अलवर में धरना नहीं होता हो, अलवर ग्रामीण के अन्दर धरना नहीं होता हो। कलक्टर को अलग टेंट लगाना पडा, सिर्फ पानी की जन सुनवाई के लिए और पुलिस लगा दी कि जो पानी की समस्या वाले लोग हैं उनको अन्दर मत आने दो, उनको इस टेंट में बिठा दो। सभापति महोदय, उस टेंट के अन्दर भी उन लोगों को पीने का पानी नहीं मिला, यह इस सरकार की बात मैं आपको बताना चाहता हूं। रहीम जी का एक दोहा है।

"रहिमन पानी राखिये, बिन पानी सब सून
पानी गए न ऊबरे, मोती, मानुष, चून"

आपकी सरकार बनी, आपके पास पानी की, बिजली की चुनौती थी। आप दोनों ही मुद्दों पर फेल रहे। देश में एक नारा भी लगता है, बिजली पानी दे न सके, वह सरकार निकम्मी है, जो सरकार निकम्मी है, वह सरकार बदलनी है। यह जनता ने तय कर लिया है ...(व्यवधान)... माननीय सभापति महोदय, यह लोग जो मेरी स्पीच पर चिल्ला रहे हैं, इन्हीं में से 50 लोगों ने मुख्य मंत्री जी को लैटर लिखकर कहा कि हमारे क्षेत्र में पानी की भयंकर समस्या है, आप उस चीज को कैसे झुठला पाएंगे, मैं यह बात कहना चाहूंगा। आप मानते नहीं है, यह सच्चाई है, हकीकत है। अभी बिजली पर आऊंगा, जब भी बताऊंगा एक हकीकत जो सीएम साहब के डिनर पर हुई, वह भी मैं बताना चाहूंगा।

आपके मंत्री जी यहां मौजूद हैं। मंत्री जी ने कह दिया कि मैं कोई बालाजी थोड़े ही हूं, जो फूंक मार कर पानी ला दूं।

श्री कन्हैयालाल (जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री): बालाजी से ही आई है बरसात। ...(व्यवधान)...

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): यह उस बरसात का पानी भी नहीं सहेज पा रहे। यह राजस्थान सरकार का पानी वाला मंत्री अगर यह कहें कि मैं बालाजी थोड़े ही हूं जो फूंक मार कर पानी ला दूं, तो पानी लाएगा कौन? जनता ने जिम्मेदारी दे दी, सरकार बना दी, डबल इंजन की बना दी। अब तो कई इंजन हैं, ट्रिपल इंजन भी है आपका। अभी रहने दो जोगाराम जी, आप बाद में बोल देना, मैं आपकी पूरी बात सुनूंगा। आप पानी क्यों नहीं दे पा रहे, यह आपकी स्थिति है जो हकीकत है। इसमें मंत्री जी का जो बयान आया, उसमें वह असहाय, निराश नजर आ रहे हैं कि वह पानी की व्यवस्था नहीं कर पा रहे, यह बात मैं आपको कहना चाहूंगा। नहीं तो आप कहते कि बालाजी ने मुझे यह ताकत दी है कि मैं राजस्थान सरकार का जलदाय मंत्री हूं, पूरी व्यवस्था करवाऊंगा चिन्ता मत करिये, जब तो कोई बात होती।

मैं आपको कहना चाहूंगा, जिस जिम्मेदारी से आप बच रहे हा ना, उसी पर इरतिजा निशात की ओर से एक शेर प्रस्तुत करता हूं।

"कुर्सी है तुम्हारा यह जनाजा तो नहीं है,
कुछ कर नहीं सकते तो उतर क्यों नहीं जाते,"

यह बात मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा।

आज इतनी जल्दी टाइम नहीं हुआ है। टाइम हमारा है। यह घड़ी मत दिखाओ, सभापति

जी पर प्रेशर मत डालो, पूरी बात सुननी पड़ेगी।

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय कार्य मंत्री): आप वहमी हो, आप इतने वहमी क्यों हो।

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): हमारी सरकार थी, हमारे मुख्य मंत्री जी, हर बार जनवरी-फरवरी में मीटिंग करते थे। आप भी कर लेना। कंटिंजेंसी प्लान तैयार होता था, कलक्टर्स को पावर दिये जाते थे। डिपार्टमेंट की तरफ से हैण्डपम्प, ट्यूबवैल दिए जाते थे, टैंकर दिए जाते थे। आपने करा ही नहीं। आज हालत यह है कि 70 परसेंट राजस्थान डार्क जोन में है। मैं बता दूंगा कितने कराए। कराए होते तो आप लोगों के कपड़े नहीं फटते। ...(व्यवधान)... जो पूरे प्रदेश में फटने लग रहे हैं। प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं है। अगर पानी आता ना, तो मुख्य मंत्री पम्प हाउस चेक करने नहीं जाता। अगर पानी आता तो मुख्य मंत्री को पम्प हाउस चेक नहीं करना पड़ता, यह आप लोगों की हालत है। ...(व्यवधान)... मुख्य मंत्री पम्प हाउस चेक करते घूम रहे हैं। मुख्य मंत्री तक को पम्प हाउस चेक करना पड़ रहा है। आप कब तक छिपाओंगे। आप कब तक इन चीजों को छिपाओंगे रहिमन पानी राखिये, बिन पानी सब सून

पानी गए न ऊबरे, मोती, मानुष, चून

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय कार्य मंत्री): सीएम खुद जाते हैं ...(व्यवधान)...

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): मुख्य मंत्री पम्प हाउस चेक करते घूम रहे हैं। मुख्य मंत्री तक को पम्प हाउस चेक करना पड़ रहा है।

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय कार्य मंत्री): आपकी तरह ऐशो आराम नहीं करते होटलों में ...(व्यवधान)...

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): आपके मुख्य मंत्री जी ने कहा कि हमने हरियाणा से कभी बात नहीं की, यमुना जल समझौतें में लैटर नहीं लिखा। आप कह रहे हो। मुख्य मंत्री जी भले आदमी है, अधिकारी जो लिखकर देते हैं बोल देते हैं। मैं बता रहा हूं आपको।

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय कार्य मंत्री): जो तथ्य है वह सत्य है।

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): हमारे पूर्व मुख्य मंत्री अशोक जी गहलोत के द्वारा और हरियाणा के पूर्व मुख्य मंत्री ओमप्रकाश चोटाला के द्वारा यमुना का पानी जो झुन्झुनू फीडर में आना था.. (समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

अभी तो शुरू ही हुआ है, अभी कहां।

श्री सभापति: आपको जो समय अलॉट किया है आपकी पार्टी ने। आपने ही अलॉट किया है।

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): टाइम है। ...(व्यवधान)... टाइम मैंने ही दिया है।

श्री सभापति: आपने ही दिया है।

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): मैं यह सारा टेबल कर दूंगा।

श्री सभापति: आपने समय दिया, मैं वही बता रहा हूं।

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): आप बात सुनिए। सभापति जी, हमारे संसदीय कार्य

मंत्री के कहने से मत चलो, थोड़ी बहुत हमारी भी मान लो।

VPS-RTM-02.08.202-13.40-2a

श्री सभापतिः आपने ही यह समय दिया है, मैंने थोड़े ही दिया है।

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): क्योंकि मुख्य मंत्रीजी ने जो यह बात कही थी न कि ...(व्यवधान)...

श्री सभापतिः सारा समय आपने ही लिखकर दिया है।

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): मुख्य मंत्रीजी ने जो बात कही थी, मैं उसको टेबल कर दूंगा। ठीक है? जो लैटर है, वह टेबल कर दूंगा। मुख्य मंत्रीजी तक वह बात चली जाये कि वहां इस सदन के अन्दर आप जो चीज बोल रहे हैं न वह सोच-समझकर, पढ़कर उसके बाद बोलें, यह बात मैं कहना चाहूंगा।

आज पानी की जो स्थिति बन रही है, आप भ्रष्टाचार की बात कर रहे थे जीरो टॉलरेंस की तो अलवर के अन्दर जिन्होंने जे.जे.एम. के अन्दर भ्रष्टाचार किया, किसी फैक्टरी के लिए स्पेशल बताया तो उन लोगों को हमने सस्पेंड किया और आप लोगों ने बहाल कर दिया, यह आपका भ्रष्टाचार के विरुद्ध जीरो टॉलरेंस है?

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय कार्य मंत्री): जेल में गये।

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): दूसरा मैं आपको यह कहना चाहूंगा कि जल जीवन मिशन को चलाने के लिए आपका जो पूरा विभाग है, उसको आप क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो? उसको प्राइवेट करना चाहते हो, उसको ठेके पर देना चाहते हो?

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय कार्य मंत्री): नियमों से, पारदर्शिता से।

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): ताकि इन पी.एच.ई.डी. के कर्मचारियों को सैलरी तक समय पर नहीं मिल सके, तो यह आप क्यों करना चाहते हो? आप उसको आर.डब्ल्यू.एस.एस.सी. को क्यों देना चाह रहे हो सब कुछ? ताकि यह लोन ले ले, कर्ज ले ले और यह काम चलता रहे। ऐसा नहीं। इस विभाग को, मंत्रीजी, मजबूत करिये। इस विभाग को कमजोर करने का काम मत करिये।

श्री सभापतिः विराजिये। हो गया।

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): पहले इस डिपार्टमेंट के अन्दर कर्मचारी होते थे, पूरा विभाग रहता था, पूरा मैटीरियल रहता था लेकिन आज वह स्थिति नहीं है। आज सब ठेकेदारों पर डिपेंड हो गये और जो बचा हुआ है उसको भी आप प्राइवेट करना चाह रहे हो।

श्री सभापतिः श्री लक्ष्मण राम।

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): यह बात मैं कहना चाहूंगा कि इसके प्राइवेट का अधिकारी विरोध कर रहे हैं, हम भी विरोध करेंगे। यह प्राइवेट नहीं होना चाहिए। यही बात कहता हुआ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। आपने मौका दिया, बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापतिः श्री लक्ष्मण राम।

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय कार्य मंत्री): आज जमा नहीं।

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): जमे या नहीं जमे। मैं सुना दूंगा तो आप ...(व्यवधान)...

श्री लक्ष्मण राम (मेड़ता): माननीय सभापति महोदय, आज बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है, पानी के ऊपर आपने बोलने का मौका दिया है, उसके लिए धन्यवाद। जल ही जीवन है, रहिमन पानी राखिये, बिनु पानी सब सून। माननीय सभापति महोदय, मैं पश्चिम राजस्थान से आता हूं जहां पर सदैव पानी की कमी रही है।

श्री जोगेश्वर गर्ग (सरकारी मुख्य सचेतक): नेता, प्रतिपक्ष तो आखिरी में बोलते हैं। आखिरी में बोलते तो ढंग से समझ में आता। ...(व्यवधान)...

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): ऐसा है कि मैंने जो बोला है न, आपका मंत्री एक-एक शब्द का जवाब दे देना, बस मैं इतना ही चाहता हूं। ...(व्यवधान)...

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय कार्य मंत्री): मंत्री सौ प्रतिशत आपको जवाब दे देंगे। एक लाजवाब जवाब देंगे।

श्री सभापति: श्री लक्ष्मण राम।

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): और जो गलत बात मुख्य मंत्रीजी बोल गये, उसका भी जवाब दोगे क्या? जो मुख्य मंत्रीजी सदन में गलत बोल गये, उसका भी जवाब देंगे क्या? बिना तथ्यों के बोल गये?

श्री जोगेश्वर गर्ग (सरकारी मुख्य सचेतक): आप जवाब सुनकर जाना। पहले मत भाग जाना।

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय कार्य मंत्री): पूरा जवाब तथ्यों सहित, दस्तावेज सहित देंगे।

श्री सभापति: विराजिये। श्री लक्ष्मण राम।

श्री लक्ष्मण राम (मेड़ता): माननीय सभापति महोदय, 80 प्रतिशत मेरा विधान सभा क्षेत्र बरसात पर निर्भर है, तालाबों पर निर्भर है। मैं इस मौके पर, मंत्री महोदय, वे सदन में विराजमान हैं, हमारे कलेक्टर हुआ करते थे सुमितजी शर्मा साहब उस जमाने में, मैं धन्यवाद दूंगा आपको कि आपने मेड़ता की गम्भीर समस्या सुनी, उस टाइम आप वहां पर कलेक्टर थे और तालाबों का आपने बहुत बड़ा, जो चारों तालाब थे मेड़ता के, उनके ऊपर ध्यान दिया और दो तालाब आज भी, ...(व्यवधान)... आज भी मेड़ता 25 परसेंट पानी तालाबों से पीता है तो मैं आपको यह धन्यवाद देता हूं।

जल जीवन मिशन बहुत ही महत्वपूर्ण योजना थी, उसमें भ्रष्टाचार की पराकाष्ठा का सब लोग कह रहे हैं तो मैं यह कहना चाहूंगा, मैं एक ठेकेदार हूं, आप तो भ्रष्टाचार की बात करते हो, अभी टेंडर चलते हैं below में और आपके जमाने में टेंडर हुए थे above में, फिर भी मैं यह कहना चाहूंगा कि एक भी जगह पर सही पानी नहीं पहुंचा है। आज भी हम लोग गांवों में यह देखते हैं कि पाइपों के मुंह खुले पड़े हुए हैं, कहीं पर पानी का अता-पता ही नहीं हैं, सड़कें सारी तोड़ दी गयी हैं, उनका कोई ध्यान नहीं है, तो मैं यह कहना चाहूंगा, मंत्री

महोदय विराजमान हैं, जल जीवन मिशन बहुत बड़ी एक योजना थी और मेरा विधान सभा क्षेत्र मेड़ता और खींवसर उस समय वह फर्स्ट फेज में आया था। उस समय बड़े कस्बों और शहरों तक ही यह सीमित था, फिर माननीय मोदीजी ने इस योजना को बढ़ा दिया और 'हर घर जल और हर घर नल' की योजना दी है। मंत्री महोदय विराजमान हैं मैं आपको कहना चाहूंगा, कलेक्टर साहब भी विराजमान हैं, कमिश्नर साहब। जो पम्प लगे थे, वे पम्प उस समय छोटे थे तो यह मंत्रीजी को नॉलेज में है, तो आप वह पम्प बड़े लगाइये इससे मेरी मेड़ता विधान सभा क्षेत्र को भरपूर पानी मिल सके, यह मेरा आपसे निवेदन है।

कोई भी बड़ी योजना बनती है तो जब वह धरातल पर आती है तो मैं यह कहना चाहूंगा कि मंत्रीजी, आप हेल्परों की भर्ती कीजिए। सबसे बड़ी समस्या जल जीवन मिशन में पानी खोलने वालों की है। जो लोग दो-तीन हजार रुपये मंथली पर लगे हुए हैं, वे गड़बड़ करते हैं, उन पर सरकार का अंकुश नहीं रहता है, तो मेरा आपसे यह निवेदन है कि आप हेल्परों की भर्ती करिये और जो पानी खोलने वाला आदमी अगर सरकारी होगा तो उसमें काफी हद तक समस्या से निजात मिलेगी।

एक बहुत बड़ी समस्या है जल जीवन मिशन में चोरी की। लोग पानी की चोरी करते हैं, खेतों में डिग्गियां भरते हैं, टैंकर बेचते हैं तो मंत्री महोदय, मैं आपसे यह कहना चाहूंगा और मेरा आपसे यह निवेदन है कि आपने जैसे बिजली में थाना अलग से खोला इसी तरह से पानी के लिए भी एकाध थाना अलग से खोलें, कानूनी कार्यवाही से निजात दिलायें। (समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

अभी तो साहब, दो मिनट ही हुए है मेरे को। ऐसे कैसे पूरा हो गया? अभी दो मिनट ही हुए हैं।

एक मैं यह निवेदन करना चाहूंगा आपको, मैं पूरे राजस्थान की बात नहीं करूंगा केवल मेड़ता की ही बात करूंगा। अमृत-2 की योजना बाकी रही है, मंत्री महोदय, मेड़ता में तो मेरी जितनी कॉलोनियां हैं मेड़ता शहर की, उन कॉलोनियों को भी आप अमृत-2 में जोड़ने का काम करें, इससे लोगों को फायदा मिलेगा, यह मेरा निवेदन है आप लोगों से। मैं यह भी कहना चाहूंगा कि उस टाइम में जो योजना बनी तो जन-प्रतिनिधि या कर्मचारियों ने ध्यान नहीं दिया, उसका सर्वे ढंग से नहीं किया और जहां पर टंकियां बननी थीं वहां पर तो बनी नहीं और जहां पर नहीं बननी थी वहां पर यह टंकियां बन गईं तो मेरे क्षेत्र में दो-तीन जगह है, करलू, लूनियास, बारा की ढाणी, वहां पर दो-तीन टंकी बनें, वहां पर बड़ी आबादी है तो आप वहां पर भी टंकियां बनाने का काम करें।

मेरे विधान सभा क्षेत्र के अधिकांश गांवों में भू-जल नीचे चला गया है, पूरे जिले में एक जायका कम्पनी ने सर्वे किया था, पूरा नागौर जिला फ्लोराइडयुक्त है, वहां पर पानी नहीं है, उसमें मेड़ता भी आता है तो तालाबों पर आप ध्यान दें। यह मेरा विशेष निवेदन है कि मेरे मेड़ता विधान सभा क्षेत्र में बड़े-बड़े तालाब हैं, उन तालाबों पर आप ध्यान दें और उन पर अपन पैसा खर्च करेंगे तो काफी हद तक पानी की समस्या मिट सकती है। अरनियाला,

जलवाला, मोररा सहित अनेक गांवों में भू-जल का स्तर काफी नीचे चला गया है। (समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

माननीय सभापति महोदय, मेरा समय काट दिया। आपको बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापतिः श्री अशोक।

श्री अशोक (हिण्डोली): माननीय सभापति महोदय, आपको बहुत-बहुत धन्यवाद कि पानी जैसी गम्भीर समस्या पर आपने मुझे बोलने का मौका दिया और नेता, प्रतिपक्ष और हमारे व्हिप साहब का भी धन्यवाद कि उन्होंने पार्टी के समय में से मुझे समय दिया।

(समयः 13.48 बजे)

(श्री संदीप शर्मा, सभापति, पदासीन)

अपनी बात को शुरू करने से पहले माननीय सभापति महोदय, निम्बाहेड़ा से आने वाले माननीय सदस्य को एक्सपांशन में मंत्री बनाया जाये, विधान सभा में उनका परफॉर्मेंस देखते हुए, यह मेरा आग्रह है आपसे। पिछली सरकार की बात हो रही थी, आसन से यह कहा गया कि पिछली सरकार के जवाब समय से नहीं आये, तो वह सरकार चली गयी और ये भी नहीं दे रहे हैं तो मुझे यह लगता है कि शायद मिनी बस में बैठकर आने वाले हैं और उसी की तैयारी, सदन में इनकी परफॉर्मेंस के हिसाब से मुझे यह लग रहा है। मैं सीधा टॉपिक पर आऊंगा, ज्यादा समय नष्ट नहीं करूंगा।

नेता, प्रतिपक्ष ने यह बताया और पूरे राजस्थान में समाचार पत्रों के माध्यम से यह पढ़ा कि जलदाय मंत्रीजी का एक फेमस डायलॉग आया कि मैं बालाजी थोड़े ही हूं कि मैं फूंक मारूंगा और पानी आ जायेगा। निश्चित रूप से गर्मियों में बड़ी गम्भीर समस्या राजस्थान में हो गयी लेकिन इस बात के अन्दर भी बड़ी मजबूरी सी दिखी लेकिन मैं यह समझ सकता हूं कि क्योंकि इस सरकार के मंत्री ज्यादातर अधिकारियों के सामने मजबूर हैं तो मजबूरी किसी न किसी दिशा में निकलकर सामने आ जाती है, वे बता नहीं पाते हैं।

मैं माननीय मंत्री महोदय को एक बात बताना चाहता हूं कि बूंदी जिले में हिण्डोली विधान सभा क्षेत्र में चम्बल योजना के तहत 997 करोड़ रुपये की एक योजना स्वीकृत हुई जिसका हमारे कार्यकाल में दो साल काम चला और 46 प्रतिशत उसका काम पूरा हुआ। अभी लम्प-सम एक साल पूरा होने वाला है, एक महीने के बाद में एक साल पूरा होने वाला है। जो 46 प्रतिशत काम पहले हुआ था, इस एक साल में उस योजना में मात्र 7 प्रतिशत ही आपके विभाग ने काम किया है और उस योजना के पीछे इन गर्मियों में हिण्डोली, नैनवा के लोगों को बीस हैंडपम्प आपके विभाग ने सेंक्शन किये हुए भी खारिज कर दिये कि हिण्डोली की चम्बल परियोजना आ रही है, तो उसका पानी आयेगा तो हैंडपम्प की क्या जरूरत है? माननीय सभापति महोदय, 7 प्रतिशत के हिसाब से तो अगले 8 साल में जाकर पानी आयेगा तो क्या 8 साल तक हिण्डोली नैनवा के लोग प्यासे रहेंगे क्या?

SSY/RTM/02.08.2024/13:50/2b

माननीय मंत्री महोदय को इस सदन में अपने जवाब में यह बात बतानी चाहिए।

इसके साथ ही आज का अख़बार मैंने पढ़ा। भू-जल संरक्षण की बात कर रहे हैं। लेकिन इस बारिश के पानी से कल जो तबाही मची, आज के अख़बार में था कि इस राजस्थान में एक परिवार के 3 लोगों की जिनमें एक मां-बेटी भी थी, दीवार गिरने से मृत्यु हो गई। हम सब उस पर खेद प्रकट करते हैं।

मैं समझता हूं कि पहला सवाल तो यह उठता है कि क्या सरकार उसकी जिम्मेदार है? भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो अभी 8 महीने से, 10 महीने से राजस्थान में काम कर रही है, क्या वह जिम्मेदार है? तो उसका जवाब है कि बिलकुल पूरे तरीके से जिम्मेदार है।

दूसरा सवाल यह उठता है कि क्या केवल वही जिम्मेदार है? तो राजस्थान का एक नागरिक होने के नाते मैं मानता हूं कि केवल वही जिम्मेदार नहीं है। आज तक इस सदन में जितने सदस्य रहे, जितनी बार सदन लगा, और मैं माफी चाहता हूं, आप आसन पर विराजे हैं, जितनी बार जो लोग, हमारे सीनियर लीडर्स आसन पर भी विराजे, हम सब लोग थोड़े-थोड़े जिम्मेदार हैं। सारे लोग जिम्मेदार हैं।

लॉबी के अन्दर जितने आईएएस ऑफिसर्स, आरएएस ऑफिसर्स बैठे हुए हैं, वह भी इसके अन्दर जिम्मेदार हैं। पीछे की दीर्घा में जो पत्रकार साथी बैठे हुए हैं, वह भी उसके जिम्मेदार हैं। इस राजस्थान के जो भी लोग जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर, तेरी-मेरी के नाम पर, किसी का नुकसान-फायदा करने के नाम पर वोट देते हैं, वह लोग भी इस हादसे के बराबर जिम्मेदार हैं।

मैं समझता हूं कि अगर इन परिस्थितियों को हमने नहीं सुधारा तो आने वाले समय में, आज हिमाचल में डैम टूट रहा है, बड़ी-बड़ी पहाड़ियां खिसक रही हैं, एक-एक हादसे में सैकड़ों लोगों की मृत्यु हो जाती है तो कहीं न कहीं इस सिस्टम के अन्दर कमी है। अगर हम एक-दूसरे के ऊपर आरोप-प्रत्यारोप की राजनीति ही करते रहे, एक-दूसरे को नीचा दिखाने और खुद को सबसे सर्वश्रेष्ठ दिखाने की राजनीति करते रहे तो आने वाले समय में इन हादसों में, यह कोई अतिश्योक्ति नहीं होगी कि कोई न कोई इस सदन में बैठने वाले का भी, कोई मिलने वाला दब जायेगा। इसलिए सीरियसली हमको सोचना पड़ेगा, इसके ऊपर काम करना पड़ेगा।

माननीय सभापति महोदय, ग्यारहवां साल आपकी कृपा से और जनता के आशीर्वाद से इस सदन में मैं आ रहा हूं। बार-बार हम यह सुनते हैं कि सदन की गरिमा, गौरवशाली इतिहास है। लेकिन जब तक ऐसी मां-बेटी पानी के आने पर दीवार के नीचे दबेंगी तब तक यह इतिहास गौरवशाली नहीं होगा। यह इतिहास गौरवशाली तब होगा जब वह मां-बेटी के सर पर पक्की छत होगी। उस दिन इस सदन का गौरवशाली इतिहास होगा।

सभापति महोदय, जब एक गरीब के परिवार को बिजली और शुद्ध पानी मिलेगा, तब जाकर इस सदन का गौरवशाली इतिहास होगा। जब गांव के बच्चों को एक किलोमीटर पर पांचवीं, 2 किलोमीटर के ऊपर आठवीं और 3 किलोमीटर पर बारहवीं स्कूल मिलेगी, उस दिन

जाकर इस सदन का गौरवशाली इतिहास होगा। जब तक 10 किलोमीटर के अन्दर गांव के बच्चे या बच्ची को सरकारी कॉलेज नहीं मिलेगा, तब तक हमारा इतिहास गौरवशाली नहीं होगा।

उस दिन गौरवशाली होगा, जब कोई गरीब, जिसकी बेटी और बेटा पेट्रोल खर्च करके कॉलेज नहीं जा सकते, यदि साइकिल से भी जाना चाहें तो 10 किलोमीटर के अन्दर उनको कॉलेज मिलेगा, उनकी शिक्षा पूरी होगी, उस दिन जाकर इस सदन का इतिहास गौरवशाली होगा।

सभापति महोदय, मैं केवल यह बातें कहने के लिए नहीं कह रहा हूं। कई लोगों को लगेगा कि भाषण दे रहा है यह तो। काम करके दिखाइये तो मुझे यह बताते हुए खुशी है, मैं क्यों बता रहा हूं क्योंकि आज सुबह मुझे वह अख़बार पढ़ते हुए इतना दुःख हुआ है जो मैं कह नहीं सकता।

मुझे खुशी है कि मेरी विधान सभा में 2 तहसीलें हैं, आजादी के बाद 71 साल हुए, 71 सालों में एक भी सरकारी कॉलेज कोई नहीं बना पाया। मुझे खुशी है कि राजस्थान के मुख्य मंत्री अशोक गहलोत जी ने 5 साल के अन्दर 7 सरकारी कॉलेज हिण्डोली विधान सभा में बनाने का काम किया।

हम केवल आरोप-प्रत्यारोप की बात करते हैं। शिक्षा की बात कीजिये। पानी की बात कीजिये।

श्री कैलाश चन्द वर्मा (बगरू): पानी पर बोलो।

श्री अशोक (हिण्डोली): क्या हो गया? क्यों तकलीफ हो रही है? सुन लीजिये, मुझे 10 मिनट मिले हैं, पार्टी ने दिये हैं। आपके नहीं ले रहा हूं। आप अपना काम कीजिये। हमको अपना काम करने दीजिये। 10 मिनट मैं बोलूंगा। आप तय नहीं करेंगे कि कौनसी बात पानी की है।

सभापति महोदय, मैं इसलिए यह बातें सदन में बता रहा हूं क्योंकि जब तक इस सदन में आरोप-प्रत्यारोप की राजनीति चलती रहेगी, तब तक हमारा फोक्स जो है वह पब्लिक इश्यूज पर डाइवर्जन रहेगा। क्योंकि हर आदमी अपने डिफेंसिव मोड में है। हर आदमी अटैक मोड में है। उसको हमें थोड़ा कम करना पड़ेगा। इस सदन के अन्दर ज्यादा समय जनता के मुद्दो पर चर्चा होनी चाहिए ताकि ऐसे हादसे नहीं हों।

सभापति महोदय, अभी आप फरमा रहे थे कि आरोप-प्रत्यारोप की राजनीति, बीच-बीच में अपनी बात में आप भी करने लगे। सभापति महोदय, मेरा तो यही कहना है कि कल वाला जो हादसा है, ऐसे हादसों की पुनरावृत्ति नहीं हो। इसकी भी जिम्मेदारी हम सदन में लें। केवल एक मंत्री के ऊपर छोड़ने से नहीं चलेगा, केवल सरकार के ऊपर छोड़ने से नहीं चलेगा। केवल सरकार पर छोड़ने से नहीं चलेगा। क्या हो गया, पेट में दर्द हो गया। बीच में मत बोलो।

श्री सभापति: शांत रहें।

श्री अशोक (हिण्डोली): क्या हो गया? अच्छी बात नहीं लग रही है। टाइम खराब कर रहे हो।

श्री सभापति: बोलिये, माननीय सदस्य बोलिये। समय समाप्त होने वाला है।

श्री अशोक (हिण्डोली): सभापति महोदय, अंत में, किसी को सच सुनने की आदत नहीं है, कोई सच सुनना नहीं चाहता। इसलिए मीठी-मीठी बातें करो। एक दूसरे की पॉलिस करो और शाम को जाकर सदन के सितारे बनकर लड्डू बांटो। इससे काम नहीं चलेगा।

सभापति महोदय, मैं अंत में अपनी बात को जल्दी खत्म करुंगा। क्योंकि बाकी जो बातें कहूंगा फिर यह खड़े होंगे और इनसे सुना नहीं जायेगा। अभी नये-नये आये हैं। अभी पार्टी, पार्टी ज्यादा कर रहे हैं। जब अगले चुनावों में जायेंगे जनता के बीच में और 5 साल में मुद्दे रह जायेंगे तब इनको पता लगेगा। गांव में जायेंगे तब लोग सवाल पूछेंगे कि आपने हमारे गांव के लिए क्या किया? आपने हमारे शहर के लिए क्या किया? आपने बच्चों की शिक्षा के लिए क्या किया? आप मुझे टोक रहे हो लेकिन 4 साल के बाद में आप चुनावों में जाना, लोग आपको पकड़ेंगे। हमारे गांव में पांचवीं थी, आपने आठवीं क्यों नहीं करायी? हमारे गांव में सड़क नहीं है।

श्री सभापति: विराजें। श्री सुरेश मोदी।

श्री अशोक (हिण्डोली): इस वजह से बच्चे स्कूल नहीं जा पाते। उसमें आपने क्या कराया? हमारी पानी की समस्या का क्या कराया?

श्री सभापति: श्री सुरेश मोदी।

श्री अशोक (हिण्डोली): हमारे अस्पताल नहीं है, आपने क्या कराया? अभी आपका पेट दुख रहा है। समय आयेगा तब आपको पता लगेगा। आपको मेरी बातें याद आयेंगी।

श्री सभापति: विराजिये।

श्री अशोक (हिण्डोली): समय पर काम की बात कर लेते तो कितना अच्छा रहता।

श्री सभापति: विराजिये, विराजिये।

श्री अशोक (हिण्डोली): सभापति महोदय, एक बहुत बड़ी गलती यह सदन करने जा रहा है।

श्री सभापति: विराजिये माननीय सदस्य।

श्री अशोक (हिण्डोली): सभापति महोदय, पहली बार हो रहा है कि होम के ऊपर कोई डिस्कशन नहीं हो रहा है। मैं सभी जिम्मेदार लोगों से आग्रह करता हूं कि होम के ऊपर डिस्कशन होना चाहिए। जिस पुलिस को राजस्थान के लोगों की सुरक्षा के लिए आपने, इस सरकार ने उनके हाथ में बंदूक दी है, रक्षक ही कहीं भक्षक नहीं हो जायें।

श्री सभापति: विराजें।

श्री अशोक (हिण्डोली): इसलिए उनके ऊपर नकेल होना भी जरूरी है। उनके ऊपर नजर रहना भी जरूरी है।

श्री सभापति: बैठिये, बैठिये। श्री सुरेश मोदी, आपका समय प्रारंभ हो गया।

श्री अशोक (हिण्डोली): उनके ऊपर चर्चा होना भी जरूरी है। सच्चाई जो है, वह सदन के माध्यम से जनता के सामने भी आना जरूरी है।

श्री सभापति: अंकित नहीं हो।

श्री अशोक (हिण्डोली): 000

श्री सभापति: बोलिये, आपका समय प्रारंभ हो गया, माननीय सुरेश मोदी जी।

श्री सुरेश मोदी (नीम का थाना): सभापति महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र नीम का थाना की सबसे बड़ी समस्या पानी की कमी है। गत वर्षों में पर्याप्त वर्षा ना होने के कारण जल स्तर लगातार गिरता जा रहा है। परिस्थिति ऐसी हो चुकी है कि ट्यूबवैल सूख चुके हैं, हैंडपम्प नाकारा हो चुके हैं। अब जो नये ट्यूबवैल खोदे जा रहे हैं उनमें 1100, 1200 फीट पर पानी मिल रहा है। कई सूखे भी जा रहे हैं। जो पानी 1100, 1200 फीट पर मिल रहा है, वह फ्लोराइड युक्त है, जो कई बीमारियों का जनक है।

सभापति महोदय, सिंचाई तो दूर की बात पेयजल की बहुत बड़ी समस्या है। बहुत पहले से मेरा क्षेत्र डार्क जोन घोषित है। जल जीवन मिशन का काम भी पानी की सप्लाई हेतु खोदे गये बोरिंग सूखे जाने के कारण, कम पानी मिलने के कारण सफल नहीं हो पा रहा है। जल जीवन मिशन के ठेकेदारों का काम बहुत धीमी गति से चल रहा है। कोई भी पंचायत ऐसी नहीं है जहां काम पूरा कर दिया गया है।

Spp/Rtm/02.08.2024/14.00/2c

मोटरें, पैनल, स्टार्टर आदि सामान सही क्वालिटी का नहीं डाला जा रहा है। इस समस्या का एक मात्र हल ..(व्यवधान).. मंत्री महोदय, आपके लिये बोल रहे हैं हम। मंत्री महोदय, तो बातों में लग रहे हैं। मंत्री महोदय, इस समस्या का एक मात्र हल क्षेत्र में नहरी पानी लाना है। इंदिरा गांधी नहर आधारित वृहद् पेयजल योजना 2022-23 में स्वीकृत हुई थी। जिसका लाभ सीकर, झुन्झुनूं व नीमकाथाना जिले के आठ विधान सभा क्षेत्रों में होना था। इस योजना की DPR स्वीकृत होकर ए एस भी जारी हो चुकी है। पूर्व में इसके लिये 7,800 करोड रुपये की स्वीकृति भी हुई थी। इस बार के बजट में, मैं धन्यवाद दूंगा 2024-25 के परिवर्तित बजट के मद संख्या 6 के क्रमांक 5 पर इसे शामिल करते हुये 7,582 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। मेरा सरकार से निवेदन है कि पेयजल की बड़ी समस्या को देखते हुये प्राथमिकता के तौर पर इस योजना का कार्य शुरू करवाने की कृपा करें। साथ ही, दो-तीन साल में इस योजना का लाभ जनता को मिल सके।

माननीय सभापति महोदय, इसी क्रम में आगे मैं निवेदन करना चाहता हूं शेखावाटी क्षेत्र को यमुना जल की सप्लाई हेतु 17 फरवरी, 2024 को हरियाणा सरकार, राजस्थान सरकार और केन्द्रीय जल शक्ति मंत्री के बीच में एक समझौता हुआ। मेरा सरकार से निवेदन है कि सबसे पहले तो उस समझौते को सदन के पटल पर रखा जाये। आज 5 महीने से ऊपर का समय व्यतीत हो गया है, लेकिन सदन के सदस्यों को यह नहीं पता है कि क्या समझौता

हमारी सरकार और हरियाणा सरकार के बीच में हुआ। बहुत सारी बातें उठ रही हैं। हरियाणा सरकार के मुख्य मंत्री कुछ कह रहे हैं। हमारे मुख्य मंत्री कुछ कह रहे हैं और मीडिया कुछ कह रहा है तो जो भी समझौता हुआ है, भले ही हमारे हित उसमें कम साधे गये हैं। लेकिन जो भी समझौता है, वह सदन के पटल पर रखा जाये। मीडिया के माध्यम से आ रही जानकारी के अनुसार इस समझौते में सीकर, चूरू व झुन्झुनूं जिलों को इसका पानी मिलेगा।

माननीय सभापति महोदय, नीमकाथाना नवगठित जिला है एवं इसमें दो विधान सभा क्षेत्र झुन्झुनूं के और दो विधान सभा क्षेत्र सीकर के शामिल करके इसे बनाया गया है। अतः यह भी स्पष्ट करें कि नीमकाथाना जिले को इस योजना के तहत पानी मिलेगा। मेरा माननीय मंत्रीजी से आग्रह है कि जब वह जवाब दें तो इस बात की स्पष्ट घोषणा करें कि नीमकाथाना जिला भी इस पानी का लाभ प्राप्त कर सकेगा।

माननीय सभापति महोदय, अभी यमुना जल हरियाणा के भेटण्डी गांव तक खुली नहर के जरिये आ रहा है। भेटण्डी गांव मेरे क्षेत्र की सीमा से केवल डेढ़ किलोमीटर दूर है और वहां खुली नहर के जरिये यमुना जल आ रहा है। मीडिया से मिली जानकारी के अनुसार यमुना जल शेखावाटी में अंडरग्राउंड पाइप लाइन के जरिये आयेगा। मेरा निवेदन है कि नीमकाथाना क्षेत्र में वर्तमान में स्थित रायपुर, पाटन, रेला, पीथमपुरीसर, माकड़ी भूदोली, झालरा एवं गांवड़ी बांधों में पाइप लाइन के जरिये अगर पानी डाल दिया जाये तो इससे जल स्तर में वृद्धि होगी और पानी की उपलब्धता के हिसाब से पूर्व में निर्मित नहरों के जरिये सिंचाई के लिये भी पानी दिया जा सकेगा। जब पानी की मात्रा तय नहीं है तो उसे बांधों में डालना ही उचित होगा। अभी DPR बनने जा रही है इसलिये मेरा मंत्रीजी से निवेदन है कि इन बातों का ध्यान रखा जाये। इन दोनों योजनाओं को पूर्ण होने में बहुत समय लगेगा। अतः जल्द से जल्द पानी की समस्या को देखते हुये इनका कार्य प्रारम्भ किया जाये।

माननीय सभापति महोदय, जनता को तुरन्त राहत पहुंचाने के लिये जल जीवन मिशन के काम में तेजी लाई जाये। इस योजना के तहत खोदे जा रहे बोरिंग की गहराई आवश्यकतानुसार बढ़ायी जाये। मेरे यहां 1100-1200 फीट से पहले पानी नहीं मिलता है। इस योजना के तहत सूखे निकल रहे बोरिंगों की एवज में नये बोरिंग खुदवाये जाने का भी प्रावधान किया जाये। मेरे क्षेत्र के बांधों में पानी के आवक के क्षेत्र में जगह जगह रूकावटें डाल दी गयी हैं। माननीय सभापति महोदय, बजरी खनन करने वालों ने बहुत गहरे-गहरे खड्डे कर दिये हैं। कई जगहों पर लोगों ने क्रेशर लगा दिये हैं जिससे बांधों में पानी आना बन्द हो गया, अतः इस ओर भी ध्यान दिया जाये। मंत्रीजी तो चले गये।

माननीय सभापति महोदय, अक्सर लोगों की शिकायतें नलों में गन्दा पानी आने की मिलती है। पानी की लाइनें लीक होने से गन्दा पानी उनमें से होकर नलों में आता है। इस बात का भी ध्यान रखकर व्यवस्था की जाये। धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री भागचन्द टांकड़ा।

श्री प्रताप सिंह सिंघवी (छबड़ा): माननीय सभापति महोदय, टाइगर के पास कालीचरण

जी बिना सिक्योरिटी के गये हैं। उनके पास बैठे हैं। कालीचरण जी की सिक्योरिटी की व्यवस्था करावें और टाइगर के पास बिना सिक्योरिटी के जाने से ही आप समझ सकते हो कि किस प्रकार के हालात बन सकते हैं।

श्री सभापतिः श्री भागचन्द टांकड़ा (अनुपस्थित) श्री जेठानन्द व्यास।

श्री जेठानन्द व्यास (बीकानेर पश्चिम): माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे राज्य में पेयजल की स्थिति पर विचार पर बोलने का मौका दिया, मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं। माननीय सभापति महोदय, राजस्थान के इतिहास में इस विधान सभा में पेयजल स्थिति पर विचार हो रहा है। विधान सभा में सबने विचार रखे हैं। मैं तो पहली बार आया हूं। यहां पेयजल की बात न होकर और इधर-उधर की बात हो रही है। यह पूरे प्रदेश के लिये ठीक नहीं है। माननीय सभापति महोदय, मैं बीकानेर से आता हूं और बीकानेर में पहले के समय में जल की बहुत कमी थी, लेकिन महाराजा गंगासिंहजी के भागीरथी प्रयासों से गंगनहर आयी और यह पूरा इलाका हरा-भरा होने लगा। आज हमारे देश के यशस्वी प्रधान मंत्रीजी, नरेन्द्र जी मोदी के नेतृत्व में चल रहा जल जीवन मिशन अभियान, जो भागीरथ का एक बहुत बड़ा प्रयास है। यह देश के हर क्षेत्र में, हर कोने-कोने में, हर घर में पेयजल उपलब्ध करवाने का एक बहुत बड़ा कार्य प्रधान मंत्रीजी ने शुरू किया है। माननीय सभापति महोदय, मैं आपको बताना चाहता हूं कि पूर्व सरकार, जो कांग्रेस की सरकार थी, वह एकदम कुप्रबन्ध था। 40 से 45 प्रतिशत पद रिक्त रहे और बड़े दुःख के साथ कहना पड़ रहा है कि मेरे क्षेत्र के ही जलदाय मंत्री थे, वह भी अपने क्षेत्र में ए.ईएन. और जे.ईएन. नहीं लगा पाये। यहां तक कि मैं आपसे एक बात और कहना चाहता हूं कि बीकानेर क्षेत्र बहुत बड़ा हो गया है और वहां ए.ईएन. और जे.ईएन. भी लगाये जायें और अलग से अधीक्षण अभियन्ता का कार्यालय भी खोला जाये जिससे कि जल की अच्छी व्यवस्था हो सके।

माननीय सभापति महोदय, पिछली सरकार ने जो ट्यूबवैल खोदकर लगाये थे, उन ट्यूबवैल की स्थिति यह है कि जहां गुणवत्ता का पानी नहीं है, उनको पता है या उनको पता नहीं है और जानकारी नहीं की होगी, वहां भी उन्होंने ट्यूबवैल लगा दिये। उन ट्यूबवैलों के पानी का आज कोई उपयोग नहीं है। स्थिति यह है कि कई ट्यूबवैल तो बन्द हो चुके हैं और ऐसी जगह ट्यूबवैल लगाये गये हैं, जहां पर 75 लाख रुपये से मेरे घर के पास में एक ट्यूबवैल बना। मैं कह रहा हूं कि इसकी जांच होनी चाहिये कि वहां 75 लाख रुपये लगे हैं क्या? लेकिन इतना घोटाला मैंने मेरे जीवन में कभी नहीं देखा जो पिछली सरकार में हुआ। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जहां टंकियां नहीं बननी चाहिये वहां पर इन्होंने टंकियां बनाना शुरू कर दिया और तीन टंकियां ऐसी हैं जो आज भी विवादित हैं। उनको पता ही नहीं कि कहां बनानी हैं। उन्होंने घोषणा कर दी, उनके लिये कोई स्थान चिह्नित नहीं किया। एक टंकी का मैं आपको बताना चाहता हूं कि एक टंकी का विवाद तो हमने सुलझाया और वह शुरू हो पायी है। अभी भी दो टंकियों की हम व्यवस्था करने जा रहे हैं लेकिन इनको कोई चिन्ता नहीं कि जनता के लिये हमें व्यवस्था करनी है। केवल जनता के लिये घोषणा अपने

ए.सी. के कमरे में बैठकर कर दी। ऐसे इनके मंत्री और ऐसी इनकी सरकार थी कांग्रेस की। ..(व्यवधान)..

माननीय सभापति महोदय, मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारे क्षेत्र में जो पुरानी पाइप लाइन है, वह इतनी पुरानी हो गयी है कि प्राय: वह अवरुद्ध हो जाती है। इसलिये मेरा यह निवेदन है कि जनता तक पानी पहुंचाने के लिये वह जितनी भी पुरानी लाइनें हैं, उनको बदला जाये। यहां तक स्थिति है कि वोट के लालच में पिछली सरकार ने उन्हीं लाइनों में से कितनी लाइनें निकाल दीं। इसलिये पीछे तक पानी नहीं पहुंच पा रहा था।

Jyg/rtm/020824/14.10/2d

वहां आज भी कुप्रबंध के कारण खराब स्थिति है लेकिन मैं आशा करता हूं कि हमारे यशस्वी मुख्य मंत्री, भजन लाल जी की जो सरकार आई है वो हर घर तक पानी पहुंचाएगी। इस विश्वास के साथ कह रहा हूं, भारत माता की जय।

श्री सभापति: श्री सोहन लाल नायक।

श्री सोहन लाल नायक (रायसिंहनगर): माननीय सभापति महोदय, आपने आज पानी पर मुझे बोलने का मौका दिया, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्रीजी से निवेदन करूंगा कि मेरे विधान सभा क्षेत्र रायसिंहनगर की शहरी क्षेत्र की जो जलदाय योजना है वो बहुत पुरानी है अब क्षेत्र का क्षेत्रफल और जनसंख्या बढ़ चुकी है, वहां पर पानी की सप्लाई बढ़ाकर वहां की आवश्यकताओं को पूरा किया जाए। इसमें 2022 में अमृत 2.0 में प्रस्ताव मांगे गए थे जिसमें खण्ड जलदाय विभाग, रायसिंहनगर द्वारा 28 करोड़ रुपये का प्रस्ताव भेजा गया जिससे रायसिंहनगर को आगामी 50 वर्षों तक पेयजल समस्या से निजात मिल सके। विभाग ने गांव 29 एनपी में 42 बीघा भूमि राज रकबा चिह्नित कर भूमि आवंटन की प्रक्रिया शुरू कर दी। पूरे विधान सभा क्षेत्र में वाटर सप्लाई के जो कर्मचारी हैं वो भी लम्बे समय से हड़ताल पर चल रहे हैं जिससे क्षेत्र बहुत विकट स्थिति में है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्रीजी से निवेदन करूंगा कि मेरे विधान सभा क्षेत्र के गांवों में जेजेएम के तहत सड़कें और चौक ठेकेदारों ने तोड़े हैं उनका पुन: निर्माण करवाया जाए और सड़कें ठीक तरह से बनाई जाए, वहां बड़े-बड़े गड्ढे बन चुके हैं। इसके अलावा मैं आपसे यह भी निवेदन करूंगा कि मेरे विधान सभा क्षेत्र के अन्दर ग्रामीण क्षेत्र के अन्दर फिल्टर पानी की जगह रॉ वाटर सप्लाई किया जा रहा है। जिससे पंजाब के कैमिकल युक्त पानी से कैंसर जैसी भयंकर बीमारी का अटैक हो रहा है। जेजेएम में ओवरहैड टैंक और डिग्गियां बनी हैं वो पानी डलने से पहले ही टूट चुकी हैं, इसकी जांच की भी आप व्यवस्था करें।

माननीय सभापति महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र के विजयनगर नगरपालिका क्षेत्र के अन्दर जलदाय विभाग के 1976 की एक जलदाय योजना है जिसमें 40 हजार किलो लीटर पानी की क्षमता है, मात्र 2 डिग्गियां हैं। 2011 की जनसंख्या के आधार पर 18425 है,

वर्तमान में 20321 है, 2135 एलपीसीडी की दर से पानी की आवश्यकता है जबकि मात्र 36 एलपीसीडी की दर से पानी मिल रहा है। 115290 किलो लीटर की क्षमता होनी चाहिए जबकि उसके विपरीत, माननीय सभापति महोदय, मंत्रीजी से निवेदन करूंगा कि एक तरफ 40 हजार किलो लीटर पानी दिया जा रहा है जबकि हमें चाहिए 115290 किलो लीटर। बहुत छोटी नगर पालिका में तीन वार्ड तो ऐसे हैं जहां आज तक एक भी बून्द पानी नहीं पहुंच पाया है। इसके अलावा मैं आपसे निवेदन करूंगा कि विजयनगर शहर में एक दिन छोड़कर पानी सप्लाई हो रहा है। जिससे शहर के लोगों को टैंकरों से पानी डलवाना पड़ता है।

माननीय सभापति महोदय, मैं यह भी निवेदन करूंगा कि विभागीय योजनाओं को बढ़ाकर विगत सरकार ने एक प्रस्ताव मांगा था जिसमें भूमि भी चिह्नित कर ली गई परंतु वो प्रस्ताव चुनाव आचार संहिता के कारण ठण्डे बस्ते में चला गया। शहर की जलदाय योजना बिलकुल छोटी होने की वजह से पानी की बहुत विकट स्थिति है। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप इसको पूरा करें। जय हिन्द।

श्री सभापतिः श्री हरलाल सहारण।

श्री हरलाल सहारण (चूरू): माननीय सभापति महोदय, मेरे को आपने बोलने का मौका दिया उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

माननीय सभापति महोदय, मैं उस जिले से आता हूं, उस तहसील से आता हूं जहां गर्मी और सर्दी का तापमान राजस्थान ही नहीं हिन्दुस्तान में भी पता चलता है कि चूरू में तापमान इतना है गर्मी में और सर्दी में। माननीय सभापति महोदय, पानी की चर्चा पर मैं माननीय मंत्रीजी को कहना चाहूंगा कि पानी पर चर्चा हो रही है और माननीय विपक्ष के सदस्य बोलकर बाहर चले जाते हैं, कई तो कहते हैं कि बोलने नहीं देंगे, कई कहते हैं कि सीख लो, कई कहते हैं कि पहली बार आए हो, उनको पता नहीं है कि आप भी पहली बार आए हो। ऐसा क्या कर रहे हैं, क्या डरा रहे हैं? क्या करें? पहली बार कोई आता है, कोई दूसरी बार आता है ..(व्यवधान).. टाइम हो जाने दो। आप बैठिए। हो जाने दो। आप बोलेंगे वैसे ही मैं बोलूंगा बीच में।

माननीय सभापति महोदय, मैं यह बात इसलिए कह रहा हूं कि सास को यदि यह पता रहे कि वह भी कभी बहू बनकर आई थी तो कभी झगड़ा नहीं होता। आपको यह पता होता, आज शिक्षा दे रहे हो, तो पहले शिक्षा वही दे देते न? जहां सरकार में बैठे थे वहां शिक्षा दे देते, आज आप पानी पर सुझाव दे रहे हो कि यह करना, यह मत करना। मैं तो पहली बार आया हूं। आप ये सुझाव पहले दे देते पानी पर। अभी रायसिंहनगर से माननीय सदस्य आते हैं वो बता रहे थे कि जांच की जाए, उसी राज के सदस्य हैं आप। उसी राज में आपने टांके बनाए, टंकियां बनाई, और अब आप हमसे उसकी जांच करवा रहे हैं? ..(व्यवधान)..

श्री सोहन लाल नायक (रायसिंहनगर): पिछले सात महीनों में बनी उनकी कह रहा था।

श्री हरलाल सहारण (चूरू): सात महीनों में बनी या दो महीनों में, बात तो वही है। मैं तो जो कह रहा हूं, मैं इसलिए कह रहा हूं कि छाजळो तो बोल ज्यावै पर सौ छेद की चालणी

नहीं बोलणी नहीं चावै। उसमें कुछ रुकता ही नहीं है। छाज बोलता है, चालणी बोलती है, यह बात आप समझो कुछ, आप अन्दर में झांककर देखें।

माननीय सभापति महोदय, मैं तो यह बात इसलिए कह रहा हूं कि जनता में अपने को यहां पर चुनकर भेजा है तो पक्ष विपक्ष पर नहीं, पानी की समस्या कैसे हल हो। आने वाला विश्व युद्ध पानी पर होगा, यह सब कह रहे हैं पर पानी के बारे में कोई सोच नहीं रहा है। मैं मंत्री महोदय, आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि मेरे गांव में टांके बनते हैं, अगर राजस्थान में कोई भी किसान अपने खेत में टांका बनाए तो उसके लिए एक स्कीम लाई जाए तो हर किसान के खेत में पानी होगा, अगर घर में पानी नहीं होगा तो खेत में बनी टंकी से पानी ले आएगा। मैंने जिला प्रमुख रहते हुए प्रस्ताव भी रखा था, हमारी पूर्व मुख्य मंत्री वसुन्धराजी के पास और मैं आपसे भी निवेदन करना चाहूंगा। पिछली सरकार के टाइम जितने जो काम हुए, मैं यह नहीं कह रहा हूं कि वो काम आज कैसे होंगे, कल कैसे होंगे, उस समय जो पाइप लाइन डाली गई, टंकियां बनाई गईं, उनमें एक ही लाइन सही नहीं डाली गई, सारी सड़कें तोड़ दी गई, सारे खुर्रे तोड़ दिए गए, इसकी जांच कराई जाए। पिछली सरकार के समय में चूरू जिले में 700 करोड़ का टेंडर हुआ, एक बार हुआ, दो बार हुआ, तीन बार हुआ, वो टेंडर आज तक, आपने उस टेंडर को कर दिया है। मैं आपको धन्यवाद देना चाहूंगा कि जल जीवन मिशन में आगे उस पर काम शुरू होगा।

माननीय सभापति महोदय, मैं बीच में एक बात कहना चाहूंगा कि कल चूरू में मेरे यहां 160 एमएम बारिश हुई, 3 घण्टे लगातार पानी बरसा, आपदा में 300 व्यापारियों की दुकानें पानी से भर गईं और कम से कम इतना पानी साठ साल में पहली बार बरसा। इसलिए मैं यह भी कहूंगा कि हमारे मंत्री महोदय के इंटरफेयर के बाद बहुत अच्छी व्यवस्था हुई। मैं यह चाहूंगा कि इसका सर्वे करके व्यापारियों को मुआवजा मिले।

माननीय सभापति महोदय, 60 साल बाद एक साथ इतनी बारिश होना, शहर खड्डे के बीच बसा हुआ है जिससे बहुत से लोगों को नुकसान हो गया इसलिए मैं आपके माध्यम से चाहूंगा कि इसका सर्वे करवाकर प्रभावितों को मुआवजा दिया जाए। माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्रीजी को धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपने टेंडर करा दिए तो जल्दी से जल्दी काम शुरू करवाएं। जिस जल जीवन मिशन में पिछली बार जो घोटाला हुआ, माननीय नेता प्रतिपक्ष अभी कह रहे थे कि हमने तो सस्पैंड किया और आपने बहाल कर दिया, आप द्वेषता की भावना से काम करते हैं। मैं तो मंत्री महोदय आपको कहूंगा कि चाहे पक्ष हो या विपक्ष, इन्होंने जिस तरह का काम किया वो विपक्ष में बैठे, आपको ऐसा काम नहीं करना है। आपको यह काम करना है। गरीब की ढाणी छोड़ दी, वार्ड छोड़ दिए, गांव में टुकड़े कर दिए, वहां पर पाइप लाइन डाली। मैं कहूंगा कि जो बची हुई ढाणियां हैं, उनमे पाइप लाइन डाली जाए और किसी भी इस 8 करोड़ की जनता में कोई पक्ष नहीं, कोई विपक्ष में नहीं, आज आप सरकार में हो इसलिए 8 करोड़ जनता को पानी पिलाना आपका काम है। इसलिए आप सबको पानी पिलाने का काम करो, कोई भेदभाव मत करो।

श्री सभापतिः श्री चन्द्रभान सिंह आक्या।

श्री हरलाल सहारण (चूरू): माननीय सभापति महोदय, आप मेरे को एक मिनट पहले ही बैठा देते हो। मैं आपको धन्यवाद दूंगा, आपने मुझे बोलने का मौका दिया। आपका धन्यवाद।

MLS/RTM/02.08.2024/14:20/2e

श्री चन्द्रभान सिंह चौहान (चित्तौड़गढ़): माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे पानी पर चर्चा करने का मौका दिया, उसके लिए धन्यवाद। मोदी जी ने 2019 में हर घर पाने पहुंचे, उसके लिए योजना बनायी। उसके लिए मैं मोदी जी को भी धन्यवाद दूं, राजस्थान की सरकार को भी धन्यवाद दूं कि इसका क्रियान्वयन हो, क्योंकि पिछली वाली सरकार से क्रियान्वयन नहीं हो पाया। मंत्री जी कन्हैयालाल जी बैठे हैं, टाइम पर इसका क्रियान्वयन हो जाये, क्योंकि आपके जो सैक्रेटरी साहब समित शर्मा जी, वे भी हमारे चित्तौड़ के कलक्टर रहे हैं और उनका अच्छा कार्यकाल रहा है, इसलिए पानी टाइम पर चित्तौड़ को मिले। इसके लिए चम्बल से जो पानी आ रहा है, उसका टैंडर भी हो गया है, ठेका भी हो गया है, पर टाइम पर वह पानी हमारे वहां पहुंच जाये और उसकी योजना हमें मिले, ऐसी मैं आशा करता हूं।

हमारे वहां घोसुंडा बांध है, उसका लेवल 23 का है। चित्तौड़गढ़ जिले को पेयजल देने के लिए अगर उसे 26 कर दिया जाये तो ज्यादा को मुआवजा भी बाकी नहीं है। उसे 26 करने से उसकी दिक्कतें काफी कम हो सकती हैं और उसे पानी मिल सकता है। घोसुंडा बांध के ओवरफ्लो का पानी घोसुंडा के तालाब में हो जाये तो घोसुंडा एरिया की मेरी जो चेरा पंचायत है, वह पानी से तर जायेगी। उसके लिए पहले भी कोई योजना बनायी थी। उसके ओवरफ्लो के पानी की भी आप योजना बना दें और 13 से 26 अगर उस बांध को कर दें तो भी हमारे पूरे चित्तौड़गढ़ जिले को रिलीफ मिल सकता है पानी का।

सभापति महोदय, चित्तौड़गढ़ जिले को डार्क जोन में ले रखा है। उसे डार्क जोन से निकालें, क्योंकि वहां काफी उद्योग वगैरह आ सकते हैं, पेयजल की काफी अच्छी व्यवस्था हो सकती है। डार्क जोन से उसे निकालने की कोशिश करें। माननीय सभापति महोदय, हमारी पंचायतों में 300 फीट से ज्यादा बोर नहीं होते हैं और आज पानी का लेवल 400-500-600 फीट हो गया है, इसलिए कोई भी सरकारी बोर होता है, 300 फीट होने के बाद राइडर लग जाता है। अतः मंत्री महोदय, उसमें कम से कम हमारे यहां 600 फीट बोर हो, उसके लिए आप सहमति दें और उसका प्रस्ताव हम जैसे भी पास कर सकते हैं, वह करेंगे तो हमारे यहां 600 फीट बोर हो जाएंगे। उसके लिए अच्छा हो जायेगा।

हैंडपम्पों का सामान टाइम पर नहीं है। सामान टाइम पर पहुंच जाये और उपलब्ध हो जाये तो अच्छा रहेगा। हैंडपम्पों के मिस्त्री नहीं हैं। नयी भर्ती करें या टैम्परेरी व्यवस्था करें, क्योंकि मिस्त्री नहीं हैं। पेयजल योजना के भी काफी अधिकारी, कर्मचारियों की कमी है, उसकी भी आप पूर्ति करें। हैंडपम्प मिस्त्रियों की भी आप पूर्ति कराएं। उसका भी ध्यान रखकर करने की कोशिश करें। पंचायतों की पेयजल की योजना जो है, उसके तीन-तीन, चार-चार, पांच-

पांच, सात-सात, आठ-आठ साल के बिल बाकी हैं। बिजली विभाग के लोग उसको बिल का कार्ड देते हैं। पहले बिजली विभाग या पीएचईडी वाले खुद उसे जमा करवाते थे। अब ग्राम पंचायतों के ऊपर डाल दिया। ग्राम पंचायतों में किश्तें आ नहीं रही हैं, इसलिए मंत्री महोदय, पीएचईडी के थ्रू उन गांवों के बिल आप लें। ग्राम पंचायतों के पुराने जितने भी बिल हैं, उन्हें माफ करें।

सरकार बैठी है तो उन्हें माफ करवाने की कोशिश करे। इससे पंचायतों को काफी रिलीफ होगा, फायदा होगा। ग्राम पंचायतों को किश्तें भी टाइम पर मिल जाएं तो भी काम अच्छा हो जायेगा। चित्तौड़गढ़ शहर में पानी की दिक्कत हो रही है, क्योंकि आधा-आधा, पौन-पौन घण्टा पानी मिल रहा है, घोसुंडा बांध से पानी की उपलब्धता होती है, इसलिए पानी की व्यवस्था कैसे हो सकती है, घोसुंडा बांध से भी आपको बताया और उसके अलावा और भी अपनी कोई योजना, चम्बल से भी योजना है, उस पानी की दिक्कत को अपन अभी टैम्परेरिली कैसे सॉर्ट-आउट कर सकते हैं, उसे आप दिखवाएं, क्योंकि हमारे वाहा माइंस भी हैं। बिरला की हैं, जे के की हैं, उसमें पानी अपन कैसे ला सकते हैं, उसकी योजना भी अपन बना सकते हैं। (समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

माननीय सभापति महोदय, दो मिनट का आप और समय दें। मंत्री महोदय, जहां पीएचईडी की मोटरें हैं, जहां पंचायतों की पीने के पानी की व्यवस्था है, वहां 24 घण्टे बिजली कैसे मिले, 24 घण्टे अगर अपन जोड़ देंगे तो भी पानी की व्यवस्था हो सकती है। गांवों में 5 घण्टे और 6 घण्टे से जोड़ी जा रही है तो पेयजल की व्यवस्था हो नहीं पाती है। अतः सरकार की तरफ से 24 घण्टे हर गांव में केवल पेयजल के लिए जुड़ जाये तो भी एक अच्छी सुविधा हो सकती है। माननीय, मेरी जो 46 पंचायतें हैं, 13 पंचायतें घोसुंडा की हैं, वहां पानी की आज की तारीख में बहुत ज्यादा शॉर्टेज है। उनकी टैम्परेरी व्यवस्था, बोर करें या कुछ और, अपन करवा सकते हैं। बारिश जितनी होनी चाहिये, वह हो नहीं पायी है। (समय-समाप्ति-सूचक घण्टी) अतः वहां भी 46 पंचायतों में व्यवस्था हो, चित्तौड़गढ़ शहर की पंचायतों में व्यवस्था हो।

श्री सभापतिः विराजिये माननीय सदस्य। श्री ललित यादव। अंकित नहीं होगा।

श्री चन्द्रभान सिंह चौहान (चित्तौड़गढ़): 000

श्री ललित यादव (मुण्डावर): सभापति महोदय, आपने मुझे जल पर बोलने का मौका दिया, उसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं। माननीय सभापति महोदय, बड़ी सकारात्मक सोच रखने वाला और बहुत ही आशावादी इन्सान हूं मैं। जिस प्रकार से पेट्रोल-डीजल, क्रूड ऑयल हम इराक-ईरान से ला रहे हैं, गैस को भी हम पाइप लाइन के जरिये बहुत दूर-दूर से लेकर आ रहे हैं, ऐसे में पानी भी कोई बहुत बड़ा विषय नहीं है। कहीं से भी लाया जा सकता है, बशर्ते सरकार की इच्छाशक्ति हो और काम करने की योजना हो। ऐसे में निश्चित रूप से पानी आ सकता है।

माननीय सभापति महोदय, मंत्री महोदय ने जब बयान दिया, अख़बार में छपा था, अभी

हमारे दो सदस्यों ने चर्चा की, मैं भी उसके बारे में बताना चाहूंगा, बालाजी बनने की बात कही। माननीय मंत्री महोदय, जब राम का और राज का रास्ता सर के ऊपर से होता है, इसलिए आपको प्रदेश की जिम्मेदारी मिली है, आप पूरे प्रदेश को पानी पिलाने की दिशा में काम करें। भ्रष्टाचार की बात यहां हो रही थी। आज आप शासन में हैं। आपके पास ताकत है। आप करें उस ताकत का उपयोग। पकड़ते क्यों नहीं हैं? रोजाना की रोजना वही विलाप यहां करते हैं कि भ्रष्टाचार हुआ है तो आप पकड़ने की बात क्यों नहीं करते? आपको यह बात केवल यहां कहने के लिए चाहिये। भ्रष्टाचार तो कहीं हुआ नहीं। हुआ है तो पकड़ लें आप। क्यों नहीं पकड़ना चाहते?

माननीय सभापति महोदय, मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि सड़कें तोड़ दीं, उनका जवाब तो गलत दे दिया, लेकिन सड़कें आज भी टूटी पड़ी हैं। मेरा आपसे निवेदन है कि उन सड़कों को सही टाइम पर पूरा करवाने का काम किया जाये। जब भी कभी चुनाव आता है, पानी की बात कहकर लोगों को ठगा जाता है, लेकिन मैं आपके माध्यम से एक बात ध्यान दिलाना चाहता हूं कि जेजेएम के माध्यम से हर घर को पानी पिलाने की बात कही गयी, लेकिन आप ही की पार्टी के एक विधायक द्वारा अलवर जिले में यह बात कहकर उन गरीब आदमियों को पानी पीने से रोक दिया गया कि अलवर जिले के दो जिले हो गये, अब बहरोड़ का पानी हम खैरथल को नहीं पीने देंगे।

15 गांवों के लोगों को प्यासा मारने के जिम्मेदार आप ही की पार्टी के विधायक और आप लोग चुप बैठे हैं। जब बहरोड़ का पानी खैरथल में नहीं दे सकते तो कैसे आप लाएंगे चम्बल का पानी लाएंगे? यह बताने की जरूरत है आपको। मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं, इस पर भी आप लोग ध्यान दें। मेरे इलाके के 15 गांव हैं- ततारपुर, बरली, रूंध, मातोड़, सोरखा, कुशालवास, अजीजपुर, बेहरोज, सोरखा कलां, चकोलिया, बिरटोली, जीन्दोली आदि में पानी दें। इसी के साथ-साथ आप इस योजना से सोडावास, माजरी खोला, झझारपुर, जीवन सिंहपुरा जैसे गांवों को भी आप जोड़ने का काम करें, जिससे उनको भी पानी पिलाया जा सके।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से ध्यान दिलवाना चाहता हूं कि मेरे मुण्डावर में ग्रामीण जेजेएम योजना बनी थी, लेकिन वह नगरपालिका हो गयी तो वहां उस योजना को बन्द कर दिया गया। जल्दी वहां पर वह योजना बन जाये। डार्क जोन में है, जमीन में पानी नहीं है। हमने नदी से पानी लाने का बनाया है, वह भी वहां करने का आप काम कर दें तो बहुत बढ़िया हो। एक मेरा निवेदन था कि पम्प चालकों को भी हम लोग स्थायी करने की बात कर सकते हैं।

सभापति महोदय, आपने पानी की बात पर बोलने का मुझे मौका दिया है, लेकिन जब पानी की बात आयी, देश में नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में 1200 करोड़ रुपये से संसद भवन बना, वहां भी बिना मांगे पानी परमात्मा ने भेज दिया। कितना भ्रष्टाचार वहां किया गया है, उस पर कोई चर्चा करवायी जाये। अडाणी को आपने एयरपोर्ट दे दिया, वहां हवाई यात्रा के

साथ-साथ पानी में नाव के माध्यम से भी जाने का अवसर मिलेगा। इन पर भी आप लोग जांच करवाने का काम करेंगे। माननीय सभापति महोदय, एक ही बरसात में जयपुर का पूरा हाल आप लोग देख रहे हैं, किस प्रकार से एक परिवार के तीन-तीन लोगों की जान जा रही है।

श्री सभापतिः यूडीएच पर बोल रहे हैं, विराजें। श्री कालूराम।

mkd/rtm/02.08.2024/14.30/2f

श्री ललित यादव (मुण्डावर): दिल्ली के अन्दर संसद में सामाजिक न्याय के योद्धा, मोहब्बत की दुकान खोलने वाले राहुल गांधी के बारे में आपकी पार्टी के कुछ सांसद कह रहे हैं कि ड्रग टेस्ट करायेंगे।

श्री सभापतिः विराजिये, विराजिये। अंकित नहीं होगा। श्री कालूराम।

श्री ललित यादव (मुण्डावर): 000

श्री कालूराम (डग): जैसा रहीम दास जी ने कहा है कि रहिमन पानी राखिये, बिन पानी सब सून, पानी गये न उबरे मोती, मानस, चून। पानी एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। इस पर हमारी सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है। अभी माननीय सदस्य कह रहे थे, सम्माननीय प्रधान मंत्री जी ने 27 हजार करोड़ रुपये जल जीवन मिशन के लिए राजस्थान को दिये। उन 27 हजार करोड़ रुपये का दुरुपयोग हुआ है। वह पैसा अगर राजस्थान में लग जाता तो आज ये दिन हमको नहीं देखने पड़ते हैं। अब हमारी सरकार को नौ महीने हुए हैं, उसमें कई ऐसे काम हो गये हैं, जिससे अब जनता को पानी मिलना शुरू हो गया है।

मेरे विधान सभा क्षेत्र में पेयजल की पांच परियोजनाएं हैं। हमारी पूर्व मुख्य मंत्री वसुन्धरा राजे सिन्धिया जी ने पीएसपी के माध्यम से जो योजना शुरू की थी, उससे बहुत अच्छा पानी मिल रहा था। इन्होंने जल जीवन मिशन के माध्यम से करोड़ों रुपयों का, मेरे विधान सभा क्षेत्र में करीब दो सौ, ढाई सौ करोड़ रुपये का काम स्वीकृत हुआ है।

माननीय सभापति महोदय, अभी तक वह कार्य पूरा नहीं हुआ है। इन्होंने अपनी वाहवाही लूटने के लिए, पहले पुरानी पाइप लाइन लगी हुई थी, उसमें बिछाकर पुरानी पाइप लाइनों में पानी छोड़ने का काम किया, ना कि नई पाइप लाइनें डालीं। आज हमें बड़ी दिक्कत हो रही है। हमें उस जगह नई पाइप लाइनें डालनी पड़ रही हैं। इन्होंने बिना स्रोत, बिना टंकी बनाये, अपने नम्बर बढ़ाने के लिए उन गावों को दो-दो सौ, ढाई-ढाई सौ कनेक्शन दे दिये, बाकी आपके पास पानी का स्रोत नहीं था, पानी कहां से मिलेगा?

आज पानी की यह स्थिति है कि गांवों में पानी नहीं जा रहा है। हमें उसे देखना पड़ेगा। मेरे विधान सभा क्षेत्र में गागरिन पेयजल परियोजना की कम से कम 70 किलोमीटर लम्बी एक लाइन डाल रखी है। इस परियोजना के माध्यम से करीब 341 गांव जुड़े हुए हैं। माननीय सभापति महोदय, पिछली सरकार में इसमें काफी गड़बड़ घोटाला हुआ है।

मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि इसकी जांच की जाये

और जिन लोगों ने सड़कें खोदी दीं और जो पाइप लाइनें डाली हैं, वे भी बिलकुल टूट गई हैं। उन गांवों को बिलकुल सही तरीके से पानी नहीं मिल रहा है।

हमारे क्षेत्र में बहुत वर्षा होती है। झालावाड़ को पानी के मामले में चेरापूंजी कहा जाता है। वहां अभी 22 इंच बारिश हो चुकी है। जयपुर में अभी सात या आठ इंच बारिश हुई होगी। हमारे क्षेत्र में कई ऐसी जगहें हैं, वहां हम काफी जल स्रोत बना सकते हैं, डैम बनाकर, छोटे माइक्रो डैम बनाकर, एनिकट बनाकर हम पानी को इकट्ठा कर सकते हैं।

इसी प्रकार से हमने कुछ गांवों का सर्वे करवाया था। उसमें निम्न गांव हैं। जैसे- मंगवालिया, बीरमाखेड़ी, पारला, उमरया, माधवी डैम, जिसकी हाइट बढ़ा सकते हैं, बिलखेड़ी, बिनायका, बिस्तुनिया, ताइका खेडा, डोबड़ा, सिंहपुर, घटोत, पारला और रामपुरा गांवों में माइक्रो डैम बनाकर, हम पानी इकट्ठा करके पानी की उपलब्धता कर सकते हैं।

मेरे विधान सभा क्षेत्र में चम्बल नदी बहकर जा रही है, उसका आधा हिस्सा राजस्थान में है और आधा हिस्सा मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश में कई लघु सिंचाई परियोजनाएं उस चम्बल के माध्मय से चल रही हैं। राजस्थान में अभी तक कोई भी परियोजना स्वीकृत नहीं है।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि अगर हमको चम्बल से सिंचाई के लिए, पीने के लिए पानी मिल जाता है तो जो 70-80 किलोमीटर हमारी लाइन है, हमें उस लाइन को नहीं उपयोग में लेना पड़ेगा।

सभापति महोदय, चौमहला में हमने एक योजना बनाई है। 1970-72 के बीच में वहां टंकियां बनी हुई थीं, वे टंकियां बहुत छोटी हैं। माननीय मंत्री महोदय अभी हमने प्रस्ताव भिजवाये हैं, उन प्रस्ताव को आप पारित करें, वहां चौमहला की जनता को 48 घंटे में पानी मिलता है। माननीय महोदय, वहां तीसरे दिन पानी मिलता है। वहां डेली सप्लाई के लिए यह परियोजना शुरू की जाये, ताकि क्षेत्र में पानी की व्यवस्था हो सके।

आपने ट्यूबवेल दिये हैं, मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं कि 20 हैंडपम्प दिये, 10 ट्यूबेल दिये। मेरे विधान सभा क्षेत्र में भवानी मंडी को राजगढ़ से जोड़ने का बहुत बड़ा काम किया है। माननीय मंत्री महोदय, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। हमारी सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है। मैं इसी आशा के साथ आपको कहना चाहता हूं कि पिछली सरकार ने कुछ गड़बड़ की है, कुछ गबन किये हैं, उनकी जांच कराई जाये और व्यवस्थित तरीके से पानी दिलाने का काम किया जाये। आपने मुझे बोलने का मौका दिया, बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री रविन्द्र सिंह भाटी।

श्री रविन्द्र सिंह भाटी (शिव): सभापति महोदय, बहुत-बहुत धन्यवाद। पानी पर चर्चा चल रही है और पानी का जो सही मूल्य हैं, वह मरुस्थल के, रेगिस्तान के लोग ही समझ सकते हैं। सीमान्त के लोगों से ज्यादा तो कोई समझ ही नहीं सकता। ऊंडे तळेरो पानी पीर मैं इते तक पूग्या हैं।

आज पानी पर चर्चा चल रही है और सीमान्त के लोगों को आजादी से लेकर आज तक

पानी नहीं मिल पाया है। एक तरफ हम मंगल ग्रह पर पानी ढूंढ रहे हैं, अलग-अलग जगह जा रहे हैं पर वाकई स्थिति क्या है? धरातल की स्थिति क्या है? इस बारे में सोचने की जरूरत है।

स्टेट और सैंट्रल गवर्नमेंट को मैं धन्यवाद देना चाहूंगा कि आप ईआरसीपी जैसी योजना लाए। साथ ही साथ, मैं निवेदन करूंगा कि वेस्टर्न राजस्थान के लिए भी ऐसी परियोजना जरूरी है, जिसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। मेरे से पहले भी कई माननीय सदस्यों ने इसकी मांग रखी, मैं उन्हें भी धन्यवाद दूंगा।

सभापति महोदय, आपके माध्यम से मैं प्रदेश की सरकार से निवेदन करना चाहूंगा कि नर्मदा व इन्दिरा गांधी नहर है, उनका काफी लम्बे समय से एक्सटेंशन रूका हुआ है और काम भी अधूरा है। सीमान्त के लोग चाहते हैं कि नर्मदा और इन्दिरा गांधी नहर को आपस में जोड़ा जाये, ताकि वह जो डीएनपी क्षेत्र है, वे जो सीमान्त के लोग हैं, उनकी जो जमीन है, उसका फायदा मिल सके, वहां बुवाई हो सके।

आज के समय में यह बहुत ज्यादा जरूरी है। मैं नर्मदा नहर की बात करूं तो 2013 में इसको लाया गया था और 2017 तक कम्प्लीट करना था, 217 गांवों का लक्ष्य था पर मुझे बहुत दुःख के साथ कहना पड़ रहा है कि आज भी वह पूरी नहीं हो पाई और अभी तक वह टेस्टिंग में चल रही है। मेरा निवेदन है कि इन्दिरा गांधी नहर परियोजना थी, उसका भी एक्सटेंशन रूका हुआ है। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि इसको भी आप दिखवाये।

बाड़मेर लिफ्ट कैनाल के माध्यम से शिव ब्लॉक के और बाड़मेर के विभिन्न गांवों तक पानी पहुंचाया जाता है पर मोहनगढ़ जहां से यह पानी आता है, वहां पर कई बार बिजली आपूर्ति की कमी के कारण, ये समस्याएं पैदा हो रही हैं। आज जल और बिजली दोनों की चर्चा है, इसलिए मैं इस मुद्दे को भी विशेष रूप से रखना चाहूंगा। मुझे भरोसा है कि आने वाले समय में प्रदेश की सरकार इन विषयों पर मुख्य रूप से ध्यान देगी। आप जो ट्यूबवेल दे रहे हैं, माननीय मंत्री जी ने, अभी सरकार ने, जो ट्यूबवेल और हैंडपम्पस हमें दिये हैं, मैं उसके लिए भी धन्यवाद देना चाहूंगा। उससे पहले भी आपने हमें कई सारे हैंडपम्पस दिये हैं, उसके लिए भी मैं धन्यवाद दूंगा। आप जो हैंडपम्प दे रहे हैं, बोरवेल 600, 700 फीट के बाद में, आपका विभाग कहता है कि इससे ज्यादा हम नहीं कर सकते हैं, अमाउंट इतना ही है।

हमारा भौगोलिक क्षेत्र जो है, भौगोलिक स्थितियां हैं, वे अलग हैं वहां की। 900-1000 फीट से पहले तो पानी ही नहीं आता, आप 600 तक खोद कर छोड़ देते हो। वहां पर जरूरत है कि प्रोपर तरीके से ट्यूबवेल हों। उन लोगों को पानी के लिए भटकना नहीं पड़े, एक ढाणी से दूसरी ढाणी के बीच का जो गैप है, वह बहुत ज्यादा है। मेरा निवेदन है कि आप इस बारे में भी सोचें।

साथ ही साथ, हमारे जो पुराने संसाधन थे, बेरियां थीं, बावड़ियां थीं। हमने उनको रख-रखाव छोड़ दिया। पुराने जो स्रोत थे, हमने उनको छोड़ दिया। जिसकी वजह से हमें ये तमाम समस्याएं देखने को मिल रही हैं। मेरा निवेदन रहेगा कि आप एक विशेष पैकेज बनाये।

विशेषकर सीमान्त के उन लोगों के लिए ताकि वे जो बेरियां हैं, तालाब हैं, बावडि़यां है, उनको हम पूरे तरीके से संरक्षित कर सकें।

साथ ही साथ, एक जायका का प्रोजेक्ट रूका हुआ है, वह काफी लम्बे समय से पेंडिंग चल रहा है। चौहटन की 18 पंचायतें, जो मेरी हैं, उसके साथ-साथ चौहटन क्षेत्र के भी कई सारे गांव इससे प्रभावित हो रहे हैं। मेरा निवेदन है कि इस बारे में भी सोचें।

मेरा निवेदन हैकि स्टाफ की बहुत ज्यादा कमी है। आपको बताना चाहूंगा, जो नर्मदा है, वहां आलेटी से लेकर गडरा तक लगभग पांच एईएन लगते हैं पर वहां पर एक एईएन ही पोस्टेड है। मेरा निवेदन है कि आप स्टाफ को भेजें। कम से कम, जो पिछली सरकार में सही काम नहीं कर रहे थे, आप तो उनको ही भेज दो, पर हमारी वे पोस्टें भर दें, ऐसा मेरा निवेदन है।

साथ ही साथ, काफी लम्बे समय से गर्मी के दिनों में आप कार्मिक लगाते हैं, इनमें कई सारी अनियमितताएं हैं। आप इन ठेकों की विशेष जांच करवायें। लम्बे समय से, जब से आपने यह ठेका प्रथा शुरू की है, तब से लेकर आज तक इसमें भारी अनियमितताएं हैं। आप इसकी जांच करायें। थोड़े दिनों पहले..।

श्री सभापति: विराजें।

Bhs/Rtm/02.08.24/14.40/2g

श्री रविन्द्र सिंह भाटी (शिव): बस, माननीय सभापति महोदय। मैं एक गांव बीजावल में गया, वहां बीजावल में गया, आप सोचो कि वह गांव जहां पर नेटवर्क नहीं है वहां पर कई सारे लोग बड़े बुजुर्ग, 80-90 साल के बुजुर्ग उस टंकी के नीचे बैठे थे वो कह रहे हैं कि साहब, तीस दिन से हमें पानी नहीं मिल रहा है, धरना दे रहे थे। साहब, धरने की स्थितियां क्यों पैदा होती हैं इसके बारे में भी हमें विचार करना होगा। साथ ही साथ मेरा निवेदन रहेगा आपसे।

श्री सभापति: विराजिये, माननीय सदस्य।

श्री रविन्द्र सिंह भाटी (शिव): बस एक मिनट। मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि भांडासर गांव हैं जहां के एक अस्सी साल के बुजुर्ग थे।

श्री सभापति: विराजिये। अंकित नहीं होगा।

श्री रविन्द्र सिंह भाटी (शिव): 000

श्री सभापति: श्री पूसाराम गोदारा।

श्री पूसाराम गोदारा (रतनगढ़): माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे पानी जैसे महत्वपूर्ण मुद्दे पर बोलने का मौका दिया, सबसे पहले यह कहना चाहूंगा कि 'जल है तो कल है जल ही जीवन है'। पूरे प्रदेश में पानी और बिजली की स्थिति वर्तमान में वास्तव में ठीक नहीं है इसलिये मैं चाहूंगा कि इसमें मेरा विधान सभा क्षेत्र रतनगढ़ भी है क्योंकि पानी बिजली पर ही निर्भर है। बिजली की हालत बहुत खराब है इस कारण से पानी की हालत

बहुत खराब है। कहने का मकसद यह है कि मैं विधान सभा क्षेत्र रतनगढ़ से आता हूं वो दो पार्ट में है, एक खारा पानी है, आधे इलाके में सिंचित एरिया है। आज हमारे को 51 एल.एल.डी. पानी की जरूरत है, मात्र 30 या 29 एम.एल.डी. पानी मिलता है और कुछ ऐसे टेल पाइंट के गांव हैं 20-25 जिनमें 15-15 दिन तक पानी नहीं जाता अन्य कोई वहां सोर्स नहीं है।

मैं माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि आपणी योजना को सुनिश्चित किया जाये और उसका पानी हर गांव तक पहुंचे। इसके अलावा शहरी रतनगढ़, राजलदेसर और छापर तीन नगर हैं हालांकि वहां ट्यूबवैल के माध्यम से पानी मिलता है। वहां आज कम से कम शहरी क्षेत्र में दस ट्यूबवैल फेल हैं ग्रामीण क्षेत्र में 14 ट्यूबवैल फेल हैं और उनकी एवज में मैं चाहूंगा सभापति महोदय, माननीय मंत्री महोदय, फेलियर ट्यूबवैल्स को निश्चित रूप से स्वीकृत करें नहीं तो हालत और ज्यादा खराब हो जायेगी।

इसके अलावा, जे.जे.एम. स्कीम फेल है। पूरा काम आज तक इसमें नहीं किया गया। मेरे इलाके में पचास परसेंट काम हुआ है लेकिन सारी सड़कें तोड़ दी, गांवों की सड़कें तोड़ दी और एक भी घर में इनके द्वारा पानी नहीं पहुंचाया गया। पांच परसेंट घरों में कनेक्शन नहीं हुए और किसी भी प्रकार की पाइपलाइन को जोड़ा नहीं गया। पाइपलाइन्स मुंह बाये खड़ी हैं। 10 टंकियां मेरे विधान सभा क्षेत्र में स्वीकृत की वो आज मुंह बाये खड़ी हैं तीन साल हो गये, टंकिंयां पूरी नहीं हुई, उन टंकियों को जोड़ा नहीं गया। पानी को यूज नहीं लिया गया। यह बजट का दुरुपयोग हो रहा है। आपकी सरकार आये आठ महीने हो गये। जे.जे.एम. स्कीम का जो कार्य चल रहा है, उन कम्पनियों के खिलाफ किसी भी प्रकार की कार्यवाही नहीं की गई। रियान नाम की मेरे यहां एक कम्पनी है उसने इतना भ्रष्टाचार किया है और यह सरकार आने के बाद एक दिन भी उसने काम नहीं किया वहां, न मेरे इलाके में किया और न चूरू जिले में किया। उसको ब्लेक लिस्ट किया जाये और अन्य को व्यवस्था दी जाये।

इसके अलावा, बहुत से ऐसे गांव हैं जहां पानी नहीं पहुंचता और ट्यूबवैल खराब हो जाते हैं पांच-पांच दिन ट्यूबवैल ठीक नहीं होते। ...(व्यवधान)... हो गये। ठीक करके आते हो तीसरे दिन फिर खराब हो जाता है। मैं पूछना चाहता हूं कि रिपेयरिंग की क्या व्यवस्था है? इस पर शिकंजा कसा जाये ऐसा मैं माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं। यह तो बोरिंग निकाली, बोरिंग के अन्दर मोटर डाली, दूसरे दिन खराब, तीसरे दिन फिर बोरिंग में मोटर डाली, फिर खराब। यह किस प्रकार का खेल है? यह पानी पिलाने का तरीका थोड़े ही है। हालात बहुत खराब हैं। ऐसी स्थिति मैं चाहूंगा कि इस चीज को भी सुदृढ़ किया जाये और इस प्रकार दोषियों के खिलाफ कार्यवाही की जाये।

सभापति महोदय, इसके अलावा ऐसे बहुत से गांव हैं जिनमें आज भी पानी नहीं जा रहा है वहां अल्टरनेटिव व्यवस्था की जाये और जो हेंडपंप हैं हमारे एरिये में सफल नहीं हैं वहां ट्यूबवैल किये जाने चाहिये। बहुत अच्छी बात है आपने ट्यूबवैल दिये लेकिन ट्यूबवैल्स की संख्या बहुत कम है। इसके अलावा पडियारा गांव है मेरा एक जिसमें 1996 में बनी हुई टंकी

गिर गई, जर्जर अवस्था में थी, उसको तत्काल बनाया जाये। 15 हजार की पापूलेशन का गांव है वह और पानी के हालात वहां खराब हैं।

मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि राजलदेसर जैसा गांव जो तहसील है वहां सहायक अभियंता कार्यालय खोला जाये और वहां से साढ़े आठ किलोमीटर पाइपलाइन रिप्लेसमेंट करने का आदेश प्रदान किया जाये।

इसके साथ-साथ, मैं बिजली के बारे में कहना चाहता हूं कि सिस्टम को जब तक सुधारा नहीं जायेगा पानी के हालात यही रहेंगे। आज मेरे विधान सभा क्षेत्र रतनगढ़ का सिस्टम ओवरलोड है। गांवों में बिजली दस-बारह घंटे नहीं मिलती, शहर में आठ घंटे बिजली नहीं मिलती, पानी कहां से मिलेगा। ओवरलोड स्थिति बनी हुई है।

श्री सभापति: विराजिये।

श्री पूसाराम गोदारा (रतनगढ़): आधा मिनट। ओवरलोड स्थिति बनी हुई है।

श्री सभापति: विराजिये। अंकित नहीं होगा।

श्री पूसाराम गोदारा (रतनगढ़): 000

श्री सभापति: श्री राम सहाय वर्मा (रेगर)।

श्री राम सहाय वर्मा (रेगर) (निवाई): माननीय सभापति महोदय, आपने सदन में बोलने का अवसर दिया, इसके लिए आपका बहुत-बहुत आभारी हूं।

सभापति महोदय, विगत कांग्रेस सरकार ने पेयजल में वैकल्पिक स्रोतों को बढ़ाने में कोई कार्य नहीं किया जिससे लोगों को मजबूरीवश ट्यूबवैल कराने पड़े, जिससे भूजल दोहन बड़े पैमाने पर हो रहा है जैसा कि कल माननीय मंत्री महोदय सदन में बता रहे थे कि 148 प्रतिशत भूजल का दोहन हो रहा है। यह गम्भीर विषय है। हम सभी को इस विषय पर चिन्तन-मनन करने की आवश्यकता है।

माननीय प्रधान मंत्री जी ने भूजल के वैकल्पिक उपयोग के रूप में ई.आर.सी.पी. योजना का प्रयास किया लेकिन विगत सरकार ने लम्बे समय तक ई.आर.सी.पी. को लटकाने का कार्य किया लेकिन मैं इन्हें कोई दोष नहीं दूंगा क्योंकि ये तो अपनी सरकार को अपनों से ही बचाने में व्यस्त थे। इन्हें कहां से राजस्थान की जनता की समस्याओं का आभास होता।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से अवगत कराना चाहता हूं कि मेरे विधान सभा क्षेत्र में दो बड़े बांध हैं पहला मासी बांध जिसमें 450 मिलियन क्यूबिक फीट पानी है। जलदाय विभाग के लिए आरक्षित है। दूसरा, बीडोली बांध जिसमें 45 मिलियन क्यूबिक फीट पानी आरक्षित है। सभापति महोदय, बताना चाहूंगा कि विगत सरकार के अपने कार्यकाल में दोनों बांधों से पानी लेने के लिए कोई ठोस प्रयास नहीं किये गये जिससे निवाई पीपलू की जनता को प्रत्येक ग्रीष्म ऋतु में पेयजल समस्या का सामना करना पड़ रहा है तथा भूजल दोहन की ओर जनता को जाना पड़ा।

सभापति महोदय, आपके माध्यम से धन्यवाद देना चाहूंगा मुख्य मंत्री महोदय को तथा विभाग के माननीय मंत्री कन्हैया लाल जी का जिन्होंने पेयजल समस्या के समाधान के लिए

इन दोनों बांधों से क्षेत्रवासियों को पेयजल उपलब्ध करवाया। मासी बांध में 114 मिलियन क्यूबिक फिट और लगभग 80 लाख लीटर पानी प्रतिदिन पेयजल उपलब्ध कराने के लिए 21 करोड़ रुपये की तकनीकी स्वीकृति जारी करवाई तथा बीडोली बांध से निवाई शहर को पानी लाने के लिए भी पाइपलाइन प्रस्तावित है।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से विगत सरकार के पेयजल स्रोत में किये गये कार्य सदन में बताना चाहूंगा। मेरा आपके माध्यम से सभी माननीय सदस्यों से निवेदन है कि कार्यों के सम्पादन के समय थोड़ा ध्यान दीजियेगा। विगत सरकार ने 11 फरवरी, 2021 को जल जीवन मिशन के तहत हर घर में जल नल कनेक्शन कार्य हेतु 154.28 करोड़ की वित्तीय स्वीकृति जारी तो की, लेकिन इस कार्य का कार्यादेश जारी करने में लगभग दो साल का समय लग गया। विधान सभा चुनाव की आचार संहिता लगने के तुरन्त पूर्व दिनांक 6 सितम्बर, 2023 को इन्होंने कार्यादेश जारी किया।

सभापति महोदय, आपके माध्यम से बताना चाहूंगा कि विगत सरकार में बैठे महानुभावों को भविष्य को देखने की शक्ति बड़ी कमाल की थी। इनको विधान सभा चुनाव पूर्व ही इस बात का आभास था कि सूबे में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने वाली है। राजस्थान की जनता की तरह हमारे विपक्ष के साथियों को भी हमारी सरकार की कार्यप्रणाली का पूरा भरोसा है, तभी तो इन्होंने जिस कार्य की प्रशासनिक स्वीकृति जारी होने में और कार्यादेश जारी होने में 21 माह का समय लिया उसी कार्य की पूर्णता अवधि 15 माह निश्चित कर दी थी। विगत सरकार का धन्यवाद जिन्होंने समय से पूर्व ही आकलन कर लिया कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस कार्य को धरातल पर पन्द्रह माह में पूरा कर देगी।

सभापति महोदय, आपके माध्यम से धन्यवाद देना चाहूंगा माननीय मुख्य मंत्री महोदय तथा विभाग के माननीय मंत्री जी का जिन्होंने सरकार गठन के साथ ही हैंडपंप व ट्यूबवैल की स्वीकृतियां जारी की। समस्या से कुछ राहत देने का नेक कार्य किया।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से बताना चाहूंगा कि आपने हिन्दी में एक कहावत सुनी होगी कि 'आंधा बांटे रेवड़ी, अपने-अपनों को ही दे।' लेकिन मेरा क्षेत्र इसमें पीछे रह गया। विगत सरकार के सत्ताधारी दल का विधायक होने के बावजूद भी मेरे विधान सभा क्षेत्र को हाशिये पर रखा। मेरे क्षेत्र की जनता के लिए पूरे विधान सभा क्षेत्र में कोई भी बृहद् जलाशय का निर्माण विगत वर्षों में नहीं किया। कोई नयी पाइपलाइन नहीं बिछायी जो हैंडपंप तथा ट्यूबवैल दिये गये वो किसी के घर पर लगवाये या किसी के बाड़े में लगवाये हैं। सार्वजनिक स्थानों पर आज भी पेयजल की समस्या व्याप्त है तथा मेरे विधान सभा क्षेत्र की जनता को धन्यवाद देना चाहूंगा जिन्होंने इतनी समस्याओं को सहते हुए अपने पांच वर्ष निकाले हैं।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन को बताना चाहूंगा कि मेरे विधान सभा क्षेत्र में कई गांव ऐसे हैं जहां आज भी पानी टेंकरों से सप्लाई हो रहा है।

श्री सभापतिः विराजो।

श्री राम सहाय वर्मा (रेगर) (निवाई): सभापति महोदय, एक मिनट तो दे दो। माननीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से मुख्य मंत्री महोदय और मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि मेरे विधान सभा क्षेत्र की पेयजल समस्याओं को देखते हुए निवाई तथा पीपलू तहसील के गांवों में उच्च क्षमता वाले जलाशयों का निर्माण करवाया जाये।

Kas/rtm/02.08.2024/14.50/2h

श्री सभापतिः मंत्री महोदय को कॉपी दे दो।

श्री राम सहाय वर्मा (रेगर) (निवाई): सभी सरकारी कार्यालयों में तथा निजी संस्थाओं में वाटर हार्वेस्टिंग प्रणाली को विकसित करवाया जाये। आपने मुझे बोलने का समय दिया, इसके लिये बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापतिः डॉ. शिखा मील।

डॉ. शिखा मील बराला (चोमू): सदन को नमस्कार। माननीय सभापति महोदय, आपका आभार कि आपने मुझे राज्य में पेयजल की स्थिति पर विचार रखने का अवसर दिया। जल ही जीवन है, पर फिलहाल स्थिति बहुत ही विकट है। डाइनेमिक ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज रिपोर्ट में 2025 तक जयपुर, अजमेर, जैसलमेर और जोधपुर में पानी की उपलब्धता का आकलन शून्य किया गया है और वह दिन दूर नहीं जब हम भी साउथ अफ्रीका के कैपटाउन जैसे शहरों की लिस्ट में शुमार होंगे। सारे देश के लिये यह एक गंभीर चेतावनी है। मेरा चौमूं विधान सभा क्षेत्र जयपुर डिस्ट्रिक्ट में आता है और वहां से पूरे प्रदेश में फल-सब्जियां सप्लाई की जाती हैं। बहुत सारे विक्रेता बाहर अपने बैनर लगाकर रखते हैं कि चौमूं की ताजा फल और सब्जियां। फिलहाल हम बूंद-बूंद पानी के लिये तरह रहे हैं, हम डार्क जोन में हैं। चौमूं ग्रामीण में पेयजल की पूर्ति के लिये जेजेएम योजना का कार्य बहुत ही शिथिल प्रगति पर है। वहां पर ग्राउंड वाटर है नहीं। बिजली बिल की स्थिति है कि उसे पंचायत पे करे या पीएचइडी डिपार्टमेंट उसे पे करे, इस पर मंत्रालय जल्दी ही अपनी स्थिति स्पष्ट करें, क्योंकि बहुत सारी योजनाएं हैं जो इसी कंफ्यूजन में शुरू नहीं हो पा रही हैं। एक-एक ठेकेदार को 15-15, 18-18 टेंडर्स दिये गये हैं। टेंडर पास होने के बाद में ठेकेदार गायब हैं, वह लोग जवाब नहीं देते हैं, इसकी वजह से कार्य आगे प्रगति नहीं कर पा रहा है। अभी तक स्टेट का जेजेएम कवरेज 51 परसेंट है, लेकिन हमारे गोविंदगढ़ ब्लॉक में वह सिर्फ 37 परसेंट है। 45 हजार घरों में कनेक्शन देने का टार्गेट था, जो अभी सिर्फ 17 हजार पर पहुंचा है। सरकार अपनी मंशा स्पष्ट करे कि 31 मार्च के बाद और टेंडर्स नहीं हो रहे हैं, और वर्क आर्डर नहीं हो रहे हैं, सरकार क्या मंशा रखती है?

फिलहाल जो सरकार है, वह डबल इंजन की सरकार कही जा रही है, पर मुझे लगता है फेल्ड इंजन की सरकार साबित हो रही है, क्योंकि न तो छत्तीसगढ़ से कोयला मिल रहा है, ना एम.पी आपको पानी दे रहा है, ना आपको हरियाणा पानी दे रहा है। केन्द्र आपको ठीक से बजट नहीं दे रहा है। केन्द्र आपको जेजेएम योजना के लिये एक्सटेंशन नहीं दे रहा है। ऐसी

स्थिति में हमारी पानी की समस्या के लिये क्या किया जायेगा? जनता पानी पीये तो कहां से पीये? सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि वह उसे निभाये और किसी तरह के अनर्गल स्टेटमेंट नहीं देते हुए जनता के प्रति अपनी जिम्मेदारी को निभाये। फिलहाल अव्यवस्था वैसे ही है।

पीएचईडी डिपार्टमेंट को राजस्थान वाटर सप्लाई एण्ड सीवरेज कॉपरेशन में बदलने का शायद प्लान हो रहा है। सरकार इस पर भी स्पष्ट करे कि इसके बाद संभवतः जो वाटर टेरिफ बढ़ेंगे, वह क्या जनता ही ढोयेगी? पानी हमारे लिये कोई लग्जरी नहीं है, वह हमारा मूलभूत अधिकार है। इसे तो सोशियल सिक्योरिटी में लाना चाहिये। इसके लिये सरकार इस पर फिर एक बार विचार करें कि पीएचईडी को अगर निगम बनाया जाता है तो उसके कर्मचारियों के वेतन का किस प्रकार से भुगतान होगा और जनता किस तरह से उसे झेलेगी।

चौमूं शहर में कुल पानी की मांग 90 लाख लीटर प्रतिदिन है, पर फिलहाल सप्लाई सिर्फ 1/3, 31.5 लाख लीटर प्रतिदिन हो रही है, जो कि सारे सोर्सेज को मिलाकर है। इस तरह एक ग्रोस डिस्प्रपोर्शन है डिमांड और सप्लाई में। लोगों को हर महीने हजारों रुपये के टेंकर्स मंगवाने पड़ रहे हैं और फिर भी बहुत ही पूअर क्वालिटी पानी पीना पड़ रहा है। फ्लोराइड युक्त पानी पीना पड रहा है। लोग पानी माफिया और टेंकर माफिया के शिकार हो रहे हैं। कांग्रेस सरकार ने चौमूं को ईसरदा बांध से पानी पिलाने की घोषणा की थी, पर वर्तमान सरकार ने उसे गोलमाल कर दिया।

अमृत-2 योजना के लिये चौमूं के नाम पर कुछ 19-20 करोड़ रुपये प्रस्तावित किये गये हैं, पर अभी तक अमृत-2 योजना का कोई रोड मैप स्पष्ट नहीं हो रहा है। हमारी मांग है कि या तो हमें बीसलपुर योजना से पानी पिलाया जाये या अमृत-2 योजना का स्टेटस क्लियर किया जाये।

भू-जल स्तर सुधारने के लिये जल शक्ति अभियान 2024 को ठीक से इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। वाटर हार्वेस्टिंग के लिये, रेन वाटर हार्वेस्टिंग के लिये ग्रामीण इलाकों में सब्सिडी देनी चाहिये। मुझे लगता है कि जनता, सिस्टम, सभी में इच्छा शक्ति की कमी है, क्योंकि मैंने उच्च अधिकारियों से भी डिसकस किया था, उसमें था कि सहारा रेगिस्तान में एक व्यक्ति ने अपनी इच्छा शक्ति का प्रदर्शन किया और एक क्षेत्र चुना जिसमें 100-100 मीटर पर 3X5 के गड्ढे खोदे और उनमें बरसात का पानी भरा गया। एक से दो साल में पूरे क्षेत्र की काया पलट हो गई, वह एक हरित क्षेत्र में बदल गया।

श्री सभापतिः विराजिए।

डॉ. शिखा मील बराला (चोमू): ऐसी ही इच्छा शक्ति जनता, सरकार और हम पक्ष-विपक्ष, सभी लोगों को दिखानी चाहिये और जनता को उनका हक देना चाहिये। आपने विचार रखने के लिये अवसर दिया, धन्यवाद।

श्री सभापतिः श्री कैलाश चन्द वर्मा।

श्री कैलाश चन्द वर्मा (बगरू): माननीय अध्यक्ष महोदय, राज्य में पेयजल की स्थिति पर

आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, उसके लिये आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। माननीय सभापति महोदय, चूंकि मुझे पता है कि पांच मिनट का न्यूनतम समय है, मैं मेरे बगरू विधान सभा क्षेत्र की मांग पर सीधा आऊंगा। मेरे को यह भी पता है कि जिस तरह से अभी माननीय नेता प्रतिपक्ष जवाब दे रहे थे, सच कहूं तो असत्य का जनरेटर, विगत सरकार के लिये चार पंक्ति कहना चाहूंगा,

नये किरदार आते रहे, मगर नाटक वही पुराना चलता रहा।
नेता होटलों में आराम करते रहे, आम आदमी घुट-घुट कर मरता रहा।

तरह-तरह के वादे किये गये कि हमने यह किया, हमने वो किया। ...(व्यवधान)... हम आपकी बातों को सुन रहे थे।

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): असत्य का जनरेटर, प्रताप सिंह जी ने आप लोगों के लिये कहा था, सदन में इस तरह की बात कहना शोभा नहीं देता। हमारे शब्दों को रिपीट मत करो, नये चुन कर लाओ। सभापति महोदय, आप इसको कार्यवाही में से हटवाओ।

श्री कैलाश चन्द वर्मा (बगरू): सभापति महोदय, आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से मेरा निवेदन रहेगा कि 2013-18 के बीच हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, उस भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बगरू विधान सभा क्षेत्र की जनता को पेयजल उपलब्ध कराने के लिये ग्राम चारणवाला में, हरमून की नांगल में जमीन अलाटमेंट की। बीसलपुर फेज-2 में बगरू विधान सभा क्षेत्र के 144 गांव, 1000 से ज्यादा ढाणियों को पानी उपलब्ध कराने के लिये 3 नवम्बर, 2016 को आदेश जारी किये। बगरू विधान सभा क्षेत्र को बीसलपुर का पेयजल उपलब्ध हो, इसके लिये 18 अगस्त, 2017 को डीपीआर बनाने के आदेश दिये। विगत भाजपा सरकार द्वारा बीसलपुर फेज-2 के लिये एक हजार करोड़ रुपये की घोषणा का प्रावधान किया। बगरू विधान सभा क्षेत्र को बीसलपुर पेयजल आपूर्ति के 23 फरवरी, 2018 को आदेश जारी किये। मगर बड़े शर्म की बात है, अभी बड़े-बड़े वादे कर रहे थे, आपकी सरकार को चीफ सैक्रेटरी चला रहे हैं। आपकी पूर्ववर्ती सरकार के समय ओसिया से आने वाली माननीय विधायक ने आप ही की सरकार के ऊपर कहा था कि पीएचईडी मिनिस्टर इज ए रबर स्टांप और सरकार को चीफ सैक्रेटरी चला रहा है। यह मैं नहीं बोल रहा, यह आंकड़ें बोल रहे हैं, आप कहोगे तो इन आंकड़ों को मैं टेबल करूंगा। आप ही की सरकार की पूर्व माननीय सदस्या ने आप ही की सरकार के खिलाफ बालावाला में डिग्गी रोड पर धरना दिया और आपके कैबिनेट मिनस्टर वहां जाकर यह कहते हैं कि यह तो भारतीय जनता पार्टी की योजना है, इसको चालू करेंगे तो भारतीय जनता पार्टी का नाम होगा। क्या कसूर था बगरू विधान सभा क्षेत्र की उस भोलीभाली जनता का जिसके साथ आपने खिलवाड़ किया?

मेरा प्रदेश के लोकप्रिय मुख्य मंत्री श्री भजन लाल जी शर्मा और जलदाय मंत्री सम्माननीय कन्हैया लाल जी से आग्रह रहेगा कि जो लोग इस बीसलपुर योजना में राजनीति कर रहे थे, कौन थे वो राजनीतिक लोग, उनका पर्दाफाश किया जाये, क्योंकि यह योजना

बगरू विधान सभा क्षेत्र के उन पांच लाख लोगों से जुड़ी हुई है, जिसमें 30 ग्राम पंचायतें, 2 नगरपालिका और लगभग बगरू शहरी क्षेत्र के 104 से 124 तक के वार्डों का ऐरिया इसमें आता है। गोनेर रोड, लूनियावास, आगरा रोड, खोरी, रोपाड़ा, मच्छ की पीपली, प्रताप नगर, जगतपुरा, टोंक रोड और 144 गांव, 1000 ढाणियां, मेरा मंत्री जी से आग्रह रहेगा कि बगरू विधान सभा क्षेत्र की टेंडर प्रक्रिया शीघ्र पूरी की जाये। बीसलपुर योजना से जुड़ी हुई बगरू की जनता के लिये शीघ्र बीसलपुर पेयजल सुनिश्चित हो, इसके लिये जल्दसे जल्द कार्य शुरू करके यह योजना, जो जनता की योजना थी, जो 2013-18 के बीच में बगरू विधान सभा क्षेत्र के लिये बनी, माननीय मंत्री महोदय, जो पानी अजमेर, किशनगढ़, ब्यावर, नावां, दौसा गया, वह पाइप लाइन बगरू के अन्दर से जा रही है।

Msk/rtm/02.08.24/1500/2j

बगरू की जनता का क्या कसूर था, जो इस योजना को आपने ठंडे बस्ते में डाल दिया। मेरा अंत में, क्योंकि हमारे मंत्री महोदय दयालु हैं। अंत में यही कहूंगा:- 'हाथी-घोड़ा पालकी, जय कन्हैया लाल की' आपने मुझे अवसर दिया, बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री लक्ष्मण।

श्री लक्ष्मण (बस्सी): सभापति जी, धन्यवाद, राज्य में पेयजल की स्थिति पर चर्चा के लिए मुझे आपने समय दिया। वैसे तो दो दिन से काफी गंभीर चर्चा हो रही है। माननीय सदस्यों ने अपने-अपने विचार व्यक्त किये, अच्छे सजेशन दिये, अगर उन पर कार्यवाही होती है तो मेरे खयाल से पानी की जो समस्या प्रदेश में है, उसका निराकरण होने में मदद मिलेगी।

माननीय सभापति महोदय, मैं केवल दो-चार छोटे-छोटे सजेशंस इसके बारे में देना चाहूंगा। अगस्त, 2019 में जब जेजेएम चालू की गयी, उसके बाद चार साल में। जैसा कि आप खुद ही बता रहे थे कि 93 लाख कनेक्शन के कार्यादेश दिये गये थे, उनमें 53 लाख कनेक्शन हो पाये। उन 53 लाख कनेक्शंस में भी कितनों में पानी आ रहा है, कितने में 55 एलपीसीडी पानी आ रहा है, इसके बारे में कोई आकलन नहीं किया गया है। सभापति महोदय, इसमें पानी के लिए जो कनेक्शन दिये हैं, वे टारगेट ओरियंटेड थे। बहुत जल्दबाजी में कनेक्शंस दिये हैं, क्योंकि पैसे लेने के लिए दिल्ली की सरकार को रिपोर्ट करना था और वहां कनेक्शन बता दिया गया, वहां पांच दिन पानी आया और उसको हमेशा के लिए पानी आना बताया गया है। जहां-जहां भी ये जेजेएम के कनेक्शन हुए हैं, वहां समस्या वैसी की वैसी ही है। कई-कई जगह तो 15-15 दिन तक जेजेएम के कनेक्शन में पानी नहीं आ रहा है और समस्या वहां पर विकट बनी हुई है। 55 एलपीसीडी की बात छोड़िये, आपको 20-25 लीटर पानी प्रतिदिन किसी व्यक्ति को नहीं मिल रहा है।

इस सम्बन्ध में मेरा निवेदन है, मेरा सुझाव है। अभी आप बता रहे हैं कि बजट में 15 हजार करोड़ रुपये खर्च करके 25 लाख कनेक्शन 8 महीने के अन्दर दे दिये जायेंगे। यह

कतई संभव नहीं है। आप जब चार साल के अन्दर 53 लाख कनेक्शन दे पाते हैं तो ऐसी कौनसी मशीनरी है, ऐसी कौनसी इनके पास चमत्कारी संस्थाएं हैं, जो 8 महीने के अन्दर 25 लाख कनेक्शन देंगे। अगर कनेक्शन देंगे तो उनके अन्दर पानी नहीं आ पायेगा। आप कनेक्शन देने की बात कर रहे हैं। राजस्थान की भौगोलिक स्थिति अलग-अलग है। कई जगह एक हजार फीट तक भी पानी नहीं है, कई जगह बिल्कुल भी पानी नहीं है और कई जगह पहाड़ी इलाका है। सब में एक साथ नॉर्म्स तय कर दिये हैं कि सब जगह कुएं खोद दिये जायेंगे, कुओं को रिचार्ज कर दिया जायेगा, ट्यूबवैल खोद दिये जाएंगे। सभापति महोदय, मैं बताना चाहता हूं कि जितने भी ट्यूबवैल खोदे गये हैं, वे सारे के सारे फेल हो गये। वे पांच-छह महीने तक चलते हैं, उसके बाद वे ड्राई हो जाते हैं। राजस्थान में कुओं की बात कर ही नहीं सकते हैं। कुएं पूरे सूख गये, कितने भी गहरे खोद लो। आपको पानी नहीं मिलेगा। उनसे आप जेजेएम के कनेक्शन कर रहे हैं तो किस तरीके से पानी आयेगा। दूसरी स्थिति यह है कि अगर आप बहुत ज्यादा गहरा खोद रहे हैं तो पानी की क्वालिटी बहुत अच्छी नहीं है। पानी पोटेबल नहीं है। उसमें फ्लोराइड की मात्रा बहुत ज्यादा है। नाइट्रेट है, आर्सेनिक है, लवणीय पानी है, इससे लोगों का स्वास्थ्य खराब हो रहा है। एक तरफ तो आप पानी देने की बात कर रहे हैं। दूसरी तरफ लोगों का स्वास्थ्य खराब करने की स्थिति पैदा कर रहे हैं।

मैं दूसरा सुझाव दूंगा कि हमारे जो परम्परागत स्रोत हैं, जैसे कुएं हैं, नालियां हैं, खडीन हैं, टांके हैं, उन पर ज्यादा इन्वेस्टमेंट करिये, उन पर ज्यादा पैसे खर्च करिये। वे पीने के पानी के विश्वसनीय स्रोत हैं। उनसे पानी का पुनर्भरण भी होगा और उसके अलावा लोगों को अच्छा पानी मिलेगा, दूषित पानी नहीं मिलेगा, बरसात का पानी मिलेगा। तीसरा, ये जितने भी ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, उनमें तेजी लायी जानी चाहिए। तेजी लाकर उनको पूरा किया जाना चाहिए, जैसे ईआरसीपी है। नर्मदा का जो समझौता किया है, उसको धरातल पर लाया जाए। (समय समाप्ति सूचक घंटी)

माननीय सभापति महोदय, मेरा एक और है। ये चीजें टारगेट आरियंटेड चीजें हैं, जैसे ईसरदा का है। ईसरदा में दो साल में पानी नहीं आने वाला है। वहां 700 गांवों के अन्दर लाइनें डाल दी गयी हैं। लाइनें डाल दीं, पम्प हाउस कहां बनेगा? कहां फिल्टर हाउस बनेगा? जमीन चिह्नित नहीं है। फिर भी आप ऐसे पैसे खर्च कर रहे हैं तो पानी के नाम से जनता के पैसों की बर्बादी हो रही है। सुनियोजित तरीके से कोई काम नहीं हो रहा है। आपने समय दिया, उसके लिए बहुत-बहुत दिया।

श्री सभापतिः श्री ताराचन्द।

(समयः बजे)

(श्री राजेन्द्र पारीक, सभापति, पदासीन)

श्री ताराचन्द (डूंगरगढ़): सभापति महोदय, मुझे आपने पेयजल पर बोलने का मौका दिया, उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। सभापति महोदय, जल जीवन मिशन बहुत बढ़िया

योजना थी। राजस्थान में पिछली सरकार ने राजस्थान को 33वें नम्बर पर रखा और स्थिति यह कर दी कि कहीं पर तो कुएं खोदे, कहीं पर टंकियां बनाकर छोड़ दीं। कहीं पर पाइप बिछाकर छोड़ दिये। किसी के घर पर जैसे खाली टोंटी लगा दी, वहां पर पानी आने का कोई साधन ही नहीं है। बहुत-सी ऐसी टंकियां हैं, जो सूख गयी हैं, उनमें आज तक पानी नहीं भरा गया है। इन्होंने ऐसे खुला भ्रष्टाचार किया है। इनके ठेकेदार, इनके साथ बड़े-बड़े मंत्री और उन्हीं के ठेकेदार, सारी इस योजना की भद्द पटक कर छोड़ दी और लोगों को प्यासा मरने के मजबूर कर दिया।

सभापति महोदय, मैं मेरे विधान सभा क्षेत्र श्रीडूंगरगढ़ पर आऊंगा। मेरे विधान सभा क्षेत्र में 117 गांव हैं और एक कस्बा है। विधान सभा क्षेत्र में सभी पेयजल योजनाएं हैं, वे भू-जल पर आधारित हैं और भू-जल स्तर बहुत ज्यादा नीचे गिर गया है। 400 से 500 मीटर नीचे, मतलब 1500 फुट के बाद में पीने का पानी आता है। यह स्थिति हमारे भू-जल की है। पूर्व में बने ज्यादातर नलकूप जो कि 700-800 फीट थे, वे सूख गये, जिसमें आम जन को पेयजल की समस्या का सामना करना पड़ रहा है। इसके निवारण के लिए वर्तमान में नये नलकूपों की बड़ी आवश्यकता बनी हुई है। वर्तमान में किसी भी निजी ठेकेदार के पास विभाग का कोई कार्यादेश नहीं है, जिससे नलकूपों का निर्माण करवाया जा सके। भू-जल विभाग के पास पर्याप्त क्षमता की मशीनें भी उपलब्ध नहीं हैं, जिससे नलकूपों का निर्माण करवाया जा सके। पूरे विधान सभा क्षेत्र में पीने के पानी की भंयकर समस्या बनी हुई है। मैं आपके माध्यम से निवेदन करता हूं कि भू-जल विभाग को कम से कम 5 नयी मशीनें जो कि कॉम्बीनेशन प्रकार की हों, 2 हजार फीट तक रोटेरी ड्रिलिंग एवं डीटीएच भेजने की क्षमता से कार्य कर सके। ऐसी मशीनें विभाग को लानी होंगी, जिससे राजकोष को भारी बचत होगी। मशीनों को पूरे जिले में अन्य विकास कार्यों में भी लिया जा सकता है। पिछले छह माह से स्वीकृत हुआ एक भी नलकूप नहीं खुदा है और पुराने नलकूप सूख चुके हैं। पूरे विधान सभा क्षेत्र में पेयजल की भारी समस्या उत्पन्न हो गयी है। पिछली कांग्रेस सरकार ने जिला स्तर पर एकल ठेकेदार की निविदा कार्यादेश दिये थे, जिससे ठेकेदार ने अपनी मोनोपोली चलायी। उसके पास एक ही ड्रिलिंग मशीन होने के कारण कार्य में अनावश्यक विलंब किया। अतः मेरा आपसे निवेदन है कि आगे से अगर ठेका देना हो तो उपखण्ड वार निविदा जारी करने हेतु अधिकारी को निर्देशित करें, ताकि अन्य संवेदक भाग ले सकें एवं मोनोपोली को समाप्त किया जा सके और नलकूपों का निर्माण शीघ्र हो सके। अतः मेरा आपसे निवेदन है कि पेयजल समस्या की जल्दी से जल्दी कार्यवाही करवाने की कृपा करें, ताकि जनता को राहत मिल सके।

सभापति महोदय, पिछली सरकार ने हमारे जो इंदिरा गांधी नहर से जल जीवन मिशन के तहत जो पानी आना था, 700-800 करोड़ रुपये के लगभग का ठेका हो चुका था। सब कुछ हो चुका था, किन्तु इनकी बिल्कुल भी इच्छाशक्ति नहीं थी। ये तो लूटने में लगे हुए थे, इनको जनता की परवाह नहीं थी कि जनता को पानी मिलेगा कि नहीं मिलेगा। यह ऐसी

स्थिति करके छोड़ दी है कि हम छह महीने के भीतर भी उसको नहीं सुधार पाये। हमें आगे इसको सुधारना बहुत जरूरी है। पहले इन्होंने ठेका लिया और नलकूप 600 फीट खोदकर छोड़ गये। उसका पैसा पूरा उठा लिया। ऐसे कम से कम 60 परसेंट नलकूप हैं, जो खोदकर छोड़ दिये हैं, उनमें एक बूंद भी पानी नहीं आया और उनका पूरा का पूरा पैसा उठ गया।

सभापति महोदय, मेरा आपके माध्यम से मंत्री जी से निवेदन है कि ऐसा जो भ्रष्टाचार हुआ है, उसके खिलाफ कार्यवाही करें और ठेकेदारों को पकड़े, उन्होंने पाइप बिछाकर छोड़ दिये और कहीं से पानी से नहीं जोड़ा। कबाड़खाने से पाइप लाकर बिछाकर छोड़ दिये और खुला भ्रष्टाचार किया है। इस भ्रष्टाचार के ताण्डव को उजागर करिये, ताकि जनता को इनके कारनामों का पता लगे कि ये कितनी बुरी दशा करके गये हैं? ताकि आने वाली जनता की पीढियां भी इनको माफ नहीं करेगी। धन्यवाद, जय हिन्द, जय भारत।

mdp/rtm/02.08.2024/15:10/2k

श्री सभापतिः श्री पितराम सिंह काला।

श्री गुरवीर सिंह (सादुलशहर): सभापति जी, मैं टेबल करना चाहता हूं।

श्री सभापतिः एक बार इनको बोलने दीजिए।

श्री पितराम सिंह काला (पिलानी): सभापति महोदय, आपने मुझे पानी की चर्चा पर बोलने का मौका दिया, इसके लिए धन्यवाद। मैं शेखावाटी के उस क्षेत्र से आता हूं जो पिलानी का क्षेत्र है। पूरे विश्व में प्रसिद्ध है शिक्षा नगरी के नाम से। जो नासा की रिपोर्ट आयी थी, उस रिपोर्ट के अनुसार सबसे ज्यादा भू-जल स्तर यदि कहीं नीचे गया है तो वह शेखावाटी क्षेत्र के अन्दर गया है। इसमें भी विशेष रूप से पिलानी का जो क्षेत्र है, वह पानी की स्थिति के अन्दर शायद राजस्थान में सबसे खराब स्थिति के अन्दर है। आज पानी की वहां यह स्थिति है कि तीन-तीन दिन से लोगों को पानी नहीं मिल रहा है। पानी के जो ट्यूबवेल हैं, वह इतने गहरे चले गये हैं कि 1300-1400 फीट गहराई तक चले गये। उसके बाद भी पानी उपलब्ध नहीं हो रहा है।

सभापति महोदय, आपके माध्यम से मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि कल हालांकि इन्होंने प्रश्न जो लगाया था, उसके माध्यम से सारी चीजें बता दीं, वह भी मैं बाद में बताऊंगा। जो ट्यूबवेल हैं, यदि उनको गहरा करवा दिया जाए तो विभाग के ऊपर खर्चा नहीं आयेगा और मात्र दो-ढाई लाख से नया ट्यूबवेल तैयार हो जाएगा। यह काम आप करवाए। इसी के साथ पिलानी एक ऐसा क्षेत्र था, जिसके अन्दर पानी को लेकर गांवों के अन्दर चुनाव का बहिष्कार किया गया था। दस-बारह गांव ऐसे थे, जिन्होंने कह दिया हमें पानी नहीं मिलेगा तो हम चुनाव में हिस्सा नहीं लेंगे। लोकतंत्र के अन्दर कोई आदमी यदि चुनाव का बहिष्कार करता है तो यह हमारे लिए, 75 वर्ष हो गये, बड़े शर्म की बात है।

सभापति जी, मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि ट्यूबवेल गहरे तो करवाएं, इसके साथ ही जो छोटी-छोटी चीजें हैं, जैसे पाइप है, केबल है, किट आउट वगैरह हैं, स्टार्टर वगैरह,

छोटी-छोटी चीजें आप उपलब्ध करवाएं, कंटीजेंसी के अन्दर। छोटे-छोटे काम के लिए वहां पर आपके नीचे के अधिकारी हैं, जैसे जेइएन है, जो डील करता है, उसके पास यह समस्या आती है तो वह एक्सइएन की तरफ देखता है, एक्सइएन एसई की तरफ देखता है। वह समस्या का समाधान नहीं कर सकता। आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि जो छोटे-मोटे आवश्यक सामान हैं, उसके लिए आप विभाग को अधिकृत करे, टेंडर की आवश्यकता हो तो टेंडर करें और उनको वह सामान उपलब्ध करवाएं।

सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि पिलानी विधान सभा क्षेत्र के अन्दर पिछले 10-11 महीनों से किसान आंदोलन पर बैठे हुए हैं। वह केवल इसी बात के लिए आंदोलन पर बैठे हुए हैं कि हमारी समस्या का समाधान किया जाए। मैं उस तरफ भी आपका ध्यान दिलाना चाहूंगा। एक महत्वपूर्ण प्रश्न है कि जितने ट्यूबवेल सूख गये, उन सूखे हुए ट्यूबवेल की कोई संख्या निर्धारित नहीं की जाए। उस क्षेत्र के अन्दर जितने ट्यूबवेल सूख गये, उनकी जगह नया ट्यूबवेल करवाया जाए। यह बहुत आवश्यक है। दूसरा, एक कुंड है। (समय समाप्ति सूचक घंटी) यदि कुंड के लिए अनुदान दे दिया जाए तो यह ट्यूबवेल का विकल्प हो सकता है। इस पर भी विचार किया जाए।

माननीय सभापति जी, अंत में, आपने घंटी बजा दी, मैं मंत्री महोदय को धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने अपने प्रश्न के जवाब में कल यह कहा था कि आपकी अमृत-2 योजना है, उसके अन्दर पिलानी और चिड़ावा शहर दोनों को सम्मिलित कर लिया गया है। इसी के साथ कुम्भाराम लिफ्ट योजना है, माननीय मंत्री महोदय ने कहा था कि मैं मार्च, 2027 तक वहां आपके प्रत्येक घर के अन्दर पानी पहुंचा दूंगा। इसके लिए दिल की गहराइयों से मंत्री जी को धन्यवाद। जय हिन्द। जय भारत।

श्री सभापतिः श्री प्रताप पुरी।

श्री गुरवीर सिंह (सादुलशहर): सभापति जी, एक ही मिनट लूंगा। एक मिनट से ज्यादा नहीं लगेगी। चार ही सुझाव हैं। चार लाइनों के। कल से चर्चा हो रही है विपक्ष और पार्टी सत्ता दोनों की तरफ से मांग हुई है भ्रष्टाचार पर। उसके लिए मेरे चार सुझाव हैं।

श्री सभापतिः प्लीज, विराजिए। सरकार के संज्ञान में आ गया। अंकित नहीं होगा।

श्री गुरवीर सिंह (सादुलशहर): 000

श्री सभापतिः प्लीज, विराजिए।

श्री गुरवीर सिंह (सादुलशहर): 000

श्री सभापतिः आप विराजिए। माननीय सदस्य, विराजिए। श्री प्रतापपुरी। अंकित नहीं होगा। सहयोग कीजिए, माननीय सदस्य।

श्री गुरवीर सिंह (सादुलशहर): 000

श्री प्रताप पुरी (पोकरण): धन्यवाद, सभापति महोदय। आपने मुझे बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर बोलने का मौका दिया, इसके लिए हृदय से साधुवाद व धन्यवाद। निश्चय ही दोनों ही विषय, चूंकि मुझे कल भी बोलना था, परंतु कल मौका नहीं मिला, आज दिया। दोनों ही

बहुत महत्वपूर्ण विषय हैं जल और विद्युत। दोनों हमारे जीवन की रेखा हैं। दोनों ही महत्वपूर्ण विषय हैं। जल के लिए तो आप सबने कहा है जल जीवन है, जल है तो कल है। परंतु आंखों के जल की बूंद और बरसात के जल की बूंद, दोनों की बहुत महत्वपूर्ण है और दोनों के लिए हमें सोचना पड़ेगा कि पानी के कारण किसी की आंखों में पानी नहीं आए और बरसात की बूंद एक भी न व्यर्थ जाए। इसके लिए सरकार अपनी अच्छी योजना बनाए। वर्षा का पानी बहकर नहीं जाए वही हमारे जीवन का आधार बनेगा। वही है जो कल है।

गांव का पानी गांव में और शहर का पानी शहर में। इसके लिए मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि हमारे पारम्परिक जल स्रोत हैं, उनके लिए योजना बनाकर संरक्षित किया जाए और उनको सुरक्षित किया जाए। चूंकि शहरों की तुलना में गांवों को पानी अधिक चाहिए, क्योंकि वहां पशुपालन भी है। गांवों के लिए विशेष रूप से योजना बनाकर पारम्परिक जल स्त्रोतों का पुनः सृजन किया जाए। मेरे क्षेत्र में, माननीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से सबको विदित कराना चाहता हूं कि पारम्पिक स्रोत के लिए, कुएं, तालाब, बावड़ी आदि, सभी सदस्यों ने विषय रखा। मैं भी कहूंगा कि मेरे क्षेत्र में सबसे ऐतिहासिक एक तालाब है जो भणियाणा गांव में है, जो 60 गांवों की पानी की पूर्ति करता था। परंतु दुर्भाग्य यह है कि उसका रख-रखाव अभी नहीं हो रहा है। बबूलों ने चारों तरफ से घेर लिया है और अतिक्रमण भी हुए हैं। जहां-जहां ऐसे अतिक्रमण हैं, तालाब, नाड़ी आदि पर और जो हमारे पारम्परिक जल स्रोत हैं, उनमें बबूल आदि उग गये हैं तो सरकार ग्राम पंचायत को अनिवार्य नरेगा में लेकर इसकी सफाई जरूर करवाये। इसलिए भणियाणा तालाब जीवन का आधार रहा है। 60 गांवों को जल की आपूर्ति अकाल में भी करता था, उसको विशेष पैकेज देकर, आपके माध्यम से मंत्री जी को कहूंगा कि भणियाणा को एक बहुत बड़ी सौगात देने की कृपा करें।

भणियाणा और फलसूंड में जेइएन कार्यालय भी नहीं है। मेरा विधान सभा क्षेत्र 300 किलोमीटर लम्बा है। इसको कवर करने के लिए इनकी नियुक्ति भी अवश्य करें। आपने हैंडपम्पों की सौगात दी है, लेकिन मैं मानता हूं कि बहुत कम पड़ती है। 300 किलोमीटर में वह 10 ट्यूबवेल और 20 हैंडपम्प किसको देकर राज़ी करेंगे। यह मेरी ही नहीं सभी सदस्यों की मांग है कि इसको दुगुना किया जाए। एक विशेष मांग उठी थी कि सोलर युक्त हैंडपम्प भी हम सबको स्वीकृत किये जाए। धार्मिक स्थान, स्कूल, अस्पताल में विशेष प्राथमिकता के साथ हमको आप सौगात देंगे तो अच्छा रहेगा।

सभापति महोदय, मेरे क्षेत्र में नहर भी लगती है और नहरी क्षेत्र में 62 हजार 650 हैक्टेयर कुल भूमि जम्बेश्वर केनाल कमांड क्षेत्र पानी के लिए 310 क्यूसेक पानी हमको स्वीकृत किया था। परंतु दुर्भाग्य है कि हमें केवल मात्र 176 क्यूसेक पानी ही मिल पा रहा है। मैं आपके माध्यम से निवेदन करूंगा कि इस 62 हजार 650 हैक्टेयर में 310 क्यूसेक पानी हमारे को दिया जाए और सिंचित किया जाए। इंदिरा गांधी परियोजना के तहत जो किसानों को मुरब्बे आवंटित किये जाते थे, वह 2017 से रुके पड़े हैं। उनको भी स्वीकृत किया

जाए। अधिशासी अभियंता जो फलौदी में बैठता है, उसको पोकरण में बैठाया जावे। मेरी विधान सभा में रामदेवरा और पोकरण, दोनों ऐतिहासिक और धार्मिक नगरी है। इनके लिए लाइट और पानी की विशेष व्यवस्था की जाए। पोकरण में पूरे देश के और दुनिया के दर्शनार्थी आते हैं, इनको लाभान्वित करने के लिए विशेष पैकेज दिया जाए।

लाइट के लिए भी मैं आपसे एक मिनट में मेरी बात पूरी करूंगा। दिये तले अँधेरा देखना है तो जैसलमेर और पोकरण को देखें। सबसे ज्यादा सोलर एवं पवन ऊर्जा के माध्यम से पूरे प्रदेश और देश को विद्युत कोई दे रहा है तो पोकरण और जैसलमेर दे रहा है। वहां पर ही हम लाइट के लिए त्रस्त हैं। वहां की जितनी कंपनियां हैं, उनमें स्थानीय कार्यकर्ताओं को, स्थानीय नागरिकों को प्राथमिकता से रोजगार दिया जाए। वहां का जो सीएसआर है, वह स्थानीय विकास के लिए खर्च किया जाए। पोकरण में 3700 कनेक्शन 2018 के बाकी पड़े हैं। उन कृषि कनेक्शनों के डिमांड भी जमा हो गये हैं, परंतु वे बाकी हैं। ऐसे मेरा पूरा क्षेत्र वंचित पडा है, कनेक्शन के लिए भी और कृषि कनेक्शन के लिए भी। सरकार इसको प्राथमिकता से ले, क्योंकि जब उनसे डिमांड नोटिस भरवा दिया है। 2018 में भरे गये हैं, 2024 आ गया है। किसान के पैसे हमारे खाते में आ गये, लेकिन किसान के घर अभी तक लाइट नहीं गयी है। इस व्यवस्था को सुचारु किया जाए। पोकरण नगर पालिका 132 है, चूंकि पोकरण और रामदेवरा दोनों पास में हैं, धार्मिक होने के कारण उसको भी विशेष प्राथमिकता देते हुए बढ़ाया जाए।

Ans/rtm 15.20 2l 02.08.2024

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से एक निवेदन करूंगा भणियाणा, फलसूंड और सांकड़ा अधिशासी अभियंता के कार्यालय की स्वीकृति जरूर प्रदान करे।

श्री सभापति: श्री भगवाना राम सैनी।

श्री प्रताप पुरी (पोकरण): मैं आपका भी धन्यवाद करता हूं और मंत्री जी से आपके माध्यम से निवेदन करूंगा कि हमारी सबसे बड़ी समस्या है, देचू में 220 केवी का है उसको 400 केवी का करके, स्पेशल यहां की योजना दी जाए।

श्री सभापति: विराजिए।

श्री प्रताप पुरी (पोकरण): आपने मुझे समय दिया, धन्यवाद। मैं मानता हूं आपके माध्यम से मेरी बात को मंत्री जी गंभीरता से सुनेंगे। मेरे क्षेत्र की समस्याओं का समाधान, प्रदेश की समस्याओं का समाधान करेंगे। बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री भगवाना राम सैनी (उदयपुरवाटी): सभापति महोदय, आपने पानी जैसे मुद्दे पर मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए आपका धन्यवाद। मैं सीधा ही मेरे विधान सभा क्षेत्र उदयपुरवाटी पर आता हूं। उदयपुरवाटी विधान सभा में 41 पंचायतें, 03 नगरपालिकाएँ हैं और केवल 148 टयूबवैल हैं। वहां इतनी गंभीर समस्या है। पहाड़ी बेल्ट होने के कारण से पानी भी बहुत गहरा चला गया। जो टयूबवैल लगाए जाते हैं, हर 6 महीने बाद पानी कम पड़ जाता

है। इतनी गंभीर समस्या के लिए आपने 10 ट्यूबवैल और 20 हैण्डपम्प दिए, यह बहुत कम मात्रा में हैं। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से एक निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे पानी गहरा जाने के कारण वहां हैण्डपम्प सक्सेज नहीं है। मैं आपके माध्यम से निवेदन करूंगा कि हमें उनके बदले ट्यूबवैल दिए जाएं तो अच्छा रहेगा।

उदयपुरवाटी नगरपालिका बड़ा कस्बा है, 60-60 हजार की आबादी का कस्बा है, उसमें 15-15 दिन तक पानी नहीं आता। बड़े-बड़े गांव हैं, बड़ी ढाणियां हैं, 500-500,1000-1000 की बस्ती है। छापोरी मण्डावरा हमारे पापड़ा पचरंगी जोधपुरा जैसे गांव, बड़ी ढाणियों में पानी का कोई विशेष प्लान नहीं है।

मेरा 6-7 महीने का जो मेरा अनुभव रहा, गाँवों में पीएचडी के ट्यूबवैल है वहां कैबल, मोटर और पाइप की बहुत कमी रही है। लगभग-लगभग पानी मिला ही नहीं। मैं यह भी कहना चाहता हू कि पांच साल पहले पानी 500-700 फीट के ऊपर था, वह पानी अब 1000-1100 के लेवल पर चला गया। मोटर नीचे जाने से कैबल बार-बार फॉल्ट होती है। मोटर जल जाती है। आपके पीएचडी डिपार्टमेंट मोटर बांध कर डालते हैं और दूसरे दिन जल जाती है। यह गंभीर समस्या है। बार-बार मोटर चेंज नहीं कर सकते, ना रिपेयरिंग की जा सकती है।

इसके साथ ही एक बहुत बड़ी समस्या आई टीएसएस की। गाँवों में पंचायतों द्वारा ट्यूबवैल बनाए गए हैं, उन ट्यूबवैल में सरपंच लोग पल्ला झाड़ लेते हैं। पक्षपाती नीति के कारण उनको करते नहीं हैं। पक्ष-विपक्ष के सभी माननीय सदस्यों के यहां विचार आए कि बिल नहीं भरे जा रहे। यह सच्चाई है कि उनका बिल बाकी है। सरकार सुनिश्चित करे कि उनका बिल कौन भरेगा। गर्मियों में सावरगी और मण्डावरा ऐसे गांव हैं जहां पानी का ट्यूबवैल नहीं था और टीएसएस के पानी से काम चला रहे थे। उनका कनेक्शन कटने से बहुत गंभीर समस्या हो गई। मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि उन ट्यूबवैल की रिपेयरिंग, रख-रखाव, बिल चुकाने के लिए सरकार यह निश्चित करे कि पंचायत लेवल पर हो या पीएचडी लेवल पर हो, उसी से काम चलेगा, सरपंचों पर छोड़ दिया तो यह गंभीर समस्या है।

ट्यूबवैल गहरे कराने की सरकार की योजना है, मैं इसका स्वागत करता हूं। कुछ को गहरा कराने से उनमें पानी आ जाएगा। इसके अलावा नहीं हो तो उसके पास ही ट्यूबवैल बन जाता है, तो कनेक्शन उसमें काम आ जाएगा। मैं आपके माध्यम से कह रहा हूं, इसकी लिस्ट मंत्री महोदय के पास पहुंचा देंगे।

मैं निवेदन करूंगा कि टीएसएस के ट्यूबवैल भी हैं, उनमें भी कनेक्शन हैं, उनमें भी सारी चीज़ें हैं, तो क्यों ना उनको भी गहरा कराने के लिए सरकार सोचे। पानी की व्यवस्था सरकार को करनी है। मेरे विधान सभा क्षेत्र में दिनों दिन पानी गहरा जा रहा है। जब तक बाहर का पानी नहीं आएगा, तब तक वहां स्थाई समाधान नहीं हो सकता। मेरा सरकार से निवेदन है कि वह सोचे। कुम्भाराम लिफ्ट योजना में पिछली सरकार ने प्लान बनाया था, सारे टीएसएफएस वगैरह हो गए, टेंडर भी हो गया लेकिन वर्क आर्डर जारी नहीं किए, तो जल्दी से

जल्दी वर्क आर्डर जारी किया जाए।

श्री सभापतिः श्री अमृतलाल मीणा।

श्री भगवाना राम सैनी (उदयपुरवाटी): दो महीने पहले हमारे भूतरबड़ी नगरपालिका से, अंडर ग्राउंड कैबल डली हुई है, तीन दिन तक फॉल्ट नहीं निकला, 15 गांव जुड़े हुए हैं।

श्री सभापतिः विराजिए। श्री अमृतलाल मीणा।

श्री भगवाना राम सैनी (उदयपुरवाटी): तीन दिन तक 15 गांवों में पानी की एक बूंद नहीं आई।

श्री सभापतिः विराजिए।

श्री भगवाना राम सैनी (उदयपुरवाटी): बिजली की व्यवस्था करे।

श्री अमृतलाल मीणा (सलूम्बर): सभापति महोदय, आपके माध्यम से सदन को बताना चाहूंगा, दो दिन से पेयजल पर चर्चा कर रहे हैं, यह समस्या क्यों आई, पिछली सरकार की गलत नीतियों की वजह से हुई।

सभापति महोदय, आपने भी बावड़ियों का पानी पीया होगा। अपने बाप-दादाओं ने भी पीया। पिछले 10-15 साल से पानी की जो समस्या आ रही है, आने वाले समय के लिए बहुत गंभीर होगी। सभी दलों को मिलकर, इसका समाधान करने की जरूरत है। हमने उधर आरोप लगा दिया, उन्होंने इधर लगा दिया, इससे पानी की समस्या का समाधान नहीं होगा। ओनली मेवाड़ को छोड़कर, राजस्थान के दक्षिण एरिया को छोड़कर पानी की बहुत गंभीर समस्या है, ऐसा नहीं है कहीं आने वाले समय में आप उधर आ जाओ, गांव के गांव पानी से छोड़ दें। बहुत गंभीर समस्या है इसलिए इस पर मन्थन करने की जरूरत है। पहला मौका है जब दो दिन से पानी पर चर्चा हो रही है।

माननीय सभापति महोदय, मैं जलदाय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि वर्तमान में पूरे प्रदेश में जल जीवन मिशन के अरबों रूपये के कार्य चल रहे हैं, जिसमें विभागीय अधिकारी तकनीकी जांच के बाद भी, प्राइवेट वर्कशॉप कम्पनी प्रत्येक बिल पर, जांच की नाम पर 1 लाख 32 हजार भुगतान उठा रही है, यह गंभीर विषय है। पहले से चल रहा है, इनके कार्यकाल की बात नहीं है। जब से जल जीवन मिशन शुरू हुआ तब से। बेरोजगार तकनीकी कर्मी, कम्पनी में जॉब करते हैं, साइड में ठेकेदार को डरा-धमका कर मुंह मांगा पैसा अलग से वसूल कर रहे है। स्वयं अधिकारी भाषा बोल रहे हैं, कौन बोल रहे हैं, वह जेईएन, एईएन, जिससे कार्य प्रगति में कम हो गया। ठेकेदार का कार्य नहीं कर पा रहे। अरबों रूपये के कार्य, उक्त कम्पनी करोड़ों रूपये फालतू का कमा लेती है। (समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

बस हो गया क्या, साहब? दो मिनट कहने दो।

मेरा निवेदन है कि तकनीकी अधिकारियों की टीम बनाकर करें। मेरा मंत्री जी से भी निवेदन है 5-7 साल से प्रयासरत हूं। 5 करोड़ की स्कीम थी, 16 करोड़ तक की स्कीम चली गई सलूम्बर में, अभी तक काम नहीं हुआ। जल जीवन मिशन में बड़े कार्य हैं, जिसमें 2-3 उच्च जलाशय, टंकी का कार्य पूर्ण करने का।

माननीय सभापति महोदय, आपने इस सदन में राय दी, कालीचरण सराफ जी ने भी दी, कृपलानी जी ने भी दी, अजय सिंह जी ने, उधर से भी वरिष्ठ सदस्यों ने दी, जिसे अमल में लाना बहुत जरूरी है। आने वाला समय बहुत गंभीर है। जल जीवन मिशन में पूर्व में ऐसे कार्य समयावधि प्रकरण की स्वीकृति नहीं होने से आज तक लम्बित हैं, ऐसे कार्यों पर भी सम्बन्धित खण्ड अभियंता, दस प्रतिशत पेनल्टी लगाते हुए फाइनल कर देना चाहिए। विभाग के टाइम एक्सटेंशन प्रोविजनल कौन जारी कर सकता है। जल जीवन मिशन के कुछ कार्य ऐसे भी है जो ठेकेदार ने ले लिए लेकिन 3-3 साल गुजर जाने के बाद भी कार्य बंद पड़े हैं। ऐसा हमारे वहां का एक ठेकेदार है1 माननीय मंत्री जी आए, निर्देश दिया। एक मार्च की बात है। उसको ब्लैक लिस्टेड कर दीजिए। इधर पाइप डाला, उधर पाइप डाला और बीच में पाइप नहीं डाला और बजट उठा लिया।

VPS-RTM-02.08.202-15.30-2m

इस प्रकार से पानी के ऊपर बहुत गहराई से दो दिन से चर्चा हो रही है तो मेरा यह कहना है कि मेरे सेमारी में एक ए.ईएन. ऑफिस पी.एच.ई.डी. की हो और सराड़ा खण्ड बनाकर एक्स.ईएन. ऑफिस खोला जाये।

श्री सभापति: श्री मांगेलाल मीना।

श्री अमृतलाल मीणा (सलूम्बर): सराड़ा, बड़गांव को जयसमन्द के पानी से जोड़ा जाये। धन्यवाद। ...(व्यवधान)...

श्री मांगेलाल मीना (राजगढ़-लक्ष्मणगढ़): माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का अवसर प्रदान किया, इसके लिए आपका आभार और आपको धन्यवाद। हम दो दिन से पानी की चर्चा कर रहे हैं। पानी की विकट समस्या है और अपन सब इसके लिए जिम्मेदार हैं कि पर्यावरण को अपन ने नष्ट किया। अवैध खनन किये और पेड़ों की अंधाधुंध कटाई, ये प्रमुख कारण हैं। इनकी तरफ सभी माननीय सदस्यों ने ध्यान आकर्षित किया। उनका भी मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। इस बिन्दु पर अपने को ध्यान देने की आवश्यकता है।

माननीय सभापति महोदय, अलवर जिला राजस्थान का सबसे ज्यादा बड़ा जिला है और ड्राई जोन है। यहां पर पानी की इतनी किल्लत है कि हमारे राजगढ़-लक्ष्मणगढ़ के जो लोग हैं, वे सुबह चार बजे जगते हैं और अपना टिफिन तैयार करने के लिए, रोजी-रोटी के लिए या तो वे जयपुर आते हैं या वे अलवर की सुध लेते हैं और रात को दस बजे वापस आते हैं। वहां पर पानी न सिंचाई के लिए उपलब्ध है और न ही पेयजल के लिए उपलब्ध है। अपन ई.आर.सी.पी. की बात कर रहे हैं बड़े लम्बे समय से। वर्ष 2005 से सुनते आये हैं, यह जनता के साथ छलावा है। राजनीतिक कारणों से इसमें इस बिन्दु पर ज्यादा गहनता से विचार नहीं किया गया किसी के द्वारा भी। इसमें मेरा यह निवेदन है कि यह जनता के साथ छलावा है, केवल अभी तक सपने दिखाने का ही काम किया है। पूर्ववर्ती गहलोत सरकार के द्वारा नवनेरा बांध और ईसरदा बांध परियोजना की एक पहल उन्होंने हाथ में ली थी, इसके

लिए इस मौके पर मैं उनको धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि जो हमारे दौसा जिले तक, राजगढ़ के समीप तक ईसरदा बांध परियोजना से पानी जाने का, पेयजल उपलब्ध करवाने के लिए वहां पर पानी जा रहा है।

आप सब लोगों से गहलोत साहब भागीरथ की भूमिका तो अदा करके चले गये। मैं अब राज्य सरकार से, वर्तमान सरकार से यह आग्रह करता हूं कि इस बहती गंगा में हाथ धोने का काम आप भी कर लें, जिससे पूर्वी राजस्थान की जनता का जीवन का उत्थान हो जायेगा और पूर्वी राजस्थान नहर योजना है, यह पूर्वी राजस्थान की एक जीवन रेखा के नाम से जानी जायेगी तो इसमें आपकी महत्वपूर्ण भूमिका की जरूरत है। आप डबल इंजन की सरकार की बात करते हैं तो मैं आपसे यह निवेदन करना चाहूंगा कि न तो केन्द्र सरकार ने ई.आर.सी.पी. के लिए कोई पैसा दिया और न ही राज्य सरकार ने बजट में कोई पैसा दिया है। यह जनता के साथ में एक तरह से धोखा है। इससे यह साफ जाहिर होता है कि राज्य सरकार की दृढ़ इच्छा शक्ति नहीं है इस योजना को क्रियान्वित करने के लिए, इससे यह साफ जाहिर हो जाता है।

ई.आर.सी.पी. के बिन्दु पर मेरा यह निवेदन है कि मैं इस पर कुछ सुझाव देना चाहूंगा। इसमें डी.पी.आर. में सारे रियासतकालीन राजगढ़-लक्ष्मणगढ़ के अन्य जिलों के बांधों को भी जोड़ा जाये जिससे कि जल स्तर भूमि का ऊपर आयेगा, जिससे हमारे सिंचाई और पेयजल की अपने आप ही 80 परसेंट समस्या का समाधान हो जायेगा। इर्रिगेशन डिपार्टमेंट के जितने भी बांध हैं, मैक्सिमम पंचायती राज विभाग के हवाले कर दिये हैं तो क्या पंचायती राज विभाग में तकनीकी अधिकारी हैं? किसी भी सरकार ने इस ओर ध्यान नहीं दिया है तो सरकार को इस ओर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। जल की बात करते हैं लेकिन जल को इकट्ठा करने के लिए, डैमों की स्थिति के बारे में बात नहीं करते हैं। मैन पावर की कमी होने की वजह से बांधों के भराव क्षेत्र में कॉलोनियां कट रही हैं, नहरों में एनक्रोचमेंट हो रहे हैं। इसके लिए मैं आपसे यह निवेदन करना चाहूंगा लक्ष्मणगढ़ में एक रूपारेल नदी है, वहां पर pick up weir बना हुआ है तो उसकी हाइट बढ़ाने की जरूरत है, भौगोलिक परिस्थितियों के कारण जो फीडर कैनाल वहां से जा रही थी, जिसकी सिल्टिंग होने से हाइट वगैरह बढ़ गयी है, जमीन का स्तर बढ़ गया है तो जो बांधों में पानी आता था गौर फावड़ी, मौजपुर, लक्ष्मणगढ़, कनवाड़ा, इनसे क्या है कि लक्ष्मणगढ़ की 60 परसेंट जनता आबाद हो जाती थी और पानी की समस्या हल हो जाती थी, यहां पर भी पानी लाने के लिए काम करें, इसके लिए मेरा निवेदन है।

ई.आर.सी.पी. एक लॉन्ग-टर्म योजना है। शॉर्ट-टर्म के लिए उस पहलू पर आना पड़ेगा अपने को, माननीय सभापति महोदय, मैं थोड़ा टाइम चाहूंगा। अपने को उस पहलू पर आना पड़ेगा। ईसरदा बांध परियोजना के सेकण्ड फेज में जिला जयपुर और अलवर को जोड़ा गया था जिसमें ईसरदा बांध का पानी बसवा तक चला गया। तीन किलोमीटर ही राजगढ़ नगरीय क्षेत्र है, वहां आज जो पानी आ रहा है, जो टैंकरों के द्वारा सप्लाई हो रहा है, वह न के बराबर

ही है, उससे आपूर्ति नहीं हो पाती है। इस योजना को करें। ई.आर.सी.पी. कब आयेगी तो इसको ईसरदा बांध परियोजना से आगे बढ़ाया जाये।

श्री सभापतिः श्री हमीर सिंह भायल। आप विराजिये। माननीय सदस्य, सहयोग कीजिए।

श्री मांगेलाल मीना (राजगढ़-लक्ष्मणगढ़): बजट घोषणा वर्ष 2021-22 के बिन्दु संख्या 178 में अलवर जिले की सात पंचायत समिति एवं राजगढ़, खेड़ली, थानागाजी, रैणी को पानी उपलब्ध करवाने के लिए इस योजना को हाथ में लिया गया था। इसके लिए जमीन भी आवंटित कर दी, पम्प हाउस निर्माण के लिए जमीन भी आवंटित हो गयी है तो मेरा सरकार से यह निवेदन है कि इस बिन्दु की तरफ भी ध्यान दिया जाये।

माननीय सभापति महोदय, आपने समय दिया, इसके लिए आपको धन्यवाद।

श्री हमीर सिंह भायल (सिवाना): माननीय सभापति महोदय, पेयजल पर चर्चा के लिए मुझे बोलने का अवसर दिया, इसके लिए आपको धन्यवाद। मैं मेरे क्षेत्र की पेयजल की तीन स्कीम्स से उम्मेदसागर, पोकरण फलसूंड और नर्मदा प्रोजेक्ट से, यह तीन स्कीम्स जरूर लागू हैं, पर एक प्रोजेक्ट का पानी जरूर आया है, पर तीनों ही स्कीम्स के अंतिम छोर पर मेरा सिवाना विधान सभा क्षेत्र है। इसी वजह से 2004 से लगातार नर्मदा प्रोजेक्ट का पानी सिणधरी क्षेत्र में जो 20-25 गांव है, 20 वर्षों से शून्य है, नर्मदा प्रोजेक्ट में जायका से आज दिन तक कोई कार्य नहीं हुआ है। इसको सिणधरी क्षेत्र को जोड़ने के लिए कैनाल, बाड़मेर लिफ्ट कैनाल सिर्फ साढ़े तीन किलोमीटर है, माननीय सभापति महोदय, मैं मंत्रीजी से यह कहना चाहूंगा कि चार किलोमीटर से उसको जोड़ा जा सकता है तो राहत मिल सकती है।

पोकरण-फलसूंड-बायतू-बालोतरा-सिवाना योजना, यह 2004 से लगाकर आज दिन तक, 2013 से 18 तक जो पाइप लाइन डली थी और एस.आर.एल. जो बनी थीं 2018 से 2023 तक उनमें एक फीट पाइप भी नहीं लगा। प्रतिपक्ष के माननीय नेता विराजे हुए हैं, मैं इसी जगह पर बैठकर इस पेयजल के लिए हर बार बोलता था परंतु उस पर ध्यान नहीं दिया गया और जल जीवन मिशन में क्या हुआ और कैसे हुआ, मैं उस पर नहीं जाऊंगा जो काला कारनामा किया है, उनको सबक भी मिलेगा। मैं यही निवेदन करूंगा कि यह एस.आर.एल. बनी हुई जो सूख रही हैं, पोकरण-फलसूंड का पानी सिवाना को और सिवाना के 99 गांवों को और समदड़ी तक कैसे पहुंचे, उम्मेदसागर का वहां पर पानी जरूर आ रहा है पर पानी के आवंटन की, लूणी से लगाकर कुछ जोधपुर फिर बालोतरा है तो यहां पर भी पूरा पर्याप्त पानी नहीं आने की वजह से देवड़ा, अरतंडी, फूलन कई गांव ऐसे हैं अंतिम छोर के, उनके यहां तक वह पानी नहीं पहुंच पा रहा है।

माननीय सभापति महोदय, मैं यह निवेदन करूंगा मंत्रीजी को कि सिवाना विधान सभा क्षेत्र के लिए एक नई डी.पी.आर. बनाकर पोकरण-फलसूंड से अलग अगर पाइप लाइन नहीं आयेगी तब तक यह सिवाना अंतिम छोर पर है, कभी भी इसको पानी नहीं मिल सकता है।

एक अभी जो फिलहाल कालोड़ी और मूटली के पास में उम्मेदसागर धवला हैड पाइंट बन जाये तो स्टॉक पानी हो जाये तो थोड़ा आगे सप्लाई के लिए राहत मिलेगी। अभी पोकरण से

आने वाले माननीय सदस्य इस बात को फरमा रहे थे कि वहां पर भू-भाग को देखते हुए इतना लम्बा एरिया है कि आप वहां पर दस हैंडपम्प दे रहे हो वह ऊँट के मुंह में जीरा के समान है तो आप सोलर हैंडपम्प भी दें और इस भूभाग को देखते हुए इस एरिया में आप हैंडपम्प या ट्यूबवैल और देंगे तो कुछ अच्छा होगा और वह भी अभी माननीय सदस्य यह फरमा रहे थे कि वास्तव में जो ट्यूबवैल खुदता है तो वह दो-तीन महीने के बाद में सूख जाता है, वहां पर पानी है ही नहीं। बारिश नहीं होगी तो पुराने जो तालाब है, एनिकट है, उनको भरने के लिए पानी भराव की कोई योजना नहीं होगी, नर्मदा का पानी जालोर जिले से दो-तीन किलोमीटर की दूरी पर है तो 10-20 पंचायतों को अपन पानी दे सकते हैं। अपन दो किलीमीटर के एरिये से देना चाहें तो वह पानी दे सकते हैं। इसके लिए एक तो मैं यह निवेदन करूंगा कि जैसे पूर्वी राजस्थान के लिए ई.आर.सी.पी. जो योजना बनी है, उसी तरह पश्चिमी रेगिस्तान के लिए भी डब्ल्यू.आर.सी.पी. योजना बनाकर बाड़मेर, बालोतरा, जैसलमेर, जोधपुर, नागौर सहित पूरे थार को अगर पानी अपन देंगे तो पीने के लिए पर्याप्त पानी मिल सकता है। वहां पर कम पानी है, मंत्रीजी, जहां पर पेयजल की स्कीम है वहां मैं आपको निवेदन करूंगा।

SSY/RTM/02.08.2024/15:40/2n

श्री सभापतिः श्री रफीक खान।

श्री हमीर सिंह भायल (सिवाना): वहां 15 या 20 का पंप लगा हुआ है। पानी नहीं होने की वजह से सिंगल फेज अगर चलायें, एक मिनट में पूरा कर रहा हूं, मेरे भाई साहब। ये सारी समस्याएं हैं। व्यक्तिगत भी अर्ज करूंगा। पानी को लेकर कहना चाहूंगा,

पानी-पानी सब करें सूखी नदियां, ताल,
मरती चिड़िया कर गई मुझसे कई सवाल,
मटका सिर पर लादकर कर पानी की आस,
चार कोस पैदल चलें पानी करें तलाश।

जय हिन्द, जय भारत।

श्री रफीक खान (आदर्श नगर): सभापति महोदय, आपने मुझे पानी की चर्चा पर बोलने का मौका दिया, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं। धन्यवाद देता हूं।

अपन सारे दिन से पानी की बात कर रहे हैं और पानी के साथ न्याय नहीं कर रहे हो।

गुनाह करके कहां जाओगे गालिब,
यह जमी भी उसकी, यह आसमां भी उसका।

जो जहां हो सब उसी का है। गुनाह माफ नहीं होंगे। ऐसी सब बातें करने से पानी की समस्या खत्म नहीं होगी।

मैं यह रिकवेस्ट करना चाहता हूं, आपको भी एक और शेर सुना दूंगा, चिंता मत करो। एक मिनट।

सभापति महोदय, मेरी विधान सभा के अन्दर, आदर्श नगर विधान सभा के अन्दर जवाहर नगर कच्ची बस्ती है, आगरा रोड और पूरा शहर, एक लाख लोगों को पानी नहीं मिलता था, जब तक राजस्थान के अन्दर इनकी सरकार थी। 2018 में हमारी सरकार बनी और आदर्श नगर विधान सभा, एक विधान सभा के अन्दर एक लाख लोगों को पानी नहीं था, मालवीय नगर से आने वाले माननीय सदस्य आप वाकिफ हो, पूरी जवाहर नगर कच्ची बस्ती में पानी नहीं था। आगरा रोड के ऊपर बसी हुई पूरी जामडोली, विजयपुरा, सुमेल किसी जगह पानी नहीं था। हमने 5 साल में सब जगह पानी के कनेक्शन दे दिये। बीसलपुर योजना से टेंडर इनवाइट किये और सब जगह कनेक्शन दे दिये, सारी जगह। लेकिन पानी तो दे दो। पानी क्यों रोक रहे हो? कहीं बैंड लगे हुए हैं। कहीं पानी की सप्लाई नहीं है। कहीं लाइनें दुरुस्त नहीं हैं।

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय कार्य मंत्री): आपके शब्दों का अर्थ दूसरा निकलता है कि पानी नहीं हैं। कहते हैं, भला आदमी इंको पाणी मर गियो।

श्री रफीक खान (आदर्श नगर): दे नहीं रहे हो। पानी दे नहीं रहे हो। लाइनें तो हमने दे दी। लेकिन पानी तो दे दो सरकार-ए-आला, हुजूर-ए-आला। पानी तो दो।

श्री सभापति: आपस में वार्ता नहीं। आप उन्हें इनवाइट मत करिये।

श्री रफीक खान (आदर्श नगर): पानी की व्यवस्था तो करो।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, आप उनको इनवाइट मत करिये। आसन की तरफ देखें।

श्री रफीक खान (आदर्श नगर): वे बीच में बोल रहे हैं।

श्री सभापति: आप मत इनवाइट करिये उनको।

श्री रफीक खान (आदर्श नगर): मैं आपको यह कहना चाहता हूं कि पानी की समस्या ऐसी है, यह केवल आगरा रोड पर ही नहीं, जवाहर नगर कच्ची बस्ती में नहीं, यह पूरे जयपुर शहर के अन्दर है।

मंत्री महोदय, मैं आपसे गुजारिश करना चाहता हूं कि जो योजनाएं हमने पिछले 5 सालों में कंपलीट कर दी, जिनके अन्दर हमने पानी के कनेक्शन दे दिये, जो कुछ कनेक्शन रह गये वह कनेक्शन दो और जितना एमएलडी पानी हमें वहां के लिए चाहिए, उतना पानी वहां अवश्य दो। क्योंकि लोग-बाग़ त्राहि-त्राहि कर रहे हैं। बिजली भी नहीं है। पानी भी नहीं है तो आदमी बहुत परेशान है।

आपसे गुजारिश करता हूं कि इस पर संज्ञान लो और यह चैक कराओ, आगरा रोड पर जामडोली, सुमेल, विजयपुरा, बगराना यहां हमने पानी की लाइनें दी, कनेक्शन दिये। खासतौर से जवाहर नगर कच्ची बस्ती में हमने लाइनें डाल दीं। अब वहां स्थिति यह है कि एक कनेक्शन है और 10 अवैध कनेक्शन हैं। पानी सड़कों पर बहता है। अधिकारी उसमें जागरूक नहीं हैं। आप उन सबसे बोलो।

एक तरफ तो आप पानी दे नहीं पा रहे हो और एक तरफ जहां पानी दे रहे हो, वहां इतना एक्सेस में पानी है कि वह सड़कों पर बिखरा रहता है। नलों पर वहां किसी तरह के

कोई मीटर नहीं लगे हुए हैं, तो अनमीटर्ड कनेक्शंस हैं, उन पर मीटर लगाओ ताकि पाबंदी लगे और मिस्यूज बंद हो।

दूसरा, मैं यह कहना चाहता हूं कि कुछ एरियाज में टेंडर होने थे और लास्ट में आकर के वे टेंडर किन्हीं कारणों से निरस्त हो गये। जिसमें बगराना एक एरिया है, जिसके अन्दर खो-नागोरियान, आपके बगरू से आने वाले सदस्य के क्षेत्र का हिस्सा भी है, तो वे टेंडर आप दुबारा से स्पीड के साथ कराओ, ताकि वहां लोगों को पानी मिल सके और आम आदमी को इससे राहत मिल सके।

हम पिछले समय क्या करते थे कि गर्मी शुरू होने से पहले कंटीजेंसी प्लान बनाते थे। आपने कोई प्लान नहीं बनाया। किसी तरह की कोई राहत का काम चालू नहीं किया। एक कंटीजेंसी प्लान बनाओ ताकि जिन एरियाज में पानी की सप्लाई आप नहीं दे पा रहे हो, जहां दे पा रहे हो वहां सप्लाई बढ़ाओ। सप्लाई नहीं दे पा रहे हो तो एक प्लान बनाओ और उसके ऊपर काम करना शुरू करो।

लक्ष्मण डूंगरी का एक प्रोजेक्ट है। ऑलमोस्ट कंपलीट है। मेरे को समझ में नहीं आ रहा कि क्यों नहीं चालू कर रहे हैं? पुरानी लक्ष्मण डूंगरी, जहां अंग्रेजों के जमाने में रामगढ़ से पानी लक्ष्मण डूंगरी आता था और वहां से पूरे जयपुर को सप्लाई होता था। हमने हमारे पिछले टेन्योर के अन्दर उसमें लाइन दे दी और पानी का पूरा सिस्टम उसमें डाल दिया। अगर हम उसको चालू करते हैं तो मैं ऐसा समझता हूं कि पूरे जयपुर शहर की समस्या खत्म हो जायेगी। वह अभी आंशिक रूप से ट्रायल पर चल रहा है तो आपसे गुजारिश है कि उसको चालू करायें।

सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद।

श्री सभापतिः श्री अरुण चौधरी।

श्री अरूण चौधरी (पचपदरा): माननीय सभापति महोदय, सबसे पहले तो मैं आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे जल की इस चर्चा में भाग लेने का मौका दिया।

माननीय सभापति महोदय, मैं, हमारे देश के प्रधान मंत्री और उनकी पूरी कैबिनेट को बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने आम जीवन के उपयोग में आने वाली चीज जल को हर घर में पहुंचाने के लिए जो हर घर जल योजना लागू की। उसके लिए उनका बहुत-बहुत धन्यवाद।

साथ ही मैं, हमारे राजस्थान के मुख्य मंत्री महोदय परम आदरणीय भजन लाल जी शर्मा साहब को भी बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने ईस्टर्न राजस्थान के लिए ईआरसीपी जैसी योजना लागू की। मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले समय में ईस्टर्न राजस्थान का पानी के हिसाब से कायाकल्प होगा।

माननीय सभापति महोदय, मैं हमारे विपक्षी भाइयों के लिए एक ही बात कहता हूं, बड़े-बड़े असत्य वादों से राजस्थान को खूब ललचाया था, पर सच तो यह है मेरे दोस्तों कि विपक्ष के राज में गांव-गांव, ढाणी-ढाणी, शहर-शहर तरसाया था। इनके राज में जो स्थिति

बनी, मैं, मेरे विधान सभा क्षेत्र को ही लूं, क्योंकि संपूर्ण राजस्थान में स्थिति बड़ी नाजुक थी। मेरे विधान सभा क्षेत्र की लगभग 18 जो टंकियां थी, जिनमें पानी नहीं पहुंचा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद में यहां उनमें से 5-6 टंकियों में अब पानी पहुंच गया और बाकी में भी मुझे पूरा विश्वास है कि शीघ्र ही पहुंचेगा। 5 साल तक वह टंकियां बनी रही और उसके अन्दर कई गांव टापरा, जागसा, बूढीवाड़ा, चांदेसरा, खट्टू, आसेड़ा, आसोतरा, बिठूजा, कनाना, कालूड़ी, सिमालया, दूधवा, बिमरलाई, बाघूंडी और कई गांव ऐसे हैं जिनके अन्दर पानी की समस्या है। जो टंकियां नहीं बना पाये और यह बातें करते हैं कि हमने यह किया, वह किया। जैसे कि रणिया देसुपुरा, डोली खुर्द, गोदावास, बांकियावास, सामलाई कला, थूमली, चांदराई, कूडी, रोडवा, उमरलाई, मूल की ढाणी, जाणियाना ऐसे कई गांवों में टंकियों की जरूरत है। वहां टंकियां बनें। 5 साल उन्होंने कुछ भी नहीं किया।

जिस तरह की यह बातें करते हैं, कहीं यह हड़ताल और धरने देते हैं। मेरे पचपदरा के अन्दर 5 साल में एक भी पाइप से किसी गांव को जोड़ा नहीं। रही बात जेजेएम योजना की, जेजेएम योजना की आज स्थिति ऐसी है कि पाइप जगह-जगह से उखड़ रहे हैं। उन्होंने सर्वे इस तरह से कराया है कि कई ढाणियों को जो 10-10 मीटर दूर हैं, उनको छोड़ा है।

मैं चाहता हूं कि हमारी यह भजन लाल जी की सरकार, आने वाले समय के अन्दर जो भी कमियां रही हैं, उनकी पूर्ति करे। इसी तरह मेरे से पूर्व हमारे सदस्यों ने कहा है कि हैंड पंप और जो ट्युब वैल दिये हैं, ये हमको ज्यादा से ज्यादा संख्या में दें। नर्मदा नहर से हमारे बालोतरा को जोड़ा जाये। बालोतरा शहर की स्थिति बड़ी विकट है। यहां 15-15 दिन तक पानी दुर्लभ हो गया है।

मैं, माननीय मंत्री महोदय से भी निवेदन करता हूं कि मैंने बालोतरा के पास में स्टोरेज की मांग की है। उसकी भी पूर्ति की जाये। कांग्रेस के लिए मैं तो यही कहूंगा कि 5 साल में थोथा चना बाजे घणा वाली नीति को लागू किया है। पोकरण-फलसूंड-बालोतरा परियोजना हो चाहे उम्मेद सागर-धवा परियोजना हो, इन दोनों परियोजनाओं की स्थिति बिलकुल सही होगी। ऐसा मुझे विश्वास है। सुचारु रूप से पानी उपलब्ध होगा।

माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

Spp/Rtm/02.08.2024/15.50/2o

श्री सभापतिः श्री नरेन्द्र सिंह (अनुपस्थित) । माननीय मंत्रीजी।

श्री कन्हैयालाल (जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री): जय बालाजी महाराज।

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय कार्य मंत्री): बालाजी महाराज की जय। गिर्राज महाराज की भी जय।

श्री कन्हैयालाल (जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री): माननीय सभापति महोदय, पानी जैसे महत्वपूर्ण विषय पर आसन ने मुझे चर्चा करने का मौका दिया, क्योंकि डिमांड में यह विषय

नहीं लिया गया था। मैंने आसन से निवेदन किया, अध्यक्ष महोदय जी से निवेदन किया। आज जो राजस्थान की स्थिति है, इस पर चर्चा करने का मौका दिया, इसके लिये तो मैं आपको धन्यवाद देता हूं। माननीय सभापति महोदय, जिस तरह से पिछले वर्षों से अत्यधिक दोहन की वजह से पानी का जल स्तर गिरता जा रहा है। इसका कैसे संचय करें। भू संरक्षण, जल संरक्षण, ये सारी चीजें एक महत्वपूर्ण विषय था जिस पर हमारी सरकार ने एक प्राधिकरण गठन करने की सोची। यह प्राधिकरण केन्द्र में पहले से लागू है और लगभग 17 राज्यों ने इसको लागू कर दिया। सदन में चर्चा के लिये इसको लेकर आये हैं।

माननीय सदस्यों ने इसमें विषय रखा कि कृषि को भी इसमें शामिल किया गया है। इसमें हमारे जन प्रतिनिधियों को नहीं जोड़ रखा है। ऐसे कुछ विषय आये थे। मैंने सदस्यों को भी बताना चाहूंगा कि इसमें कृषि और घरेलू उपभोग को इसमें नहीं लिया गया है। साथ ही, 17 राज्यों में से लगभग केन्द्र सहित 15 राज्यों के अन्दर उसमें आई ए एस अधिकारी या उसके ऊपर का अधिकारी या कोई एक्सपर्ट हो, वही इसका चेयरमैन था केवल दो राज्यों को छोड़कर।

फिर भी माननीय सदस्यों की मंशा के अनुरूप इस विधेयक को वापस प्राधिकरण, जो बनाना चाह रहे थे, उसको हमने वापस प्रवर समिति को भेजा।

बाकी दुर्भाग्य रहा कि जब उस पर चर्चा की गयी तो हमारे लक्ष्मणगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य ने, जो कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष भी हैं, उन्होंने उस चीज का, जिस भाषा में इस्तेमाल किया। आपने सौ जूते खाना और सौ कांदे खाकर वापस लिया है। मैं आपके माध्यम से, माननीय सभापति महोदय, माननीय सदस्य को बताना चाहता हूं कि किस तरह से इन्होंने पिछले बजट के चर्चा के अन्दर जितने भी विषय आये, विशेषकर हमारे जोराराम जी के जो आया, कितनी इन्होंने घोषणाएं कीं और उनमें आधी से भी ज्यादा घोषणाएं नहीं कर पाये तो क्या मैं इनको यह संज्ञा दे सकता हूं कि सौ जूते खाकर, सौ कांदे खाकर वापस लिये, यह दे सकता हूं क्या इनको?

यह नहीं कि इसके अन्दर यह-यह चीजें नहीं हैं तो वापस प्रवर समिति को भेजकर दुबारा चर्चा की जाये। मैं सभी माननीय सदस्यों को कहना चाहता हूं कि वापस दुबारा, क्योंकि पानी जैसा महत्वपूर्ण और कोई नहीं है। पानी बगैर इंसान नहीं रह सकता। जल है तो जीवन है। बिजली को तो हम पैदा कर सकते हैं, लेकिन पानी अगर खत्म हो जायेगा तो बालाजी महाराज पर ही डिपेंड करना पड़ेगा, बालाजी महाराज ही ला सकते हैं। बाकी दुर्भाग्य रहा कि जिस तरह से बार-बार बालाजी महाराज पर इन लोगों को, मैं कहना नहीं चाहता बाकी मैं कहूंगा सिर्फ एक वर्ग विशेष को खुश करने के लिये बालाजी महाराज पर से भी विश्वास हट गया इन लोगों का। माननीय सभापति महोदय, इनका विश्वास खत्म हो गया। ऐसा नहीं होना चाहिये। ..(व्यवधान).. मैं एक-एक चीज का जवाब दूंगा। मैंने चुपचाप रहकर सब सहन किया है। ..(व्यवधान)..

श्री सभापति: प्लीज सदस्य, मंत्री महोदय बोल रहे हैं।

श्री संदीप शर्मा (कोटा दक्षिण): मंत्री महोदय जवाब दे रहे हैं और यह किस तरह का इनका व्यवहार है। यह सदन की परम्पराओं को बिलकुल भूल रहे हैं।

श्री सभापति: प्लीज सदस्य, बैठिये। ..(व्यवधान)..

श्री कन्हैयालाल (जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री): माननीय सभापति महोदय, सभी माननीय सदस्यों ने अपने अपने विचार रखे। पानी का किस तरह से सदुपयोग हो। जो भी काम चल रहे हैं, वह किस क्वालिटी के हों, काम समय पर कैसे पूरे हों और जहां-जहां जो आवश्यकता थी, नई योजनाएं लाने के लिये भी लोगों ने सुझाव दिये जिससे जनता का हित हो सके। उन सभी माननीय सदस्यों का मैं स्वागत करता हूं और धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने जो-जो मुझे सुझाव दिये, उनके ऊपर मैं मेरे विभाग के अधिकारियों से कहकर उनको हम लागू करेंगे। जो काम हो सकते हैं, उनको हम लागू करेंगे।

माननीय सभापति महोदय, इसके साथ ही जिस तरह से इन्होंने सदन में जो भाषण दिया और बार-बार पिछले दो महीने से और जिस दिन हमारे देश के यशस्वी प्रधान मंत्री मोदीजी ने हमारा गांवों में पानी पहुंचाने के लिये, हर घर को पानी देने के लिये देश में एक इतिहास रचा। पूरे देश में जल जीवन मिशन योजना 15 अगस्त, 2019 को चालू की, उस योजना के अन्दर सबसे ज्यादा अगर भला होने वाला था तो राजस्थान का था। राजस्थान की जो स्थिति है, मैं आपको बताऊं यहां पर लगभग 10 प्रतिशत तो हमारा क्षेत्रफल है, साढ़े 5 प्रतिशत हमारी आबादी है और अगर रेशो से देखें तो 1.3 प्रतिशत यहां पर जल की उपलब्धता है। हमारे यहां पर माताएं-बहनें, विशेषकर पश्चिमी राजस्थान में कहीं भी जायें तो वहां पर किस तरह से पानी का संरक्षण किया जाता है, पुराने समय में टांके बनाना और नहाने के बाद उस पानी को दुबारा वापस कैसे यूज में लेना, यह सारी चीजें करते आये हैं और कितनी दूर-दूर से पानी लेकर आती थीं। जिसके घर पर पानी जाता है तो उसके लिये एक वरदान जैसा काम था। जिस तरह से इन्होंने काम की जो गति बढ़ायी और जिस तरह से इन्होंने काम किया, उस योजना को, जो कैसे काम करना चाहिये था, आज हर आदमी परेशान है कि मेरे घर पर नल तो लग गया, पर इसमें पानी कब आयेगा। बाकी काम करने का इनका जो तरीका था, सबसे पहले जहां पानी की व्यवस्था इनको करनी थी, क्योंकि जब पानी होगा तो ही योजना सफल होगी। हर आदमी कह रहा है कि मेरी टंकी खाली पड़ी है, मेरे टंकी में पानी नहीं आ रहा है। मेरे टोंटी लगा तो दी पर पानी नहीं आ रहा है। उसमें भ्रष्टाचार किया नहीं किया, वह बाद की बात है। वह जांच का विषय है और वह जांचें हो रही हैं। जिन्होंने भी भ्रष्टाचार किया है, वे जेल जायेंगे। ई.डी. भी आ रही है और सी.बी.आई. की जांच चल रही है, वह विषय अलग हैं। बाकी वह उपभोक्ता परेशान है कि वास्तव में आप लोगों ने भ्रष्टाचार किया है, क्योंकि मेरे पानी नहीं आ रहा है, क्योंकि पानी की व्यवस्था इन्होंने की ही नहीं। अगर यह पानी की व्यवस्था करते तो 2017-18 के अन्दर सबसे महत्वपूर्ण योजना, विशेषकर 13 पुराने जिले और 21 जो नये जिले बने हैं, उनके अन्दर ई आर सी पी योजना हमारे पूर्ववर्ती सरकार ने बनायी थी, उसमें 16 करोड़ रुपये देकर उसकी

डी पी आर भी बनाई। वह डी पी आर केन्द्रीय जल बोर्ड को राजस्थान सरकार ने भेजी। उसका परीक्षण किया गया। कोई भी दूसरे राज्य से पानी आता है तो उस दूसरे राज्य से एन ओ सी ली जाती है। एन ओ सी लेने के लिये मध्य प्रदेश सरकार को भी पत्र गया। दुर्भाग्य से जब तक मध्य प्रदेश सरकार से जवाब आता तब तक चुनाव आ गये और राजस्थान के अन्दर सरकार बदल गयी। मध्य प्रदेश में भी कांग्रेस की सरकार बनी। राजस्थान में भी कांग्रेस की सरकार बनी। बाकी उस पत्र का जवाब नहीं आया और सिर्फ यह चीज कहते रहे कि साहब देश के प्रधान मंत्री मोदीजी हमें 90 प्रतिशत पैसा दें तो हम यह करें। मैं कहना चाहता हूं आपके माध्यम से सभी माननीय सदस्यों को, कि किसी भी योजना में पैसा जब देंगे, जब कहीं न कहीं उसकी डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट को सैंक्शन देगी, उसका परीक्षण होने के बाद में ही तो उसका पैसा दिया जायेगा। हमारे पूर्व केन्द्रीय मंत्री, केन्द्रीय मंत्री तो अभी हैं, जिनके पास विभाग था जल शक्ति का, उन्होंने बार-बार बोला कि इसके अन्दर यह संशोधन करके यह लैटर भेज दो।

Jyg/rtm/020824/16.00/2p

दोनों जगह आपकी सरकार है। दोनों आप तय कर लो, मैं इसको, क्योंकि कोई भी केन्द्र प्रवर्तित योजना आती है उसमें 60:40 रेशो होता है। जो पूर्व प्रधान मंत्री अटल बिहारी वाजपेयीजी का सपना था कि नदियों जोड़ो, उस योजना को हमारी केन्द्र सरकार, देश के प्रधान मंत्रीजी, मोदी लागू कर रहे हैं। मैं नदी जोड़ो योजना में इसको रखूंगा और 90 परसेंट पैसा मैं इसको दूंगा, आप इसको भेजो। इन लोगों ने उस पर काम नहीं किया, क्योंकि इनको केवल राजनीति करनी थी, देश के प्रधान मंत्री मोदीजी और जल शक्ति मंत्रीजी, जो जोधपुर से आते थे, उनको बदनाम करना था कि ये पैसा नहीं देना चाह रहे हैं, केवल एक आदमी को टार्गेट करते हुए उसको नहीं करना चाहा। उससे भी बुरा क्या किया इन्होंने। चुनाव से पहले ..(व्यवधान).. सुनो आप।

जो कह रहे थे कि हमने बनाये थे, आप लोगों ने इस तरह से टेंडर लगाए, आप लोगों ने राजस्थान की जनता के साथ सिर्फ धोखा करने का काम किया। जब मध्य प्रदेश सरकार उस योजना का 2499 एमसीएम, सब लोग कहते हैं कि आपके पास कौनसा एमओयू है, हमारे पास नहीं है तो आपके पास थोड़ा आया था। हमने डिटेल कैल्कुलेशन करके भेजी थी, कोई कमी थी तो दुबारा भेजा। 2400 एमसीएम का काम था लेकिन इन्होंने केवल 40 एमसीएम की योजना बनाई, जिसमें न तो 21 जिलों को पीने का पानी मिलने वाला था, 2 लाख हैक्टेयर सिंचाई का उस योजना में था। उद्योगों के लिए योजना बनाई थी, सिर्फ उन्होंने 500 एमसीएम चुनावों से पहले, वो भी चुनावों से पहले आनन-फानन में बनाई और उसमें आधा पैसा कोंट्रेक्टर से, 40 परसेंट पैसा कोंट्रेक्टर देगा, बाद में उसको ब्याज से चुकाते रहेंगे और बाकी इर्रिगेशन डिपार्टमेंट की जितनी भी प्रोपर्टी थी उसको बेचते हुए चुनावों से पहले यह घोषणा कर दो जिससे जनता से हम वोट ले लें। अब सोचो 500 एमसीएम से किसको तो

पानी मिलता, कहां उद्योगों को मिलता, कहां सिंचाई के लिए पानी मिलता? उसी वक्त बार-बार केन्द्रीय जल शक्ति मंत्री कहते कि हमने मोडिफाइड पीकेसी योजना बना ली है, इसमें हमें ज्यादा पानी मिलेगा, हमारी बात पर विश्वास करो, बार-बार उन्होंने मीटिंग करने की कोशिश की, बार-बार यहां के अधिकारियों को बुलाया, यहां के अधिकारियों को न तो दिल्ली जाने दिया और जब वो खुद यहां बात करने के लिए आए तो कोई भी अधिकारी उनसे बात नहीं कर पाया। कोई मंत्री बात नहीं कर पाया। ..(व्यवधान).. सिर्फ इनको चुनावों के अन्दर बेनिफिट लेना था।

हमारी सरकार आई, हमारी सरकार आने के बाद में वापस उन्होंने परीक्षण केन्द्रीय जल शक्ति मंत्रीजी ने किया था, हो सकता है कि राजस्थान गवर्नमेंट ने, हमारी सरकार के परीक्षण में 2400 एमसीएम आ रहा था, बाकी उनके हिसाब से राजस्थान के हिस्से में 3400 एमसीएम पानी आ रहा था, 3400 एमसीएम पानी आ रहा था। यह कह रहे हैं कि एमओयू हुआ तो क्या हुआ, बिलकुल एमओयू हुआ है। केन्द्रीय जल शक्ति मंत्रीजी के साथ में मध्य प्रदेश के मुख्य मंत्री ..(व्यवधान).. मेरी पूरी बात सुनें। मुख्य मंत्रीजी के साथ में मिलकर, तीनों के बीच हुआ है। उसमें तय किया है 3400 एमसीएम आपका पानी है और बाकी पानी मध्य प्रदेश का है। बाकी यह कह रहे हैं कि उसका पैसा अभी तक क्यों नहीं आया? उसकी डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट बन रही है, एमओयू होने के बाद उसके सर्वे हो रहे हैं, रोजाना माननीय सदस्यों की डिमांड आती है ..(व्यवधान)..

श्री सभापतिः मंत्री महोदय को बोलने दो। ..(व्यवधान).. नेता, प्रतिपक्षजी।

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): नहीं, नहीं। कोई गलत तथ्य थोड़े रखेंगे। 3400 एमसीएम पानी आप कह रहे हो, आप यह कह रहे हो कि एमओयू में है तो ..(व्यवधान)..

श्री सभापतिः नेता, प्रतिपक्ष, आप बोल लिए न, अब बोलने दो मंत्रीजी को। ..(व्यवधान).. आप बाद में और बोल लेना। मंत्रीजी को जवाब देने दीजिए। ..(व्यवधान)..

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय कार्य मंत्री): आप मंत्री के जवाब के बीच में नहीं बोल सकते। ..(व्यवधान)..

श्री कन्हैयालाल (जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री): डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट मध्य प्रदेश सरकार और राजस्थान सरकार की बन रही है, उनको कहां-कहां पानी यूज में लेना है, राजस्थान को कहां-कहां पानी यूज में लेना है, उसके बाद में वापस कितना पैसा दुबारा बनेगा, क्योंकि अभी टेंटेटिव 48 हजार करोड़ रुपये है, हो सकता है 60 हजार करोड़ रुपये लगे, उसका 90 परसेंट पैसा केन्द्र सरकार देगी। ..(व्यवधान).. और सुनो। उससे भी बड़ा क्या फैसला किया है, जो नवनेरा बांध, जो नेता, प्रतिपक्षजी ने बोला था, ..(व्यवधान).. मैं बता रहा हूं। ..(व्यवधान).. वो बगैर जानकारी के बोल रहे थे। ..(व्यवधान)..

श्री सभापतिः नेता प्रतिपक्ष, माननीय मंत्रीजी को बोलने दीजिए। ..(व्यवधान).. उनको जवाब देने दो न। ..(व्यवधान).. आपका नम्बर आए तो आप बोल देना। ..(व्यवधान).. आप बीच में नहीं बोलेंगे। यह कोई तरीका नहीं है, विराजिए आप। ..(व्यवधान)..

श्री कन्हैयालाल (जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री): बजट के आखिर में नेता प्रतिपक्ष ने बोला था कि नवनेरा बांध, ईसरदा बांध हमने बनाया, आपने नहीं, हमने सैंक्शन किया, उसका 1700 करोड़ रुपये का जो पैसा है वो भी केन्द्र सरकार ने कहा है कि वो भी आपका 10 परसेंट में भरेंगे इसको। यह है नरेन्द्र मोदी सरकार, यह है कि देश के प्रधान मंत्री, यह भी देंगे वो। ..(व्यवधान).. वो पैसा भी इसी में इंक्लूड करेंगे। ..(व्यवधान).. सुनो। ..(व्यवधान).. पानी की व्यवस्था की नहीं। पानी की व्यवस्था की नहीं।

श्री सभापति: विराजिए। विराजिए। ..(व्यवधान).. मंत्री महोदय, आप बोलिए। आप सब सदस्य, विराजें। प्लीज।

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): मेरे पास आंकडे हैं। ..(व्यवधान)..

श्री कन्हैयालाल (जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री): दूसरी योजना जो हमारे मालवीय नगर से आने वाले माननीय सदस्य, जो हमारे बहुत सीनियर सदस्य हैं, उन्होंने उठाया है, जयपुर के पानी के लिए, पूर्व मुख्य मंत्री वसुन्धरा राजेजी ने ब्राह्मणी नदी की योजना बनाई थी, उसका क्या हुआ? उसके लिए भी हमने 6 करोड़ रुपये डीपीआर के लिए दिए थे। बाकी वो भी सरकार बदलने के बाद कोई डीपीआर नहीं बनाई, आज हमारी सरकार उस पर काम कर रही है और हमने उसकी डीपीआर पर काम करने का काम किया है ..(व्यवधान).. 8300 करोड़ रुपये की योजना बनाई है, लगभग 148 किलोमीटर की योजना है और इसमें हम दूसरा काम और कर रहे हैं। यह कह रहे हैं कि हमारे पानी की रक्षा हम नहीं करते हैं। हम ब्राह्मणी नदी का पानी जो राजस्थान का है, इसके अलावा मध्य प्रदेश सरकार ने पिछले सालों के अन्दर राजस्थान के पानी को जो काम में ले लिया उसकी हम गणना कर रहे हैं कि हमारे हिस्से का कितना पानी ले लिया। रावतभाटा में हम उस पानी को लेंगे और लगभग 500 एमसीएम पानी, 500 एमसीएम पानी जिसको ये पार्वती-काली सिंध, ईआरसीपी की बात कर रहे थे, उतना पानी तो हम ब्राह्मणी नदी से लेकर आएंगे। ..(व्यवधान).. इस पर हमारी सरकार काम कर रही है। ..(व्यवधान).. सुनो। इसकी डिटेल भी बता दूं। इसके अन्दर 16 किलोमीटर तो टनल बनेगी, और यह पानी ग्रेविटी से आएगा, फ्लो से आएगा, इसमें कोई लिफ्ट नहीं है और इसमें जो लेवल है उसमें 35 मीटर का एड है, 35 मीटर के फ्लो से पानी आएगा। सिर्फ इसमें यह है कि भैंसरोडगढ़ और वाइल्ड लाइफ अभयारण्य में 63 हैक्टेयर है, मुकन्दरा टाइगर रिजर्व में 230 हैक्टेयर है, चित्तौड़गढ़ में 285 हैक्टेयर है। ..(व्यवधान).. इसके लिए मैं धन्यवाद देना चाहता हूं हमारे यशस्वी मुख्य मंत्रीजी को जो इसमें 24 घंटे काम कर रहे हैं कि किस तरह से राजस्थान की जनता के लिए पानी लेकर आएं। यह भी हमारी सरकार काम कर रही है।

इन्होंने कहा कि यमुना जल समझौता, बार-बार कहते हैं, आपने क्या किया यमुना के ऊपर पहले, जो काम हमारी सरकार ने किया उसके बारे में आपने पहले कभी सोचा भी है?

माननीय सभापति महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि जब तब यह नहीं होता तब तक हम पानी की व्यवस्था करेंगे। इन्होंने बहुत से काम जल जीवन मिशन के अन्दर किए हैं, मैं

झोटवाड़ा का उदाहरण देता हूं। कोई भी प्रोजेक्ट बनता है तो सबसे पहले रॉ मैटेरियल की व्यवस्था की जाती है। पानी के प्रोजेक्ट में पानी होगा तभी आगे बढ़ेंगे। जल जीवन मिशन के पैसे को सिर्फ इनको खर्च करना था। ओपन वेल बना लिए, यह नहीं देखा कि इसमें पानी है कि नहीं है क्योंकि वो एस्टीमेट में, प्रोजेक्ट में बनाएंगे तभी तो आगे सेंक्शन मिलेगी, इन्होंने ट्यूबवैल ले लिए, यह नहीं देखा कि वहां पानी है कि नहीं है, इन्होंने खोद दिए और कहते हैं कि टंकियां खाली पड़ी हैं। कहते हैं कि पानी कब आएगा, यह इतना बड़ा इन्होंने किया उसकी वजह से आज हमें दिक्कत आ रही है, आप लोगों के पापों की वजह से।

आज सुबह माननीय सदस्य फुलेरा से आने वाले ने कहा, क्वेश्चन था इनका, मेरे पानी 6 एमएलडी पानी फुलेरा में है, वो क्या प्यासे मरेंगे क्या? मैं माननीय सदस्य आपसे यही कहना चाह रहा था कि अगर यह योजना पहले सही बनती, इनटेक पम्प हाउस पहले बनाते हैं, ईआरसीपी का रिजर्वेशन पहले करते हैं, वहां पर उसका फिल्टर प्लांट पहले बनाते, जहां 35 लीटर पहले रिजर्वेशन था, अगर घर-घर कनेक्शन में 55 लीटर हो गया तो पहले पानी लेकर आते और फिर उन टोंटियों में पानी चालू करते तब पानी मिलता न आपका। ..(व्यवधान).. उससे पहले कहां मिलता? तब मिलता न पानी। ..(व्यवधान).. इन्होंने यह नहीं सोचा, इनको सोचना ही नहीं है। ..(व्यवधान).. आप सब सुनो।

श्री सभापतिः प्लीज सदस्य, बार-बार खडे ना हों। आपके नेता, प्रतिपक्ष जवाब देने में सक्षम हैं। आप बार-बार खड़े होकर डिस्टर्ब ना करें। प्लीज सदस्य, विराजिए आप।

श्री कन्हैयालाल (जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री): माननीय सभापति महोदय, इन्होंने सिर्फ राजनीति की है। ..(व्यवधान).. इन्होंने सिर्फ जनता कैसे राज़ी रहे, जनता को अभी तो राज़ी रख लोगे वोट लेने के लिए, परमानेंट राज़ी तब रहेगी जब परमानेंट काम करोगे, टेम्परेरी से काम नहीं चलेगा। जल जीवन मिशन में मार्च 2023 के अन्दर घोषणा की जाती है ...

MLS/RTM/02.08.2024/16:10/2q

क्योंकि यह महत्त्वपूर्ण योजना थी, यह पूरे देश में लागू की गयी थी। इसमें स्टेट को 45 परसेंट पैसा देना था, केन्द्र को 45 परसेंट पैसा देना था और 10 परसेंट पैसा जन सहभागिता से लोगों से लेना था, जिससे उसका संचालन सही तरीके से हो जाये, समय पर उसका बिजली का बिल चला जाये और रेगुलर चले। जिस तरह से जनता जल योजना बन्द पड़ी है, स्वजल धारा है, जो भी कई योजनाएं हैं, 15 सालों से मैं भी देख रहा हूं कि क्या स्थिति होती है। उन योजनाओं का जो भी जन सहभागिता का पैसा था, इन्होंने कह दिया कि माफ किया जाये। कोई बात नहीं, आपने माफ कह दिया तो, उसका बजट दें। क्या कोई बजटीय प्रावधान है?

जिन लोगों से पैसा ले लिया, उन्हें वापस लौटाने का कोई आदेश नहीं किया। जिन सरपंचों के पैसे जमा हो गये, उन्होंने कपड़े फाड़े कि हम से तो पैसे ले लिये, उनसे क्यों नहीं

ले रहे हैं? कोई बात नहीं। उससे भी बड़ा नुकसान क्या हुआ? उससे बड़ा नुकसान आप सुनें। यह हमें समझना पड़ेगा। आज हो सकता है आपको बुरा लग रहा हो, बाकी बार-बार जनता में जाएंगे तो यह प्रॉब्लम आयेगी। हम कोई एस्टीमेट बनाते हैं, 200 कनेक्शंस के हिसाब से एस्टीमेट था, टंकी का निर्माण हो गया, लाइन डाल दी। एक घर में पांच आदमी रहते थे, एक ही परिवार में, उन्होंने सोचा, 2500-3000 रुपये आ रहे हैं, हम एक कनेक्शन लेंगे, डिपार्टमेंट में जिन्होंने एस्टीमेट बनाया, कैल्कुलेशन कर ली कि एक कनेक्शन के हिसाब से डिजाइन होगी।

टंकी बन गयी, लाइनें डल गईं। ज्योंही फ्री किया, जन प्रतिनिधियों, सरपंचों के, इनके भी पांच कनेक्शंस एक्स्ट्रा हो गये। जहां 200 कनेक्शंस थे, 400 कनेक्शंस हो चुके। अब उन 400 कनेक्शंस में पानी क्या उस टंकी से दे पाएंगे आप जहां 1 लाख लीटर की टंकी है? क्या पाइप लाइन में दे पाएंगे आप? मतलब सिर्फ राज़ी कैसे रहें, कुछ भी हो जाये, हमें तो दोबारा जीतकर, मोबाइल बांट-बूंटकर, कुछ भी बांटकर हमें तो वापस इस प्रदेश को लूटना है। ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा। यह जो हमारी सरकार कर रही है, सभापति महोदय, मैं आपसे कहना चाहता हूं, इन्होंने किया क्या है, 33वें स्थान पर हमारा राज्य है। उसकी तारीख थी मार्च, 2024 में सब जगह। हम 33वें स्थान पर आज बहुत पीछे हैं। मैं तो धन्यवाद देना चाहता हूं, हमें आश्वासन दे दिया। जरूर ये जल जीवन मिशन की वजह से जो 11 सीटें हारी हैं, इनका दण्ड हमें भुगतना पडा। इनकी वजह से।

लोग तो यह समझते हैं कि आप जीतकर आये, आप करें, तुरन्त करें। यह दण्ड भुगता है। आप गलतफहमी में हो रहे हैं कि हम जीते हैं। ...(व्यवधान)... आपके कर्म हम भुगत रहे हैं, आप नहीं जीते हैं। ...(व्यवधान)...

श्री सभापतिः प्लीज, प्लीज।

श्री कन्हैयालाल (जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री): आपके कर्म हम भुगत रहे हैं, आप नहीं जीते हैं। उसकी वजह से नुकसान हमें हुआ है। बाकी उन्होंने देख लिया। ऊपर वालों की थोड़ी नजरें हम पर थीं, बाकी उन्होंने आश्वासन दे दिया, इसको मार्च, 2024 के बाद में बढ़ाने का आश्वासन दे दिया। राजस्थान की जनता का पाप आपको लगेगा। पैसा कितना खर्च किया आप लोगों ने? 93,426 करोड़ की योजना थी। आप लोगों ने कितना खर्च किया, केवल 19,333, 20 परसेंट पैसा। 20 परसेंट पैसा भी वह था इनके हिस्से में, जो योजना पहले चल रही थी, जो मेन लाइन थी उसको भी एस्टीमेट में जोड़कर इन्होंने दिया। पैसा नहीं दिया इन्होंने। बाकी मैचिंग शेयर, आप कह रहे हैं न क्यों स्पीड होगी, सिर्फ बाकी मैचिंग शेयर का इन्होंने स्टेट गवर्नमेंट का नहीं दिया, केन्द्र का पूरा पैसा ले लिया।

हमने आने के बाद में 3 हजार करोड़ रुपये देकर जो इनके कनेक्शंस की स्पीड 2500 हजार कनेक्शंस पर डे थी, आज हमने 4500 हजार कनेक्शंस पर डे की स्पीड बढ़ायी है। हमने बढ़ायी है यह स्पीड। ऐसे बहुत से विषय हैं। ये अभी कह रहे थे कि हमारी सरकार ने कंटिंजेंसी कार्य में यह जो जाता है गर्मी में पानी के अन्दर नहीं की, सबसे पहले तो मैं

धन्यवाद देना चाहता हूं मेरे विभाग को, जो इन्होंने पहली बार कंट्रोल रूम स्थापित किया। अभी आदर्श नगर से आने वाले माननीय सदस्य कह रहे थे कि हमारे पानी के टैंकर की व्यवस्था नहीं हुई, पहली बार हमने, कोई डिपार्टमेंट नहीं चाहता कि नयी टेंशन लें, हमने हर जिला लेवल पर जहां दिक्कत थी, उसके लिए कंट्रोल रूम स्थापित किया।

जो भी पानी आता था, जो भी टैंकर के लिए कोई सूचना आती थी तो वहां से सबसे पहले टैंकर पहुंचता था। पहले लोग मैंटली, इसके लिए भी मैं तो खूब नाराज हुआ इनके ऊपर कि ये चीजें...

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय कार्य मंत्री): माननीय सभापति महोदय, पानी पर चर्चा हो रही है, आपकी इजाजत हो तो कोई एक गिलास मंत्री जी के यहां पानी का धर दे, उपयोग कर सकते हैं।

श्री कन्हैयालाल (जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री): हमने लगभग 460 करोड़ रुपये से इस गर्मी में टैंकर परिवहन से लेकर हैंडपम्प मरम्मत अभियान भी चलाया और जहां-जहां जरूरत थी, सारे काम, लगभग 489 नलकूप, 296 पूर्ण किये। 1313 हैंडपम्प्स में से 1031, ऐसे टोटल हमने सारे मिलाकर लगभग 461 करोड़ रुपये से इस गर्मी में व्यवस्था की।

अब व्यवस्था सुनें गर्मी की। आप कह रहे थे कि हमारे कपड़े फटे हैं। आप अख़बार उठाकर देखना हमसे पहले का। आपके समय में टैम्परेचर 35 से 45 डिग्री के बीच में था। आपके समय में 25 परसेंट बरसात ज्यादा हुई थी। आपके समय में भू-जल स्तर ट्यूबवैल्स का 50 फीट ऊपर था। आपके समय में 20 लाख कनेक्शंस नहीं हुए थे उस गर्मी के टाइम में। हमने 20 लाख तो वैध कनेक्शंस और 20 लाख के आसपास अवैध कनेक्शंस, 40 लाख कनेक्शंस को भी पानी दिया एक्स्ट्रा। गर्मी 45 से 52 डिग्री रही। आपके समय 300 बांध और तालाब भरे हुए थे, हमारे समय में केवल 147 थे। फिर भी हमने अवैध कनेक्शंस काटे। प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन किया। पानी का संचालन किस तरह से सही हो, लोगों के बीच जा-जाकर हमारे अधिकारियों ने एक-एक चीज का सही ढंग से पानी का वितरण किया। आपकी अपेक्षा हमारे सामने आधे भी प्रदर्शन नहीं हुए आधे भी, जबकि हमने जानकारी के लिए कंट्रोल रूम स्थापित किया। जो लोग पहले पानी अपने आप सेल्फ पैसे से लेते थे, उन्होंने देखा, कंट्रोल रूम में कह दो, अपने आप आयेगा। उसकी डिमांड ज्यादा बढ़ी तो भी हमने पूर्ति की। यह है हमारा मैंनेजमेंट। यह है भारतीय जनता पार्टी की सरकार का मैनेजमेंट। आप कहते हैं कि हमने क्या किया।

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): ये आपके बगल में मंत्री जी बैठे हैं, इन्हीं से पूछ लें क्या स्थिति है अलवर की। आपके बगल में ही बैठे हैं।

श्री कन्हैयालाल (जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री): माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि इस सरकार में हमने बजट घोषणा में, मैं तो सिर्फ दो ही चीजें कहना चाहता हूं सभी सदस्यों से कि हमने चर्चा कर ली, हो सकता है हमने भी कुछ बोला और आपने भी कुछ बोला, इससे दूर हटते हुए अगर हम भविष्य में जो भी चाहे जैसे

कनेक्शंस करेंगे तो डिजाइन के हिसाब से, कैल्कुलेशन के हिसाब से जो भी पानी हमारे पास है, वही हम डिस्ट्रीब्यूट कर पाएंगे। हम सबका मकसद है कि आने वाले इस सैशन में, मैंने अधिकारियों को बोल भी दिया, जिस तरह से बिजली विभाग के अन्दर माननीय मुख्य मंत्री जी से निवेदन भी किया है, उन्होंने हां भी भरी है, विजिलेंस भी हो।

इसके साथ-साथ, कनेक्शन के लिए पैनल्टी से लेकर सज़ा के प्रावधान से लेकर, क्योंकि मैंने पहले भी बोला कि बिजली पैदा कर सकते हैं, पानी पैदा नहीं कर पाएंगे। पानी ही आने वाले समय में सबसे बड़ी समस्या होने वाली है, क्योंकि 1984 में हमारा जो पानी का दोहन 35 परसेंट था, वह आज 148 परसेंट हो चुका है और बढ़ता जा रहा है। आने वाले समय में बहुत बड़ी तकलीफ होने वाली है, विशेषकर राजस्थान के लिए, क्योंकि जिस तरह से जलवायु परिवर्तन हो रहा है, चाहे पोंग बांध हो, चाहे हमारे दूसरे बांधों में पानी आना हो, कहीं न कहीं उनका जल स्तर गिरता जा रहा है। इस बार सबसे बड़ी समस्या, पोंग बांध से, वहां से जो सूचना आ रही है, अपने लिए हाल-फिलहाल, मैं तो अब भी बालाजी को कहूंगा, बालाजी महाराज खूब उसको जल्दी भर दें। नहीं तो आने वाले समय में यह समस्या बहुत विकराल होने वाली है। हम सबको मिलकर, पूरे सदन को मिलकर जो भी इल्लीगल कनेक्शंस से लेकर, नॉर्म्स में डिजाइन में जितने कनेक्शंस हैं, वे ही हम करें।

इसके साथ-साथ, बहुत से विषय हैं, सारी चीजें अभी। यह जो बजट में हमने कई ...(व्यवधान)... श्रवण जी, श्रवण जी, प्लीज।

श्री सभापति: प्लीज, प्लीज।

श्री कन्हैयालाल (जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री): सभापति महोदय, मैं माननीय सदस्य को बताना चाहता हूं, हमें पानी के लिए जो अभियान, जो हमेशा आप सब सदस्यों की चिन्ता रहती है कि कहीं भी हैंडपम्प, ट्यूबवैल खराब हो जाते हैं, इनकी मरम्मत के लिए हम केवल तीन महीने अभियान चलाते हैं।

mkd/rtm/02.08.2024/16.20/3a

बाकी समय में हम उनका मेंटीनेंस कैसे करें, क्योंकि पहले हर विधान सभा क्षेत्र में ज्यादा नहीं तो 20-30 हैंडपम्प मिस्त्री होते थे, वे रिटायर होते चले गये। इनका संधारण कहीं न कहीं पंचायत समिति के अंडर में रहता था और पीएचईडी विभाग, जिनको लगाता था, वे करते थे। पंचायत वाले करते थे तो वे एक दूसरे पर वह करते थे। मैं आज सदन में एक तरह से घोषणा करता हूं कि हैंडपम्प चाहे पंचायत राज में या पीएचईडी विभाग में हो, एक ही विभाग उसको देखेगा।

उसके लिए हमें अगर भर्ती करनी, क्योंकि हमारे मुख्य मंत्री जी ने चार लाख भर्तियों की योजना दी है, उसके अन्दर मेरे विभाग को भी उन्होंने टारगेट दिया है कि लगभग 25 हजार भर्ती का आपका भी बनाकर भेजो, हम तुरन्त भर्ती करेंगे। उसके अन्दर जितने भी हैंडपम्प मिस्त्री हैं, वह संख्या मेरे पास नहीं आई, लगभग पांच, सात, आठ हजार जितनी भी होगी,

क्योंकि हर दो पंचायत पर कम से कम एक हैंडपम्प मिस्त्री होना ही चाहिए, क्योंकि हैंडपम्प काफी लग रहे हैं तो समय पर मरम्मत हो जाये।

ट्यूबवेल्स के लिए भी, वह भी मैं आपको बताऊंगा। वह भी भर्ती हम कर रहे हैं। विशेषकर चालीस साल पहले जो कस्बा था, वह बहुत छोटा था, वह धीरे-धीरे काफी बड़ा बन गया, उसके अन्दर भी जो टेक्निकल हैल्पर थे, जयपुर में पहले टेक्निकल हैल्पर ज्यादा से ज्यादा 200 होंगे, 400 होंगे, एग्जेक्ट संख्या नहीं है, बाकी आज उससे चार गुना चाहिए, क्योंकि शहर चारों तरफ बढ़ता जा रहा है। उनकी भी हम लगभग सात-आठ हजार भर्ती कर रहे हैं, लगभग 300 के आसपास हम जेईएन की भर्ती कर रहे हैं, 466 हम सहायक अभियन्ता की कर रहे हैं, ऐसे जितने भी हैं, हम आने वाले समय में बहुत जल्दी इनकी भर्ती करेंगे, जिससे विभाग का काम समय पर पूरा हो।

पिछले कई सालों से यह परिपाटी चलती जा रही है कि ट्यूबवैल लगाने के लिए वहां से प्रपोजल आ जाता है, पुराने ट्यूबवेल्स को कोई देखता नहीं है कि उसमें क्या कमी है। उसको ड्राई बताते हुए, क्योंकि बीस-पच्चीस लाख का लगता है, उसके अन्दर मोटा कमीशन कहीं न कहीं मिलता था। उसमें मोटर खराब है, यह किसी ने नहीं देखा। उसकी केबल खराब है, किसी ने नहीं देखा, उसमें लोअरिंग के लिए, पाइप नीचे लोअरिंग में चले जाये तो किसी ने नहीं देखा और उसके बावजूद उसकी डीपनिंग कर दें, क्योंकि विभाग के अन्दर, जीडब्ल्यूडी में मैंने आकर देखा कि लगभग 20 से ज्यादा तो बड़ी-बड़ी पांच-पांच करोड़ की, ये बता रहे थे, उतनी कॉस्टिंग की तो मशीनें पड़ी हैं और 200-300 लोगों का स्टाफ पडा है, कभी किसी ने उनको काम में लेने की नहीं सोची। लाइट कनेक्शन के चार-पांच लाख रुपये भी लगते हैं, इसके लिए मैंने मेरे विभाग के सभी अधिकारियों से, जगह-जगह क्वालिटी कंट्रोल वालों से लेकर, जीडब्ल्यूडी से लेकर, पीएचईडी से लेकर एक कमेटी बनाकर, सबको जितने भी माननीय सदस्य मेरे पास आते हैं, पक्ष के भी आते हैं, विपक्ष के भी आते हैं, सभी को कहा कि जितने भी आपके ड्राइ ट्यूबवैल हो गये हैं, जो खराब पड़े हैं, उनकी पूरी लिस्ट दे दो। इनमें हर चीज को देखेंगे, केबल है, मोटर है, पाइप कम है और फिर भी वह खराब है, नहीं हो सकता तो उसके बराबर में मेरी मशीन से मैं दूसरा ट्यूबवेल सहित आपका डिपनिंग कर दूंगा। सबका एस्टीमेट बनाकर, क्योंकि लाइट वो ही काम आ जायेगी, पाइप वही काम आ जायेगा, मोटर काम आ जायेगी, जो 20 लाख का लग रहा है, तो एवरेज, बाबूसिंह जी को धन्यवाद दूंगा, इन्होंने मुझे यह सजेशन दिया था, यह सारा। इनका अनुभव मेरे काम में आया।

सभापति महोदय, इस गर्मी के अन्दर हमने केवल, जहां पर पिछले साल 1 हजार करोड़ के ट्यूबवेल, हैंडपम्प थे, हमने 100 करोड़ के अन्दर गर्मी में करके निकाले हैं, सिर्फ 100 करोड़। जो पैसा दस गुना लगता है, उसको हम किस तरह कम लेकर आये। जनता का पैसा है, जनता के पैसे का सदुपयोग हो। हमारे जीने के लिए जल सबसे महत्वपूर्ण है, इसका सही ढंग से उपयोग हो। यह हम बहुत जल्दी कर रहे हैं और महीने- पन्द्रह दिन में सारी डिटेल

आने के बाद उसका जितना भी बजट होगा, मुख्य मंत्री जी ने कह दिया है कि बजट में एक्स्ट्रा दे देंगे, चाहे डीजल का देना पड़े, चाहे मशीनों की मेंटीनेंस का देना पड़े, जो भी होगा, डिटेल आने के बाद वह भी हम करेंगे।

मैं तो इतना ही कहना चाहता हूं, चर्चा तो बहुत हो गई है, बिजली पर भी चर्चा करें। मैं तो यह कहना चाहता हूं कि आने वाले समय में आप सब लोग कोई भी सजेशन हो, पानी जैसा महत्वपूर्ण, इसमें कोई बीजेपी, कांग्रेस नहीं है, आप सभी लोग मेरे पास आयें और बतायें। पानी की जहां भी दिक्कत आयेगी, राजस्थान की जनता, एक भी आदमी की जहां समस्या है, उसका समाधान करने के लिए हम तत्पर हैं। हमेशा आपका स्वागत करेंगे।

श्री नरेन्द्र बुडानियां (तारानगर): जो इललीगल कनेक्शन हैं, उनको हटाने का काम कर दो।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, यह वाद-विवाद का नहीं हे।

श्री कन्हैयालाल (जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री): जिन्होंने जेजेएम में घपला किया, मैं नीचे जाऊंगा ना, साहब। मैंने चालीस से ज्यादा अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया।

श्री सभापति: मंत्री महोदय, आसन को सम्बोधित करें।

श्री कन्हैयालाल (जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री): अगर नीचे जाऊंगा, बहुत ज्यादा डीपली तो मेरे विभाग में एक भी नहीं बचेगा, इस लेवल का भ्रष्टाचार है। मैं ज्यादा नहीं कह सकता, डेप्थ से लेकर, क्योंकि मुझे विभाग,ये गर्मी भी निकालनी है, ये भी चलाना है। बाकि मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि जो भी जनता का पैसा है, उसका सदुपयोग होगा। ईमानदारी से जनता के हक में काम करेंगे। यही आपको विश्वास दिलाता हूं, बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति: माननीय सभी सदस्यगण, दोनों ही दल और छोटे-छोटे दल और निर्दलीय, आज 43 वक्ता हैं।

श्री कन्हैयालाल (जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री): ये हमारे माननीय प्रतिपक्ष नेता, आर.डब्ल्यू.एस.एस.सी. के गठन को 45 वर्ष पूरे हो चुके हैं। न तो हम इसमें कार्मिक की सेवा, शर्तों के नियमों में कोई परिवर्तन कर रहे हैं। ये सिर्फ इसलिए किया गया है कि जिस तरह से आज स्थिति यह है कि कई माननीय सदस्यों ने मुझे बोला कि, साहब, अभी तो उसकी डेट बढ़ी ही नहीं, जल जीवन मिशन की। सरकार कीलिमिट खत्म होने के बाद में, क्योंकि यह पानी जैसा महत्वपूर्ण है, सरकार की लोन लेने की लिमिट खत्म हो चुकी है। हमें लोन लेने के लिए इसके थ्रू लोन लेकर जनता के हित में पानी पिलायेंगे। इसलिए हमने इसकी चर्चा की है, बाकि हम इसमें कोई चैंज नहीं कर रहे हैं।

श्री सभापति: माननीय सदस्य श्री श्रवण कुमार जी, विराजिये। मैं सभी से आग्रह करता हूं। माननीय सदस्य, आसन पांवों पर खड़ा है। माननीय पूरे सदन को अवगत कराना चाहता हूं कि हमारे पास 43 वक्ता हैं। आपके दोनों दलों और निर्दलियों का 6 घंटे का समय मेरे पास में आया है। आप समय पर बोलेंगे, समय पर अपनी बात को पूरी करेंगे तो साढ़े चार

बजने वाली है और 6 घंटे गिन लो तो साढ़े दस, ग्यारह बजेगी।

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय कार्य मंत्री): इसकी व्यवस्था हो चुकी है, 9 बजे तक चलाना है।

श्री सभापति: अब आपका समय है, आप तय करके मुझे दे देंगे तो समय पर समाप्त हो जायेगा। सभी वक्ता अपनी बात पहले अपने विधान सभा क्षेत्र की कोई डिमांड है, वह डिमांड पहले रखें और समय पर अपनी बात को समाप्त करें। माननीय श्री पुष्पेन्द्र सिंह जी।

श्री पुष्पेन्द्र सिंह (बाली): माननीय सभापति महोदय..।

श्री सभापति: प्लीज, ऊर्जा मंत्री जी प्रस्ताव रखेंगे।

श्री हीरालाल नागर (राज्य मंत्री, ऊर्जा): सभापति महोदय, मैं आपकी अनुमति से...

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय कार्य मंत्री): पिछला बजट पढ़ लें, ..(व्यवधान).. पीछे जाकर पढ़ लें, यह सजग सरकार है, जन हितैषी सरकार है, काम करने वाली सरकार है और समय पर..।

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): ये संसदीय कार्य मंत्री का फेल्योर हैं, ये प्रस्ताव नहीं कर रहे हैं और सदस्यों को बुलवा रहे हो।

राज्य में बिजली की स्थिति पर विचार

श्री हीरालाल नागर (राज्य मंत्री, ऊर्जा): अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि राज्य में बिजली की स्थिति पर विचार किया जाये।

श्री सभापति: विचार किया जाये, जो पक्ष में हो, हां कहें।

(स्वीकृत)

किया गया।

श्री रफीक खान (आदर्श नगर): आप समय बढ़ा दो, यह बहुत ही इम्पोर्टेंट इश्यु है। सभी सदस्य बोलना चाहते हैं तो समय की पाबन्दी नहीं रखी जाये। सभी को बोलने का मौका दिया जाये।

श्री सभापति: माननीय पुष्पेन्द्र सिंह जी।

श्री पुष्पेन्द्र सिंह (बाली): आदरणीय सभापति महोदय, आज बिजली पर मुझे इस सदन में विचार रखने का मौका दिया है, मैं तहे दिल से आपका बहुत-बहुत आभार व्यक्त करता हूं। बिजली एक ऐसा विषय है, किसी भी राज्य की तरक्की और उनके युवाओं को रोजगार दिलाना है या इस प्रदेश की यदि प्रगति करनी है तो सबसे पहले ऊर्जा और बिजली की क्या स्थिति है, उस प्रदेश की, उसी तुलना से आपकी प्रगति होती है। 2013-18 में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई और किस हालत में हमने उस सरकार में सम्भाला।

Bhs/Rtm/02.08.24/16.30/3b

2013 में जब हमने सरकार सम्भाली तब हमारी तीनों कंपनियां विद्युत वितरण कंपनी हो या प्रसारण निगम हो या उत्पादन निगम हो, ये तीनों इतने बड़े घाटे में चल रही थी कि सरकार

को उनको चालाने के लिए एक बहुत तकलीफदायक स्थिति खड़ी हो गई। उस टाइम में हमारी तत्कालीन मुख्य मंत्री जी ने चिन्ता जाहिर करते हुए, उन्होंने जब वो स्वराज यात्रा निकाली तब उन्होंने ग्रामीण जनता को और सबको विश्वास दिया था कि हम 24X7 आपको विद्युत उपलब्ध करायेंगे और जब हकीकत में राज हमारे पास आया तो डिस्कोम की इतनी बुरी हालत थी कि 78 हजार करोड़ का घाटा तीनों डिस्कोम्स पर था। बैंकों ने लोन देना बन्द कर दिया और बिजली सुचारु रूप से गांवों में चौबीस घंटे पहुंचाना बहुत ही गम्भीर मामला हो गया।

मैं धन्यवाद देना चाहूंगा हमारे तत्कालीन ऊर्जा मंत्री पीयूष गोयल जी ने पूरे देश में उदय योजना लागू की। उदय योजना के तहत एफ.आर.बी.एम. एक्ट के तहत कुछ शिथिलता मिली हमको। उसके अन्तर्गत डिस्कोम्स का 75 प्रतिशत कर्ज स्टेट गवर्नमेंट अपने हैड में लेकर डिस्कोम्स की फाइनेंशियल स्थिति को वापस सुधारा। उस टाइम हमारे ऊपर तीनों डिस्कोम्स पर 78 हजार करोड़ का लोन था। बैंकों ने हमें लोन देना बन्द कर दिया। इस व्यवस्था को हम कैसे चलायें, जेनरेटर्स को हम कैसे पैसा दें, किस तरह से हम इस पूरे तंत्र को खड़ा करें, प्रसारण में हमारे नये जी.एस.एस. खड़े करें, कैसे हम गरीब आदमी को कनेक्शन दें, इस पूरे विषय को ध्यान में रखते हुए उदय योजना के तहत 62 हजार करोड़ रुपये स्टेट गवर्नमेंट ने अपने खाते पर लिये तब जाकर और जो शेष 18 हजार करोड़ थे, कंपनियों ने बॉड जारी करके, जो 13-14 परसेंट ब्याज पर लोन ले रखा था उसको बॉड जारी करके 8-9 परसेंट ब्याज पर हमको वह पैसा मिला और इस तरह से हमने फाइनेंशियल कंडीशन को रिस्ट्रेन करके डिस्कोम्स को उबारने का काम किया।

सभापति महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि हमने उस घाटे को कम किया। हमने खाली घाटे को कम नहीं किया, हमने कोशिश की ए.टी. एंड सी. लोसेज को हम करें और हमने ए.टी. एंड सी. लोसेज को कम करते हुए इन तीनों डिस्कोम्स की माली हालत को हमारे कार्यकाल में हम प्रोफिट में लेकर आये। अगर आप 2016-17 का देखें तो लगभग 25-2600 करोड़ रुपये हम प्रोफिट में लेकर आये। 2017-18 में हम वापस इसको प्रोफिट में लेकर आये जो हमको 2013 में फाइनेंशियल ईयर में साढे बारह हजार करोड़ का एनुअल लोस था उस एनुअल लोस को उदय योजना के तहत हमारे डेब्ट्स को गवर्नमेंट में शिफ्ट करते हुए और शेष राशि के बोंड जारी करके कम इंट्रेस्ट पर पैसा लिया और हमने इन डिस्कोम्स को प्रोफिट में लाकर खड़ा किया।

सभापति महोदय, 2018 में हम लगभग 2700 करोड़ रुपये के प्रोफिट में इन डिस्कोम्स को लेकर के आये और आज हालत यह है कि 2023-24 में अगर आप बेलेंस शीट देखेंगे तो एनुअल लोस 9 हजार करोड़ से ऊपर वापस हो गया है और आज आपकी डिस्कोम्स की जो लायबिलिटी है वापस 91 हजार करोड़ आप पर कर्जा चढ़ गया। आज मैं यह कहना चाह रहा हूं कि यह बात कागजों में कहते हैं कि ए.टी. एंड सी. लोसेज हमारे टाइम में हमने 15 प्रतिशत कर दी। अगर आपने ए.टी. एंड सी. लोसेज पन्द्रह परसेंट कर दी तो आपके लोसेज

9 हजार करोड़ क्यों हो गए? अगर आपके लोसेज ही पन्द्रह परसेंट के अन्दर आ गया तो आपके ए.टी.एंड सी. लोसेज 9 हजार करोड़ से ऊपर जाने ही नहीं चाहिये आपको तो प्रोफिट में होना चाहिये। हमारे टाइम जो हम 18 परसेंट तक लेकर आये, हम 15 परसेंट तक लेकर नहीं आये, हमने कोशिश की कि जहां 27 परसेंट ए.टी. एंड सी. लोसेज चल रहा था उसको हम 18 परसेंट तक लेकर आये और 2018 में हमने 2700 करोड़ के प्रोफिट पर लाकर खड़ा किया और आप कह रहे हो कि हम 15 परसेंट के अन्दर ए.टी. एंड सी. लोसेज लेकर के आ गये तो फिर आपके ऊपर 9 हजार करोड़ का वार्षिक घाटा कैसे हुआ और आज वह डेब्ट 91 हजार करोड़ तक कैसे पहुंच गया?

सभापति महोदय, आपने अपने कार्यकाल में कहा, मुख्य मंत्री जी ने अपने बजट भाषण में कहा कि हम 2022 तक हम सभी किसानों को दिन में लाइट दे देंगे। आपने दिन में लाइट कब दी? आपने बजट में घोषणा की 2022 में कि हम दिन में सभी किसानों को लाइट दे देंगे वह घोषणा आज दिन तक लागू नहीं हुई। उस घोषणा को हम लागू करेंगे। हमारे बजट पर मुख्य मंत्री जी ने एक बात कही है और यह कैसे होगा, यह कुसुम ए और कुसुम सी से होगा। राजस्थान में अभी हमने साढ़े चार हजार एल.ओ.आई. दे दी। किसानों को एल.ओ.आई. दे दी और 33 के.वी. जी.एस.एस. पर दो मेगावाट के और एक मेगावाट के सोलर हम स्थापित करने जा रहे हैं, किसानों के खेत पर स्थापित हो रहे हैं जिससे आने वाले समय में किसान उस जी.एस.एस. पर दिन में लाइट देगा ताकि किसानों को हम दिन में लाइट दे सकते हैं और हम इसको क्रय कर रहे हैं।

सभापति महोदय, आज की तारीख में कुसुम ए के तहत 3.14 रुपये में केन्द्र सरकार की योजना के तहत डिस्कोम क्रय करेगा और जो कुसुम सी है जो रिवर्स बिडिंग के तहत जो आज डिस्कोम ले रहा है उसकी कोस्ट आज 2.84 रुपये आ गई है, 2.70 रुपये आ गई है और सबसे बड़ी बात है मैं धन्यवाद देना चाहता हूं इस देश के प्रधान मंत्री जी को कि उन्होंने दूरदृष्टि रखते हुए किसानों की आय को दुगनी कैसे करें हम, किसान को खेती के साथ-साथ कैसे हम उसकी आय को दुगनी करें। आज जो वह बिजली पैदा करेगा, डिस्कोम को इसके जो पी.पी.ए. साइन हुए हैं जो देगा, उसकी रिवर्स बिडिंग के तहत पच्चीस साल तक उसका पी.पी.ए. है उसके बाद उसको रिबेट दी है। जहां भी किसान के पांच एच.पी. की मोटर है, जहां 7.5 एच.पी. की मोटर है, जहां 10 एच.पी. की मोटर है कुसुम सी योजना के तहत केन्द्र सरकार ने 35 से 40 परसेंट रिबेट दी है सोलर लगाने की। एक मेगावाट में जो 3 करोड़ रुपये उसकी लागत लगती थी आज 30 परसेंट 35 परसेंट रिबेट के तहत वह 2 करोड़ में लग रहा है। किसान को उसका लाभ मिल रहा है। किसान को उसका फायदा मिलेगा ताकि वो किसान अपनी जमीन पर वह सोलर लगा सकता है।

सभापति महोदय, इसके साथ-साथ, आपने यहां घोषणा कर दी। घोषणा ही करनी थी आपको। पूर्ववर्ती सरकार ने घोषणा की कि 2012 से लेकर 2022 तक हम सब कनेक्शन दे देंगे। यह घोषणा आपके 2022 के बजट में थी। आपने घोषणा तो कर दी पर आपने

राजस्थान का तंत्र नहीं सुधारा। आपने राजस्थान में प्रसारण निगम के जो 132 के.वी. के खड़े करने थे या 220 के.वी. जो आपको खड़े करने थे या 400 के.वी. के जो जी.एस.एस. खड़े करने थे या जो गांवों में 33 के.वी. खड़ा करना था वो आप खड़े कर नहीं सके और आपने घोषणा कर दी। जगह-जगह बिजली के कनेक्शन दे दिये आपने। आपने कनेक्शन तो दे दिये और आज यह स्थिति हो गई कि किसान को 6 घंटे लाइट नहीं मिल सकती क्योंकि वह जी.एस.एस. इतना ओवरलोडेड रहा, सिस्टम इतना ओवरलाडेड रहा कि हमारे किसान को 6 घंटे आप पूरी बिजली दे नहीं सके। आज हालत यह है कि हमको इस आर.डी.एस.एस. के तहत आर.डी.एस.एस. जो फर्स्ट पार्ट है उस फर्स्ट पार्ट के तहत हमने आर.डी.एस.एस. में पूरे राजस्थान के तीनों डिस्कोम्स में हम 33 के.वी. जी.एस.एस. बनाने जा रहे हैं। हम एग्रीकल्चर और डोमेस्टिक लाइट को सेग्रिगेशन में उसका पैसा काम में ले रहे हैं। स्मार्ट मीटरिंग में हम आ रहे हैं।

Kas/rtm/02.08.2024/16.40/3c

आपकी ओपन लाइंस को केबल लगाकर आरडीएसएस स्कीम में इस तंत्र को और मजबूत करके स्मार्ट मिटरिंग के तहत आने वाले समय में 15 परसेंट से कम छीजत लाने की कोशिश हम कर रहे हैं। इस आरडीएसएस के तहत केन्द्र सरकार ने पहले पार्ट में 18 हजार करोड़ रुपये हमें स्वीकृत किये। यह किये तो थे 2022 में लेकिन, आपने दिसम्बर तक 10 परसेंट पैसा भी खर्च नहीं किया। अगर आपने टाइम पर पैसा खर्च किया होता, टाइम पर आपने टेंडर किया होता, टाइम पर एलओआई दी होती, टाइम पर इसका एग्जीक्यूशन किया होता तो आपको इसका और फायदा मिलता। डिस्कॉम को मात्र 25-30 परसेंट देने पड़ते, लेकिन आपने इस प्रोजेक्ट को लेट कर दिया। कुसुम पार्ट 2, जो लगभग 26-28 हजार करोड़ रुपये का है, उसमें कुसुम योजना को लागू किया है। कुसुम सी योजना को भी इसमें लागू किया है, ताकि कुसुम सी में जो भी सोलर के प्लांट लग रहे हैं, उस कुसुम सी के तहत उसको रिबेट मिले। उसको कस्टम का भी फायदा मिलेगा, अगर टाइम पर वह प्रोजेक्ट लगा देगा तो उसको पूरी कि पूरी कस्टम ड्यूटी और पूरी जीएसटी भी किसान को मिलेगी, यह फायदा हमारी केन्द्र सरकार ने दिया है, ताकि आने वाले समय में छोटी-छोटी जगह हम सोलर लगाये। इसके लिये हमें कोई लंबा-चौडा सिस्टम डवलप करने की जरूरत नहीं है। 765 या 400 के.वी. जी.एस.एस. लगाने की जरूरत नहीं है, बड़ी ट्रांसमिशन लाइन खड़ी करने की जरूरत नहीं है। दो-दो मेगावाट की यूनिट लगाएं, ताकि उस क्षेत्र के आसपास के किसानों को और ग्रामीणों को उसका फायदा मिले।

आपने तो बड़ी बात की थी कि 2022 तक हम सभी किसानों को सुबह बिजली देंगे, लेकिन आपने खाली घोषणा की। यह काम हम आपको 2027 में कर के देंगे, यह हम आपको विश्वास देते हैं। हम यह नहीं कहते कि हम 2024 में कर देंगे या 2025 तक कर देंगे। हमने आते ही चार महीने से कम समय में 4500 मेगावाट की एलओआई जारी कर दी

और वह काम प्रारंभ हो गया है। लगभग 400 मेगावाट तो कमीशन हो गया है और जी.एस.एस. में लाइट चालू हो गई। इससे आने वाले समय में हमारे किसान को सुबह बिजली मिलेगी।

आपने तो ऐसी हालत की है, बिजली उत्पादन की बात करूं, आप एनर्जी असेस भी नहीं कर पाये। 2013 में जब हम आये तो छबड़ा के प्लांट चल रहे थे, सूरतगढ़ के प्लांट चल रहे थे, कालीसिंध का सीओडी हमारे कार्यकाल में हुआ। छबड़ा में कमीशन हमने किया, एक प्लांट आपने सीओडी कर दी, वह भी आपने कब किया, कमीशन होने के बाद साल डेढ़ साल निकालने के बाद आपने सीओडी की। सूरतगढ़ का प्लांट कमीशन हो गया, पर सीओडी करने में आपने साल-डेढ़ साल लगा दिया। हम सब जानते हैं कि सूरतगढ का प्लांट सबसे महंगा प्लांट है। उसकी पर यूनिट कॉस्ट मुझे लगता है कि साढ़े पांच-छ रुपये से कम नहीं होगी। उसके कोयले के ट्रांसपोर्टेशन में जो खर्चा आता है, उस प्लांट में साढ़े पांच-छ रुपये से कम बिजली उत्पादन नहीं होती है। आपने आपके कार्यकाल 2009 में डिसीजन लिया कि सुपर क्रिटिकल प्लांट हम सूरतगढ़ लेकर आयेंगे।

आप सूरतगढ़ लेकर आ गये, आपने काम स्टार्ट कर दिया, पैसे इन्वेस्टमेंट कर दिये, तो हमको कम्प्लीट करना पडा। हमारे समय में कमीशन हो गया, लेकिन आपने सीओडी की साल भर पहले, हमने कितना लॉस किया? अगर पहले सीओडी हो जाती तो प्लांट रनिंग में आ जाता। आज सूरतगढ़ की हालत क्या है, अगर यही प्लांट आपने कालीसिंध में लगा दिया होता, मुझे आज भी 2013 का मुख्य मंत्री जी का भाषण याद है कि हम बांसवाड़ा में 800 मेगावाट के दो प्लांट ला रहे हैं। मैंने सुना आपने जमीन भी एक्वायर कर ली थी, पर आज दिन तक वह प्लांट लेकर नहीं आये। आपने बजट भाषण में कहा कि हम 6 हजार मेगावाट बिजली के लिये कोयला यंत्र लेकर आ रहे हैं। आप एक भी ग्राउंड लेकर आये? आपने कहा हम बाड़मेर में 1100 मेगावाट लिग्नाइट लेकर आयेंगे। आप लेकर आये, कुछ हुआ भी वहां? आपने कहा कि बीकानेर गुढा में 125 मेगावाट का लेकर आयेंगे, कुछ हुआ? आपने कहा कि कालीसिंध में 800 मेगावाट का लेकर आयेंगे, कुछ हुआ? आपने कहा 1320, 660X2 छबड़ा में लेकर आयेंगे, अभी तक कुछ भी नहीं हुआ। आपने निविदा आमंत्रित करके उसको वापस केंसिल कर दिया। आज राजस्थान में बिजली की जो स्थिति पैदा हुई है, उसकी जिम्मेदारी आपके पांच साल के कार्यकाल की है। आपने पांच साल बिजली उत्पादन में ध्यान ही नहीं दिया, आप एनर्जी असेस नहीं कर सके। आपने कहा किसानों को बिजली के कनेक्शन दे दो, बिजली है कहां?

आपने बजट भाषण में यह भी कहा कि पिट हैड में 3200 मेगावाट बिजली लेकर आयेंगे। उसका एमओयू हमारी सरकार ने किया। 800 X4 के हमने एमओयू किये हैं। हमने कोयला रिजर्व किया है, हम लेकर आयेंगे। हम एनटीपीसी के साथ और कोल इंडिया के साथ टेरिफ बेस्ड बिडिंग करके 3325 मेगावाट कोयले और लिग्नाइट से उत्पादन करने का हमने एमओयू किया। यह 2029 तक आयेगा, आज अगर आप चाहो कि आज हम एमओयू साइन

करें तो एक थर्मल को बनने में 5-6 साल लगते हैं। आने वाले समय में राजस्थान आपको याद करेगा। आज गर्मी में बच्चे, बुजुर्ग जो बेहाल हो रहे हैं, उसकी पूरी जिम्मेदारी आपके सरकार के टाइम की बनती है।

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय कार्य मंत्री): माननीय सदस्य, हमारी तकलीफ के कारनामे इनके समय के हैं क्या?

श्री पुष्पेन्द्र सिंह (बाली): इनके ही है। मैं प्रतिपक्ष से यह निवेदन करना चाहता हूं कि कवाई कौन लेकर आया, यह वसुन्धरा जी के कार्यकाल में आया। बाड़मेर में जेएसडब्ल्यू 1180 मेगावाट, 135 के 8 लिग्नाइट स्टेशन आये, किसके कार्यकाल में आये, वह हमारे कार्यकाल में आये। कालीसिंध में 600X2 किसके कार्यकाल में आये, वह भारतीय जनता पार्टी की सरकार के समय में आये। छबडा I & II किसके कार्यकाल में आया, वह वसुन्धरा जी के कार्यकाल में आया, गजेन्द्र सिंह जी के समय में आया। मेरा आपसे निवेदन है गिरल के जो प्लांट हैं 125X2 यह किसके कार्यकाल में आया, वसुन्धरा जी के कार्यकाल में आया। इसके अलावा धौलपुर गैस प्लांट किसके कार्यकाल में आया? जब बिजली की कमी थी, आपने बिजली खरीदी, आपने रामगढ गैस प्लांट पूरे पांच साल तक नहीं चलाया। धौलपुर गैस प्लांट आपने पूरे पांच साल तक नहीं चलाया। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं मुख्य मंत्री जी को और ऊर्जा मंत्री जी को, जब देखा कि वास्तव में बिजली की स्थिति खराब है तो आज हमारे धौलपुर और रामगढ़ के प्लांट सुचारु रूप से चल रहे हैं। गिरल का प्रोजेक्ट हमारे कार्यकाल में बना, हमारे समय में उसका सीओडी हुआ, वह 2016 से बंद पडा है। क्यों बंद पडा है, इसलिए बंद पडा है कि आपने जो माइंस अलॉट की है, उस पर सल्फर वेल्यू 7 परसेंट है और 7 परसेंट के सल्फर वेल्यू से वह प्लांट चल नहीं सकता है। हमारे पास वहां और भी लिग्नाइट है, जो आपने राजमेस को दिया है, राजमेस को जो माइनिंग दी है, उसके कांट्रेक्ट से अधिक उसको लाइसेंस मिला है। उससे माइनिंग वापस लेकर क्या हम उस गिरल को स्टार्ट नहीं कर सकते हैं? आज गिरल एक मात्र प्लांट है जो आपको 500-600 करोड़ का लॉस पर ईयर दे रहा है। आपको फिक्स रेट देना पड़ रहा है। आपने जो लोन ले रखा है, उसको आपको देना पड रहा है। लगभग 500 करोड़ प्रतिवर्ष का घाटा उस गिरल प्लांट से उठाना पड रहा है।

Msk/rtm/02.08.24/1650/3d

(समय: बजे)

(श्री अर्जुन लाल जीनगर, सभापति, पदासीन)

मैं आज कुछ बात कहना चाहूंगा कि उत्पादन की बात करूं तो हमारे टाइम में उत्पादन को 2018-19 में 900 करोड़ रुपये के प्राफिट पर हमने लाकर खड़ा किया। यह भी बहुत बड़ा हाथी था। नये-नये अधिकारियों को, उस टाइम के हमारे जो सीएमडी, एन.के.कोठारी थे, हमने हमारे कार्यकाल में विज्ञप्ति निकालकर पूरे हिन्दुस्तान के जितने भी अच्छे थर्मल चलाते थे,

हमने इंटरव्यू लेकर 2017 में एन.के.कोठारी जी को सीएमडी बनाया। उन्होंने इस लॉस बेस्ड प्लांट को दो-ढाई साल के अन्दर 900 करोड़ रुपये के प्राफिट पर थर्मल को लाकर खड़ा किया। फिर आपकी सरकार के आने के बाद आपने उसकी एलपीएस खतम कर दी, लेट-पेमेंट सरचार्ज खतम कर दिये। आपने इक्विटी जो देनी थी, वह आपने खतम कर दी। फिर कागजों में उसको 4 हजार करोड़ घाटे में बताया। मैं आपसे आज निवेदन करना चाहता हूं कि 2023 में आपने जब उत्पादन छोड़ा, तब आप उत्पादन पर 27 हजार करोड़ का घाटा छोड़कर चले गये। 27 हजार करोड़ का घाटा केवल उत्पादन पर, जो प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन हम छोड़कर गये थे।

मैं ट्रांसमिशन की बात करूं। ट्रांसमिशन में 2014-15 में पूरे हिन्दुस्तान में राजस्थान प्रसारण निगम को अवार्ड मिला था। 2017 में हमको अवार्ड मिला कि इस पूरे हिन्दुस्तान में सबसे अच्छा ट्रांसमिशन सिस्टम अगर डवलप हुआ है, जो प्रॉफिट मेकिंग आर्गेनाइजेशन है, वह राजस्थान का है। हम 183 करोड़ रुपये के प्रॉफिट चल रहे थे और आपके कार्यकाल 2023-24 में 645 करोड़ माइनस में चले गये।

मैं ट्रांसमिशन की बात करूं तो हमने 765 के 2 सब-स्टेशन हमारे कार्यकाल में बनाये, 400 केवी के 8 सब-स्टेशन बनाये, 220 केवी के 32 सब-स्टेशन, 132 केवी 99 सब-स्टेशन बनाये। आपने अपने कार्यकाल में 2018-23 में 400 केवी का खाली 1 सब-स्टेशन है, 400 का 1 बनाया, 220 के खाली 5 बनाया, 132 के मात्र 37 बनाये। आपने कुल 43 सब-स्टेशन बनाये। हमारे समय में जिस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर डवलप हुआ, जिस तरह से एनर्जी हर गांव तक पहुंचने लगी, हर घर तक पहुंचने लगी और जितने कनेक्शन हुए। आपने अपने कार्यकाल में इस ट्रांसमिशन में बिल्कुल भी काम नहीं किया। हमने हमारे कार्यकाल में 11 हजार 430 करोड़ का पूंजीगत व्यय किया है। आपने अपने कार्यकाल में खाली 4 हजार 369 करोड़ रुपये खर्च किये हैं। मेरा आपसे दूसरा निवेदन है।

मैं हमारे मुख्य मंत्री जी और ऊर्जा मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि इन्होंने पहले साल में आते ही 765 के 6 सब-स्टेशन, 400 केवी 7 सब-स्टेशन हाथ में लिए, 220 केवी के 15 जीएसस हाथ में लिए और 132 के 47 नये जीएसएस बनाने का काम आपने अपने हाथ में लिया है, जिससे आने वाले समय में हर घर, गांव, ढाणी तक और किसानों को अन-इंटरप्टेड बिजली पहुंचा सकें। मैं हमारे मुख्य मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूं। ऐसे लोग हैं, उन्होंने ए.ईन. ऑफिस में फाइल भर रखी है, जिनके पास आजादी के 75 साल बाद भी आज भी डोमेस्टिक कनेक्शन नहीं हैं, उनके लिए भी उन्होंने इस बजट में दो लाख कनेक्शन देने की घोषणा की है। आप 1 लाख 41 हजार कनेक्शन जो छोड़कर गये हैं, उनको भी आने वाले दो साल के अन्दर पूरा करने के लिए घोषणा की है। ...(व्यवधान)... उसके जिम्मेदार भी आप ही हो।

श्री सभापतिः आपस में नहीं। माननीय सदस्य, बीच में नहीं। आपका मौका आये तब बोलना।

श्री पुष्पेन्द्र सिंह (बाली): मेरा आपसे निवेदन है कि 2022 तक कनेक्शन की आपने जो डिमांड जारी की है। आपने कहा कि मैं दो साल में कर दूंगा, आप दो साल में नहीं कर पाये। उसके 1 लाख 50 हजार कनेक्शन शेष हैं, हमारे मुख्य मंत्री जी ने इस बजट में घोषणा की कि आने वाले साल-डेढ़ साल के अन्दर उसका पूरा ध्यान रखते हुए हम किसानों को जितने भी शेष कनेक्शन हैं, हम देने का काम करेंगे। मेरा आपसे यही निवेदन है कि आपने अपने पांच साल के कार्यकाल में और आपने हमेशा किया है, आपने 2008-13 में यही किया। बिजली पर आपका कोई कंट्रोल नहीं रहा। बिजली का कोई ध्यान नहीं रखा। मैं आपसे यही पूछना चाहता हूं कि आपने एग्रीकल्चर कनेक्शन आपने टीडब्ल्यू पर दिया। राजस्थान में 2 हजार कांट्रेक्टर होंगे जो कि बिजली विभाग से रजिस्टर्ड कांट्रेक्टर हैं। डिस्कॉम को सामान देना था। लेबर कांट्रेक्ट सीएलआरसी पर देनी थी, पर आपने टीडब्ल्यू पर दिया और 40 परसेंट अबव दिया। मतलब कोई कनेक्शन दो लाख पर बैठता था तो आपने उसको 2 लाख 80 हजार रुपये।

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय कार्य मंत्री): माननीय सदस्य, कितना परसेंट अबव।

श्री पुष्पेन्द्र सिंह (बाली): 40 परसेंट। 40 परसेंट अबव देकर। मैं आपको खुला कहता हूं कि आपके कार्यकाल में इसमें जितनी धांधली हुई है। क्योंकि जो टी.डब्ल्यू. सप्लायर था, उसने कभी भी सिटेल नहीं कराया है। उसने सामान खरीदा है, उसका प्रोपर सीटेल नहीं हुआ है। वह आज डिस्कॉम की प्रॉपर्टी बन गयी। वह ट्रांसफार्मर डिस्कॉम की प्रॉपर्टी बन गया, वह केबल डिस्कॉम की प्रॉपर्टी बन गयी, पर आपने इसका लैब से सीटेल नहीं कराया। उसकी पूर्ण जांच नहीं करायी और आपने 40 परसेंट अबव दिया है। मैं सरकार से यही पूछना चाहता हूं कि राजस्थान में लगभग 2 से 3 हजार कांट्रेक्टर हैं, जो कि रजिस्टर्ड कांट्रेक्टर हैं। हर जिले में 100-200 कांट्रेक्टर होंगे। मैं चाहूंगा कि मंत्री जी आज घोषणा करें कि आने वाले जितने भी एग्रीकल्चर कनेक्शन हैं, हम सीआरसी कांट्रेक्टर को देंगे। बढ़ी हुई रेटों पर जो टी.डब्ल्यू. कांट्रेक्टर को दिये हैं, वह काम आप नहीं देंगे। दूसरा मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं। आरडीएसएस की स्कीम।

एक माननीय सदस्य: इसको एक्सप्लेन करें, इस सबमें कहीं प्रोब्लम है।

श्री पुष्पेन्द्र सिंह (बाली): यह है कि टी.डब्ल्यू कांट्रेक्टर जो टर्नकी वर्क्स पर जो काम दिया है। यह 40 परसेंट अबव पर काम लिया है।

श्री यूनुस खान (डीडवाना): पांच साल तक एक ही ठेकेदार को दे रखा। ये पूछना चाह रहे हैं कि क्यों दिया है?

श्री पुष्पेन्द्र सिंह (बाली): पैसे कमाने के लिए दिये हैं। मेरा आपसे दूसरा निवेदन है कि आर.डी.एस.एस. के तहत आपका 8 हजार करोड़ का काम होने वाला है। इसमें लाइंस स्ट्रेंथनिंग होंगी, नये ट्रांसफार्मर लगेंगे, कई जगह आप ओपन वायर्स को हटाकर केबल लगायेंगे, आप स्मार्ट मीटरिंग करेंगे। ये टेण्डर भी जो पूर्ववर्ती सरकार के टाइम हुआ, वह भी 40 परसेंट अबव हुआ, जिसका आज दिन तक 10 परसेंट से ज्यादा काम नहीं हो पाया है।

मैं आपसे यह निवेदन करना चाहता हूं। मंत्री जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि यह आपके टाइम की बात नहीं है। जो डीपीआर बनी, डीपीआर बनने बाद उस डीपीआर में जो संशोधन हुआ, 100 परसेंट और 200 परसेंट डीपीआर में संशोधन हो गया। आज कोई सर्कल की डीपीआर बनायी है या बन्द कमरे में बनायी है, एक्चुअल में मौके पर जाकर डीपीआर नहीं बनायी है। वह डीपीआर आप चेंज करते हैं, जो कि पूर्ववर्ती सरकार के समय में चेंज हुई है, मैं चाहता हूं कि आप उसकी जांच करें। आपने 200 परसेंट चेंज कर दी। कांट्रेक्टर यह चाहता है कि मैं दूसरा काम नहीं करूं। मुझे जितना केबल का काम मिल जाये, अगर उसको केबल 10 किलोमीटर लगानी थी तो उसने डीपीआर को चेंज करते हुए, केबल 20 किलोमीटर की कर दी। आपने 100 परसेंट डीपीआर चेंज कर दी। कांट्रेक्टर यह चाहता है कि कांट्रेक्ट मेरे हिसाब से चले और हम चाहते हैं कि जनता के हिसाब से, जनता की सुविधा के हिसाब से काम हो। नये ट्रांसफार्मर लगें, सिस्टम में सुधार आये। मैं चाहता हूं कि आरटीजीपी एक्ट के तहत आप 50 परसेंट तक डीपीआर में चेंज ला सकते हैं, पर आप आरटीजीपी एक्ट के तहत 100-200 परसेंट चेंज नहीं ला सकते हैं, 250 परसेंट चेंज नहीं ला सकते हैं।

mdp/rtm/02.08.2024/17:00/3e

इसका जिम्मेदार कौन है? ये पूर्ववर्ती सरकार के समय कांट्रेक्टर्स के हित को ध्यान में रखते हुए जो डीपीआर चेंज की है, जो आरडीएसएस स्कीम, जो केन्द्र की योजना है, उस योजना को राजस्थान में अच्छे ढंग से लागू करनी थी, उसको खाली कांट्रेक्टर के हित में, उनके कहने से इस डीपीआर में चेंज लाए हैं, उसके जिम्मेदार कौन है? उसक खिलाफ आप जांच बैठाकर, विशेष व्यक्तियों के खिलाफ कार्यवाही करना चाहेंगे या नहीं करना चाहेंगे? इसके बारे में आप मुझे बताइए। आपने मौका दिया, बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिन्द। जय भारत।

श्री सभापति: श्री टीकाराम जी जूली।

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): कितनी भी जांच करवा लीजिए। ...(व्यवधान)... हम तो राज़ी हैं। जेल में डालिए।

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय कार्य मंत्री): माननीय नेता प्रतिपक्ष, पहले अपने सदस्यों को बुलाओ।

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): अकेला ही काफी हूं।

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय कार्य मंत्री): आपको तो लास्ट में बोलना चाहिए। ओपनर कैसे आ गये।

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): सभापति महोदय, आज मैं धन्यवाद देता हूं जो बिजली पर चर्चा हुई। मेरे से पूर्व वक्ताओं ने जिस प्रकार से बात की। उसको देखकर ऐसा लग रहा है कि राजस्थान में तो जो कुछ हुआ है, वह पिछले हमारे समय में ही हुआ है। अगर मैं दूसरी बात और कहूं कि उससे पहले माननीय सदस्य ही मंत्री थे, बिजली के, ये सारी व्यवस्था कर जाते तो ये दिक्कत नहीं होती। इसका मतलब ये सारी अव्यवस्थाएं इनके

समय की थी और यही कारण है कि माननीय सदस्य की इतनी काबिलियत होने के बाद भी अबकी बार इनको मंत्री भी नहीं बनाया। हम तो सोच रहे थे कि बिजली का मंत्री बनाते तो हो सकता है, इतना ज्ञान होने के बाद में भी। ये आप लोगों की हालत है। आप सब लोग मुख्य मंत्री जी तारीफ कर रहे हैं, इसमें दो चीजें हैं, या तो मुख्य मंत्री जी का निर्णय सही है कि उन्होंने इनके अन्दर काबिलियत नहीं देखी या फिर इनकी जो काबिलियत है, उसका आप लोग उपयोग नहीं करना चाहते हैं। पहली बात ये है।

सभापति महोदय, मैं सीधा मुद्दे पर आता हूं। ये आरोप-प्रत्यारोप लगते रहेंगे, लगाते रहे हैं। बिजली में ही बची थी, इसमें भी आप आज जांच की घोषणा कर देना। बाकी तो सब में कर ही रहे हैं आप। बात यह है कि आज जो हालत है प्रदेश की, आज की नहीं पिछले तीन महीने से जो हालत हो रही है। किसान दिनभर खेत में काम करता है। शाम को घर पहुंचता है, खाने के समय लाइट नहीं। मजदूर दिनभर मजदूरी करता है, शाम को घर पहुंचता है, लाइट नहीं। पूरे प्रदेश के अन्दर आम पब्लिक, आम जनता, बिजली से जितनी त्रस्त है, इतनी शायद किसी और बात से त्रस्त नहीं होगी। हालत ये है कि आठ बजे लाइट जाती है, सात बजे लाइट जाती है और पूरी-पूरी रात लाइट नहीं आती।

मैं मंत्री जी का धन्यवाद देता हूं कि मंत्री जी ने हम सबको बुलाया। आपने हम सबकी मीटिंग ली, सुझाव मांगे। नतीजा क्या हुआ? नतीजा जीरो। उस दिन आपने कहा कि बिजली की भी व्यवस्था कराएंगे, सामान की भी व्यवस्था कराएंगे। एक-एक महीना हो गया है ट्रांसफार्मर नहीं दे पा रहे हैं, बिजली की तो बात छोड़ दीजिए। इसलिए मैं बार-बार कहता हूं और आप लोगों को बुरा लगता है। यह सरकार की जिम्मेदारी है कि बिजली, पानी, शिक्षा, चिकित्सा जैसी सुविधाएं आम जनता को उपलब्ध कराए। यह कमाई के साधन नहीं हैं। जिसको हम सोच रहे हैं घाटे में, घाटे में, आपकी कौनसी कंपनी घाटे में नहीं है? बता दीजिए। केन्द्र सरकार की बता दीजिए, मैं अभी बता दूंगा सारी। आपके समय में घाटे में नहीं रही हो, हमारे समय में नहीं रही हो। घाटे में रहती है, क्योंकि जनता के लिए है, जनता की सेवा के लिए है।

आप बड़ी-बड़ी बातें करते थे। आपने कहा कि हम महंगाई कम करेंगे। कहां महंगाई कम कर रहे हैं आप? मैं पूछना चाहता हूं आपसे पिछले एक महीने के अन्दर, सबसे पहले मेरा व्यवस्था का प्रश्न भी है, सदन जब चल रहा है, चलते सदन के अन्दर पूरे राजस्थान के अन्दर किसी भी प्रकार का कोई टैक्स न लगाया जा सकता है, न घटाया जा सकता है, न घोषणा की जा सकती है। आम जनता पर आप कोई भार नहीं डाल सकते हैं। आपने डाल दिया। चलते सदन के अन्दर। यह हाउस की गरिमा को आप जिस प्रकार से बार-बार तार-तार करते हैं, पहले आपको हाउस के अन्दर सूचना देनी चाहिए थी, उसके बाद फ्यूल सरचार्ज बढ़ाना चाहिए था। लेकिन आपको तो संविधान की या विधान सभा की मान-मर्यादाओं की कोई वेल्यू नहीं है। आप तो सत्ता के नशे में चल रहे हैं, जैसे हाथी मदमस्त होकर चलता है, ऐसे ही आप लोग चल रहे हैं।

आपने कहा चुनाव से पहले कि पूरे देश के अन्दर सबसे ज्यादा महंगी बिजली है तो राजस्थान में है। आपने कहा पूरे देश के अन्दर डीजल-पेट्रोल राजस्थान में महंगा है। हरियाणा के बराबर करेंगे। कर दिया आपने डीजल-पेट्रोल हरियाणा के बराबर? बिजली के अन्दर मैं कहना चाहूंगा कि फ्यूल सरचार्ज आपने जनता को थोप दिया, फ्लेट रेट आपने जनता के ऊपर थोप दिए। यही नहीं जो नये कनेक्शन हैं, जिनको सब्सिडी मिलनी चाहिए थी, आप मेरे से पूछ रहे थे कि आपको सब्सिडी देनी थी तो फिर फार्म क्यों भरवाए? जनता की इच्छा के ऊपर इस योजना को लागू किया था। जो इस छूट का लाभ लेना चाहता है, वह एप्लाई कर दे, जो नहीं लेना चाहता है, वह नहीं करे। आप इसका जारी रखो। आप भी कह दीजिए कि जो स्वैच्छिक लाभ लेना चाहता है, वह एप्लाई करे, उसको छूट देंगे। जो नहीं लेना चाहता है, उसको नहीं देंगे। आप लोग यह चाहते नहीं है। आप लोगों की मंशा ठीक नहीं है। आपने दो महीने का बिल एक महीने में कर दिया। मान लीजिए पहले 100 यूनिट की छूट मिल रही थी, एक महीने में वह 75 की छूट लेता, एक महीने में 25 की छूट लेता, उसको लाभ मिलता। आज आपने इस चीज को डायरेक्ट हर महीने का बिल कर दिया। आपने पिछली बार भी हर महीने का किया था। हमारी सरकार ने वापस दो महीने का किया। आप फिर उसको एक महीने का करना चाहते हैं। आपकी मंशा जनता के हित में नहीं है। यह मैं कहना चाहूंगा।

आज बिजली नहीं है, ट्रांसफार्मर नहीं है, केबल नहीं है। यह हालत आपके विभाग की बनी हुई है। ऊपर से विभाग का कर्मचारी, अगर काम करते हुए उसकी डैथ हो जाए तो डिस्कॉम पल्ला और झाड़ लेता है कि आप जानो, आपकी मर्जी। ये हालत है।

दूसरा, आप बार-बार कहते हैं कि आप सिर्फ घोषणा करते हैं। मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि सरकार कोई भी रही हो, पहले हमारी सरकार, आपकी सरकार, फिर हमारी, फिर आपकी। हमने लास्ट जो बजट किया, मार्च के अन्दर बजट आया। हमने कामों को सेंक्शन किया, बजट में घोषणा की, उनकी वित्तीय स्वीकृति निकाल दी, टेंडर निकाल दिए, वर्क आर्डर निकाल दिए। काफी काम तो शुरू हो गये। आपकी सरकार ने एक आर्डर ऐसा निकाला 22 दिसम्बर के अन्दर कि सभी विभागों के सभी कार्य पर तत्काल प्रभाव से रोक लगायी जाती है, 20/12 को। सरपंच अपनी पंचायत का काम नहीं कर सकता, पीडब्ल्यूडी अपनी सड़क नहीं बना सकती, पीएचईडी के कनेक्शन नहीं हो सकते तो आपके बिजली के काम कैसे हो जाएंगे? सारे कामों को तो रोक दिया। फिर प्रदेश के अन्दर ये मैसेज देना कि ये सिर्फ घोषणाएं करते हैं, ये काम पूरे नहीं करते हैं। हम घोषणाएं करेंगे, हम काम भी पूरा करेंगे। आप बहुत अच्छे।

हमारे खोले हुए कॉलेज आपको बुरे लग रहे हैं। आप इस बजट के अन्दर फिर घोषणा कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? जब आपको लगता है कि हमने ज्यादा कॉलेज खोल दिए। यह स्थिति इस सरकार की है। मैं यह कहना चाहूंगा कि नये कामों पर जो रोक लगायी है, उसको संज्ञान में लेकर तुरंत ही इस रोक को हटाना चाहिए। हालत तो ये है कि कर्मचारियों की

तनख्वाह कल शाम को 5 बजे आयी, आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ। ये हालात इस सरकार के बन रहे हैं। आप और लोगों को जो ज्ञान दे रहे हैं, वह बात मैं कहना चाह रहा हूं। ...(व्यवधान)... मैं बिजली के लिए जोधपुर में, बीकानेर में, नागौर में, झालावाड़ में, जिन जगह के मैं नाम ले रहा हूं।

श्री श्रीचन्द कृपलानी (निम्बाहेड़ा): आपने क्या किया? आपने न तो बिजली की लाइन दी ...(व्यवधान)... न ही ट्रांसफार्मर मिला।

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): आप बैठिए।

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): आपकी आवाज समझ में नहीं आ रही है। ...(व्यवधान)... आप मत बोलिए।

श्री सभापति: आप सब बैठिए। आपस में नहीं।

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): सभापति जी, मेरा आपसे निवेदन है और पूरे सदन का ये प्रस्ताव है कि देवनानी जी इनको मंत्री नहीं बना पा रहे हैं तो इनके साइलेंसर तो लगा दीजिए कम से कम आवाज तो कम हो जाए। दिनभर वहां बात करते हैं, डिस्टर्ब करते हैं हाउस को।

Ans/rtm 17.10 3f 02.08.2024

आपके जोधपुर, बीकानेर, नागौर, झालावाड़ में बीजेपी के कार्यकर्ता और बिजली के कर्मचारियों के अन्दर मुठभेड़ हुई है, आपस में झड़प हुई है। दूर क्यों जाते हो, आप लोगों ने राज्यपाल महोदय के सम्मान में हमें भी डिनर पर बुलाया था। मैंने देखा आपके सदस्य वहां सीएम के प्रोग्राम में बिजली के अधिकारी थे, उनके कपड़े फाड़ने में कसर नहीं छोड़ी, यह तो आप लोगों की हालत है। यह असत्य नहीं है, यह हकीकत है। मैं बता दूंगा, चित्तौड़ ज़िले के सदस्य है। मैं असत्य नहीं बोलता। सदन के अन्दर मैं कभी भी मिथ्या तथ्य पेश नहीं करता। जो हकीकत है वही कहता हूं। अपने गिरेबान में झांक कर देख लो। आप खुद क्यों नहीं समझ रहे हो। सबके पास फोन आते हैं। अभी आठ बजे आपका फोन मुझे दे देना, मैं बता दूंगा कि वे फोन किस चीज के लिए आ रहे हैं। बिजली के अलावा किसी चीज के लिए फोन नहीं आ रहे। देर रात तक फोन आते हैं। अब आप लोग बंद करते हो तो आपकी मर्जी है, आपके अधिकारी तो बंद कर लेते हैं। हकीकत है प्रदेश की, पूरी जनता कह रही है। आप यहां विधान सभा में बैठे हो, क्षेत्र में जाएंगे तब पता चलेगा कि जनता आपको क्या कह रही है। वह तो मैंने बता ही दिया था जो ट्रिपल इंजन की सरकार थी छत्तीसगढ़ की। मुख्य मंत्री जी ने ट्वीट किया और फिर अगले दिन आपने ट्वीट कर दिया कि यह तो पहले ही एमओयू हो गया था गलती से। पहले एमओयू हो गया तो फिर आप जुलाई में ट्वीट क्यों कर रहे हो, यह बात समझ में नहीं आई। यह बात मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा।

पहले आपकी दिल्ली की सरकार, वह कोई काम नहीं कर पाई, नेहरू जी की गलती है। आप कुछ नहीं कर पा रहे, पिछली सरकार की गलती है। क्यों? कब तक पिछली सरकार को

कोसोगे? वह कह रहे थे ना कि आपके टेम्परेचर 45 रहा, हमारे भी अधिकतम टेम्परेचर रहा, अधिकतम सर्दी रही, कोविड रहा, लेकिन बिजली के लिए राजस्थान की जनता को हमने परेशानी नहीं आने दी। पहली बार ऐसा हो रहा है, एक ऐसी सरकार है गूंगी-बहरी, चाहे विधान सभा में बोल लो, चाहे टीवी, अख़बार में छपवा लो, चाहे जनता आपके कार्यालयों पर प्रदर्शन कर ले, चाहे कलेक्टर के यहां प्रदर्शन कर ले, सरकार के कानों पर जूँ तक नहीं रेंग रही।

दिन की बिजली की बात कर रहे हो ना। हमारी वजह से आप दिन की बिजली दे रहे हो। रिन्यूएबल एनर्जी के अन्दर पूरा राजस्थान पूरे देश में नम्बर वन, हम लेकर आए हैं हमारे समय में, जिसकी वजह से दिन की बिजली आ रही है।

अभी पूर्व मंत्री जी एमओयू की बात रख रहे थे। एक दिन में हो जाता है एमओयू? जिस कुसुम योजना की आप बात कर रहे हो, जिसके एमओयू की आप बात कर रहे हो, एक दिन में हो जाता है एमओयू? सारी फाइलें, सारी प्रक्रिया, सारा प्रोसेस हमारे समय का चल रहा है, मैं आप लोगों को यह बात कहना चाहूंगा। हमने फ्री बिजली देकर, बिजली में छूट देकर लोगों की मदद की, आपको यह बात जरूर समझनी चाहिए।

आप बार-बार घाटे की बात कर रहे हो। पॉवर फाइनेंस कॉरपोरेशन की रिपोर्ट कहती है कि वर्ष 2022-23 में देश के अलग-अलग राज्यों को डिस्कॉम को 68 हजार 832 करोड़ का घाटा हुआ है, जो कि 2021-22 की तुलना में ज्यादा है। केन्द्र की भाजपा सरकार के भी पांच साल, यानी 2017-18 से 2020-22 तक में पूरे देश के डिस्कॉम का घाटा 3 लाख करोड़ से भी ज्यादा है। आप बार-बार पिछली सरकार, पिछली सरकार कह रहे हो। 2017-18 में यह 56 हजार 206 करोड़, 2018-19 में 80 हजार 189 करोड़, 2019-20 में 60 हजार 231 करोड़, 2020-21 में 76 हजार 899 करोड़, 2021-22 में 16 हजार 570 करोड़, 2022-23 में 68 हजार 832 करोड़ का घाटा हुआ। तो पूरे देश में ही कोई डिस्कॉम घाटे से नहीं बच पाया तो राजस्थान भी नहीं बच पाता, यह बात आपको समझनी पड़ेगी।

दूसरी बात, यह घाटा क्यों हो रहा है? आप लास्ट में जवाब दे तब बता देना। आप लोगों ने कहा, क्योंकि मोदी जी के मित्र है, उन्होंने फोरेन में कोयले की माइंस ले ली। भारत सरकार ने एक आर्डर निकाल दिया कि दस परसेंट कोयला विदेश से लेना पड़ेगा। इंडोनेशिया से। ए-वन की कम्पनी से लेना पड़ेगा, क्योंकि उन लोगों को फायदा पहुंचाना है। देश में कोयला खूब है, हमारे पास खूब है। वह घटिया क्वालिटी का कोयला है, महंगा कोयला है।

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय कार्य मंत्री): वह तो आप खा गए।

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): आप खा रहे हो। खाने वाले आप हो। आप हो, आप खा रहे हो। खाने में कोई कमी आप लोगों ने नहीं छोड़ रखी है, यह बात मैं बताना चाहूंगा। राजस्थान का भौगोलिक क्षेत्र है, लोसेज तो आते है ना। कहां बाड़मेर व जैसलमेर, कहां हनुमानगढ व गंगानगर, कहां धोलपुर, पूरा बॉर्डर इतना बड़ा है, पर देश की जो भौगोलिक स्थिति है वह और जगह से अलग है।

आप बार-बार उदय योजना का जिक्र करते हैं। अभी हमारे बाली से आने वाले माननीय सदस्य ने भी जिक्र किया। यह पहली बार नहीं हुआ है कि कम्पनियों का जो कर्ज है उसको माफ किया हो, या सरकार ने उसको टेकओवर किया हो। 2002 के अन्दर 35 हजार करोड़ का बेलआउट पैकेज बिजली कम्पनियों को दिया था। 2012 में भी फाइनेंशियल रिस्ट्रक्चरिंग पैकेज में 56 हजार 908 करोड़ का पैकेज दिया। 2015 में उदय योजना में 2.3 लाख करोड़ का पैकेज दिया। 2020 में लिक्विडिटी इन्फ्यूजन स्कीम में 1.35 लाख करोड़ का पैकेज दिया। 2022 में भी रिवैम्प्ड डिस्ट्रिब्यूशन सैक्टर स्कीम में 97 हजार 631 करोड़ का पैकेज बिजली कम्पनियों को दिया, क्योंकि बिजली का बनाना, वितरण होना अनवरत प्रक्रिया है। इसलिए घाटा और कर्ज इसके अन्दर बढ़ता रहता है।

मैं अभी कुछ चीज़ें टेबल भी कर दूंगा, क्योंकि समय की काफी दिक्कत है। हमारी सरकार को केन्द्र सरकार ने जो निर्देशित किए, बिजली सुधार लागू किए थे, इसलिए ही एफआरबीएम में हमें 0.5 परसेंट लोन की एक्स्ट्रा छूट मिली, जो नियमों के तहत थी। आप कैसे कह सकते हैं कि हमारा मैनेजमेंट सही नहीं था?

बजट चर्चा के दौरान, हमारी अजमेर दक्षिण से माननीय सदस्या आती है, आपने यह बात कहीं कि रिन्युएबल एनर्जी का राज्यपाल के अभिभाषण में कोई जिक्र नहीं है। मैं कहना चाहूंगा कि फरवरी, 2023 के अभिभाषण के बिन्दु संख्या 51 में रिन्युएबल एनर्जी पर स्पष्ट लिखा है कि 2018 से अब तक 11 हजार 727 मेगावाट सौर ऊर्जा संयंत्र, 132 पवन ऊर्जा संयंत्र एवं 1690 मेगावाट के हाईब्रिड संयंत्र स्थापित किए गए हैं। यह खुद यही पर कहा गया है। आप पता नहीं कहां से बातें ले आते हो। लिखने की जरूरत नहीं है, मैं दे दूंगा, मेरे पास कॉपी है। ...(व्यवधान)...

माननीय सदस्य कह रहे थे कि 1 हजार मेगावाट की क्षमता भी हमारी सरकार ने विकसित की। मैं बताना चाहूंगा कि हमने दिसम्बर, 2023 तक 15 हजार 195 मेगावाट की क्षमता विकसित की थी। केवल एक साल 2021-22 में ही 5248 मेगावाट की क्षमता विकसित की। दिसम्बर, 2023 तक राजस्थान में सोलर क्षमता 15 हजार 195 मेगावाट, पवन ऊर्जा क्षमता 4442 मेगावाट, हाईब्रिड़ एनर्जी 1690 मेगावाट, बायोमास एनर्जी की क्षमता 128 मेगावाट प्रदेश में मौजूद है जो कि कुल मिलाकर पूरे देश में सबसे अधिक है।

यही नहीं, प्रधान मंत्री जी ग्लासगो की सीओपी समिट 2021 में बोलकर आए कि 2030 तक भारत 500 गीगावाट अक्षय ऊर्जा का उत्पादन करेगा। इसके भी सबसे ज्यादा लक्ष्य उन्होंने राजस्थान को दिए। क्योंकि वह जानते थे कि यहां कांग्रेस की सरकार है, अच्छा काम कर रही है, इसलिए इसको ज्यादा लक्ष्य देंगे, तो समय पर पूरे होंगे। यह बात मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा।

हमारी सरकार जैसे ही बदली, जो लक्ष्य 2030 तक था, अब आप लोगों को दो साल का तो वैसे ही दे दिया, अब वह 32 का कर दिया कि यह नहीं कर पाएंगे, इसलिए इनको दो साल एक्स्ट्रा दो, यह आप लोगों की हालत है।

श्री सभापतिः हो गया?

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): मैं एक बात कहना चाहूंगा, उसके बाद अपनी बात को समाप्त करूंगा। किसी सदस्य ने आरटीआई लगाई है। भरतपुर की आरटीआई लगाई है, मुख्य मंत्री जी के क्षेत्र की। वहां कोई कटौती नहीं है। माननीय मंत्री जी, वहां व्यवस्था हो सकती है तो पूरे प्रदेश में क्यों नहीं हो सकती? यह आरटीआई भी टेबल कर दूंगा। मुख्य मंत्री जी के क्षेत्र में जो लोग रहते हैं उनको बिजली की ज्यादा जरूरत है क्या?

डॉ. सुभाष गर्ग (भरतपुर): जिला है ...(व्यवधान)... नदबई विधान सभा क्षेत्र है, यह तो बता दो। ...(व्यवधान)...

VPS-RTM-02.08.202-17.20-3g

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): यह मैं वह जी.एस.एस. बता देता हूं, जहां पर यह जो सारा मामला है। यह जिगाना, सेंथारा, घाना है। ...(व्यवधान)...

श्री सभापतिः ठीक है, हो गया यह तो।

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): मेरे कहने का मतलब यह है कि पूरे प्रदेश की जो जनता है, वे सबके मुख्य मंत्री हैं। ...(व्यवधान)...

श्री सभापतिः श्री कुलदीपजी।

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): ऐसा मत करो, अन्याय मत करो, प्रदेश की जनता को बांटो मत। माननीय सभापतिजी, मैं भी इतने वर्षों से इस विधान सभा में आ रहा हूं। परसों विधान सभा के अन्दर भी बिजली चली गयी, परसों एस.एम.एस. हॉस्पिटल के अन्दर बिजली चली गयी, यह हालत है, यह हालत है, इस सरकार का इकबाल है! चाहे एक मिनट के लिए ही गयी हो पर गयी तो है। वह तो जनरेटर चल गया, यहां कोई मोमबत्ती के इंतजार में बैठते क्या? हद हो गयी। ...(व्यवधान)...

श्री सभापतिः विराजिये।

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): माननीय सभापति महोदय, आपको धन्यवाद।

श्री सभापतिः श्री कुलदीपजी।

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय कार्य मंत्री): माननीय सभापति महोदय, मेरे मित्र, इधर उधर की बातें न कर, यह बताओ कि बिजली तंत्र का भट्टा किसने बैठाया? हे मेरे मित्र, यह बताओ। ...(व्यवधान)...

श्री रफीक खान (आदर्श नगर): आपने। ...(व्यवधान)...

श्री सभापतिः श्री कुलदीपजी।

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): माननीय सभापति महोदय, दो लाइन मैं आपको कहना चाहता हूं।

मत कर परवाह उनकी जो आज देते हैं ताना,

मत कर परवाह उनकी जो आज देते हैं ताना,

झुका देंगे यह सिर, जब आयेगा तेरा जमाना,
लहरें बन जाये तूफान, कश्ती का काम है बहना,
कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना।
कहते रहो आप।

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय कार्य मंत्री): लोगों का काम है कहना पर कश्ती पार लगाना हमारा जमाना। ...(व्यवधान)...

श्री सभापति: प्रतिपक्ष के नेता शायर हो गये हैं। ...(व्यवधान)...

श्री कुलदीप (विराटनगर): माननीय सभापति महोदय, दो मिनट का समय निकल चुका है, आप इसका ध्यान रखियेगा। ...(व्यवधान)...

श्री सभापति: हो गया, हो गया। माननीय कुलदीपजी। श्रवणजी, आपका भी नम्बर आ रहा है। आपका नम्बर आ रहा है। इनके बाद आपका नम्बर ही है।

श्री कुलदीप (विराटनगर): माननीय सभापति महोदय, ढाई मिनट का समय निकल गया है, मैं आपसे यह आग्रह करूंगा कि समय का मेरा भी ध्यान रखियेगा। अभी आज जो बड़ा अति महत्वपूर्ण विषय चल रहा है बिजली विभाग का और बहुत सारे विषय निकलकर आये हैं। यह बात सही है कि मैं एक किसान का बेटा हूं, ग्रामीण क्षेत्र से आता हूं, एक ढाणी से निकल कर आता हूं और राजस्थान की जनता को बिजली मिलनी भी चाहिए। उस काश्तकार का क्या दोष है?

माननीय सभापति महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं आपके माध्यम से प्रतिपक्ष से कि इनकी सरकार पांच साल रही है। अभी नेता, प्रतिपक्ष ने बहुत सारे विषय रखे हैं और यह कहा है कि हमने ऐसा क्या किया, हमने इतने सारे संयंत्र लगा दिये। अगर आज राजस्थान में जो बिजली की स्थिति खराब हुई है, उसका सबसे बड़ा कोई जिम्मेदार है तो आपकी कांग्रेस पार्टी की सरकार जिम्मेदार है क्योंकि पांच साल में आपने बिजली पर ध्यान नहीं दिया।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से कुछ विषयों पर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। सच बहुत कड़वा होता है और मैं यह समझता हूं कि यह हमारा राजस्थान की जनता के द्वारा चुना हुआ मन्दिर है और इस मन्दिर में हम जनता के द्वारा आयी हुई बातों को यहां पर रखते हैं। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि 2019 में कोयला आधारित स्रोतों पर इनकी सरकार ने, कांग्रेस की सरकार ने 6000 मेगावाट स्थापित करने की घोषणा बजट में की थी तो मैं यह पूछना चाहता हूं नेता, प्रतिपक्ष से और विपक्ष से कि कम से कम इस बारे में सदन को अवगत कराते कि जो 6000 मेगावाट की आपकी सरकार ने घोषणा की थी, उसका हुआ क्या?

दूसरा विषय मैं यह आग्रह करना चाहता हूं कि बजट 2022 में 1320 मेगावाट छबड़ा में, 800 मेगावाट कालीसिंध में, 125 मेगावाट गुढा वेस्ट-बीकानेर में जो आपकी सरकार ने घोषणा की थी, उसके बारे में भी यदि आप यहां पर बताते तो अच्छा लगता कि जो आज

राजस्थान में हम जिस बिजली के लिए संघर्ष कर रहे हैं, आखिर में इसका जिम्मेदार कौन है? इसीलिए मैंने यह कहा कि आपकी सरकार का बड़ा दोष रहा है और मैं यह आग्रह करना चाहता हूं, माननीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से कि जो 2023 में आपकी कांग्रेस की सरकार ने 1100 मेगावाट लिग्नाइट की एक परियोजना लगाने की बाड़मेर में घोषणा की थी, उसके बारे में भी सदन को यदि बताते तो अच्छा लगता और अगर यह सारे संयंत्र आपके लग जाते यदि आपका पांच साल में यह काम पूरा हुआ होता तो आज राजस्थान की जनता को इस बिजली के संकट से जूझना नहीं पड़ता।

माननीय सभापति महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि इन्हीं की सरकार ने 2019 में आर.पी.ओ. की लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए 1 हजार 426 मेगावाट क्षमता की पवन ऊर्जा एवं 4 हजार 885 मेगावाट क्षमता की सौर ऊर्जा परियोजनाओं के विकास करने की घोषणा की थी और तो और 2023 के बजट में 11 हजार मेगावाट अक्षय ऊर्जा परियोजना की घोषणा की थी।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से विपक्ष से यह पूछना चाहता हूं कि इसके बारे में भी आप जिक्र करते कि आपकी सरकार ने क्या किया? हमारे राजस्थान के मुख्य मंत्री महोदय ने इतना शानदार और जानदार बजट दिया जिसकी चर्चा पूरे राजस्थान में ही नहीं बल्कि पूरे देश में इस बात की चर्चा की जा रही है, उसके ऊपर भी आपको आपत्ति है कि आप इस योजना को कैसे पूरी करेंगे लेकिन मैं यह कहना चाहता हूं विपक्ष से कि आपने पांच साल में जो-जो घोषणाएं की उन घोषणाओं को भी आपने लागू करने का काम नहीं किया और सबसे बड़ा जो संकट राजस्थान में आया वह तत्कालीन कांग्रेस पार्टी की सरकार के कारण से आया है।

माननीय सभापति महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि एन.टी.पी.सी. लिमिटेड से इन्होंने 500 मेगावाट की बिजली परियोजना स्थापित करने की बात कही है और इन्होंने भूमि का आवंटन भी नहीं किया, ऐसी हालत आपकी पार्टी की सरकार में रही है। अभी प्रतिपक्ष के माननीय नेता यह कह रहे थे कि हमने हमारे समय में इतनी बिजली राजस्थान में पैदा की और इतनी बिजली हमने खरीदी है। मेरे पास कुछ आकड़े अभी आये हैं। हीटवेव चली राजस्थान में, वह तो न तो कांग्रेस के लोग लेकर आये और न भारतीय जनता पार्टी के लोग लेकर आये। यह तो कुदरत का खेल है इसलिए प्रकृति किसी की मानती भी नहीं है, प्रकृति का कोई इलाज भी नहीं है। प्रकृति का ऐसा कहर पूरे देश में चला, उसके कारण से बिजली का संकट बढ़ा।

माननीय सभापति महोदय, मैं यह आग्रह करना चाहता हूं, 2022 का आंकड़ा भी मेरे पास में है, 2023 के आंकड़े भी मेरे पास है, 2024 के आंकड़े भी मेरे पास है। अप्रैल माह, 2022 में, मैं लाख यूनिट की बात कर रहा हूं, आपकी सरकार ने 2750 लाख यूनिट अप्रैल माह में और हमारी सरकार ने अभी 2716 लाख यूनिट बिजली की जो मांग थी, मई में 2919 और 2024 में 3318 यानी, हमारी सरकार में अभी इस समय हीटवेव के कारण से 25

परसेंट मांग बढ़ी है। आपके अप्रैल माह में भी दस परसेंट मांग बढ़ी और जून माह की यदि मैं बात करूं तो आपके समय में 2962 लाख यूनिट की मांग थी और हमारे समय में इसी माह में 3438 लाख यूनिट की मांग थी यानी, 27 परसेंट मांग राजस्थान में बढ़ी है। माननीय सभापति महोदय, मैं यह निवेदन करना चाह रहा था कि जुलाई माह में 2341 लाख यूनिट और इस समय हमारे 2024 में 3060 लाख यूनिट बिजली की मांग बढ़ी, जिसमें 13 परसेंट की बढ़ोतरी हुई है। ऐसी हालात इस प्रकृति के कारण से हुई है।

हमारे माननीय नेता, प्रतिपक्ष ने बहुत सारे विषय रखे हैं। मैं उनसे यह आग्रह करना चाहता हूं, आपकी सरकार के आकड़े हैं बहुत सारे, मैंने पहले भी यह कहा कि मैं किसान का बेटा हूं और हो सकता है कि बाकी माननीय सदस्य तो कहां पर रहते होंगे, लेकिन शुद्ध रूप से मैं ढाणी में रहता हूं और वहीं रहकर काम करता हूं। जितनी बिजली की हमारे इलाके में कटौती होती है, वह सबके साथ ही होती है, लेकिन आपके समय के कुछ आकड़े, मैंने 2022-23, 2023-24 के लिये हैं। अप्रैल माह में 4647 लाख यूनिट और मई में 1107 लाख यूनिट, जून में 1626 लाख यूनिट और जुलाई माह में 195 लाख यूनिट, यानी मैं बात करूं बढ़ोतरी 2024 से, जिसको कम्पेयर मैं करता हूं तो हमारे समय में 52 लाख यूनिट, 844 लाख यूनिट, 1233 लाख यूनिट और 577 लाख यूनिट बिजली यह प्रतिदिन के हालात रहे हैं और कटौती, आपके समय की यदि मैं बात करूं, माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से नेता, प्रतिपक्ष से यह पूछना चाहता हूं कि आपके समय में अप्रैल माह में 3.48, मई में, हां, घंटे की बात है यह। साथ में मई माह में 1.14, जून में 1.34 और जुलाई में 0.24 यह कटौती घंटों में पूरे राजस्थान में आपकी सरकार के समय हुई है, यह आंकड़े हैं, इसको आप शुद्ध भी कर लीजिए और एक बार आपके आंकड़े दुरुस्त भी करिये। हमारे 2024 के जो हमारे माह चल रहे हैं, अप्रैल में 0.04, मई में 0.43, जून में 1.10, जुलाई में 0.49, ऐसी कटौती हुई है और मैं इतना ही कह सकता हूं कि वास्तव में ग्रामीण क्षेत्र में जो बिजली की कटौती हुई है, इसके समय में किसान को वास्तव में बहुत सारी दिक्कतें हुई हैं।

अभी बात चल रही थी नुकसान-नफे की, बहुत सारी बातें नेता, प्रतिपक्ष महोदय के द्वारा कही गयी हैं। कुछ आकड़े इस प्रकार के हैं जो राजस्थान को रसातल में भेजने का यदि किसी ने काम किया तो आपकी पार्टी ने, आपके सरकार के समय आप लोगों ने किया। अगर आपका मैनेजमेंट अच्छा होता, यदि आपका जहां पर बिजली उत्पादन होता है, अगर उनका मेंटिनेंस ठीक प्रकार से होता और आपका प्रोडक्शन अच्छा होता, जितनी डिमांड राजस्थान में है, कितनी बिजली कंज्यूम हो रही है, अगर उसका ठीक प्रकार से आप मेंटिनेंस करते या उसके लिए अच्छा इंतजाम करते और संयंत्र लगाने का काम करते तो आज राजस्थान की ऐसी स्थिति नहीं होती।

SSY/RTM/02.08.2024/17:30/3H

जो किसान 24 घंटे गर्मी में मरता है, जिम्मेदार कौन? केवल भाषण देने से काम नहीं

चलता।

सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इनके समय 2023 में जो इन्होंने बिजली खरीदी, उसका मैं विवरण भी आपके सामने रखना चाहता हूं। अप्रैल माह में 2594 लाख यूनिट, मई माह में 5690 लाख यूनिट, जून माह में 4705 लाख यूनिट, जुलाई में 5080 लाख यूनिट। हमने कितनी यूनिट बिजली खरीदी, इसका मैं बताना चाह रहा हूं, अप्रैल माह में 3543, जो मई में आपने 5690 लाख यूनिट बिजली खरीद की, हमने 15436 लाख यूनिट बिजली, यानि आपसे तीन गुणा बिजली राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, भजन लाल जी की सरकार ने खरीदने का काम किया है। जो राजस्थान की जनता के काम आ रहा है।

साथ ही जून माह में आपका 4705 लाख यूनिट और हमने कितनी खरीदी? 11078 लाख यूनिट हमने परचेज की है। उनके मैं रेट भी बताना चाहता हूं। ऐसी क्या मजबूरी कांग्रेस सरकार की थी? कांग्रेस ने आखिर में इस पैसे का दुरूपयोग कैसे किया? ऐसे कौन लोग आपकी सरकार में थे जो राजस्थान की जनता के खून-पसीने की गाढ़ी कमाई के पैसे का दुरूपयोग किया गया? उसका नुकसान राजस्थान की सरकार को, राजस्थान की जनता को किया गया।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से आग्रह करना चाहता हूं कि इन्होंने जो बिजली खरीद अप्रैल माह में की, 4.94 रुपये के हिसाब से खरीद की, हमने 4.29 के हिसाब से परचेज की। मई में इन्होंने 5.43 रुपये के हिसाब से खरीद की, हमने 4.66 के हिसाब से खरीद की। इन्होंने जून माह में 6 रुपये प्रति यूनिट के हिसाब से बिजली खरीद की, हमारी सरकार ने 4.91 के हिसाब से बिजली खरीद की। ऐसे ही इन्होंने जुलाई माह में 6.03 के हिसाब से बिजली परचेज की और हमारी सरकार ने 4.76 रुपये के हिसाब से बिजली खरीद की। अब आप इसको कंपेयर कर लीजिये। आपके सामने ऐसी क्या मजबूरियां थीं कि राजस्थान की जनता का जो पैसा था, उसको आपने खर्च करने का प्रयास किया?

सभापति महोदय, बहुत सारे विषय अभी चल रहे थे। लेकिन मैं कुछ जनरल बिन्दु, बहुत सारे बिन्दु हैं, हमारी सरकार ने कितने भी एमओयू किये, यह भी इनको पीड़ा है। लेकिन मैं कुछ विषयों पर माननीय मंत्री महोदय का ध्यानाकर्षित कराना चाहता हूं, राजस्थान में सबका विषय है। अभी नेता, प्रतिपक्ष महोदय ने एक बात और कही कि बहुत सारी कैजुअल्टी राजस्थान में बिजली को लेकर होती हैं। वास्तव में होती हैं। मेरे विधान सभा क्षेत्र विराटनगर में आपके कांग्रेस के 5 साल में 15 लोगों की डैथ हुई है। जिसमें आपकी सरकार ने मात्र 3 या 4 लोगों को पैसा देने का काम किया है। उनको सहायता देने का काम किया है।

मैं, बिजली मंत्री महोदय आपसे एक आग्रह करना चाहता हूं कि अभी मेरी विधान सभा में 10 दिन पहले ऐसी कैजुअल्टी हुई है। राजस्थान के जो बड़े ग्रिड हैं, जहां से बिजली की सप्लाई होती है, वहां पर जो बड़ी-बड़ी कंपनियां काम करती हैं, उनको मेन पावर के लिए काम करने का टेंडर मिलता है। वह संविदा के आधार पर ऐसे कर्मियों को रखते हैं, जो ना

डिप्लोमाधारी होते हैं, ना डिग्रीधारी होते हैं। उनकी लापरवाही के कारण से बहुत सारी कैजुअल्टी राजस्थान में होती हैं।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से आग्रह करना चाहता हूं कि ऐसी कंपनियों के खिलाफ कार्यवाही भी करिये। बिना किसी डिप्लोमा, डिग्री के अगर ऐसी कंपनियां संविदा पर कर्मी रखती हैं, जिनके कारण से दुर्घटनाएं होती हैं, उनको रोकने के लिए उनको ब्लैक लिस्टेड करिये और उनके खिलाफ कानूनी कार्यवाही भी होनी चाहिए।

सभापति महोदय, साथ में एक और निवेदन करना चाहता हूं कि राजस्थान में एक और भी कारण है। उसका कारण मैं बताना भी चाहता हूं। इस पर ध्यान, 5 साल पता नहीं कांग्रेस के मित्रों के सामने क्या समस्याएं थी, अब जितने हमारे ग्रिड बने हुए हैं, अगर उनके सेपरेशन का काम यदि आप लोग करते, उनको सेपरेट करते, बड़े-बड़े कस्बे हैं, जिनमें किसी की पापुलेशन 25 हजार है, किसी की 20 हजार है। मेरे इलाके में ऐसे बहुत सारे, हमारी सरकार बनने के बाद, मैंने कुछ जो हमारे ग्रिड बने हैं, उनको सेपरेट करवाने का काम किया है। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं राजस्थान के मुख्य मंत्री महोदय का और माननीय ऊर्जा मंत्री जी का कि आपने जो यह बड़े ग्रिड थे, इनको सेपरेट करने की योजना आप लेकर आये हो। मैं आग्रह करता हूं कि यदि यह सेपरेशन का काम हो जायेगा तो मैं इतना कह सकता हूं कि आज जैसे पावटा कस्बे की पापुलेशन 25 हजार है, वहां जब शट डाउन लिया जाता है तो पूरे पावटा कस्बे की लाइट कट जाती है।

महोदय, मेरा दो मिनट का समय माननीय नेता, प्रतिपक्ष ने खर्च किया था इसलिए मैं माफी चाहता हूं। मैं अपने विचार जो सेंसेटिव बिन्दु हैं उस पर भी रखना चाहता हूं। जब शट डाउन होता है तो उस समय पूरे शहर की, पूरे कस्बे की लाइट कट जाती है। इसलिए मैं, मंत्री महोदय आपसे आग्रह करुंगा कि पूरे राजस्थान में नहीं, मेरे विधान सभा क्षेत्र विराटनगर की तो मैं बात करता ही हूं, मेरे ऐसे बहुत सारे ग्रिड हैं कारोली बड़ा ग्रिड है, भांकरी प्रागपुरा ग्रिड है, तुलसीपुरा ठिकरिया ग्रिड है, पावटा ग्रिड है, लुहाकड़ा ग्रिड है, बड़नगर, विराटनगर, नवरंगपुरा, कुलडा, रामपुरा, झाझियाकलां, छापड़ा, गोविन्दपुरा, बड़ीजुड़ी, साइवाड़, नाथावाला, चिमनपुरा ऐसे बहुत सारे ग्रिड हैं, मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूं कि ये सब जो बड़े ग्रिड्स हैं, इन पर आप सेपरेट करवाने का काम प्रारंभ करिये। मैं इतना कह सकता हूं कि उससे हमारे काश्तकार को जो बिजली नहीं मिलती है, उसको प्रोपर समय पर बिजली मिलेगी।

सभापति महोदय, मैं एक निवेदन करना चाहता हूं, यह मैंने पहले भी कहा था, यह सदन हमारा पवित्र मन्दिर है, यहां पर आकर केवल हाय-हल्ला करने से काम नहीं चलता। लक्ष्मणगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य बहुत वरिष्ठ नेता हैं। आज हैं नहीं। मेरी कहने की कुछ इच्छा भी है। ऐसे बिन्दु लेकर आते हैं, आप लोगों का स्वागत है, लेकिन मैं प्रार्थना करना चाहता हूं कि ऐसे विषयों पर केवल वैल में खड़ा होकर, ऐसे-ऐसे इशारे करके, सबको बुलाकर हाय-हल्ला करने से काम नहीं चलेगा।

मैं विपक्ष से भी आग्रह करना चाहता हूं कि अच्छी कोई योजना यदि आपके दिमाग में

है, कोई प्लानिंग आपके दिमाग में है तो सरकार के सामने रखिये।

श्री सभापतिः विराजिये।

श्री कुलदीप (विराटनगर): आप भी बराबर के हमारे हिस्सेदार हैं। राजस्थान में आपका भी राज रहा है। आप ऐसे प्रस्ताव रखिये जिससे हमारी सरकार, जब जनता को हमने भगवान, ईश्वर मानकर काम करने का संकल्प लिया था तो हम आपकी बात पर भी विचार करेंगे। इस बात के लिए जब राजस्थान की जनता से हमने वादा किया है तो आपकी बात भी सुनेंगे। हमें कहां हर्ज है।

इसलिए मैं आग्रह करुंगा कि अच्छे सुझाव लेकर आइये। केवल यहां वैल में आकर, खड़े होकर अखबारों की सुर्खियां बनने के लिए, टीवी में सुर्खियां बनने के लिए इस प्रकार की बातें लेकर आते हो उससे काम चलने वाला नहीं है।

श्री सभापतिः श्री श्रवण कुमार।

श्री कुलदीप (विराटनगर): सभापति महोदय, यह मैंने पहले भी कहा था कि सच बड़ा कड़वा होता है। सुनने में तकलीफ होती है। आपने समय दिया, इसके लिए धन्यवाद।

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): जीत जाओगे, जीत जाओगे, अब की बार बोल लो।

सूचना

NPCIL प्रोजेक्ट की स्थापना के क्रम में पुलिस द्वारा आदिवासियों पर बल प्रयोग

श्री जयकृष्ण पटेल (बागीदोरा): पाइंट ऑफ इन्फोर्मेशन। सर, पाइंट ऑफ इन्फार्मेशन, प्लीज।

हमारे वहां पर जो NPCIL प्रोजेक्ट स्थापित हो रहा था, उसमें भूमि अधिग्रहण करने के लिए शासन, प्रशासन ने जो वहां पर पुलिस द्वारा आम जन को खदेड़ा गया और जेल के अन्दर भरा गया है।

श्री सभापतिः संज्ञान में आ गया।

श्री जयकृष्ण पटेल (बागीदोरा): हम आपके माध्यम से सरकार को अवगत कराना चाहते हैं कि वहां पर शांति व्यवस्था बनाई जाये।

श्री सभापतिः श्री श्रवण कुमार।

श्री थावर चन्द (धरियावद): प्रदर्शन चल रहा है और वहां पर आदिवासियों के साथ मारपीट हो रही है। उनको जेलों में डाला जा रहा है ...(व्यवधान)...

श्री सभापतिः आपकी बात सदन में आ गई ना। समझ में आ गयी। सदन में आ गयी बात। बैठे हैं। विराजें।

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय कार्य मंत्री): माननीय सभापति महोदय, एक सेकण्ड। माननीय साथी ने जो विषय रखा।

श्री सभापतिः जरूर।

श्री यूनुस खान (डीडवाना): टाइम तो बढ़वा लिया ना आपने।

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण): टाइम नहीं बढा है।

सदन की कार्यवाही

विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय कार्य मंत्री): सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन का समय एक घंटे के लिए और बढ़ाया जाय।

श्री सभापति: क्या सदन की सहमति है?

(स्वीकृत)

सदन का समय एक घंटे के लिए बढ़ाया गया।

सूचना

NPCIL प्रोजेक्ट की स्थापना के क्रम में पुलिस द्वारा आदिवासियों पर बल प्रयोग

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय कार्य मंत्री): फिर वह आ जायेंगे। गर्ग साहब आ जायेंगे, तब। एक मिनट, जवाब दे दूं इनका।

माननीय सदस्यों ने जो विषय रखा है, इसकी मैंने अभी प्रारंभिक जांच प्रारंभ की। बाकी डिटेल तो सम्बन्धित विभाग से, कलेक्टर, एसपी से रिपोर्ट लेकर सदन में बता दिया जायेगा।

केन्द्र सरकार का NPCIL प्रोजेक्ट बन रहा है। भूमि अवाप्ति बहुत पहले ही हो चुकी है। पूरी भूमि कंपनी के पास है। प्रोजेक्ट वाले के पास है। उस भूमि पर चारदीवारी बनाने का कार्य सुबह से शांतिपूर्वक चल रहा है।

श्री जयकृष्ण पटेल (बागीदोरा): सर, शांतिपूर्वक नहीं चल रहा है। प्लीज सर, यह गलत बात है ...(व्यवधान)... वहां पर आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं।

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय कार्य मंत्री): बीच में नहीं बोलते हैं। बीच में नहीं बोलते हैं।

श्री जयकृष्ण पटेल (बागीदोरा): आम जनता परेशान है।

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय कार्य मंत्री): बीच में नहीं बोलते हैं। सीखो पहले बोलना विधान सभा में। ...(व्यवधान)... बैठो, जवाब सुनना पड़ेगा ना। जब आप विषय रखो तो जवाब सुनिये ना। ...(व्यवधान)... विषय रखा है, जवाब सुनिये।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, विराजें।

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय कार्य मंत्री): विषय रखा है, जवाब सुनिये।

श्री सभापति: माननीय सदस्य ...(व्यवधान)...आप विराजिये।

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय कार्य मंत्री): जवाब सुनिये, आप कौन, बीच में बोल रहे हो ...(व्यवधान)...

श्री सभापति: आप विराजें। ...(व्यवधान)...

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय कार्य मंत्री): जवाब सुनिये। बैठिये।

श्री सभापति: आप तो विराजो। ...(व्यवधान)...

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय कार्य मंत्री): आप जवाब सुन लीजिये। ...(व्यवधान)...

श्री सभापति: आप विराजिये। ...(व्यवधान)...

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय कार्य मंत्री): शांति पूर्वक चल रहा है ...(व्यवधान)...

श्री सभापतिः आराम से, बात तो सुन लो भाई। ...(व्यवधान)...

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय कार्य मंत्री): जो जमीन अवाप्त की, उसका मुआवजा दिया जा चुका है।

श्री सभापतिः मंत्री जी कुछ कह रहे हैं। ...(व्यवधान)...

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय कार्य मंत्री): घर जिन्होंने मांगे थे, उनको घर दिये जा चुके हैं।

श्री सभापतिः मंत्री जी कुछ कह रहे हैं।

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय कार्य मंत्री): और मौके पर पूर्ण रूप से शांति है। कोई अव्यवस्था नहीं है। यह सिर्फ सनसनी पैदा करने के लिए गलत तथ्यों के साथ जानकारी दी गई है। इसके लिए हम नियमों के अनुसार इनके विरुद्ध कार्य करेंगे ...(व्यवधान)... गलत जानकारी देने के लिए हम इनके विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही करेंगे।

श्री सभापतिः श्री श्रवण जी ...(व्यवधान)... श्री श्रवण जी। माननीय सदस्य, विराजो ...(व्यवधान)... आप विराजिये। रफीक जी, विराजें ...(व्यवधान)... क्या है यह ...(व्यवधान)...विराजें, यह सदन सबकी सुनने वाला है ...(व्यवधान)... आप विराजो।

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): संज्ञान में आ गया ना।

श्री सभापतिः विराजिये। ...(व्यवधान)...

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): माननीय सदस्य, यह संज्ञान में आ गया है। कार्यवाही होगी, ऐसे करने से थोड़े ही हो जायेगी।

श्री सभापतिः श्रवण जी।

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): बैठे ना। संज्ञान में आ गया ना। सरकार के संज्ञान में आ गया और क्या करोगे?

Spp/Rtm/02.08.2024/17.40/3j

श्री सभापतिः सरकार के संज्ञान में बात आ गयी है, उसमें उचित जवाब भी मिल जायेगा। ..(व्यवधान).. आपके सदस्य बोल रहे हैं। ..(व्यवधान).. माननीय सदस्य श्री श्रवण जी। ..(व्यवधान).. आपके मैम्बर बोल रहे हैं। ..(व्यवधान).. आपके सदस्य बोल रहे हैं। ..(व्यवधान)..

राज्य में बिजली की स्थिति पर विचार

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): अपने सदस्य बोलते हैं, आप हल्ला मचा रहे हो।..(व्यवधान).. माननीय सभापति महोदय, आज बिजली और पानी जैसी महत्वपूर्ण और जीवन की बहुत ही जरूरी चीजें हैं, उनके ऊपर आपने चर्चा करायी। ..(व्यवधान)..

श्री सभापतिः श्रवण जी, आपसे आग्रह है 17.40 पर आप बोल रहे हैं। आपको 10 मिनट का समय है। आपको 10 मिनट का समय दिया है।..(व्यवधान)..

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): शुरू नहीं किया, उससे पहले कहना शुरू कर दिया।

..(व्यवधान).. मैं यह कह रहा हूं -

'जिन्दगी में शौक पाला नहीं जाता

शीशे का प्याला कभी उछाला नहीं जाता।'

श्री सभापति: शुरूआत अच्छी करो। क्यो शेर बोलना है। ..(व्यवधान)..

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): सभापति जी, आप डिस्टर्ब कर रहे हो फिर कहोगे कि आपका टाइम हो गया। माननीय संसदीय कार्य मंत्री महोदय, बताओ कुछ, मदद करो मेरी। मदद करो।

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय कार्य मंत्री): आपका समय बाकी है।

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): बाकी है। अभी शुरू हुआ है न? 17.41 से मानना।

'जिन्दगी में शौक पाला नहीं जाता

शीशे का प्याला कभी उछाला नहीं जाता।

मेहनत से संवर जाती है जिन्दगी

हर काम तकदीर पर छोड़ा नहीं जाता।'

माननीय सभापति महोदय, बहुत लम्बे और ...(व्यवधान)..मेरा टाइम देख लेना।

श्री सभापति: श्रवण जी एक सैकण्ड बिराजें। जोगेश्वर जी गर्ग सरकारी मुख्य सचेतक कार्य सलाहकार समिति का सातवां प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगे।

समिति प्रतिवेदन

कार्य सलाहकार समिति का प्रतिवेदन (क्रम संख्या 7)

श्री जोगेश्वर गर्ग (सरकारी मुख्य सचेतक): माननीय सभापति महोदय, मैं आपकी अनुमति से कार्य सलाहकार समिति के सातवें प्रतिवेदन का उपस्थापन करता हूं।

कार्य सलाहकार समिति की बैठक दिनांक 02 अगस्त, 2024 को मध्याह्न पश्चात् 3.00 बजे माननीय अध्यक्ष के वेश्म (चैम्बर) में हुई। समिति ने निर्णय लिया कि सोमवार, दिनांक 05 अगस्त, 2024 व मंगलवार, दिनांक 06 अगस्त, 2024 को सदन में लिये जाने वाले कार्य का नियतन निम्न प्रकार किया जाय:-

शनिवार, दिनांक 03 अगस्त, 2024 रविवार, दिनांक 04 अगस्त, 2024	बैठक नहीं होगी।
सोमवार, दिनांक 05 अगस्त, 2024	विधायकों के अनुभवों एवं नवाचारों पर विचार।
मंगलवार,दिनांक 06 अगस्त,2024	राज्य में आपदा प्रबंधन की स्थिति पर विचार।

माननीय सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन कार्य सलाहकार समिति के सातवें प्रतिवेदन पर अपनी सहमति प्रकट करता है।

श्री सभापति: प्रश्न यह है कि यह सदन कार्य सलाहकार समिति के सातवें प्रतिवेदन पर

अपनी सहमति प्रकट करता है?

(स्वीकृत)

सदन द्वारा प्रतिवेदन पर सहमति प्रकट की गयी।

माननीय श्रवण जी, आपका समय अब शुरू होता है।

राज्य में बिजली की स्थिति पर विचार

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): अब शुरू होगा न। माननीय सभापति महोदय, कुछ समय पहले बिजली के पूर्व मंत्रीजी बोल रहे थे, उन्होंने सारी बातें ऐसी बतायीं कि पूरा राजस्थान आप लोगों ने बसाया है और जो सुविधा दे रहे हो, वह भी आप ही दे रहे हो। आप देखिये कोई महिला का घरवाला एक्सपायर हो जाता है और वह विधवा हो जाती है और सारा गांव यह कहने लग जाये, विधवा हो गयी, विधवा हो गयी तो वह मर ही जायेगी। आप तो जब से बैठे हो सात महीने से, आपने क्या किया? आपने क्या किया? आप क्या करोगे, यह बोलो। आप क्या करना चाहते हो? देखिये आप, जो व्यक्ति दूसरों पर अंगुली उठाना शुरू कर देता है उसकी अंगुली अपने आप ही कट जाती है। आपको मैं सलाह दे रहा हूं, मेरा 44 साल का बहुत लम्बा अनुभव है, अगर आप ऐसे ही करते रह जाओगे आप पहले, आप पहले तो ट्रेन निकल जायेगी। एक बार ये, एक बार आप, क्यों आते हो? आप दोनों ही गड़बड़ हो। आप दोनों ही गड़बड़ हो। मैंने एक दिन पहले भी कहा था कि जिसकी बीवी भाग जाये और आया और रात ले जाये, वह अपने आपको निकम्मा समझ ले आज से। अब देखिये, आप जब से आये हो, यही बातें करते हो।

डा. ऋतु बनावत (बयाना): यह कोई तरीका है क्या? महिलाओं की बात आप इस तरह से कैसे कह रहे हो? यह कोई तरीका है? ..(व्यवधान)....

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): क्या हो गया? क्या कह दिया? ..(व्यवधान).... क्या कह दिया? अगर आपको बुरा लगा तो ..(व्यवधान).... आप देखिये, जो व्यक्ति दूसरों पर थोपता है कि आपने काम नहीं किया। मैं कह रहा हूं आपको मौका मिला हुआ है न, आप करिये न, हम मना थोड़ी करेंगे। पी एच ई डी मंत्रीजी कह रहे हैं कि यह गड़बड़ हुई। आप जांच करवाइये न। आपके हाथ में कलम है और जांच करवाकर जो दोषी हैं, उनको जेल में भेजिये। आपको कौन मना करता है? और मना करेगा तो उसको कहेंगे कि आप इसके साथी हो। बिजली मंत्रीजी भी यह कह रहे थे कि बहुत बुरा हो रहा है। मैं कह रहा हूं बुरा हो रहा है न, सारा सिस्टम कोलैप्स हो रहा है और जब तक देश में ठेका प्रथा रहेगी, ऐसे ही होता रहेगा। एडमिनिस्ट्रेशन जिसका कमजोर होता है, वह ऐसे ही करता है न। आप देखिये, आपको मौका मिला हुआ है, आप बड़े आराम से, तसल्ली से अधिकारी आपकी मानते हैं, कलम आपके हाथ में है। मंत्र और तंत्र दोनों आपके पास मौजूद हैं। अगर मंत्र मारेगा तो तंत्र अपने आप फडफड़ायेगा। आप सही करिये, हम आपके साथ हैं। पर आप यह मत करिये काम करने के टाइम में, आज पूरे 7 महीने हो चुके आपको। 3 तारीख को 8 महीने हो जायेंगे। 8 महीने में सूरजगढ़ विधान सभा में एक भी ट्यूबवैल नहीं खुदा और भाषण दे रहे थे सारा पानी-पानी

कर दिया। बाबा, असत्य के पुलिन्दे भी अच्छे होते हैं। आपने बिजली का एक भी काम किया नहीं। ऐसे लग रहा है कि सारा बिजलीमय हो गया है। बिजली का काम भी नहीं हुआ है। अब की बार राजस्थान में टेम्प्रेचर की बात कर रहे थे। टेम्प्रेचर 40 हो, 45 हो, यह राजस्थान पहले का बसा हुआ था, आज तो बसा नहीं। कभी टेम्प्रेचर बढ़ जाता है, कभी घट जाता है। बिजली आपने दी ही नहीं। अब की बार तो बिजली की त्राहि-त्राहि रही है फिर उसके बाद में भी, अभी मेरे एक साथी कह रहे थे आपने छह रुपये यूनिट खरीदी। सुबह बाजार में जाते हैं सब्जी का भाव होता है दो रुपया और शाम को होता है चार रुपया। भाव बदलते रहते हैं, आपको उससे क्या लेना है? सरकार में जो बैठेगा, वह मंहगी और सस्ती नहीं देखेगा। जनता उनके लिये पहले है। जब आप वोट लेने के लिये गये थे और जिस झोपड़ी में बाबा बैठा था, आपने कहा था बाबा, वोट दे तेरे को लाइट देंगे, पानी देंगे, चिकित्सा देंगे, शिक्षा देंगे, आप कहकर आये थे न। बाबा वहीं बैठा है, आपने आज तक एक बल्ब नहीं लगाया। बातें कर रहे हो। ..(व्यवधान).. मेहरबानी करके लम्बाई बहुत ज्यादा दे दी, दिमाग नहीं दिया, बैठ जाओ। लम्बाई खूब दी पर दिमाग नहीं दिया।

माननीय सभापति महोदय, मैं यह कह रहा हूं कि जो व्यक्ति काम करेगा, उसको कोई मना नहीं करेगा। अभी हमारे एक साथी यह कह रहे थे। अभी हमारे पूर्व मंत्री कह रहे थे, कोठारी साहब के आने के बाद बिजली में बहुत ज्यादा सुधार हुआ। कौन मना कर रहा है? ..(व्यवधान)..

श्री सभापतिः आप बिराजें।

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): आप हिन्दुस्तान में सनातन धर्म की बातें कर रहे हैं, वह बैठ जाओ। अभी कह रहे थे कोठारी साहब के आने के बाद में बिजली में बहुत सुधार हुआ है। कोठारी जी मरे तो नहीं न। जिन्दा है न, लेकर आओ न। लेकर आओ न। पर आपकी पैसे के लेनदेन में बिगड़ी हुई है उससे। आपने कहा कि कोठारी ज्यादा पैसे खा गया, हमको कम दिया। इस मामले में आपने उसको निकाल दिया। उस समय मैं यहां पर एम एल ए था। आप देखिये, बिजली की बात कर रहे हो, बिजली आप पैदा करने की बात करोगे तो पैदा करनी पड़ेगी। आप राज कर रहे हो। राज करेगा तो उसको जनता की सेवा तो करनी ही पड़ेगी।

आपने अभी कहा चुनाव में खूब असत्य बोले। पर असत्य बोलने के बाद में क्या मिल गया हमको? कुछ नहीं मिला न। आप क्या सोचते हो कि आप ही समझदार हो। आपका भी एक वोट पड़ता है, झोपड़ी में बैठा हुआ बाबा का भी एक वोट पड़ता है। वह समझता है कि हमारे को असत्य बोलकर गये है तो इस कोने में बैठा देते हैं। क्या हो गया असत्य बोलने से, मिला कुछ? तुम बोलकर देख लेना। तुम भी बोलकर देख लेना। 22 आओगे और जो आज की स्थिति में आप चल रहे हैं तो पंजा भी नहीं मंडेगा। काम करना सीख जाओ, काम करोगे तो जनता अपने आप देखेगी। पूरे हिन्दुस्तान में तीन-तीन बार एमपी में राज कर लिया, 35 साल ज्योति बसु ने कर लिया। काम करने से ही तो किया न। इसलिए मैं कह

रहा हूं, इनकी चर्चा मत किया करो, आप तो काम किया करो। मैं बता रहा हूं, बिजली बोर्ड की हालत क्या है। एक दिन, आपके मंत्री जी बैठे थे, मैं भी बैठा था, मामला यह चला कि हॉस्टलों के चार्जेज घरों के बराबर लगेंगे और मंत्री जी ने हां भर ली।

क्यों मंत्री जी, असत्य तो नहीं बोल रहा हूं न? आपके एमडी बैठे थे और एमडी साहब ने टेलीफोन भी कर दिया कि वीसीआर जो भरी है, उसे काट दीजिये दोबारा। वह एससी आज तक नहीं काटी, बोले कहने से क्या होता है, जब आपके ऑर्डर इस तरह से टांय टांय फिस्स हो जाते हैं, उसके बाद कहां बचा है, एडमिनिस्ट्रेशन कहां बचा है?

Jyg/rtm/020824/17.50/3k

टेलीफोन हो जाए अधिकारी के पास आपका तो टेलीफोन के अन्दर कपड़कान आनी चाहिए कि वो जला हुआ जा रहा है और जलता-जलता जाए तो अधिकारी खड़ा हो जाएगा, सोचेगा कि क्या आ गया? आपका टेलीफोन कोई मानता नहीं, नीचे वाला कोई सुनता नहीं। कलेक्टर की बाबू नहीं मानता, बाबू की सिपाही नहीं मानता। यह मामला बहुत बड़ा गम्भीर है, इस पर विचार कीजिए। राजस्थान में अनुशासन बहुत तगड़ा था, आप लोगों ने उस अनुशासन को जीरो कर दिया। ..(व्यवधान).. जीरो कर दिया इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि ये जो बातें आप टेलीफोन पर कहो और बात करो उसका इम्प्लीमेंट होना चाहिए। ..(व्यवधान).. पहले विधान सभाओं में क्वेश्चन आ जाता था तो मंत्री को रात को बुखार हो जाती थी। हमारा देखा हुआ काम है। आप भी हमारे साथ के हो, पहले विधान सभा में क्वेश्चन आता था तो मंत्री को रात को बुखार आ जाती थी कि सुबह पूछेंगे तो क्या होगा? पर होता कब था? पहले वाले अध्यक्ष ने किया या अब वाले अध्यक्ष ने किया, मुझे मालूम नहीं, एक क्वेश्चन उसी कांस्टीट्यूएंसी का पूछेगा, दो क्वेश्चन में सारा खतम हो जाएगा। यह हमने देखा हुआ है, सारा सदन बोलता था और क्वेश्चन में मंत्री के होश उड़ जाते थे। अब तो बढ़िया काम हो रखा है, अध्यक्ष ने आपको फंसा रखा है, दो क्वेश्चन, डोडाराम, पोखाराम, मोलाराम, तीन बोल गए, बैठ जाओ। क्या है ये? अगर पूरे राजस्थान की समस्या है, उसका निवारण नहीं कर सकते, मंत्री जवाब नहीं दे सकता तो किस बात का राज कर रहे हो आप? मोटर-गाडियों के लिए कर रहे हो? ..(व्यवधान)..

श्री श्रीचन्द कृपलानी (निम्बाहेड़ा): यह आप किसको कह रहे हो? यह शुरू किसने किया?

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): आपके दिमाग नहीं है। यह कोई बचपन में गड़बड़ हुई हुई है, कोई खास बात नहीं है। ..(व्यवधान)..

माननीय सभापति महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र में 2021 में 2800 कनेक्शन हुए और आपने 2800 कनेक्शन तो कर दिए लेकिन वो सिस्टम में आपने कोई बदलाव नहीं किया। 2 से 2.5 मेगावाट उसकी कैपेसिटी बढ़ गई। मेरा एक साथी बता रहा था कि सारे ट्रांसफार्मर गर्म हो जाते हैं। आप यह बताइए कि सिस्टम को तो बढ़ाते जा रहे हो और बिजली को कम करते जा रहे हो। सिस्टम को बढ़ाना है, कनेक्शन बढ़ा रहे हो तो सिस्टम को भी बढ़ाना

पड़ेगा। तार ढीले पड़े हैं, एक्सीडेंट होकर मर जाता है, हड़ताल हो जाती है तो 5 लाख रुपये देने पड़ते हैं। क्यों आपके जेईएन, एईएन को दिखता नहीं है क्या कि तार ढीले पड़े हैं? जिनके पशु खेत में हल चलाते हैं, उन पशुओं के तार अड़ जाते हैं, (समय समाप्ति सूचक घण्टी) माननीय सभापति महोदय, मिनट हुई है चार। चार मिनट हुई है 4.37 पर बोलने लगा था, अभी 5-7 मिनट और है। ..(व्यवधान).. मेरे खड़े होते ही आपके क्या बुखार हो जाती है? ..(व्यवधान).. ।

श्री सभापतिः माननीय सदस्य, गोपाल शर्मा।

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): 33 केवी के, 132 केवी के जीएसएस आपने कोई नए नहीं लगाए हैं। आप कनेक्शन का कह रहे हो कि हम 12 हजार कनेक्शन और देंगे। दो न, कौन मना करता है? पर इसका जो सिस्टम है उसको तो आप बढ़ाओ। बगैर सिस्टम को बढ़ाए आप कुछ भी नहीं कर सकते। सेल्फ फाइनेंस कनेक्शन होता है। सेल्फ फाइनेंस कनेक्शन में आदमी 80 हजार, 90 हजार, 1 लाख, 2 लाख जमा कराकर कनेक्शन ले लेता है। जब उसका ट्रांसफार्मर जल जाता है तो बिजली बोर्ड का एईएन क्या कहता है? इसको आप कहीं भी लेकर जाओ, हम नहीं लेंगे। जब बिजली बोर्ड से हमारा कनेक्शन जुड़ गया, हम उसके कंज्यूमर बन गए, हम उसके कंज्यूमर बनने के बाद आप यह कैसे कह सकते हो कि उस ट्रांसफार्मर को लुहारू लेकर जाओ या हरियाणा लेकर जाओ या बम्बई लेकर जाओ। उसी कम्पनी का माल है, उसी कम्पनी में हमने पैसा दिया तो आपको ठीक करना पड़ेगा, इसके नियम में आप परिवर्तन करो। ..(व्यवधान)..

श्री सभापतिः श्री गोपाल शर्मा।

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): माननीय सभापति महोदय, एक मिनट। एक बहुत बढ़िया बात है। कॉलोनियों में आप कॉमर्शियल चार्ज लगाते हो, और आप देखिए कॉमर्शियल चार्ज लगाने से उन कॉलोनियों में लोगों ने मकान बनाना बंद कर दिया। आप इसके अन्दर 50 परसेंट सुधार कीजिए। जिससे लोगों को पैसा जमा कराने में थोड़ा-बहुत तो राहत मिले। कुछ कॉलोनियां 50 परसेंट बसी हुई हैं। उसके अन्दर भी आप यही कर रहे हो कि आपका प्लॉट 500 गज का है। ..(व्यवधान).. आप खड़े हो गए क्या? आपका भी दिमाग खराब हो गया क्या? ..(व्यवधान).. ये कहां से आते हैं?

श्री गोपाल शर्मा (सिविल लाईन्स): आदरणीय सभापति महोदय, मेरे बड़े भ्राता और मेरे गांव के श्रीमान् श्रवणजी के बाद बोलने के लिए अनुमति दी, इसके लिए मैं आपका बहुत-बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। ..(व्यवधान)..

श्रवणजी भाई साहब,

इस फलक को है जिद बिजलियां गिराने की,
इस फलक को है जिद बिजलियां गिराने की,
इधर हमें है धुन, आशियां बनाने की।

कितना खुशी का मौका है, एक तो हमारे माननीय सदस्यों ने ..(व्यवधान).. बाद में एक

साथ ..(व्यवधान)..

श्री सभापति: श्रवणजी, आप विराजिए।

श्री गोपाल शर्मा (सिविल लाईन्स): ..(व्यवधान).. कट गया, कट गया। बिजली बंद।

कितना खुशी का मौका है, मैं अपने को कहने से रोक नहीं पा रहा हूं कि जब दो-तीन माननीय सदस्यों की बात ध्यान में आती है कि हम यहां आकर क्या देखते हैं, हमको यह पता होता तो हम यहां आते ही नहीं। मैं कह रहा हूं कि इससे अच्छा और पक्ष और प्रतिपक्ष हो ही नहीं सकता। अगर हम लोग तय कर लें, जमीन से जुड़े हुए हमारे नेता, माननीय भजन लाल जी और जमीन से जुड़े हुए टीकाराम जी जूली, हमारे जोगारामजी पटेल, इस तरह के लोग, झाबर सिंह जी खर्रा, अगर तय कर लें कि हमको राजस्थान को आगे बढ़ाना है।

श्री सभापति: धारीवालजी का नाम नहीं ले रहे हो? धारीवालजी का?

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय कार्य मंत्री): श्रवणजी।

श्री गोपाल शर्मा (सिविल लाईन्स): श्रवणजी तो भाई हैं, इनसे नहीं लड़ाई है। अगर ये तय कर लें तो बिजली, पानी सड़क, अस्पताल, क्या राजस्थान इसी से जूझता रहेगा या हमारा कोई और सपना है? क्या हम यही करते रहेंगे कि बिजली की कटौती हो गई, आप जिम्मेदार, मैं कहूं कि क्या किसी दिन अख़बार का पन्ना देखा है जब पिछला शासन था और उसमें बिजली की कटौती के मोहल्लों के नाम नहीं आते थे, हर बात आते थे। यह राजस्थान है, बढ़ता हुआ राजस्थान, अगर यहां पर कटौती नहीं होगी, यहां पर ज्यादा बिजली की मांग नहीं होगी तो हम आगे बढ़ेंगे कैसे? कैसे बढ़ेंगे? आदरणीय भैरोंसिंहजी कहते थे कि क्या कोई लोक कल्याणकारी सरकार हो सकती है जो घाटे में नहीं हो? घाटे में होने का मतलब है कि सरकार लोक कल्याण के लिए समर्पित है और अगर घाटा भ्रष्टाचार के कारण है तो धारीवालजी भाई साहब से ज्यादा ज्ञानवान कोई नहीं है। अगर ये तय कर लें कि आने वाले सवा चार साल के अन्दर मैं भ्रष्टाचार नहीं होने दूंगा तो सरकार की इतनी मदद कर सकते हैं जितनी इन्होंने कोटा की है। कोटा हमेशा याद रखेगा आपको लेकिन भारतीय जनता पार्टी को जब आप किसान की बात करेंगे, बिजली की बात करेंगे तो लोग कांग्रेस को याद नहीं करेंगे, लोग भाजपा को याद करेंगे। उसका कारण है कि बारानी भूमि का लगान, बारानी भूमि का लगान अगर किसी ने माफ किया तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया, भैंरोसिंहजी ने किया। उन्होंने कहा कि जो फसलें भगवान के ऊपर आधारित हैं, उसका लगान लेना अन्याय है। (समय समाप्ति सूचक घण्टी)

आदरणीय सभापति महोदय, आप बताइए, सबको बोलने के लिए दिए बीस-बीस मिनट। मेरे को तो बात ही शुरू नहीं करने दी। ..(व्यवधान)..

श्री सभापति: श्रवणजी, आप विराजिए। आप बोलिए फटाफट। ..(व्यवधान)..

श्री गोपाल शर्मा (सिविल लाईन्स): आदरणीय सभापति महोदय, ये किसी से छिपा हुआ नहीं है कि जब राजस्थान के अन्दर सरकार बदली तो खजाना खाली था। वो खजाना कहां गया, इसकी जांच होनी चाहिए। उसका कारण है कि हमारे एक माननीय विद्वान सदस्य ने

कहा कि एसीडी के अन्दर जितने मामले हमने दर्ज करवाए, उतने किसी ने नहीं करवाए। मैं गारंटी के साथ आपसे निवेदन करता हूं माननीय सभापति महोदय, जितने मामलों को मुख्य मंत्री स्तर पर रोका गया, उतना राजस्थान के इतिहास में आज तक नहीं हुआ, आज तक नहीं हुआ। ऐसे-ऐसे भ्रष्टाचार के मामले ..(व्यवधान).. अगर जांच की जाए, नारको टेस्ट करवाया जाए ..(व्यवधान)..

MLS/RTM/02.08.2024/18:00/3I

श्री सभापतिः ...(व्यवधान)... माननीय सदस्य।

श्री गोपाल शर्मा (सिविल लाईन्स): अगर नार्को टैस्ट करवाया जाये तो पता चलेगा बिजली के मामले में हस्तक्षेप करवाने की कोशिश हुई तो 8 नम्बर से हुई, 8 नम्बर से हुई। **(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)** सभापति महोदय, अपने आचार्य चाणक्य थे प्रधान मंत्री, एक व्यक्ति मिलने आया तो उन्होंने दीया बुझा दिया, बोले कि सरकार का काम खत्म हो गया, अब व्यक्ति का काम शुरू हुआ है और दूसरी तरफ कांग्रेस के राज में एक अधिकारी से मैंने कहा कि एक पत्रकार को बिजली का कनेक्शन दे दीजिये। उनके परिवार के व्यक्ति आपके कैबिनेट मंत्री रहे हुए हैं।

श्री सभापतिः विराजें। माननीय शान्ती धारीवाल।

श्री गोपाल शर्मा (सिविल लाईन्स): मुझे खत्म करने का तो अवसर दीजिये, वाक्य तो पूरा करने दीजिये। वाक्य तो पूरा करूं। तो उनके परिवार के व्यक्ति कैबिनेट मंत्री थे। उन्होंने कहा, आप तो मेरा सिद्धान्त तोड़ रहे हैं।

श्री सभापतिः माननीय धारीवाल जी। आप खड़े हो जाइये। आपका समय कटेगा।

श्री गोपाल शर्मा (सिविल लाईन्स): सभापति महोदय, एक बार नजर तो मिलाइये। ये हमारे बड़े भाई हैं, ये बैठे रहेंगे थोड़ी देर। हम लोगों ने आपका विरोध नहीं किया था।

श्री सभापतिः माननीय धारीवाल जी, आपको आपकी पार्टी ने 15 मिनट अलॉट किये हैं।

श्री गोपाल शर्मा (सिविल लाईन्स): हम लोग का मतलब भाजपा ने तो किया था।

श्री सभापतिः धारीवाल जी, आपके 15 मिनट खत्म हो रहे हैं।

श्री गोपाल शर्मा (सिविल लाईन्स): सभापति महोदय, बस दो मिनट, दो मिनट।

श्री सभापतिः आपको आपकी पार्टी ने 15 मिनट दिये हैं। आप शुरू करें।

श्री शान्ती धारीवाल (कोटा उत्तर): 15 मिनट दिये हैं न, अभी 18 हुए हैं, अब इसको 15 की बजाय 20 कर दें।

श्री गोपाल शर्मा (सिविल लाईन्स): आखिर में कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी का जो नारा है, हर घर बिजली, वह भारतीय जनता पार्टी पूरा करके रहेगी।

श्री शान्ती धारीवाल (कोटा उत्तर): सभापति महोदय, आज की जो बिजली की चर्चा थी, असल में यह विषय इसलिए रखा गया कि आज जो हालात राजस्थान में बिजली के हैं, उनमें किस प्रकार से सुधार हो सकता है, लेकिन मुझे दु:ख इस बात का है कि जो पहले वक्ता थे,

जो पहले एनर्जी मिनिस्टर थे, वे तो पूरा इतिहास ही बताते रहे, हमने यह किया, हमने यह किया, हमने यह किया, हमने यह किया, हमने यह किया। उन्होंने यह किया कि उनसे तो बिजली की सप्लाई तक नहीं हो पायी उस जमाने में। नतीजा यह हुआ कि कोटा, भरतपुर, अजमेर, बीकानेर यहां पर प्राइवेट कम्पनियों को देना पडा और उन प्राइवेट कम्पनियों ने जनता को लूट खाया।

ये बिजली मंत्री बैठे हुए हैं, ये भी मेरे जिले से ही आते हैं। इनसे कहें कि छाती पर हाथ धरकर यह कह दें कि क्या बिजली कम्पनियों ने जनता को नहीं लूटा? किसने किया था यह फैसला? और 20 साल का एग्रीमेंट किया। ...(व्यवधान)... मुझे पता है, चुनाव के वक्त में मैंने भी जनता से यह वादा किया था कि हमारा राज आयेगा तो इन कम्पनियों को हटाएंगे, लेकिन जब राज आया और मैंने एग्रीमेंट देखा प्राइवेट कम्पनियों और पावर मिनिस्ट्री के बीच में तो उसमें 20 साल लिखे हुए थे। अब 20 साल का एग्रीमेंट करने के बाद में तो मैं हटा भी कैसे सकता था? लूट खाया जनता को। उन लोगों ने लूट खाया। आप लोग इतने इनएफिशिएंट थे कि आप शहरों को सप्लाई तक नहीं कर सके। नतीजा यह हुआ कि आपने प्राइवेट कम्पनियों को बुलाया। कलकत्ता की कम्पनी को बुलाकर डिस्ट्रीब्यूशन का काम दिया।

खैर, सवाल यह है कि आज ऐसे क्या हालात हो गये कि बिजली की आपूर्ति गड़बड़ा गयी? क्यों गड़बड़ा गयी, इस पर विचार करने की बात है। अच्छा, गड़बड़ा भी गयी और उसके साथ-साथ पावर कट भी। पावर कट हो रहा है। बिजली की आपूर्ति में व्यवधान हो रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों की तो यह हालत है कि रात को 2 बजे तो बिजली दी जाती है और 6 बजे तक दी जाती है और उसके बाद में बिजली बन्द की जाती है। दिन भर में कोई 5 मिनट-10 मिनट, 5 मिनट-10 मिनट, कभी बिजली आ जाये तो आ जाये। यह हालत है। राजस्थान में इस प्रकार के हालात कभी नहीं देखे गये। कभी नहीं देखे गये। मैं आपको बताना चाहता हूं...

श्री सभापतिः धारीवाल जी, एक आग्रह है। आप हम सबसे सीनियर हैं। मैं आग्रह करता हूं, क्या किया जा सकता है, आप उस पर विचार करें। यह सलाह दें।

श्री शान्ती धारीवाल (कोटा उत्तर): क्या?

श्री सभापतिः क्या किया जा सकता है अब नया, वह बात बताएं आप तो सदन को।

श्री शान्ती धारीवाल (कोटा उत्तर): यह तो जिनके पास सरकार है, वे बताएंगे। हमारे पास सरकार होती तो हम बताते कि क्या कर लेते।

श्री सभापतिः आपके अनुभव का लाभ दें।

श्री शान्ती धारीवाल (कोटा उत्तर): सभापति महोदय, मुझसे ही क्यों पूछ रहे हैं आप? ये इतने वक्ता बोल लिये, उनसे भी पूछ लेते यह सवाल।

टाइम्स ऑफ इंडिया में 5 जुलाई की एक खबर आयी है। 5 जुलाई की खबर में लिखा हुआ है, According to a report by Grid Controller of India (GCI), ग्रिड कंट्रोलर ऑफ इंडिया की रिपोर्ट है - "According to a report by Grid Controller of India (GCI), a central PSU, Rajasthan endures the most severe and prolonged

power outages in comparison to any other state in the country.", यह हालत है। सारे देश में राजस्थान में सबसे ज्यादा बिजली की गड़बड़ी है और कमी है, यह ग्रिड कंट्रोलर का सर्टिफिकेट है। लिखा क्या है, देखिये आप।

मैं आपको जून की पांच-छह तारीखें बता देता हूं। 21 जून को 3.53 मैगा यूनिट की कमी थी, 22 जून को फिर यह बढ़कर हो गयी 6.13 मैगा यूनिट, 23 जून को फिर बढ़कर हो गयी 8.23 मैगा यूनिट, 24 जून को फिर बढ़कर हो गयी यह 7.63 मैगा यूनिट। उसके बाद में जरूर कम हुई। 25 जून को यह हो गयी 4.7 मैगा यूनिट, 26 जून को हो गयी 1.90 मैगा यूनिट और 27 जून को हो गयी 1.4 मैगा यूनिट। इतनी बड़ी यूनिट की कमी। इतनी कमी कभी रही ही नहीं, राजस्थान के इतिहास में उठाकर देख लीजिये आप कि कभी भी राजस्थान को इतनी कमी महसूस नहीं हुई, जितनी आपके टाइम पर हुई है।

राज्य सरकार के पास हमेशा मांग क्या है और बिजली की उपलब्धता क्या है, इसका आकलन रहता है। हर वक्त रहता है, जानकारी रहती है, जो दिसम्बर में भी थी। दिसम्बर में चुनाव में आप आ गये, लेकिन उस वक्त भी जानकारी थी कि मांग तो क्या होगी और उपलब्धता क्या है। आगामी माह की उपलब्धता और उसके अनुमान का आकलन भी आपके विभाग को रहता है। यह कंटीन्युअस प्रोसेस है, नियमित प्रक्रिया है, परन्तु सरकार एवं उनकी पावर कम्पनियों ने समय रहते कोई काम नहीं किया। अगर काम किया होता तो मालूम पड़ जाता कि इतनी मांग अगले महीने में आयेगी और हमारे पास इतनी उपलब्धता है। हमारे पास मौजूद नहीं है तो कहीं से इन्तजाम करके बिजली लायी जाये।

नेटवर्क, पावर कम्पनियों ने समय रहते कोई आवश्यक कार्यवाही नहीं की। नेटवर्क सिस्टम का इम्प्रूवमेंट नहीं किया और विद्युत आपूर्ति शॉर्ट टर्म परचेज जो होती है, हमेशा होती है शॉर्ट टर्म परचेज, वह शॉर्ट टर्म परचेज भी मुनासिब दरों पर बिजली प्राप्त नहीं की, जो कि आपको करनी चाहिये थी, परन्तु ऊर्जा विकास निगम में होती कैसे? आदरणीय विद्युत मंत्री जी, हालत तो यह है कि ये सब चीजें कैसे हों, ऊर्जा विकास निगम में न तो कोई एमडी है, न कोई डाइरेक्टर है और न ही कोई चीफ इंजीनियर है। मतलब जेईएन, एईएन, एक्सईएन, इनसे काम चल रहा है। कहां से सुधार होगा? ये कौन लगायेगा? आपकी समझ में नहीं आ रही थी बात तो कांग्रेसियों से पूछ लेते, भाई लगाओ, बताओ, किसी न किसी तरह से राजस्थान का भला तो करें। ...(व्यवधान)...

mkd/rtm/02.08.2024/18.10/3m

विराजो, आप विराजो। देखो, आप बात सुनना। आप संसदीय मंत्री हो। संसदीय मंत्री हो, ऐसे बीच में नहीं बोला जाता। जब कोई ऐसी बात आती है, तभी जाकर आप उठो, ऐसे मत उठो।

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय कार्य मंत्री): ऐसे ही आई है, ये लगाओ नहीं, पता नहीं लग रहा है। पारीक साहब।

श्री शान्ती धारीवाल (कोटा उत्तर): अभी माननीय पुष्पेन्द्र जी कह गये कि छबड़ा और सूरतगढ़। हमने सूरतगढ़ में इकाइयां लगाईं, लगाई आपने? क्या नतीजा निकला? उसका कॉमर्शियल ओपरेशनल सर्टिफिकेट तो हम लेकर आये, तैयार तो हमने किया उसको, आप तो सिर्फ लगाकर के भाग गये, डेढ़ साल तक झूलते रहे हम, उनको दुरुस्त किया, सब कुछ किया, ये किया, वह किया, ट्रायल दी और उसके बाद में कम्प्लीशन सर्टिफिकेट लेकर के हम आये, तब जाकर के वह चालू हो पाई।

आपका रूफ टॉप, आपका सोलर 1100 मेगावाट का हमने पैदा किया, पूरे देश में कहीं पर भी रूफ टॉप सोलर 1100 मेगावाट का नहीं होगा। 600 मेगावाट की दो यूनिट और एक 800 यूनिट की कालीसिंध की यूनिट, इसकी स्वीकृति भी हमने दी। आपने कहा कि हमने लगाई। भाई, स्वीकृति तो हमारे टाइम पर ही हो गई थी, सरकार बदल गई, लगाना तो था ही आपको, करना क्या था, बजट का इंतजाम तो हम करके गये थे, लेकिन केन्द्र सरकार की बदनीयती देखो। केन्द्र सरकार ने पर्यावरण और कोल आवंटन की क्लीयरेंस देने में कम से कम डेढ़ साल, दो साल लगा दिये और आज भी आठ महीने से आप विराजमान हैं, इस विभाग पर, लेकिन आज भी वह शुरू नहीं हो पाई है। आठ महीने तो ये हो गये हैं और डेढ़ साल हमारे टाइम पर हो गये। ये तो केन्द्र सरकार का हाल है।

किसान कनेक्शन की आप बात कर रहे हैं। एक साल से भी अधिक समय हो गया। कृषि विद्युत कनेक्शन हेतु किसानों ने डिमांड नोट जारी करवा रखी है, परन्तु कहीं सामान नहीं है, कहीं ठेकेदार नहीं है, कोई देखने वाला ही नहीं है। असल में देखा जाये तो कोई देखने वाला ही नहीं है कि हो क्या रहा है। एक-एक साल से किसानों का डिमांड नोट का पैसा जमा है।

घरेलू कनेक्शनों और कई क्षेत्रों में तो 6-6 महीने से डिमांड नोट तक जारी नहीं हुए।

श्री सभापति: आपस में चर्चा नहीं करें।

श्री शान्ती धारीवाल (कोटा उत्तर): आप बाद में बोल लेना। कहीं मीटर नहीं है, कहीं सर्विस लाइन नहीं है, 88 हजार मामले तो ऐसे हैं, जहां पर इस प्रकार के न तो मीटर है, न लाइन है, कुछ नहीं है। औद्यागिक कनेक्शन 450 पड़े हुए हैं।

आदरणीय पुष्पेन्द्र जी कह रहे थे 220 और 132 केवी के जीएसएस के लिए, ये 220 और 132 जीएसएस की मंजूरी और लाइनें भी हमारे टाइम से स्वीकृत पड़ी हुई हैं, उनमें कोई काम नहीं हो रहा है। अब कह रहे हो कि करेंगे, करेंगे। आठ महीने तो हो गये, कब करोगे? ये सब स्वीकृत तो हमारे टाइम पर ही हो गये। ट्रांसमिशन और डिस्ट्रिब्यूशन के लोसेज हो रहे हैं। साहब बढ़ गये, ये मानकर चलो, जो हम छोड़कर गये थे ना, उससे लोसेज बढ़े हैं, उस बात को छुपाने से बात छुपेगी नहीं।

आपने कहा था कि साहब सस्ती बिजली देंगे। सस्ती बिजली का हाल यह है कि 88 हजार मेगावाट के अक्षय ऊर्जा और ग्रीन हाइड्रोजन के प्रोजेक्ट आपके पास पड़े हुए हैं, किसलिए पड़े हुए हैं? उनको जमीन चाहिए और जमीन नहीं दे पा रहे हैं। नीति बनायेंगे,

नीति बनायेंगे, कल आना, परसों आना, ये होगा, वो होगा, 88 हजार मेगावाट के, हमने बड़ी मुश्किल से जाकर इन लोगों को तैयार किया था। इनसे इन्वेस्टमेंट समिट में जाकर एमओयू किया, सब कुछ किया और वे तैयार हो गये, लेकिन आज भी धक्के खा रहे हैं, नतीजा यह है कि आप जमीन तक नहीं दे रहे हैं। जमीन कोई अपने बाप की है क्या? यह जनता की जमीन है, इसको देने में दिक्कत क्या है? मैं कहता हूं, बल्कि जमीन आपको फ्री में देनी चाहिए। कोई आपत्ति क्यों? क्योंकि आखिर बिजली की प्रोब्लम सॉल्व करनी है। यह अक्षय ऊर्जा और ग्रीन एनर्जी लानी है तो निश्चित तौर पर इस प्रकार की पॉलिसी आप बनाओ, तब जाकर के यह काम होगा, वरना काम होगा भी नहीं।

मैं कोई लम्बी बात नहीं कहता। केन्द्र सरकार की एक योजना चली, 2024 में सूर्य घर, सूर्य घर योजना की हालत आप देखिये। मैं आपको पढ़कर बताता हूं कि आपने क्या किया, इन आठ महीनों की मैं बात बता रहा हूं, इन आठ महीनों में गुजरात में 1 लाख 22 हजार 143 इंस्टोलेशन हो गये, महाराष्ट्र में 34 हजार 804 हो गये, केरल में 23 हजार 908 हो गये, उत्तर प्रदेश में 20 हजार 100 हो गये, तमिलनाडु में 7 हजार 803 हो गये और मध्य प्रदेश में 7042 हो गये, लेकिन राजस्थान में 7 हजार 55 हुए हैं। अब इसमें भी क्या जोर आ रहा है? यह तो केन्द्र सरकार की योजना है। दूसरे स्टेट में तो लाख और लाख के आसपास पहुंच गये और आप 7 हजार पर अटके हुए हो। मेहरबानी करके, मैं कोई लम्बी बात नहीं कहता, चूंकि आप मेरे जिले के हो।

श्री सभापतिः धारीवाल साहब, एक मिनट में अपनी बात समाप्त करें।

श्री शान्ती धारीवाल (कोटा उत्तर): इसलिए, मैं आपसे कहता हूं कि इन अफसरों की जगह भरो। इन अफसरों की जगह भरो और कायदे के अफसर लगाओ। तब जाकर काम होगा। आप यह मानकर चलिये। जनता की हालत आज यह है कि अगर आज चुनाव हो जाये तो एक अकेली बिजली आपको हरा देगी मैं दावे के साथ कहता हूं।

श्री सभापतिः धारीवाल जी, एक मिनट में समाप्त करें।

श्री शान्ती धारीवाल (कोटा उत्तर): कृपया, इसमें सुधारने की बात करो। ये पुरानी बातें मत करो कि पुराने में यह था, वह था। इतना कर्जा था, यह था, ये कर्जे, वर्जे तो चलते रहेंगे।

श्री सभापतिः माननीय अतुल भंसाली जी।

श्री शान्ती धारीवाल (कोटा उत्तर): कोई भी कल्याणकारी सरकार ऐसी नहीं है, जो कि ट्रांसपोर्ट का मामला हो, रेल का मामला हो, बिजली का मामला और पानी का मामला हो, कोई कमाई का साधन हो, ये कमाई की चीजें नहीं हैं, ये कल्याण की चीजें हैं, धन्यवाद।

श्री अतुल भंसाली (जोधपुर): माननीय सभापति महोदय, आज बिजली चर्चा का विषय है और आज जिस तरह की ऊर्जा विपक्ष के सदस्यों में देखने को मिल रही है। मुझे लगता है कि पिछले पांच साल में इनकी पूरी ऊर्जा सरकार को बचाने में चली गई और इन्होंने ऊर्जा विभाग के ऊपर ध्यान ही नहीं दिया और उसका परिणाम पूरी जनता और राजस्थान की

जनता भुगत रही है।

सबसे बड़ी बात हम आज पानी और बिजली पर चर्चा कर रहे हैं। इतने अच्छे सुझाव विपक्ष की तरफ से आ रहे हैं तो शायद पिछले पांच साल में या तो इनकी सुनने वाला कोई नहीं था या उनको बोलने नहीं दिया गया। इसकी भी एक जांच करने की जरूरत है।

जिस तरह से एक माननीय सदस्य ने अभी, जिनको बाबाओं से बहुत प्यार है और हर बात में बाबा नजर आते हैं तो यह उनका नहीं, उनकी कांग्रेस, उनकी पार्टी का जेनेटिक ऐसा है कि उनको हर चीज में, हर उस चीज में बाबा ही नजर आते हैं। जिसके बारे में उनका ध्यान जाता है।

(समय बजे)

(श्री फूलसिंह मीणा, सभापति, पदासीन)

जब बिजली और अनुशासन की बात करते हैं, डिपार्टमेंट की। मैं आपको एक छोटा उदाहरण बताता हूं, बिजली बैंकिंग व्यवस्था के अन्तर्गत पूर्ववर्ती सरकार ने 35 हजार 234 लाख यूनिट बिजली उधार ली और वह पूरी उधारी आने वाली सरकार के ऊपर छोड़कर गये। हमारी सरकार के आने बाद लगभग 24 हजार लाख यूनिट वापस हमने केन्द्र सरकार के उस बैंक में जमा की।

आप समझ गये होंगे कि जैसा घाटा वे छोड़कर गये, जिस तरह 2018 के अन्दर फायदे में उनको बिजली का विभाग देकर गये। उसको जिस हिसाब से इतने कर्जे में हमको सौंपकर गये। हर जगह जहां भी हाथ डालोगे। मैं जिस टीचर से पढ़ता था, उनका नाम बिस्सा जी था। वे तब अकाउंटस पढ़ाते थे। हम कोई गलती करते थे तो बोलते थे रहने दे, पास हो जायेगा, मैंने बोलो क्यों? तो बोले जो जोहेगा वो रोयेगा।

Bhs/Rtm/02.08.24/18.20/3n

तो हम जोह रहे हैं और हम ही रो रहे हैं क्यों, रोने का काम इसलिये है कि इतने डिपार्टमेंट्स के ऊपर चर्चा हुई, हर चर्चा में एक ही विषय सामने आया कि बिना वित्तीय अनुशासन के पिछली सरकार पूरे पांच साल चली और उस वित्तीय अनुशासन के खराब होने का आज खामियाजा जल को भुगतना पड़ रहा है, बिजली को भी और दूसरे सेक्टर में भी भुगतना पड़ रहा है।

मैं अब आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूं जोधपुर डिस्कोम का, ये बात करते हैं भ्रष्टाचार की, ये बात करते हैं काम करो भ्रष्टाचार होता रहेगा पर भ्रष्टाचार एक अलग विषय है पर काम में कोताही क्यों हुई, हर तरह के काम में डिस्कोम की ठेकेदारी के अन्दर सारे काम जो अलग-अलग बांटने चाहिये थे, पूर्व मंत्री महोदय ने भी बताया कि राजस्थान में इतने ठेकेदार हैं उनको आप काम दो, उसकी जगह दिल्ली, गुड़गांव और बाहर से बुलाकर पूरे डिस्कोम का एक-एक ठेका एक-एक ठेकेदार को दे दिया गया और मैं आपको बताता हूं कि दो महीने में हमारे बिजली मंत्री ने खूब मीटिंगें कीं। उन मीटिंग्स का सार यह निकला, जो

अपने मैन समस्या चल रही थी उसके अन्दर पिछली सरकार में जो 2022 में वह काम मिला, 2022 से फरवरी, 2024 तक जीरो परसेंट काम हुआ जोधपुर डिस्कोम में, और जो प्रगति हुई 10-12 परसेंट की वह भी हमारे पीछे पड़ने के बाद में इन पिछले 6-7 महीनों में हुई।

सभापति महोदय, मैं मंत्री महोदय से भी आग्रह करता हूं कि ऐसी जितनी भी कोताही बरती गई है काम करने में, जिसकी वजह से, चूंकि यह प्रोब्लम जनरेशन की है, प्रोब्लम है डिस्ट्रिब्यूशन की और जनरेशन और डिस्ट्रिब्यूशन हमारे मुख्य मंत्री या कोई कार्यकर्ता ऐसा जादूगर तो हैं नहीं जैसे जादूगर आपके मुखिया थे। हम काम करने वाले लोग हैं जमीन पर काम करने वाले लोग हैं, वो काम करना, वो डिस्ट्रिब्यूशन और जेनरेशन करने से ही होगा, कोई जादू की छड़ी घुमाने से नहीं होगा और जिस तरह से मांग बढ़ी, मैं धन्यवाद देता हूं हमारे मुखिया भजन लाल जी को और हमारे बिजली मंत्री नागर साहब को कि उन्होंने हर वीक में, हर दस दिन में बार-बार विधायकों से बात की, हमारी समस्याओं से अवगत हुए, जहां से भी बिजली भारत में उनको मिली, विद्युत एक्सचेंज के द्वारा उन्होंने वह बिजली किसी भी भाव पर खरीदी। यह नहीं देखा कि उसका क्या परिणाम होगा पर एक बार जनता को जितनी बिजली मिल सके उतनी बिजली उपलब्ध कराने का इन्होंने काम किया। आप सब विपक्ष के लोगों ने भी इनकी तारीफ की। अभी सदन जब चल रहा था तभी वे सबको ग्रुपवाइज बुला कर डिस्कस कर रहे थे, वो क्यों कर रहे थे? क्योंकि उनकी मंशा अच्छी है, सरकार की मंशा अच्छी है। सरकार चाहती है कि जनता बिना बिजली के नहीं रहे।

सभापति महोदय, अभी आदरणीय टीकाराम जी जूली साहब ने बताया था कि अस्पताल में बिजली चली गई, एक मिनट वहां चली गई। यह 9.10.2021 का पेपर है और एस.एम.एस. हॉस्पिटल में बिजली नहीं थी और पूरा ऑपरेशन, टैस्टिंग कई घंटों तक, हम यह बात कर रहे थे एक मिनट की, ये कई घंटों तक टॉर्च की रोशनी में और मोमबत्ती के अन्दर इलाज हुआ। आप बात करते हो, जब आप बात करते हो, आप अपने गरेबान में झांक कर नहीं देखते हो और आर.डी.एस.एस. के अन्दर जो काम अब तक पूरा हो जाना चाहिये था, जोधपुर शहर ऐसा है कि लगभग सभी घरों में बिजली है, सभी घरों में कनेक्शन है, उसके बाद बिजली की क्या समस्या है। दिन में तीन-तीन, चार-चार बार बिजली कट रही है, उसकी पूरी जांच की, तब मालूम पड़ा कि डिस्ट्रिब्यूशन नेटवर्क जिस जे.के. एंटरप्राइजेज को दे रखा था उसने मलाई खा ली, पैसे उठा लिये, काम अभी तक 9-10 परसेंट किया, पेमेंट पूरा उठा लिया और हम उसकी जब जांच कर रहे हैं तो हमको समझ में ही नहीं आ रहा है कि इसके आगे क्या करें और इस तरह के काम ग्रामीण इलाकों में भी हुए हैं। मैं उसकी भी जांच करने का आग्रह करूंगा, पर जांच से कुछ नहीं होगा।

सभापति महोदय, जैसा कि नागर साहब ने और सरकार ने एक बीड़ा उठाया कि पहले हम बिजली की व्यवस्था को दुरुस्त करेंगे, बिजली जहां से जनरेशन करनी होगी, अगले पांच साल में पचास हजार मेगावाट जनरेशन का जो बीड़ा उठाया, उसको पूरा करेंगे और जो-जो

वादे संकल्प पत्र में किये गये हैं उन वादों को पूरा करने के लिए जो भी नीतिगत निर्णय लेना होगा केन्द्र सरकार का, राज्य सरकार का जो भी सहयोग होगा उसको लेकर हम उस कार्य को पूरा करेंगे। जब बात करते हैं तो वो बोले कि हमारे को आप दोष मत दो। कैसे नहीं दें, आपने 18 हजार मेगावाट बिजली जेनरेशन का नया प्लान बनाया और पिछले पांच साल में और कुल आप 1300 मेगावाट बिजली ही जनरेट कर पाये और उसका परिणाम भी हम ही भुगत रहे हैं। हम नहीं भुगत रहे राजस्थान की जनता भुगत रही है और उसका जो पैसे का भार है वह भी जनता को ही आता है और सबसे बड़ी बात जब विद्युत की ये जो कटौती की बात कर रहे हैं सबको मालूम है कि पिछले पांच साल में और पिछले 2014 से 2024 में जो भारत के अन्दर सम्पन्नता आई है पच्चीस करोड़ लोग मोदी जी की योजना और उनकी नीतियों की वजह से गरीबी की रेखा से बाहर निकले हैं और किसी भी देश का पूरे वर्ल्ड में एक ही मीटर होता है कि वह देश सम्पन्न हो रहा है या नहीं, सम्पन्नता का सीधा मापन उस देश में एनर्जी का कंजम्पशन कितना होता है और 25 परसेंट एनर्जी का कंजम्शन पिछले चार महीने में राजस्थान में बढ़ा है। सम्पन्नता जरूर आई, पर हमने बिजली का इतना उपयोग किया कि पूरा जो ट्रांसमिशन सिस्टम था वह पूरा गड़बड़ा गया। फिर भी मैं सरकार का और माननीय मंत्री महोदय का बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूं कि इन्होंने सचेत रहते हुए एक भावना के साथ जो काम किया, उससे एक बात जरूर है कि उसके अन्दर व्यवस्था को सम्भालने का पूरा काम किया, पर धीरे-धीरे मैं समझता हूं कि जो की पाइंट अभी ध्यान में आये हैं उनको ध्यान में रख कर सरकार अगले वर्ष इस तरह की कोई समस्या नहीं आये उसका एक मास्टर प्लान बना कर काम करेगी। धन्यवाद। जय हिन्द। जय भारत।

श्री सभापतिः श्री राजेन्द्र जी पारीक।

श्री राजेन्द्र पारीक (सीकर): माननीय सभापति महोदय, आज पूरा राजस्थान, खास तौर से जहां से मैं आता हूं यहां पर कृषक ज्यादा हैं। आज कृषक का और वहां ग्रामीण अंचल में जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनके सामने इतनी बड़ी समस्या है कि कई बार तो रात को 11-12 बजे तक फोन आते हैं कि, साहब, लाइट नहीं है और 7 बजे से लेकर 2-2 बजे तक लाइट नहीं है। बच्चे पढ़ने वाले हैं उनके सामने भी यह समस्या है कि वो कैसे अपनी पढ़ाई पूरी करें और यह कोई अचानक होने वाली समस्या नहीं है माननीय सभापति महोदय। एकाध कोई ग्रिड शटडाउन ले ले और कर ले तब तो बात समझ में आती है लेकिन विगत चार-पांच महीने से अनवरत यह स्थिति बनी हुई है। बाली से आने वाले माननीय सदस्य ने बड़ी बिगुल बजाई और सारा का सारा दोष उन्होंने पूर्व सरकार पर रख दिया कि पूर्ववर्ती सरकार की वजह से ही यह सारी समस्या बनी हुई है।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से एक निवेदन करना चाहूंगा कि माननीय मंत्री महोदय, आपको एक व्हाइट पेपर लाना चाहिये। आपको व्हाइट पेपर लाना चाहिये विगत सरकार का और आपका एक तुलनात्मक अध्ययन करके आप एक

व्हाइट पेपर रखिये, ताकि लोगों को पता चले। आज पूरा राजस्थान केवल यह जानने के लिए उत्सुक है कि हमारी समस्या का समाधान होगा या नहीं होगा और हम यहां बैठे हुए हैं इसको कोसने में, उसको कोसने में। प्रश्न सिर्फ सीधा सा है, 'तू इधर-उधर की न बात कर, यह बता कि कारवां क्यों लुटा। मैं बताऊं कि कारवां क्यों लुटा, तेरा रहजनों से था वास्तां, हमें रहजनों से गर्ज नहीं, तेरी रहबरी पर मलाल है।'

माननीय मंत्री महोदय, आप आठ महीने से इस विभाग को सम्भाले बैठे हुए हैं, अभी माननीय धारीवाल जी ने जो आपको सारी की सारी बातें बताई कि आपके डिपार्टमेंट में अधिकारी तक नहीं है तो कभी आपके संज्ञान यह बात नहीं आई कि अधिकारी नहीं है तो काम कौन करेगा। हम इस सदन में सिर्फ यह करने के लिए ही बैठे हुए हैं कि पिछली सरकार में यह हो गया। इससे समाधान हो जायेगा? काश्तकार को बिजली चाहिये। पढ़ने वाले बच्चों को बिजली चाहिये। वह हम दे नहीं पा रहे हैं और हम सिर्फ इस बात पर चर्चा कर रहे हैं कि, साहब, उसने नहीं किया, उसने नहीं किया।

सभापति महोदय, आज जो स्थिति बनी हुई है मैं चूंकि समय की बहुत सीमा है, मैं सीधे-सीधे अपने क्षेत्र की बात करना चाहूंगा। सीकर जिस तरह से तेजी से बढ़ रहा है, सीकर के क्षेत्र में काफी नवाचार वहां पर हुए हैं और वहां पर अनवरत आबादी का विस्तार खास तौर से शिक्षा की वजह से हो रहा है और शिक्षा में जिस तरह की लाइट वगैरह चाहिये, लोड भी बढ़ रहा है। माननीय सभापति महोदय, आपके संज्ञान में लाऊं मैं कि सीकर में सीकर शहर में 90 हजार कनेक्शन हैं। आपके विद्युत विभाग के जो नॉर्म्स हैं उनके अनुसार एक ए.इएन. के जिम्मे 15 हजार कनेक्शन होने चाहिये, 90 हजार कनेक्शन हैं। अब आप उनसे क्या उम्मीद रख सकते हैं कि जहां कहीं भी यदि फॉल्ट हो जाये तो एक ए.इएन. कितने एरिये को सम्भालेगा। वहां पर तीन ए.इएन. हैं लेकिन तीनों की स्थिति इतनी ओवरलोडेड है कि कई बार वह चाह करके भी, वह दिल से चाहता है कि समस्या का समाधान तत्काल कर दूं, लेकिन ओवरलोडेड होने की वजह से वह नहीं कर पाता।

माननीय सभापति महोदय, यदि मंत्री जी इस बात को उचित समझें कि हमको सिस्टम को रिऑर्गेनाइज करना है, सिस्टम को स्ट्रेंथन करना है तो इतने कंजूमर जहां हैं निश्चित रूप से बिजली का लोड भी बढ़ रहा है। इतने कंजूमर जहां हैं वहां पर उनको तत्काल कुछ ए.इएन्स. की और एक्स.इएन्स. को नयी पोस्ट क्रियेट करनी चाहिये क्योंकि बिजली का लोड अनवरत बढ़ेगा सीकर में। सीकर में एजुकेशन की वजह से आज जिस तरह से एक मिनी भारत बना हुआ है सीकर में।

Kas/rtm/02.08.2024/18.30/3o

वहां पर यदि हम कोई नई पोस्ट क्रिएट कर पायेंगे तो निश्चित रूप से हम क्वालिटी की बिजली दे पायेंगे। लोड बढ़ रहा है तो आपको वहां 33 के.वी. के ग्रिड भी नये बनाने चाहिये।

माननीय सभापति महोदय, 33 के.वी. की और 11 के.वी. की लाइनें आबादी के ऊपर से

गई हुई हैं। लाइनें तो पिछले 30-40 साल से हैं, चूंकि लोगों के पास जमीनें थीं, वहां पर आबादी बस गई। वहां वह तार सीधे ऊपर से जा रहे हैं और कई बार इस तरह के हादसे हुए हैं, केजुएल्टीज हुई हैं, खास तौर से पतंग के दिनों में। पिछले साल भी एक ही परिवार के दो भाई थे, दोनों के एक-एक लड़का था, दोनों की अकाल मृत्यु केवल बिजली के तार के छूने से हुई। गरीब आदमी इतना पैसा रखता नहीं कि उन लाइनों को अपने खर्चे पर कैबल करा ले या अंडर ग्राउंड करा ले। विभाग को ही इस बात का संज्ञान लेना चाहिये, खास तौर से आबादी के ऊपर से गुजरने वाली लाइनों को तत्काल या तो अंडर ग्राउंड करें या फिर कैबल करें, यह एक बहुत बड़ी समस्या है।

माननीय सभापति महोदय, सीकर संभाग बन गया और संभाग बनने से जो संभाग की अर्हताएं हैं, उसमें संभागीय चीफ इंजीनियर का पद होना चाहिये, जबकि आपने वहां नहीं लगा रखा है, वह झुंझुनूं में है। जब आपसे मिले थे, तब भी आपके संज्ञान में यह बात आई थी। यदि यह संभव हो सके तो यह करें।

माननीय सभापति महोदय, बढ़ती हुई आबादी की वजह से हॉस्टल भी काफी बढ़ रहे हैं, और भी कई तरह की बिल्डिंग वहां बन रही हैं। चूंकि रास्ते सकड़े हैं, वहां पर इनका सिस्टम डवलप करने के लिये जो ट्रांसफार्मर वगैरह लगाये जाते हैं, वह जगह इनको नहीं मिलती तो यह रास्ते में लगा देते हैं। इनको एन्श्योर करना चाहिये कि जो भी इस तरह की बिल्डिंग हैं, वहां पर यूटिलिटी स्पेस छोड़ना पड़ेगा, तभी जाकर यह वहां पर ट्रांसफार्मर वगैरह लगायें, अदरवाइज उसको मना करें। जो आदमी कुछ बनाना चाह रहा है तो उसकी जिम्मेदारी है कि वो स्पेस उपलब्ध कराये, यह भी एक बहुत बड़ी समस्या है, जिस पर संज्ञान लिया जाना चाहिये।

सभापति महोदय, पिछली बार सरकार ने 100 यूनिट तक बिजली फ्री की थी। उसके रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं। अब जो भी नया विद्युत कनेक्शन लेता है, उसको 100 यूनिट बिजली फ्री नहीं मिलती। माननीय सभापति महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदय से आग्रह करना चाहूंगा कि जो भी नये कंजूमर हैं वह सेकण्ड सिटीजन तो है नहीं, वो भी इसी देश का नागरिक है, इसी स्टेट का नागरिक है, तो सेकण्ड सिटीजन जैसा उसके साथ व्यवहार नहीं किया जाना चाहिये। जब एक फैसेलिटी एक को मिल रही है, परिवार में दो भाई है, पहले ज्वाइंट कनेक्शन था, अब दोनों ने अलग-अलग कनेक्शन कर लिये, तो दूसरा भाई यदि कनेक्शन लेता है, तो उस दूसरे वाले भाई को फायदा नहीं मिलेगा। मेरा मानना है कि यदि किसी ने दूसरा कनेक्शन लिया है, आपको पूरे कनेक्शन करने का वह सारा खर्चा दे रहा है, तो वह 100 यूनिट फ्री बिजली उसको भी मिलनी चाहिये।

माननीय सभापति महोदय, रात में जब लाइट जाती है, तो और भी ज्यादा नहीं कर सकें तो माननीय मंत्री महोदय इतना तो आपको एन्श्योर करना चाहिये कि कृषक के पास एक मैसेज चला जाये कि इतनी बजे से इतनी बजे तक लाइट जायेगी। उसकी जानकारी में ही नहीं है कि लाइट कब जायेगी। वह पूरी तरह से असमंजस की स्थिति में है। वह सिंचाई

करने की तैयारी कर रहा है और अचानक पता चला कि लाइट तो चली गई। कब आयेगी, इसका पता नहीं। कहां से गई है, आगे से गई है। यह आगे से या पीछे से जैसे भी जाये, हो सकता है कि बिजली की स्केयरसिटी है तो आप नहीं कर पा रहे होंगे, लेकिन कम से कम काश्तकार को यह तो संज्ञान में होना चाहिये कि बिजली वापस कितनी देर में आयेगी। माननीय सभापति महोदय, आज की तारीख में काश्तकार की स्थिति ऐसी हो रही है कि वह रात-रात बैठकर जागता है कि कब बिजली आये और कब मैं अपने खेत की सिंचाई करूं, क्योंकि वह अपनी औलाद की तरह फसल को पालता है। यह काश्तकार ही है जिन्होंने अन्न में हमको आत्म निर्भर किया है। धरती का सीना चीर कर वह जितना अनाज पैदा करता है, वह रात-रात जाग कर यदि अनाज पैदा करेगा, तो कब तक करेगा? उसके पास सूचना होनी चाहिये कि इतनी बजे से इतनी बजे तक बिजली नहीं रहेगी, ताकि वह चैन से सो तो सके। माननीय सभापति महोदय, यह एक बहुत बड़ी समस्या उसके सामने हो रही है।

सभापति महोदय, प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना बहुत बड़ी योजना है और मैं समझता हूं कि इस योजना से निश्चित रूप से हर स्टेट को इसका फायदा मिलेगा, लेकिन इस मामले में राजस्थान थोड़ा फिसड्डी रहा। मेरा मानना तो यह है इसमें कंपनियों के सामने कई बार इस तरह की समस्या आती है कि उनके पास मीटर नहीं है। पहले तो वह मीटर अरेंज करता है, फिर उसको डिपार्टमेंट में टेस्टिंग के लिये भेजता है। उसमें एक-एक, डेढ-डेढ महीना लग जाता है। यदि आप यह एन्श्योर कर लें कि जब जिसको जरूरत होगी, क्योंकि इसमें करीब 78 हजार रुपये मिलते हैं, चूंकि उसको खुद के बिल का भी फायदा होता है, वह लगाना चाहता है, लेकिन लगाने के लिये जिस तरह की व्यवस्था होनी चाहिये, सोलर में जो भी कंपनियां लगी हुई हैं, उनके पास इतने साधन नहीं हैं। तो आपको कम से कम उनके साथ बैठकर वार्ता करनी चाहिये कि जब वह यह कह दे कि मुझे कनेक्शन चाहिये, आप तत्काल उसको वह सारी की सारी सुविधा उपलब्ध कराये, तो इसका बड़ा फायदा मिलेगा।

सभापति महोदय, इसके साथ मैं एक और निवेदन करना चाहूंगा, चूंकि सीकर शहर का आबादी के हिसाब से काफी घनत्व है। उस घनत्व के हिसाब से जो संकरी गलियां हैं, वहां जब रोड अपग्रेड हुई तो लाइनें काफी नीचे आ गईं। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि जब मैं आपसे व्यक्तिगत रूप से मिला था, तब भी मैंने आपको जिक्र किया था कि वह लाइनें अंडर ग्राउंड होनी चाहिये।

श्री सभापति: श्रीमती अनिता भदेल।

श्री राजेन्द्र पारीक (सीकर): सभापति महोदय, एक मिनट और लूंगा। मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि एफआरटी की टीम जो इनका काम करती है।

श्री सभापति: क्लोज कीजिए।

श्री राजेन्द्र पारीक (सीकर): एक मिनट। एफआरटी की टीम काम करती है, कई बार एक्सीडेंट होते हैं और केजुएल्टीज होती है। मैं जब मंत्री महोदय से व्यक्तिगत रूप से मिला था, तब भी मैंने इनको निवेदन किया था कि आप एफआरटी पर काम करने वाले लोगों को

स्काई लिफ्टर अरेंज कराएं।

श्री सभापतिः श्रीमती अनिता भदेल। अंकित नहीं होगा।

श्री राजेन्द्र पारीक (सीकर): 000

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण): धन्यवाद माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे बिजली की चर्चा पर बोलने का अवसर दिया। आज के इस भौतिकवादी युग में बिजली जीवन के लिये नितांत आवश्यक हो गई। अभी सीकर से आने वाले माननीय सदस्य बता रहे थे कि कृषकों को बिजली की कितनी आवश्यकता है। बिना बिजली के कृषि संभव नहीं है। आजकल गृहणियों के लिये भी बिजली बहुत आवश्यक है। बिजली के बिना घर के काम असंभव से लगते हैं। शिक्षा के लिये बिजली कितनी आवश्यक है, यह तो हम बहुत अच्छे से जानते हैं। औद्योगीकरण में भी बिजली की बहुत बड़ी आवश्यकता है। यदि आपको युवाओं को रोजगार देना है तो बिजली होनी ही चाहिये। बिजली तो आज हमारी मूलभूत आवश्यकताओं में शुमार है। पिछले तीन महीनों से राजस्थान की बिजली की स्थिति पर हमारे विपक्ष के साथी बहुत चतुराई से चर्चा कर रहे थे और अपने आपको बहुत साफगोई से बचाने की कोशिश कर रहे थे।

माननीय सभापति महोदय, मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण आंकड़ा आपको बताना चाहूंगी, पिछली गवर्नमेंट में चूंकि सरकार बचानी है, बचानी है, इस उपक्रम में ही लगे रहे और इस कारण से बिजली उत्पादन होना चाहिये, छीजत कम से कम हो, इस पर कोई ध्यान नहीं दिया। चूंकि पहले कोरोना था और फिर चुनाव आ गये, ऐसी स्थिति में प्रदेश की जनता को फौरी तौर पर, एक्चुअल में नहीं, फौरी तौर पर हम कैसे संतुष्ट कर सकते हैं, कैसे बिजली दे सकते हैं, माननीय सभापति महोदय, उस बिजली की व्यवस्था उन्होंने कैसे की, 35234.55 लाख यूनिट बिजली उधार ली। कब ली, चुनाव के दो-तीन महीने पहले और नवम्बर तक, चुनाव तक, ताकि वोट पड जाये। यह 35 हजार लाख यूनिट कोई छोटा-मोटा आंकड़ा नहीं होता, बहुत बड़ा आंकडा है। उधार ली और उधार लेने के बाद इसको छोड़ दी आने वाले समय के लिये। आने वाले समय में तो बीजेपी की गवर्नमेंट बन गई। चूंकि बैंकिंग सिस्टम से केन्द्र सरकार से यह बिजली ली है, जब आप उधार लोगे तो उसको रिर्टन करना ही पड़ेगा। वर्तमान सरकार ने अप्रैल से, क्योंकि इसी समय देनी है, लेट आप दे नहीं सकते, क्योंकि आपने एग्रीमेंट में ऐसा कहा है। अप्रैल, जून और जुलाई में करीब 24 हजार लाख यूनिट बिजली और आगामी अगस्त और सितम्बर में 11232.54 लाख यूनिट बिजली आपको देनी पड़ रही है। यही वो महीने हैं जिसमें यह 35 हजार लाख यूनिट बिजली आपको रिर्टन करनी पड़ रही है। इस कारण से ही राजस्थान में बिजली नहीं मिल पा रही है। आपने बिजली उधार लेकर जनता को तो दे दी, लेकिन यह नहीं कहा कि हमने उधार लेकर दी है और आने वाली सरकार को इसको लौटाना पड़ेगा। वह लौटाने का काम हमारी सरकार कर रही है। धन्य है हमारे बिजली मंत्री नागर साहब, जिन्होंने इस वज़न को सहा है और इसके साथ राजस्थान को कैसे बिजली मिले, इसकी भी कोशिश की है।

Msk/rtm/02.08.24/1840/3p

माननीय सभापति महोदय, दो पांइट बताकर मैं अपनी बात की शुरूआत करूंगी। आप देखिये, फ्यूल सरचार्ज की बात आयी। हमारे नेता प्रतिपक्ष महोदय ने फ्यूल सरचार्ज की बात की। उन्होंने मेरा भी उल्लेख किया। माननीय सभापति महोदय, 2023 चूंकि चुनावी वर्ष था, उस 2023 में अप्रेल महीने में, अप्रेल, मई, जून, जुलाई, ये ही चार मंथ होते हैं, जब बिजली की बहुत अधिक डिमांड होती है और उस डिमांड की पूर्ति के लिए हमें बिजली इधर-उधर से खरीदनी पड़ती है। 2 हजार 594 लाख यूनिट बिजली 4 रुपये 94 पैसे के भाव से खरीदी, जबकि हमने इसी महीने, सीकर से आने वाले माननीय सदस्य, ध्यान दीजियेगा। हमने इसी महीने में 3 हजार 543 लाख यूनिट बिजली खरीदी और वह 4 रुपये 29 पैसे में खरीदी। इसका मीनिंग साफ है कि 65 पैसे कम में बिजली खरीदी है, आपके समय से 65 पैसे कम प्रति यूनिट। मई में 5 हजार 690 लाख यूनिट, 5 रुपये 43 पैसे के हिसाब से, मई में हमने खरीदी 15 हजार 436 यूनिट, 4 रुपये 66 पैसे, इसका मतलब है कि 77 पैसे कम में। जून में हमने जो बिजली खरीदी है 4 हजार 705 लाख यूनिट, 6 रुपये पर-यूनिट के हिसाब से आपने यह बिजली खरीदी। आपने तो 6 रुपये से 17 रुपये यूनिट तक भी बिजली खरीदी है। उसके कारण से राजस्थान की जनता को महंगी बिजली भोगनी पड़ी। आपने फ्यूल सरचार्ज 19-19 बार बढ़ाये हैं। हमने इसी जून के महीने में 11 हजार 98 लाख यूनिट, वह भी 4 रुपये 91 पैसे। इसका मतलब है कि 1 रुपया 9 पैसे कम में। माननीय सभापति महोदय, जब मैं 2023 और 2024 के जुलाई के महीने की बात करती हूं, जुलाई के महीने में 5 हजार 880 लाख यूनिट खरीदी, हमने जुलाई के महीने में 5 हजार 914 लाख यूनिट। लेकिन आपने जो खरीदी, वह 6 रुपये 3 पैसे थी, हमने जो खरीदी वह 4 रुपये 76 पैसे थी, इसका मतलब है 1 रुपये 27 पैसे कम दर पर हमने बिजली खरीदी। ...(व्यवधान)...

श्री सभापतिः प्लीज माननीय सदस्य, आप वहां बात कर रहे हैं और पूरा हाउस डिस्टर्ब हो रहा है।

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण): यह इसलिए कहना चाहती हूं कि मुझे मेरी सरकार और मेरे मंत्री पर गर्व होता है, क्योंकि किस तरह से कम कीमत पर बिजली खरीदकर हम लोगों को दे सकें, हम उपभोक्ताओं को कम कीमत पर बिजली उपलब्ध करा सकें, उस नाते से हमारी सरकार ने प्रयास किया और प्रयास करके यह बिजली देने का काम हमारी सरकार ने किया है।

माननीय सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगी कि हमारी सरकार आने के बाद में अनुबंधित राजकीय, केन्द्रीय और निजी क्षेत्र के संयंत्रों से बिजली उत्पादन को पूर्ण क्षमता पर संचालित करने का प्रयास किया जा रहा है, जिसका उल्लेख बाली से आने वाले माननीय सदस्य ने किया था कि आपने धौलपुर की गैस आधारित जो बिजली परियोजना थी, उसको

पूरे पांच साल बंद रखा। लेकिन हमारी सरकार में आने के बाद में उस गैस परियोजना पर बिजली उत्पादन प्रारंभ हुआ है और उस बिजली उत्पादन के प्रारंभ होने से हमें बिजली मिलना प्रारंभ हुई।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपको इसके अतिरिक्त बताना चाहूंगी कि 2023 में आप साफगोई से बच गये। भगवान ने आपके ऊपर कृपा की। भगवान ने क्या कृपा की कि उस समय, जब 2024 में हीटवेव चल रही है, इन्हीं महीनों में आपके समय में बिपरजॉय तूफान आ गया, 2023 में। याद करें। वह बिपरजॉय तूफान आने से टैम्प्रेचर नीचे गिरा और टैम्प्रेचर नीचे गिरने से डिमांड कम हो गयी। डिमांड कम हुई इस वजह से आप बिजली दे पाये। लेकिन हमारे साथ में उसके विपरीत हुआ।

श्री राजेन्द्र पारीक (सीकर): भगवान से प्रार्थना कीजिये कि ऐसा तूफान आ जाये। ...(व्यवधान)...

श्री सभापति: प्लीज सदस्य, आप बोल रहे थे तो कोई डिस्टर्ब नहीं किया। प्लीज, पारीक साहब।

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण): मैं बता रही हूं। आप बोले थे, तब मैं नहीं बोली थी। प्राकृतिक चीजें हैं, उन प्राकृतिक चीजों में आप न तो कुछ कर सकते हैं, न मैं कुछ कर सकती हूं। ...(व्यवधान)...

श्री सभापति: प्लीज पारीक साहब, अभी आपके पड़ोस में अख़बार की कटिंग बता रहे थे।

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण): इसलिए मैं निवेदन करना चाह रही हूं कि 2022 में अप्रेल महीने में 2 हजार 750 लाख यूनिट, 2023 में 2 हजार 466 लाख यूनिट, वहीं डिमांड 2 हजार 716 लाख यूनिट अप्रेल 2024 में। मैं तो इतना भर कहना चाह रही हूं, मेरे कहने का मीनिंग इतना भर है कि कैसे डिमांड और सप्लाई में अन्तर होता है और बहुत सारे कारण उस पर डिपेंड होते हैं। उसमें प्रकृति भी एक बहुत बड़ा कारण होती है। माननीय सदस्य, मैं आपको इतना ही निवेदन करना चाहती हूं। माननीय सभापति महोदय, ये कह रहे थे कि हमने कैसे कुछ नहीं क्या। आप देखिये, वर्तमान सरकार द्वारा भविष्य की ऊर्जा आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए 3 हजार 325 मेगावाट कोयला आधारित और 28 हजार 500 मेगावाट की अक्षय ऊर्जा आधारित परियोजनाओं को उत्पादन निगम द्वारा एवं केन्द्रीय उपक्रमों एनटीपीसी, एनजीईएल और कोल इण्डिया प्राइवेट लिमिटेड के साथ एमओयू करके इसको किया है। माननीय सभापति महोदय, चूंकि प्रदेश की बिजली की स्थिति क्या है और उसके कारण से आज की समस्या पर प्रकाश डालना जरूरी थी।

मैं मेरे विधान सभा क्षेत्र, अपने शहर की कुछ समस्याओं के बारे में निवेदन करके अपनी बात को पूरा करना चाहूंगी। अजमेर डिस्कॉम चूंकि फ्रेंचाइजी पर टाटा पॉवर को दिया हुआ है, इसलिए माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगी पूरे अजमेर शहर बिजली फ्रेंचाइजी पर टाटा पॉवर को दी हुई है, टाटा पॉवर न तो कोई मेटेंनेस करती है, उनके यहां जितने ए.ईएन. सर्कल हैं, जितने 15 हजार की आबादी पर जितने ए.ईएन. सर्कल होने

चाहिए, ऑलरेडी हमारे यहां तीन-चार ए.ईएन. सर्कल हैं, लेकिन उन ए.ईएन. सर्कल को बन्द करके टाटा पॉवर हाथ पर हाथ रखकर बैठी है। मैं कल की घटना बताती हूं। सुबह 10 बजे से लाइट गयी हुई थी, रात के 10 बजे तक लाइट नहीं आयी। मैंने चार बार उनको फोन किया कि लाइट क्यों नहीं आ रही है, जबकि कल बारिश थी। टाटा पॉवर को आप पाबंद करिये कि लोगों की इस बिजली की समस्या को दूर करे। दूसरी तरफ जो हमारे ऊपर से हाईटेंशन लाइन जा रही है। क्योंकि शहर है और आबादी धीरे-धीर बढ़ गयी। चूंकि अजमेर शहर अरावली की पर्वत श्रृंखलाओं से घिरा हुआ है। उस अरावली की पर्वत श्रृंखला के ऊपर कई अवैध कच्ची बस्तियां भी हैं, लेकिन हम उनको तोड़ तो नहीं सकते। (समय समाप्ति सूचक घंटी)

श्री सभापति: प्लीज आधा मिनट में समाप्त करें।

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण): हमने मकान बनाने की अनुमति दी। उनको बिजली का कनेक्शन दिया, पानी का कनेक्शन दिया, सड़क बनायी। मेरा इतना निवेदन है कि जो 11 केवी, 32 केवी की जो हाईटेंशन लाइनें हमारी आबादी के ऊपर से जा रही हैं, उनको किसी तरह से कोई स्कीम बनाकर कोई प्रोजेक्ट लाकर आप उसकी अंडरग्राउंड कैबलिंग करने का काम करेंगे तो चोरी भी रूकेगी और हम अच्छी गुणवत्ता वाली बिजली दे पायेंगे।

मेरा एक तीसरा निवेदन है कि अजमेर में चूंकि फ्लोटिंग पोपूलेशन बहुत है, दरगाह की वजह से और पुष्कर की वजह से।

श्री सभापति: श्री रामनिवास जी गवाड़िया।

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण): बस लास्ट पाइंट बोल रही हूं। हमारे यहां बहुत सारे अवैध रोहिंग्या बांग्लादेशी आकर मकान बना लिये, दरगाह क्षेत्र में। उन्होंने बिना लीगल कनेक्शन लिए, हम लीगल तरीके से बिजली के कनेक्शन लेते हैं। किसी भी अधिकारी की, टाटा पॉवर के अधिकारी की वहां जाने की हिम्मत नहीं है कि वे वहां जायें..(व्यवधान)...

श्री सभापति: माननीय सदस्य, बोलिए।

श्री रामनिवास गावड़िया (परबतसर): माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे बिजली जैसे महत्वपूर्ण और गंभीर विषय पर बोलने का अवसर दिया, उसके लिए धन्यवाद। सभापति महोदय, ऊर्जा सही रूप में प्रदेश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी के रूप में जानी जाती है। न केवल उद्योग, चाहे कृषि सम्बन्धी कार्य हो, चाहे अन्य सेवा क्षेत्र हो। अगर आर्थिक रूप से गतिविधियों का संचालन करने का कार्य किया जा सकता है तो वह बिजली के माध्यम से किया जा सकता है। माननीय सभापति महोदय, बिजली ऐसा विभाग है, जो प्रदेश के लाखों परिवारों में रोशनी देने का काम करता है। लेकिन आज इस प्रदेश की स्थिति ऐसी है कि सत्ता पक्ष के लोग, जो आंकड़े बताकर वाहवाही लूटने का काम कर रहे हैं, सभापति महोदय, हम इस सदन में इस प्रदेश की 8 करोड़ जनता के आशीर्वाद से यहां आते हैं। आज गांवों में स्थिति यह है कि उनको आंकड़ों से मतलब नहीं है। उनको समय पर बिजली चाहिए। जब

ग्रहणी शाम को चूल्हा जलाती है तो वह देखती है कि अंधेरा है। मजदूर जब मजदूरी करके घर आता है और वह कोशिश करता है कि उसके बच्चे को वह अपनी निगरानी में दो घंटे पढ़ाई करवा सके, लेकिन उस समय इस प्रदेश में अंधकार रहता है। सभापति महोदय, इस प्रदेश की सरकार ने, ये सदन में बैठकर चाहे कितनी भी वाहवाही लूट लें, जब यह सदन दो-तीन दिन बाद यहां से एडजोर्न हो जाएगा, उसके बाद जब हम लोग गांवों में जाएंगे तो इन लोगों को पता चलेगा कि किस तरह से गांवों में हाहाकार मचा हुआ है। आपकी सरकार ने बिजली और पानी के मुद्दे पर इकबाल खतम कर लिया। आने वाले समय में आप सब लोगों को उसका भुगतान करना पड़ेगा, यह मैं इस सदन में आपके माध्यम से कहना चाहता हूं। माननीय सभापति महोदय, सरकारी आंकड़े यह कहते हैं कि सरकार लगभग 24 हजार मेगावाट बिजली का उत्पादन कर सकती है। मैं लंबी-चौड़ी बात नहीं करते हुए पिछले महीने जुलाई की बात करूं तो यह प्रदेश की जनता को लगभग 16 हजार मेगावाट बिजली चाहिए थी, लेकिन इस राजस्थान की सरकार केवल मात्र 10 से 11 हजार मेगावाट बिजली उपलब्ध करवा पायी, जो हम सब लोगों के लिए शर्मनाक है।

mdp/rtm/02.08.2024/18:50/3q

सभापति महोदय, आज गांवों में विजिलेंस के नाम पर लूट मचाई जा रही है। इनके अधिकारियों पर इनका अंकुश नहीं है। सदन में मंत्री जी के द्वारा जो जवाब दिया जाता है, उस पर कोई इम्प्लीमेंट नहीं होता, क्योंकि अधिकारियों पर इनकी कोई लगाम नहीं है। ब्यूरोक्रेसी पूर्णतया इस सरकार के ऊपर हावी हो रखी है। अघोषित बिजली कटौती के नाम पर घंटों तक हर रोज लाइट काट ली जाती है। कोई पता नहीं होता है कि कब आयेगी, कोई फिक्स समय नहीं है। इन्होंने कोई सीमा तय नहीं कर रखी है कि पांच घंटे बाद आयेगी या दस घंटे बाद आयेगी। आज इस प्रदेश की स्थिति ऐसी है कि हम सब लोगों को इस बात के लिए दुःख होता है कि हम सब लोग इस सदन में चुनकर आये हैं, जनता ये कहती है कि माननीय सदस्य, हमें मतलब नहीं है कि सरकार आपकी है या नहीं, हमने आपको यहां से चुनाव जीता कर भेजा है तो बिजली की व्यवस्था कीजिए। मैं इस सरकार से इतना ही कहना चाहता हूं कि अगर आपकी सरकार का थोड़ा-सा भी इकबाल कायम है, तो माननीय मंत्री जी जब आप सदन में जवाब दें तो इस बात का ध्यान रखना कि सदन में जो 200 सदस्य आते हैं और जो अधिकारी आईएएस, आईपीएस, जिनके घरों में हर समय बिजली रहती है, आप इस सदन में इस बात का जवाब देना और आज से घोषणा कर देना कि रात के समय 5 घंटे हम सब लोगों के भी बिजली कटौती रहेगी और कोई अल्टरनेट व्यवस्था नहीं होगी, ताकि वह किसान, वह मजदूर यह सांत्वना लेकर सो सके कि जो सरकार अपने घर में रोशनी नहीं दे सकती, वह हमारे बच्चों को क्या रोशनी देगी, हमारे घर में क्या उजाला करेगी? किसान इस बात की सांत्वना लेकर सो सके कि इस सरकार का इकबाल खतम हो गया। ये बिजली-पानी नहीं दे सकती।

माननीय सभापति महोदय, आज स्थिति यह है कि ये लोग कह रहे हैं कि कृषि कनेक्शन, कृषि कनेक्शन तो दिसम्बर, 2023 के बाद जिसने एप्लाई किए हैं, उसका अब तक नंबर नहीं आया और गांव में जो कृषि कनेक्शन हो रहे हैं, किसान अपने खर्चे पर कनेक्शन करवाता है। उसके बाद ठेकेदार और इनके अधिकारी मिलीभगत करके कार्यादेश निकलवाकर उसका बिल भुगतान खुद के नाम करवा लेते हैं। साथ ही जब उसका ट्रांसफार्मर जल जाता है और वह लेने जाता है तो खुद के किराये पर लेकर आता है। खुद भाड़ा देता है और उसके बाद इनके अधिकारी उसके बिल में कोई समायोजन नहीं करते। मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि इस ओर हम सब लोगों को ध्यान देना चाहिए, क्योंकि जिस अन्नदाता की वजह से हम सब लोग सदन में है, कम से कम उसका तो ध्यान रखना चाहिए।

सभापति महोदय, आज 63 केवी और 100 केवी के ट्रांसफार्मर किसी भी विभाग में, इनके जो भी विभाग हैं, वहां कहीं भी उपलब्ध नहीं है। किसान परेशान होकर वहां जाता है तो उसको रोज-रोज चक्कर कटवाए जाते हैं। चक्कर काटने के बाद वह खुद के खर्चे पर लेकर आता है। मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि आप विशेष रूप से 63 और 100 केवी के ट्रांसफार्मर की समय पर अविलेबिलिटी करवाइए ताकि किसान को उसका फायदा मिल सके। मेरे से पहले कई सदस्यों ने कहा कि आबादी क्षेत्र के ऊपर जो हाईटेंशन लाइन है, उसी तरह सरकारी स्कूलों के ऊपर से भी 11 हजार और 33 हजार की लाइनें, सरकार ऐसी कोई कार्य योजना बनाए ताकि पूरे प्रदेश में जितने भी सरकारी स्कूल हैं, उनके ऊपर से विद्युत लाइनों को हटाया जाए, क्योंकि हम लोग कहते हैं कि हमारा आने वाला भविष्य इस स्कूल में पढ़ता है। उस भविष्य के लिए हम लोग यहां इस सदन में बैठकर क्या कर रह हैं? सरकार अपनी योजना बनाकर पूरे प्रदेश के स्कूलों के ऊपर से इन लाइनों को हटाया जाए। किसान के खेत के ऊपर से जो हाईटेंशन लाइन जा रही है, उसका मुआवजा किसान को दिया जाए।

माननीय सभापति महोदय, ऐसे कई मोहल्ले, कई कस्बे हैं, जहां पुराने बिजली के तारों का जाल फैला हुआ है। रोजाना वहां एक्सीडेंट होते हैं, दुर्घटनाएं होती हैं, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से मांग करता हूं कि आप इसके लिए कोई भूमिगत योजना बनाएं कि उस कैबल को भूमिगत किया जा सके, जिससे दुर्घटनाओं से बचा जा सके। आबादी में रहने वाले लोगों को सुरक्षा मिल सके। इस बात पर चर्चा होनी चाहिए। आज ये लोग बात कर रहे हैं सोलर सब्सिडी की। कितनी भी हम लोग यहां बात करेंगे, लेकिन कोई भी सरकार आयेगी तो कहेगी कोयले की कमी है। लगभग 58 परसेंट आज हम लोग कोयले से बिजली का उत्पादन कर रहे हैं। 10 से 12 परसेंट मात्र हम लोग सोलर से बिजली का उत्पादन कर रहे हैं। हम लोगों को सोलर सब्सिडी पर ध्यान देना चाहिए। जब हम लोग सोलर पर काम करेंगे तो निश्चित तौर पर हम लोग परिणाम पर पहुंच पाएंगे ताकि हम लोग कोयले के ऊपर या सरकार के ऊपर निर्भर नहीं रहे। कभी हम लोग कह देते हैं कि केन्द्र में हमारी सरकार नहीं

है। अब तो केन्द्र में भी आपकी सरकार है। फायदा लीजिए, क्योंकि आपके नेता प्रतिपक्ष हर सवाल पर यही कहते थे कि केन्द्र में हमारी सरकार है, आप लोग हमारे साथ चलिए। अब तो किसी की जरूरत ही नहीं है। माननीय मंत्री जी आप स्वयं जाइए, आपकी सरकार जाए और इस पर ध्यान दें।

किसान, एलडी मैसेज के नाम पर जो रोजाना बिजली काटी जाती है। माननीय सभापति महोदय, मेरा आपके माध्यम से निवेदन है कि आपके अधिकारी चाहे किसी भी वजह से लाइट काटे, लेकिन वे लोग इतना-सा कहकर इतिश्री कर लेते हैं कि एलडी मैसेज है। मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि इस पर ध्यान दें। दूसरा, एफआरटी की जो टीमें काम कर रही हैं, वह बिना गाड़ी के संचालित हो रही हैं। वह समय पर फॉल्ट नहीं निकाल पाती, जिसका खामियाजा किसान को भुगतना पड़ता है। इसलिए एफआरटी की जो टीम है, उसका अलग से कंट्रोल रूम बनाया जावे, उसकी मॉनिटरिंग की जाए और उसको गाड़ी और जो भी संसाधन हैं, उपलब्ध कराए जाएं।

(समय बजे)

(श्री वासुदेव देवनानी, अध्यक्ष, पदासीन)

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि हमारे नागौर जिले में जो कृषि कनेक्शन हैं और जिनके बिल हैं, चूंकि हमारा जिला डीडवाना कुचामन अलग से बन गया, लेकिन प्रिंटिंग प्रेस अभी-भी, वहां से प्रिंट होकर आता है नागौर से, जबकि डीडवाना में हमारा सुचारु रूप से कार्यालय है और वहां प्रिंटिंग मशीनें भी हैं।

श्री अध्यक्ष: श्री अंशुमान सिंह भाटी। पांच मिनट में पूरा कीजिए।

श्री रामनिवास गावड़िया (परबतसर): आप यह कोशिश करें कि किसान को बिजली का बिल लेट मिलता है, इसलिए डीडवाना से उसको प्रिंट करवा कर किसान को दिया जाए, ताकि उसका फायदा किसान को मिल सके।

सदन की कार्यवाही

विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

श्री जोगेश्वर गर्ग (सरकारी मुख्य सचेतक): अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन का समय एक घंटा और बढ़ाया जावे।

श्री अध्यक्ष: नौ बजे तक?

श्री जोगेश्वर गर्ग (सरकारी मुख्य सचेतक): एक घंटा।

श्री अध्यक्ष: क्या सदन का समय एक घंटा बढ़ाया जावे?

(स्वीकृत)

सदन का समय एक घंटा बढ़ाया गया।

पांच मिनट में सब लोग समाप्त कीजिए।

राज्य में बिजली की स्थिति पर विचार

श्री अंशुमान सिंह भाटी (कोलायत): आदरणीय अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बिजली की

स्थिति पर अपने विचार रखने का मौका दिया, उसके लिए मैं आपका बहुत-बहुत आभार प्रकट करता हूं।

मुझसे पूर्व विपक्ष के वक्ताओं ने यह बताया कि कैसे राजस्थान की जनता ट्रिपिंग, पॉवर कट, कम वोल्टेज, पॉवर शार्टेज जैसी समस्याओं से गुजर रही है। मैं पूछना चाहूंगा कि क्या ये समस्या एक दिन, एक रात में उत्पन्न हुई? जो खुद की जिम्मेदारियों से पांच साल भागते रहे, वे आज हमसे पांच महीने का हिसाब मांग रहे हैं। आज के परिदृश्य में मुझे एक कहावत याद आती है -

बेरी नेत बुलाया, कर भाया सुं रोस,
हाथा कीजै काम और कीन्है दीजे दोस

राजस्थान की जनता को यह भी पता लगना चाहिए कि जिस समस्या से वह गुजर रही है, उसका सही कसूरवार पूर्ववर्ती सरकार के अन्दर सत्ता के दो केन्द्रों की लड़ाई थी। आपने जिस प्रकार से लूट की छूट दी, उसी कारण से राजस्थान की जनता के सपनों व उम्मीदों पर बहुत बड़ा कुठाराघात किया। मैं उस जिले, उस क्षेत्र से आता हूं जिसने विगत सरकार में लगातार पांच साल ऊर्जा मंत्रालय सँभाला। जिनसे खुद का जिला नहीं संभाला गया, खुद का गृह क्षेत्र नहीं संभाला गया, वे राजस्थान की बात करते हैं।

बीकानेर जिले में एकमात्र 400 केवी की जीएसएस 2019 से ओवरलोड चल रहा था। यहां 630 एमवीए के ट्रांसफार्मर पर 900 का लोड है। बड़े नये ट्रांसफार्मर बनने के लिए 6 महीने लगते हैं। मैन्यूफेक्चरिंग के बाद ट्रांसपोर्टेशन, इंस्टालेशन और चार्जिंग के अन्दर 6 महीने अतिरिक्त लगते हैं। तकरीबन 12 से 15 महीने का टाइम लगता है। 2019 से हमें लगातार 500 एमवीए के अतिरिक्त ट्रांसफार्मर की आवश्यकता थी, परंतु आपने उस पर ध्यान नहीं दिया। मैं तो धन्यवाद देना चाहूंगा हमारे ऊर्जा मंत्री जी का, जिन्होंने इस विषय की गंभीरता को देखते हुए जून, 2024 के अन्दर नये 500 एमवीए ट्रांसफार्मर के परचेज आर्डर निकाले, जिससे निश्चित रूप से पूरे बीकानेर जिले को एक राहत मिलेगी।

इसी प्रकार से मैंने अभी हाल ही में सर्वे कराया। एक बज्जू एईएन सर्किल के अन्दर 8 हजार से अधिक 12 मासी ढाणी आज भी अंधेरे के अन्दर रह रही है। मेरे कोलायत विधान सभा क्षेत्र के अन्दर 12 हजार ऐसे परिवार हैं, जो आज भी अंधेरे में रह रहे हैं। भारत-पाक सीमा पर हिन्दुस्तान के आखिरी छोर पर इस रेगिस्तान की भीषण गर्मी में बिना पानी, बिना बिजली के वे लोग जी टिका कर बैठे हैं। जब केन्द्र सरकार की आरडीएसएस योजना आई तो उनको एक उम्मीद बंधी कि कोई तो हमारी सुध लेगा। परंतु जैसे-जैसे काम चालू हुए, सर्वे चालू हुआ, धरातल पर काम चालू हुआ, आपने ऐसा पक्षपात किया कि चलते कार्य के अन्दर पात्र घरों को छोड़कर खुद के खास लोगों के आपने लाइट लगायी। जो वास्तविक आदमी वहां पर परेशान हो रहा था, वह आज भी परेशान हो रहा है। आप यह देखिए कि हमारा क्या कसूर था, 77 साल बाद भी हम उड़ीक रहे हैं कि आप सब हमारा ध्यान देंगे।

अध्यक्ष महोदय, मैं उम्मीद करता हूं कि इसी प्रकार से सौभाग्य योजना के अन्दर केन्द्र

सरकार ने कांग्रेस सरकार को 2021-22 के अन्दर तकरीबन 358 करोड़ का फंड दिया। उसके अन्दर से बीकानेर जिले को तकरीबन 93 करोड़ का फंड मिला, परंतु देखिए 6 महीने तक डिस्कॉम वह फाइल दबाती रही। उन्होंने टेंडर नहीं किए।

Ans/rtm 19.00 4a 02.08.2024

जब देखा कि आखिरी एक महीना बचा है, तुरंत प्रभाव से टेंडर करना पड़ेगा नहीं तो फण्ड लेप्स होगा, हमें ओलमा मिलेगा। तो आनन-फानन में उन्होंने टेंडर किया उसका नतीजा यह निकला कि आप ना तो वहां काम करा पाए, ना आपके पास सामान की उपलब्धता हुई, ना ही ठेकेदारों ने उस पर इंटरेस्ट दिखाया, उस कारण से तकरीबन यह 358 करोड़ रूपये भी लैप्स हुए। मैं उम्मीद करुंगा, इस आधुनिक भारत के अन्दर मोदी जी सरकार के अन्दर, भजनलाल जी सरकार के अन्दर हम आरडीएफएस योजना के अन्दर जो भी ढाणी वंचित है, उसमें कांग्रेस-बीजेपी छोड़ते हुए, जो भी पात्र ढ़ाणी है उनका नया सर्वे कराए और जो आज अंधकार में रह रहे हैं, उनके घर में अपन रोशनी लेकर आए।

मैं आपसे बात करना चाहूंगा कि धरातल पर कोई भी काम नहीं किया गया। हम यह देखते हैं कि थोथी घोषणाओं का एक अम्बार लगा दिया गया, सिर्फ सस्ती लोकप्रियता के लिए, धरातल पर कोई काम नहीं किया गया। हमारे क्षेत्र में 4 जीएसएस मौखिक रूप से आपने घोषित कर दिए परन्तु आज तक बिलकुल भी काम नहीं किया गया।

श्री अध्यक्षः बैठिए। कुमारी रीटा चौधरी। पांच मिनट।

श्री अंशुमान सिंह भाटी (कोलायत): हुकुम, मैं लास्ट में एक सुझाव दे रहा हूं।

श्री अध्यक्षः विराजिए।

श्री अंशुमान सिंह भाटी (कोलायत): मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि जिस प्रकार से पश्चिमी राजस्थान में..

कुमारी रीटा चौधरी (मंडावा): अध्यक्ष महोदय, बहुत ही गंभीर मुद्दे पर इस सदन में चर्चा हो रही है।

श्री अंशुमान सिंह भाटी (कोलायत): जिस प्रकार से आंधी-तूफान चलते हैं, उससे हमारे जितने भी पोल है..

श्री अध्यक्षः बैठिए। 9 बजे बाद नहीं चलाएंगे।

कुमारी रीटा चौधरी (मंडावा): आज जो स्थिति पूरे राजस्थान में बिजली की है, इससे पहले कभी भी नहीं थी। पूरे राजस्थान में भी ग्रामीण क्षेत्र के अन्दर बद से बदतर जो स्थिति बिजली के मामले में हो रही है, चारों तरफ त्राहि-त्राहि हो रही है।

सरकार कोई भी रही हो, कांग्रेस की रही हो या बीजेपी की रही हो, एक जन कल्याणकारी सरकार का यह दायित्व होता है कि वह अपनी जनता को अच्छी बिजली दे, अच्छा पानी दे, अच्छी शिक्षा दे, अच्छी चिकित्सा दे। अध्यक्ष महोदय, मुझे दु:ख के साथ कहना पड़ रहा है, कोई संकोच भी नहीं है कि यह सरकार पूरी तरह से बिजली के मामले में फेल है।

ऊर्जा मंत्री जी, मैं आपका ध्यान किसानों की तरफ ले जाना चाहूंगी। आपका शासन आने के बाद कृषि कनेक्शन, कुओं के सामान्य कनेक्शन है वह बंद हो गए हैं। मेरे विधान सभा क्षेत्र मंडावा में कनेक्शन नहीं हो रहे हैं। लम्बित कनेक्शन 600 हैं, डिमांड नोट जमा हो गया। किसानों ने किस तरीके से अपना डिमांड नोट जमा कराया होगा। छह-छह महीने, साल-साल भर हो गया डिमांड नोट जमा कराए, उनके कनेक्शन नहीं हुए। कृपया करके, मंत्री महोदय, किसानों पर दया करके, उनकी व्यवस्था करवाओ, उनके कनेक्शन करवाओ।

दूसरा, मंडावा विधान सभा के अन्दर या तो यह हो गया कि गैर भाजपाई विधायक है उनके क्षेत्र के अन्दर बिजली नहीं देंगे। आपको भी मैंने कहा, आपके अधिकारियों को मैंने बताया कि मंडावा के अन्दर भेदभाव हो रहा है, गांव के अन्दर बिजली नहीं दी जा रही है। ग्रामीण क्षेत्र में जब शाम को 6 बजे महिला रसोई में खाना बनाने जाती है, तो बिजली चली जाती है और बिजली 12 बजे, 01 बजे आती है। ना तो बच्चे पढ़ पाते हैं, ना वह महिला खाना पका पाती है, ना घर के सदस्य खाना खा सकते हैं।

आपने सौर ऊर्जा पर बहुत ध्यान दिया। आप कुसुम योजना की बात करते हैं, मैं स्वागत करती हूं, मंत्री महोदय, लेकिन रात के समय ग्रामीण क्षेत्र में किसानों को कैसे बिजली मिलेगी, उस पर हम लोगों को ध्यान देने की आवश्यकता है।

अभी मुख्य मंत्री जी ने एमओयू किया। सौर ऊर्जा पर पूरा जोर दे दिया। हमारे प्रधान मंत्री जी भी सौर ऊर्जा की बात कर रहे हैं, केवल सौर ऊर्जा से काम नहीं चलेगा। आप देख लीजिए, यूरोप में भी सौर ऊर्जा पर बहुत ध्यान दिया, सौर ऊर्जा का खूब प्रचार हुआ, आज यूरोप की व्यवस्था पूरी तरह से फेल हो गई है, उसका ग्रिड फेल हो गया है। यूरोप से अच्छा ग्रिड हमारे यहां नहीं है, हमारा कमजोर ग्रिड है। आपकी कुसुम योजना अच्छी है। रात के समय लोगों को बिजली कैसे मिले, उस पर भी आप लोगों को ध्यान देने की आवश्यकता है।

अध्यक्ष महोदय, अभी अनिता जी बोल रहे थे, उससे पहले बाली से आने वाले पूर्व मंत्री जी बोल रहे थे। मैंने पिछले कुछ प्रसंग सुने थे उत्तर के अन्दर। ऊर्जा मंत्री ने भी सारा का सारा ब्लेम कांग्रेस की सरकार पर लगाया और बैंकिंग को जिम्मेदार माना।

मैं एक बात बताऊंगी। मेरे पिताजी रामनारायण चौधरी जी ऊर्जा मंत्री बने, उस समय राजस्थान की हालत बहुत खराब थी। वह मुख्य मंत्री जी के पास गए, उन्होंने उनसे कहा कि आज किसानों की स्थिति बहुत दयनीय है, उनको ट्रांसफार्मर टाइम पर नहीं मिलता, उसके पैसे उनको नहीं मिलते, आने-जाने का किराया भी किसान से लिया जाता है, तो मुख्य मंत्री महोदय आप बिजली की व्यवस्था करें। मुख्य मंत्री जी ने जवाब दिया, चौधरी साहब बहुत ज्यादा ऋण लेना पड़ेगा। तत्कालीन ऊर्जा मंत्री, चौधरी साहब ने कहा कि हमारी जिम्मेदारी है कि हम जनता को किस तरीके से बिजली मुहैया कराए। अगर आपको 200 करोड़ रुपये का लोन लेना है तो आप ले, लेकिन किसानों को पूरी बिजली मिले, क्योंकि उनके ऊपर हमारे देश की अर्थव्यवस्था टिकी हुई है। जब तक आप इस सोच के साथ कि जनता को हम लोगों को सारी सुविधाएं मुहैया करानी है, जिसके अन्दर बिजली बहुत महत्वपूर्ण है, नहीं तो हम

आगे नहीं बढ़ सकते।

आपने कांग्रेस को कोस लिया, हमने बीजेपी की बात कर ली। मंत्री महोदय, 8 महीने हो गए, अब तो आप लोग जागो उस भ्रम से कि कांग्रेस सरकार की वजह से यह हो रहा है। कांग्रेस ने बैंकिंग से बिजली खरीदी थी उसके माध्यम से उसके अन्दर आपने अप्रैल का महीना निकाल दिया, जनवरी, फरवरी, मार्च। अब आप मुझे बताइये कि रबी की फसल के लिए आपका क्या इंतजाम है? आने वाली दिपावली के लिए आपका क्या इंतजाम है। यह मुख्य मुद्दे हैं, जिन पर यहां चर्चा होनी चाहिए।

हमारे मंत्री जी बहुत संवेदनशील है, क्योंकि हम सब बुलाकर इन्होंने चर्चा भी की। मंत्री महोदय, आप विशेषकर ग्रामीण क्षेत्र व किसानों के ऊपर न्याय करते हुए, बिजली को और बढ़ाने की कृपा करें। बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री अध्यक्षः श्रीमती कल्पना देवी।

श्रीमती कल्पना देवी (लाडपुरा): माननीय अध्यक्ष जी, आपने बहुत ही महत्वपूर्ण विषय बिजली पर चर्चा का समय रखा और मुझे बोलने का अवसर दिया, उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। बिजली की स्थिति क्या है, सदन में यहां सभी विराजे हैं, सब उस समस्या से अवगत हैं। इसी वजह से आपने इतनी महत्वपूर्ण चर्चा के लिए समय दिया है। मेरे से पूर्व, हमारे बाली से आने वाले माननीय सदस्य ने खूब अच्छी तरह से, खूब विस्तार में जानकारी दी कि पिछली सरकार ने क्या किया, उसके पहले सरकार ने क्या किया, तो मैं दुबारा उन बातों को दोहराना नहीं चाहती।

हमारी पूर्ववर्ती भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, उसने प्रदेश में बिजली का डिपार्टमेंट था उसको प्रोफिट में छोड़ा लेकिन आप अभी 2023 में जब गए, आपने राज्यपाल जी के अभिभाषण में कहलवाया था कि 88 हजार करोड़ का घाटा छोड़कर गए हैं। उदय योजना केन्द्र की एक योजना थी। सारे बिजली के बोर्ड हैं, उनको खराब स्थिति से निकालने के बाद भी, जो स्थिति आप करके गए हैं, यह कोई छिपी हुई बात नहीं है।

नेता, प्रतिपक्ष कह रहे थे कि हमें ट्रांसफार्मर नहीं मिल रहे तथा और क्या-क्या स्थिति है, उसके बारे में भी बताया। माननीय कोटा उत्तर के सदस्य भी कह रहे थे कि कोटा में क्या स्थिति है। पिछली बार जब मैं विधायक बनी थी तो 2019 में पहली बजट घोषणा थी कि मेरे क्षेत्र में 132 केवी का जीएसएस बनना था, परन्तु पूरे पांच साल निकल गए लेकिन उस जीएसएस का कोई अता पता नहीं था। मैं हमारे माननीय मुख्य मंत्री भजन लाल जी को व ऊर्जा मंत्री जी को बहुत-बहुत धन्यवाद देती हूं कि आते ही उन्होंने जोर लगाया कि यह जीएसएस तुरंत कम्प्लीट किया जाए। माननीय मंत्री जी ने खुद इसमें दखल देकर इसको चालू करवाया। मेरे क्षेत्र की जनता की ओर से माननीय मुख्य मंत्री जी व माननीय ऊर्जा मंत्री जी को इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

कृषि कनेक्शन की बात कर रहे थे। मैं कहना चाहती हूं कि 120 कृषि कनेक्शन 2016 से मार्च, 2023 तक के पेंडिंग हैं। पूरी राशि जमा भी हो चुकी थी, फिर भी एक भी कनेक्शन

नहीं मिल रहा था। मेरे इस विषय पर भी आग्रह करने के बाद, अभी थोड़े दिन पहले 120 में से 20 कनेक्शन तो दिए गए हैं, मंत्री जी के आश्वासन पर मैं भरोसा करती हूं, आने वाले समय में बाकी भी पूरे हो जाएंगे।

मैं धन्यवाद देना चाहती हूं कि आपने बजट में जो घोषणाएं की हैं, जिस तरीके की स्थिति खासतौर से हमारे ग्रामीण इलाक़े में है, रात में बिजली नहीं आ रही, जब बच्चे पढ़ने जाते हैं तो बिजली नहीं है, यह स्थिति एक दिन में नहीं हुई है। आपने पांच साल में इंफ्रास्ट्रक्चर पर एक रुपया भी नहीं लगाया, उसके कारण जो भट्ठा ठप हुआ है, उसका हमको आज यह भुगतना पड़ रहा है।

VPS-RTM-02.08.202-19.10-4b

परंतु इस बजट में जिस तरीके से ट्रांसफार्मर्स और इंफ्रास्ट्रक्चर पर बजट की घोषणा में आपने सभी क्षेत्र में पैसे दिये हैं तो मैं यह समझती हूं कि आने वाले समय में यह समस्या भी दूर हो जायेगी। आपने मेरे क्षेत्र में अर्जुनपुरा, नार्दन बाईपास, चन्देसर, मंडाना कसार, मानसगांव सब जगह पर जी.एस.एस. दिये हैं, उसके लिए धन्यवाद पर साथ ही इसके साथ मैं एक छोटी सी मांग रखना चाहती हूं कि मेरे धाकडखेडी क्षेत्र में भी 132 केवी जी.एस.एस. दें और उद्योग नगर क्षेत्र के लिए भी जो बहुत ही घनी आबादी का क्षेत्र है और वहां पर इंडस्ट्रियल एरिया है, वहां पर भी बिजली की बहुत मांग रहती है, इसके लिए भी मैं आपसे मांग करती हूं।

साथ ही, मेरे से पूर्व बहुत सारे माननीय सदस्यों ने भी इसकी मांग की है कि आबादी क्षेत्र में जो हाईटेंशन की लाइनें जाती हैं, जो घर के ऊपर है तो उसके लिए प्लीज, एक स्पेशल प्रोजेक्ट बनाकर अंडरग्राउंड करने की आप कृपा करें। (समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र में एक KEDL कम्पनी है जो शहरी क्षेत्रों में बिजली का संचालन करती है। वहां पर लगभग 1 लाख 40 हजार लोग रहते हैं और इसमें बहुत ही समस्या आ रही है। मेंटिनेंस के नाम पर यह आये दिन सप्लाई बंद करते हैं और कई बार रात को भी बिजली गुल हो जाती है और अधिकारियों का सिर्फ रेवेन्यू पर ध्यान है। ...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्ष: श्री हरिमोहन शर्मा।

श्रीमती कल्पना देवी (लाडपुरा): आपसे अनुरोध है कि तुरंत प्रभाव से, माननीय अध्यक्ष महोदय, पांच मिनट, KEDL को इन शर्तों पर कार्य नहीं करने पर एक कमेटी का आप गठन करें।

श्री अध्यक्ष: पांच ही मिनट तय है। पांच मिनट में जो कहना है वह कह दें।

श्रीमती कल्पना देवी (लाडपुरा): और जिसमें जन-प्रतिनिधि को भी शामिल किया जाये जिससे दूध का दूध और पानी का पानी हो जाये। दो मिनट।

श्री अध्यक्ष: बस हो गया।

श्रीमती कल्पना देवी (लाडपुरा): दो मिनट भी नहीं हुआ।

श्री अध्यक्ष: पांच मिनट की जगह छह मिनट हो गये। मेरे को नौ बजे खतम भी करना है।

श्री हरिमोहन शर्मा (बून्दी): माननीय अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले तो मैं आपको इस बात के लिए बधाई दूंगा कि यह सदन के इतिहास में बहुत लम्बे समय के बाद बिजली पर और पानी पर एक-एक दिन की चर्चा यहां पर आपने कराई इसके लिए आपका हृदय के गहनतम स्तर पर बहुत-बहुत आभार।

हमारे शासन में अनेक कमियां रही होंगी, हमें माफ कीजिए आप लेकिन आठ महीने का अपना आईना भी तो साफ कीजिए। इन आठ माह में जो आपको कार्य करना था, सबसे पहली बात तो माननीय अध्यक्ष महोदय, यह निर्विवाद है कि पूरे राजस्थान में बिजली का गम्भीर संकट है और ऐसी परिस्थितियां राजस्थान के इतिहास में पहले कभी पैदा नहीं हुईं। ग्रामीण क्षेत्र में जो जनता तड़प रही है, किसान बिलबिला रहा है, जो उसके बच्चे रात को जब खेत से आते हैं और खाना खाने के लिए तड़प रहे हैं, जो हालात इस राजस्थान में पैदा हुए हैं उन हालात को आप देखिये। उन हालात में जो लोग परेशान होकर, विचलित होकर इस समस्या के समाधान के लिए जो जन आंदोलन करके जो आपका ध्यान आकर्षित करते हैं आप उनके खिलाफ पुलिस, प्रशासन का उपयोग करके, लोकतंत्र की हत्या कर उनके खिलाफ मुकदमे चला रहे हैं। आज भी बूंदी में, कोटा में और अन्य गांवों में किसानों के बच्चे और किसानों ने आज भी बूंदी में आंदोलन किया, कल भी आंदोलन किया पर आपने क्या किया? पुलिस, प्रशासन के माध्यम से उस आवाज उठाने वाले को उनके खिलाफ मुकदमे चलाये हैं। तो, माननीय, जिनके पास आज गृह मंत्रीजी का चार्ज है, विधान सभा में जो गृह मंत्रालय का जवाब देते हैं और, माननीय विद्युत मंत्रीजी, मेरा तो विनम्र अनुरोध और प्रार्थना है कि और तो आप कर न सको लेकिन उन लोगों के मुकदमे तो आप वापस ले लेना क्योंकि यह आपकी जिम्मेदारी है व्यवस्था करने की, उस जिम्मेदारी को आप इस बात से पूरी करें, उनको मुकदमों से मुक्त कीजिए।

आज जो हालात आपके सामने हैं, आपने बजट में यह घोषणा की कि आप 1 लाख 45 हजार कृषि विद्युत कनेक्शन और 2 लाख 8 हजार घरेलू कनेक्शन देंगे पर आज जो हालात है, आपके पास बिजली ही नहीं है। आप यह बताइये कि इन कनेक्शनों को देने के लिए कितनी मेगावाट बिजली आपको चाहिए और यह कितनी मेगावाट बिजली आप कब तक पैदा कर देंगे ताकि आप कनेक्शनों को दे सकें? अभी तो पुराने कनेक्शनों को भी बिजली नहीं देने की समस्या है और आप फिर लाखों पर आगे जा रहे हो। आप तो हम पर आरोप लगाते हो कि हमने असत्य वादे किये, यह आप अपने आप में आपका यह असत्य वादा साफ आपके सामने है तो मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि इस प्रकार की बात जो आपकी यहां पर आज आ रही है, 220, 132, 33 केवी जी.एस.एस. की स्वीकृतियां जारी हो गईं। मेरा आपसे विनम्र अनुरोध है कि आप मॉनिटरिंग कीजिए। सारे काम ठप पड़े हुए हैं। जिस गति से काम

होने चाहिए थे, वह उस गति से नहीं हो रहे हैं। अगर आप व्यवस्था में सुधार करना चाहते हैं तो मेहरबानी करके टाइम बाउंड प्रोग्राम बनाइये कि जो स्वीकृतियां जारी की गयी हैं उन स्वीकृतियों के हिसाब से वह 132 केवी जी.एस.एस. का काम चालू हो, 33 केवी जी.एस.एस. का काम चालू हो और 220 केवी जी.एस.एस. का, जो भी आपने तय कर रखे हैं, उनके काम चालू हो।

आज बूंदी जैसे छोटे जिले में भी जिनका इंफ्रास्ट्रक्चर आपने तैयार कर दिया लेकिन आपके पास ट्रांसफार्मर ही नहीं है। 1600 ट्रांसफार्मर अगर आज आप बूंदी को दे दो तो कल की तारीख में उनको कनेक्शन जारी हो सकते हैं लेकिन ट्रांसफार्मर आपके पास में नहीं है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, और तो और एक ऐसी कम्पनी आ गयी यहां पर चाहे वह कांग्रेस के टाइम पर आई हो, यह मैंने आपसे भी निवेदन किया था और आपसे भी निवेदन किया था कि 2015 के, और जगह तो 2017 के कनेक्शन हो गये, 2018 के कनेक्शन चल रहे हैं, 2016 के हो गये पर बूंदी में तालेड़ा पंचायत समिति में एक ऐसी कम्पनी है कहीं बाहर की और ऐसा राज कर रही है वह कम्पनी कि चाहे हमारा राज हो या चाहे आपका राज हो, अधिकारी बार-बार में यह लिख रहे हैं लेकिन वह कनेक्शन देने में ही पैसा खा रहे हैं। पैसा खाकर वह कनेक्शन दे रही है, सारा काम उनको करना है और आज भी 2015 के कनेक्शन पूरे नहीं हुए हैं।

श्री अध्यक्ष: श्री यूनुस खान।

श्री हरिमोहन शर्मा (बून्दी): तो सज़ा यह मिल रही है कि 2016 और 2017 के कनेक्शन नहीं हो पा रहे हैं। साहब, यह तो कुछ भी नहीं हुआ आज तो।

श्री अध्यक्ष: सबको पांच-पांच मिनट का समय दिया है। यहां पर भी सबको पांच-पांच मिनट में बैठा रहा हूं, इनको भी बैठाया है।

श्री हरिमोहन शर्मा (बून्दी): फिर तो यह सारा मामला ही यूं ही रह गया, साहब।

श्री अध्यक्ष: विषय इतना लम्बा है कि आप इतने अच्छे वक्ता हैं, अच्छे अनुभवी हैं कि आप तो एक घंटा भी बोल सकते हैं। अगली बार बुलवाएंगे।

श्री यूनुस खान (डीडवाना): माननीय अध्यक्ष महोदय, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। मैं सबसे पहले सरकार को यह धन्यवाद दूंगा कि बिजली और पानी पर दो दिन से जो चर्चा सरकार करवा रही है, इसको गम्भीरता से लिया, इसके लिए सरकार को धन्यवाद। मेरे से पहले हमारे बूंदी से आने वाले माननीय सदस्य ने भी धन्यवाद दिया और मैं भी देना चाहता हूं और ज्यादा समय नहीं है इसलिए सीधा इसी पर आ रहा हूं।

श्री अध्यक्ष: हां, आप सीधे बात पर आ जाइये।

श्री यूनुस खान (डीडवाना): ऊर्जा विभाग का इस पांच वर्ष का जो स्लोगन है वह स्लोगन एनर्जी सिक्योरिटी पर है और इनका यह कहना है कि ऊर्जा के बिना कोई भी प्रांत आगे नहीं बढ़ सकता। There is a direct correlation between rate of increasing GDP and the rate of increasing energy. यह ऊर्जा विभाग ने अपना अब स्लोगन तय किया है

कि हम ऊर्जा के क्षेत्र में काम करेंगे और मैं सरकार को यह कहना चाहता हूं कि ऊर्जा और पानी में अगर आपने काम कर लिया क्योंकि अभी जो डिमांड है वह ज्यादा ऊर्जा और पानी की ही है, तो निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी।

मेरा यह कहना है कि अभी हमारे कोटा उत्तर से आने वाले माननीय सदस्य ने यह कहा कि आप व्हाइट पेपर लाएं, तो मैं भी उनकी मांग का समर्थन करता हूं। मैं इसलिए समर्थन करता हूं कि मैं यह आकड़े देख रहा था कि जब अभी जो बिजली है 23500 मेगावाट का इनका आपका जो, आपके ही कार्यकाल का यह प्रतिवेदन है, इसमें यह लिखा हुआ है। उसमें अगर हम देखें तो वसुन्धरा राजे जी जब मुख्य मंत्री थीं, पिछली सरकार जब थी, उसमें 7148 मेगावाट बिजली पैदा की और जब इनकी सरकार थी तो उसने 2523 मेगावाट ही बिजली पैदा की इसलिए गजेन्द्र सिंह जी, पुष्पेन्द्र सिंहजी और नागर साहब, इन तीनों की एक कमेटी बनाइये और आप व्हाइट पेपर लाइये और बताइये कि किसने कितनी बिजली पैदा की? चूंकि, अभी आपको तो आठ महीने ही हुए हैं, यह सब भी कह रहे हैं कि आठ महीने ही हुए हैं, तो इन्होंने जो आपको विरासत में दिया, बी.जे.पी. का नारा भी है विरासत का, आपको जो विरासत में मिला है, वह आप बताइये और आप जो विरासत में छोड़कर गये पांच साल में वह भी बताइये तो इनको पता चलेगा कि व्हाइट पेपर क्या होता है? इसलिए आपके पास अनुभवी लोग हैं, गजेन्द्र सिंहजी बैठे हैं इस डिपार्टमेंट को चलाये हुए हैं, पुष्पेन्द्रजी बहुत अच्छा बोलकर गये हैं तो मेरा यह कहना है कि इन तीनों की एक कमेटी बनाकर व्हाइट पेपर लाकर आप बताइये।

SSY/RTM/02.08.2024/19:20/4C

कोटा उत्तर से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि हम पाइप लाइन में छोड़कर गये, तो मैं आपको कहूंगा कि वसुन्धरा जी जो पाइप लाइन में छोड़कर गई, उसी की तो आपने कॉमर्शियल इजाजत ली है, बाकी आपने तो कुछ किया नहीं। इसलिए इनको विरासत में मिला है। 8 महीने में आप क्यों डर रहे हो? आपको तो विरासत में मिला है इसलिए बिजली नहीं दे पा रहे हो। जनसंख्या बढ़ गई, तापमान बढ़ गया, वह सारी चीजें बढ़ गई, इसलिए वह डिमांड बढ़ गई, क्योंकि जनरेशन, डिमांड और सप्लाई में जो गैप है, उसके कारण ही आपको प्रोब्लम आई। इसलिए मेरा यह कहना है कि आप यह लाइये।

अभी मैं इन्हीं के, यह देखिये, मैं कोई अलग आंकड़े नहीं पढ़ूंगा।

श्री अध्यक्ष: वैसे लोगों के इनकी और उनकी समझ में नहीं आता। यह साफ बता दो।

श्री यूनुस खान (डीडवाना): सर, एक मिनट आपने ले ली। मेरा यह कहना है कि यह प्रतिवेदन मैं पढ़ रहा था।

माननीय अध्यक्ष जी, इस प्रतिवेदन में इन्होंने कहा कि हमने कितने कर दिये। मन नहीं डोल रहा है। यह आप ही का प्रतिवेदन है। कुसुम योजना कंपोनेंट सी में इन्होंने 5 साल में मात्र 35.81 मेगावाट का एमओयू किया। वह भी किसके साथ किया? एलएनसी इंडिया

लिमिटेड, यह मेरा पेपर नहीं है, यह आप ही का पेपर है।

लेकिन मैं इस सरकार को बधाई देना चाहूंगा कि इन्होंने प्रधान मंत्री कुसुम योजना कंपोनेंट सी में 4179 मेगावाट का एलओए कर लिया। उसके लिए मैं बधाई देना चाहूंगा। इसलिए मैं आपको कह रहा हूं कि एक बार व्हाइट पेपर लाइये।

यह बार-बार कह रहे हैं कि बिजली नहीं मिल रही है, बिजली नहीं मिल रही है। मतलब, यह सवाल नहीं है, सवाल यह है कि राजस्थान की पॉपुलेशन बढ़ गई, डिमांड बढ़ गई, इसलिए आप जनरेशन करिये। अगर जनरेशन करेंगे तो निश्चित रूप से समस्या का समाधान होगा। चूंकि आपने घंटी बजा दी, एक मिनट मेरे क्षेत्र के लिए लूंगा।

श्री अध्यक्ष: आधा मिनट।

श्री यूनुस खान (डीडवाना): माननीय अध्यक्ष महोदय, आपको इतना ही कहूंगा कि मैं और भी बहुत सारी चीजें पढ़ रहा था। अभी हमारे विराटनगर से आने वाले सदस्य ने बता दिया कि किस रेट पर इन्होंने खरीदी कांग्रेस के शासन में और किस रेट पर वसुन्धरा जी के शासन में खरीदी और किस रेट पर इन्होंने खरीदी। उनका भी आप कंपेरिजन कर सकते हैं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं एक आंकड़ा और देख रहा था, उसमें इन्होंने जो बिजली बेची और खरीदी, यानि लगभग 4017 करोड़ की तो खरीदी थी लास्ट में और बेची कितनी सी, 234 करोड़ की बिजली बेची।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यह बात कहते हुए आपसे यही निवेदन करूंगा कि डीडवाना में मेरी मांग रहेगी माननीय ऊर्जा मंत्री जी से कि मैंने आपको पर्सनली भी कहा है, चिट्ठी भी लिखी है। पिछले 5 वर्ष में जो सौभाग्य योजना है, सीएलआरसी का जो कांट्रेक्ट, यह क्या कारण था कि एक ही व्यक्ति को मिला? उस व्यक्ति ने 5 साल में चाहे हमारा मौलासर है, डीडवाना है, खाटू है, उसमें काम किया। मैं आपसे यह मांग करुंगा कि एक बार जांच कराइये। असलियत सामने आयेगी कि 5 सालों में क्या हुआ। अंत में, एक बार बजट के अन्दर जो डीडवाना क्षेत्र के लिए आपने घोषणाएं की, उसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं।

अध्यक्ष जी, आपने टाइम दिया, हालांकि यह पेपर सारे ही रह गये।

श्री अध्यक्ष: सदन में सब लोग इतने विद्वान हैं कि यदि एक-एक घंटा बोलें तो शायद मैं उनको सुनना चाह रहा हूं, लेकिन श्रेष्ठ विद्वान वह होता है जो संक्षेप में, 5 मिनट में पूरा सार कह दे।

श्री ललित मीणा, 5 मिनट।

श्री ललित मीना (किशनगंज): माननीय अध्यक्ष महोदय, बिजली की चर्चा पर आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, मैं आपका बहुत-बहुत आभार प्रकट करता हूं।

मैं सबसे पहले सरकार को धन्यवाद देना चाहूंगा कि इतनी महत्वपूर्ण जो बिजली पर चर्चा हो रही है, उसके लिए अलग से समय निकालकर पूरा दिन तय किया। बिजली पर अभी सभी विद्वानों ने अपनी-अपनी बात रखी। पक्ष, विपक्ष ने, हमारे सभी साथियों ने बात रखी।

पिछले 2013 से 2018, 2018 से 2023 और उसके पहले 2009 से 2013 भी कई सारे सुझाव आये कि कौनसी सरकार ने क्या किया। लेकिन मैं कहूंगा कि पिछले 5 साल में जो सरकार का खाका, जो हमारे वरिष्ठ सदस्यों ने बताया, उसमें मैं बारां जिले की बात करूं या हमारे राजस्थान की बात करूं तो 765 बना, वह बारां जिले को बहुत बड़ी सौगात मिली। उसकी वजह से लाइट तंत्र बारां का अच्छा हुआ। फागी में भी बना। दो 765 बने। 400 केवी का भी अभी यहां पर जिक्र हुआ।

मैं अपनी विधान सभा की बात करूं तो जब पिछली बार 2013 से 2018 तक मैं था तो उस समय तीन 132, हमारे पूर्व दोनों ऊर्जा मंत्री यहां विराजे हैं, उस समय स्वीकृत हुए और आज उसका लाभ जनता को पिछले 5 साल मिला। पिछले 5 साल में एक भी वहां पर 33 केवी जीएसएस, 132 कोई चीज सैंक्शन नहीं हो पाई। अब 220, 2018 में सैंक्शन हुआ, वह भी पिछले 6 साल से पैंडिंग है। अभी ऊर्जा मंत्री जी ने जब से शपथ ली है, मुख्य मंत्री जी ने, तब से उसका काम चालू हुआ है। मैं धन्यवाद दूंगा कि कम से कम हमारे उस बारां जिले को 220 का काम पिछले 2018 में छोड़कर गये थे, वह काम अब चालू हुआ है।

मैं कहूं, पिछली वसुन्धरा जी की सरकार थी 2013 से 2018 और अभी वर्तमान में सरकार आई, जो काम छोड़कर गये, उसको अब चालू करना पड़ रहा है। तो आप आकलन खुद ही कर सकते हैं। हमारे यहां विपक्ष के साथी और विपक्ष के नेता भी कह रहे थे, हमारे ऊपर कह रहे थे कि इन्होंने जो छोड़कर गये थे 88 हजार करोड़ का, जो घाटा आप छोड़कर गये, उसकी भरपाई अब हमको, हमारी सरकार को करनी है। उसी की माथापच्ची से आगे आम जन को लाइट देने का काम कर रहे हैं।

इसके साथ-साथ अभी बजट में दो 132 जीएसएस मेरी विधान सभा में मुझे दिये। वह भी भूमि पूजन करके, उद्घाटन भी 3 साल में वह बनेगा, तैयार हो जायेगा तो आम जनता को लाभ मिलेगा।

आते ही सरकार ने अपना काम संभाला, उस दिन से इंफ्रास्ट्रक्चर पर ध्यान दिया। चाहे पश्चिमी राजस्थान हो तो वहां विंड मिल अलग से लगाने का काम किया। सौर ऊर्जा के लिए अलग से हमारे प्रधान मंत्री जी ने 8 मार्च, 2019 में पीएम कुसुम निधि के माध्यम से योजना रखी, उसके माध्यम से किसानों को कितना लाभ होगा? 30 परसेंट सेंटर गवर्नमेंट देगी, 30 परसेंट स्टेट और 30 परसेंट ऋण मिलाकर, 10 परसेंट किसान को लगायें तो किसान भी सशक्त होगा। आज इस योजना के माध्यम से ग्रामीण स्तर पर, लोकल लेवल पर लाइट डवलप होगी और वह 33 केवी जीएसएस से वहां जुडेगी। इसका लाभ लोकल लेवल पर पड़ेगा। पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर से वहां लाइट जो कंपोजिशन होता है, वहां की गरीब जनता को जो आप कह रहे हैं कि रात को नींद नहीं आती है। अभी लाइट की स्थिति, पिछले 5 साल और उसके पिछले 5 साल, उसका कंपेरिजन सब लोगों ने यहां पर किया, तो मैं उसकी चर्चा में नहीं जाऊंगा।

माननीय अध्यक्ष महोदय, आज इस सदन के माध्यम से एक बहुत बड़ा सुझाव देना

चाहूंगा कि मेरी विधान सभा एमपी से लगती है। एमपी गवर्नमेंट में जो लाभ किसानों को दिया जा रहा है, साढ़े 7 एचपी का जो लोड है, उस पर उनका फिक्स किया हुआ है कि 12 हजार रुपये आपको महीना देना पड़ेगा। ऐसे ही 10 एचपी का 16 हजार है, 15 एचपी का 20 हजार है, तो क्यों ना जो डिफरेंस आता है लोड पर, एचपी का भी, 20 एचपी का कनेक्शन है तो उसका फिक्स कर दें। एक किसान का, दो किसानों का अगर कनेक्शन 20 एचपी का है और अलग-अलग बिल आ रहा है तो हम उसको फिक्स कर दें।

श्री अध्यक्षः श्री समरजीत सिंह।

श्री ललित मीना (किशनगंज): माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने का समय दिया, उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री समरजीत सिंह (भीनमाल): अध्यक्ष महोदय, आज बिजली पर चर्चा कराने के लिए जैसा अभी बूंदी से आने वाले विधायक महोदय ने कहा, मैं विशेष तौर से आपको धन्यवाद देना चाहूंगा कि एक सार्थक चर्चा आपने रखवायी। बिजली की समस्या जो हमने इन 4-6 महीनों में देखी, यह मैं तो यहां खड़ा होकर कह सकता हूं कि मेरे 25-30 साल के राजनीतिक जीवन में पहली बार इस तरह का क्राइसिस देखा है, जब आम आदमी घर में बैठकर रात को घरेलू बिजली के लिए तड़प रहा है।

इसका सबसे बड़ा उदाहरण तो इसी में आता है कि जब लोग हमें पूछते हैं, जब मुख्य मंत्री जी ने एप्रोप्रिएशन बिल पर जवाब दिया तब कहा, लोगों में यह संदेश गया कि एमएलए फ्लैट्स में भी रूफ टॉप सोलर लगाने की जरूरत पड़ रही है। इस राज की नाक के नीचे एमएलए फ्लैट्स में भी रूफ टॉप सोलर लगाने की घोषणा मुख्य मंत्री जी को इसलिए करनी पड़ी होगी शायद, जब अपने में से ही किसी एमएलए ने कहा होगा कि विधायक आवास में भी बिजली कट रही है। यह हालात हैं, इन हालातों को हमें स्वीकार करना पड़ेगा। सरकारें आयेंगी, जायेंगी।

अभी बाली से आने वाले पूर्व मंत्री जी ने काफी विस्तृत बातें कीं, मैं उन पर नहीं जाना चाहूंगा। मैं तो इतना ही कहना चाहूंगा कि आपने इतना अच्छा किया तो आप भी 2018 में इधर आये थे। हम तो 2023 में आये हैं, आप तो 2018 में इधर पधारे थे। अब वापस पधारे हो। यह आना-जाना तो लगा रहेगा। जनता फंसी हुई है। जनता तो यह कहती है, मेरा एक शेर सुन लीजिए गर्ग साहब, जनता के तो यह हाल हो गये हैं, जनता कहती है,

'नजर कहती है कि दिल ने धोखा दे दिया,
दिल कहता है कि नजर से धोखा दे दिया,
किसने क्या किया किसके साथ है 'मीर',
हमको तो इन दोनों ने मिलकर तबाह कर दिया।'

जनता तो यह कह रही है कि तुमने क्या किया, तुमने क्या किया, हमारे हालात आजादी के 75 साल बाद भी यह हैं कि हम बिजली के लिए तड़प रहे हैं। इस स्थिति को हमें समझना पड़ेगा। हमें बात करनी चाहिए। मैं सरकार को भी धन्यवाद देना चाहूंगा कि इस

सेशन के दौरान डिविजन वाइज मंत्री जी ने मीटिंग्स की। एमएलएज ने अपनी समस्याएं रखी।

Spp/Rtm/02.08.2024/19.30/4d

और उसमें भी एक बात, चाहे आप सदन में मत बोलिये, हम बैठे थे। आप और हम सब मिलकर बैठे थे और सभी ने अपने अपने क्षेत्र की समस्याएं उठायीं। उससे एक बात तय थी कि समस्या तो है और इस समस्या को आपको कैसे मैनेज करना है, इस पर सरकार को ध्यान देना चाहिये।

माननीय अध्यक्ष महोदय, वर्तमान हालात को हम किस तरह से डिमांड एण्ड सप्लाई को सही तरीके से चला पाते हैं। बिजली की सप्लाई की कमी क्यों आती है? कोयले की कमी थी। आपकी तो अब डबल इंजन की सरकार है और मुझे तो दुःख होता है, मैं जालौर-सिरोही से आता हूं, कांडला से सारा कोयला मेरे जालौर से होकर जाता है और वह ट्रेक सारे दिन बन्द पडा रहता है। कोयला इतना जा रहा है, कहां जा रहा है और आपको मिल ही नहीं रहा है। आपका मैनेजमेंट होना चाहिये। सरकार को चाहिये कि सप्लाई में जो कमी है, उस सप्लाई की कमी को कैसे ठीक करें। हमारे पड़ोस में गुजरात में, वहां आप सोलर पॉलिसी को देखिये। हर खेत में सोलर की प्लेट्स लगी हुई हैं। हर घर के अदंर रूफ टॉप्स लगे हुए हैं। आप लोग अगर इस तरीके की पॉलिसीज लायें अगले पांच साल में, तो कहीं जाकर हम इन चीजों को कंट्रोल कर सकेंगे।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपका ज्यादा समय नहीं लेकर विशेष तौर पर अभी जो सप्लाई सिस्टम है, उसकी तरफ कहना चाहूंगा कि यह लोड सेटिंग की बात आती है। हम कहते हैं कि लोड सेटिंग गड़बड़ हो रही है। एग्रीकल्चर कनेक्शन की, घर कनेक्शन की, इस सेटिंग को भी तो इंसान ही करेगा। आप इस तरह से सेट करिये कि शाम को गांव में लोगों को बिजली खेती के समय, रसोई के समय मिले। (समय समाप्ति सूचक घंटी)

हमारे यहां एग्रीकल्चर कनेक्शनों की स्थिति है। प्राइवेट कम्पनियों को मैटेरियल और उसके साथ काम दे दिया गया है। वह सामान नहीं पहुंच रहा है। इन चीजों पर आप ध्यान दें और सरकार अगर पॉजीटिवली यह सारे भेदभाव भूलकर काम करे तो राजस्थान की सप्लाई को, सिस्टम को सुधारने में कोई कमी नहीं रह सकती। मैं उम्मीद करता हूं ..(व्यवधान)..

श्री यूनुस खान (डीडवाना): एक शेर पढ़ दो।

श्री समरजीत सिंह (भीनमाल): अब शेर अगली बार पढ़ लेंगे न। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यही कहना चाहता हूं कि सरकार को चाहिये कि इस मैनेजमेंट को सुधारे। बजाय एक-दूसरे पर दोषारोपण करने के, हम सिस्टम को सुधारें तो लोगों को मूलभूत सुविधाएं इससे दे पायेंगे। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: श्री लालाराम (अनुपस्थित)। श्री पब्बाराम विश्नोई।

श्री पब्बाराम विश्नोई (फलौदी): धन्यवाद माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी पिछले वक्ताओं द्वारा कहा गया कि बिजली उधार ली गयी। उधार लेने के बाद में जिस समय में हमें ज्यादा अत्यधिक आवश्यकता थी, उस समय हमको लौटाना पडा और अन्य खरीद भी करनी पड़ी। मैं तो यूं कहूंगा यह संस्कृत की उक्ति है। उस उक्ति के अनुसार काम किया। यह उक्ति है -

"यावज्जीवेत सुखं जीवेद ऋणं कृत्वा घृतं पिवेत,

जब तक हमारी सरकार रहे ऋण लेते रहो, कर्जा लेते रहो और जो जोयेगा सो रोयेगा, जो आयेगा सो रोयेगा। इस बात से आपने काम किया। आपने ट्रांसफार्मर सिस्टम को कोलेप्स करके रख दिया। इसका एक उदाहरण आपको देता हूं कि हमारे यहां पर तीन 132 के ट्रांसफार्मर थे, उसके ऊपर आग्मेंटेशन तक नहीं किया गया। मैं माननीय ऊर्जा मंत्रीजी को धन्यवाद देता हूं कि आपने सांवरीज और मेरे यहां के जी एस एस पर अतिरिक्त ट्रांसफार्मर सैंक्शन किये। मैं आपसे निवेदन करता हूं कि इसको तुरंत सप्लाई कीजिये और एक खेतुसर का एक 132 का हमारे यहां आपके पहले के समय का ही है, उसके ऊपर भी आग्मेंटेशन का काम कीजिये। इससे हमारे यहां पर बिजली की व्यवस्था में थोड़ा सुधार हो जायेगा। दूसरे में, लोहावट के अन्दर, हालांकि वह क्षेत्र तो माननीय गजेन्द्र सिंह जी का है, परंतु वह मेरे से इसलिये जुड़ा हुआ है कि वह लोड मेरे फलौदी के अन्दर 220 के ऊपर आ रहा है, वह 220 का जो सैंक्शन किया हुआ है, यह आपको मैं बता रहा हूं। माननीय गजेन्द्र सिंहजी जब ऊर्जा मंत्री थे, उस समय में उन्होंने वहां पर 220 का सैंक्शन किया था। आपने पांच साल में उस 220 का कनेक्शन तक नहीं किया, उसके अन्दर एक पत्थर नहीं रखा। मैं आपसे एक निवेदन करता हूं कि लोहावट वाले जो 220 का है, उसका काम तुरंत शुरू करवायें ताकि मेरे फलौदी क्षेत्र के जो लोड है, वह कम हो जाये और हमारे वहां के किसानों को सुविधा हो। फलौदी के अन्दर जो सिंचित क्षेत्र विकसित हुआ है, जिसके कारण वहां पर लोड बढ़ा है और इसके चलते आर डी एस एस स्कीम के तहत लोड अभी जब हुआ है तो उसके अन्दर लगभग 15-20-35 केवी के जी एस एस कम पड़ते हैं और 132 के दो जी एस एस की कमी है, मेरा आपसे निवेदन है कि उनके प्रपोजल भी गये हुए हैं, तो माननीय ऊर्जा मंत्री जी वहां जाकर भी आये थे और परिस्थितियों को देखकर भी आये थे।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा एक और निवेदन था कि एफ आर टी में जो काम करने वाले हैं, उनके साथ दुर्घटनाएं होती हैं। अभी एक वक्ता ने कहा भी था कि उन ठेकेदारों को यह जिम्मेवारी दे दीजिये कि आप इनका बीमा जरूर करवायेंगे। अगर आप बीमा नहीं करवायेंगे और कोई घटना हो गयी तो उसके बीमा की राशि उस ठेकेदार को भुगतनी पड़ेगी। इस प्रकार की व्यवस्था जरूर कर दीजिये। नहीं तो वह मजदूर मारा जाता है और उसका परिवार रोता रहता है। (समय समाप्ति सूचक घंटी)

दीन दयाल ग्राम ज्योति योजना के तहत जिस प्रकार से 2013 से 2018 के बीच में जो काम हुआ, 65 साल के बाद में भी 18 हजार गांवों में एक भी बल्ब नहीं था, मैं माननीय प्रधान मंत्रीजी को धन्यवाद देता हूं कि 18 हजार गांवों में बल्ब जला। उन्हीं 18 हजार गांवों

में जब सरकार बदली तो आपने वह कनेक्शन देने बन्द कर दिये। सौभाग्य योजना की भी राशि वापस लौटा दी क्योंकि आपको भी पता था कि यह क्रेडिट मिलेगा माननीय नरेन्द्र मोदीजी को, इसलिये आपने काम नहीं किया। 500 रुपये में कनेक्शन हो रहा था। आज हर पंचायत के अन्दर कम से कम 300 से 400 कनेक्शन बाकी हैं। (समय समाप्ति सूचक घंटी)

मैं माननीय ऊर्जा मंत्रीजी से निवेदन करता हूं कि आप इसको किसी भी रूप में 2019 तक हम कर देंगे, ऐसा मत करना। उस दीन दयाल ग्राम ज्योति योजना के तहत जो भी घरेलू कनेक्शन बाकी है, वह पूरे के पूरे कनेक्शन दीजिये। माननीय अध्यक्ष महोदय, एक और बात को कहकर अपनी बात को पूरी करूंगा।

कुसुम योजना के अन्दर यह कम्पनियां और अधिकारी मिलकर लास्ट में जाकर जो किसान ने दे रखा है उससे दो पैसे, चार पैसे कम करके वह प्रोजेक्ट हथिया लेते हैं। मेरा आपसे निवेदन है प्रधान मंत्रीजी का यह स्पष्ट मत है कि किसान को इसका लाभ मिलना चाहिये। इन कम्पनियों को इससे बाहर कीजिये और लोगों को पार्टनरशिप में दीजिये। आठ-आठ करोड़ की योजना है तो आप पार्टनरशिप में देंगे तो वह लोग कर लेंगे। आपसे मेरा यही निवेदन है। (समय समाप्ति सूचक घंटी)

श्री अध्यक्षः श्री मनीष यादव। आप बोलिये। शुरू करो। नाम पुकारने के साथ ही शुरू कर देना चाहिये। अगले बोलते रहते हैं।

श्री मनीष यादव (शाहपुरा): माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने बिजली पर बोलने का मौका दिया और धन्यवाद आपको इसलिये भी देना चाहता हूं। मैंने भी बिजली कटौती पर पर्ची के माध्यम से मामला उठाया और आपने व्यवस्था दी कि बिजली पर चर्चा कराकर आज प्रदेश का जो संकट है, जो जनता त्रस्त है, मैं दो पंक्तियों से जनता की व्यथा कहना चाहता हूं -

'रोने की सज़ा है ना रुलाने की सज़ा है,
यह गरीब और पिछड़ों को सताने की सज़ा है।
हंसती हुई आंखों में आ जाते हैं आंसू
ये सरकार से उम्मीद लगाने की सज़ा है।।

माननीय अध्यक्ष महोदय, आज आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा क्योंकि मुझे लग रहा है कि जिस अमृतकाल में भारतीय जनता पार्टी जी रही है, जिस अमृतकाल में भारतीय जनता पार्टी तरह-तरह के दावे करती है और प्रधान मंत्री से लेकर हर कार्यकर्ता इस देश में अमृतकाल आने की बात करता है और दूसरी तरफ राजस्थान की भोली-भाली जनता, जो चुनाव में लुभावने वादों के साथ में सरकार लेकर आ जाती है। आज आठ महीने हो गये, राजस्थान का हर वर्ग, आज मेरे सामने जो सरकार के रूप में जो मंत्री महोदय बैठे हैं, यह भारतीय जनता पार्टी से आये हुए विधायक बैठे हैं, यह अपने अन्तर्मन में झांककर देखें कि जनता किस तरह से बिजली संकट से जूझ रही है। आज जनता को रोना आ रहा है। आज बुजुर्ग, महिलाएं, बच्चे, नौजवान, बीमार व्यक्ति यहां तक कि अस्पतालों में

भी बिजली के ऐसे हालात बने हुए हैं कि हर जगह पर बिजली का कट है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, ग्रामीण क्षेत्रों के हालात ऐसे बन गये हैं कि जनता, जोकिसान खेत में मजदूरी करता है, किसानी करता है, जो मजदूर अपना काम चलाता है और वह इंतजार करता है कि रात के समय मुझे चैन से सोने का अवसर मिलेगा। उसके साथ कैसा घटित होता है। यह दर्द का विषय मैं इसलिये कहना चाहता हूं कि मैं भी गांव के क्षेत्र से आता हूं और जब गांव में लोगों की पीड़ा देखता हूं, बिजली कटौती के समय जब लोग रात-रात भर इंतजार करते रहते हैं कि कब बिजली आयेगी। मैं आपसे कहना चाहता हूं, सरकार के लोगों से कहना चाहता हूं कि राजस्थान में पॉवर रिजर्व के नाम पर क्या कोटा, भरतपुर या राजस्थान की भोली-भाली जनता को भ्रमित करने के लिये जहां पांच जगह उप चुनाव होने हैं, आप बिजली रिजर्व के नाम पर किस अधिकार से बिजली का रिजर्व करके वहां पर बिजली कट नहीं करते।

Jyg/rtm/020824/19.40/4e

और चुनाव के समय केवल धोखा देने के लिए जब उप चुनाव हो जाएंगे, तो जनता आपका असल चेहरा देखेगी। आप भरतपुर और कोटा या पांच जगह उप चुनाव होने हैं राजस्थान की 8 करोड़ की जनता की कोई गलती नहीं है।

कृपलानीजी, यह विषय बीच में बोलने का नहीं है, यह विषय जनता के दर्द का है, उस दर्द को आपको समझना   पडेगा, यह सब तकलीफ का समय है जब हम सब लोगों को, आपको और हमको इस विषय पर ध्यान देना पड़ेगा कि हम केवल भाषण में ही अमृत काल की बात करेंगे, क्या हम 2047 में एक विकसित भारत की कल्पना करेंगे, आजादी के 75 साल बाद भी जब घरों में लाइट नहीं आती, 6 से 8 घण्टे तक बिजली कटौती होती है, यह कैसा समय चल रहा है, यह कैसी सरकार चल रही है, हमें देखने का समय है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, जब देश में भ्रष्टाचार के नाम पर लड़ाई होगी तो देश की संसद भी टपकेगी, देश में जब भ्रष्टाचार होगा तो बिजली के तार भी झूलेंगे, दुर्घटनाएं भी होंगी। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि 2017 में माननीय विराट नगर से आने वाले विधायक कह रहे थे कि वहां पर दुर्घटना हो गई, 2017 में ट्रांसफार्मर फटने से एक परिवार के बारह से अधिक लोग मर गए और यह हमें देखना पड़ेगा। आए दिन लोगों के साथ दुर्घटनाएं होती हैं, ट्रांसफार्मर के लिए आज जनता, किसान, नौजवान परेशान रहता है, बिजली के तार घरों के बाहर झूलते रहते हैं। हमें सोचना पड़ेगा, आज बिजली शिफ्टिंग के लिए अगर कोई काम करना चाहें। (समय समाप्ति सूचक घण्टी)

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं एक मिनट में अपनी बात पूरी करूंगा। आज बिजली तार शिफ्टिंग के लिए एस्टीमेट बनाना पड़ता है। गरीब किसान, मजदूर को एक-एक लाख रुपये चुकाना पड़ता है, क्या सरकार की जिम्मेदारी नहीं है कि जनता के दर्द को समझे? क्या हमारी जिम्मेदारी नहीं है कि सदन में बैठकर हम कानून बनाएं कि जिसके घर के ऊपर से

बिजली की लाइन जा रही है, हम उसको हटाएंगे, उसको हम जनहित में हटाकर जनता को न्याय देने का काम करेंगे।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं अंत में अपनी बात पूरी करते हुए एक लाइन कहूंगा, मैं जिंदा हूं इसलिए बोल रहा हूं, दुनिया कभी गूंगे की कहानी नहीं लिखती। बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: श्री गोरधन।

श्री गोरधन (धोद): माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने इस बिजली के मुद्दे पर बोलने का समय दिया, इसके लिए धन्यवाद।

जैसा अभी हमारे विपक्ष के साथियों ने बहुत जोर-जोर से बोल रहे थे लेकिन इनको यह पता नहीं है कि अभी सरकार बने आठ महीने हुए हैं, जो ये बिजली का तंत्र फेल हुआ है वो आपकी वजह से ही फेल हुआ है क्योंकि जिस प्रकार से ..(व्यवधान).. आपकी वजह से और आपकी वजह से ही हम सब लोग जीते हैं। यह भी सही है।

श्री अध्यक्ष: दोनों आप-आप हो। ये आपको आप कहते हैं और आप इनको आप कहते हैं।

श्री गोरधन (धोद): माननीय अध्यक्ष महोदय, सरकार को इसलिए धन्यवाद है कि इस बिजली और पानी जैसे सेंसेटिव मुद्दे पर जिस प्रकार से चर्चा की है, क्योंकि एक बहुत जनता से जुड़ा हुआ मुद्दा है और जिस प्रकार से पांच सालों में कांग्रेस ने जो बिजली का तंत्र चलाया और जिस प्रकार से लेने और देने का काम आज हमारे ऊपर बढ़ रहा है, जो बैंकिंग सुविधाएं इन्होंने जो की थी, उधारी बिजली लेकर, उसका भार हमें अब भोगना पड़ रहा है। तो मैं यह सोचता हूं कि यह बिना प्लानिंग के किया गया काम है, इसकी वजह से जनता को सब कुछ झेलना पड़ रहा है। मैं माननीय मंत्री महोदय को वास्तव में धन्यवाद देना चाहूंगा कि यदि ये बिजली के मुद्दे पर सेंसेटिव नहीं होते, हमारे सभी विधायकों को बुलाकर बात भी नहीं करते और समय-समय पर हमें गाइडेंस भी देते हैं और हम भी इनको बताते हैं कि इस प्रकार से हमारी समस्या का समाधान हो सकता है। लेकिन, माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्रीजी से यह कहना चाहूंगा कि क्यों न हम जिस प्रकार से हमारी जो पवन ऊर्जा है, या सौर ऊर्जा है या पानी से जो बिजली बनती है, उनका हम ज्यादा से ज्यादा उपयोग करें, उन संसाधनों को हम ज्यादा से ज्यादा काम में लें जिससे हमें बिजली का उत्पादन दिन को हो सके और इसका स्टोरेज करने का सिस्टम जरूर अपनाएं जिससे कि हमारी समस्या का समाधान हो। आज जिस प्रकार से हम यूं कह सकते हैं कि गांवों में बिजली की जब समस्या आती है तो गांवों में बिजली कम देते हैं। मेरा आग्रह है कि जो उद्योग-धंधे रात्रि में चलते हैं उन उद्योग-धंधों को दिन में बिजली दी जाए क्योंकि दिन में सौर ऊर्जा से उसको सप्लाई की जा सकती है। इसलिए मेरा विशेष आग्रह है कि गांवों में बिजली का थोड़ा विशेष ध्यान रखें क्योंकि वहां पर भी हमारे बहुत सारे ऐसे बच्चे रहते हैं, पढ़ने वाले रहते हैं, बड़े-बुजुर्ग रहते हैं, उनको भी बिजली की आवश्यकता पड़ती है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से माननीय मंत्रीजी से निवेदन करना चाहूंगा

कि मेरे विधान सभा क्षेत्र में जिस प्रकार से दो हाई टेंशन लाइनें जा रही हैं, इनमें से एक तो लगभग 765 किलोवाट की है जो बहुत बड़ी लाइन है, जिससे हमारे उस क्षेत्र में जो आबादी क्षेत्र है और यूआईटी क्षेत्र भी है, उस लाइन को यदि हम दूसरी साइड से, क्योंकि वहां पर करोड़ों की जमीन है, यदि वहां से जाती है तो सीकर का और हमारे उस यूआईटी क्षेत्र का और हमारे विधान सभा क्षेत्र का विकास भी अवरुद्ध होगा क्योंकि मेडिकल कॉलेज भी उधर ही बनी हुई है। इस प्रकार से हम किसानों को जो भी हाई टेंशन लाइन जाती है तो उस लाइन के नीचे से हमने 30 परसेंट का मुआवजा बढ़ाया है उसको हम 50 परसेंट करें जिससे किसानों को ठीक लाभ हो। क्योंकि किसानों के खेत में एक प्रकार से जब हाई टेंशन लाइन गुजरती है तो वहां वो पोल लगने के बाद में या तार वहां से जाने के बाद में मैं सोचता हूं कि किसान की जमीन कोई काम की नहीं रहती है, इसलिए मेरा आग्रह है कि उसको ठीक ढंग से मुआवजा दिया जाए जिससे काश्तकारों का भला हो सके।

मेरा निवेदन यह भी रहेगा कि सीकर में पूरे 20 हजार कनेक्शन किसानों के बाकी हैं, तो उसमें मेरे धोद विधान सभा क्षेत्र के 10 हजार किसानों के कृषि कनेक्शन बाकी है तो उनको जल्दी से जल्दी जारी करवाएं। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने जो समय दिया उसके लिए आपका धन्यवाद।

श्री अध्यक्षः डा. ऋतु बनावत।

डा. ऋतु बनावत (बयाना): माननीय अध्यक्ष महोदय, धन्यवाद। आपने बिजली पर चर्चा में मुझे सम्मिलित किया, मेरे को बोलने का अवसर दिया।

माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी लगातार बात चल रही थी कि आपने नहीं किया, आपने नहीं किया और हम जो यहां बैठे हैं वो चीजों को उस स्तर पर कर नहीं पाते। हम सोचते हैं, हम सोचना चाहते हैं कि हमारे जो राजस्थान के 8 करोड़ लोग हैं वो बिजली पूरी पाएं, उनका अधिकार बनता है। आप देखिए कि 2013 में जब भाजपा की सरकार थी और लगातार विधायकों ने बात की कि बिजली मिलती थी, 20-20 घण्टे भी बिजली मिलती थी, 22 घण्टे भी बिजली मिलती थी, तो मैं यह कहना चाहूंगी कि पिछली सरकार ने क्यों ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर डवलप नहीं किया कि जो प्रोग्रेस हम बिजली में कर रहे थे वो लगातार जारी रहता। जारी रहता तो आप याद करो और अपने दिल पर हाथ रखकर कहो कि जब पिछली बार गर्मी का समय था, गर्मी का समय था तो आपके अधिकारी बिजली प्राप्त कर रहे थे, राहत कैम्पों में बैठे थे, एसी में बैठे थे, लेकिन गरीब लोगों को, गांव के लोगों को उस समय भी बिजली नहीं मिल रही थी।

आज जो परेशानियां हुई है इन आठ महीनों में, मैं यह कहना चाहती हूं कि बिजली की जो डिमांड और सप्लाई में गैप आया है, हमने क्यों नहीं सोचा कि वो गैप नहीं आए। हमारी योजनाएं क्यों ऐसी नहीं होती कि वो गैप भरा जाए और ऐसी योजनाएं बने कि कितनी डिमांड आ सकती है। हम अदूरदर्शिता के कारण से क्यों पीछे रह जाते हैं? हमें बिजली के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने की आवश्यकता है। विण्ड के थ्रू हो, सोलर के थ्रू हो, अक्षय ऊर्जा के

थ्रू हो, या कोयले से उत्पन्न करके बिजली बनाने की बात हो, हमें डिपेंडेंसी खतम करनी पड़ेगी। आज मैं पढ़ रही थी कि उधारी में बिजली लेते-लेते हम इतनी उधारी में हो गए कि जब हमें आवश्यकता होती है तो हमें लौटानी पड़ती है। तो ऐसा क्यों होता है? यह सोचने का विषय हम सब लोगों के लिए है।

अभी कई साथी कह रहे थे कि जब हम अपने-अपने क्षेत्रों में विधान सभा खतम होगी तो जाएंगे तो लोग हमसे शिकायत करेंगे, निश्चित तौर पर करेंगे और उनका अधिकार है, उन्होंने हमें चुनकर यहां भेजा है लेकिन हम इन परिस्थितियों से निपटने के लिए एक दूसरे पर आरोप-प्रत्यारोप लगाते रहेंगे तो समस्या का समाधान नहीं होगा। सदन में यह जो चर्चा की जा रही है वो क्यों की जा रही है कि हमें अच्छे सुझाव चाहिए कि हम इस स्थिति से कैसे निपटेंगे। तो हमें सबसे पहली जरूरत यह है कि इंफ्रास्ट्रक्चर डवलप करने की बहुत जरूरत है। हमने, पिछली सरकार ने बहुत सारे जीएसएस की घोषणा की लेकिन उनकी मॉनिटरिंग नहीं की कि कितने काम हुए और कितने काम नहीं हुए। इस सरकार ने आकर उन कामों को गति देने का प्रयास किया और गति दे रही है। आप देखिए कि मेरे विधान सभा क्षेत्र में 220 केवी की घोषणा इस बजट में हुई। मैं बहुत-बहुत धन्यवाद दूंगी मुख्य मंत्रीजी का और आदरणीय ऊर्जा मंत्रीजी का कि उन्होंने यह घोषणा की।

MLS/RTM/02.08.2024/19:50/4f

बजट घोषणा होने के तुरन्त बाद प्रभारी मंत्री जाते हैं, जगहों का निरीक्षण करते हैं और जल्दी से जल्दी काम कैसे पूरे हों, इसके निर्देश देकर आते हैं, यह सबसे बड़ी बात है। अगर आपने यह कर लिया होता तो यह परिस्थिति हमे फेस नहीं करनी पड़ती। (समय-समाप्ति-सूचक घण्टी) साथ ही, मैं यह कहूंगी कि मेरे क्षेत्र में पहाड़ी इलाका भी बहुत सारा है। आये दिन फॉल्ट होते रहते हैं। पहाड़ी से लाइनें जा रही हैं, तो अंडरग्राउंड लाइंस दी जाएं।

श्री अध्यक्ष: श्री फूल सिंह मीणा।

डा. ऋतु बनावत (बयाना): और व्यवस्थाओं को सुधारने के लिए जो छोटे जीएसएस हैं, उनकी एक श्रृंखला बनायी जाये जिससे 220 केवी बनकर तैयार हो तो लोड शेडिंग की प्रॉब्लम नहीं हो और अच्छे तौर पर रूरल इलाके में बिजली मिल पाये। धन्यवाद।

श्री फूल सिंह मीणा (उदयपुर ग्रामीण): माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे इस महत्त्वपूर्ण विषय बिजली की चर्चा पर भाग लेने का मौका दिया, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

सदन की कार्यवाही

विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

श्री जोगेश्वर गर्ग (सरकारी मुख्य सचेतक): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन का समय आज की कार्यवाही पूर्ण होने तक बढ़ाया जाये।

श्री अध्यक्ष: प्रश्न यह है कि सदन का समय आज की कार्यवाही पूर्ण होने तक बढ़ाया जाये?

(स्वीकृत)

सदन का समय आज की कार्यवाही पूर्ण होने तक के लिए बढ़ाया गया।

लेकिन 9 बजे का है। आप चलाते रहें, भोजन विपक्ष के नेता की ओर से होगा।

राज्य में बिजली की स्थिति पर विचार

श्री फूल सिंह मीणा (उदयपुर ग्रामीण): माननीय अध्यक्ष महोदय, पूर्ववर्ती सरकार ने हमारे आदिवासियों के लिए जो सोलर ऊर्जा का बहुत बड़ा काम करने की जिम्मेदारी ली, अजमेर डिस्कॉम के पूर्व एमडी +++ द्वारा उनके परिवार के बेटे-बहू के नाम पर पार्टनरों के रूप में कम्पनियां बनायी गईं। 291 करोड़ रुपये का घोटाला किया गया। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके मार्फत् मंत्री महोदय से इसकी उच्च स्तरीय जांच करने की मांग करूंगा।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपको बताना चाहता हूं कि भारत सरकार ने आरडीएसएस योजना में बिजली कम्पनियों को विद्युत तंत्र के सुधार हेतु 18,358 करोड़ रुपये स्वीकृत किये थे। इसमें से केवल 9,678 करोड़ रुपये स्मार्ट मीटर के लिए एवं 8,660 करोड़ रुपये वितरण तंत्र के सुदृढ़ीकरण के लिए खर्च किये जाएंगे। गांवों में सिंगल फेज सिस्टम के स्थान पर मध्य प्रदेश की तर्ज पर थ्री फेज फीडर घरेलू कनेक्शनों को अलग खींचकर सुदृढ़ीकरण किया जाये और विद्युत तंत्र से गांवों में निर्बाध विद्युत आपूर्ति की जाये।

अध्यक्ष महोदय, टीएसपी क्षेत्र में शेष रहे घरेलू कनेक्शनों को भी आरडीएसएस योजना में शामिल किया जाये। ऊंची दर पर पिछली सरकार द्वारा आरडीएसएस योजना में दिये गये टैंडरों की जांच उच्च स्तरीय समिति से करायी जाये, क्योंकि 6,700 करोड़ के टैंडर को 7,592 करोड़ रुपये में दिया गया। माननीय अध्यक्ष महोदय, यही नहीं, पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार द्वारा किसानों को कनेक्शन देने के लिए 35 हजार कनेक्शन अजमेर डिस्कॉम को देने हेतु टैंडर शर्तें बदलकर 753 करोड़ के काम को 1,208 करोड़ रुपये में दिया गया। सीधे तौर पर अकेले अजमेर डिस्कॉम में 455 करोड़ रुपये का राजकोष में चूना लगाया गया।

ठेकेदारों ने एक पैनल बना लिया और उस पैनल में केवल एक ही ठेकेदार का नाम आया। उसके अन्दर केवल एक ही ठेकेदार आने की वजह से -8.50 प्रतिशत की दर थी, जबकि वास्तव में इसका और भी हमें फायदा मिल सकता था।

अध्यक्ष महोदय, मैं बताना चाहता हूं, मेरे पहले जो वक्ता थे, जो वास्तव में हमारे कोटा से आने वाले बहुत सीनियर माननीय सदस्य हैं, वे अखबारों की कटिंग बता रहे थे। अखबारों की ही कटिंग मैं बता रहा हूं। अध्यक्ष महोदय, दैनिक भास्कर की न्यूज, 16.02.2022, बांसवाड़ा में सोलर सिस्टम लगाने के लिए 291 करोड़ रुपये का घाटा। घोटाले में साथ लगे अधिकारी को भी जांच के लिए दिया।

अध्यक्ष महोदय, यही नहीं और भी हैं। यह भास्कर की ही न्यूज है। वास्तव में 6,700 करोड़ रुपये के टेंडर को 7,592 तक पहुंचा दिया। 900 करोड़ रुपये का नुकसान सरकार को करवाया गया। सोलर पैनल के अन्दर 12 करोड़ रुपये का, जो वास्तव में सप्लायर कम्पनी पर जुर्माना किया गया, वह भी अधिकारियों को... (समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

श्री अध्यक्ष: श्री घनश्याम।

श्री फूल सिंह मीणा (उदयपुर ग्रामीण): अध्यक्ष महोदय, यह अख़बार की कटिंग बताएं तो यह बहुत है। उदयपुर जिले में गैर टीएसपी क्षेत्र में 956 करोड़ रुपये...

श्री घनश्याम (टोडाभीम): माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने बिजली के विषय पर मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। माननीय अध्यक्ष महोदय, आज राजस्थान में बिजली की दो तरह की स्थिति बना दी। आप शहरों के लोगों को 24 घण्टे बिजली दे रहे हैं, गांव के लोगों से आपकी ऐसी क्या नफरत है? मैं मंत्री जी और सरकार से आग्रह करना चाहूंगा, आपने गांवों में जो स्थिति पैदा कर दी, गांवों के लोगों से इतनी क्या ईर्ष्या है कि आप वहां चार-पांच घण्टे बिजली दे रहे हैं?

माननीय अध्यक्ष महोदय, जिस तरह के हालात 70 साल में कभी पैदा नहीं हुए, वे आपने 3 महीने में पैदा कर दिये। सभी सदस्य कह रहे थे, पक्ष के सदस्य कह रहे थे कि कांग्रेस की पूर्ववर्ती सरकार के कारनामों की वजह से हुआ है। कांग्रेस की सरकार में लगातार 20 घण्टे, 22 घण्टे बिजली दी गयी है। आपकी सरकार को आये हुए 8 महीने हो गये, आपने क्यों नहीं व्यवस्था को सुधारा? आप कह रहे हैं कर्जा ले लो, कर्जा तो आप 1 लाख करोड़ का लेंगे, तब सरकार को चलाएंगे? आप 500 करोड़ रुपये और ले लें। एक हजार करोड़ का कर्जा ले लें, कौन मना करता है? सभी विपक्ष के साथी इसका समर्थन करते हैं, आप कितना भी कर्जा लें, क्या परेशानी आ रही है, उस परेशानी में हम आपका साथ देंगे, पर आप राजस्थान की जनता को बिजली दें और राजस्थान के किसानों के साथ भेदभाव न करें।

राजस्थान के गांव में कोई रहता है तो उसका क्या दोष है? आप शहरों में बिजली दे रहे हैं, हमारे घरों में बिजली आ रही है। एमपी, एमएलए, मिनिस्टर,आईएएस, आईपीएस, सब एयर कंडीशनर्स में सो रहे हैं और गांव का आदमी तड़प रहा है। महिलाएं हैं, बच्चे हैं, गांवों के लोग रात भर चौपालों पर बैठे रहते हैं और वे चर्चा करते रहते हैं कि कब बिजली आयेगी। क्या दोष है उन लोगों का? आज हालात इस तरह के पैदा हो गये। कोई फोन करता है तो आज फोन उठाने को तैयार नहीं है कि लोड शेडिंग पर चली गयी। पांच-पांच मिनट में बिजली ट्रिप हो रही है। इस तरह की व्यवस्था आप लोगों ने बना दी। जनता बहुत परेशान है। जनता का श्राप आपको महंगा पड़ेगा।

(समय: बजे)

(श्री फूल सिंह मीणा, सभापति, पदासीन)

माननीय सभापति महोदय, अघोषित बिजली जो आप काट रहे हैं, यह आपको सुनिश्चित करना चाहिये। आप बिजली नहीं दे रहे, कोई बात नहीं, पर आप जनता को आगाह करें। जनता को आगाह करें कि इतने बजे से इतने बजे तक बिजली नहीं आयेगी तो जनता उसकी व्यवस्था करे। आप बिजली नहीं देकर इनवर्टर कम्पनियों को फायदा पहुंचा रहे हैं। 20 साल में जितने इनवर्टर नहीं बिके, इन तीन महीनों में बिक गये। क्या व्यवस्था है यह, क्या घोटाला है, मैं यह आपके द्वारा जानना चाहता हूं? सारे इनवर्टर तीन महीनों में बिक गये।

माननीय सभापति महोदय, आज जो स्थिति आप पैदा कर रहे हैं, गांव के लोग धरना-प्रदर्शन करने के लिए मजबूर हो गये हैं। उनके खिलाफ आप मुकदमा दर्ज करा रहे हैं। यह कौन-सी बात है? एक तरफ तो आप बिजली नहीं दे रहे, दूसरी तरफ आप मुकदमा दर्ज करा रहे हैं, पुलिस उन्हें डण्डे मार रही है। इस तरह की व्यवस्था नहीं होनी चाहिये प्रदेश में। आपको सुनिश्चित करना चाहिये। ...(व्यवधान)... माननीय मंत्री जी, टोडाभीम की पिता तुल्य जनता ने भेजा है हमें। आपकी उस पर नहीं आये।

श्री सभापति: प्लीज आवाज नहीं।

श्री घनश्याम (टोडाभीम): सभापति महोदय, मेरा आपसे निवेदन है, अभी कई माननीय सदस्य कह रहे थे कि श्वेत पत्र जारी करें। करें श्वेत पत्र जारी, जनता को इन चीजों से कोई लेना-देना नहीं है। गलती हमारी रही, आपकी रही, श्वेत पत्र जारी करें, कोई दिक्कत नहीं, पर जनता को बिजली चाहिये। ...(व्यवधान)... हां, मैं भी समर्थन करता हूं, कर दें श्वेत पत्र जारी, पर जनता जो गांवों में रहती है, उसे बिजली चाहिये। उनकी बिजली की व्यवस्था कैसे होगी, इस पर हमें विचार करना होगा। (समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

अगर हम बिजली नहीं दे पाएंगे तो इसके लिए सब लोग दोषी हैं। यह ऐसी महत्त्वपूर्ण चर्चा है बिजली, पानी, इस पर हम सब एकमत हैं। कोई विरोध नहीं है किसी तरीके का। कोई विरोध नहीं कर रहा। आपको इसमें प्लानिंग करनी चाहिये। 8-8 महीने हो गये, 10-10 महीने सरकार में आपको आये हुए हो गये और फिर भी आप कांग्रेस का रोना रो रहे हैं। कांग्रेस ने तो बिजली के क्षेत्र में किसी तरह की परेशानी पैदा नहीं होने दी।

mkd/rtm/02.08.2024/20.00/4g

माननीय सभापति महोदय, यह बात जनता प्रमाणित करती है। कांग्रेस के टाइम पर कभी बिजली की कटौती नहीं हुई, 20-20 घंटे तक बिजली आई है और जो हालात आपने पैदा किये हैं, जनता ये सब जान रही है।

मैं आपसे गांवों की बात करना चाहता हूं। आपको गांवों के लोगों से नफरत क्यों हैं? आप तो ये बता दें मुझे। आप शहरों में बिजली दे रहे हैं, गांवों के लोग जब रात को देखते है, बिजली नहीं आती तो शहरों में लाइट आती रहती है। वे देखते रहते हैं कि हमने कौन-सा दोष किया गांव में पैदा होकर, शहरों की लाइट को वे देखते हैं। कितनी परेशानी, बच्चे, महिलाएं गांव में तड़फते रहते हैं और वे हमको कोसते रहते हैं।

सभापति महोदय, मेरा एक मंत्री जी से व्यक्तिगत निवेदन है कि आपने सभी सम्भागों की मीटिंग ली है। हमारे भरतपुर सम्भाग की मीटिंग आपने 26 तारीख को रखी और वह कैंसिल कर दी गई। उस मीटिंग को पुन: आप करायें। सभी जन-प्रतिनिधियों, अधिकारियों को बिठाकर बात करें कि इसका क्या उपचार हो सकता है। मेरा यह भी निवेदन आपसे रहेगा।

एक बिजली डिपार्टमेंट में जो प्राइवेट ठेकेदार काम कर रहे हैं, ये बिलकुल संवेदनहीन लोग हैं। ये समय पर काम नहीं करते हैं। ये पैसा लेते हैं।

श्री सभापतिः श्री बालमुकुन्दाचार्य जी। अंकित नहीं होगा।

श्री घनश्याम (टोडाभीम): 000

श्री बालमुकुन्दाचार्य (हवा महल): धन्यवाद, माननीय सभापति महोदय। आपने मुझे बोलने का अवसर दिया।

श्री सभापतिः समय पूरा दिया है। आपके संगठन ने दिया है।

श्री बालमुकुन्दाचार्य (हवा महल): महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि ऊर्जा पर सुझाव तो कम और ऊर्जा पर पिछली चर्चाएं अधिक हुईं। बात ठीक है, पिछले कुछ कर नहीं पाये और अनगिनत कर्जा छोड़ दिया। उसका नतीजा अब हम लोग भुगत रहे हैं लेकिन फिर भी मैं धन्यवाद देना चाहूंगा माननीय मुख्य मंत्री महोदय और ऊर्जा मंत्री जी को कि उन्होंने इस व्यवस्था को सम्भाल लिया। इस व्यवस्था को सम्भालने के पश्चात पर्याप्त रूप से बिजली की व्यवस्था हो पा रही है और जो थोड़ी कमी है, वह भी मुझे पूर्णतः विश्वास है आगे ठीक हो जायेगी।

गत कांग्रेस सरकार के समय बिजली में भ्रष्टाचार और घोटाला हुआ। उन कार्यों के लिए मैं निवेदन करूंगा कि जांच होनी चाहिए, ताकि श्वेत पत्र की जो बात हो रही है, वह सामने आ जाये, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाये।

सभापति महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र में सरकारी जमीनों पर, बावड़ियों पर अनगिनत तरीके से कब्जे होकर अवैध रूप से कनेक्शन दिये गये, उनको काटना चाहिए, ताकि अवैध कनेक्शन जो हैं, भले ही वे फैक्ट्रियां हों या इंडस्ट्रीज हों, उन अवैध कनेक्शनों की वजह से जो लोग बिल चुका रहे हैं और नियम कायदे से चल रहे हैं, उनको भी पर्याप्त बिजली नहीं मिल पा रही है। इसको भी देखने की आवश्यकता है।

इसी प्रकार से हमारे अर्जुन कॉलोनी वार्ड नम्बर 25, मीणा कॉलोनी वार्ड नम्बर 22, पंजाबी कॉलोनी वार्ड नम्बर 12, बासबदनपुरा वार्ड नम्बर 25, इनमें अनगिनत अवैध रूप से फैक्ट्रियां और कारखाने चल रहे हैं, जिनमें अवैध रूप से बिजली दी गई थी और वह आज तक चल रही है। उसको काटने की आवश्यकता है, जांचने की आवश्यकता है।

जयसिंहपुरा खोर क्षेत्र में मानबाग, नाई की थड़ी, दिल्ली रोड, अमृत विहार, जामिया मस्जिद के आसपास अवैध रूप से बिजली के कनेक्शन संचालित हैं। इसी प्रकार से जयसिंहपुरा खोर क्षेत्र में डेढ़ लाख की आबादी निवास करती है तथा नई कॉलोनियां विकसित हो रही हैं। जिससे वहां पर बिजली की मांग बढ़ रही है और आये दिन बिजली की समस्या उत्पन्न होती है। उसमें ग्रिड को अपग्रेड करने की आवश्यकता है। वहां पर बिजली पर्याप्त मिले, उसके लिए आप कोई व्यवस्था करें।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि जयसिंहपुरा खोर में जीएसएस पॉवर ग्रिड की बड़ी मांग है, जिससे बिजली की समस्या का समाधान हो सकता है। इसी प्रकार से शास्त्री नगर, भट्टा बस्ती, कब्रिस्तान के आसपास अवैध रूप से कॉलोनियां बसाई जा रही हैं जिनमें भी अवैध कनेक्शन हैं। मैं स्वंय मौके पर

जाकर अधिकारियों को कई बार अवगत करा चुका हूं, वहां पर काटने की आवश्यकता है।

मैं निवेदन करना चाहूंगा मंत्री महोदय से कि सौर ऊर्जा की ओर हमें आगे बढ़ना चाहिए। हम ग्रीन ऊर्जा की बात करते हैं तो फैक्ट्रियां हों, छोटे कारखाने हों, दुकानें हों या घर हों, उन पर सब्सिडी के माध्यम से अधिक से अधिक सौर पैनल की व्यवस्था करनी चाहिए। इसके लिए विशेष टीम गठित करके, सौर ऊर्जा की ओर हमें आगे बढ़ना चाहिए। जिससे हमारी बिजली की समस्या दूर हो पाये।

राजस्थान में जयपुर, अजमेर, जोधपुर डिस्कॉम में निरन्तर पिछले शासन में अनियमितताएं रही हैं। मैं वे सारे पेपर टेबल करता हूं। मैंने मंत्री महोदय को उसकी एक कॉपी भिजवा भी दी है। राजस्थान में सौर ऊर्जा के भंडार हैं और बिजली का संकट उसके माध्यम से दूर हो सकता है। मैं अन्तिम बात कहते हुए यही निवेदन करूंगा कि पिछले जो काम हुए हैं, उनकी जांच होनी चाहिए। हमें आगे बिजली की समस्या को दूर करने के लिए, बिजली की आवश्यकता तो निरन्तर पड़ेगी, राजस्थान आगे की ओर बढ़ रहा है, विकसित राजस्थान, अग्रणी राजस्थान है तो उसमें आवश्यकता तो पड़ेगी, लेकिन साथ में हमें अब सौर ऊर्जा की ओर बढ़ना चाहिए, ताकि समस्या का निदान हो पाये। मुझे बोलने का अवसर दिया, उसके लिए धन्यवाद।

श्री सभापतिः श्री गणेशराज जी बंसल।

श्री गणेशराज बंसल (हनुमानगढ़): सभापति महोदय, आज आपने बिजली की चर्चा पर बोलने का अवसर दिया, उसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

मैं आपके माध्यम से ऊर्जा मंत्री महोदय को निवेदन करूंगा कि वर्तमान में प्रदेश में बिजली की समस्या बहुत अधिक है। हमारे जो ग्रामीण इलाके के लोग हैं, वे इस समस्या से त्रस्त हैं। जो कृषि कनेक्शन हैं, मेरा विधान सभा क्षेत्र हरियाली का क्षेत्र है। वहां नहरों व भूमिगत ट्यूबवैल से ही कृषि का उत्पादन होता है, खेती होती है। वर्तमान में कृषि कनेक्शन नहीं होने के कारण लोगों को समस्याओं से जूझना पड़ता है। नहरों में भी पानी बहुत कम है। वर्तमान में 2018 तक के कनेक्शन दिये जा रहे हैं, जबकि 2023 तक के डिमांड नोटिस भरवा लिये गये हैं।

हमारे काश्तकार बिजली की तरफ मुंह देख रहे हैं, रात्रि के समय ग्रामीण इलाके में एलडी कट लग जाते हैं, लोग हम जन-प्रतिनिधियों को फोन करते हैं, हम अधिकारियों को फोन करते हैं, अधिकारी फोन नहीं उठाते हैं। लोग जन-प्रतिनिधियों के कपड़े फाड़ने तक मजबूर हैं।

मेरा बिजली मंत्री महोदय से यही निवेदन है कि वर्तमान में ट्रांसफार्मर भी नहीं हैं और जो आरडीएसएस के तहत कनेक्शन ढाणियों में दिये जा रहे हैं, वे भी बन्द हैं। कृपा करके उनकी तरफ ध्यान दिया जाये और बिजली का उत्पादन बढ़ाया जाये।

रात्रि के समय के लिए बिजली की स्टोरेज करने की व्यवस्था की जाये। जब शाम को सौर ऊर्जा बन्द हो जाती है तो रात्रि के टाइम जमा हुई बिजली जनता में वितरित करके जनता को इसका लाभ पहुंचाये। वर्तमान में, भारतीय जनता पार्टी के माननीय मुख्य मंत्री

भजनलाल जी शर्मा के नेतृत्व में लोक कल्याणकारी सरकार है। उसकी तरफ जनता मुंह बाए देख रही है, ताकि विकास हो सके।

मैं निवेदन करूंगा कि आप जनता की समस्या को समझते हुए, जनता को बिजली, पानी समय पर उपलब्ध करायें। धन्यवाद। जय हिन्द।

श्री सभापतिः श्री अमित चाचाण जी।

श्री अमित चाचाण (नोहर): धन्यवाद, सभापति महोदय, आपने बिजली की व्यवस्था पर बोलने का अवसर दिया।

अध्यक्ष महोदय ने आज जो वर्तमान में राज्य में बिजली की व्यवस्था है, उस पर आज सदन में चर्चा का समय दिया था, लेकिन अफसोस की बात है कि सत्ता पक्ष के एक भी विधायक ने यह नहीं कहा कि आज पूरे राज्य के अन्दर बिजली कटौती से क्षेत्र की जनता परेशान है या तो सत्ता पक्ष के विधायकों के यहां बिजली कटौती हो नहीं रही है या वे सत्य बात इस सदन में बताना नहीं चाहते हैं। जब वे क्षेत्र में जायेंगे, तब उनसे जनता पूछेगी कि आपने बिजली कटौती की बात विधान सभा में क्यों नहीं की?

माननीय सभापति महोदय, पिछले 35 वर्षों से हम एक ही नारा सुनते आ रहे हैं कि बिजली, पानी जो दे न सके, वो सरकार निकम्मी है। आज 35 वर्ष के बाद भी हालात ज्यों के त्यों हैं। आज सबसे बुरी हालत किसी डिपार्टमेंट की है तो इस विद्युत विभाग की है। यह डिपार्टमेंट भगवान भरोसे चल रहा है। जो ब्लॉक लेवल के अधिकारी होते हैं, वे न तो फील्ड में जाते हैं, आज किसानों को चक्कर काटने पड़ते हैं।

विभाग के द्वारा बिल किस तरह से पहुंचाया जाता है, प्रत्येक बिलों में त्रुटियां होती हैं, एवरेज के नाम पर अत्यधिक बिल पहुंचाया जाता है, वे लगातार सेटलमेंट के लिए चक्कर काटते रहते हैं। आज डिपार्टमेंट के पास न ट्रांसफार्मर हैं, न तार हैं, न पोल हैं, किसी भी जगह, घरेलू कनेक्शन की बात हो, कृषि कनेक्शन की बात हो, आज यह विभाग कई-कई महीनों से लम्बित कनेक्शन भी नहीं दे पा रहा है। यह बड़ी सोचने वाली बात है।

आज ग्रामीण क्षेत्र में मार, जिस तरह माननीय सदस्यों ने बताया, आज इस बिजली संकट से सबसे ज्यादा कोई प्रभावित है तो छोटे कस्बों और गांवों में बसने वाले ग्रामीण लोग हैं। महीने भर से सदन चल रहा है, हम जयपुर में हैं। जयपुर में एक मिनट भी लाइट नहीं कटती है, बड़े महानगरों में लाइट नहीं कटती है। लगातार सबसे ज्यादा कटौती हो रही है तो ग्रामीण क्षेत्र में हो रही है, चाहे वह रख-रखाव के नाम पर की जा रही है, चाहे वह एलडी कट के नाम पर की जा रही हो। वहां के लोकल अधिकारियों के द्वारा सन्तुष्टिपूर्ण जवाब भी नहीं दिया जाता है कि आपने कटौती कितने समय के लिए की है, कितने टाइम के लिए है।

Bhs/Rtm/02.08.24/20.10/4h

कब आपके बिजली आपूर्ति पूर्ण कर दी जायेगी। यह बहुत ही दयनीय स्थिति है और आज तो सत्ता पक्ष के लोग मात्र कांग्रेस की सरकार पर आरोप-प्रत्यारोप ही करते रहे उन्होंने

एक शब्द भी यह नहीं कहा कि हमारे क्षेत्र में भी बिजली की कटौती हो रही है। बहुत बड़े दर्द की बात है कि आज दस-दस घंटे, पन्द्रह-पन्द्रह घंटे क्षेत्र में किसानों को बिजली नहीं मिल रही है। यह बहुत ही अफसोस की बात है। मेरा मंत्री महोदय से अनुरोध है कि आप बिजली कटौती करो, हम मानते हैं कि समस्या आती है लेकिन बड़े शहरों में भी बिजली कटौती होनी चाहिये। बड़े शहरों में आप दस मिनट की बिजली कटौती करोगे तो ग्रामीण क्षेत्र की चार-पांच घंटे की पूर्ति आपका बिजली विभाग करेगा। ग्रामीण क्षेत्र की जनता के साथ और शहरी क्षेत्र की जनता के साथ यह आप भेदभाव न करें। बहुत बुरी हालत आज क्षेत्र के किसानों की है, चाहे मजदूरों की बात करें बहुत बुरी हालत है। आज न तो बिजली मिल रही है दूसरी तरफ यह सरकार बिजली बिलों के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्र के उपभोक्ताओं के करंट लगाने का काम कर रही है। बार-बार बिजली बिलों की बढ़ोतरी करने का काम कर रही है। एक तरफ यह कहती है कि हम जन-कल्याकारी सरकार है। (समय समाप्ति सूचक घंटी।) माननीय सभापति महोदय, 8.08 बजे शुरू हुआ है मेरा।

श्री सभापतिः एक मिनट।

श्री अमित चाचाण (नोहर): दो मिनट और हैं मैं नोट कर रहा हूं सबका टाइम।

श्री सभापतिः एक मिनट है, मेरे पास है।

श्री अमित चाचाण (नोहर): माननीय, मेरा तो यही अनुरोध है कि समय पर आप बिजली दें और ब्लॉक लेवल पर जो समस्याएं आज हैं उनकी पूर्ति करें चाहे ट्रांसफार्मर की हो, मीटर की बात हो, पोल की बात हो, खंभों की बात हो, जो भी है और दूसरी तरफ माननीय मंत्री महोदय, आप बैठे हैं जो क्षतिग्रस्त तार हैं, क्षतिग्रस्त पोल हैं, क्षतिग्रस्त ट्रांसफार्मर हैं उनको भी समय रहते नहीं बदला जाता जिसकी वजह से दुर्घटना घटने की आशंका रहती है। पूरे राजस्थान में हमने देखा है करंट लगने से चाहे वह पशु हो, चाहे व्यक्ति हो, ग्रामीण क्षेत्र की जनता हो करंट लगने से उनकी मृत्यु होती है इस पर हमें विशेष तौर से ध्यान देना होगा कि हम समय रहते हुए क्षतिग्रस्त जितने तार और पोल हैं उनको बदलें।

दूसरी तरफ जो सरकारी स्कूलें हैं, गोशालाएं हैं उनके ऊपर से जो ग्रामीण क्षेत्रों में लाइन जा रही है चाहे वह 11 हजार की हो, चाहे 33 हजार की हो, उसका पैसा कोई वहन नहीं कर सकता। इसमें हमें नियमों में शिथिलता देनी चाहिये कि राजकीय विद्यालय या गोशालाओं में जहां-जहां उनके ऊपर से लाइनें जा रही हैं उनकी हम शिफ्टिंग करें, जिससे कि उनको सुविधा हो सके।

माननीय मंत्री महोदय, यह हम आपसे अनुरोध करते हैं और एक ग्रामीण क्षेत्रों में कमजोर लोगों की तो वी.सी.आर. भरी जाती है लेकिन बड़े लोगों की वी.सी.आर. नहीं भरी जाती। कमजोर लोगों को परेशान किया जाता है वी.सी.आर. के नाम पर तो यह भी मैं आपको कहना चाहता हूं कि ग्रामीण क्षेत्रों में जो छोटी-छोटी मजदूरी करते हैं, जो किसान हैं, जो समय पर बिल नहीं भर पाते उनको और अधिक समय दें और उनकी वी.सी.आर. न भरें जिससे कि उनको परेशानी का सामना नहीं करना पड़े। समय रहते आप पूरे सामान की

सुविधा उपलब्ध करवायें। इस विभाग के अन्दर कोई बड़ा पैसे वाला है वह पैसे देकर तो अपना एस्टीमेट कम करवा लेता है लेकिन यह भार गरीब और मध्यम वर्ग के व्यक्ति पर पड़ता है कि अत्यधिक एस्टीमेट बना कर उनको दे दिया जाता है वो बिल के पैसे वो जमा नहीं करा पाते, उनके कनेक्शन आज भी आधे-अधूरे हैं। इसके साथ जितनी भी वंचित ढाणियां हैं उन वंचित ढाणियों में पिछली गवर्नमेंट स्कीम लेकर आयी थी, पांच-पांच ढाणियों का ग्रुप बनाया था उनमें काश्तकारों ने जो स्वीकृत हुए उनमें पैसे भी जमा करवा दिये, लेकिन आज भी उन ढाणियों के कनेक्शन नहीं हो रहे हैं, इसलिये मेरा यह भी निवेदन रहेगा कि आप उन ढाणियों के भी कनेक्शन करायें। धन्यवाद। जय हिन्द। जय भारत।

श्री सभापतिः श्री राधेश्याम बैरवा।

श्री राधेश्याम बैरवा (बारां-अटरू): माननीय सभापति महोदय, सर्वप्रथम मैं आपको सादर धन्यवाद देता हूं कि आपके द्वारा मुझे ऊर्जा विभाग पर बोलने का मौका दिया गया।

माननीय सभापति महोदय, प्रधान मंत्री जी के हर घर, हर खेत बिजली निर्बाध रूप से उपलब्ध कराने के संकल्प को साकार करने के लिए माननीय वित्त मंत्री महोदय ने पी.एम. सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के अन्तर्गत प्रत्येक जिले में आदर्श ग्राम बनाना प्रस्तावित किया है। माननीय, मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्य मंत्री महोदय एवं वित्त मंत्री महोदया को धन्यवाद देना चाहूंगा कि उनके द्वारा मेरे क्षेत्र बारां में ऊर्जा उत्पादन क्षमता सृजित करने के बारे में निर्णय लिया गया इससे निश्चित ही क्षेत्र में विकास के नये आयाम स्थापित होंगे।

माननीय सभापति महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र अटरू में 220 के.वी. जी.एस.एस. कवाई क्षेत्र में स्थित है। चूंकि मेरा क्षेत्र कृषि प्रधान क्षेत्र है जिससे रबी के सीजन में ओवरलोडिंग की समस्या उत्पन्न हो जाती है एवं किसानों को कृषि कनेक्शन हेतु उचित वोल्टेज प्राप्त नहीं होते हैं एवं बार-बार ट्रिपिंग की समस्या उत्पन्न होती है। माननीय मुख्य मंत्री महोदय एवं ऊर्जा मंत्री महोदय द्वारा 2024 तक लगाई गई सभी आवेदित पत्रावलियों को कनेक्शन जारी करने के निर्देश दिये गये हैं। इस क्षेत्र में ओवरलोडिंग की समस्या के निस्तारण हेतु अटरू क्षेत्र के अन्तर्गत दीवाली, खेड़ली, बांसला, गोविन्दपुरा, रिछन्दा व बांधपुरा गांव में जी.एस.एस. बनवाना अत्यन्त आवश्यक है।

माननीय सभापति महोदय, इस समस्या के निस्तारण के लिए बारां शहर के नलका, मेल खेड़ी रोड, मांगरोल रोड, कर्मा जी की बावड़ी के पास बरडिया में व मंडोला या भूल-भुलैया चौराहे के आस-पास नवीन जी.एस.एस. निर्माण की सख्त आवश्यकता है। जिला चिकित्सालय बारां एवं चार मूर्ति क्षेत्र के लिए आपात स्थिति में 33 के.वी. लाइन की वैकल्पिक व्यवस्था नहीं है। अत: एक किलोमीटर भूमिगत केबल डालकर रिंग सिस्टम बनाया जाये। बारां शहर में भूमिगत केबल क्षतिग्रस्त अवस्था में है जिसका दुरुस्तीकरण किया जाये। बारां शहर में वोल्टेज की समस्या के निस्तारण के लिए विभाग द्वारा उचित स्थान पर नया ट्रांसफार्मर लगवाये जायें।

माननीय सभापति महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र में अभियंताओं के पद रिक्त होने से

कार्य प्रभावित होता है ऐसे रिक्त पदों को भरा जाये। इसी के साथ एक बार फिर से मैं सदन में बोलने का अवसर देने के लिए माननीय सभापति महोदय का आभार व्यक्त करता हूं। जय-जय राजस्थान। जय हिन्द। जय भारत।

श्री सभापतिः श्री जीवाराम जी चौधरी।

श्री जीवाराम चौधरी (सांचोर): बहुत-बहुत धन्यवाद सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का समय दिया उसके लिए। आज मैं पूरे दिन से बिजली के बारे में बड़ी गहराई से सुन रहा था। इतनी गहराई से सुन रहा था ...(व्यवधान)... इसकी मूल जो प्रॉब्लम शुरू हुई आदरणीय सभापति महोदय, 1947 में जब हमारा देश आजाद हुआ, उस समय जो भूल हुई, यह दुर्भाग्य रहा हमारे इस देश का, अगर सरदार वल्लभ भाई पटेल उस समय के प्रधान मंत्री बनते तो आज हमको न इनका बोलना पड़ता, न इनका बोलना पड़ता। ...(व्यवधान)... बिजली कोई रोटी नहीं है जो लोया बनाया टप-टप और रोटी बनाई टप-टप करके कि ये लो बिजली। यह संयंत्र है। इसको लगाने में ...(व्यवधान)... मैं तो उदाहरण दे रहा हूं, दीदी...(व्यवधान)... और यह सत्य है कल आप भी यह कहोगी अन्दर से तो कि यह बात बिलकुल सत्य है वह भूल हुई उसका भुगतान हम अभी तक कर रहे हैं और अभी मैं धन्यवाद देता हूं राजस्थान की जनता को वरना तो एक इधर, एक उधर। 6 महीने पहले तो कोई समस्या नहीं थी और 6 महीने के बाद यह सरकार बनने के बाद जो समस्याएं उत्पन्न हुई है जिसका कोई पार नहीं। इसका मतलब 6 महीने में इतनी समस्या पैदा हो गई? जहां से छोड़ कर जाते हैं सभापति महोदय, मैं अगर किचन में रोटी बनाता हूं अगर तीन किलो आटा है तो मेरी जगह कोई आयेगा रोटी बनाने वाला तो तीन किलो आटे की ही रोटी बनेगी इस बात की सत्यता को स्वीकार करना पड़ेगा।

सभापति महोदय, आज हमारी सरकार बहुत जोरदार प्रयास कर ही है। मैं आपको कहना चाहूंगा कि ...(व्यवधान)... सरकार हमारी है क्यों नहीं है, अगर आप अपनी नहीं मानते हो तो मत मानो। अभी वर्तमान में हमारी सरकार के प्रयास बहुत सराहनीय है। इसमें कोई दोराय नहीं है। मैं दावे के साथ कहता हूं आने वाले कुछ ही दिनों में इस सारी समस्या का समाधान होगा। हमारे राजस्थान में अभी 18 से 20-22 घंटे मिलती है 24 घंटे बिजली मिलेगी आपको थोड़े दिनों के बाद और आप कहोगे, ऐसी परिस्थिति हो जायेगी कि आपको वाह-वाह करनी पड़ेगी और आपको वाह-वाह करनी पड़ेगी और करोगे इसलिये मैं तो मेरा निवेदन करना चाह रहा हूं ...(व्यवधान)... ये उलाहना दे रहे हैं, 2022 तक किसानों के पास से इन्होंने एग्रीकल्चर कनेक्शन के डिमाण्ड ले लिये 2022 तक के और इनके पास सामान देने के लिए 2017-18 तक का भी नहीं था और 2022 तक कनेक्शन के डिमाण्ड ले लिये। काश्तकार आज घूम रहे हैं। आज हमारी सरकार हर महीने हर विधान सभा क्षेत्र में दो सौ, पांच सौ, आठ सौ कनेक्शन दे रही है। ट्रांसफार्मर ऐसी चीज है सभापति महोदय, ट्रांसफार्मर कोई आटे का लोया नहीं है कि टप-टप बनाया और भेज दिया। एक ट्रांसफार्मर बनाने में एक दिन पूरा लगता है। वह फैक्ट्री में बनता है। यह कोई ज़बानी जमा-खर्च में नहीं बनता।

इसलिये मेरा निवेदन है हमारी सरकार बहुत जोरदार प्रयास कर रही है।

Kas/rtm/02.08.2024/20.20/4j

और अभी तक 6 महीने में जो प्रयास हुए हैं, वे भी बहुत सराहनीय हैं। मैं माननीय ऊर्जा मंत्री जी को बहुत-बहुत धन्यवाद दूंगा।

सभापति महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र सांचोर में भादुना में 220 के.वी. में एक अतिरिक्त ट्रांसफार्मर की जरूरत है और एक कारोला में 132 जी.एस.एस. पर ट्रांसफार्मर की जरूरत है। यह इनके समय में आदेश किया हुआ है, आर्डर दिया हुआ है, लेकिन जब अभी हमारी मीटिंग हुई तो अधिकारियों ने कहा कि साहब, अभी दो महीने में हम इसको देंगे, इस प्रकार की व्यवस्था है। मेरे विधान सभा क्षेत्र सांचोर में चितरवाड़ा क्षेत्र में करीब 100 गांवों को 132 के.वी. जी.एस.एस. को धोरीमन्ना जिला बाड़मेर से काफी वर्षों से जोड़ा हुआ है। इसकी लाइन पुरानी व अति जर्जर हो गई है। इस कारण आये दिन लाइन में फॉल्ट होना, वाल्टेज की कमी आम बात हो चुकी है, जिस कारण मेरे किसान भाइयों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। अत: मेरे विधान सभा क्षेत्र के उन 100 गांवों को नहर क्षेत्र में बने जी.एस.एस., 33 के.वी. के जी.एस.एस. के बदले 132 के.वी. का जी.एस.एस. बनाया जाये।

श्री सभापति: श्री विकास चौधरी। अंकित नहीं होगा।

श्री विकास चौधरी (किशनगढ़): धन्यवाद सभापति महोदय, आपने ऊर्जा जैसे महत्वपूर्ण विषय पर मुझे बात रखने का समय दिया, उसके लिये मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं।

श्री जीवाराम चौधरी (सांचोर): 000

श्री सभापति: प्लीज। आप बोलिए।

श्री विकास चौधरी (किशनगढ़): सभापति महोदय, पिछले 8 महीने में जब से प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, सरकार और ऊर्जा विभाग ...(व्यवधान)... आप सुनो तो सही। सरकार और ऊर्जा विभाग ...(व्यवधान)... सुनो, मैं पुराना रिश्ता ही बता रहा हूं। सरकार और ऊर्जा विभाग, दोनों का पावर मैनेजमेंट पटरी से उतर गया और दुरुस्त होने का नाम नहीं ले रहा है। सभापति महोदय, जिस तरह गांव वालों को पता नहीं चलता कब बिजली जा रही है, कब आ रही है, उसी प्रकार सरकार के मंत्रियों के पास अघोषित पावर कट चल रहा है। सभापति महोदय, प्रदेश की जनता को बिजली समस्या के निराकरण के लिये यह समझ में नहीं आ रहा कि आखिर पावर किसके पास है। प्रदेश में पावर के सब-सेंटर बहुत बन गये। सीएमओ कह रहा है मैं पावर का सब-सेंटर हूं। एक तरफ सीएस कह रहा है मैं पावर का सब-सेंटर हूं, लेकिन मुझे लगता है अभी दिल्ली से पर्ची राजस्थान में आई नहीं।

सभापति महोदय, अभी जीवाराम जी बात कर रहे थे, नेहरू जी का नाम ले रहे थे, एक तरफ विकसित भारत की बात कर रहे थे, लेकिन अपने ...(व्यवधान)... कर्तव्यों से यह भागते नजर आ रहे हैं। विश्व में पर-केपिटा इलेक्ट्रिसिटी कंजम्प्शन में भारत का 117वा

स्थान है। राजस्थान में पिछली सरकार ने राज्य में सोलर नीति लागू करने के लिये 11 हजार मेगावाट सोलर की स्थापना की थी। मैं आपके माध्यम से सरकार के मंत्री जी से निवेदन करुंगा कि गरीबों को फ्री बिजली दी जाये।

सभापति महोदय, मैं मंत्री जी को कहना चाहता हूं कि टेबल पर रखा पैन उठाते क्यों नहीं, प्रदेश को बिजली नहीं दे पा रहे, यह बताते क्यों नहीं। जब हमारे किसान भाई पूछते हैं, किसान बिजली मांगते हैं, तो यह कहते हैं कि मोदी जी तीसरी बार देश के प्रधान मंत्री बन गये। हमारे पढ़ने वाले नौजवान बच्चे बिजली मांगते हैं, तो यह कहते हैं कि भारत विकसित हो रहा है, भारत विश्व गुरु बनने जा रहा है। उद्योग के लिये व्यापारी बिजली मांगते हैं, तो यह कहते हैं कि देश में डबल इंजन की सरकार है। लगातार जनता को गुमराह करने का काम आप लोग कर रहे हैं। बिजली के लिये पूरा प्रदेश त्राहिमाम कर रहा है। सभापति महोदय, पिछले 6 महीने से अघोषित बिजली कटौती से किसान और उद्योग, दोनों की उत्पादकता में कमी आई है और डिस्कॉम के हाल देखे नहीं जाते।

सभापति महोदय, मेरे किशनगढ़ विधान सभा क्षेत्र के लिये मैं मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि वहां जल्द से जल्द नये जी.एस.एस. स्वीकृत करें। ग्रामीण क्षेत्रों में ट्रांसफार्मर लोड नहीं उठा पा रहे हैं और अत्यधिक भार के कारण वे ब्लास्ट हो जाते हैं। इससे रातभर बिजली नहीं आती, लोग परेशान होते हैं। हमारे किशनगढ़ विधान सभा क्षेत्र में घरों के ऊपर 11 हजार की लाइन जा रही है, लोग उससे भी बुरी तरह दुःखी हैं।

सभापति महोदय, व्यापारियों को क्या मिला? व्यापारियों को इस सरकार से नोटबंदी मिली, व्यापारियों को जीएसटी मिला, व्यापारियों को फिक्स चार्ज मिला, सरचार्ज मिला, ट्रिपिंग मिली। मैं जब बाहर निकलता हूं तो लोग कहते हैं कि आप बिजली नहीं दे रहे हो। मैंने कहा कि हम कहां से दें, सरकार तो सामने बैठी है, सत्ता पक्ष सामने बैठा है। वो कहते हैं कि वे तो आप पर आरोप लगा रहे हैं। सभापति महोदय, मैं हमारे सत्ता पक्ष के साथियों से कहना चाहता हूं, मोदी जी से नहीं, अटल बिहारी वाजपेयी जी से आपको सीखना चाहिये। सत्ता पक्ष और विपक्ष को आरोप लगाने के बजाय अपनी अंतर आत्मा में झांकना चाहिये कि आज किसान किस प्रकार से बिजली के लिये तड़प रहा है। आज वे नौजवान जो पढ़ना चाहते हैं, रातभर लाइट नहीं आती है, वह तड़प रहे हैं, किसान तड़प रहे हैं। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं मंत्री जी..

श्री सभापतिः श्री महेन्द्र पाल मीना। अंकित नहीं होगा।

श्री विकास चौधरी (किशनगढ़): 000

श्री महेन्द्र पाल मीना (जमवारामगढ़): सम्माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे बिजली की चर्चा पर बोलने का मौका दिया, इसके लिये मैं आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। सभापति महोदय, मैं राजस्थान के यशस्वी मुख्य मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूं

श्री विकास चौधरी (किशनगढ़): 000

श्री सभापतिः अंकित नहीं होगा।

श्री महेन्द्र पाल मीना (जमवारामगढ़): किसान के बेटे हमारे राज्य के मुख्य मंत्री और हमारे ऊर्जा मंत्री, जिन्होंने किसान के हित में सोचा और ऐसी व्यवस्था की कि जिस प्रकार से कांग्रेस राज में कुप्रबंध हुआ, मैं धन्यवाद देता हूं राजस्थान के ऊर्जा मंत्री जी को जिन्होंने हमारे जमवारामगढ़ में 132 जी.एस.एस. धोला में खोला और आंधी के 132 के.वी. को क्रमोन्नत करके 220 किया। मैं धन्यवाद देता हूं हमारे ऊर्जा मंत्री जी को और मैं कहना चाहता हूं कि आपने जिस प्रकार फीडर सुधार में जो काम किया, वह अपने आप में मील का पत्थर साबित होने जा रहा है।

सभापति महोदय, मैं मांग करता हूं कि धोला में सहायक अभियंता कार्यालय खोला जाये और साथ में जे.ईएन. ऑफिस धोला, गठवाड़ी, सायपुरा, बिरासना में खोले जाएं। साथ में 33 के.वी. जी.एस.एस. खरकडा, लांगडियावास, साइवाड, केलाकाबास और पापड़ में खोला जाये।

सभापति महोदय, मैं इन कांग्रेस भाइयों को इनकी वस्तु स्थिति बताना चाहता हूं, पूर्ववर्ती सरकार ने किस प्रकार से राजस्थान में थोथी घोषणा करके इस बिजली के ढर्रे को खराब कर दिया। गत सरकार में फरवरी, 2019 में कोयला आधारित स्रोतों से 6 हजार मेगावाट स्थापित करने की घोषणा की गई थी। इस घोषणा के दो वर्ष बाद इस योजना के तहत बजट फरवरी 2022 में 1320 मेगावाट क्षमता छबड़ा, 800 मेगावाट, कालीसिंध 125 मेगावाट गुढ़ा बीकानेर में उत्पादन निगम द्वारा स्थापित करने की घोषणा की गई थी। सभापति महोदय, इस परियोजना के क्रियान्वयन हेतु राज्य सरकार द्वारा अंश पूंजी की व्यवस्था नहीं करने के कारण विगत दो वर्षों से उत्पादन इकाई स्थापित करने का कार्य नहीं हो पाया। यहां तक कि कोल आधारित परियोजना स्थापित करने हेतु निजी विकासकर्ता के चयन हेतु टेरिफ आधारित निविदाएं आमंत्रित नहीं की गईं।

सभापति महोदय, इसी प्रकार बजट वर्ष 2023 में 1100 मेगावाट लिग्नाइट आधारित परियोजना बाड़मेर में लगाने की घोषणा की गई थी, किन्तु इसे स्थापित करने हेतु राज्य सरकार स्तर पर कोई निर्णय नहीं लिया गया, इससे इनका कुप्रबंधन साफ दिखता है। सभापति महोदय, बजट 2019 में आरपीओ की पूर्ति हेतु 4800 मेगावाट सौर ऊर्जा व 1426 मेगावाट पवन ऊर्जा क्षमता का विकास हेतु घोषणा की गई थी एवं बजट फरवरी, 2023 में राज्य में 1100 मेगावाट की अक्षय ऊर्जा परियोजनाएं चालू करने की घोषणा की गई थी। आरपीओ की पूर्ति हेतु सौर व पवन ऊर्जा क्षमता विकसित करने हेतु सेकी से निविदा करवा कर मात्र अनुबंध हस्ताक्षरित कर लिये। सभापति महोदय, जिस प्रकार से पिछली कांग्रेस सरकार ने थोथी घोषणाएं करके जो अनुबंध किये, उस पर कोई रुचि नहीं दिखाई, जिसके कारण हमारे राजस्थान में बिजली की ऐसी व्यवस्था हो गई।

सभापति महोदय, मैं आपसे कहना चाहता हूं सौर ऊर्जा के निर्बाध रूप से प्रवाह हेतु प्रसारण तंत्र के सुदृढीकरण हेतु कोई कार्य नहीं किया गया। बजट घोषणा फरवरी, 2023 के अनुरूप अक्षय ऊर्जा परियोजनाएं चालू करने की दिशा में विशेष कार्य नहीं किया गया।

Msk/rtm/02.08.24/2030/4k

सभापति महोदय, हमारे कांग्रेस के भाई कहते हैं कि हमने वह किया, हमने वह किया, लेकिन जिस प्रकार से पिछली सरकार ने जो कुप्रबंध किया, जिस प्रकार से सरकार ने थोथी घोषणा की है, उसका कारण है कि आज राजस्थान में बिजली की गड़बड़ हुई है। लेकिन में राजस्थान के यशस्वी मुख्य मंत्री महोदय और हमारे ऊर्जा मंत्री जी को धन्यवाद देता हूं कि जिन्होंने कुशलता के साथ बिजली को हाथ में लिया है और धीरे-धीरे बहुत ही अच्छा प्रबंध हुआ है।

साथ ही, मैं इनकी बैंकिंग बिजली की व्यवस्था भी बताना चाहता हूं। पूर्ववर्ती सरकार ने अतिरिक्त बिजली उत्पादन व छीजत में कमी की ओर ध्यान न देकर चुनावी समय में प्रदेश की जनता को फौरी राहत देने के नाम पर बिजली बैंकिंग व्यवस्था के माध्यम से तात्कालिक आवश्यकताएं पूरी करने हेतु 35 हजार 234 लाख यूनिट बिजली उधार ली जबकि ऊर्जा विभाग पर पड़ने वाले नकारात्मक प्रभाव व भविष्य में होने वाली बिजली की कमी को अनदेखा किया व उक्त उधार ली गयी बिजली को बैंकिंग व्यवस्था के माध्यम से हमारी सरकार के कार्यकाल में वापस करना पड़ रहा है। माह अप्रेल, 2024 से जुलाई, 2024 तक 24 लाख यूनिट बिजली बैंकिंग सैक्टर में वापस दी जा चुकी है व 11 हजार लाख यूनिट बिजली अगस्त व सितम्बर में वापस की जानी है, जिसके कारण अप्रैल से लेकर सितम्बर तक बिजली कटौती करनी पड़ रही है, जिससे राहत देने के लिये हमारी सरकार द्वारा राज्य की मांग के अनुरूप विद्युत उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु..

श्री सभापति: अंकित नहीं होगा। श्री मनोज कुमार।

श्री महेन्द्र पाल मीना (जमवारामगढ़): 000

श्री मनोज कुमार (सुजानगढ़): सभापति महोदय, धन्यवाद। बिजली की चर्चा में आपने बोलने के लिए समय दिया। सभापति महोदय, आज पूरे प्रदेश में बिजली का जो संकट बना हुआ है और इतनी बारिश हो रही है। मई-जून में हमेशा बिजली की थोड़ी किल्लत देखने का मिलती है। अब अगस्त आ गया है, पर बिजली की समस्या वैसी की वैसी बनी हुई है। आज भी गांवों में रात-रात भर बिजली की कटौती हो रही है। आज भी एलडी के मैसेज के माध्यम से कटौती की जा रही है। जबकि ऐसा कभी नहीं हुआ कि बरसात के सीजन में इतनी कटौती हो रही है। सबसे ज्यादा परेशान कोई है तो आज किसान है। उसको छह घंटे पर्याप्त बिजली नहीं मिलती। लगातार छह घंटे नहीं मिलती, टुकड़ों में बिजली देते हैं। उसमें भी जब बार-बार ट्रिपिंग आती है तो वह अपना माथा पकड़कर बैठ जाता है। एक बार ट्रिपिंग आने का मतलब है कि उसके 10-15 मिनट चले जाते हैं। कुओं में पानी इतना गहरा है, लाइन भरने में चला जाता है। वह आकर मोटर वापस चलाता है, पानी चलना शुरू होता है, इतने में वापस ट्रिपिंग आ जाती है। तो छह घंटे की बिजली तीन घंटे भी उसको नहीं मिलती है। किसानों को ट्रिपिंग की बहुत बड़ी समस्या हो रही है। अगर किसी किसान का ट्रांसफॉर्मर जल जाये तो

उस किसान की जो फसल सूखती है, उससे उसकी आंखों के आंसू सूख जाते हैं। 10-10, 15-15, 20-20 दिन कोई पता नहीं, कब ट्रांसफॉर्मर मिलेगा? इतनी किल्लत है। आज सबसे बड़ी जरूरत है कि सबसे पहले उस किसान को आप ट्रांसफार्मर दें, जिसकी फसल खेत में खड़ी है। नये कनेक्शन वाले को आप दस दिन देर से देंगे तो उसकी कोई दिक्कत नहीं है, पर जिसकी फसल खड़ी है और सूखने जा रही है, उसको ट्रांसफॉर्मर नहीं मिलेगा तो उसकी क्या हालत हो जायेगी, आप समझिए। सभापति महोदय, वह किसान कहीं का नहीं रहता।

किसान की एक बहुत बड़ी समस्या है कि वह कई बार बिजली के बिल नहीं भर पाता। तो वह विभाग से विनती करता है कि आधे पैसे ले लो, आधे पैसे मैं जब फसल पक जायेगी, उसको बेचकर दे दूंगा। पर उसके साथ कोई रियायत नहीं करते और दिक्कत तब होती है जब कई बार उसका ट्रांसफार्मर उतारकर ले जाते हैं। कम से कम कृषि में थोड़ी-सी रियायत देने का काम करें कि अगर उसकी फसल तैयार हो और किसी कारण से कोई नहीं देता तो उसके कोई ब्याज पैनल्टी लगाकर उसको मौका आप दे सकते हैं। घरेलू कनेक्शन में जब पैनल्टी ब्याज लगाकर एक-दो महीने कनेक्शन नहीं काटते तो उसका कनेक्शन तुरन्त नहीं काटा जाये। अपन जानते हैं कि तीन महीने में फसल में तैयार हो जाती है, कई बार एक-दो महीने का डिले हो जाता है। कम से कम उसका ट्रांसफार्मर नहीं उतारा जाये, यह व्यवस्था आप करायें, ताकि वह फसल बेचकर दे सके।

मंत्री महोदय, मैं आपको इस बात के लिए धन्यवाद दूंगा कि आपने सब एमएलएज को बुलाकर उनसे चर्चा की कि उनके विधान सभा क्षेत्र में बिजली क्या समस्या है। पर उसके बाद आपने फिक्स चार्ज के माध्यम से बिजली बढ़ाने का काम किया और एक अतिरिक्त बोझ पूरे प्रदेश में डालने का काम किया है। विभाग, जो ठेकेदारों के भरोसे है। ठेकेदार किसानों को कॉपरेट नहीं करते। उसका ट्रांसफार्मर जलता है तो कह देते हैं कि आप ही लेकर जाओ, आप ही इसको लगाओ। उसको मजबूरी में लगाना पड़ता है, जबकि उसका काम नहीं है। उसके पास टेक्निकल आदमी नहीं है, पर उसको मजबूरी में ये काम करने पड़ते हैं, जबकि ये काम आपके विभाग में ठेकेदार नियुक्त हैं, उनके हैं।

एक बहुत बड़ी समस्या किसानों को सर्दियों में आती है। सर्दियों में जब रात के ब्लॉक में बिजली दी जाती है तो बहुत बड़ी दिक्कत होती है। कम से कम यह व्यवस्था करें कि सर्दियों में दिन के ब्लॉक में किसान को बिजली मिले, क्योंकि रात को जब कड़कड़ाती ठण्ड में जब वह फसल को पानी देने जाता है, वह दे नहीं पाता। बड़ी मुश्किल होती है, आदमी खड़े-खड़े जम जाता है, उस स्थिति में उसको पानी में काम करना पड़ता है। तो कैसे भी व्यवस्था करके इस व्यवस्था को बनाएं कि किसान को सर्दी में कम से कम दो ब्लॉक में बिजली मिले, दिन में मिले।

आरडीएसएस का काम बहुत धीमा चल रहा है, आपको ध्यान है। इसको कैसे ही करके तेज करवायें। जितनी भी ढाणियां हैं, पांच के ग्रुप बनाकर, छह के ग्रुप बनाकर, इन ढाणियों में आप कनेक्शन जरूर दें। जैसे आज पानी आम आदमी की जरूरत बन गया है, वैसे ही

बिजली भी आज आम आदमी की जरूरत बन गयी है। ढाणियों में भी आम आदमी रहता है। वहां भी किसान रहता है, जो हमारे लिए खेत में अनाज पैदा करता है। अगर उसको बिजली नहीं मिल रही है तो बहुत बड़ी समस्या है। बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री छोटू सिंह जी।

श्री छोटूसिंह (जैसलमेर): माननीय सभापति महोदय, बिजली और पानी दोनों ऐसे मामले हैं, जो जीवन जीने से जुड़े हुए हैं। आरोप-प्रत्यारोप लगते हैं, लेकिन अपन सब को यह सोचना है कि इस चीज में सुधार आना चाहिए। मैं भुक्तभोगी हूं कि पूर्ववर्ती सरकार के समय 220 का जीएसएस स्वीकृत हुआ है, 132 का स्वीकृत हुआ और कनेक्शन पर कनेक्शन देते रहे, चाहे सुपर का हो, चाहे स्पेशल का हो या चाहे सामान्य का हो। ये नॉर्म्स हैं कि एक जीएसएस पर 80 या 88 से ज्यादा कनेक्शन नहीं होने चाहिए। हमने तो कनेक्शन 125 और 150 कर दिये। किसान के साथ आदरणीय यह बहुत बड़ा धोखा है। उसको लाइट कैसे मिलेगी? रबी की फसल, मैंने हकीकत में वहां जाकर देखा तो लोगों का बीज उनके खेत के अन्दर ही रहा। यह मेरे जैसलमेर की स्थिति थी। मैं मानता हूं कि इस चीज को सुधारने में समय तो लगेगा। वर्तमान में जिस हिसाब से बहुत अच्छा बजट भाषण लिया है, अच्छी स्कीमें ली हैं, नये-नये जीएसएस लिए हैं। मेरे क्षेत्र में भी लिये हैं। मैं माननीय मुख्य मंत्री जी को और मंत्री जी को धन्यवाद देता हूं, लेकिन क्रियान्विति में अभी समय लगेगा। इस समय के हिसाब से मैं चाहता हूं, आदरणीय मेरे ये दो जीएसएस कब चालू होंगे?

एक प्रोब्लम सबसे बड़ी है, जो मेरे यहां एक गोडावन पक्षी की है, जीआईबी, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड की। उसके पीछे यह है कि गोडावन मर जायेगा, इसलिए लाइन नहीं ले सकते। आदरणीय, इंसान भी हैं और गोडावन है। दोनों की कद्र तो होनी चाहिए। यदि इंसान ही नहीं रहेगा, इंसान को मजबूरियां आयेंगी, इंसान खेती नहीं कर पायेगा तो फिर काम कैसे चलेगा? आदरणीय, मेरा निवेदन है कि मंत्री जी पहले तो यह करें कि आपने इसके बारे में एक कमेटी जैसलमेर भेजी। हम जनप्रतिनिधियों को किसी को भी पता नहीं है कि यह कमेटी क्या फैसला करके आयी है। इसलिए आदरणीय आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि इस कमेटी ने जो फैसला किया है और हमारे ये दोनों जीएसएस कब शुरू होंगे, आदरणीय यह बताना है, ताकि मेरे को जाकर, जनता जर्नादन है, मुझे चार-छह महीने की ऑडिट देनी है।

दूसरा निवेदन है कि कुछ ऐसे जीएसएस हैं, जो 33, 11 के बनाने हैं। आप कनेक्शन देते जाते हैं। पूर्ववर्ती सरकार ने भी दिये और हमने भी घोषणा की है कि हम भी देंगे, लेकिन उसके अन्दर आपको बिजली तो देनी पड़ेगी तभी तो कनेक्शन होगा। आज हालात ये हैं कि जो कनेक्शन दिये हुए हैं, उनमें भी लाइट नहीं आ रही है और सबसे बड़ी परेशानी यह हो रही है कि थ्रू-आउट बिल आ रहा है। मीडर रीडिंग से बिल नहीं, रेगुलर बिल, उतार-चढ़ाव का बराबर करके हर महीने आ रहा है। किसान तो मारा जा रहा है। किसान कहां से पैसा भरेगा? उसका थ्रू-आउट बिल आता है और बिल के लिए, यदि मीटर रीडिंग हो तो यह तो होता है

कि रीडिंग कम आयी है तो पैसा ही कम लगेगा। पैसा तो आप पूरा ले रहे हैं। छह घंटे के हिसाब से ले रहे हैं। लाइट के अन्दर ट्रिपिंग आ जाती है, दो-दो घंटे तक रुक जाते हैं।

mdp/rtm/02.08.2024/20:40/4I

मेरा निवेदन है कि यह सबसे बड़ा काम है।

दूसरा निवेदन और है। (समय समाप्ति सूचक घंटी) सभापति जी, एक मिनट। हम धन्यवाद देते हैं हमारे देश के आदरणीय प्रधान मंत्री जी को, मेरे क्षेत्र के हिसाब से दूरियां हैं, चाहे वह पानी की पाइप लाइन का हो, चाहे बिजली का हो, आप छोटी-सी जगह में, छोटे-से शहरों में, उनकी दूरी एक-एक किलोमीटर, दो-दो किलोमीटर और मेरे गांव से गांव की दूरी 20 से 25 किलोमीटर है। मैं जिस क्षेत्र से आता हूं, उसका क्षेत्रफल भी 400 किलोमीटर लम्बा है। मैं इस चीज का भी अफसोस करता हूं कि शहर में एमएलए होता है, उसको यात्रा भत्ता गाड़ी मिलती है 45 हजार और मैं उस इलाके में पूरे में घूमता रहता हूं तो मेरे को भी 45 हजार। ये तो नॉर्म्स में नहीं है। इतने बड़े क्षेत्र में घूमने के लिए कम से कम आपको रोज का 5 हजार, 10 हजार का डीजल भराना पड़ता है व कच्चे रास्ते में गाड़ी खराब और होती है।

श्री सभापति: विराजिए। आप बैठिए।

श्री छोटूसिंह (जैसलमेर): आप दे रह हैं मुझे सिर्फ शहर के हिसाब से। आदरणीय हमारे कालीचरण जी घूमते हैं, उनको भी 45 हजार, वह तो मखमल की रोड पर घूमते हैं और हम घूमते हैं पूरे क्षेत्र के अन्दर 400 किलोमीटर, उसकी भी वही रेट। यह नहीं होना चाहिए। बीए पास है। बीए पास की नौकरी मिलनी चाहिए।

श्री सभापति: श्री जयकृष्ण पटेल जी। अंकित नहीं होगा।

श्री छोटूसिंह (जैसलमेर): 000

श्री जयकृष्ण पटेल (बागीदोरा): माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। एक तरफ पक्ष है, एक तरफ विपक्ष है, लेकिन मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि राजस्थान की जनता यहां पर देख रही है कि इस लाइन के अन्दर जो बैठा है, वह निष्पक्ष है। मैं निष्पक्ष तरीके से हमारे क्षेत्र की बात आपके सामने रखने की कोशिश करूंगा।

माननीय सभापति महोदय, आज बिजली के महत्वपूर्ण मुद्दे पर बात हो रही है। हम आपके माध्यम से बताना चाहते हैं कि जिस तरीके से हमारा दक्षिणी राजस्थान के अन्दर आदिवासी बाहुल्य इलाका है, वहां पर पहाड़ी इलाका है और बिजली के ट्रांसफार्मर की समस्या है। वहां पर एईएन, एक्सईएन जो अधिकारी होते हैं, अगर जनता की कोई समस्या होती है और उन अधिकारियों को फोन जाता है तो फोन नहीं उठता है और जनता का समाधान भी नहीं होता है। जनता हमसे उम्मीद लगाती है, हमसे बात करती है तो वहां का एईएन, एक्सईएन हमारी बात भी नहीं सुनता है।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से कहना चाहता हूं कि वहां पर झुग्गी-झोपड़ियों के अन्दर हमारे जो गरीब बच्चे हैं, गरीब व शोषित बच्चे हैं, वह अध्ययन बिजली के माध्यम से करते हैं। अगर वहां पर अच्छी लाइट की सुविधा नहीं होगी तो वहां पर अच्छी शिक्षा नहीं मिलेगी। अच्छी शिक्षा नहीं मिलेगी तो वहां के क्षेत्र का विकास नहीं होगा। मैं सरकार को अवगत कराना चाहता हूं कि यह जो समस्या है गंभीर समस्या है। हमारे वहां पर पहले ट्रांसफार्मर का जीरो रुपया लिया जाता था। मैं आपके माध्यम से सरकार को बताना चाहता हूं कि कृषि कनेक्शन का पहले 2 हजार यूनिट फ्री दिया जा रहा था। आज की तारीख में समस्या ये है कि फ्री में जो बिजली का कनेक्शन दिया जा रहा था, उसका पोर्टल बंद हो चुका है। 1.15 पैसे की दर से पर यूनिट बिजली का बिल आता था, वहां पर सब्सिडी भी मिलती थी, वह भी नहीं मिल रही है। डोमेस्टिक, ग्रामीण इलाके के अन्दर जो बिजली का बिल आता था, वह 200 यूनिट पर फ्री था। जन आधार से कनेक्ट होकर वहां पर बिजली का बिल आना चाहिए तो 200 यूनिट फ्री रहेगा। वहां पर जन आधार कनेक्शन के माध्यम से बिजली का जो डोमेस्टिक मीटर होता है, उसको कनेक्ट किया जाए ताकि वहां को जनता को फायदा मिल सके।

सभापति महोदय, वहां पर एक कंपनी है सिक्योर, जो बिल जमा करने की, कनेक्शन और सर्विस सम्बन्धी समस्त सुविधाएं देती हैं। वह मोबाइल पर ही सुविधाएं दे रही हैं। वहां की जनता परेशान है और 160 रुपये प्रति उपभोक्ता बिल का एक्स्ट्रा चार्ज लिया जा रहा है। ऐसी सिक्योर कंपनी जो जनता को सुविधाएं नहीं दे रही हैं और टेंडर के माध्यम से काम कर रही है, उसको ब्लेकलिस्टेड किया जाए और तत्काल प्रभाव से बंद किया जाए। मेरे बांसवाड़ा के अन्दर कुशलगढ़ से लगाकर बिजली की जो समस्याएं आ रही हैं, उसके बारे में बताना चाहता हूं। 132 केवी जो नेगड़िया के अन्दर जो बिजली का ट्रांसफार्मर लगा हुआ है, वह कुशलगढ़, बागीदोरा और चोरड़ी के माध्यम से पूरे विधान सभा क्षेत्र के अन्दर बिजली सप्लाई की जा सकती है। 132 केवी का दलोट के अन्दर पवन ऊर्जा के माध्यम से जो ट्रांसफार्मर लगा हुआ है, उसको 220 केवी अपग्रेड करके लगाये।

माननीय सभापति महोदय, सोलर ऊर्जा का जो प्लांट है, मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि नयी टेक्नॉलोजी के माध्यम से एक ब्रेसलेस डीसी एसी मोटर के माध्यम से कनेक्शन करके सौर ऊर्जा के माध्यम से वहां के किसानों को, गरीबों को बिजली उपलब्ध करायी जाए। एक अंतिम बात और कहना चाहता हूं कि आज जिस बांसवाड़ा जिले के अन्दर बिजली की बात कर रहे है, एनपीसीएल का परमाणु ऊर्जा केन्द्र स्थापित किया जा रहा है। उसके अन्दर वहां पर मुआवजे के लिए कुछ ग्रामीणजन और खाताधारक लोग थे, उनको जबरन पुलिस प्रशासन द्वारा खदेड़ा गया। मैं आपके माध्यम से अवगत कराना चाहता हूं कि उन लोगों को सुरक्षा मुहैया कराई जाए। जो लोग वहां पर पहाड़ी इलाके के अन्दर दूर-दराज क्षेत्र के अन्दर आज की तारीख में घर परिवार छोड़ कर भाग रहे हैं, उनको सरकार और प्रशासन भोजन और रहने की सुविधा उपलब्ध कराए। उनकी मांग क्या है? सरकार और

प्रशासन मिलकर उनसे वार्ता करे और उनकी मांग को पूरा किया जाए। माननीय सभापति महोदय, एनपीसीएल पॉवर प्लांट है। वहां पर ग्रामीणजनों की मांग है।

श्री सभापति: श्री चेतन पटेल जी। अंकित नहीं होगा।

श्री जयकृष्ण पटेल (बागीदोरा): 000

सूचना

कोटा में पशुओं में रहस्यमयी बीमारी

श्री चेतन पटेल कोलाना (पीपल्दा): सभापति जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी को अवगत कराना चाहूंगा कि हमारे कोटा जिला में देवनारायण पशुपालक आवासीय योजना है, जिसमें पशुओं में रहस्यमयी बीमारी आ गयी है। दो दिन में 22 पशुओं की मौत हो चुकी हैं। सैकड़ों पशु बीमार है। पशुपालकों का कहना है कि उनके शरीर का जो तापमान है 106 की डिग्री है, खाना-पीना छोड़ रखा है और गले के नीचे सूजन आ रही है।

श्री सभापति: हो गया। पशुओं की बीमारी है। श्री हाकम अली जी। आपकी एंट्री हो गयी।

राज्य में बिजली की स्थिति पर विचार

श्री हाकम अली खां (फतेहपुर): माननीय सभापति जी, आपने मुझे बहुत ही सीरियस मुद्दा बिजली और पानी का, उस पर बोलने का मौका दिया, बहुत धन्यवाद। बहुत ही दुर्भाग्य की बात है कि सदन की हालत क्या है, यह देखिए, चाहे पक्ष हो या विपक्ष हो। एकतरफ तो हम बार-बार चिल्ला रहे हैं बिजली, पानी, शायद आपने आज अख़बार पढ़ा होगा, भास्कर अख़बार में लिखा हुआ था कि पानी जैसे संवेदनशील मुद्दे पर चर्चा थी और सदन में मात्र 60 सदस्य बैठे थे और एक-दूसरे पर आरोप-प्रत्यारोप लगाकर सदन की छुट्टी करके चले गये, जनता देखती की देखती रह गयी। वही हाल बिजली पर कर रखा है।

सत्ता पक्ष तो विपक्ष पर डाल देता है कि आपने क्या किया पांच साल और विपक्ष, सत्ता पक्ष पर डाल देता है कि आपने 9 महीने में क्याकिया? गांव में बैठे हुए उस किसान को क्या मिला? कुछ नहीं मिला। वह आज भी अपने काम पर था, कल भी अपने काम पर था। हमको डिस्कशन इस पर करना चाहिए था कि बिजली हम कैसे ज्यादा पैदा कर सकते हैं और गांव को, किसान को बिजली कैसे दे सकते हैं, चाहे सत्ता पक्ष के हो, चाहे विपक्ष के हो। सत्ता पक्ष के सदस्य माननीय मुख्य मंत्री जी को और बिजली मंत्री जी को धन्यवाद दे रहे हैं। बिजली काट रहे हैं, इसके लिए धन्यवाद दे रहे हैं क्या? ये कहते कि माननीय मंत्री महोदय, मुख्य मंत्री जी, गांव के लोग फोन कर रहे हैं हमें, चिल्ला रहे हैं, चाहे हमारे हो या चाहे आपके गांव के हो। कोई ऐसा गांव नहीं है जिसमें सिर्फ कांग्रेस के लोग रहते हैं या बीजेपी के। उस गांव में दोनों, तीनों पक्ष के लोग रहते हैं। ये लोकतंत्र हैं, इसमें सब तरह के आदमी रहते हैं और वे यह इंतजार कर रहे थे कि आज बिजली जैसे मुद्दे पर चर्चा है और हमारी बात हमारे विधायक उठायेंगे। हम लोग तो एक दूसरे पर लांछन लगाकर चले जाएंगे।

सभापति महोदय, माननीय बाली से आने वाले पूर्व मंत्री जी इनके साथ मैं 2017 में मीटिंग में था। इन्होंने एक बात कही थी, वह खरी बात होनी चाहिए कि बिजली की किल्लत

थी और अधिकारी इनके साथ में थे। अधिकारियों को इन्होंने कहा कि बिजली की किल्लत क्यों है? साहब, क्या करें ओवर लोड है, इन्होंने कहा कि मैं कुछ नहीं सुनना चाहता। आप चाहते हैं क्या कि हम विपक्ष में चले जाए सत्ता छोड़कर और उन अधिकारियों ने इनको विपक्ष में बैठा दिया था? डिस्कशन पॉजिटिव होना चाहिए। देख लीजिए अधिकारियों की लॉबी का क्या हाल है? इस जैसे मुद्दे पर आज सारे अधिकारी यहां मौजूद होने चाहिए, लेकिन मात्र तीन अधिकारी बैठे हैं। ये भी क्यों सीरियस होंगे? इसलिए मैं यह कहना चाहता हूं कि बिजली कैसे ग्रामीण लोगों को दी जाए, किसान को दी जाए, इस पर डिस्कशन करना चाहिए, न कि एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाकर।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि ढाणियों में जो लोग बस गये, उनको बिजली का कनेक्शन दीजिए। पहले चाहे आप की सरकार हो 2013 से 2018 या 2018 से 2023 हमारी सरकार हो, 500 रुपये में ढाणियों में कनेक्शन करने की योजना आयी थी। उस योजना को आपने बंद कर दिया। उस योजना को आप बराये मेहरबानी वापस चालू कीजिए, क्योंकि ढाणी में जो लोग बसते हैं, वे गरीब हैं। वह ट्रांसफार्मर से लेकर खेत तक ले जाने के लिए एक लाख रुपये का डिमांड नोटिस वह जमा नहीं करा सकता और वह जमा नहीं करा सकता तो बिजली नहीं ले सकता। इसलिए 500 रुपये वाली योजना को वापस चालू की जाए व कनेक्शन दिया जाए।

Ans/rtm 20.50 4m 02.08.2024

मेरा फतेहपुर शहर बहुत बड़ा हो गया है। लाइनें ऊपर से जा रही है, उनका अंडरग्राउण्ड किया जाए। ग्रिड की मांग है। रामगढ़ सब डिविजन के अन्दर तख्तसर एक गांव पड़ता है, उस गांव में बिजली विभाग को जमीन अलाटमेंट कर दी है, मैंने आपको मीटिंग में भी कहा था। जमीन अलाटमेंट कर दी, एक किसान ने दान कर दी, उसमें ग्रिड़ सैंक्शन कर दीजिए, वहाँ की बिजली की समस्या खतम हो जाएगी। फतेहपुर शहर में ग्रिड की मांग है। अधिकारियों ने आपको प्रपोजल भेज दिया, उस दिन मीटिंग में बात हुई उसके बाद, वह ग्रिड सैंक्शन कर दीजिए।

एक समस्या पूरे राजस्थान की है, हर सदस्य की है कि जो कालोनियां नई बस गई, शहर बड़ा हो गया, गांव बड़ा हो गया, उसमें पहले बिजली आती थी, चाहे किसान के खेत से आओ या गांव के नजदीक से आओ, वह जमीन के बीच से आती थी। अब उस बिजली की लाइन को शिफ्ट करने के लिए जो प्लाट लेकर मकान बनाता है उसको डिमांड नोटिस के पैसे भरने पड़ते हैं, कि यह शिफ्टिंग चार्ज आप भरो। वह प्लाट का पैसा भी किसी से लेकर देता है तो फिर वह 80-90 हजार रूपये देकर कैसे बिजली का कनेक्शन कराएंगा। मेरी सरकार से मांग है कि या तो आप एमपी, एमएलए लैड में कर दो कि एमपी, एमएलए कोष में से अपन दे सकते हैं। जो रेवेन्यू विलेज हो उसका कर सकते है, कॉलोनी का नहीं दे सकते, यह उसमें शिथिलता दी जाए, ताकि उनको फायदा मिल सके।

सरकार के पास खजाने में कोई कमी नहीं रहती है। सरकार बहुत बड़ी होती है। सरकार माई-बाप होती है। जैसा कि मंडावा से आने वाली माननीय सदस्या ने कहा कि रामनारायण जी ने कहा था 200 नहीं अगर 400 करोड़ लगे तो भी क्या है सरकार का दायित्व बनता है जनता को सुविधा देना। सरकार का दायित्व बनता है कि जनता को पानी, बिजली की सुविधा दो, 200 नहीं 400 करोड़ रूपये भी कर्जा लेना पड़े तो पड़े लेकिन सरकार जनता को सुविधा दे।

माननीय सभापति महोदय आपके माध्यम से मेरा मंत्री जी से निवेदन है कि लाइन शफ्टिंग चार्ज निगम वहन करे। निगम के पास पैसे की कोई कमी नहीं है। निगम कम्पनियां बहुत पैसे कमा रही है। राजस्थान से बहुत पैसे कमा-कमाकर कम्पनियां लेकर जा रही है।

श्री सभापति: श्री सुरेश जी धाकड़।

श्री हाकम अली खां (फतेहपुर): कम्पनियां ना आपकी है, ना हमारी है। यह कम्पनियां कमा कर चली जाएगी। आप इधर और हम उधर चले जाएंगे।

श्री सभापति: अंकित नहीं होगा।

श्री हाकम अली खां (फतेहपुर): 000

डॉ. सुरेश धाकड़ (बेगूं): सभापति महोदय, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। आज बिजली की चर्चा चल रही है। सुबह से हमारे विपक्ष के मित्र कह रहे हैं कि यह कर दिया, वह कर दिया। यह सारा करा कराया कुंडा आपका ही है। आपके कुकर्मों की सज़ा हम भुगत रहे हैं। आप जो बैंकिंग सिस्टम प्रणाली करके गए ना श्रीमान जी ...(व्यवधान)... आप सुन लो। आने जाने की चिंता मत करो। हम आपको आने वाले 50 सालों तक नहीं आने देंगे। हमारे देश के प्रधान मंत्री जी भी कहते हैं और गृह मंत्री भी। कान खोलकर सुन लो। आपने बैंकिंग प्रणाली तय की। आपने चुनाव देखकर कह दिया कि हम आपको इतने यूनिट बिजली आपको दे देंगे। आपके मुख्य मंत्री जी को, सबको मालूम था। ...(व्यवधान)... सुनो, सुनने का माद्दा रखो। आप होटलों में बैठे थे, आपको मालूम नहीं था कि किसान को बिजली मिल रही है या नहीं मिल रही। मैं गांव में था, मुझे मालूम था आपकी सरकार में बिजली कितनी मिलती थी। अब हमारे ऊपर लोड आ गया। यह समझौता करके चले गए तो हमें आपको देनी पड़ रही है वापिस बिजली, उधार लिया तो चुकाना पड़ेगा।

अभी आप कह रहे थे कि इतिहास में पहली बार हुआ। इतिहास में पहली बार नहीं, आपकी सरकार में हर बार हुआ, रोज हुआ। आपके होटलों में अख़बार पहुंचे या नहीं पहुंचे लेकिन यह पढ़ लो। इसमें लिखा हुआ है 15 करोड़ महंगी यूनिट बिजली खरीदी। एक दिन 8 तारीख को आपने 13 रूपये 96 पैसे में बिजली खरीदी। छुट्टी के दिन भी 7-8 घंटे बिजली गुल। छुट्टी के दिन भी 7-8 घंटे बिजली कटौती। अब कहां से बताओंगे, यह सच्चाई है। थोड़ी आपकी मेहरबानी भी रही है। केवल हमारी वजह से ही नहीं हुआ। आपका भी इसमें बहुत बड़ा योगदान है, हम तो अभी-अभी सरकार में आए हैं। 8 महीने में रिजल्ट की बात

कर रहे हो, महीने भर बाद रिजल्ट भी आ जाएगा। सरकार को 9 महीने तो होने दो, आपको रिजल्ट भी बताएंगे कि क्या रिजल्ट आया।

अभी हमारे फतेहपुर से आने वाले सदस्य, मुख्य मंत्री जी व ऊर्जा मंत्री जी को धन्यवाद दे रहे थे। बिलकुल, मैं डंके की चोट धन्यवाद देता हूं कि देश की आजादी के बाद पहली बार बेगूं को 220 केवी का ग्रिड मिला, इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूं।

मेरा आदिवासी क्षेत्र, भील बाहुल्य क्षेत्र है। वहां के लोग मुझसे मांगते थे, कहते थे बिजली नहीं है। आपके विधायक तो वहां जाते ही नहीं थे। गलती से चुने गए थे। जनता ने नहीं चुना था, वह तो बाई मिस्टेक आ गए थे। वहां 33 केवी ग्रिड ऊर्जा मंत्री जी ने किया, मैं ऊर्जा मंत्री जी को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने उस दूर क्षेत्र में भी यह काम करने की कोशिश की।

दोस्तों, मैं आपसे एक बात जरूर कहना चाहता हूं। मेरे सभी साथी विधायक है, ऊर्जा मंत्री जी यहां विराजमान है, सभी अधिकारी भी विराजमान है। वीसीआर की एक बहुत बड़ी समस्या रहती है।

श्री हाकम अली खां (फतेहपुर): सही बोलो, सही।

डॉ. सुरेश धाकड़ (बेगूं): सही बोल रहा हूं। आप तो केवल सुनो। जब वीसीआर करने जाते हैं तो मेरा एक सुझाव है कि बिजली डिपार्टमेंट की कोई जिम्मेदारी होती है कि डायरेक्ट मोटर चल रही है, चोरी-चकारी हो रही है तो उसको पकड़ने का काम सरकार करे। लेकिन उस किसान को, जैसा कि मध्यप्रदेश में टेम्परेरी कनेक्शन की व्यवस्था है। वहां 4 महीने के लिए कनेक्शन दे दो, तीन एचपी के 8 हजार, पांच एचपी के 8 हजार 700, सात एचपी के 13 हजार और दस एचपी के 18 हजार, उसको कुछ नहीं करना होता है केवल विद्युत विभाग में गए, एक एपलीकेशन लिखी और उसको चार महीने के लिए टेम्परेरी कनेक्शन मिल सकता है, ऐसी व्यवस्था राजस्थान में लागू होनी चाहिए। किसान को बार-बार चोर घोषित किया जाता है, वीसीआर भरने के नाम पर डराया-धमकाया जाता है। मैं सरकार से अनुग्रह करूंगा कि कोई कमेटी बनाकर मध्यप्रदेश भेजे और वहां की व्यवस्था भी देखकर आए। 2 हजार यूनिट तक फ्री बिजली मिल रही है।

वहां जब शिवराज जी मुख्य मंत्री बने थे, आज से 24 साल पहले, तो उन्होंने मुख्य मंत्री बनते ही कहा कि बिजली के थोड़े बहुत पैसे देने पड़ेगे। हमारी पार्टी के लोगों ने भी विरोध किया, लेकिन उस आदमी को मैं धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने बिजली की जो नीति बनाई, उसकी बदौलत मध्यप्रदेश में 20 साल से आज भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। बीच में गलती से जरूर 10-15 महीने आप आ गए। मंत्री महोदय, मेरा आपसे निवेदन है कि वहां अभी भी 10 घंटे बिजली मिलती है। सुबह साढ़े आठ बजे से शाम साढ़े छह बजे तक किसानों को बिजली मिलती है।

सभापति महोदय, वैसे भी बोलने का मौका मिलता नहीं है। मैं बोलने की कोशिश कम करता हूं, लेकिन आज मौका मिलना चाहिए। दस घंटे बिजली मिलती है, वहां की टैरिफ़ अगर

आप देखेंगे तो आपको खुद को पता लगेगा कि बहुत सस्ती, मात्र 1875 रूपये तीन एचपी के 6 महीने का चार्ज। 5 एचपी का 3 हजार का, सात एचपी का 3700 रूपये और दस एचपी का 3875 रूपये चार्ज है, जो 6 महीने में एक बार बिल जमा कराना पड़ता है और हाथों-हाथ रेगूलर कनेक्शन भी मिल जाता है।

मैं दो-तीन बातें और कहना चाहूंगा। सरकार से मेरी डिमांड रहेगी कि शहर और गांव में पहले लड़के-लड़की में भेदभाव होता था। आपके समय भी होता था। हमारी सरकार है, तो मैं मांग करुंगा शहर और गांव में, शहर में रहने वाला भी इंसान है और गांव में रहने वाला भी इंसान है, तो बिजली दोनों को बराबर मिलनी चाहिए। कटौती गांव में हो शहर में भी होनी चाहिए। भेदभाव खतम होना चाहिए।

अंत में, जब किसान के ट्रांसफार्मर लगा और वह ट्रांसफार्मर चोरी हो गया, बाद में ऑयल चोरी हो गया, तो उसको एफआईआर दर्ज कराने के लिए थानों के चक्कर काटने पड़ते हैं। आज ही मंत्री जी घोषणा करे कि मैं इसको समाप्त करने की घोषणा करता हूं और किसान को सीधा ट्रांसफार्मर मिलना चाहिए। किसानों को कृषि कनेक्शन के सामान जितने जल्दी मिल सकते हैं उतना जल्दी होना चाहिए।

आपने समय थोड़ा बहुत कम ही दिया है लेकिन एक अंतिम निवेदन। जिस प्रकार घरों के ऊपर तार निकल रहे हैं, तार को हटाने के लिए अगर डिपार्टमेंट व्यवस्था नहीं करता है तो हम लोग उसके लिए पैसा देने के लिए तैयार है। लेकिन एक व्यवस्था होनी चाहिए कि एमएलए अगर पैसा देता है तो केवल 25 परसेंट डिमांड पर वह काम होना चाहिए। आपने मुझे बोलने का अवसर दिया उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय।

श्री सभापतिः श्री सुभाष जी गर्ग।

डॉ. सुभाष गर्ग (भरतपुर): सभापति महोदय, धन्यवाद। बिजली पर चर्चा हो रही है, मैं सरकार को धन्यवाद देना चाहूंगा कि आज बिजली पर चर्चा रखकर, बिजली सुधार की बात कर रहे हैं।

मैं समय की बाध्यता को देखते हुए, बहुत ज्यादा ना कहते हुए, रिफार्म्स की बात करना चाहूंगा। अपन सबने बहुत सारे सुझाव दिए हैं। किसान की चर्चा की, बैसिक प्रोबलम है। मेरा मानना है समस्या थी, समस्या है और समस्या रहेगी। चाहे कोई भी सरकार आए, कोई भी जाए, समस्या रहेगी। उसका कारण है कि जो रिफार्म्स की बात करते हैं, मैं इसमें चार चीजों पर चर्चा करना चाहूंगा, ट्रांसमिशन, प्रोडक्शन, डिस्ट्रिब्यूशन, रेगुलेशन।

सबसे ज्यादा हम डिमांड सप्लाई की बात कर रहे हैं लेकिन सबसे अहम प्रोबलम ट्रांसमिशन है, उस पर चर्चा बहुत कम देखने व सुनने को मिली। ट्रांसमिशन और इस सिस्टम को सुधारने के लिए पांच कम्पनियां बनाई गई। एक तो बड़ी कम्पनी बना दी, उसके सहारे तीनों नीचे कम्पनियां काम कर रही है। माननीय सभापति महोदय, क्या कारण है, मैं माननीय मंत्री से भी कहना चाहूंगा, इस पर आप इंटरनल चर्चा करिए। पूर्व मंत्रियों को भी बुलाइये। बड़ी-बड़ी कम्पनियां बनाने के बावजूद भी पूरा एस्टेब्लिशमेंट एक्सपंडिचर इंक्रीज

करने के बावजूद भी इस सिस्टम में सुधार क्यों नहीं हो पा रहा। ट्रांसमिशन के सम्बन्ध में एक चीज और कहना चाहूंगा कि अभी दो सिस्टम चलते हैं, विद्युत नियामक आयोग काम करता है। कई बार मैं देखता हूं पावर मंत्री, मुख्य मंत्री सब कुछ है, कई बार मुझे लगता है पावर एग्जिस्ट कहां करती है। पावर एग्जिस्ट करती है कम्पनियों में। कम्पनी के चैयरमेन, सीएमडी, एमडी। यह वास्तविकता है, सरकार चाहे पूर्ववर्ती हो चाहे वर्तमान सरकार हो, फिर दुबारा कहता हूं, मैंने कल भी कहा था, परसों भी कहा था, कि मंत्रियों को पूरी कम्पनी का सीएमडी बनाइये। चैयरमेन बना दीजिए, एमडी भी नहीं बनाए तो। एमडी केवल तकनीकी आदमी हो और प्रशासनिक अधिकारी हो और चैयरमेन कम से कम मंत्री को होना चाहिए, तब जाकर कुछ सुधार हो पाएगा। पॉलिटिकल सिस्टम को आप इम्प्रूव कर पाएंगे।

VPS-RTM-02.08.202-21.00-4n

इसमें दो सिस्टम हैं और यहां पर मौजूद हैं मंत्रीजी, और पूर्व मंत्रीजी भी मौजूद हैं। इसमें जो टैरिफ बेस्ड सिस्टम और यह जो रेगुलेटेड टैरिफ मैकेनिज्म सिस्टम है इसका अध्ययन करवा लीजिए, मंत्रीजी। इसमें आप देखिये कि बड़ा घोटाला है, इस सिस्टम में और इसमें मिलकर नियामक कम्पनियों ने और नियामक आयोग के अधिकारी मिलकर बड़े-बड़े घोटाले करते हैं। इसकी जांच करवाइये। मैं यह नहीं कहता कि यह अब ही हो रहा है, यह कई वर्षों से हो रहा है और बड़े-बड़े अडानीजी जैसे जो उद्योगपति इसमें इन्वॉल्व हैं। वे किस तरह से टैरिफ रेटों का निर्धारण करवाते हैं, कैसे टैरिफ बेस्ड सिस्टम में ऑक्शन दिये जाते हैं और सरकार चाहकर भी आज 400 केवी जीएसएस नहीं लगवा सकती क्योंकि उसकी कोस्ट 500 करोड़ रुपये से जैसे ही ऊपर आती है तो आपको इसके टैरिफ बेस्ड सिस्टम में जाना पड़ेगा। किस का? ...(व्यवधान)...

आप किसी का भी ले लो, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं, मैं सेक्टर की बात कर रहा हूं, मैं इंडस्ट्रीज की बात कर रहा हूं कि किस तरह से इस सिस्टम को हाईजैक किया गया है। तो मेरा यह मानना है मंत्रीजी, इस सिस्टम को आप सुधारिये। आपको एक मौका दिया गया है। आप अधिकारियों को बैठाइये और पूर्व मंत्रियों को बुलाइये और इस सिस्टम को चेंज करवाइये। आज भी आप घोषणा कर दीजिए 400 केवी जीएसएस की, पूर्व सरकार ने एक 400 केवी जीएसएस भरतपुर जिले के कुम्हेर में लगाने के लिए कहा था, आज एक साल, डेढ़ साल हो गया है लेकिन नहीं लगा पा रहे हैं। कारण क्या है? टैरिफ बेस्ड सिस्टम में जो विद्युत नियामक आयोग के जो अधिकारी अभी रिटायर हुए है न, छह महीने से वे फाइल को रोककर बैठे हुए थे। वे अब रिटायर हो गये। यह तो अच्छा हुआ कि वे रिटायर हो गये। आप उसकी भी जांच करवा लीजिए कि क्या कारण था कि वे परमिशन नहीं दे रहे थे सरकार को। सरकार बिलकुल असहाय। भारत सरकार 30 परसेंट अनुदान देती है आपको इस सिस्टम के तहत जो रेगुलेटेड वाला सिस्टम है, उसमें आपको फायदा होगा तो आप इस सिस्टम को आप लागू करिये।

माननीय सभापति महोदय, एक बात और कहना चाहूंगा क्योंकि बात तो बहुत कहने की है कि ट्रांसमिशन सिस्टम, इस तंत्र को भी आप मजबूत करवाइये। 220, 132 और 33 केवी जीएसएस, 33 केवी जीएसएस के लिए तो आप लेकर आ रहे हैं, इसके लिए मैं आपको बहुत धन्यवाद भी देना चाहूंगा कि दस हजार करोड़ रुपये की योजना आप लेकर आये हैं। इसका आप जाल बिछा दीजिए। कई बार उत्पादन भले ही नहीं है आपके पास लेकिन अगर तंत्र को मजबूत कर दिया तो किसानों को रेगुलर तरीके से बिजली मिलेगी।

श्री सभापतिः श्री ललितजी यादव।

डॉ. सुभाष गर्ग (भरतपुर): भरतपुर के लिए यह कहना चाहूंगा कि 220 और 132 केवी जीएसएस आप दें।

श्री सभापतिः अंकित नहीं होगा।

डॉ. सुभाष गर्ग (भरतपुर): 000

श्री ललित यादव (मुण्डावर): माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे बिजली जैसे महत्वपूर्ण मुद्दे पर बोलने का अवसर दिया, इसके लिए आपको धन्यवाद और मेरी पार्टी के नेताओं का भी धन्यवाद।

माननीय सभापति महोदय, न कोई खुशबू, न कोई फूल, न ही कोई रौनक उस पर कांटों की जहालत देखी नहीं जाती। हमने खोली थी इस बाग़ में अपनी आंखें, हमसे इस बाग़ की हालत देखी नहीं जाती। जैसी हालत इन आठ महीनों में बनी इस बाग़ की।

माननीय सभापति महोदय, बिजली पर चर्चा हो रही है और मुझे यह कहते हुए बड़ा दुःख इस बात से होता है कि आपने एक राजस्थान के दो राजस्थान करने का काम किया। 80 परसेंट राजस्थान गांवों में बसता है, जिसको आपने यातना देने का काम किया और 20 परसेंट राजस्थान शहरों में बसता है, आप गांवों की बिजली रोज काट रहे हो दिन में, 24 घंटे ही काट रहे हो और शहर में बिजली लगातार आ रही है। मेरी कोई दुश्मनी किसी से नहीं है, लेकिन मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि बराबर लाइट मिलने का अधिकार पूरे राजस्थान के प्रत्येक व्यक्ति का है जो आप नहीं दे पा रहे हो।

माननीय सभापति महोदय, क्या गलती है उन लोगों की जिन्होंने वोट देकर आपको सरकार में बैठाया? क्या गलती है उन लोगों की जिन्होंने वोट देकर आपके 14 सांसदों को जिताकर भेजा, क्या यह गलती है उनकी कि 11 सांसद आपके हराकर भेज दिये? आप बिजली देना नहीं चाहते हो, गांव का व्यक्ति परेशान हो रहा है। आप चाहे किसी भी तरीके से यह व्यवस्था करें, कैसे भी बिजली खरीदें लेकिन गांव में बिजली देने की आज आवश्यकता है क्योंकि जिस प्रकार से महिला, किसान, बेरोजगार, नौजवान तकलीफ में होता है जब घर पहुंचता है और रात के दो-दो बजे तक फोन करता है और हम सब लोग इस सदन में बैठकर बढ़िया ठंडे-गर्म इस सदन का आनंद ले रहे हैं। मुझे यह बात कहते हुए कतई अफसोस नहीं है कि हम लोग यहां ठंड में बैठे, यहां पर बैठने का हमें कतई अधिकार नहीं है जब तक हम लोग गांवों में पूरी बिजली नहीं दे पाये। कम से कम रात को तो सोने की

लाइट तो उनको दे पायें और हम लोग यहां इस ठंडे-गर्म सदन में बैठकर चर्चा कर रहे हैं।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि किस प्रकार से आज हालात गांवों की बनी हुई है। मेरे इलाके में रात को तीन-तीन बजे तक फोन आ रहे हैं कि साहब, बिजली नहीं आ रही है और लोग तड़प रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। इसलिए सरकार इस तरफ जरूर ध्यान दे और जनता को बिजली देने काम काम करे। मेरे इलाके में 220 केवी जीएसस स्वीकृत है और लम्बे समय से परेशानी चल रही है, किसान को बिजली नहीं मिल पा रही है और बारबार ट्रिपिंग हो रही है। किसान को 220 वोल्टेज मिल रहा है जिससे किसान की मोटर जल रही है सीजन के टाइम पर और किसान को कितनी ही परेशानी झेलनी पड़ रही है तो इस तरफ भी हमें ध्यान देने की आवश्यकता है।

माननीय सभापति महोदय, वी.सी.आर. नाम की बीमारी जो गांव में अधिकारी पहुंचता है तो वहां के लाइन मैन को वह साथ ले जाता है और वह लाइन मैन उसको कहां पर लेकर जाता है? जो उसकी बात नहीं मानता, जो उसके अनुसार नहीं चलता, वह उसके घर पर ले जाकर वी.सी.आर. भरवाने का काम करता है। जो उसकी जेब गर्म कर देता है तो वहां पर वी.सी.आर. नहीं भरी जाती है तो इस तरफ भी आपको ध्यान देने की आवश्यकता है।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपसे यह कहना चाहता हूं कि बिजली अगर काटनी है तो फैक्ट्रियों की काटिये। मेरे इलाके में नीमराना औद्योगिक क्षेत्र है वहां पर तो 24 घंटे लाइट आती है। उसके बगल में मेरा गांव है और वहां पर लाइट नहीं आती है, तो कितनी तकलीफ उस गांव के लोगों को होती होगी, इस बात का ध्यान आपको नहीं है। **(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)**

जितनी चोरी ये औद्योगिक लोग कर रहे हैं, किसान तो उसकी चोरी भी नहीं कर रहा है, गांव का व्यक्ति चोरी नहीं कर रहा है जितनी वे लोग चोरी कर रहे हैं। मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं, माननीय सभापति महोदय, गांव में किसी व्यक्ति की वी.सी.आर. आपने भर दी, उसको फ्री आपने कर दिया और फ्री बिजली वह जला रहा है इसलिए मेरा आपको यह सुझाव है कि उसको भी आप लोग वापस से लाइट से जोड़ने का काम करिये और उससे कम पैसे उस वी.सी.आर. के लेकर सैटलमेंट करके, इंस्टालमेंट में लेकर उसको भी आप अवसर देने का काम करें, जिससे मैं यह समझता हूं कि इसका समाधान हो पायेगा।

माननीय सभापति महोदय, मेरे इलाके के बानसूर में 220 केवी जीएसएस का टॉप चेंजर पिछले सात महीने से खराब पडा है और किसान को बड़ी तकलीफ झेलनी पड़ रही है तो मेरा यह निवेदन है कि आप इसको भी लगवाने का काम करें। सैकड़ों कृषि ट्रांसफार्मर, घरेलू ट्रांसफार्मर जले हुए पड़े हैं, उनकी भी पूर्ति नहीं हो पा रही है तो उनकी भी सरकार पूरी पूर्ति करने का काम करें।

श्री सभापतिः श्री अर्जुनलालजी, विभाजन संख्या-12।

श्री ललित यादव (मुण्डावर): माननीय सभापति महोदय, मेरा आपसे यह निवेदन है कि सरकार इस तरफ जरूर ध्यान दें।

श्री सभापतिः अब अंकित नहीं होगा।

श्री ललित यादव (मुण्डावर): 000

श्री अर्जुन लाल (बिलाड़ा): माननीय सभापति महोदय, जैसा कि कहा गया है कि राजा, योगी, बिजली,जल इनकी उल्टी रीत, 'परसराम' दूरै रहो, मत कोय राखो प्रीत।।

श्री सभापतिः आप रिकार्ड देख लेना।

श्री अर्जुन लाल (बिलाड़ा): आज हमारे बिजली के मंत्रीजी और जल मंत्रीजी भी यहां पर विराजे हुए हैं और साथ में यह कहा है कि-

क्षिति, जल, पावक, गगन, समीरा।
पंच रचित अति अधम शरीरा॥

तो यह जो जल और बिजली इस जगत में सबसे अत्यावश्यक अभी है और इसके लिए मैं मेरे विधान सभा क्षेत्र और पूरे प्रदेश के लिए कुछ तंत्र सुधार के लिए मांग भी करूंगा और निवेदन भी करूंगा कि हमारे देश के यशस्वी प्रधान मंत्रीजी नरेन्द्र भाई मोदीजी ने वित्त पोषित करके आर.डी.एस.एस. योजना लागू की थी। उस योजना में मंत्री महोदय से मेरा आपके माध्यम से यह निवेदन है कि जो हमारी 11 केवी और 33 केवी की लाइनें कई जगह पर साथ में चल रही हैं तो उनके दोनों के फीडर अलग करने की बहुत ही जरूरत है, ताकि उनको सेपरेट करने से किसानों को और घरेलू उपभोक्ताओं को, औद्योगिक क्षेत्र में कभी फॉल्ट आ जाती है तो पूरा का पूरा सिस्टम ठप हो जाता है। 133 केवी जीएसएस पर फॉल्ट आ गयी तो पूरा एरिया ही बंद हो जाता है, 220 केवी जीएसएस में फॉल्ट आ जाती है तो पूरा क्षेत्र ही बंद हो जाता है तो उनमें दोनों की लाइनें अलग-अलग करने का और वह गुणवत्तायुक्त बिजली मिलने का हमें अवसर इससे मिलेगा। यह दोनों लाइनें अलग-अलग होनी चाहिए, सपरेट होनी चाहिए और साथ ही साथ जो हमारे डोमेस्टिक कनेक्शन है और एग्रीकल्चर कनेक्शन है गांवों के अन्दर उनमें भी लाइनें दोनों की अलग-अलग हों। एग्रीकल्चर में कभी फॉल्ट हो जाता है तो डोमेस्टिक को काट देते हैं और डोमेस्टिक में फॉल्ट हो जाता है तो एग्रीकल्चर को भी काट देते हैं तो यह यह अलग-अलग होगी तो नहीं कटेगी।

दूसरा मेरे वहां बिलाडा में 1992 में 220 केवी जीएसएस का सब स्टेशन बना था और अपन बारबार सभी सदस्य यह कह रहे हैं कि इतनी डिमांड बढ़ गयी है, दस साल बाद कनेक्शन डबल हो गये हैं तो हमारे वहां पर जो 220 आज से करीबन तीस साल पहले बना था तो उसका क्रमोन्नयन करने के लिए जहां भी 220 केवी जीएसएस आज से दस साल के पहले बने हुए हैं वहां पर 400 केवी जीएसएस हो जाए तो निश्चित रूप से इसमें सुधार आयेगा।

SSY/RTM/02.08.2024/21:10/4o

मंत्री महोदय से मेरा निवेदन है कि 10 साल पहले 2009 के अन्दर, मेरे बिलाड़ा विधान सभा क्षेत्र में कापेड़ा सेज के लिए, सेज के उद्यमियों ने 22 बीघा जमीन खरीदी थी। प्रसारण

निगम को उनके नाम दे दिये। लेकिन 2010 के बाद आज तक वहां ना तो 132 केवी जीएसएस का कोई काम हुआ है, वहां जो सारे उद्योग स्थापित होने थे, वे सारे ठप हो गये हैं। वहां पर कोई काम नहीं हो रहा है।

मेरा निवेदन है कि वैसे भी अभी हमारे जैतारण में आपने और मुख्य मंत्री जी ने 220 केवी का सब स्टेशन दिया है। पहले भी 132 का बिलाड़ा से ही मिला था। अब वहां की डिमांड बढ़ गयी है। बिलाड़ा में अगर 400 केवी का जीएसएस स्थापित हो जायेगा तो बहुत अच्छा रहेगा।

इसके साथ ही एक रिंग सिस्टम हो जाना चाहिए 132 के बीच में, आपस मैं जैसे कहीं भी बीच में, जैसे मेरे बिलाड़ा से पीपाड़ जाता है, जैतारण जाता है, सोजत जाता है, बोरुंदा जाता है, तो किसी एक भी सैक्शन पर यदि आपस में रिंग सिस्टम बन जाता है, एक लाइन खींचकर चारों जीएसएस को मिल जाती है तो कोई एक जीएसएस खराब हो गया तो दूसरे जीएसएस से उसको बिजली मिल जायेगी। ग्रिड उसका बन जायेगा। रिंग बन जायेगी। ग्रिड तो अलग है। रिंग सिस्टम हो जाता है तो निश्चित रूप से उसमें सही रहेगा।

एक मिनट, किसानों के खेतों में से जो पाइप लाइन निकलती है, जो 785 केवी की बड़ी लाइन निकल रही है, उस टावर की साइज भी करीब आधा बीघा की होती है। जब नीचे से वह टावर बड़ा होता है तो आधे बीघे की साइज होती है। उसमें किसान को सिर्फ उसकी जो फसल बोई होती है, उसका मुआवजा देते हैं।

एक सेकण्ड, एक बिन्दु रहा है।

उसके लिए किसानों को बड़ी लाइन निकालने के लिए जमीन का मुआवजा देना चाहिए क्योंकि उनके खेत में से, फिर बाद में वह ना तो कभी कन्वर्जन करवा सकते हैं, ना उसमें कॉमर्शियल, डामेस्टिक कोई कॉलोनी कट सकती है। उनका भुगतान मिलना चाहिए।

श्री सभापतिः श्री जाकिर हुसैन गैसावत।

श्री अर्जुन लाल (बिलाड़ा): इसके साथ ही साथ मेरी विधान सभा में ...(व्यवधान)...

श्री सभापतिः अंकित नहीं होगा।

श्री अर्जुन लाल (बिलाड़ा): 000

श्री जाकिर हुसैन गैसावत (मकराना): माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे बहुत ही महत्वपूर्ण बिजली के मुद्दे पर बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं।

मैं, मेरी बात शुरू करने से पहले एक शेर पढ़ना चाहता हूं,

औरों के ख्यालात की लेते हो तलाशी,
खुद के गिरेबान में झांका नहीं जाता।

माननीय सभापति महोदय, जिस तरह से दोपहर से बिजली के अन्दर वाद-विवाद, विचार-विमर्श हो रहा है, हम देख रहे हैं कि हां पक्ष लॉबी वाले कभी भी मंत्री जी को यह नहीं कह रहे हैं कि हमारे लाइट नहीं हैं, हमारे बिजली में कटौती है। खाली एक-दूसरे पर आरोप

लगा रहे हैं।

सभापति महोदय, या तो मंत्री जी हमारे साथ भेदभाव कर रहे हैं, हां पक्ष लॉबी वाले को बिजली फुल दे रहे हैं इनके विधान सभा क्षेत्रों में और हमारे ना पक्ष लॉबी वाले में लाइट की कटौती है, इसलिए आज सुबह से देखने को मिल रहा है कि आप खाली आरोप के अलावा कोई दूसरा काम कुछ नहीं कर रहे हैं। 8 महीने हो गये, शादी हो गई, हनीमून भी हो गया, मौज-मस्ती भी हो गई, अब तो काम पर लगो।

प्रदेश की हालत 8 महीने से ऐसी हो गई कि बिजली की मारामारी चल रही है। अभी अन्दर टेलीफोन बंद है। जैसे ही बाहर जायेंगे ना पक्ष लॉबी में, टेलीफोन अगर दस आयेंगे तो 8 टेलीफोन में, एमएलए साहब हमारी लाइट गई, हम रोटी खाने बैठे, किसान आदमी, लाइट कब आयेगी। आगे फोन करते हैं, एसई से बात करो, एईएन से, जेईएन से, लाइन मैन से, एक ही जवाब है कि एलटी से लाइट गई। अब एलटी क्या प्रोब्लम है? किसी के पास जवाब ही नहीं है। 8 महीनों में बिजली की इतनी हालत खराब हुई है कि जिसकी सीमा नहीं है।

अभी 2 महीने पहले जब टेम्परेचर 52 डिग्री पहुंच गया था तो मेरे मकराना में हालत ऐसी थी मंत्री महोदय जी, आपको मैं बताना चाहता हूं कि जिस तरह से कोरोना के अन्दर गैस के सिलेंडर ढूंढ रहे थे ना, उस तरह हम ट्रांसफार्मर ढूंढ रहे थे। कोई झालावाड़ से ट्रांसफार्मर मंगा रहे थे। तीन दिन से लाइट नहीं थी। कहीं भीलवाड़ा से ट्रांसफार्मर आ रहा है। नागौर से आ रहा है। डीडवाना से आ रहा है। बिजली का मामला बहुत चौपट हो रहा है।

अभी जोगाराम जी कह रहे थे कि पंडित जवाहर लाल नेहरु को प्रधान मंत्री बनाते, सॉरी, हां जीवाराम जी, जोगाराम जी सामने दिखते हैं ना डेली, जीवाराम जी कह रहे थे कि पंडित जवाहर लाल जी नेहरु को प्रधान मंत्री बनाते तो यह नौबत नहीं आती। मैं आपको कहना चाहता हूं कि भारत के प्रथम प्रधान मंत्री पंडित जवाहर लाल नेहरु जब बने थे, गिने-चुने घरों के अन्दर लाइट आती थी। आज घर-घर, ढाणी-ढाणी लाइट पहुंची है तो यह मात्र कांग्रेस की देन है।

मैं आपको यह कहना चाहता हूं कि एक तो यह जो एवरेज के नाम से बिजली के बिल आ रहे हैं, हमारे मकराना में एक-एक हजार यूनिट एवरेज के नाम से भर दिये। रीडिंग के अन्दर, वह बिलकुल नहीं है। आपको मैं, मेरी मकराना की जो समस्या है, उसके बारे में मंत्री जी को बताना चाहता हूं कि ग्रामीण क्षेत्र में मकराना में 132 केवी जीएसएस की आवश्यकता है, जिसका प्रपोजल भी भेजा हुआ है, वहां पर 132 जीएसएस लगाकर करवा देंगे तो हमारे ग्रामीण क्षेत्र की समस्या पूरी हो जायेगी।

एक, गैलासर के अन्दर जीएसएस स्वीकृत है। उसका भी काम आप स्टार्ट करें। मकराना-गच्छीपुरा-नागौर आने वाली लाइन पुरानी है। बार-बार फॉल्ट हो जाते हैं। कनेक्शन अधिक होने के कारण ट्रांसफार्मर जल जाते हैं। कुछ शहर की समस्याएं भी हैं। मकराना रोड बालाजी जीएसएस पर 8 एमबीए व 5 एमबीए के 2 ट्रांसफार्मर स्थापित हैं। उन 5 एमबीए के स्थान पर 8 एमबीए ट्रांसफार्मर स्थापित करें। नई बाई पास पर एक नया 33/11 केवी का

जीएसएस बनायें। लग्नशाह हॉस्पिटल के पास 33/11 जीएसएस की डिमांड है। वहां पर भी बनायें। एसएस स्कीम के तहत अधिक लोड वाले 11 केवी फीडर को करायें। शिव बस्ती, गली नंबर 4 और 5 में इसको जोड़ा जाये।

श्री सभापतिः समाप्त कीजिये। श्री शंकर सिंह जी रावत।

श्री शंकरसिंह रावत (ब्यावर): सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का मौका दिया विद्युत के लिए, उसके लिए आपको बहुत-बहुत आभार।

माननीय सभापति महोदय, कांग्रेस के सदस्य भी बड़ी-बड़ी बातें करके हमारी सरकार पर सिर्फ आरोप लगाने का कार्य कर रहे थे। इसके अलावा कुछ नहीं किया। आपको पता नहीं है कि हमारे यशस्वी मुख्य मंत्री महोदय आदरणीय भजन लाल जी ने जैसे ही राजस्थान में पदभार ग्रहण किया, बजट पेश किया, सिर्फ आपके अलावा, पूरे राजस्थान की जनता ने इसको सराहा है।

आज जैसे ही 5 साल पूरे होंगे, आप देखना, बिजली में सुधार इतना जल्दी करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आपके 5 सालों के कारनामों को अभी तक सुधारने में टाइम लगेगा। इसलिए उसमें समय लग रहा है।

माननीय सभापति महोदय, हम पक्ष और विपक्ष सदन में एक-दूसरे को कोसने की बात करते हैं। बिजली में सुधार कैसे हो सकता है, इसमें बहुत कम लोगों ने अपने सुझाव दिये हैं। माननीय मंत्री महोदय से मैं तो निवेदन करना चाहूंगा कि इस व्यवस्था को सुधारने के लिए कैसे हम काम कर सकते हैं, जिससे किसान हमारे सुखी हों, बिजली की व्यवस्था सुधरे, किसान को दिन में बिजली मिले, खेती में पानी पिलाने के लिए इसमें सुधार करना चाहिए।

इनकी तरफ हमें नहीं देखना है। इन्होंने पिछले 5 सालों में अपना सारा समय और शक्ति होटलों के अन्दर निकाल दी। एक होटल वाले दूसरे होटल वालों के ऊपर सिर्फ निकम्मा, नालायक, बेईमान जैसे आरोप लगाते रहे। लेकिन हमारी सरकार कैसे चलायें, यही इनका उद्देश्य रहा। इनके कार्यों को, इनके कारनामों को सुधारने के लिए माननीय मंत्री महोदय आपको बहुत सख्ती से कार्य करना पड़ेगा।

हमारा काम कैसे अच्छा चले, अभी आपने राजस्थान में इतनी सीटें लाने का जो काम किया है, वह सिर्फ हमारी राजस्थान की जनता को बरगलाकर, आरक्षण बंद कर देंगे, संविधान को यह खतरे में डाल देंगे, ऐसी असत्य बोल-बोलकर आपने राजस्थान की जनता को बहकाकर 11 सीटें लेकर आ गये हो।

Spp/Rtm/02.08.2024/21.20/4p

यह भूल जाओ कभी आपका यह सपना साकार होने वाला है। अभी यह निश्चित तौर पर यह जनता बार-बार बहकावे में नहीं आती है। एक बार तो आ गयी कि किसानों का सम्पूर्ण कर्जा 10 दिन के अन्दर माफ कर देंगे। आज सरकार बनाकर तो देखो। आ गये लोग झांसे में, 10 दिन के अन्दर कर्जा माफी की इन्तजारी करते रहे और पांच साल निकल गये।

बेरोजगार भी आपके चक्कर में आ गये। घर बैठे आपको 3,500 रुपया मिल जायेगा। आपने भेज दिया? और सारे लोग आपके चक्कर में आकर एक बार सरकार बना दी और दूसरी बार आपने झांसा दे दिया और 11 सीटें ले गये। अब बार-बार चक्कर में आने वाले नहीं है। अब 2047 तक देश को विकसित भारत बनाने के लिये हमारे पूरे देश की जनता सिर्फ और सिर्फ प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदीजी की तरफ टुकर-टुकर नजर लगाये हुए देख रहे है। आप सब देखोगे 2047 तक इस देश के अन्दर मोदीजी के अलावा ..(व्यवधान)..

श्री सभापति: श्रीमती इन्द्रा।

श्रीमती इन्द्रा (बामनवास): माननीय सभापति महोदय, आपका धन्यवाद और मेरी पार्टी का धन्यवाद, जिन्होंने मुझे बोलने का मौका दिया। ब्यावर वाले माननीय सदस्य मेरे से पहले बोल रहे थे और बिजली के मुद्दे पर नहीं बोल रहे थे। जबकि रात के 9.30 बज रहे हैं। इस समय हम इस सदन के अन्दर बैठे हुए हैं तो पिछली कांग्रेस की सरकार की बुराई करने के लिये नहीं, हम अपनी बिजली की समस्या को दूर करने के लिये यहां पर बैठे हैं। लेकिन शर्म आने की बात यह है कि अपनी पार्टी की बड़ाइयों के पुल बांधने में, सी एम की बड़ाई करने में ही इनका समय निकल जायेगा पांच साल का और आप देखते रहना कि अगली बार किस तरह से बहुमत के साथ में कांग्रेस की सरकार बनती है। आपको किस तरह से मुंहतोड़ जवाब राजस्थान की यह जनता देगी। सत्ता पक्ष के लोग बार-बार कह रहे हैं कि आपने यह नहीं किया, वह नहीं किया। लेकिन मैं कहना चाहती हूं कि अगर हम लोग नहीं करते तो हमारे समय में क्यों बिजली आती। हमारे समय में क्यों नहीं ऐसी दुर्दशा हुई। आपके समय में क्यों दुर्दशा हो रही है ऐसी, क्योंकि आपका कुप्रबन्ध है, हमारा कुप्रबन्ध नहीं था। हमने कुछ भी किया, किसी से भी कर्जा लिया, जो भी करना था, वह हमने किया। आप भी करिये न, आपको कौन मना कर रहा है? लेकिन राजस्थान की जनता यह देख रही है कि कौन सही है और कौन गलत है। आपको इसका जवाब जब आप क्षेत्र में जायेंगे, उस समय देंगे। आप लोग इस तरह की बातें करके स्वयं की नाकामी को दूसरे के ऊपर आरोप डालकर छुपाने की बात करते हो। लेकिन मैं कहना चाहूंगी कि आज मैं आपके सामने इस सदन में बोल रही हूं कि आप मेरा पिछला इतिहास भी देख लीजिये पांच साल का, जब-जब सरकार से कोई मेरी समस्या रही और सरकार से नहीं हुई तो उस समय भी बोला। यह आप देख लीजिये मेरा इतिहास। मैं कभी भी किसी के सामने दबती नहीं हूं चाहे सत्ता पक्ष हो चाहे विपक्ष हो। मैं कहना चाहूंगी कि किस तरीके से मैंने अपनी बात के लिये क्योंकि जनता हमको चुनकर सरकार की बड़ाई करने के लिये नहीं भेजती, हमें सी एम की बड़ाई करने के लिये नहीं भेजती। हमें भेजती है कि अपनी समस्याओं को, क्षेत्र की समस्याओं को जाकर विधान सभा के अन्दर जाकर बोलें। मैं कहना चाहूंगी कि जिस तरीके से अभी कुछ दिन पहले सवाल किया और उस सवाल के जवाब में मंत्री महोदय ने कहा कि जांच करवा लेंगे। यहां से एक अधिकारी जाते हैं और जिस फीडर के अन्दर जांच करनी है उस फीडर के जन-प्रतिनिधियों को नहीं बुलाकर 20-30 किलोमीटर के जन-प्रतिनिधियों को मोटर साइकिल पर, जिनकी

शिकायत हुई है, उनको बिठाकर लाते हैं और उनसे ज्ञान करवाकर आ जाते हैं। जिस अधिकारी से मैंने बात की तो वे कहते हैं, हमने सब सही किया है। ठीक है सही किया है तो कोई दिक्कत नहीं है, कुछ दिन बाद में जब कोई बड़ी घटना हो जायेगी, फिर मैं आपको इस सदन के अन्दर घेरने का काम करूंगी।

आज महिलाएं सुबह उठती हैं, शाम को खाना बनाने के टाइम पर फोन करती हैं। आप लोग कहते हैं पेपर लीक, पेपर लीक, क्या आपके टाइम पर नहीं हुआ? लेकिन आप बच्चों को पढ़ने ही नहीं दोगे, बच्चों को लाइट ही नहीं दोगे तो कैसे परीक्षा देने लायक बनेंगे? आज वह अपनी पीड़ा व्यक्त करते हैं कि साहब लाइट नहीं आ रही, लाइट तो दिला दो, खाना नहीं खा पा रहे। किस तरह की पीड़ा वे व्यक्त करते हैं। हम उनकी पीड़ा को सुनकर बेहद दु:खी होते हैं। लेकिन आज आप सब लोगों को यह जानकारी है कि पिछली बार हमने फ्री लाइट देने के बाद भी ऐसी दुर्दशा इस राजस्थान की नहीं होने दी जिस तरीके से आपने बिजली की रेट और बढ़ाकर कर दी।

आपकी शुरूआत जिस तरीके से अंधेरे से हुई है, आने वाले समय में आप देख लेना यह अँधेरा कायम रहेगा चार साल तक और चार साल बाद में उजाला राजस्थान में नई सरकार करेगी। मैं कहना चाहूंगी कि जिस तरीके से आपने कहा और हमने बार-बार इस सदन में बोला लेकिन सदन के अन्दर मंत्रियों का कोई असर नहीं होता, अधिकारियों के ऊपर आपका कोई लगाम नहीं है, आपका कोई डिसिप्लिन नहीं है। आज भी आपकी वैसी की वैसी स्थिति अगर क्षेत्र के अन्दर रहती है और अधिकारी-कर्मचारी फोन नहीं उठाते तो यहां आपका कोई असर नहीं पड़ रहा। लेकिन आप सोच रहे हैं कि विपक्ष के लोगों को कमजोर कर रहे हैं। आप विपक्ष के लोगों को कमजोर नहीं कर रहे बल्कि आप खुद कमजोर हो रहे हैं, क्योंकि आप कमजोर लोग हो। मंत्रियों की नहीं चल रही, यह चीज ऐसा दर्शाता है। आप सब लोग इन चीजों को देखने की कोशिश करें।

माननीय सभापति महोदय, हम कहना चाहेंगे कि आपका इस तरह का जो रवैया है, यह आपके ऊपर ही भारी पड़ेगा और याद रखना चार साल बाद आप जनता के बीच में जाओगे तो यह आप लोगों को झेलना पड़ेगा। माननीय सभापति महोदय, इस सदन में आपके माध्यम से मैं बताना चाहूंगी कि मेरे विधान सभा क्षेत्र के अन्दर मैंने पांच साल काफी कोशिश की और आप उठाकर देख लीजिये कि मैंने क्या-क्या किया और आप लोगों को यह बताना चाहूंगी कि लाइनमैनों के नीचे जो हैल्पर लगाते हैं, उनकी ऐसी दुर्दशा हो रही है, वे चिपक जाते हैं, कोई मर जाता है, कोई अपाहिज हो जाता है और इस तरीके का वह दंश झेल रहे हैं तो इनके बारे में भी जांच करने की आवश्यकता है और आपको देखने की आवश्यकता है। बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री शत्रुघन गौतम (अनुपस्थित)। श्री श्रीचन्द कृपलानी।

श्री श्रीचन्द कृपलानी (निम्बाहेड़ा): मेरी बात सुनो, मैं बहुत तैयारी करके आया था, लेकिन समय बहुत कम है।

श्री सभापतिः प्लीज आप स्टार्ट करें।

श्री श्रीचन्द कृपलानी (निम्बाहेड़ा): मैं एक बात कह रहा हूं, पहले सुन लो। एक डायलॉग लिखकर लाया हूं, सुनो मेरी बात।

बिजली सारी बेच दी गहलोत की सरकार ने
जनता की तुमने ना सुनी हर घर था जब अंधकार में,
कभी कोयला कम न था, बिजली के बाजार में,
कांग्रेसी थोड़ी शर्म करो क्यों लूटा भ्रष्टाचार में।।`

अच्छा मुझे तो जूली साहब, दो चीजों का जवाब दे दो..(व्यवधान).. हाकिम जी, बैठो। आपके हाथ जोड़ लूं, बैठो। आपके पैर पड़ जाऊं, बैठो। ..(व्यवधान).. और व्यवस्था करूं। जूली साहब, मुझे तो आप एक बात बता दो कि कांग्रेस के टाइम में दो बिजली मंत्री थे आपके। बी.डी.कल्ला साहब और भँवर सिंह जी भाटी, अच्छी व्यवस्था थी तो दोनों कहां हैं वे? हैं क्या यहां सदन में? दोनों ही नहीं आये। मुझे अब बताओ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष डोटासरा जी, रोज बिजली, पानी, इस पर बोलो, उस पर बोलो। आज वे कहां गये? आज जो मुख्य समस्या है, आप चिल्ला रहे हो न, आपके अध्यक्ष नहीं हैं यहां पर, शर्म आनी चाहिये आपको। आपका अध्यक्ष गायब है यहां से। राजस्थान की विपक्षी पार्टी के नेता, जूली साहब को मैं धन्यवाद देता हूं फिर भी वे यहां पर बैठे हैं। ..(व्यवधान).. पार्टी अध्यक्ष हैं तो क्या नहीं बैठना चाहिये? जो रोज-रोज समस्याओं के बारे में बात करते थे कि बिजली की समस्या हो रही है, आज कहां गयी समस्या? वह धारीवाल जी, दो मिनट बोलकर चले गये रेस्ट करने के लिये। ..(व्यवधान)..

श्री सभापतिः प्लीज इधर से कोई डिस्टर्ब नहीं किया। प्लीज सदस्य, आप आसन को सम्बोधित करें।

श्री श्रीचन्द कृपलानी (निम्बाहेड़ा): मेरी बात सुनो आप। ..(व्यवधान).. आप सुनना। आपको ही कर रहा हूं मेरे काकाजी। मेरी बात सुनो आप। आजादी के बाद आपको सहन नहीं हो रहा है। फूलसिंहजी आप हंसाओ मत। ..(व्यवधान).. माननीय सभापति महोदय, आजादी के 75 साल में 50 साल तक, जूली साहब, आपने राज किया, ठीक है। आपने राज किया बार-बार, वह जीवाराम जी कहां गये, वे सही कह रहे थे। लेकिन मैं उस बात को दोहराऊंगा नहीं। आपने गहलोत के पांच साल के राज में आप बार-बार कह रहे हो न, ट्रांसफार्मर नहीं हैं, लाइन नहीं है, पोल नहीं हैं, भजनलाल जी पर आरोप लगा रहे हो, हीरालाल जी पर आरोप लगा रहे हो, शर्म आनी चाहिये तुम्हें, डूब मरो। आपने कनेक्शन, डिमांड के पैसे जमा कराये चार साल पहले, लोग रोते फिर रहे हैं, गांव-गांव में रोते फिर रहे हैं, लोग रोते फिर रहे हैं। चार साल हो गये पैसे जमा कराये हुये। फिर भी ..(व्यवधान).. जो बिजली की समस्या है न ..(व्यवधान)..

श्री सभापतिः आप सुनो न। ..(व्यवधान).. आप सुनने का भी माद्दा रखो। ..(व्यवधान).. माननीय सदस्य ..(व्यवधान)..

श्री श्रीचन्द कृपलानी (निम्बाहेड़ा): माननीय सभापति महोदय, यह जो बिजली की समस्या पैदा हुई, मैं मानता हूं थोड़ी बहुत बिजली की समस्या है। लेकिन वह समस्या पैदा हुई ..(व्यवधान).. बात तो सुन लो।

श्री सभापति: आप उधर देखो ही मत। ..(व्यवधान)..

श्री श्रीचन्द कृपलानी (निम्बाहेड़ा): बोलने की नहीं दे रहे, यह क्या बात हुई?

श्री सभापति: फिर आप बोलोगे तो वे भी नहीं बोलने देंगे, क्या मतलब है? ..(व्यवधान)..

श्री श्रीचन्द कृपलानी (निम्बाहेड़ा): यह बिजली की समस्या पैदा हुई न.. ..(व्यवधान)..

Jyg/rtm/020824/21.30/4q

श्री सभापति: आपके सदस्य उधर इशारा कर-करके बोल रहे थे, इन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। ..(व्यवधान).. अभी क्यों कर रहे हो आप? ..(व्यवधान).. प्लीज, सहयोग करें। ..(व्यवधान)..

श्री श्रीचन्द कृपलानी (निम्बाहेड़ा): आपके मुख्य मंत्री गहलोत साहब से पूछो कि क्या एग्रीमेंट किए थे उन्होंने, आज हम पर आरोप लगा रहे हो। यदि उन्होंने सही एग्रीमेंट किए होते तो यहां पर बिजली की समस्या नहीं रहती। ..(व्यवधान).. वीसीआर लागू करो आप, आरोप हमारे पर, ..(व्यवधान).. आप बताओ दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना में 5 सालों में एक रुपया खर्च नहीं किया कांग्रेस के राज में, एक रुपया खर्च नहीं किया आपने, ..(व्यवधान).. सौभाग्य योजना, कुसुम योजना। कुसुम योजना में वर्ष 2019-20 में जब हमारा राज था, 918 करोड़ रुपये का बजट था माननीय सभापति महोदय, 2023 में 1.83 रुपये था, क्या खर्च किया? ..(व्यवधान)..

माननीय सभापति महोदय, मेरा आपसे यह निवेदन है कि यह समस्या पैदा क्यों हुई? अभी धारीवालजी कह रहे थे कि एमडी नहीं लगाया आपने, आपके राज के जितने एमडी है न, जूली साहब, उनकी लिस्ट लाओ, सबसे मंथली लेते थे आपके मंत्री और भ्रष्टाचार का आरोप मैं लगा रहा हूं साफ, आप लिस्ट लाओ, इस राजस्थान का मीडिया और अख़बार भरे पड़े हैं। ..(व्यवधान).. आप एमडी की बात कर रहे हो कि हमने एमडी नहीं लगाया।

श्री सभापति: प्लीज समाप्त करें।

श्री सोहन लाल नायक।

श्री श्रीचन्द कृपलानी (निम्बाहेड़ा): पूर्व एमडीज की आप व्यवस्था नहीं कर पाए। पांच साल में ..(व्यवधान)..

श्री सोहन लाल नायक (रायसिंहनगर): माननीय सभापति महोदय, आज महत्वपूर्ण चर्चा जो बिजली पर हो रही है, इस पर आपने मुझे बोलने का टाइम दिया, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। ..(व्यवधान)..

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से निवेदन

करूंगा कि हमारे क्षेत्र के अन्दर 40 हजार उपभोक्ता हैं, रायसिंहनगर उप खण्ड क्षेत्र के अन्दर, मेरा आपके माध्यम से निवेदन है कि इस सरकार के अन्दर दो प्रकार की व्यवस्था कर रखी है। ग्रामीण और शहरी, हम शहरियों का विरोध नहीं करते लेकिन ग्रामीण वाले यह भी चाहते हैं कि हमें भी बराबर की बिजली मिलनी चाहिए। मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि मेरे उप खण्ड रायसिंहनगर के अन्दर 40 हजार उपभोक्ता हैं और एक एईएन ऑफिस है, मंत्री महोदय से आपके माध्यम से निवेदन करूंगा कि वहां दो एईएन ऑफिस खोले जाएं, एक ग्रामीण और दूसरा शहरी। जिससे क्षेत्र के उपभोक्ताओं को राहत मिले।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से यह भी निवेदन करूंगा कि बिजली का सिस्टम बहुत पुराना है। आज भी गांवों के अन्दर लोहे के खम्भे लगे हुए हैं और तारें बहुत ढीली हैं। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि उस सिस्टम को सुधारा जाए।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि एमएलए लेड के अन्दर जो नोर्म्स बना रखे हैं पांच ढाणियों का इसको कम करके तीन ढाणियों का किया जाए, जिससे दूर दराज की ढाणियां हैं उनमें रहने वाले लोगों को फायदा दे सकें।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे क्षेत्र के अन्दर एलडी कट के नाम पर और 220 केवी सूरतगढ़-पदमपुर ओवर लोड के नाम से दो-दो कट लग रहे हैं, जिसमें चार-चार, पांच-पांच घण्टे बिजली गुल रहती है। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि ये दो कट न लगे, चाहे एलडी कट लगे चाहे ओवर लोड का कट लगे, एक ही कट लगे। इससे हमारे क्षेत्र के लोगों को ज्यादा परेशान न किया जाए। शहर के अन्दर, ढाणियों में और गांव में एलटी लाइन की एबी केबल खराब हैं जिससे आए दिन हादसे होते रहते हैं। उनको बदलने की व्यवस्था की जाए।

माननीय सभापति महोदय, मैं ज्यादा न कहते हुए, अभी कृपलानीजी कह रहे थे कि हमारे जीवारामजी बोल रहे हैं। जीवारामजी की स्थिति तो यह है, माननीय सभापति महोदय, हमारे शादी के अन्दर आदमी जाता है तो उससे पूछते हैं कि बाराती हैं क्या या घराती हैं क्या, कोई कहता है कि मैं तो खामखां हूं। वो यह कहता है कि मैं ना बाराती हूं ना घराती हूं मैं तो खामखां हूं तो वो तो खामखां हैं। जो बीच में आकर दोनों तरफ की बात करते हैं।

माननीय सभापति महोदय, मेरे दो सदस्यों ने यह कहा, मेरे सत्ता पक्ष के ..(व्यवधान)..

श्री श्रीचन्द कृपलानी (निम्बाहेड़ा): जो माननीय सदस्य जनता के वोटों से जीतकर आया है, उनके लिए कह रहे हैं, शर्म आनी चाहिए इनको। वो खामखां हैं?

श्री सोहन लाल नायक (रायसिंहनगर): आपने भी तो जीवारामजी का नाम लिया था।

श्री श्रीचन्द कृपलानी (निम्बाहेड़ा): यूनुस जी, सब निर्दलीय खडे हों, जीवारामजी को खामखां कैसे कह दिया इन्होंने? ..(व्यवधान).. आप भी खड़े हों, यह क्या बात हुई? ..(व्यवधान)..

श्री सोहन लाल नायक (रायसिंहनगर): माननीय सभापति महोदय, मैं आपसे निवेदन

करूंगा ..(व्यवधान).. हमारे सत्ता पक्ष के साथियों ने कहा 50 साल, 47 साल, तो मैं यह कहना चाहता हूं। ..(व्यवधान)..

श्री अविनाश गहलोत (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, ये हमारे माननीय सदस्य के बारे में कह रहे हैं, कल वो आकर हिसाब लेंगे। ..(व्यवधान).. कल वो आएंगे, आपसे हिसाब लेंगे। ..(व्यवधान).. आपसे ऐसी कैसी बात की है?

श्री सभापति: श्री मनोज कुमार।

..(व्यवधान).. और का अंकित नहीं होगा।

श्री अविनाश गहलोत (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री): 000

श्री श्रीचन्द कृपलानी (निम्बाहेड़ा): 000

श्री सोहन लाल नायक (रायसिंहनगर): 000

श्री मनोज कुमार (सादुलपुर): माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, उसके लिए मैं आपका आभारी हूं। सबसे पहले मैं मंत्री महोदय का इस बात के लिए धन्यवाद जरूर करूंगा कि इन्होंने बिजली की बात पर चिंता जरूर की है कि वास्तव में राजस्थान में बिजली नहीं मिल रही है। बिजली की हमारे पास कमी है, बिजली का उत्पादन हमारे पास प्रोपर नहीं है। इसलिए माननीय मंत्री महोदय ने हम सब विधायकों को अपनेजोन वाइज बुलाकर चर्चा की। लेकिन माननीय सभापति महोदय, मैं माननीय मंत्रीजी से इतना जरूर कहूंगा कि बिजली का उत्पादन चाहे भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो चाहे कांग्रेस की सरकार की बात हो, वास्तविकता में यह है कि हमारे राजस्थान की जनता बिजली की कमी से परेशान है। इससे बड़ी परेशानी कोई हो नहीं सकती। इसके लिए हम सब 200 लोग, चाहें हम आरोप किसी पर भी लगाएं, चाहे मैनेजमेंट के कुप्रबंधन की बात करें, चाहे भ्रष्टाचार की बात करें, लेकिन उससे राजस्थान के आम नागरिक को, आम जनता को इस बात से कोई लेना-देना नहीं है, उनको सिर्फ बिजली और पानी की आवश्यकता है और वो चीज उनको मिलनी चाहिए।

माननीय सभापति महोदय, मैं बिजली की कमी के साथ ही एक बात और कहना चाहता हूं कि आपके पास, उत्पादन बड़े लेवल के ऊपर बड़ी मुश्किल से होगा, बड़ा समय लगेगा, लेकिन आप पीएम सूर्य योजना की जो घोषणा की है, इसको कैम्प लगाकर घर-घर जल्दी पहुंचा दीजिए, गांव मैं बैठे हुए व्यक्ति के लिए बिजली का उत्पादन भी हो जाएगा, तुरंत हो जाएगा और उनकी समस्याओं का समाधान हो जाएगा।

माननीय सभापति महोदय, इसके साथ मैं दो-तीन और निवेदन माननीय मंत्री महोदय से करना चाहता हूं। आपका क्वालिटी कण्ट्रोल, आपकी जो रोजाना की टैक्निकल समस्याएं हैं, पोल में, कैबल में, ट्रांसफार्मर में, मीटर में, ये आपके विद्युत भवन में बैठने वाले अधिकारी इन क्वालिटी कण्ट्रोल में भारी गड़बड़ करते हैं, इस कारण रोजाना वहां छीजत होती है, रोजाना वहां पोल टूटते हैं, कैबल जलती है, उस पर आप बहुत बड़ा ध्यान करें। माननीय

सभापति महोदय, आपके स्टोर्स चाहे विद्युत विभाग के जयपुर से लेकर आखिरी एईएन, जेईएन के ऑफिस तक, इन स्टोर्स की ऑडिट करवा लीजिए, इनमें भारी गम्भीर अनियमिताएं मिलेंगी। तीसरी बात मैं यह कह रहा था कि टेंडर की प्रक्रिया के बारे में जिस दिन आपसे मीटिंग थी, उसमें मेरी बात हो रही थी कि ट्रांसफार्मर एक महीना और लगेगा, अभी तक टेस्टिंग में लगेगा, टेंडर की प्रक्रिया में समय लगेगा, ये जो अधिकारी जयपुर में हमारे बैठे हैं, इनको टेंडर की प्रक्रिया समय से तीन महीने पहले शुरू कर देनी चाहिए और जो समय हो उससे पहले टेंडर हो जाए और उसकी क्वालिटी कण्ट्रोल और जांच हो जाए, जिससे उपभोक्ता को उस देरी का भुगतान नहीं करना पड़े।

माननीय सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जो व्यक्तिगत सेल्फ फाइनेंस में जो कनेक्शन लेते हैं, पिछले 5 वर्ष में सेल्फ फाइनेंस के एईएन ऑफिसों की जांच करवा लीजिए, पैसा उपभोक्ता ने दिया माल और सामान टोटल विद्युत विभाग का लगा, उन ठेकेदारों ने और उन ऑफिसों ने मिलकर आपके उस सामान को गड़बड़ करने का काम किया है। इसके साथ ही मेरी दो मांग माननीय मंत्रीजी से करना चाहता हूं कि एक तो मेरा 220 केवी का जीएसएस है, उसके लिए आपसे दो बार चर्चा हो भी चुकी है। आप उसको तुरंत प्रभाव से लगाने का काम करें। एक मेरा सिद्धमुख और चांदगोठी में जेईएन ऑफिस है, उन दोनों को एईएन ऑफिस में क्रमोन्नत करने का आप काम करें। दो चीज मैं आपके ठेकेदारों की बताना चाहूंगा। आपका आरडीएसएस टेंडर टीएन 639 मैसर्स ईश्वर मैटल इंडस्ट्री, मैसर्स भारत निर्माण इंफ्रांस्ट्रक्चर कम्पनी जोधपुर द्वारा 165 करोड़ का कार्यादेश गलत अनुभव प्रमाण पत्र के आधार पर ले रखा है, उन अधिकारियों ने आज तक न तो टेंडर निरस्त किया है, वहां उन अधिकारियों ने मिलीभगत करके आज भी वहां वो कार्य चल रहा है माननीय मंत्री महोदय, आप गम्भीरता से इस सब्जेक्ट को लिखें, नोट करें और इसकी जांच कराएं।

दूसरा मैं कहता हूं कि आरटीपीपी रूल 2013 के रूल नम्बर 73 में वर्णित है कि ऑरिजनल कोंट्रेक्ट के स्कॉप में बिना कोई परिवर्तन किए किसी इंडिविजुअल आइटम की मात्रा में कोंट्रेक्ट वैल्यु में निर्धारित सीमा तक ही नियमानुसार परिवर्तन किया जा सकता है।

MLS/RTM/02.08.2024/21:40/5a

श्री सभापतिः श्री विद्याधर सिंह।

श्री मनोज कुमार (सादुलपुर): इसके उपरान्त भी आरडीएसएस के 13 सर्किल में 2682...

श्री सभापतिः अंकित नहीं होगा।

श्री मनोज कुमार (सादुलपुर): 000

श्री विद्याधर सिंह (फुलेरा): सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, उसके लिए धन्यवाद।

श्री मनोज कुमार (सादुलपुर): 000

श्री सभापतिः अंकित नहीं होगा।

श्री मनोज कुमार (सादुलपुर): 000

श्री सभापतिः आपका समय चालू है विद्याधर सिंह जी।

श्री विद्याधर सिंह (फुलेरा): पूर्व बिजली मंत्री जी यह कह रहे थे कि इतना घाटा दिया, हमने इतने फायदे में छोड़ा, भाई, आप एक तरफ तो विकसित भारत की बात कर रह हैं, मोदी जी कह रहे हैं, विकसित भारत बनाऊंगा और एक तरफ कह रहे हैं, बिजली-पानी में हम कमाएंगे। भाई, स्वास्थ्य की तरह हॉस्पिटलों में हम पैसा कमाते हैं क्या? मंत्री जी कह रहे थे, इतना घाटा, हम इतने फायदे में थे, ये बिजली-पानी सरकार का काम है देने का। इसमें घाटा-नफा नहीं। आज हालात क्या हो गये हैं, मैं बता रहा हूं, फुलेरा के हालात ये हैं, मंत्री जी, सुनिये, तीन-तीन दिनों तक फुलेरा में लाइटें नहीं आती हैं।

शाकम्भरी का एरिया पिछड़ा हुआ एरिया है। वहां पांच-पांच, दस-दस दिन तक ट्रांसफॉर्मर जल जाएं, कोई पूछने वाला नहीं है। मैं तो इतना भी कहूंगा, परसों रात की बात है, मैं सांगानेर में रहता हूं, मुख्य मंत्री जी सांगानेर से चुनकर आते हैं, रात को साढ़े 10 बजे लाइट गयी थी और सुबह 5 बजे तक लाइट नहीं आयी थी। मंत्री जी बता दें, अपना वक्तव्य दे दें अगर मैं गलत कह रहा हूं तो। दूसरी बात, देखिये क्या है, आप लोग और हम यहां बैठे हैं, बहुत अच्छी बात है। हम यहां बैठकर एक-दूसरे की बुराई कर रहे हैं। इससे कोई फायदा नहीं होने वाला, कोई फायदा नहीं होने वाला। जनता हमें देख रही है।

हम बात कर रहे हैं कि हमारा बिजली तंत्र कैसे सुधरे। हाकिम जी कह रहे थे, अभी बीच में तो दो ही अधिकारी रह गये थे और तीसरे भी उठकर चले गये थे। कहने का मतलब, जब तक आप इन अधिकारियों पर लगाम नहीं लगाएंगे, व्यवस्था में सुधार नहीं होगा। दूसरी बात, आज व्यवस्था ऐसी हो गयी है, जैसे आपदा हुई थी न, अन्तरराष्ट्रीय आपदा कोरोना, आज तीन-चार महीने से, कोरोना में तो लोग चले गये थे, शर्त इतनी हो रही है, बात इतनी है कि बिजली के कारण हमारे यहां मरे नहीं, लेकिन बाकी बचा भी नहीं। यानी सुबह से शाम, रात को महिलाएं गालियां दे रही हैं, बच्चे गालियां दे रहे हैं कि हम कहां से पढ़ें। और आप विकसित भारत की बात कर रहे हैं।

देखिये, जो वैलफेयर स्टेट होता है, उसमें विकसित भारत तब होगा, जैसे आप स्वास्थ्य का मामला है, फ्री दे रहे हैं, हॉस्पिटल में कमाई थोड़ी कर रहे हैं, ऐसे ही बिजली फ्री देंगे। ऐसे ही पानी फ्री देंगे। **(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)** अभी मंत्री जी कह रहे थे, डूब मरो। कौन कह रहे थे, हां, कृपलानी जी। कहां डूब मरें? कौन-से तालाब में? पानी है ही नहीं आपके पास। आप बताएं न कहां जाएं? उसमें ही हम डूब मरें। बात तो बड़ी-बड़ी करते हैं, मैं तो एक ही बात कहता हूं, यह गम्भीर विषय है, आप गांवों में जाना, हमने खोये हैं अपने आदमी, यहां 125 थे। कितने रह गये? 70 रह गये। क्यों रह गये? क्योंकि आपकी तरह बड़बोलेपन और बढ़ाई के भूखे और घमण्ड में आ गये।

नतीजा यह हुआ कि 70 पर आ गये। अबकी बार आप तो 55 के ऊपर भी नहीं जाएंगे।

55 के ऊपर, यह जिम्मेदारी है। मेरी जिम्मेदारी है। आप देख लेना गिनकर जब अगली बार आओ। अब जाना गांवों में, गांव आपका स्वागत करेगा बिजली और पानी के मुद्दे पर।

श्री सभापतिः सुश्री नौक्षम चौधरी जी।

श्री विद्याधर सिंह (फुलेरा): दो ही मुद्दे हैं। दो ही मुद्दे हैं, बिजली और पानी। देख लेना...

श्री सभापतिः अंकित नहीं होगा।

श्री विद्याधर सिंह (फुलेरा): 000

सुश्री नौक्षम (कामां): मैं आपको जवाब देने जा रही हूं। माननीय सभापति महोदय, **जो वतन का नहीं है, उसकी हिमायत छोड़ दें,**

जो वतन का नहीं है, उसकी हिमायत छोड़ दें,
जो मुकद्दर में नहीं है, अब उसकी चाहत छोड़ दें।
मुफ़लिसों की आपको न परवाह है न फिकर,

अगर आपको मुफलिसों की परवाह होती तो आप दोबारा यहां बैठकर राज कर रहे होते, वहां बैठकर हमें इतने ज्ञान और सुझाव न दे रहे होते।

मुफ़लिसों की आपको न परवाह है न फिकर,
इसलिए मशविरा अब यह है कि अब सियासत छोड़ दें।

हम आपको विकसित भारत भी लाकर देंगे और ऊपर वाले ने जिन्दगी दी तो आपको विकसित राजस्थान भी लाकर देंगे। इसकी परवाह मत कीजिये आप। ...(व्यवधान)... विकसित प्रदेश तो देखेंगे।

माननीय सभापति महोदय, सुबह से चर्चा चल रही है। पहले तो मैं माननीय मुख्य मंत्री जी का, आपका, माननीय मंत्री जी का बहुत-बहुत धन्यवाद करना चाहती हूं, शुक्रिया अदा करना चाहती हूं कि जो इतनी महत्त्वपूर्ण हमारे जीवन की मूल धारा है, उसे आपने पूरा एक दिन दिया है और पूरे सत्तापक्ष और विपक्ष को पूरा अवसर प्रदान किया है, पर जो मौका दिख रहा है यहां पर कि आपस के कटाक्ष में हम यह भूल गये हैं कि हम आपस की नाराजगी छोड़कर बिजली की मूलभूत समस्या पर चलें, उस पर एक-दूसरे को सुझाव दें।

जब आप लोग राज कर रहे थे, कामां क्षेत्र की बात करें, जहां से मैं आती हूं, ग्रामीण क्षेत्र है, अति पिछड़ा क्षेत्र है तो 20 हजार से लेकर 40 हजार रुपये में ट्रांसफॉर्मर मिलता था। एक गरीब आदमी, ग्रामीण क्षेत्र से आने वाले व्यक्ति को 40 हजार रुपये अपने घर में टंकी लगाने के लिए देने पड़ रहे हैं, उसका नतीजा यह है कि आज आप हमें वहां बैठकर सुझाव दे रहे हैं और हम आपकी बात सुन रहे हैं। यह वह सरकार है, मैं माननीय मंत्री जी का धन्यवाद करना चाहती हूं कि जब प्रदेश में यह बात चली कि आज बिजली की समस्या आ रही है, वे प्रत्येक विभाग, प्रत्येक जिले में गये और उन्होंने सत्तापक्ष और विपक्ष के सभी विधायकों को बुलाया।

तभी भी नहीं, जब विधान सभा चल रही थी, तब भी सारे विभागों को एक साथ एकत्रित किया कि आप अपनी सबसे महत्त्वपूर्ण डिमांड यानी बिजली पर अपने सुझाव दीजिये और

बताइये। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से यह भी बताना चाहती हूं कि बहुत पिछड़ा क्षेत्र होने की वजह से कामां में 132 केवी का जीएसएस है, जिसे मैं 220 केवी में तब्दील करने के लिए आपके माध्यम से मंत्री जी से निवेदन करना चाहती हूं।

मंत्री जी, मैं माननीय सभापति महोदय के माध्यम से आपके सामने एक और अपनी मांग रखना चाहती हूं कि जो अधिकारीगण हैं, भ्रष्ट अधिकारीगण गत सरकार के लगे हुए हैं, एक्सईएन और जेईएन, उनका आप तबादला करें ताकि मूल रूप से जो कामां की बिजली की समस्या है, जो ये भ्रष्ट अधिकारी गत सरकार ने लगाये हुए थे, उनका तबादला हो सके और पूरे कामां क्षेत्र को बिजली मिल सके। मेरा आपसे यह निवेदन है। जुरहेड़ा में 40 साल पुरानी लाइनें हैं और वे तब की हैं जब वहां जनसंख्या 3000 थी। माननीय सभापति महोदय, आज की जुरहेड़ा की जनसंख्या 30000 है, ओवरलोड हो रहा है, मैं आपके माध्यम से वहां पर अलग से 132 केवी के जीएसएस की डिमांड करती हूं। **(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)**

नगरपालिका की जितनी भी समस्त लाइनें हैं, वे टूट चुकी हैं। जितनी भी ओवरलोड की हमारी हाई टैंशन की वोल्टेज लाइनें हैं, उनको भी बदला जाये, यह मैं आपके माध्यम से मांग रखती हूं।

श्री सभापतिः श्री डूंगरराम जी गेदर।

श्री डूंगरराम गेदर (सूरतगढ़): अध्यक्ष महोदय, धन्यवाद, आपने मुझे बोलने का समय दिया। मैं आपके माध्यम से ऊर्जा मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि एक तो जो एफआरटी टीम है, उसकी ड्यूटी, टाइम, उनके नाम और मोबाइल नम्बर सार्वजनिक किये जाएं ताकि कोई उन्हें मोबाइल कर सके, क्योंकि टोल फ्री नम्बर जो आपने दिया है, वह लग नहीं रहा है और उनसे बात होती नहीं है। दूसरा, सूरतगढ़ में विभिन्न मांगों को लेकर कर्मचारी काफी दिनों से हड़ताल पर हैं। उस दिन जब अपनी बातचीत हुई थी, उस दिन भी आपसे कहा था, लेकिन आज तक वे हड़ताल पर हैं। उनकी मांगों को माना जाये और उनकी समस्या का समाधान किया जाये। पांच ढाणियों के जो कनेक्शंस आपने दिये हैं, वहां हमारा बिजली का नेटवर्क जा रहा है, लेकिन आज कोई छठा व्यक्ति वहां ढाणी में कनेक्शन मांग रहा है तो उसे विभाग कनेक्शन नहीं देता है कि हमारा लोड बढ़ाना पड़ेगा।

जब गांवों में इस तरह से हम लोग कनेक्शन दे रहे हैं तो फिर ढाणियों में भी भले ही छठा हो, सातवां हो, आठवां हो, ये कनेक्शन देने के भी आदेश आप लोग यहां से जारी करें।

mkd/rtm/02.08.2024/21.50/5b

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि पूरे प्रदेश के अन्दर किसी भी विभाग का कर्मचारी हो, अभियन्ता हो, उसका कहीं भी ट्रांसफर हो सकता है, लेकिन बिजली विभाग के अन्दर जो पांच कम्पनियां हैं, उन कम्पनियों में आपस में कर्मचारियों के, अभियन्ताओं के ट्रांसफर नहीं हो रहे हैं तो इनको भी, ये राजस्थान के ही हैं, उनके ट्रांसफर करने के लिए, एक से दूसरे डिस्कॉम में ट्रांसफर करने का काम खोला जावे।

विद्युत विभाग के जो कर्मचारी और अभियन्ता हैं, वे बहुत ही हार्ड ड्यूटी करते हैं। पिछले दिनों जब से लाइट की समस्या आ रही है, उनको 24 घंटे काम करना पड़ता है, इसलिए इनको हार्ड ड्यूटी अलाउंस देने का काम किया जाये। ओपीएस स्कीम के अन्दर आपने जीपीएफ खाता आवंटित कर दिया है, लेकिन जीपीएफ की कटौती अभी तक हो नहीं रही है, यह भी किया जाये।

सूरतगढ़ विधान सभा क्षेत्र के अन्दर राजियासर में एईएन ऑफिस खोला जाये, ताकि वहां काम का बंटवारा हो सके और वे लोग अच्छी तरह से काम कर सकें। पूरे क्षेत्र में जगह-जगह खम्भे जर्जर हो गये हैं, एलटी लाइन नहीं है, एलटी लाइन नहीं होने की वजह से ये बहुत ज्यादा फॉल्ट हो रहे हैं। एलटी लाइन बदली जाये और जगह-जगह जो खम्भे जर्जर हैं, उनकी हालत सुधारी जाये।

मैं आपके माध्यम से यह भी कहना चाहता हूं कि जनवरी में इसी सदन के अन्दर प्रश्न के जवाब में आपने जवाब दिया कि रतासर, भोपालपुरा का जीएसएस कार्य प्रगति पर है, शीघ्र पूरा होने वाला है, लेकिन मैं आपके माध्यम से सभापति महोदय कहना चाहता हूं कि आज तक वहां एक भी ईंट नहीं गिरी है, कोई काम चालू नहीं हुआ है। उस टाइम भले ही हम लोग कितने भी, 100 रुपये यूनिट बिजली खरीद रहे थे, लेकिन किसानों को 6 घंटे बिजली दे रहे थे।

आज आप कितने ही रुपये की बिजली खरीदो, यह कोई पूछने वाला नहीं है, लेकिन हम दो या तीन घंटे ही बिजली दे पा रहे हैं। किसानों की जो बिजली की कटौती हो रही है, उस कटौती को दूसरे दिन हम लोग नहीं दे पा रहे हैं। यह काम भी हम लोगों को आज करने की जरूरत है। जो मीटर खराब हैं, खराब मीटर की वजह से एवरेज बिल आता है और एवरेज बिल की वजह से जो 100 यूनिट फ्री का लाभ उन किसानों को और ग्रामीणों को मिलना चाहिए, वह नहीं मिलता है। इसलिए सारे के सारे मीटर चैंज किये जाये। आपने बोलने का समय दिया, धन्यवाद।

श्री सभापति: लादुलाल पितलिया।

श्री लादु लाल पितलिया (सहाड़ा): जय श्री श्याम की जय। माननीय सभापति महोदय, बिजली के ऊपर बोलने के लिए मुझे मौका दिया, उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। मेरे विधान सभा क्षेत्र सहाड़ा, जिला भीलवाड़ा में बिजली की बहुत भारी समस्या है। शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत कटौती की जा रही है। बरसात का समय है। शाम के समय जब महिलाओं को रसोई का काम होता है, तब बिजली कटौती कर दी जाती है। तब मेरे क्षेत्र से बहुत कार्यकर्ताओं के फोन आते हैं।

गंगापुर नगरपालिका के अन्तर्गत विद्युत तंत्र को विकसित करने हेतु 11 केवी एवं एलटी लाइनों को अंडरग्राउंड किया जाये। रायपुर कोसीथल में सामान्य श्रेणी के 850 कृषि कनेक्शनों की डिमांड जमा है, लेकिन सामान के अभाव से नये कनेक्शन नहीं किये जा रहे हैं। सभी किसानों के विद्युत कनेक्शन चालू करवाने का श्रम करावें।

माननीय सभापति महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र में गंगापुर और रायपुर में 132 केवी जीएसएस स्थित है और देवरिया में 33 केवी फीडर पर चार 33 केवी जीएसएस जुड़े हुए हैं। जिनमें देवरिया अन्तिम छोर पर स्थित है तथा कोसीथल में 33 केवी जीएसएस पर भी चार फीडर जुड़े हुए हैं। रायपुर में 200 केवी जेएसएस में दो साल से काम अधूरा पडा है, केवल चारों तरफ बाउंड्री हो रखी है।

माननीय मंत्री महोदय जी से निवेदन है कि इसे जल्दी पूरा करावें, ताकि आम जनता को लाभ मिल सके। रबी के सीजन में ओवरलोड और कम वोल्टेज की समस्या बहुत रहती है।

मेरे विधान सभा क्षेत्र के बाड़ी, जो करेड़ा ग्रिड से जुड़ा है, उसको रायपुर ग्रिड से जोड़ने पर कुछ वोल्टेज की समस्या से निजात मिल सकती है। डेली कार्यकर्ताओं का फोन आ रहा है। वोल्टेज की समस्या को पूर्ण से खत्म करने के लिए कुछ जीएसएस बनाने की आवश्यकता है। बरड़ौद सुवाणा में 33 केवी जीएसएस, सांगवा में 33 केवी जीएसएस, गूंदली में 33 केवी जीएसएस, पालरा में 33 केवी जीएसएस, सातल्यास में 33 केवी जीएसएस, रालीखेड़ा में 33 केवी जीएसएस, बांगपुरा राम खेड़ा में औद्योगिक क्षेत्र के विकास हेतु 33 केवी जीएसएस और नेगडिया खेडा, सहाड़ा में 33 केवी जीएसएस आदि जीएसएस स्वीकृत करके वोल्टेज समस्या हल हो सकती है।

अतः आपसे अनुरोध है कि 33 केवी जीएसएस स्वीकृत कराने का श्रम करें। रायपुर में बटोर में 33 केवी जीएसएस ग्रिड स्वीकृत है, इसका कार्य आरडीएसएस में होना है, इसका काम जल्दी शुरू किया जाये।

माननीय, मेरे विधान सभा क्षेत्र में हमीरगढ़ में सहायक अभियन्ता, अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड कार्यालय खोलने की आवश्यकता है, बिजली की पूर्ण समस्या की पुख्ता व्यवस्था करने के लिए अधिकारियों को निर्देशित करावें, आमजन को राहत मिल सके।

हमारे उधर किसानों की डीपी चोरी होती है, वे थाने में जाते हैं, उसके बाद में वे रिपोर्ट लिखते हैं। हमारे भाई साहब, जो पड़ोसी बेगूं वाले बोले सुरेश जी, 10 लेटर लिखने पढ़ते हैं, 10 किसानों के चोरी होगी, तब मिलेगा। तब तक पहले वाले किसान के तो तीन-चार महीने लग जाते हैं। उनकी फसल ही खराब हो जाती है तो माननीय मंत्री महोदय से निवेदन है कि जल्दी से जल्दी से नियम से थोड़ा छुटकारा दें।

इस समय सहाड़ा विधान सभा क्षेत्र के लिए शानदार बजट दिया, माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने, इसके लिए भी बहुत-बहुत धन्यवाद। जय श्रीराम, वन्दे, गो-मातरम।

श्री सभापति: श्रीमती रमीला खड़ीया।

श्रीमती रमीला खड़ीया (कुशलगढ़): सभापति महोदय, मुझे आज बिजली के ऊपर बोलने का अवसर दिया, आपको बहुत-बहुत धन्यवाद।

सभापति महोदय, आज जिसके ऊपर चर्चा हो रही है, यह बहुत गम्भीर समस्या है। सभापति महोदय, आज मेरे विधान सभा क्षेत्र में बिजली बिलकुल नहीं है। मैं किसान की बेटी

हूं। आज किसान यह कह रहे हैं कि तार के ऊपर तो करंट नहीं आ रहा है और बिल के ऊपर करंट आ रहा है। आज हमारे राजस्थान में बिजली की समस्या है। मैं मंत्री जी को धन्यवाद देती हूं कि बिजली जैसे महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा की।

मंत्री महोदय, मैं आज यह कहना चाहती हूं कि मेरे विधान सभा क्षेत्र कुशलगढ़ में सज्जनगढ़ व कुशलगढ़ इसमें 133 केवी की आवश्यकता है। पंचायत समिति छोटी सरवा, पंचायत समिति सज्जनगढ़ में, ऐसी कई समस्याएं हैं। मंत्री महोदय जी से मैं कहना चाहती हूं कि जिस समय आप रिप्लाई दें तो कुशलगढ़ की जरूर बात करें।

सभापति महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र में ऐसे गांव हैं, जहा आज तक घरेलू कनेक्शन नहीं मिले हैं। मैं मंत्री जी से मांग करती हूं कि जो भी गांव छूटे हुए हैं, इन गांवों में कनेक्शन देने पर विचार करें। मैं गांव के नाम पढ़ना चाहती हूं।

सभापति महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र कुशलगढ़ पहाड़ी इलाका है। उसमें अलग-अलग गांव और अलग-ढाणियां बसी हुई हैं। इसलिए, आज तक उनको कनेक्शन नहीं मिले हैं। ऐसे कई गांव हैं, कोटडा, बिजोरी, नवागांव, बड़ी सरवा, लोहारिया, उमरसुखा, बस्सी इन गांवों में कनेक्शन अभी तक नहीं पहुंचे हैं।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से कहना चाहती हूं कि जरूर मेरे विधान सभा क्षेत्र की बात रखें। आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, आपको बहुत-बहुत धन्यवाद, जय हिन्द।

श्री सभापतिः श्री आदू राम जी।

श्री आदू राम मेघवाल (चौहटन): माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे लोकतंत्र के पवित्र सदन में राजस्थान प्रदेश और विधान सभा क्षेत्र चौहटन की बिजली की वर्तमान स्थिति पर बोलने का सुअवसर प्रदान किया, इसके लिए आपका मैं आभार प्रकट करता हूं।

माननीय सभापति महोदय, चौहटन विधान सभा के अन्दर, मैं धन्यवाद देना चाहूंगा हमारे यशस्वी मुख्य मंत्री जी भजनलाल जी शर्मा जी को और हमारे बिजली मंत्री हीरालाल जी नागर साहब को, जिन्होंने बाछढाऊं के अन्दर 132 केवी जीएसएस की इस बजट के अन्दर घोषणा की है।

Bhs/Rtm/02.08.24/22.00/5c

मैं इनका आभार प्रकट करता हूं और आज के इस मौक़े पर मैं हमारे राजस्थान की पूर्व मुख्य मंत्री वसुन्धरा राजे सिंधिया जी को भी याद करूंगा कि उन्होंने उस समय में हमारे बाड़मेर और जैसलमेर जिलों में जहां लोग गांव व ढाणियों में रहते हैं, दूर-दूर ढाणियां हैं उन्होंने उस समय में जो किसानों को एक तोहफा दिया, जिस समय हॉर्स पॉवर के ऊपर बिजली का कनेक्शन करके जहां डिमाण्ड तीन-तीन लाख के आते थे और उस समय 35 हजार के ऊपर डिमाण्ड राशि से किसानों को विद्युतीकरण कर कृषि कनेक्शन दिये। मैं, सभापति महोदय, आपके माध्यम से हमारे मंत्री महोदय जी को कहना चाहूंगा कि हमारे

चौहटन विधान सभा क्षेत्र में चौहटन, धनाऊ, सेड़वा और हमारा फागलिया पंचायत समिति है इनमें तीन ए.ईएन. बैठते हैं एक धनाऊ के अन्दर ए.ईएन. की पोस्ट क्रियेट की जाये और इस विधान सभा क्षेत्र के अन्दर जो एक्स.ईएन. की पोस्ट है जो हमारे गुडामालानी हमें जाना पड़ता है जहां हमारे विधान सभा क्षेत्र से डेढ़ सौ किलोमीटर दूर पड़ता है इसलिये मैं हमारे मंत्री महोदय जी से निवेदन करूंगा कि हमारे चौहटन के अन्दर एक्स.ईएन. ऑफिस खोला जाये और जिस तरह से पुरानी लाइनें जो हैं जहां वोल्टेज की समस्या रहती है ऐसी जगह 33के.वी. के जी.एस.एस. खोले जायें जिसमें हमारा तरला है, हमारा केकड़ है और ऐसे कई गांव हैं, गोड़ का तला है, बुरान का तला है ऐसे गांवों में 33 के.वी. के जी.एस.एस. खोले जायें जिससे आने वाले समय में बिजली की समस्या से निजात मिले।

(समय: बजे)

(श्री अर्जुन लाल जीनगर, सभापति, पदासीन।)

माननीय सभापति महोदय, थार की शुष्क भूमि बाड़मेर जिले में ईंधन स्रोत और कपूरड़ी जालिपा लिग्नाइट खदानों के बाड़मेर संयंत्र का संचालन राजवेस्ट लिमिटेड द्वारा किया जाता है। इस संयंत्र में 135 मेगावाट इकाइयां हैं जो 1080 मेगावाट बिजली का उत्पादन करती हैं जहां बाड़मेर में प्रतिदिन अनुमानित 85 और 90 लाख यूनिट बिजली की आवश्यकता है परन्तु आवश्यकता से भी कम बिजली मिल रही है। यदि नियमित बिजली की आपूर्ति की जाती है तो निश्चित रूप से बिजली संकट की स्थिति में सुधार किया जा सकता है।

माननीय सभापति महोदय, प्रदेश में देवी-देवताओं के मन्दिरों और धार्मिक स्थलों को घरेलू आधारित दर प्राप्त न कर कॉमर्शियल दर प्राप्त की जाती है जो अधिक महंगी और अधिक खर्चीली वाली है। ऐसे में लोकहित विषय पर उचित निर्णय किया जाना चाहिये। मन्दिरों तथा धार्मिक स्थलों में खर्च होने वाली बिजली बिल की राशि व्यावसायिक दर से न होकर घरेलू दर पर की जानी चाहिये ताकि आर्थिक नुकसान से बचा जा सके।

माननीय सभापति महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र में वर्तमान में अघोषित बिजली कटौती से आमजन को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। पर्याप्त मांग में बिजली न मिलने पर किसान भाइयों की फसलें सूखने के कगार पर हैं। बहुत से किसानों को कृषि कनेक्शन, जले हुए ट्रांसफार्मर के स्थान पर नवीन ट्रांसफार्मर एवं अन्य आवश्यक उपकरण समय पर नहीं मिल पाते हैं इसलिये माननीय ऊर्जा मंत्री महोदय जी से निवेदन रहेगा कि इस हेतु विभाग को आवश्यक दिशा-निर्देश प्रदान कर आम जनता की समस्या का समाधान करायें।

माननीय सभापति महोदय, मेरा आपसे निवेदन रहेगा कि इस वित्तीय वर्ष की बजट घोषणा में हमारे 132 के.वी. का जी.एस.एस. जो बासड़ऊ के अन्दर हुआ है, बाड़मेर जिला भारत-पाक सीमा पर स्थित है, चौहटन विधान सभा क्षेत्र की ओर से आग्रह करवाना चाहता हूं कि सीमावर्ती क्षेत्र बहुत ही अधिक विस्तृत होने के कारण विद्युत विभाग में घरेलू तथा कृषि कनेक्शनों का लोड अधिकरहता है और अन्तिम छोर पर बड़े फागलिया जो पंचायत समिति है उसमें अधिकतर एससी/एसटी के लोग निवासरत हैं। ...(व्यवधान)...

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): यह आपकी सीरियसनेस है बिजली के ऊपर तभी तो बिजली नहीं आ रही है। ध्यान ही नहीं है आप लोगों का।

श्री आदू राम मेघवाल (चौहटन): आज भी आर.डी.एस.एस. के कनेक्शन बहुत संख्या के अन्दर बाकी हैं।

श्री सभापति: माननीय सदस्य को बोलने दें, नये हैं।

श्री आदू राम मेघवाल (चौहटन): माननीय सभापति महोदय, मेरा निवेदन रहेगा कि आप यह घरेलू कनेक्शन अतिशीघ्र करवा कर आम लोगों को फायदा पहुंचायें। धन्यवाद। जय हिन्द। जय भारत।

श्री सभापति: माननीय मंत्री महोदय।

श्री हीरालाल नागर (राज्य मंत्री, ऊर्जा): माननीय अध्यक्ष महोदय, राज्य में बिजली की स्थिति पर चर्चा के लिए मैं सबसे पहले आपका आभार भी प्रकट करता हूं और यह जो समस्या आम आदमी के उपभोग से जुड़ी हुई है और इस पर सभी पक्ष और विपक्ष के सदस्यों ने बहुत महत्वपूर्ण सुझाव दिये हैं। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि सभी सदस्यों के जो भी महत्वपूर्ण सुझाव आये हैं हम उन पर गम्भीरता से विचार भी करेंगे और उनके समाधान का प्रयास भी करेंगे। यह बिजली की समस्या किसी राजनीतिक दल की समस्या नहीं है, यह पूरे प्रदेश की समस्या है और इस समस्या को हम सब मिल करके आपस में समस्या भी बतायेंगे उसका समाधान भी करेंगे और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि बिना किसी राजनीतिक भेदभाव के और क्षेत्र में हम बिजली की समस्या के समाधान के लिए जो भी काम होगा इस विभाग में वो हर क्षेत्र में करने का पूरा प्रयास करेंगे, इसका मैं विश्वास भी दिलाता हूं।

माननीय सदस्यों, इस समस्या के लिए जो आप सबने मुझे भी बताया और बीच-बीच में अपने प्रश्न काल में प्रश्नों के माध्यम से भी जो सवाल किये उसमें भी मैंने आपके सभी प्रश्नों के उत्तर देने का प्रयास किया और उसके माध्यम से मेरे पास जानकारी भी आई लेकिन वास्तव में हम इस पर गम्भीरता से विचार करें तो निश्चित रूप से यह समस्या सबके लिए गम्भीर भी है लेकिन मैंने भी समझा है, मैंने भी इसको देखने का प्रयास किया है और मैंने कई बार अधिकारियों के साथ मीटिंग भी की, उनके साथ जब समस्या आती थी विधायक महोदय सभी पक्ष-विपक्ष के समस्या से अवगत कराते थे तो मैंने अधिकारियों के साथ भी कहा कि यह क्यों आ रहा है ऐसा और इसको नहीं आना चाहिये। मैंने भी आप ही की तरह इस विभाग को सम्भाला था तो निश्चित

(समय: बजे)

(श्री वासुदेव देवनानी, अध्यक्ष, पदासीन।)

रूप से मैं भी इसकी जड़ तक समस्या क्या है, इससे अनभिज्ञ था लेकिन जब मैं जड़ तक गया तो मैंने देखा कि यह समस्या आखिर क्यों है इसको समझा भी सही और आपने देखा होगा कि मैंने इसे समझने के लिए चाहे वो हमारा पूरा रेगिस्तानी क्षेत्र हो, सब जगह,

मैं बाड़मेर गया, जैसलमेर से लेकर के बीकानेर, जोधपुर तक चाहे वो भरतपुर हो मैंने हर सम्भागों का दौरा करके और उस क्षेत्र की समस्या का समाधान करने का और समझने का प्रयास किया। लेकिन मेरे भी जब समझ में आया, सारे विभाग और हमारे डिस्कोम और हमारे जनरेशन से लेकर के और हमारे चाहे वह अक्षय ऊर्जा हो, जो भी हम खरीदते हैं जहां से लाइट वो सब विभागों की हमने चर्चा की। मेरे भी यह समझ में आया कि मेरे प्रतिपक्ष के जो आप सदस्य हैं, जो आपके कार्यकाल में पांच साल में जो मेहनत होनी चाहिये थी, जो काम होना चाहिये था, मुझे निश्चित रूप से कोई संकोच नहीं है कि वह काम आप लोग नहीं कर पाये लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आप जिस काम को नहीं कर पाये उस काम को हम करके दिखायेंगे, इसको मैं आपको पूरे विश्वास के साथ कहता हूं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे मुख्य मंत्री जी की अगर किसी विभाग में चिन्ता है तो सबसे बड़ी चिन्ता इस ऊर्जा विभाग की है। यह कई बार वे मुझे कह चुके हैं, हमारे अधिकारियों को कह चुके हैं कि सारे विभागों की जितनी चिन्ता नहीं है उतनी चिन्ता मुझे ऊर्जा विभाग की है, इसके लिए उन्होंने निरन्तर प्रयास भी किया और आज उसमें कोई कमी भी नहीं छोडी।

हमारे प्रतिपक्ष के नेता बता रहे थे कि जिस तरह से हमने कोई भेदभाव किया है, हम भेदभाव नहीं बरत रहे हैं। विपक्ष के सभी सदस्यों के साथ मैंने इस विधान सभा में यहीं पर बुला कर कक्ष में मीटिंग भी की है। आपने जो समस्या बताई है उसका मैंने प्रयास भी किया है आपके सामने ही निर्देश भी दिये हैं। देखिये, समस्या का समाधान होना या नहीं होना यह अलग चीज है लेकिन हमारी नीयत में खोट नहीं है, यह मैं आपको बता देता हूं। आपकी जो समस्याएं आयेंगी चाहे वो विपक्ष की हों या पक्ष की हों, मैंने अधिकारियों को भी कहा है।

Kas/rtm/02.08.2024/22.10/5d

जो भी जनप्रतिनिधि की समस्या आये, उसको सुना भी जाये, उसका निष्पक्षता के साथ समाधान करने का प्रयास भी किया जाये। जब मैंने इस विभाग को सँभाला सबसे पहली समस्या कोल की आई। हमारे मुख्य मंत्री जी को भी चिंता हुई, उस कोल की समस्या के समाधान के लिये माननीय मुख्य मंत्री जी भी दिल्ली गये, मैं भी उनके साथ गया, हम कोल मिनिस्टर से मिले, ऊर्जा मंत्री जी से मिले। उन्होंने छत्तीसगढ़ के मुख्य मंत्री जी से बात की और प्रयास किया और उनके प्रयासों से हमारी डबल इंजन की सरकार के कोल मंत्री प्रहलाद जोषी जी ने कहा कि आपको कम कोयला मिल रहा है। उन्होंने अधिकारियों को बुलाया, निर्देश दिये कि राजस्थान में कोयले की कोई कमी नहीं होनी चाहिये, जितना कोयला इनको चाहिये, उतना निरंतर दिया जाये। उसी दिन से हमें लगातार कोल मिलने लगा और हमें 25-25 रैक कोल इंडिया से डिस्पेच होने लग गई। हमने उनको यह भी कहा कि हमने यह सब विरासत में संभाला है। हमसे कभी रेलवे पैसा मांगता है, कभी कोल इंडिया मांगता है, पैसे हों

या नहीं हों, हमारा कोल नहीं रुकना चाहिये। उन्होंने उसी समय अधिकारियों को कहा, इनकी न रैक रुके और न कोल रुके, हमें इनको सहयोग करना है और राजस्थान को ऊर्जा में आगे लाना है और उन्होंने हमें यह करके बताया। जब से हम सरकार में आये हैं, कोल की एक दिन भी प्रोब्लम नहीं आई। आज भी हमारे ऊर्जा के संयत्रों में दस दिन का कोल का स्टोरेज है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे पूर्व मुख्य मंत्री जी ने जिस तरह से ट्विट किया, हमें दो कोल ब्लॉक, एक 30 हैक्टेयर मिल गया और 26 हैक्टेयर मिल गया, एक 34 हैक्टेयर और मिलना था और 2 कोल ब्लॉक और मिलने हैं। हम जब भी किसी को कोई आग्रह करेंगे, पत्र लिखेंगे तो पहले तो उसका धन्यवाद ही देंगे या क्या कहेंगे? उन्होंने उस पत्र में उनका धन्यवाद दिया कि हमें आपने जो सहयोग किया, उसके लिये आपका धन्यवाद, लेकिन हमारी और भी बड़ी समस्या है, इसका समाधान आवश्यक है। जब वहां पत्रकारों ने पूछा होगा कि आपने क्या सारी कोल माइंस की परमिशन दे दी है क्या? तो उन्होंने कह दिया कि हमने ऐसी कोई परमिशन नहीं दी है। उसको गलत तरीके से माननीय पूर्व मुख्य मंत्री जी ने ट्विट किया। नेता, प्रतिपक्ष महोदय, राजनीति नहीं होनी चाहिये, मैं दिल से बोल रहा हूं। मैं यहां कोई राजनीतिक रूप से नहीं बोल रहा हूं, मैं दिल से बोल रहा हू और सत्य बोल रहा हूं। यहां लिखा हुआ है, गांधी जी सामने हैं, आप उनको भी देखते रहो। मैं सत्य बोल रहा हूं और मैंने स्पष्टीकरण दिया ...(व्यवधान)... मेरे स्पष्टीकरण देने के बाद भी ..

श्री अध्यक्ष: सचेतक जी, बैठिए, पहले ही इतना लेट करा दिया। आपके मंत्री जी ही बोल रहे हैं।

श्री हीरालाल नागर (राज्य मंत्री, ऊर्जा): फिर माननीय पूर्व मुख्य मंत्री जी ने असत्य वादे करने के आरोप लगाये। यह एक समस्या है, हमारे कोल ब्लॉक नहीं मिले, यह बंद हो जायें, क्या हमारे थर्मल नहीं चलें, आप लोग यह चाहते हैं क्या? फिर क्यों उस पर राजनीति करके खुशी मना रहे हो, ट्विट कर रहे हो, क्या मतलब था, क्यों करना चाहिये? ...(व्यवधान)...आपने भी प्रयास किया, आपकी सरकार ने भी प्रयास किया था। माननीय अशोक गहलोत जी छत्तीसगढ़ जाकर आ गये। आप क्यों नहीं कर पाये, क्यों नहीं वह माइंस आप दिला पाये? क्या कारण था, आप क्यों नहीं दिला पाये? आपकी तो सरकार थी ना, यह क्यों किया, साहब, क्यों महंगा कोयला खरीदना पड़ा? आपने क्यों उस समय रैक के टेंडर को ज्यादा बढ़ाया, ट्रांसपोर्टेशन किया, कुछ तो कारण होगा? कोई तो उसके पीछे कारण था। इम्पोर्टेड कोल खरीदना था, कमी होनी चाहिये, क्यों खरीदा, साहब? जो कोयला साढ़े चार हजार रुपये टन में आता था, 18 हजार रुपये टन में खरीदा है। उसको 18 हजार रुपये टन का भाव दिया है इम्पोर्टेड कोल के नाम पर। यह आपकी सरकार के कारनामे हैं।

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): भारत सरकार के निर्देश थे कि 10 परसेंट कोयला विदेश से मंगाना था।

श्री हीरालाल नागर (राज्य मंत्री, ऊर्जा): कोई मैनडेट नहीं था, कोई जरूरी नहीं था, आपके

पास है तो कोई जरूरी नहीं। उन्होंने यह कहा कि अगर नहीं है तो विकल्प था। आपने वह विकल्प चुना जिसमें फायदा ज्यादा था। क्यों किया आपने ऐसा साहब?

यह कोल महंगा मिला, हमें अपनी केप्टिव माइंस से कोल नहीं मिलने से, एक चीज और बता दूं, आपको पता नहीं होगा, हम अपने आवंटित माइंस से कोल नहीं ले पाते, माइनिंग नहीं कर पाते और हम उसी कोल के लिये अगर कोल इंडिया के पास जाते कि हमें अतिरिक्त कोयला दे दो, वह 40 परसेंट रेट ज्यादा लेकर हमें कोल देते, बात को समझो आप। तो 40 परसेंट ज्यादा रेट वहां लग रही है, यह 40 परसेंट ज्यादा रेट उस समय लगी तो यह फ्यूल सरचार्ज उसी का नतीजा है। यह फ्यूल सरचार्ज क्यों लग रहा है, फ्यूल की कॉस्ट ज्यादा आयेगी ...(व्यवधान)... प्लांटों में फिक्स कॉस्ट अलग है और वेरियेबल कॉस्ट अलग है। वेरियबल कॉस्ट में ज्यों ही भाव बढ़ेगा तो जनरेशन ज्यादा वसूल करेगा, भाव कम होगा, जितनी रेट में आयेगा तो वह करेगा। जनरेशन ने हमसे ज्यादा रेट वसूल की है, आपकी समय की है, 18 हजार की वसूल की, वह सब फ्यूल सरचार्ज के रूप में उपभोक्ता को देना होता है। आज आप यहां सदन में कह रहे हो फ्यूल चार्जेज लगा दिया, यह फ्यूल चार्जेज तो आपके समय का दिया हुआ है, हम नहीं लगा रहे हैं। हमने हमारे समय पर इस जनरेशन की रेट को भी थोड़े से समय में कम किया है। हमने पीएलएफ भी बढ़ाया है। आपके समय 50-55 परसेंट उत्पादन था। अब कोई भी फैक्टरी ले लो आप, अगर वह 50 परसेंट उत्पादन करेगी तो लोस तो होना ही है, कॉस्ट तो ज्यादा ही आनी है। आप तो समझदार हो, आप सब जानते हो। आज जब हम इसको 74 परसेंट पर लेकर आये हैं, अगर हमारा पीएलएफ बढ़ा है तो फिर कॉस्ट तो कम आनी ही है। आपकी 50-55 परसेंट, हम 65 पर लेकर आये, आज 74 पर लेकर आये हैं। हमने यह बिजली कहां से दी, हमने पीएलएफ भी बढ़ाया है, तो हमारा उत्पादन बढ़ा है ना। डिमांड तो 25 परसेंट, 28 परसेंट बढ़ गई, उतना हमारे पास नहीं था। हमने हमारे जनरेशन के इन प्लांटों को दुरुस्त किया, कोयला रेगुलर किया। आपके समय कोयले में पत्थर आते थे, भाटे आते थे, उनको ठीक किया।

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): हमारे टाइम में तो पानी आता था, लेकिन बिजली तो आती थी।

श्री हीरालाल नागर (राज्य मंत्री, ऊर्जा): बिजली आती थी, वह भी मैं अभी बता दूंगा आपको, आप सुन लेना। वह रिकार्ड भी मेरे पास है कि बिजली कैसे आती थी और कितनी आती थी, मैं बताऊंगा और आप भी कहेंगे कि हां सही है, क्योंकि आप अच्छे आदमी हैं।

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी, आप तो यह बताओ कि यह अच्छे आदमी ठीक जगह हैं क्या?

श्री हीरालाल नागर (राज्य मंत्री, ऊर्जा): आपने हमारे उत्पादन का देख लिया।

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय कार्य मंत्री): सही जगह है, पड़ोस वाले कोई गड़बड़ नहीं करे तो सही जगह है।

श्री हीरालाल नागर (राज्य मंत्री, ऊर्जा): उत्पादन में और बता दूं, आप सुनो। आपके

समय में जनरेशन को पैसा नहीं मिलता था, इनको पेमेंट समय पर करना होता है। आप क्या करते थे, कि पैसा नहीं है, कोल इंडिया को देना है, रैक का रेल को देना है, तो लोन ले लो। सरकार इनको समय पर पैसा नहीं दे रही, कोई फंड नहीं दे रही। इसकी वजह से पैसा नहीं होता था, आपने फ्री तो दे दी, लेकिन उसका पैसा तो सरकार को ही देना था ना।

Msk/rtm/02.08.24/2220/5e

इनको नहीं दे पाते थे तो हमारे उत्पादन तंत्र को भी लोन के लिए मजबूर होना पड़ा। उसका ब्याज लग रहा है, तो इन सब चीजों की वजह से इस उत्पादन तंत्र में भी घाटा। साहब, इसमें तो घाटे का सवाल ही नहीं उठता। घाटा हो ही नहीं सकता है, यह क्यों हुआ? इनमें भी घाटा है। प्रसारण में घाटा है। हमारे वितरण तंत्र में डिस्कॉम में घाटा है।

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): हम चला देंगे।

श्री हीरालाल नागर (राज्य मंत्री, ऊर्जा): ...(व्यवधान)... आप तो वैसे ही चला देंगे, जैसे आपने खरीद-खरीकर चलाया है। देखिये साहब आप सुनिये। 2013 से 2018 में हमारे डिस्कॉमों पर जिस तरह से हमने 62 हजार 400 करोड़ के ऋण से उदय योजना में इनको मुक्ति दिलायी, उसके बाद इन कंपनियों पर आपके पांच साल में 2 हजार करोड़ के करीब के मुनाफे में आपको सौंपा था। फिर आपने 1 लाख 39 हजार 200 करोड़ के कर्ज में इन कंपनियों को दिवाला कर दिया। आपने 88 हजार करोड़ के ऊपर तो डिस्कॉमों पर कर्ज थे, हमारे उत्पादन, वितरण का करेंगे तो 1 लाख 39 हजार करोड़ का कर्ज था। ये सब चीजें पहले आ चुकी हैं, ज्यादा बताने का कोई समय नहीं है।

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय कार्य मंत्री): आप तो पूरा बता दें।

श्री हीरालाल नागर (राज्य मंत्री, ऊर्जा): देखिये, माननीय नेता, प्रतिपक्ष कह रहे थे, मेरे एक प्रश्न में भी आपने कहा कि आप आखिर डेढ़ लाख कृषि कनेक्शन कैसे देंगे? यह सही बात है। आपने सही कहा। मैं आपको बता रहा हूं, आपने सही कहा कि आखिर देंगे कैसे? माननीय नेता प्रतिपक्ष, आपने यह तब नहीं सोचा जब 12 से 22 के कनेक्शन आपने जारी किये, डिमांड नोटिस उनसे ले लिया, किसान परेशान हो रहा है। आपने तब क्यों नहीं सोचा कि हम इनको कैसे जारी कर रहे हैं, हमारे पास वितरण नहीं, हमारे पास प्रसारण नहीं, हमारे पास उत्पादन नहीं। फिर आपने क्या सोचकर जारी किया?

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): हम तो देते।

श्री हीरालाल नागर (राज्य मंत्री, ऊर्जा): आप कहां से देते? आपने कहां दिये? आपने दे दिये होते तो फिर आपने हमारे ऊपर यह लोड क्यों दिया? आपको देना था। आपकी सोच सही थी तो आपको 2023 में इन कनेक्शनों देकर जनता को लाभ पहुंचाना था। आपने हमारे गले में यह सांप क्यों डाला? आपने दे दिये होते, ये तो हमने नहीं निकाले। इनका न हमने डिमांड नोटिस का पैसा लिया। यह तो आप सब लेकर, खर्च करके चले गये।

श्री यूनुस खान (डीडवाना): सब कुछ इनको ही कहेंगे क्या, उधर भी कहें।

श्री मनोज कुमार (सादुलपुर): यह जनता ने भार डाल दिया ...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी, आप सीधा बोलें, इनको छोड़ें।

श्री हीरालाल नागर (राज्य मंत्री, ऊर्जा): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि हमने जो कहा है, वह करेंगे। यह आप नोट कर लें। हमने कहा है कि डेढ़ लाख कनेक्शन हम देंगे, हम यह देंगे, इसकी तैयारी हमने कर रखी है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि पूरा रोड मैप बना रखा है। हम कैसे देंगे, मैं आपको समझा देता हूं। हम सोलर बढ़ा रहे हैं। हमने 4 हजार 41 सौ मेगावाट के सोलर के ऑर्डर दे दिये हैं। हम कुसुम योजना में अभी और ऑर्डर देंगे। हम पीएम सूर्य घर योजना लेकर आये हैं, उसमें भी लगभग एक लाख रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं। सात हजार ने अपने घरों पर लगवा लिए हैं। उसको तत्परता के साथ और लगायेंगे। जितने कनेक्शन हैं, उनके लिए हमने कहा कि हम आने वाले दो साल के अन्दर-अन्दर सभी कृषि कनेक्शनों को दिन में शिफ्ट करेंगे, सोलर से उनको बिजली देंगे, इसलिए हम सोलर को बढ़ावा दे रहे हैं। सोलर पर देंगे तो हमारा रात का लोड कम हो जायेगा, जो आज रात में लोड आ रहा है, वह नहीं होगा। इसलिए मैं आपकी चिन्ता दूर कर दूं, हमारे पास सब फिक्स हैं। हमने तैयारी कर रखी है, आप चिन्ता न करें। आपकी चिन्ता भी जायज है, लेकिन हम इसको करके दिखायेंगे।

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): लाइट अगर ऐसी ही रहे तो सब पीएम सोलर ले लेंगे और आपका सारा झंझट ही खतम हो जायेगा।

श्री हीरालाल नागर (राज्य मंत्री, ऊर्जा): हमारे एक सदस्य अभी बोल रहे थे कि विधायक आवास पर भी सोलर लगा रहे हैं। अब आपका ज्ञान दुरुस्त कैसे करूं, आप इनको पाठ तो पढ़ाओ।

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): समझा दूंगा।

श्री हीरालाल नागर (राज्य मंत्री, ऊर्जा): कहा कि नहीं कहा, साहब। उसका क्या मतलब था? आपके विधायक आवास पर सोलर लगायेंगे। हम 1 हजार मेगावाट के सोलर सभी सरकारी कार्यालयों पर लगा रहे हैं, उसकी बिड भी हमने निकाल दी है। ...(व्यवधान)... उसकी बिड भी हमने निकाल दी।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, ज्यादा देर होगी तो आपको समझ में नहीं आयेगी।

श्री हीरालाल नागर (राज्य मंत्री, ऊर्जा): माननीय अध्यक्ष महोदय, इन्होंने एक करामात क्या की? माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से इनको बताना चाहता हूं कि जादूगर जी ने बड़ा जोरदार जादू किया। हां, आप सुनें तो सही, हम बैंकिंग करेंगे, बैंकिंग मतलब बिजली उधार लेंगे। आपने उधार लेकर उस समय जो बिजली दी। माननीय अध्यक्ष महोदय, वह सांप भी उधार लेकर हमारे गले में डाल गये। ...(व्यवधान)... माननीय अध्यक्ष महोदय, इनको पता था कि हम आयेंगे, नहीं आयेंगे, कोई हमने कर्म तो ऐसे नहीं किये कि हम आ जायें। इनके पास पैसे नहीं थे, बजट नहीं था, ये तो मोबाइल बांटते, ये किट बांट रहे थे, बिजली खरीदने के पैसे कहां से लाते? आपके पास पैसे नहीं थे, आपके पास बजट नहीं

था। आपने बैंकिंग की। आप एक बात बतायें, हम सब समझते हैं, हम इतने तो भोले नहीं हैं, सब विधायक हैं, आप सब जानकार हैं। ये बिजली सर्दी में सस्ती मिलती है या गर्मी में सस्ती मिलती है? कब सस्ती होती है? जब सर्दी में बिजली सस्ती होती है तो सस्ती बिजली तो बैंकिंग कर ली। माननीय, महंगी बिजली गर्मी के टाइम पर हमें खरीदकर देनी पड़ी। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से सब सदस्यों से कहना चाहता हूं कि आप इस खेल को समझो। आप समझो, साहब।

इनका मैं आपको माहवार बताता हूं। हमने 01 से 14 मई, 2024 में लोड शेडिंग 16.15 लाख यूनिट किया, एवरेज और हमने 219 लाख यूनिट लौटायी। हमने 15 से 31 मई, 2024 तक 44 लाख यूनिट काटी, लौटायी 147 लाख यूनिट। हमने जून 2024 में ही 41 लाख काटी रोजाना और 140 लाख रोजाना लौटायी। हमने जुलाई में 23.34 लाख रोजाना काटी और 211 लाख लौटायी। यह मेरे पास रिकॉर्ड है। ...(व्यवधान)... यह रिकॉर्डेड है। हमने आपका जो कर्ज लौटाया, हमने लौटायी। साहब, एक मिनट आप सुनें। किसी को डाउट हो तो आप तो मुझसे अच्छी तरह परिचित हो। आप सभी मेरी तारीफ भी कर रहे हैं कि मुझे बुलाया, हमसे बात की। आपके जो भी सही काम होंगे, वह भी हम करेंगे, आप चिंता मत करो, लेकिन आप सुनो तो सही। आप मेरे पास आ जाना, मैं आपको समझा दूंगा, समझना हो तो। माननीय अध्यक्ष महोदय, इन्होंने 35 हजार 234 लाख यूनिट बिजली बैंकिंग की, हम अभी तक 24 हजार लाख यूनिट बिजली लौटा चुके हैं और अभी दो महीने में 11 हजार लाख यूनिट बिजली और लौटानी है। अभी तो यह सिलसिला और चलेगा।

mdp/rtm/02.08.2024/22:30/5f

केवल मैं आपको चार्ट दिखा दूं, मेरा डेटा दिखा दूं, केवल एक दिन ऐसा रहा है पूरे इन चार महीनों में जिस दिन हमने लौटायी कम और काटी ज्यादा, बाकी एक दिन भी ऐसा नहीं रहा जिस दिन हमने काटी ज्यादा हो, लगातार हमने ज्यादा लौटाई और काटी कम है, यह किस की देन है? अध्यक्ष महोदय, इनको समझ में ही नहीं आ रहा है। ध्यान ही किधर है।

श्री अध्यक्षः माननीय मंत्री जी, साढ़े दस बज गये, इनकी समझ में कम आ रहा है।

श्री हीरालाल नागर (राज्य मंत्री, ऊर्जा): माननीय अध्यक्ष महोदय, ये कहते हैं कि हमने कोई बिजली नहीं काटी। ये कहते हैं कि हमने हमारे राज में कोई बिजली नहीं काटी। आप कहानी सुनिए। 2022-23 में आपका था, 2023 में कोई कारण हो गया, उस समय मौसम ऐसा रहा कि 2023 में गर्मी में आपकी बिजली काटने की समस्या कम रही। मैं आपकी तुलना करता हूं, 2022 से। क्या हुआ? 2022 भी तो आपका ही था।

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): बिजली की चर्चा कर रहे हैं, गांवों में बिजली नहीं है।

श्री हीरालाल नागर (राज्य मंत्री, ऊर्जा): माननीय सदस्य, बात सुनिए। माननीय नेता, प्रतिपक्ष, सुनना चाहते हैं क्या? समझ गये क्या? पक्का।

श्री अध्यक्षः मैंने पहले ही कहा।

श्री रफीक खान (आदर्श नगर): ये बताओं कि बिजली कैसे दे रहे हैं? उसकी क्या प्लानिंग है?

श्री हीरालाल नागर (राज्य मंत्री, ऊर्जा): साहब, वह भी बताऊंगा, सुनिए तो सही।

श्री अध्यक्ष: इन्होंने भी सुना है। आज 12 बजे तक तो बोलना ही है।

श्री हीरालाल नागर (राज्य मंत्री, ऊर्जा): माननीय अध्यक्ष महोदय, हम बिजली पर चिंता कर रहे हैं। मतलब की बात बता रहा हूं, ये कहते हैं रात को हमें जनता सोने नहीं देती। ...(व्यवधान)... अब यहां बैठे हो तो क्यों वहां पर जा रहे हैं, जब सोने ही नहीं देती है तो क्यों परेशान हो रहे है आप? वहां जाकर भी परेशान होना है तो जल्दी क्यों है?

श्री अध्यक्ष: आप इधर देखिए। दिनभर इन्होंने सुना है, अब आप सुनिए।

श्री हीरालाल नागर (राज्य मंत्री, ऊर्जा): इन्होंने 2022 में अप्रैल में एवरेज, अप्रैल 2022 में इनके समय में जो एलडी से, लोड सेटिंग से जो मैसेज आये हैं, उसके द्वारा जो कटौती हुई है, अप्रैल 2022 में 3 घंटे 48 मिनट, आपके समय का रिकॉर्ड है, मेरा नहीं है।

श्री अध्यक्ष: सब लोग बैठिए। एक सेकण्ड, जो आपको बोलना था, आप बोलते रहे, अब आप इनका उत्तर सुनिए।

श्री हीरालाल नागर (राज्य मंत्री, ऊर्जा): माननीय अध्यक्ष महोदय, हमने अप्रैल 2024 में, पूरा एवरेज जो हमारा आया वह एवेरज बता रहा हूं 4 मिनट का आया है। मई 2022 में आपने 1 घंटा 14 मिनट एवरेज काटी, हमने काटी मात्र 43 मिनट एवरेज। आपके 2022 और 2024 के बीच में बता रहा हूं। जून में आपने 1 घंटा 34 मिनट काटी एवरेज, ये आपका रिकॉर्ड है। हमने काटी 1 घंटा 10 मिनट, ये एवरेज है हमारे अप्रैल, मई, जून का। आप कह रहे हैं हमने काटी ही नहीं। ये आपके समय का रिकॉर्ड है, जिसको हमने लिया है, ये कहां से आया? आप बताइए कहां से आया? आपके समय का रिकॉर्ड है बिजली कटने का।

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): अध्यक्ष जी, हमने मान लिया कि लाइट 24 घंटे आ रही है। कोई मतलब ही नहीं है कहने का।

श्री हीरालाल नागर (राज्य मंत्री, ऊर्जा): इनको पूरी बात सुनने दीजिए। चर्चा आपने करवाई है। हम तो तैयार थे। आपने चर्चा की मांग की, अध्यक्ष जी ने आदेश दिया।

श्री अध्यक्ष: अपनी सीट से जाकर बोलिए।

श्री हीरालाल नागर (राज्य मंत्री, ऊर्जा): माननीय अध्यक्ष महोदय, ये कहते हैं कि हमने कोई बिजली के आदेश नहीं दिये, काटी नहीं। मैं इनको बताना चाहता हूं कि आपके समय के आदेश है जिनमें 27 अप्रैल, 2022, 30 अप्रैल 2022, 22 दिसम्बर, 2022, 7 जनवरी, 2023, 17 जनवरी, 2023, 21 जनवरी, 2023, ये आपके आर्डर निकले हैं, इनकी कापियां हैं मेरे पास। बिजली कटौती के बाकायदा आर्डर निकाले हैं आपने। गांव, ढाणियों में तो कटौती की ही, जयपुर में भी कटौती की, संभागीय मुख्यालयों पर भी आर्डर निकाले आपने। कोई जगह ऐसी नहीं छोड़ी जहां कटौती के आदेश नहीं हो। यह सब आपके समय के आदेश हैं और आप कहते हैं कि कटौती नहीं की। ...(व्यवधान)... मान रहे है आप।

श्री अध्यक्षः अब आप आगे की बताइए।

श्री हीरालाल नागर (राज्य मंत्री, ऊर्जा): अब मैं इनको पिछली सरकार की थोथी घोषणाएं बताता हूं। आपने क्या-क्या घोषणा की थी, एक तो पूरी करते। ...(व्यवधान)... अच्छा तो इसको मान लीजिए पढ़ा हुआ, मैं इसको टेबल कर दूंगा। हमारे वैसे तो पूर्व मंत्री जी बता चुके हैं कि क्या-क्या घोषणा आपने की थी। बता दे इनको।

माननीय अध्यक्ष जी, इन्होंने 19 फरवरी को कोयला आधारित 6000 मेगावाट क्षमता के थर्मल प्लांट लगाने की घोषणा की, जिसकी कोई प्रगति नहीं हुई। तीन वर्ष बाद 2022 में 1320 मेगावाट का छबड़ा में, 800 मेगावाट का कालीसिंध में, 125 मेगावाट का गुढा बीकानेर में स्थापित करने की घोषणा की, जिसका रिजल्ट शून्य है। कांग्रेस के समय, ये कहते हैं कि हमने सुपर क्रिटिकल का सीओडी कराया। आपने कराया, लगाया, हमने मान लिया आपने कराया। जब पहले वहां लगा हुआ था, उसका कोयले का रिजल्ट मालूम था, दूर पड़ता है। आपकी उपलब्धि है ये एक, सबसे महंगी बिजली वहीं से मिलती है। हमारा ये पूरा कोयला आता है, मध्य प्रदेश से। छबड़ा, कोटा या झालावाड़ के रास्ते में, हमारे समय में झालावाड़, कोटा में प्लांट लगे, आप सूरतगढ़ में, आपने जो सुपर क्रिटिकल लगाया है, पहले की गलती हो गयी तो दोबारा तो नहीं लगाते दो-दो, महंगी बिजली हमें वहां से लेने को मजबूर होना पड़ रहा है, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन इतना पड़ता है। यही नहीं, आपके समय जो इंस्टालेशन हुआ, सारा काम हुआ, वह 400 मेगावाट से ज्यादा, 600 मेगावाट का, दोनों प्लांट चल ही नहीं रहे हैं। पांच साल हो गये, आपने कुछ नहीं किया। बात सुनिए आप, मैं सूरतगढ़ गया, क्यों नहीं चल रहे हैं? हमने जाकर देखा, हमने समझा, उन्होंने कहा कि, साहब, ये बीएचईएल ने सप्लाई किया है। भेल की प्रॉब्लम है, वह ठीक करने नहीं आ रहे हैं। हमने निर्देश दिलवाए, कहा कि तुम्हारे और प्लांट आने हैं, तुम्हें घुसने नहीं देंगे हम, आखिर में भेल को आकर वहां ठीक करना पडा। हमने एक प्लांट को ठीक करवा लिया है। दूसरा अभी शटडाउन में है। जिसको ठीक किया, उसकी 550 तक हमारी जनरेशन आ गयी है। आपके 400 से ज्यादा नहीं आ रही थी।

दूसरा, जो हमारा ठीक हो रहा है, वह भी 15 दिन में ठीक हो जायेगा। उसको भी पूरी क्षमता से चलाने लग जाएंगे। हम हमारा उत्पादन बढ़ा रहे हैं। बिना संयंत्र लगाये कर रहे हैं। यह आपको कराना था। आपके मंत्री जी तो दोनों ही वहीं से आते थे। सूरतगढ़ जाकर क्यों नहीं देखा? क्यों नहीं गये? ...(व्यवधान)... आपने 2023 में लिग्नाइट आधारित 1100 मेगावाट के प्लांट की घोषणा की, बाड़मेर के लिए, पांच वर्ष में आपने कुछ नहीं किया। आपकी एक उपलब्धि है, माननीय नेता, प्रतिपक्ष, आप अभी कह रहे थे।

श्री अध्यक्षः आप इधर बताइए। मेरे माध्यम से बताइए।

श्री हीरालाल नागर (राज्य मंत्री, ऊर्जा): अध्यक्ष महोदय, ये अभी कह रहे थे कि सोलर लगाए। आपकी उपलब्धि है कि 1310 मेगावाट की सौर ऊर्जा और 283 मेगावट की पवन ऊर्जा, जो आपके समय चालू हुई है। ये दो उपलब्धियां हैं आपकी। अभी आप कह रहे थे कि

हमने सोलर लगाए 21 हजार मेगावाट के। 21 हजार मेगावाट के आपने कहां से सोलर लगा लिये। आपको पता नहीं है जो 21 हजार मेगावट बता रहे हैं आप, वह तो सेगी की बिड करके अपने पास जमीन है, अपने यहां जनरेशन है सोलर का। हमारे पास 15 परसेंट, 12 परसेंट ज्यादा रेडीशन है और सारे देश से सोलर लगाने यहां आते हैं, ये बिजली हमारी सेंटर ग्रिड में डालकर यहां से ले जाते हैं। वह तो ट्रांसमिशन हो रही है, हमारे को नहीं मिल रही है। आपका ज्ञान दुरुस्त कर लीजिए, वह 21 हजार मेगावाट हमें नहीं मिल रही है। हमारे यहां केवल प्रोड्यूस हो रही है और बाहर के राज्यों को जा रही है, सेगी के थ्रू। आप कह रहे हैं हमने लगायी है, 2100 मेगावाट।

Ans/rtm 22.40 5g 02.08.2024

मैं भी चौंक गया कि इतनी बिजली लगा देते तो माननीय अध्यक्ष महोदय, हम एग्रीकल्चर को डे पर कर देते, अगर यह 21 हजार मेगावाट लगा देते तो, पर नहीं कर पा रहे।

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): 20-22 ज़िले तो हमने कर दिए थे दिन में। रिकार्ड चेक कर लेना।

श्री हीरालाल नागर (राज्य मंत्री, ऊर्जा): मेरे पास अभी मसाला बहुत है, आप कहें तो। ..(व्यवधान)...आरडीएसएस योजना केन्द्र की योजना है। आपने टेंडर किए ...(व्यवधान)...

श्री राजेन्द्र पारीक (सीकर): अध्यक्ष महोदय, ग्रामीण अंचल में काश्तकार को बहुत बड़ी परेशानी हो रही है बिजली की कमी की वजह से, उसका कोई समाधान कर दें। ...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्षः सुनो भई। आप क्यों बोल रहे हैं।

श्री राजेन्द्र पारीक (सीकर): आप यह इंश्योर करो कि कल से ही देंगे। यह इंश्योर करो ना आप। उसने क्या किया, उसने क्या किया, सुबह से यही सुन रहे हैं। कल से बिजली दे रहे हैं, यह इंश्योर करो आप तो।

श्री हीरालाल नागर (राज्य मंत्री, ऊर्जा): हां, मैं इंश्योर कर रहा हूं कि...

श्री राजेन्द्र पारीक (सीकर): कल से बिजली दे रहे हैं, यह इंश्योर करो आप तो।

श्री हीरालाल नागर (राज्य मंत्री, ऊर्जा): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से इनको बताना चाहूंगा, सोलर सेम चल रही है हमारी शोर्ट टर्म प्लानिंग हमारे जनरेशन के प्लांट को ठीक कर रहे है, उससे जनरेशन बना रहे है और हम लोंग टर्म प्लानिंग भी कर रहे हैं। हमने सरकार में आते ही सबसे पहले काम किया लोंग टर्म प्लानिंग का, शोर्ट टर्म में तो थोड़ा अब चल रहे हैं नीचे तक। बाकी हमने पहले लोंग टर्म में इसलिए किया क्योंकि उसमें समय लगता है, वह कोई एक दिन में नहीं आता। हम कोई भी थर्मल् लगाएंगे, उसमें चार-पांच साल लगते हैं। ...(व्यवधान)... जो भी है, लेकिन हम घबराए नहीं। आपने इसलिए नहीं लगाया, देखो मैं बहुत सही बता रहा हूं, आपने इसलिए नहीं लगाया कि लगाएंगे तो हम,

इसका फायदा तो हमें मिलना नहीं है। आप तो होटलों में घूमते रहे, इतना समय ही नहीं मिल पाया कि लगाने की प्लानिंग कर लेते।

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): दो साल कोरोना था इसलिए नहीं लगा पाए। आप कोरोना का भी देखो।

श्री हीरालाल नागर (राज्य मंत्री, ऊर्जा मंत्री): नहीं, नहीं आप प्लानिंग में रह गए। ...(व्यवधान)... जूली साहब, एक बात बताओ, आपकी सरकार स्टेबल थी ही नहीं, आपको तो यह पता था कि कब चले जाएं हम, आज इधर कल उधर। रोज इधर-उधर हो रहा था ना पलड़ा, तो कैसे निर्णय कर पाते, कर ही नहीं पाए। ...(व्यवधान)... देखिये, हमारी सरकार डबल इंजन की है, हमारी सरकार स्थिर है इसलिए हमने आते ही लोंग टर्म प्लानिंग की, अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से इनको बताना चाहता हूं।

हमने शक्ति पॉलिसी के तहत 3200 मेगावाट के थर्मल प्लांट और 8 हजार मेगावाट के सोलर प्लांट की बिडिंग, कुल 11 हजार 200 मेगावाट की बिडिंग, टैरिफ बेस निकालिए जो 34 हजार करोड़ की है, उसकी प्रक्रिया हमने चालू कर दी है। हमने भविष्य की आवश्यकताओं को देखते हुए उत्पादन निगम, एनटीपीसी, एनजीइएल, कोल इंडिया नेवेली लिग्नाईट जैसे केन्द्रीय उपक्रमों के साथ संयुक्त उपक्रम के माध्यम से 3 हजार 325 मेगावाट का कोलबेस और 28 हजार 500 मेगावाट की अक्षय ऊर्जा के एमओयू किए हैं जिसकी लागत 1 लाख 50 हजार करोड़ है। ...(व्यवधान)...हमने कुसुम योजना के भी कम्पोनेंसी के भी 4400 मेगावाट के आदेश जारी कर दिए हैं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय प्रतिपक्ष के सदस्यों को बताना चाहता हूं, तत्कालीन पूर्व मुख्य मंत्री अशोक जी गहलोत ने घोषणा करी कि हम बिजली में आत्मनिर्भर हो गए। जब आप बिजली में आत्मनिर्भर हो गए थे तो फिर आपने बैंकिंग क्यों करी। आप बताओ ना साहब, आपको बैंकिंग की जरूरत क्यों पड़ी, आप आत्मनिर्भर थे तो। ...(व्यवधान)...

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): हमारे में से भी ज्यादातर लोगों ने बैंकिंग कर रखी होगी। यह एक प्रक्रिया है। आम आदमी पैसे वाला होता है वह भी बैंकों में पैसा रखता है, निकाल लेता है। इसी प्रकार से बिजली खरीद लेते हैं और बेच देते हैं, उसी से करते हैं। आप एक बात बताओ, उस आदमी में कलाकारी थी, चाहे बैंकिंग की हो, चाहे मंहगी खरीदी हो, राजस्थान के किसान को, आम जनता को बिजली दी, आपकी तरह परेशान नहीं रखा।

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय कार्य मंत्री): एक बात बताओ, आइंदा बिजली की चर्चा मांगोंगे तो अभी हमारे पास बहुत है, नहीं तो कह दो गलती हो गई ...(व्यवधान)...

श्री हीरालाल नागर (राज्य मंत्री, ऊर्जा): अध्यक्ष महोदय, हमारे पास भी बहुत से आते रहते हैं। हमारे पास भी बैंकिंग वाले आए। मैंने पूछा यह बैंकिंग क्या होता है? कहा कि बैंकिंग कर लो, यह अच्छा होता है। क्यों भई, क्यों कर ले बैंकिंग? कहा कि, साहब, यह सर्दी में भी सस्ती में मिल जाती है, बैंकिंग कर लो फिर सस्ती रेट में दे देना, इसमें सब सेटिंग-

वेटिंग होती है। यही काम करना था क्या, साहब, आप क्यों महंगी बिजली खरीदकर देने को मजबूर होना पड़ता ...(व्यवधान)... किसकी वजह से, आपकी वजह से।

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी, जल्दी समाप्त करें। ...(व्यवधान)...

श्री हीरालाल नागर (राज्य मंत्री, ऊर्जा): माननीय अध्यक्ष जी, में आपके माध्यम से सदन को बताना चाहता हूं कि विगत प्रसारण तंत्र में प्रसारण तंत्र की हालत ऐसी है, मैं सुदूर रेगिस्तान में भी गया हूं, मैंने देखा है वहां 5-5 फीडर पर एग्रीकल्चर को चला रहे हैं। 4-4 फीडर पर चला रहे हैं। आप कह रहे हो हमने दिन में देना शुरू कर दिया था हमारे टाइम। मैं खुद देखकर आया हूं, वहां क्षमता ही नहीं हैं ट्रांसमिशन की। वहां ट्रांसफार्मर की क्षमता ही नहीं है। चार-चार घंटे चलाना पड़ रहा है एक-एक ब्लाक को, ऐसी हालत है। आपने ट्रांसमिशन में कोई काम नहीं किया। पिछली सरकार ने प्रसारण तंत्र को प्रभावी रखने के लिये 132, 220, 400 और 765 केवी के ऊपर ध्यान नहीं दिया। आपने केवल अपने समय 2018 से 23 तक 400 केवी का मात्र एक, 220 केवी के 05, 132 के 47 कुल 43 सब स्टेशन ही निर्माण करवा पाये आप। हमने आते ही इनकी क्षमताओं को, 112 नये जीएसएस हाथ में लिये हैं, 48 प्रगतिरत हैं 22 के कार्यादेश जारी कर दिये गये हैं, 4 की निविदायें प्रक्रिया में हैं और 48 की हम और निविदा शुरू करने जा रहे हैं।

यही नहीं, हमने प्रसारण तंत्र के लिये गवर्नमेंट पीएसयू से सेंटल पीएसयू से पीजीसीआइ से भी एमओयू किया है जिसमें 10 हजार करोड़ रूपये का इनवेस्टमेंट होगा। प्रसारण तंत्र को इसके साथ मिलकर मजबूत भी करेंगे और आने वाले दस की डिमांड है, उसके अनुसार हम काम कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि आग लगते ही कुआं खोद लो। हम आगे की सोच के चल रहे हैं। हम 2047 को विकसित बनाने की योजना लेकर चल रहे है। कई सदस्यों ने अभी विचार रखे। उनके व्यक्तिगत जवाब भी हैं मेरे पास।

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): बाद में अपने-अपने इलाक़े में जाएंगे जब पता चलेगा।

श्री हीरालाल नागर (राज्य मंत्री, ऊर्जा): माननीय कई सदस्यों ने प्रश्न उठाये ...(व्यवधान)...उनके व्यक्तिगत जवाब भी हैं मेरे पास। दया है मन में। मैं असत्य नहीं बोलता, मैं दयालु हूं। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, जितने भी हमारे सदस्य हैं, इस सरकार के कार्यकाल में आप देखोंगे, आपका वितरण में कोई काम नहीं बचेगा जो हम नहीं कर पायेंगे। जितने आप कहेंगे, जहां फिजिबल है, सारे जीएसएस बनाएंगे। जीएसएस के लिये आपको पहले मांगना पडता था, जरूरत नहीं है। आप बता देना हम पक्ष विपक्ष के सबके बनाएंगे, कही कोई नहीं छोडेंगे, यह जनता सारा राजस्थान हमारा है। ...(व्यवधान)...

प्रसारण तंत्र का आपने देख लिया। हमारी डबल इंजन की सरकार है। ये जो आरडीएसएस का काम चल रहा है, आरडीएसएस वास्तव में ठेकेदारी प्रथा में काम धीरे हो रहा है। आपके समय के टेण्डर थे, मैंने अधिकारियों को कहा है, इस टेण्डर को ढंग से बनाओं। मैं तो वैसे भी हमारे मुख्य मंत्री जी को लेकर जाऊंगा, हम तो बात भी करेंगे कि आरडीएसएस में टेण्डर

की बाध्यता हटा दी जाये तो सीएलआरसी पर हम बहुत अच्छा काम कर सकते है इसके लिये भी हम केन्द्र में कोशिश करेंगे। क्या होगा या नहीं पर अच्छी बात के लिये प्रयास करने में कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि उसमें हम ज्यादा फास्ट काम कर सकते हैं।

VPS-RTM-02.08.202-22.50-5h

जब तक आर.डी.एस.एस. का फास्ट काम नहीं होगा तो वहां तक वितरण तंत्र को हम मजबूत नहीं कर सकते इसमें असत्य बोलने में कोई मतलब नहीं है। हम सारे फीडर, 7896 करोड़ रुपये का प्रोजेक्ट हमारा स्वीकृत हो चुका है जिसमें लगभग 7500 फीडर नये बनेंगे और उससे हम सिंगल फीडर गांवों का जो 24 घंटा होगा, एग्रीकल्चर का फीडर जो है, उसको भी अलग करेंगे, सिंगल फीडर को अलग करेंगे। गांव को अलग करेंगे ताकि गांव की लाइट, कभी एग्रीकल्चर की लाइट कट रही है पर गांव में 24 घंटे यह चालू रहे और वहां की लाइट ट्रिपिंग नहीं हो। अभी यह होता है और अब आप कहते हो कि यह क्यों जा रही है? साहब, यह तो आठ-आठ घंटे जा रही है। एग्रीकल्चर वाला है वह चार बार शट-डाउन लेता है, चार घंटे हो गये, दिन में वह चार शट-डाउन लेता है तो चार बार कट जाती है तो 24 घंटे वह लाइन गांवों में भी कटती है, वह सिंगल फेज भी कटती है, थ्री फेज भी कटती है, जिसकी वजह से आपको ज्यादा नजर आता है दिन में पर हम तो लोड शेडिंग दिन में नहीं करते, रात में ही करते हैं इसलिए वह दिन की जो लोड शेडिंग होती है, जो भी शट-डाउन लेते हैं वह तो गिनती में ही नहीं है, हर कोई शट-डाउन ले लेता है आज। वह फिर जरूरत नहीं पड़ेगी, हम अलग करेंगे उन फीडरों को।

श्री घनश्याम (टोडाभीम): आप रात को मत करो, दिन में ही करो। ...(व्यवधान)...

श्री हीरालाल नागर (राज्य मंत्री, ऊर्जा): नेता, प्रतिपक्षजी और माननीय अध्यक्षजी, आप अब इनकी क्लास तो लो एक बार, नहीं ले सको तो आप हमारे पास ले आओ, हम दे देंगे कि रात और दिन में कैसे कटती है? हम समझा देंगे न। ...(व्यवधान)...

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): आप तो केवल यह बता दो सारी चर्चा के बाद में, सारे सदस्य आपके और हमारे यह चाहते हैं, हमने आपको खूब सुन लिया, आप तो यह बता दो कि यह जो प्रॉब्लम चल रही है न राजस्थान में यह कब तक हल हो जायेगी? यह आप 2047 मत बताओ। ...(व्यवधान)...

श्री हीरालाल नागर (राज्य मंत्री, ऊर्जा): देखिये, आप बात सुनें। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपको यह बात बताना चाहता हूं कि देखिये हमारी नीयत में खोट नहीं है। तीन दिन पहले यह चर्चा होना तय हुआ, तीन दिन पहले ही माननीय अध्यक्षजी के यहां से यह आया कि इस पर चर्चा होगी। अब पता है, हमारी नीयत ठीक है, इन्द्र देवता को भी पता है कि ये ईमानदारी से काम कर रहे हैं तो एक दो दिन पहले ही यह पानी बरसा दिया, दो दिन से कोई कटौती नहीं हो रही है, कहीं पर हमने एक यूनिट बिजली भी नहीं काटी है पिछले दो दिन में। आप यह बताओ कि यह तो चमत्कार है या नहीं है? अब आप यह कह रहे हो कि

हनुमानजी का नाम लेते ही क्यों आये? हम तो इन्द्र देवता का नाम ले रहे हैं। हम तो इन्द्र देवता का नाम ले रहे हैं और उन्होंने मेहरबानी कर दी, साहब।

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): इस पर विधान सभा पर चर्चा होगी इसलिए दो दिन से आपने यह लाइट दे रखी है और यह इन्द्र भगवान कब तक बचायेगा? ...(व्यवधान)...

श्री हीरालाल नागर (राज्य मंत्री, ऊर्जा): इन्द्र की कृपा है कि नहीं है? ...(व्यवधान)...

श्री श्रीचन्द कृपलानी (निम्बाहेड़ा): बालाजी की जय। ...(व्यवधान)...

(भारतीय जनता पार्टी के कई माननीय सदस्यों द्वारा अपनी-अपनी सीट से नारे)

श्री अध्यक्ष: आप विराजिये। यह नारेबाजी नहीं। नहीं। यह सदन है। यह सदन है। ...(व्यवधान)...

श्री हीरालाल नागर (राज्य मंत्री, ऊर्जा): यह कृपा हो जायेगी। अब हम तो उसकी कृपा पर ही है। निश्चित रूप से हम मेहनत भी कर रहे हैं, ईमानदारी से भी कर रहे हैं।...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्ष: आप तो इतने सीनियर हो। आप बैठिये। आप बैठो। ...(व्यवधान)...

श्री हीरालाल नागर (राज्य मंत्री, ऊर्जा): माननीय अध्यक्ष महोदय, अंत में मैं यही निवेदन करना चाहता हूं कि सात माह से हमारे माननीय मुख्य मंत्री श्री भजन लालजी के निर्देशन में हम और हमारा विभाग, हमारे विभाग के अधिकारी हों या चाहे कर्मचारी हों, वे पूरी तत्परता से सेवा में लगे हुए हैं, हम कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं, किसी प्रकार की कोई कमी नहीं छोड़ रहे हैं। शुरूआत में मैंने अधिकारियों के साथ बहुत ही जद्दोजहद की है, विभाग की तकनीकी बारीकियों को भी समझा और मुझे यह पीड़ा होती है और मैं भी यह मानता हूं कि जब किसान की लाइट कटती है, चाहे वे छोटे बच्चे हों, तो निश्चित रूप से यह तकलीफ है और इसको हम भी समझते हैं और आप भी समझते हो, यह नहीं होना चाहिए लेकिन इस पीड़ा से हम परेशान हैं। हमारे मुख्य मंत्रीजी का यह निर्देश है कि जिस भी रेट में मिल जाये, कैसे भी मिल जाये, हमें कोई इच्छा नहीं है कि एक भी दिन बिजली काटे। चाहे वह हमें विंड से मिले, मैं आपको थोड़ा सा और समझा दूं कि हमें सोलर में पांच हजार मिल जाती है। साहब, रात को भी जब चार हजार, साढ़े चार हजार हमें विंड से मिलती है तो कभी-कभी तो रात को दो-ढाई हजार भी नहीं मिलती और कभी-कभी तो दो सौ भी नहीं आती है विंड से। जब रात को सोलर नहीं है, विंड से नहीं आती है तो फिर, टोडाभीम से आने वाले माननीय सदस्य, मैं आपको यह बताना चाहूंगा कि फिर हम वहां पर एक्सचेंज से भी खरीदते हैं, हम दो दिन पहले भी बिडिंग करते हैं, एक दिन पहले भी करते हैं, तो हम फिर शॉर्ट-टर्म बिडिंग भी करते हैं। जब वह बिलकुल नहीं मिलती और हमारा यह गैप होता है तो उस समय हमें अगर ग्रिड को बचाना है तो हमें फिर यह लोड-शेडिंग करना ही पड़ेगा, नहीं तो फिर सिस्टम फेल्योर हो जायेगा इसलिए रात को काटनी पड़ती है। यह हमारी मजबूरी है, यह हमें परेशानी होती है, इसलिए यह पीड़ा हम भी समझें।

अब मैं यह कहूंगा कि इस चर्चा में काफी अच्छे सुझाव दोनों पक्षों की तरफ से आये हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे पक्ष के माननीय सदस्य और प्रतिपक्ष के माननीय सदस्य

भी इस समस्या से अच्छी तरह से अवगत हैं, ये यह मानते हैं कि इसके समाधान में कुछ समय लगेगा। यह समस्या तात्कालिक नहीं है लेकिन हम ने आने वाले समय के लिए एक हजार मेगावाट बिजली की एक ओर बिड निकाल दी है, जिसको अभी शॉर्ट-टर्म बिड की है, हम दो हजार मेगावाट की सर्दियों के लिए एक और बिड निकाल रहे हैं, हम बैंकिंग नहीं करेंगे अब, हमने कान पकड़ लिये हैं, आपसे यह सीख ले ली है कि बैंकिंग कतई नहीं करनी है। हम अब बिड करके जो भी परचेजिंग रेट आयेगी उस पर खरीदेंगे न कि बैंकिंग करेंगे और हम आने वाली सर्दियों के लिए, रबी के सीजन के लिए अभी से ही चिंतित हैं और अभी से हम प्रयास भी कर रहे हैं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं अपनी बात को माननीय अटलजी की इन पंक्तियों के साथ समापन करना चाहता हूं-

उजियारे में, अंधकार में,
कल कहार में, बीच धार में,
घोर घृणा में, पूत प्यार में,
क्षणिक जीत में, दीर्घ हार में,
जीवन के शत-शत आकर्षक,
अरमानों को ढलना होगा
कदम मिलाकर चलना होगा।
कदम मिलाकर चलना होगा।

श्री अध्यक्षः धन्यवाद। आप सब एक बार विराजिये। माननीय मंत्रीजी।

सभी माननीय सदस्यों को यह जानकारी है कि 05 तारीख को अपने नवाचार के कार्यक्रम के लिए मैंने सोचा है। सारे माननीय सदस्य अपने क्षेत्रों में उन्होंने जो कोई भी नया कार्य किया है, उसको बताने के लिए स्वतंत्र होंगे। अपने-अपने सचेतकों को आप अपना नाम लिखा दें ताकि उसका लाभ पूरे 200 माननीय सदस्यों को हो सके। आप इसकी तैयारी करे आएं।

सदन की बैठक सोमवार, दिनांक 05 अगस्त, 2024 के प्रातः 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की बैठक 22.56 बजे सोमवार, दिनांक 05 अगस्त 2024 के 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई।)

....